

Indian Journal of Social Concerns

इण्डियन जर्नल ऑफ सोशल कन्सर्न्स

(कला-मानविकी-समाजविज्ञान-जनसंचार-विधि-वाणिज्य-विज्ञान, वैचारिकी की अन्तरराष्ट्रीय द्विमासिक शोध पत्रिका)

Volume -12:

Issue - 55

Sep. - Oct. 2023

Ghaziabad

A RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

(An International Peer-Reviewed & Refereed Journal)

Journal Impact Factor No. : 7.841

Editor

Dr. RAJ NARAYAN SHUKHLA

Asstt. Editor

Dr. MUKTA SONI

Art Editor

(MS) MANISHA VERMA

Legal AdvisorDr. JASWANT SAINI
SHRI BHAGWAN VERMA**Office Assistant**

JITENDER GIRDHAR

Editor in Chief

Dr. HARI SHARAN VERMA

Sub EditorDr. PUSHPA
Dr. BEENA PANDEY (SHUKLA)**Managing Editor**

Dr. SANGEETA VERMA

Joint EditorDr. PRIYANKA SINGH
Dr. SUBHASH SAINI**Computer Operator**

MS. NEHA VERMA

- The responsibility of the originality of the articles/papers shall be of the author.
- The editor does not owe any kind of responsibility in this regard



Dr. Hari Sharan Verma

D.Litt

Editor in Chief

Dr. Raj Narayan Shukhla

Editor

Dr. Sangeeta Verma

Managing Editor

**मानविकी शोध पीठ प्रारम्भ सोसायटी,
गाज़ियाबाद द्वारा संचालित**

LIFE MEMBERS OF INDIAN JOURNAL OF SOCIAL CONCERNS

1. **Dr. Praveen Kumar Verma**
Associate Professor, Hindi Department, GGD Sanatan Dharam Post Graduate College, Palwal.
2. **Smt. Veena Pandey (Shukla)**
Hindi Teacher, Jawahar Navodya Vidyalya, Dhoom Dadri, Distt. Gautambudhnagar - 203207 (U.P.)
3. **Dr. Suman**
H.No. 1001, Radha Swami Colony, Rohtak Road, Bhiwani (Haryana)
4. **Principal**
Sat Jinda Kalyana College, Kalanaur (Rohtak, Haryana) 124113
5. **Dr. Subhash Chand Saini** (Hindi Department, Dyal Singh College, Karnal, Haryana)
6. **Dr. Vimla Devi**, Associat Professor (History), Swami Vivekanand Govt. (PG) College, Lohaghat, Champawat (Uttarakhand)
7. **Princepal**, Associat Professor (Hindi), Aggarwal College, Ballabgarh (Haryana)
8. **Dr. Dinesh Mani Tirpathi (Principal)** L-P=-K Inter College sardar Nagar, Basdila Gorkhpur
9. **Dr. Govind Prakash Acharya** F--63, Chandra Vardai Nagar, UIT, Colony, Shaheed Bhagat Singh Marg, OppositeRamganj Thana, Taragarh Road, Ajmer (Rajasthan) Pincod--305003.
10. **Amardeep Singh** Mcf C -21, Near Deep Vatika, Bhagat Singh Colony, Ballabgarh121004, Mob. 9873814066

प्रकाशक : डॉ० राजनारायण शुक्ला, सम्पादक
SH, A-5, कविनगर, गाजियाबाद (उ० प्र०)
दूरभाष : 9910777969

E-mail : harisharanverma1@gmail.com

WWW.IJSCJOURNAL.COM

सहयोग राशि (भारत में)

(व्यक्तिगत) (आजीवन 5100 रुपये)

(संस्थागत) (आजीवन 7100 रुपये)

कृपया सहयोग राशि बैंक ड्राफ्ट से ही भेजें।

बैंक ड्राफ्ट, संपादक "इण्डियन जर्नल ऑफ सोशल कन्सर्न्स" के पक्ष में देय होगा। आजीवन सदस्यता केवल दस वर्षों के लिए मान्य होगी। यदि किसी कारणवश पत्रिका का प्रकाशन बन्द हो जाता है तो आजीवन सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

संपादकीय कार्यालय :

1. **डॉ० हरिशरण वर्मा, प्रधान सम्पादक**
F-120, सेक्टर-10, DLF, फरीदाबाद (हरियाणा)
harisharanverma1@gmail.com 09355676460
WWW.IJSCJOURNAL.COM

2. **डॉ० राजनारायण शुक्ला, सम्पादक**
SH, A-5, कविनगर, गाजियाबाद (उ० प्र०)

क्षेत्रीय सम्पादक

- डॉ० वाई.आर. शर्मा, A-24, रेजिडेंसल कैम्पस, न्यू कैम्पस, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू-180001, फोन : 09419145967
- डॉ० सलमा असलम, ओल्ड टाउन बारामुला, कश्मीर पिन-193101, मौ० 9682162934
- डॉ० आरती लोकेश P.o.Box 99846, Dubai, UAE 97150-4270752
- श्री मोहनलाल, 11 अशोक विहार, संजय नगर, पो. इज्जत नगर बरेली (उ० प्र०) फोन : 09456045552
- श्री जितेन्द्र गिरधर, कार्यालय सहायक 105/26 जवाहर नगर, कॉर्पोरेटिव बैंक के पीछे, रोहतक 09896126686
- डॉ० विमला देवी, सहायक प्रोफेसर (इतिहास) स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट चंपावत (उत्तराखण्ड)-262524 - 9411900411
- डॉ० प्रिया कपूर, सहायक प्रोफेसर, डी० ए० वी शताब्दी कालेज, फरीदाबाद मौ० 9711196954
- डॉ० किरण मिश्रा, सहायक प्रोफेसर, हिन्दी, रामगुलामराय पी० जी० कालेज, देवरिया गोरखपुर-273001 मौ० 7007018819
- डॉ० ऊषा रानी, हिन्दी-विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5
- विमला टोप्पो, एस० आर० इंटरप्राइसेस म्युनिसिपल काम्पलेक्स सोपन 04, डेरी फार्म, पोर्ट बलेयर, पी० ओ० जंगली घाट-744103 साउथ अंडमान
- डॉ० राजपाल, सहायक प्रो० राजकीय स्थानकोत्तर महाविद्यालय, हिसार

संरक्षक मण्डल :

- डॉ० चक्रधर त्रिपाठी कुलपति, उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरोपुट, 763004, चलभाषा: 9437568809
- डॉ० दिनेश मणी त्रिपाठी, प्रधानाचार्य एन० पी० के० आई कालेज, सरदार नगर बसडीला (गोरखपुर) उ० प्र०
- डॉ० नरेश मिश्रा (पूर्व आचार्य, हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
- डॉ० वाई.आर.शर्मा, (राजनीति शास्त्र विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू)
- डॉ० सुधांशु कुमार शुक्ल चेयर हिन्दी, आई. सी. सी. वासा विश्वविद्यालय, वासा (पोलैन्ड) मौ० 48579125129
- डॉ० तपन कुमार शण्डिल्य, कुलपति, डॉ० श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय राँची, (झारखण्ड) 9431049871
- डॉ० जंगबहादुर पाण्डेय (पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग) राँची विश्वविद्यालय, राँची - 834008 फोन : 09431595318
- सुदेश रावत प्राचार्या एस. एन. आर. जयराम महिला कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र हरियाणा 36119 (सेठ नारंग राय लोहिया जय राम महिला कॉलेज)

परामर्शदात्री समिति :

- डॉ० विजयदत्त शर्मा, पूर्व निदेशक, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी पंचकूला(हरियाणा)
- डॉ० सुधेश (पूर्व आचार्य, हिन्दी विभाग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)
- डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल (पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, वर्धमान कॉलेज, बिजनौर)
- डॉ० राजकुमारी सिंह, प्रोफेसर एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय लोधीपुर राजपूत मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 9760187147
- डॉ० माया मलिक, पूर्व प्रोफेसर हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
- डॉ० ममता सिंहल, (एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग) जे० वी० जैन कॉलेज सहारनपुर
- डॉ० विनीत बाला, सहायक प्रो. भूगोल विभाग, वैश्य पी.जी. कॉलेज, रोहतक

संपादकीय विशेषज्ञ समिति :

हिन्दी विभाग:

- डॉ० राजेश पाण्डे (डी.वी. कॉलेज, उरई, जिला जालौन, उ० प्र०)
- डॉ० अनिता, सहायक प्रोफेसर, (हिन्दी), श्री अरविन्दो कालिज दिल्ली (साध्य) मौ० 8595718895
- डॉ० सुशील कुमार शर्मा (अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग, मेघालय)
- डॉ० शशि मंगला, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गोस्वामी गणेशदत्त स्नातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पलवल
- डॉ० के० डी० शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, गोस्वामी गणेशदत्त स्नातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पलवल
- मुकेश चन्द्र गुप्ता (हिन्दी विभाग, एम.एच.पी.जी. कॉलेज, मुरादाबाद)
- डॉ० गीता पाण्डेय (रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, एस.डी.

9. डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा (सह प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग) गोस्वामी गणेशदत्त सनातन धर्म महाविद्यालय, पलवल
10. डॉ० सुधा चौहान, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, वैश्य कालिज, भिवानी
11. डॉ० रूबी, (सीनियर सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग कश्मीर)
12. डॉ० सुमन राठी, सहायक प्रो० हिन्दी विभाग, मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर रोहतक
13. डॉ० सुधा कुमारी (हिन्दी विभाग) एन०जी०एफ० डिग्री कालिज, उड्डू, अध्ययन केन्द्र मथूरा रोड, पलवल 982719456
14. डॉ० एम. के. कलशेट्टी, हिन्दी विभाग, श्री माधवराव पाटिल महाविद्यालय, मुरुम तह० अमरगा, जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)-413605
15. डॉ० मनोज पंड्या, व्याख्याता हिन्दी विभाग, श्री गोविन्द गुरु, राजस्थान महाविद्यालय, बांसवाड़ा-327001, मो० 09414308404
16. डॉ. कृष्णा जून, प्रो० हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
17. डॉ. विपिन गुप्ता, सहायक प्रोफेसर, वैश्य कॉलेज भिवानी
18. प्रो० (डॉ०) वन्दना शर्मा, म. न. 2, प्रोफेसर लॉज, किचम सी. डी. एम., मोदीनगर (उ.प्र.) 201204, मो० 2760411251
19. डॉ० जाहिदा जबीन, (प्रो० एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर-६)
20. डॉ० टी०डी० दिनकर, (एसो० प्रो० एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़)
21. डॉ० सुभाष सैनी, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग दयालसिंह कॉलेज, करनाल, हरियाणा)
22. डॉ० उर्विजा शर्मा, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग शम्भु दयाल स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, गाजियाबाद)
23. डॉ० कामना कौशिक, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग एम.के. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, सिरसा 09896796006)
24. डॉ० मधुकान्त, (वरिष्ठ साहित्यकार) 211-L मॉडल टाऊन, रोहतक
25. डॉ० कंचन पुरी, विभागध्यक्ष, रघुनाथ गर्ल्स पी० जी० कालेज मेरठ
26. डॉ० प्रवेश कुमारी, सहायक प्रो० हिन्दी बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर रोहतक
27. डॉ० राजपाल, सहायक प्रो० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार
28. डॉ० प्रवेश कुमारी, सहायक प्रो० टिकाराम कन्या कॉलेज, सोनीपत, हरियाणा
29. प्रो. प्रणव शास्त्री, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत - 262 001 उ. प्र. मो. 98379 60530 drpranav&pbt23@rediffmail-com
30. प्रो. राखी उपाध्याय, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष - हिन्दी विभाग, डी. ए .वी. कॉलेज, देहरादून - 248 001 (उत्तराखण्ड) मो. 94111 90099 drrakhi-418@gmail-com
31. डॉ० सुनीता जसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर - हिन्दी विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (हिमाचल प्रदेश) मो.70186 21542

अंग्रेजी विभाग:

1. डॉ. ममता सिंहल, अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर, उ.प्र.
2. डॉ. रणदीप राणा, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
3. डॉ. जयवीर सिंह हुड्डा, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
4. डॉ० रविन्द्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, चौ० चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
5. डॉ. अनिल वर्मा (पूर्व रीडर, अंग्रेजी विभाग, जे.वी. जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सहारनपुर)

6. डॉ० जे. के. शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक
8. डॉ. पी.के. शर्मा, (प्रो., अंग्रेजी-विभाग, राजकीय के.आर.जी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर)
9. डॉ. गीता रानी शर्मा, (सहायक प्रोफेसर) गो.ग.दत्त सनातन धर्म कॉलेज, पलवल
10. डॉ. किरण शर्मा, (एसोसिएट प्रोफेसर) राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक
11. डॉ० राजाराम, सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी) ओम स्ट्रुलिंग ग्लोबल, विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)

वाणिज्य विभाग:

1. डॉ० नवीन कुमार गर्ग (वाणिज्य विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० ए.के. जैन, पूर्व रीडर (वाणिज्य विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर)
3. डॉ० दिनेश जून, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फरीदाबाद
4. डॉ० एम.एल. गुप्ता, (पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन संकाय, एस.एस.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़ एवं संयोजक-शोध उपाधि समिति एवं संयोजक बोर्ड ऑफ स्टीडिज चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)
5. डॉ० वजीर सिंह नेहरा, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, म.द.वि. रोहतक
6. डॉ० संजीव कुमार, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, म.द.वि. रोहतक
7. डॉ. गीता गुप्ता, (सहायक प्रोफेसर) वाणिज्य विभाग, वैश्य महिला महाविद्यालय, रोहतक)
7. डॉ. नरेन्द्रपाल सिंह, (एसोसिएट प्रोफेसर) वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, उ.प्र.)

राजनीति शास्त्र विभाग:

1. साकेत सिसोदिया, (राजनीति शास्त्र विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद)
2. डॉ० रोचना मित्तल (रीडर एवं अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र-विभाग, शम्भु दयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
3. डॉ० कौशल गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, देशबन्धु महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली Mob.: 09810938437
4. डॉ०पी.के. वार्ष्णेय, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, जे.वी.जैन कॉलेज, सहारनपुर
5. डॉ० सुदीप कुमार, सहायक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, पेहवा (कुरुक्षेत्र) Mob.: 9416293686
6. डॉ० वाई०आर० शर्मा, एसो० प्रो०, राजनीति शास्त्र विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (कश्मीर)
7. डॉ. रेनु राणा, (सहायक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, पं. नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक 124001
8. डॉ. ममता देवी, (सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक शास्त्र विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

इतिहास विभाग:

1. डॉ० भूकन सिंह (प्रवक्ता, इतिहास विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० मनीष सिन्हा, पी.जी. विभाग, इतिहास, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार-824231
3. डॉ० राजीव जून, सहायक प्रो० इतिहास, सी.आर. इन्स्टीट्यूट ऑफ ला, रोहतक
4. डॉ० मीनाक्षी (सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग) सी.आर. किसान कॉलेज, जीन्द

भूगोल विभाग:

1. डॉ० पी.के. शर्मा, पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, भूगोल विभाग, जे.वी. जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सहारनपुर
2. रश्मि गोयल (भूगोल विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद)
3. डॉ० भूपेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजकीय पी.जी. कॉलेज, हिसार
4. डॉ० विनीत बाला, सहायक प्रो. भूगोल विभाग, वैश्य पी.जी. कॉलेज, रोहतक
5. डॉ० प्रदीप कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहरा, रोहतक

शिक्षा विभाग:

1. डॉ० उमेन्द्र मलिक, एसिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.द.वि. रोहतक
2. डॉ० संदीप कुमार, सहायक प्रो० शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली/एसोसिएट
3. डॉ० तपन कुमार बसन्तिया, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया कैम्पा, विनोभा नगर, बार्ड नं. 29, Behind ANMCH मगध कालोनी, गया-823001 बिहार Mob.: 09435724964
4. डॉ० (प्रो०) अनामिका शर्मा, प्राचार्या, एम.आर. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरीदाबाद
5. डॉ० मनोज रानी, सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी) एम.एल.आर.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चरखी दादरी (भिवानी)
6. डॉ० अनीता ढाका, (प्राचार्या, आर.जी.सी.ई. कॉलेज, ग्रेटर, नोएडा।)
7. डॉ० ममता देवी, (सहा. प्रो. बी.आई.एम.टी. कॉलेज कमालपुर गढ़ रोड़, मेरठ)

गृह विज्ञान

1. डॉ० श्रीमती पंकज शर्मा, (सहायक प्राफेसर), गृह विज्ञान (प्रसार शिक्षा) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रोहतक

शारीरिक शिक्षा विभाग:

1. डॉ० सरिता चौधरी, सहायक प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग, आर्य गर्ल्स कॉलेज, अम्बाला कैंट, हरियाणा
2. डॉ० वरुण मलिक, सहायक प्रोफेसर, म.द.वि., रोहतक
3. डॉ० सुनील डबास, (पद्मश्री व द्रोणाचार्य अवार्ड) HOD in physical education "DGC Gurugram

समाज शास्त्र विभाग:

1. प्रवीण कुमार (समाजशास्त्र विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० कमलेश भारद्वाज, समाज शास्त्र विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद

मनोविज्ञान विभाग:

1. डॉ० चन्द्रशेखर, सहायक प्रोफेसर साइकलोजी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
2. डॉ. रश्मि रावत, (मनोविज्ञान विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, देहरादून)
3. अनिल कुमार लाल (प्रवक्ता, मनोविज्ञान विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)

अर्थशास्त्र विभाग:

1. डॉ० जसवीर सिंह (पूर्व रीडर अर्थशास्त्र विभाग, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मवाना)
2. डॉ० सुशील कुमार (एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद, उ०प्र०)
3. डॉ० अखिलेश मिश्रा (प्राध्यापक, अर्थशास्त्र-विभाग, एस.डी.पी. जी. कॉलेज, गाजियाबाद)
4. डॉ० सत्यवीर सिंह सैनी, एसो०प्रो० (अर्थ०वि०, गो०ग० सनातन धर्म पी०जी० कॉलेज, पलवल)

विधि विभाग:

1. डॉ० नरेश कुमार, (प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
2. डॉ० विमल जोशी, (प्रोफेसर, विधि-विभाग भगत फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर, सोनीपत)
3. डॉ० जसवन्त सैनी, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
4. डॉ० वेदपाल देशवाल, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
5. डॉ. अशोक कुमार शर्मा, एसो. प्रोफेसर, विधि विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर
6. डॉ. राजेश हुड्डा, सहायक प्रो०, विधि विभाग, बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत
7. डॉ० सत्यपाल सिंह, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
8. डॉ० सोनू, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
9. डॉ० अर्चना वशिष्ठ, (सहायक प्रोफेसर, के०आर० मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुरुग्राम)
10. डॉ० आनन्द सिंह देशवाल, (सहायक प्रोफेसर, सी०आर० कॉलेज ऑफ लॉ रोहतक)
11. अनसुईया यादव, (सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा)

गणित विभाग:

1. डॉ० विनोद कुमार, रीडर एवं अध्यक्ष गणित विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर
2. डॉ० विरेश शर्मा, लेक्चरर गणित विभाग, एन.ए.एस. कॉलेज, मेरठ
3. डॉ० सलौनी श्रीवास्तव सहायक प्रो०, गणित विभाग आर० बी० एस० कालेज आगरा
4. Dr. Dhruv Kumar Singh.HOD, Department of Mathematics, YBN University, Rajaulatu, Namkum, Ranchi, Jharkhand, India. Pin-834010
5. डॉ० रश्मि मिश्रा प्रोफेसर (एप्लाइड साइंस एंड हमनीटीएस), मैथमेटिक्स गनेशी लाल बजाज इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नॉएडा

कम्प्यूटर विभाग:

1. प्रो० एस.एस. भाटिया (अध्यक्ष, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन, थापर विवि, पटियाला)
2. सर्वजीत सिंह भाटिया (प्रवक्ता, कम्प्यूटर साईंस, खालसा कॉलेज, पटियाला)
3. डॉ० बालकिशन सिंहल, सहायक प्रोफेसर, कम्प्यूटर विभाग, म०द०विश्वविद्यालय, रोहतक

संस्कृत विभाग:

1. डॉ० रामकरण भारद्वाज पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, लाजपत राय कॉलेज, साहिबाबाद (गाजियाबाद)
2. डॉ० सुनीता सैनी, एस० प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
3. डॉ० सुमन, (सहायक प्रोफेसर, संस्कृत-विभाग, आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी।)
4. डॉ० दिनेश मणि त्रिपाठी [प्रधानाचार्य] एल०पी०के० इंटर कॉलेज सरदार नगर बसडिला (गोरखपुर)
5. डॉ० दानपति तिवारी, प्रोफेसर, एवं अध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापिठ, वाराणसी, उत्तर-प्रदेश
6. डॉ० दिनेशचन्द्र शुक्ल, सहायक प्रोफेसर, महात्मा गांधी काशी विद्यापिठ, वाराणसी, उत्तर-प्रदेश

रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग:

1. डॉ० आर०एस० सिवाच, प्रो० एवं अध्यक्ष, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, म०द०वि०, रोहतक

दृश्यकला विभाग:

1. डॉ० सुषमा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दृश्यकला विभाग, म०द० विश्वविद्यालय, रोहतक

पंजाबी विभाग:

1. डॉ० सिमरजीत कौर, सहायक प्रो० (पंजाबी), ईश्वरजोत डिग्री कालेज, पेहवा (कुरुक्षेत्र)

संगीत विभाग:

1. डॉ० संध्या रानी, अध्यक्षा, संगीत विभाग, यूआरएलए, राजकीय पीजी कॉलेज, बरेली
2. डॉ० हुकमचन्द, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष तथा डीन, संगीत विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
3. डॉ० अनीता शर्मा, (संगीत-गायन प्राध्यापिका, जयराम महिला महाविद्यालय लोहारमाजरा (कुरुक्षेत्र)
4. डॉ० वन्दना जोशी, (सहायक प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग, एस.एस.जे. परिसर, अल्मोड़ा)

पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग:

1. डॉ० सरोजनी नंदल, प्रोफेसर (पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

उर्दू विभाग:

1. डॉ० मो. नूरुल हक, (एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, उर्दू, बरेली कॉलेज, बरेली)

कृषि विभाग

1. डॉ० गोविन्द प्रकाश आचार्य सह-आचार्य (कृषि-प्रसार) श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा राजस्थान मो. 9460545836

An update on UGC - List Journals

The UGC List of Journals is a dynamic list which is revised periodically. Initially the list contained only journals included in Scopus, Web of Science and Indian Citation Index. The list was expanded to include recommendations from the academic community. The UGC portal was opened twice in 2017 to universities to upload their recommendations based on filtering criteria available at <https://www.ugc.ac.in/journallist/methodology.pdf>. The UGC approved list of Journals is considered for recruitment, promotion and career advancement not only in universities and colleges but also other institutions of higher education in India. As such, it is the responsibility of UGC to curate its list of approved journals and to ensure that it contains only high-quality journals.

To this end, the Standing Committee on Notification on Journals removed many poor quality/predatory/questionable journals from the list between 25th May 2017 and 19th September 2017. This is an ongoing process and since then the Committee has screened all the journals recommended by universities and also those listed in the ICI, which were re-evaluated and rescored on filtering criteria defined by the Standing Committee. Based on careful analysis, 4,305 journals were removed from the current UGC-Approved list of Journals on 2nd May, 2018 because of poor quality/incorrect or insufficient information/false claims.

The Standing Committee reiterates that removal/non-inclusion of a journal does not necessarily indicate that it is of poor quality, but it may also be due to non-availability of information such as details of editorial board, indexing information, year of its commencement, frequency and regularity of its publication schedule, etc. It may be noted that a dedicated web site for journals is one of the primary criteria for inclusion of journals. The websites should provide full postal addresses, e-mail addresses of chief editor and editors, and at least some of these addresses ought to be verifiable official addresses. Some of the established journals recommended by universities that did not have dedicated websites, or websites that have not been updated, might have been dropped from the approved list as of now. However, they may be considered for re-inclusion once they fulfil these basic criteria and are re-recommended by universities.

The UGC's Standing Committee on Notification on Journals has also decided that the recommendation portal will be opened once every year for universities to recommend journals. However, from this year onwards, every recommendation submitted by the universities will be reviewed under the supervision of Standing Committee on Notification of Journals to ascertain that only good-quality journals, with correct publication details, are included in the UGC approved list.

The UGC would also like to clarify that 4,305 journals which have been removed on 2nd May, 2018 were UGC-approved journals till that date and, as such, articles published/accepted in them prior to 2nd May 2018 by applicants for recruitment/promotion may be considered and given points accordingly by universities.

The academic community will appreciate that in its endeavour to curate its list of approved journals, UGC will enrich it with high-quality, peer-reviewed journals. Such a dynamic list is to the benefit of all.

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ स.
1.	जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध व्यवसाय का अरविन्द कुमार	भौगोलिक अध्ययन	10-13
2.	जनपद हरदोई में जल संसाधनों की उपलब्धता एवं उपयोगिता का भौगोलिक विश्लेषण डॉ० एन० यू० खान, अषफाक अहमद		14-19
3.	विपणन भूगोल का एकीकरण: एक व्यवहारिक अध्ययन डॉ० नाज़िया खान, डॉ० ए० सी० त्रिपाठी		20-23
4.	जनपद शाहजहाँपुर में कृषि विकास एवं नियोजन का भौगोलिक अध्ययन डॉ० एन० यू० खान, नवीन जायसवाल		24-28
5.	भारत में विपणन भूगोल के विकास का अध्ययन डॉ० नाज़िया खान, डॉ० ए० सी० त्रिपाठी		29-31
6.	जनपद पीलीभीत में कृषि विकास पर सिंचाई का प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन डॉ० एन० यू० खान, रामकान्त		32-36
7.	जनकवि रमाशंकर 'विद्रोही' की क्रांतिधर्मी चेतना सुरेंद्र प्रसाद 'सुमन', जितेन्द्र नाथ 'ललन'		37-39
8.	ONE NATION ONE ELECTION: DOES INDIA NEED IT? Ajit Singh		40-43
9.	भारत आंतरिक वबाह्य सुरक्षा चुनौतियां डॉ० एम.एस.मांजू		44-49
10.	विद्यानिवास मिश्र और युगीन परिस्थितियों का समग्र अध्ययन डॉ० अनीता		50-53
11.	मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानियों में नारी जीवन ममता यादव		54-56
12.	सुदामा पांडे 'धूमिल' की कविताओं में जनतंत्र डॉ० सुनील कुमार		57-59
13.	नारी शक्ति बंदन अधिनियम—एक ऐतिहासिक फैसला डॉ० रेणुका पोद्दार		60-62
14.	धर्म एवं अमृतलाल नागर समीक्षा मिश्र		63-68
15.	"सरदार पटेल और महिला सशक्तिकरण" गीता कुमारी		69-70
16.	'आषाढ का एक दिन' नाटक में मल्लिका की अंतिम परिणति स्निग्ध सिंह		71-72
17.	भाषा और संस्कृति डॉ० नीवा शर्मा		73-75
18.	हिंदी उपन्यास और स्वाधीनता आंदोलन डॉ० अनिल कुमारी		76-78
19.	स्वदेशी पर "महात्मा गांधी" के विचार Sh. Takdeer Singh		79-81
20.	नारी मन के अंतर्द्वंद्व और उसकी नई वैचारिकी (मुद्राराक्षस के कहानी—साहित्य के परिप्रेक्ष्य में) चंचल, डॉ. कुलभूषण शर्मा		82-85
21.	जलते हुए गांव में गुजरती रेणु की लेखन कला मणिक पंडा		86-90
22.	'महाभोज' उपन्यास में राजनीतिक समस्याएँ पिकी देवी		91-93
23.	तेजेन्द्र शर्मा की कहानियों में पश्चिमी और भारतीय संस्कृति का समन्वय अंजली		94-96
24.	विजय संदेश की कहानियों में संवेदना एवं शिल्प डॉ० दिनेश श्रीवास		97-100
25.	माली : राजनीति और मानव—व्यवहार में ढहते मानव—मूल्य डॉ० विजय कुमार संदेश		101-103

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ स.
26.	विनोबा भावे की मानवतावादी दृष्टि अनिमा तिग्गा		104-106
27.	रेवाड़ी जिले में भूमि जोत की धारणाएं एवं विखंडन के कारण डॉ० दीपा, अंजु		107-110
28.	राज्य का सामाजिक दायित्व स्त्रियों के सन्दर्भ में डॉ० हिमांशु कुमार		111-112
29.	आदर्श शिक्षक के पर्यायरूप सर्व पल्ली राधाकृष्णन (5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर विशेष) डॉ० जंग बहादुर पाण्डेय 'तारेश'		113-114
30.	या देवी सर्वभूतेषु चामुंडा रूपेण संस्थिता डॉ० तारामणि पाण्डेय		115-116
31.	जनपद बरेली में मृदा संसाधन का कृषि विकास पर प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन डॉ० एन० यू० खान, पंचम सिंह		117-120
32.	'मनरेगा योजना का आर्थिक सशक्तिकरण में सकारात्मक प्रभाव (बोकारो जिले के नावाडीह प्रखण्ड के संदर्भ में) रूपलाल महतो		121-124
33.	शील कौशिक के साहित्य में पुरुष मनोविज्ञान हितेश कुमारी, डॉ० प्रवेश कुमारी		125-126
34.	प्रेमचन्द के समकालीन उपन्यासकारों की प्रेम धारणा चन्द्रमणि किशोर		127-131
35.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला सशक्तिकरण का एक प्रयास डॉ० बबीता, पुनम		132-137
36.	शिक्षा — संस्कार डॉ० (श्रीमती) राजेश गिल		138-140
37.	Review of Social Sector Expenditures of States at Aggregate Level in India Dr. Manju Dalal		141-145
38.	Embracing Post-Human Intelligence: Rethinking Education in the Era of Artificial Intelligence and Warfare Technology Niketa Malik		146-150
39.	Importance of Educating Girl Child in the Society Dr. Shibu V Raju		151-153
40.	Breaking Boundaries: Exploring Female Spaces and Patriarchy in Mahesh Dattani's <i>Final Solutions</i> Niketa Malik		154-157
41.	Dyslexia-A Reading Disability Dr. Meena, Mrs. Priya Mittal		158-160
42.	"NEP, 2020: A POWERFUL TOOL TO ESTABLISH INDIA AS GLOBAL LEADER" Dr. Suresh Kumar		161-165
43.	A Descriptive study on Need of Emotional Maturity Among Youths in Modern Era Dr Vandana Sharon Singh, Mr Pradeep Kumar Kashyap		166-168
44.	Domestic Violence In India: A Review of Present Scenario Dr. Madhusudan		169-173
45.	ENDORSE GREEN ENERGY- NEED OF THE HOUR Dr. Amita Dhaaka		174-176

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ स.
46.	Analysis Of Dividend Payout of Indian Automobile Industry. A Study On Nse Listed Companies.	Renu Dahiya	177-182
47.	Foreign Direct Investment: An Overview	Dr. Anita Gupta	183-187
48.	Discourse: A perspective to understand power dynamics of a society	Aarti Tomar	188-191
49.	The Intrinsic Relation Of Rule of Law & Human Rights	Dr. Santosh Kumar Sharma	192-193
50.	Nature In William Wordsworth's Imagination: A Study Of "an Evening Walk" And "descriptive Sketches"	Ghanshyam Kumar	194-198
51.	संगीत में नाद तत्त्व डॉ० रुचि गर्ग		199-201
52.	संताली भाषा एवं इनकी विशिष्ट ध्वनियाँ शम्भुनाथ सोरेन		202-204

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ स.
------	------	------	----------



सारांश

सम्पूर्ण विश्व में भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। ग्रामीण परिवारों के विशाल बहुमत को लाभकारी रोजगार प्रदान करता है। यह सालाना आधार पर लगभग 8.47 मिलियन लोगों को रोजगार देता है जिसमें से 71 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार 26° 46' उत्तरी अक्षांश से 27° 43' एवं देशान्तरीय विस्तार 79° 7' पूर्वी देशान्तर से 80° 2' तक है। सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 2181 वर्ग किलोमीटर है। अध्ययन क्षेत्र समान ऊपजाऊ भू-भाग है जिसके कारण कृषि एवं पशु पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कुल पशुधन की संख्या 5.50 लाख है जिसमें गौवंशीय पशुधन 1.10 लाख, महिषवंशीय पशुधन 2.95 लाख एवं अजातवंशीय पशुधन 1.43 लाख है। कुल दुग्ध उत्पादन 100550 मीटरी टन है जिसमें गाय से प्राप्त दुग्ध उत्पादन 30725 मीटरी टन, भैंसे से प्राप्त दुग्ध उत्पादन 67385 मीटरी टन एवं बकरी से प्राप्त दुग्ध उत्पादन 2440 मीटरी टन है। अध्ययन क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय के समक्ष अनेक समस्याएँ व्याप्त हैं जिनका प्रबन्धन आवश्यक है।

भूमिका:

दुग्ध व्यवसाय भारत में सबसे बड़ा कृषि व्यवसायों में से एक है और भारतीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। भारत 2019-2020 में 188 मिलियन मीट्रिक के साथ विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक प्रमुख कारक निजी डेयरी उद्यमों का प्रसार है जो अब देश में 60 प्रतिशत से अधिक डेयरी प्रसंस्करण क्षमता के लिए जिम्मेदार है। डेयरी एक मात्र कृषि उत्पाद है जिसमें लगभग 70-80 प्रतिशत अन्तिम बाजार मूल्य किसानों के साथ साझा किया जाता है। विश्व में भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत 1998 से दुनिया भर में डेयरी उत्पादों का प्रमुख उत्पादक एवं उपभोक्ता है। हाल के वर्षों में हाल के वर्षों में भारत में दूध और दुग्ध उत्पादक उद्योग में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आई0 एस0 ए0 आर0 सी0 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेयरी उद्योग 2019 में आई0 एन0 आर0 10527 बिलियन के मूल्य पर पहुँच गया। आगे देखते हुए बाजार 2025 तक आई0 एन0 आर0 25491 बिलियन के मूल्य तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत में कुल दूध उत्पादन के पशुपालन और डेयरी विभाग के अनुसार 48 प्रतिशत दूध का उत्पादन निर्माता स्तर पर किया जाता है या मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-उत्पादकों को बेचा जाता है। शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विक्री के लिए अधिशेष का शेष 52 प्रतिशत उपलब्ध है। इस 52 प्रतिशत में से यह अनुमान लगाया जाता है कि बेचे जाने वाले दूध का लगभग 40 प्रतिशत संगठित क्षेत्र जैसे सहकारी समितियों और निजी डेयरियों और शेष 60 प्रतिशत

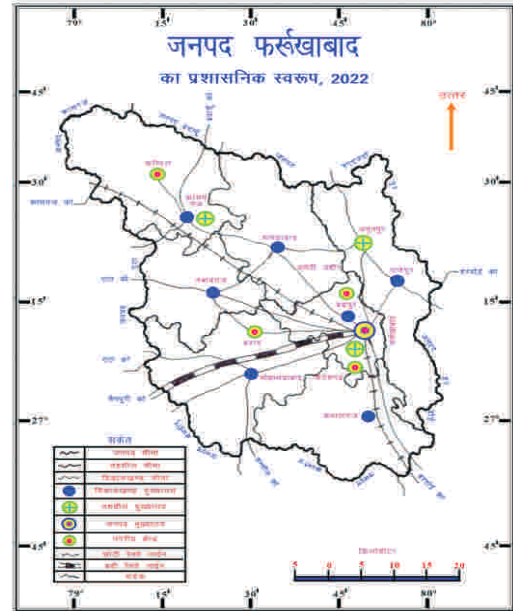
असंगठित क्षेत्र द्वारा संभाला जाता है।

अध्ययन क्षेत्र:

प्रस्तुत शोध-पत्र का अध्ययन क्षेत्र जनपद फर्रुखाबाद है जो गंगा के मैदान में स्थित है। इसका इसका अक्षांशीय विस्तार 26° 46' उत्तरी अक्षांश से 27° 43' एवं देशान्तरीय विस्तार 79° 7' पूर्वी देशान्तर से 80° 2' तक विस्तृत है। सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 2181 वर्ग किलोमीटर है। जनपद फर्रुखाबाद का उत्तरी सीमा पर बदायूँ एवं शाहजहाँपुर जनपद तथा दक्षिण में जनपद कन्नौज, पूर्व में हरदोई जनपद और पश्चिम में जनपद एटा एवं मैनपुरी का विस्तार है।

प्रशासनिक दृष्टि से 01 जनपद मुख्यालय, (फतेहगढ़), 03 तहसील मुख्यालय (कायमगंज, अमृतपुर एवं फर्रुखाबाद), 07 विकासखण्ड, 87. न्याय पंचायत, 600 ग्राम पंचायत एवं 1007 कुल राजस्व ग्राम है। स्थानीय प्रशासन एवं निकायों को दृष्टि से 02 नगर पालिका परिषद, 01 छावनी क्षेत्र एवं 04 नगर पंचायत स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 18.85 लाख व्यक्ति है जिसमें 10.06 लाख पुरुष एवं 8.78 लाख स्त्रियाँ सम्मिलित हैं।

जनपद फर्रुखाबाद का इतिहास बहुत ही दूरस्थ प्राचीनकाल का है। कांस्य युग के दौरान कई पूर्व ऐतिहासिक हथियार और उपकरण यहाँ मिले थे। महाभारत युद्ध के अन्त तक प्राचीनकाल से जनपद का पारंपरिक इतिहास पुराणों और महाभारत से प्राप्त होता है।



शोध पारकल्पना:

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में निम्न परिकल्पनाएँ उभरकर सामने आती हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:—

1. अध्ययन क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में आय का मुख्य साधन

है जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक है।

- अध्ययन क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त कार्य के रूप में विद्यमान है। दूध पोषण प्राप्ति का प्रमुख एवं सस्ता साधन है।
- अध्ययन क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय के लिए यहाँ पर समस्त भौगोलिक दशायें अनुकूल है।
- अध्ययन क्षेत्र में पशुधन उच्च कोटि के नहीं है जिससे दुग्ध उत्पादकता की मात्रा कम है।
- अध्ययन क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय असंगठित क्षेत्र में है जिससे दूध एवं दुग्ध से निर्मित पदार्थों की कीमत पशु पालकों को प्राप्त नहीं हो पाती है।

प्राकृतिक दशायें:

प्रकृति से इस जनपद को मैदानी उच्चावचन का वरदान प्राप्त है जहाँ पर उर्वर दोमट मृदा और पर्याप्त मात्रा में धरातलीय तथा भूमिगत जल की मात्रा उपलब्ध है। भूवैज्ञानिक संरचना के दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र गांगेय मैदान की कांप मृदा से निर्मित भू-भाग है। यहाँ पर गंगा, रामगंगा एवं काली नदियाँ प्रवाहित होती है। शुष्क मानसूनी जलवायु से युक्त इस क्षेत्र का औसत तापमान 25.50 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा 85-90 सेन्टीमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता 75 प्रतिशत एवं औसत वायुगति 5.50 किलोमीटर प्रति घन्टा है। मानसूनी पतझड़ी वृक्षों से युक्त वन भूमि 2506 हेक्टेयर है, जहाँ वृक्षों के अतिरिक्त झाड़, झाड़ियाँ, पंटेरी, कांस व दाव प्रकार की लम्बी घासें उगती हैं। नदियों के समीपवर्ती क्षेत्र में वन्य जीवों के झुण्ड दिखलाई पड़ते हैं।

आर्थिक दशायें:

जनपद फर्रुखाबाद की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि एवं पशुपालन है जिसमें कार्यशील जनसंख्या का 55 प्रतिशत भाग शामिल है। शुद्ध कृषित भूमि 173.47 हजार हेक्टेयर है। एक से अधिक बार बोई गई भूमि 55 हजार हेक्टेयर एवं सकल कृषित भूमि 228.35 हजार हेक्टेयर है। कृषि गहनता 132 प्रतिशत है। शुद्ध सिंचित भूमि 169 हजार हेक्टेयर एक से अधिक बार सिंचित भूमि 214.29 हजार हेक्टेयर है। सिंचाई गहनता 127 प्रतिशत है। जनपद फर्रुखाबाद में परिवहन साधनों में सड़क एवं रेल मार्ग प्रमुख है। रेल मार्ग की लम्बाई 104 किलोमीटर है जिस पर 19 रेलवे स्टेशन है। पक्की सड़कों की लम्बाई 2444 हेक्टेयर है। बस स्टेशनों की संख्या 16 है। वित्तीय संस्थाओं की संख्या 132 है।

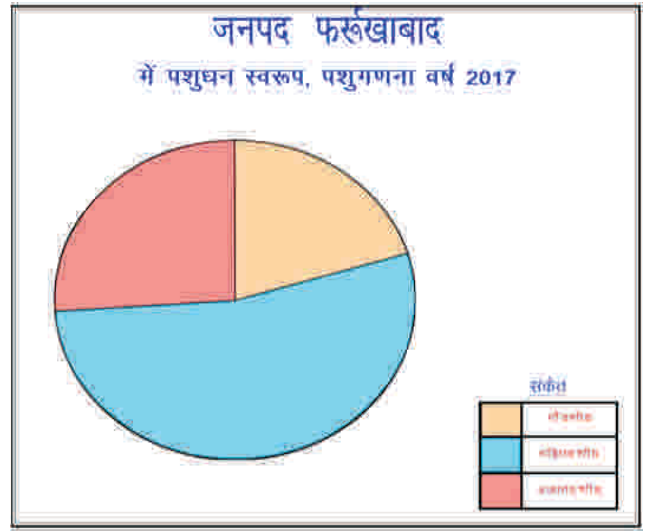
पशुपालन:

जनपद फर्रुखाबाद में पशुगणना वर्ष 2017 के अनुसार 550125 है जिसमें गौवंशीय पशुधन 110950, महिषवंशीय पशुधन 295710 एवं अजातवंशीय पशुधन 143465 है। पशुधन घनत्व 252 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि तालिका- में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 01 जनपद फर्रुखाबाद में पशुधन का क्षेत्रीय वितरण, पशुगणना वर्ष 2017

क्र० सं०	विकासखण्ड	पशुधन			कुल पशुधन	पशुधन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में
		गौवंशीय	महिषवंशीय	अजातवंशीय		
1-	कायमगंज	10705	31275	18705	60685	160
2-	नवाबगंज	10670	33195	18609	62474	258
3-	शमसाबाद	13525	41120	21125	75770	221
4-	राजेपुर	17780	32375	20165	70320	200
5-	बढ़पुर	13800	37365	19762	70927	498
6-	मोहम्मदाबाद	24490	55995	19139	99524	246
7-	कमालगंज	17510	50475	18850	86835	268
योग ग्रामीण		108480	281700	136355	526535	246
नगरीय योग		2470	14010	7110	23590	550
योग जनपद		110950	295710	143465	550125	252

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
जनपद फर्रुखाबाद 2022।



नवंबर 2022 - 01

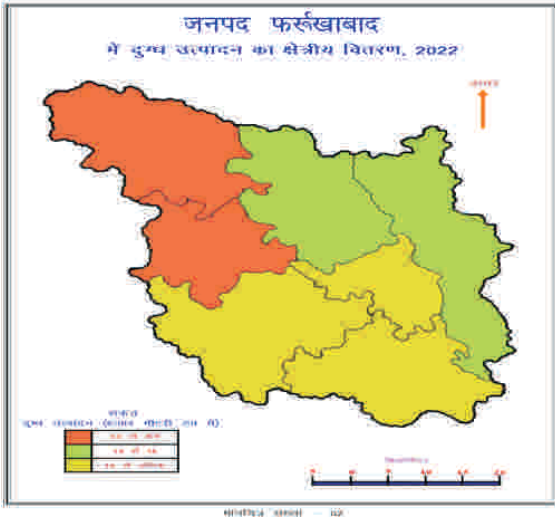
दुग्ध उपलब्धता:

जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध उत्पादन 100550 मीटरीटन है जिसमें गाय से प्राप्त दुग्ध उत्पादन 30725 मीटरी टन, भैंस से प्राप्त दुग्ध उत्पादन 67385 मीटरीटन एवं बकरी से प्राप्त दुग्ध उत्पादन 2440 मीटरी टन है। दुग्ध उपलब्धता 100.50 प्रति व्यक्ति किलोग्राम है। जैसा कि तालिका- में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 02 जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध उत्पादन का क्षेत्रीय वितरण, 2022

क्र० सं०	विकासखण्ड	दुग्ध उत्पादन मीटरी टन में			योग	दुग्ध उपलब्धता किलोग्राम में
		गाय	भैंस	बकरी		
1-	कायमगंज	3550	8545	335	12430	95.75
2-	नवाबगंज	3595	8765	360	12720	90.50
3-	शमसाबाद	3850	9680	355	13885	95.25
4-	राजेपुर	4675	8570	325	13570	90.50
5-	बढ़पुर	4840	9870	290	15000	100.75
6-	मोहम्मदाबाद	5425	11005	395	16825	110.50
7-	कमालगंज	4790	10950	380	16120	105.25
योग जनपद		30725	67385	2440	100550	100.50
प्रतिशत		30.55	67.00	2.45	100.00	-

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं दुग्ध संकलन केन्द्र से प्राप्त सूचना पर आधारित।



श्वेत क्रान्ति एवं दुग्ध उत्पादन:

देश में दूध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में संगठित रूप से पहला क्रान्तिकारी प्रयास वर्ष 1970 से आरम्भ हुआ जिसे हम श्वेत क्रान्ति के नाम से जानते हैं। जनपद फर्रुखाबाद में श्वेत क्रान्ति के विशेष प्रभाव देखने को मिला है। आपरेशन फ्लड योजना प्रथम के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों साथ-साथ लम्बी दूरी के लिए दूध के परिवहन और भण्डारण सुविधाओं का विकास किया गया। जनपद फर्रुखाबाद के विभिन्न विकासखण्डों में सहकारी दुग्ध समितियों की स्थापना का कार्य वृहद स्तर पर किया गया। 1975 में जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध उत्पादन 60 हजार मीटरी टन था। श्वेत क्रान्ति आन्दोलन की इस मुख्य समयावधि में जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि 2015 में हुई जिसमें कुल दुग्ध उत्पादन 88330 मीटरी टन हो गया। जो कि वर्तमान में 100550 मीटरी टन है।

दुग्ध उत्पादकता केन्द्र एवं विपणन समितियाँ:

जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध व्यवसाय का विकास करने हेतु विकासखण्ड स्तर पर दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना की गयी जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों का दूध उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्डवार प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से स्पष्ट है कि यहाँ पर 104 समितियाँ कार्यरत हैं तथा सदस्यों की संख्या 7072 है जैसा कि तालिका- से स्पष्ट है।

तालिका संख्या – 03

जनपद फर्रुखाबाद में प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन समितियों एवं सदस्यों का क्षेत्रीय वितरण, 2022

क्र० सं०	विकासखण्ड	संख्या	सदस्यों की संख्या
1-	कायमगंज	9	13.22
2-	नवाबगंज	8	12.86
3-	शमसाबाद	14	14.17
4-	राजेपुर	14	14.22
5-	बडपुर	18	14.35
6-	मोहम्मदाबाद	21	15.70
7-	कमालगंज	20	15.48
योग जनपद		104	1000

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, जनपद फर्रुखाबाद 2022।

दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के उत्पादक केन्द्र:

पशुओं से प्राप्त दूध मूल रूप से द्रवीय अवस्था में होता है जिससे प्रसंस्करण तथा प्रशोधन की प्रक्रिया द्वारा अन्य दुग्ध पदार्थों का निर्माण किया जाता है। जनपद फर्रुखाबाद में प्रादेशिक सहकारी दुग्ध संघ द्वारा स्थापित दुग्ध पदार्थ विनिर्माण इकाई द्वारा शिशु आहार दुग्ध चूर्ण, घी, मक्खन, सूखा दुग्ध, पाउडर, पनीर तथा मिल्क केक जैसे दुग्ध पदार्थों का निर्माण किया जाता है। इन दुग्ध निर्माण इकाईयों में जनपद फर्रुखाबाद के दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों से विभिन्न ग्रामीण सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से दूध का एकत्रीकरण किया जाता है। दूध को प्रशीतन प्रक्रिया द्वारा, पौलीपेक कर समीपवर्ती नगरीय क्षेत्रों में बिक्री हेतु भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार का टोण्ड तथा यास्युराज्ड दूध तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिशुओं के लिए उपयुक्त पराग दुग्ध पाउडर, पराग देशी घी, पराग मक्खन, तथा पनीर जैसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी समस्यायें:

आज डेयरी व्यवसाय की प्रगति व्यापक स्तर पर महसूस की जाती है। किसान मवेशी पालन करते हैं और दुग्ध व्यवसाय में सहयोग करते हैं। ऐसे तमाम किसान और पशुपालक हैं जो बाजार और दुग्ध व्यवसाय को अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद उचित हक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस तरह से किसान लगातार ठगे हुए महसूस करते हैं और अन्ततः यह व्यवसाय उन्हें लाभ प्रद नहीं लगता और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। उपर्युक्त समस्याओं के अलावा अन्य कई समस्याएं दुग्ध व्यवसाय की रुग्ण बना रही हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. जनपद फर्रुखाबाद में पशुधन में रख-रखाव, आहार पेयजल की समस्या मुख्य है। इसके साथ ही उत्तम नस्ल के पशुधन की संख्या सीमित है।
2. अध्ययन क्षेत्र में पशुधन में रोगग्रस्त की समस्या आम है। इसके साथ ही कृषकों एवं पशुपालकों द्वारा पाले जाने वाले पशुओं में दुर्बल तथा वृद्ध पशुओं की संख्या अपेक्षा से अधिक है।
3. जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध व्यवसाय परम्परागत आधार पर ही किया जा रहा है। आज भी अधिकांश पशुपालक देशी नस्ल के पशुओं को पालते हैं जिनकी दुग्ध उत्पादकता प्रायः कम रहती है।
4. जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध का उत्पादन सामयिक रूप से स्थिर नहीं रहता है अपितु इसके उत्पादन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।
5. जनपद फर्रुखाबाद में पशुधन के विकास में वित्तीय समस्या का संकट सामने आता है। अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के

कारण किसान एवं पशुपालन उत्तम नस्ल के पशुओं को नहीं खरीद पाते हैं।

6. जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध व्यवसाय के विकास में विपणन की समस्या मुख्य है। सहकारी समितियों की संख्या कम है।
7. अध्ययन क्षेत्र में दुग्ध पदार्थों से निर्मित औद्योगिक इकाईयों की संख्या कम है।
8. जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध उत्पादकों द्वारा उत्पादित दूध के परीक्षण, प्रसंस्करण तथा प्रशोधन सम्बन्धी अनेक समस्याएं हैं।
9. जनपद फर्रुखाबाद में आज भी दुग्ध उत्पादकों की संख्या का एक बड़ा भाग सहकारी स्तर पर मिलने वाली दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित है।
10. जनपद फर्रुखाबाद में पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों में जानकारी की कमी विशेष रूप से दिखलाई पड़ती है।

दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी प्रबन्धन:-

जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध व्यवसाय को विकसित करने के लिए किसानों एवं पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने की जरूरत है। दुग्ध व्यवसाय आकर्षण एवं बेहतर बनाने के लिए लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी प्रबन्धन इस प्रकार हैं

1. अध्ययन क्षेत्र में पशुधन के लिए आवास पेयजल एवं उत्तम आहार का प्रबन्धन आवश्यक है।
2. अध्ययन क्षेत्र में दुधारु पशु के लिए स्वच्छता, सकामक रोगों को रोकथाम एवं समय-समय पर पशुओं के रख-रखाव के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
3. अध्ययन क्षेत्र में शुद्ध दूध उत्पादन के लिए दुग्धशाला आधुनिक ढंग से बना होना आवश्यक है।
4. अध्ययन क्षेत्र में दूध को डेयरी फार्म या गाँव से संग्रह केन्द्र तक भेजते समय रास्ते में दूध की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु सभी पर्याप्त सावधानियाँ बरतनी चाहिए।
5. दुग्ध व्यवसाय से सम्बन्धित अनेक योजनायें क्रियान्वित की गई है। जनपद फर्रुखाबाद में अधिकतम दूध उत्पादकता की प्राप्ति के लिए इन योजनाओं का क्रियान्वयन आवश्यक है।
6. जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध व्यवसाय के सफल संचालन के लिए नयी तकनीकी को अपनाने की आवश्यकता है।
7. जनपद फर्रुखाबाद में दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 02 सहकारी समितियों की स्थापना की जानी आवश्यक है।
8. जनपद फर्रुखाबाद में पशुपालक एवं दुग्ध व्यवसायों से जुड़े

व्यक्तियों को दुग्ध अनुसंधान केन्द्रों पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. अध्ययन क्षेत्र में सहकारी स्तर पर संगोष्ठी आयोजित कर दुग्ध व्यवसाय को विकसित करने हेतु जानकारी प्रदान की जानी आवश्यक है।
10. अध्ययन क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय को विकसित एवं गुणवत्ता परक बनाने के लिए उचित प्रबन्धन आवश्यक है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास तीव्र गति से सम्भव हो सकेगा।

सन्दर्भ

1. कौषिक, एस0डी0 2014 :आर्थिक भूगोल के सरल सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन्स मेरठ पृष्ठ-205
2. बेहरा, सुनीता 2014: कृषि सहभागिता का पर्याय डेयरी उद्योग, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका मई अंक पृष्ठ-16
3. कुमार मंयक, 2014 :सहकारी क्षेत्र में बढ़ रहा है दुग्ध व्यवसाय, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, मई अंक पृष्ठ-26
4. नारायण, प्रेम 2021: कृषि आधारित उद्यमिता विकास में आत्मनिर्भरता कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका जनवरी अंक पृष्ठ-26
5. ग्रामीण विकास की सम्भावनाएं, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका जनवरी अंक 2021 पृष्ठ-29
6. कुमार गौरव 2016:भारत में डेयरी उद्योग, सफलताएं और चुनौतियां कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका मार्च अंक पृष्ठ-39
7. मौर्य, सिंह बलवन्त 2016 : खेती जनित कारोबार से जुड़कर बन रहे हैं स्वावलम्बी, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका मार्च अंक पृष्ठ-43
8. चौधरी, आर0 एस0 2005 :पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान पृष्ठ-22
9. जिला विकास पुस्तिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद फर्रुखाबाद 2022
10. जिला सांख्यिकीय पत्रिका अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद फर्रुखाबाद 2022

शोधार्थी

अरविन्द कुमार

जी.एफ. महाविद्यालय

शाहजहाँपुर

(उ.प्र.)

जनपद हरदोई में जल संसाधनों की उपलब्धता एवं उपयोगिता का भौगोलिक विश्लेषण

डॉ० एन० यू० खान, अशाफाक अहमद

सारांश

जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके अभाव में मानव जीवन, जन्तु तथा वातावरण की अनेक क्रियायें असम्भव हैं। जनपद हरदोई का अक्षांशीय विस्तार 26° 53' उत्तरी अक्षांश से 27° 47' तथा देशान्तरिय विस्तार 79° 41' पूर्वी देशान्तर से 80° 49' के मध्य स्थित है तथा भौगोलिक क्षेत्रफल 5989 वर्ग किलोमीटर है। सम्पूर्ण क्षेत्र समान एवं जलवायु मानसूनी है। कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया है। जल संसाधनों की उपलब्धता भूपृष्ठीय एवं अवमृदा जल के रूप में मिलती है। नदियां, नहरें, झीलें एवं तालाब भूपृष्ठीय जल के स्रोत हैं। अवमृदा जल स्तर की गहराई 8.25 मीटर है जो मानसून पूर्व 8.60 मीटर एवं मानसून पश्चात् 7.90 मीटर है। पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक, पशुपालन मत्स्य एवं सामाजिक वानिकी में जल की विशेष उपयोगिता है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, नगरीयकरण के कारण जल संसाधन सम्बन्धी समस्यायें सामने आ रही हैं जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है जिसके लिए जल प्रबन्धन के समुचित उपाय किए जाने चाहिए।

प्रस्तावना:

'जल' एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, जो पृथ्वी की जीवन शक्ति विकास की पोषणीयता, पर्यावरण की धारणीयता और पृथ्वी पर जीवन का पर्याय है। जल संसाधनों की उपलब्धता में स्थिरता और आबादी में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार घट रही है। देश में उपलब्ध कुल धरातलीय और भौम जल संसाधनों की आंकलित मात्रा 1869 घन किलोमीटर है, जिसमें 690 घन किलोमीटर धरातलीय या सतही जल और 432 घन किलोमीटर भौम जल उपयोग करने योग्य है। मौजूदा कुल जल खपत 1050 घन किलोमीटर में से 76 प्रतिशत कृषि कार्यों में 10 प्रतिशत उद्योगों में, 7 प्रतिशत ऊर्जा, 5 प्रतिशत घरेलू और 2 प्रतिशत अन्य कार्यों में प्रयोग हो रहा है। भूजल संसाधनों के अत्यधिक दोहन के फलस्वरूप भूजल स्तर में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती विश्व जनसंख्या पारिस्थितिकी तन्त्र की सुरक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने और भोजन का उत्पादन करने एवं पेयजल की आपूर्ति में मीठे पानी की कमी महसूस हो रही है। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार 69.7 प्रतिशत व्यक्ति नल, 35.7 प्रतिशत हैण्डपम्प, 18.2 प्रतिशत तालाब या झील, 5.6 प्रतिशत कुआं एवं 3.8 प्रतिशत व्यक्ति पानी के लिए अन्य साधनों पर

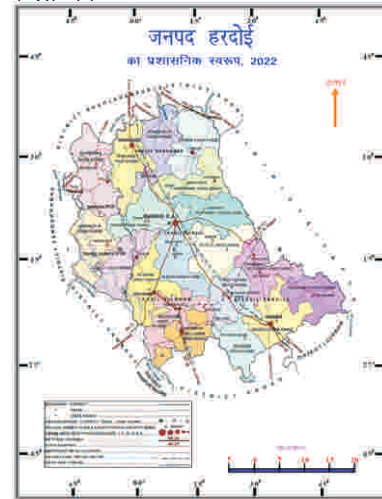
निर्भर हैं। हमारे देश में हर साल 1.80 करोड़ बढ़ती जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना एक चुनौती है। वर्ष 2050 तक 165 करोड़ व्यक्तियों के लिए 1447 अरब घन मीटर जल एवं 45 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न की व्यवस्था करने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं भी से बनानी पड़ेगी।

अध्ययन क्षेत्र:

प्रस्तुत शोध-पत्र का अध्ययन क्षेत्र जनपद हरदोई है जिसका अक्षांशीय विस्तार 26° 53' उत्तरी अक्षांश से 27° 47' एवं देशान्तरिय विस्तार 79° 41' पूर्वी देशान्तर से 80° 49' के मध्य है। सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 5989 वर्ग किलोमीटर है। अध्ययन क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर शाहजहाँपुर एवं लखीमपुर खीरी जनपद, दक्षिणी सीमा पर कानपुर एवं उन्नाव जनपद, पूर्वी सीमा पर सीतापुर एवं लखनऊ जनपद एवं पश्चिमी सीमा पर जनपद फर्रुखाबाद स्थित है।

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद हरदोई में 01 जनपद मुख्यालय हरदोई, 05 तहसीले (हरदोई, शाहाबाद, सवायपुर, सण्डीला, बिलग्राम) 19 विकासखण्ड, 191 न्याय पंचायत, 1306 ग्रामपंचायत एवं कुल राजस्व ग्राम 2070 है। स्थानीय प्रशासन एवं निकायों की दृष्टि से 07 नगरपालिका परिषद एवं 07 नगर पंचायत हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 40.92 लाख व्यक्ति है जिसमें 21.91 लाख पुरुष एवं 19.01 लाख स्त्रियां सम्मिलित हैं।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जनपद हरदोई अवध के सूबे का एक हिस्सा रहा है जिसे कौशलों के नाम से जाना जाता था जनपद हरदोई का नामकरण किदवन्तियों के अनुसार हरदेव बाबा के नाम पर रखा गया जो एक भक्त थे और आज से लगभग साढ़े ग्यारह सौ वर्ष पूर्व यहाँ निवास करते थे।



अध्ययन के उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध-पत्र में क्षेत्रीय स्तर पर जल संसाधनों की उपलब्धता तथा उपयोगिता का तो अध्ययन किया गया है साथ ही क्षेत्र में जल स्रोतों के स्वरूप अवमृदा जल स्तर में परिवर्तन तथा स्थलीय जल के स्थानिक वितरण का भी विस्तृत अध्ययन किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर जल संसाधनों के संरक्षण सम्बन्धी सुझावों तथा उपायों का समावेश भी इस शोध कार्य के मुख्य केन्द्र बिन्दु है। यहीं शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

शोध-परिकल्पना:

प्रस्तुत शोध-पत्र का अध्ययन करते समय निम्न परिकल्पनायें सामने ऊभर कर आई है जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. जनपद हरदोई में एक दर्जन नदियां प्रवाहित होती है जिसमें अधिकांश सतत् वाहिनी है। इनके जल का उपयोग कृषि, पशुपालन एवं उद्योगों में किया जा रहा है।
2. अध्ययन क्षेत्र में पर्याप्त जल उपलब्धता के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में परिवर्तन दिखलाई देता है।
3. जनपद हरदोई में नहरों की लम्बाई 1548 किलोमीटर है किन्तु इनका वितरण असमान है। जल क्षमता भी कम हो रही है।
4. अध्ययन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 90-100 सेन्टीमीटर है, वर्षा अनियमित व अनिश्चित है।
5. तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, उद्योग एवं अन्य व्यवसायों में जल की मांग में वृद्धि के कारण जल संसाधनों पर अनवरत दबाव बढ़ रहा है।

प्राकृतिक दशायें:

जनपद हरदोई का अधिकांश भाग मैदानी है। इसका ढाल उत्तर से दक्षिण को है। अध्ययन क्षेत्र की समुद्र तल से ऊँचाई 150 मीटर है। यहाँ पर परतदार अवसादी चट्टानों का विस्तार है जिनकी गहराई 1000-1500 मीटर है तथा इनका निर्माण गंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा लाये गये हिमालयन अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। ये चट्टानें प्रवेश्य, रन्ध्रयुक्त व मुलायम है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता के कारण यह कृषि प्रधान क्षेत्र है। उत्तरी भागों में चीका, दोमट, जलोढ़, मध्य भागों में 'खादर' तथा दक्षिणी क्षेत्र में दोमट कटेहर तथा उदला व भूड़ मिट्टी देखने की मिलती है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 27.25 डिग्री सेन्टीग्रेड व वार्षिक तापान्तर 15 डिग्री सेन्टीग्रेड है। वार्षिक वर्षा का औसत 95 सेन्टीमीटर है। दक्षिणी भाग की तुलना में उत्तरी क्षेत्रों में औसतन 10 से 15सेन्टीमीटर अधिक वर्षा होती है। वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता यहाँ की प्रमुख समस्या है। लघुशीत काल, लम्बी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में गर्म 'लू' हवाओं का चलना, शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा अन्य मुख्य विशेषताएं हैं। गंगा, रामगंगा, गर्रा, सैंधा सुखेता, गरई, गोराई, गोमती, साई, अटारवन, गरेरा एवं बेहटा यहाँ की प्रमुख नदियाँ व बरसाती नाले हैं। नदियों के समीपवर्ती भागों में वर्षा ऋतु में बाढ़ का प्रकोप बना रहता

है। मानसूनी पतझड़ी प्राकृतिक वनस्पति, वनों का क्षेत्र 2.05 प्रतिशत, सामाजिक व कृषि वानिकी में सड़कों, नहरों, मेढ़ों पर वृक्षारोपण अन्य प्रमुख विशेषतायें हैं।

आर्थिक दशायें:

जनपद हरदोई आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है आज भी यहाँ की प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि एवं पशुपालन ही हैं क्योंकि कुल कार्यशील जनसंख्या का 55 प्रतिशत भाग कृषि व पशुपालन क्षेत्र में ही कार्यरत है। इस प्रकार 6.25 लाख व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र से प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त है। साथ ही 435.31 हजार हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, जो कुल सकल प्रतिवेदित भूमि का 72.70 प्रतिशत भाग है। इस प्रकार जनपद हरदोई कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस तरह दो फसली क्षेत्र का 55.18 प्रतिशत होना तथा 155 प्रतिशत कृषि गहनता सूचकांक का मिलना कृषि क्षेत्र की उत्तम स्थिति का परिचायक है। अध्ययन क्षेत्र में 555.92 हजार हेक्टेयर भूमि पर खाद्यान्न फसलें तथा 45 हजार हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक फसलें उगायी जाती है, जो सकल बोए गए क्षेत्र का क्रमशः 82.30 तथा 6.60 प्रतिशत है।

जनपद हरदोई में कुल पशु सम्पदा 15.92 लाख है। कुल कुक्कुट पालन की संख्या 2.45 लाख है। यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों का विकास तेजी से हुआ है। हरदोई, शाहाबाद, सण्डीला, मल्लावां, पिहानी बिलग्राम एवं साण्डी मुख्य वृहद स्तरीय उद्योगों के मुख्य केन्द्र है। परिवहन साधनों की दृष्टि से यहाँ पर रेल एवं सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। रेल मार्ग की कुल लम्बाई 169 किलोमीटर है। हरदोई मुख्य स्टेशन है। सड़क मार्गों की कुल लम्बाई 4785 किलोमीटर है।

जल संसाधनों की उपलब्धता:

स्थलीय भाग पर जल की उपलब्धता मुख्यतः दो रूपों भूपृष्ठीय एवं अवमृदा जल के रूप में होती है। नदियों, बरसाती नालों, नहरों, तालाबों व झीलों में भूपृष्ठीय जल मिलता है, जबकि भूपृष्ठीय जल वर्षा का जल तथा सिंचाई का जल प्रवेश्य चट्टानों में प्रवेश करके अर्थात् रिचार्ज प्रक्रिया के तहत भूमि के अन्दर कुछ गहराई पर कठोर परतों में स्पंज के समान एकत्रित रहता है जिसको 'अवमृदा जल' कहते हैं जो स्रोतों, कुओं, हैण्डपम्पों, नलकूपों आदि के द्वारा भूपृष्ठ पर आकर मानव उपयोग में आता है। जनपद हरदोई में एक दर्जन से अधिक नदिया बहती है। तालाबों एवं झीलों की संख्या 1120 है जिनके अन्तर्गत 556.80 हेक्टेयर क्षेत्रफल सम्मिलित है। नहरों की लम्बाई 1548 किलोमीटर है। इस प्रकार जनपद हरदोई में भूपृष्ठीय जल स्रोतों की स्थिति सन्तोषप्रद है परन्तु ग्रीष्मकाल में भूपृष्ठीय जल की न्यूनता बनी रहती है।

अवमृदा जल की दृष्टि से जनपद हरदोई अच्छी स्थिति में है किन्तु वर्षा की मात्रा 90-100 सेन्टीमीटर होना, वर्षा की

अनिश्चितता व अनियमितता भूपृष्ठीय जल स्रोतों का सिकुड़ते जाना, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में जल की बढ़ती माँग व तीव्रतर जल दोहन आदि के कारण अवमृदा जल स्तर में 0.50 मीटर तक की गइराई का बढ़ना चिन्तनीय है। सर्वेक्षण के मोटे अनुमान के अनुसार जनपद हरदोई में अवमृदा जल राशि 150 लाख हेक्टोमीटर है, जिसमें प्रतिवर्ष 105 लाख हेक्टोमीटर अवमृदा जल पीने, घरेलू, सिंचाई, औद्योगिक और नगरीय जल आपूर्ति में व्यय हो जाता है, शेष 45 लाख हेक्टोमीटर अवमृदा जल राशि भूगर्भ में बचती है।

जनपद हरदोई में भूगर्भ जल संरक्षण विभाग द्वारा 110 भूगर्भ जल पर्यवेक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है जो वर्ष भर वर्षा की मात्रा, भूजल स्तर की गहराई अवमृदा जल की रिचार्ज गति, जल की उपलब्धता व दोहन की तीव्रता की गणना करते हैं। जनपद हरदोई में अवमृदा जल की औसत गहराई 8.25 मीटर है, जो मानसून पूर्व 8.60 मीटर तथा मानसून के पश्चात् औसतन 7.90 मीटर रहती है। इस प्रकार वर्ष भर अवमृदा जल के स्तर में 0.70 मीटर का अन्तर आ जाता है। यह वार्षिक वर्षा की मात्रा पर भी निर्भर करता है।

यदि अवमृदा जल के स्थानिक वितरण का अध्ययन करें तो सूरसा, अहिरोरी, संडीला एवं भरावन विकास खण्डों में अवमृदा जल स्तर की गहराई 8.15 से 8.30 मीटर के मध्य मिलती है। वहीं दूसरी ओर टडियावां, बिलग्राम विकासखण्डों में अवमृदा जल स्तर की गहराई 7.75 मीटर से कम है। इसके साथ ही भरखनी, शाहाबाद, टोडरपुर, पिहानी, कछौला, बेहन्दर विकासखण्डों में अवमृदा जल स्तर की गहराई 7.75 से 8.15 मीटर के मध्य मिलती है। जैसा कि तालिका- में दर्शाया गया है।

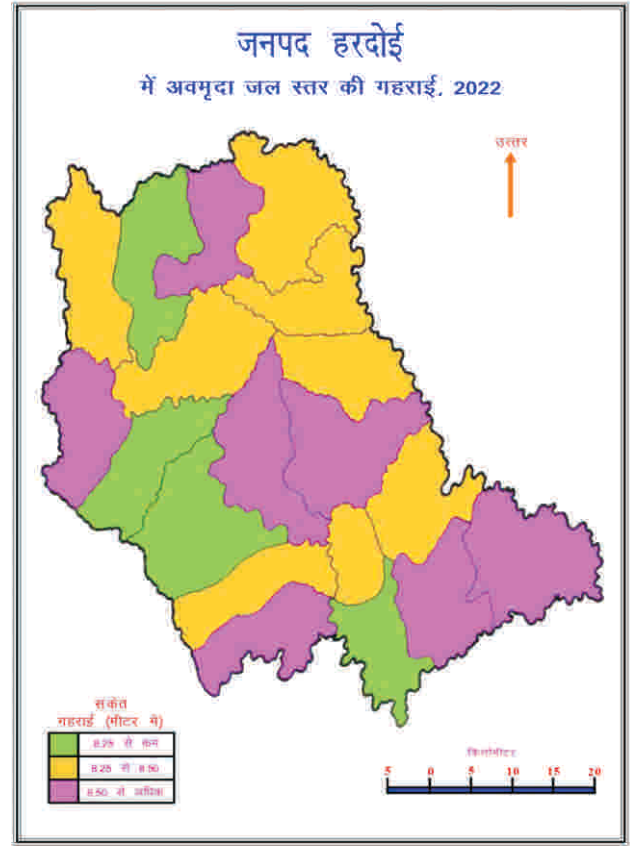
तालिका संख्या – 01

जनपद हरदोई में अवमृदा जल स्तर की गहराई का

वितरण 2022

क्रम सं०	विकासखण्ड	मानसून पूर्व	मानसून पश्चात्	औसत
1-	भरखनी	8.25	7.70	8.00
2-	शाहाबाद	8.10	7.60	7.85
3-	टोडरपुर	8.50	7.55	8.05
4-	पिहानी	8.35	7.45	7.85
5-	बावन	8.40	7.40	7.90
6-	हरियावाँ	8.30	7.25	7.77
7-	टडियावाँ	8.45	7.15	7.65
8-	सूरसा	8.60	7.70	8.15
9-	अहिरोरी	8.70	7.65	8.17
10-	हरपालपुर	8.65	7.60	8.12
11-	सॉडी	8.15	7.55	7.85
12-	बिलग्राम	8.20	7.35	7.77
13-	माधोगंज	8.35	7.40	7.85
14-	मल्लावाँ	8.55	7.50	8.02
15-	कोथावाँ	8.25	7.35	7.80
16-	कछौला	8.30	7.80	8.05
17-	बेहन्दर	8.20	7.85	8.02
18-	संडीला	8.65	7.75	8.20
19-	भरावन	8.70	7.80	8.25
	योग जनपद	8.60	7.90	8.25

- स्रोत: 1. भूगर्भ जल विभाग कार्यालय, जनपद हरदोई से प्राप्त सूचना पर आधारित।
2. स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित।



मानचित्र संख्या - 01

जल संसाधनों की उपयोगिता

जनपद हरदोई में जल का उपयोग पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक, पशुपालन मत्स्य, सामाजिक वानिकी आदि कार्यों में किया जाता है। यहाँ पर कुल 1907 ग्राम है। परिवारों की संख्या 6.38 लाख है। इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प की संख्या 12800, सामान्य परम्परागत हैण्डपम्प की संख्या 81024, ग्रामीण कुए 1400 एवं ओवर हैण्ड टैंक 225 है। जबकि नगरीय क्षेत्र में नलकूपों की संख्या 200, अवर जलाशय संख्या 55, जल धारण क्षमता 85735 किलोमीटर, इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प संख्या 13155 एवं प्रति व्यक्ति दैनिक जल आपूर्ति 5.50 एम0एल0डी0 है। औद्योगिक कार्य हेतु जल का उपयोग भूमिगत जल के द्वारा की जाती है। सिंचाई कार्य हेतु नहरों की लम्बाई 1548 किलोमीटर, राजकीय नलकूप 758, निजी नलकूप 10120, डीजल चालित पम्पिंग सेट्स 92985 एवं अन्य प्रकार के साधन 5179 है। कुल कृषि भूमि का 92.73 प्रतिशत शुद्धसिंचित है। एक से अधिक बार सिंचित भूमि 62.80 प्रतिशत एवं सकल सिंचित भूमि 82.08 प्रतिशत है तथा सिंचाई गहनता 162 प्रतिशत है। जनपद हरदोई में नहरों द्वारा 4.76 प्रतिशत, राजकीय नलकूप द्वारा 0.80 प्रतिशत, निजी नलकूप द्वारा

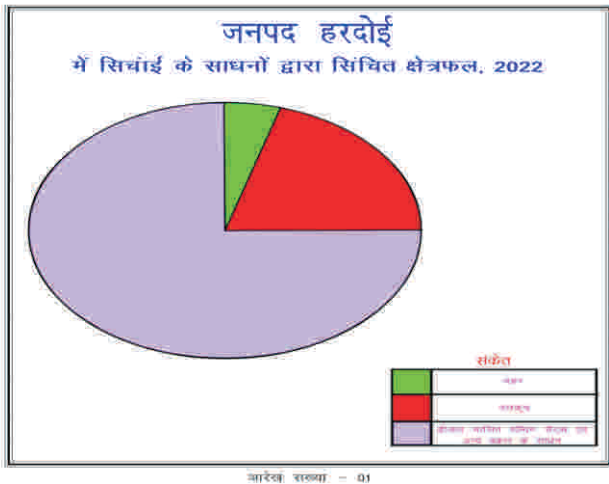
18.82 प्रतिशत, डीजल चालित पम्पिंग सैट्स द्वारा 75.10 प्रतिशत एवं अन्य प्रकार के साधनों द्वारा 0.52 भूमि सिंचित है। जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-02

जनपद हरदोई में सिंचाई के साधन एवं सिंचित क्षेत्रफल 2022

अवमृदा जल स्तर की गहराई (मीटर में)				
क्र० सं०	सिंचाई के साधन	संख्या	सिंचित भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रतिशत में
1.	नहर (किलोमीटर में)	1548	19145	4.76
2.	राजकीय नलकूप	758	3182	6.80
3.	निजी नलकूप	10120	75685	18.82
4.	डीजल चालित पम्पिंग सैट्स	92985	302090	75.10
5.	अन्य प्रकार के साधन	5179	2113	0.52

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद हरदोई 2022।



स्थानीय स्तर पर जल संसाधन सम्बन्धी समस्याएँ:

जनपद हरदोई जल संसाधनों की दृष्टि से विकसित क्षेत्र है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, नगरीकरण, कृषि फसलों में वृद्धि एवं सिंचाई आवृत्ति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप जल की माँग दिनोंदिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण जल आपूर्ति की समस्याएँ सामने आ रही हैं। अध्ययन क्षेत्र में व्याप्त जल संसाधन सम्बन्धी समस्याओं का विवेचन करना आवश्यक है जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. जनपद हरदोई में वर्षा काल में नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे लगभग 225 ग्राम जल प्लावित हो जाते हैं। जल का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण यह व्यर्थ ही रहता है।
2. जनपद हरदोई में जल संसाधन का वितरण क्षेत्रीय एवं सामयिक है। नदियों के समीपवर्ती भागों में भूपृष्ठीय व औद्योगिक जल की

प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, परन्तु नदी खादर से हटकर दूरवर्ती क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल राशि की कमी के साथ-साथ भूमिगत जल का स्तर भी 10-15 मीटर है। ग्रीष्म काल में यह स्थिति और गम्भीर हो जाती है।

3. अध्ययन क्षेत्र में बहने वाली नदियों की गहराई चौड़ाई कम होना, सिल्ट का जमाव, वर्षा की कमी, तालाबों एवं झीलों का सिकुड़ते जाना एवं नहरों में जल की कमी के कारण भूपृष्ठीय जल स्रोतों में कमी आ रही है।
4. जनपद हरदोई का क्षेत्र भी जल प्रदूषण की समस्याओं से ग्रस्त है। मानवीय क्रिया-कलापों के कारण विभिन्न प्रदूषणकारी तत्व जल को प्रदूषित कर रहे हैं।
5. जनपद हरदोई में जुलाई में सितम्बर माह तक नदियों नहरों, तालाबों व झीलों में जल की मात्रा 85 से 100 प्रतिशत रहती है। जबकि इस समय में जल की माँग भी 40-50 प्रतिशत रहती है, विशेषतः कृषि में सिंचाई की माँग बहुत कम रहती है। जबकि इसके विपरीत मार्च से मध्य जून तक जल की माँग तो 95 से 100 प्रतिशत हो जाती है। ऐसी स्थिति में जल की आपूर्ति एवं उपलब्धता जल के अभाव व उच्च तापमान के कारण 20-30 प्रतिशत ही रह जाती है।
6. जनपद हरदोई में निजी नलकूपों व डीजल चालित पम्पिंग सैट्स तथा हैण्डपम्पों व नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में ओवर हैडटकों की संख्या में तीव्रतर वृद्धि, साथ ही औद्योगिक व पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ती जल की माँग ने जल के अति दोहन के कारण अवमृदा जल के स्तर को तेजी से गहरा किया है। परिणामतः रिचार्ज व डिस्चार्ज में अन्तर बढ़ रहा है, जिसमें जनपद हरदोई में 0.50 से 0.75 मीटर भूजल स्तर प्रति वर्ष नीचे जा रहा है, जबकि विगत 10 से 15 वर्षों में जल की माँग 150 प्रतिशत बढ़ी है।
7. घरेलू कार्यों, कृषि व औद्योगिक क्षेत्र तथा पशुपालन कार्यों में आज भी प्राचीन तरीकों व विधियों से जल का प्रयोग किया जाता है जिससे 20 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त जल का दुरुपयोग होता है, जिससे जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
8. जनपद हरदोई में नहरों में जल आपूर्ति की गिरती क्षमता है। कुल नहरों की लम्बाई 1548 किलोमीटर है। जो पर्याप्त है, परन्तु उद्गम बांधों में जल की कमी, जल की सभी क्षेत्रों में बढ़ती माँग, नहरों के रख-रखाव में कमी व सिल्ट के जमाव आदि के कारण नहरों में जल प्रवाह की मात्रा व समय दोनों में ही कमी आई है, फलतः सिंचाई के अन्य साधनों पर अवमृदा

जल के दोहन का दबाव बढ़ रहा है तथा रिचार्ज प्रक्रिया भी धीमी हो रही है जिससे अवमृदा जल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है।

9. आज हमारा जन मानस व सरकारें, विशेषतः युवा पीढ़ी अभी भावी जल संकट के प्रति सचेत नहीं है, जिससे जल संरक्षण व जल संवर्धन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

10. राज्य व केन्द्रीय सरकारों तथा अन्य संस्थाओं ने समय-समय पर जल संरक्षण सम्बन्धी कानून परिनियम तथा अधिनियम बनाये हैं, परन्तु या तो उनमें खामियाँ हैं या सरकारें उनको लागू कराने के प्रति गम्भीर ही नहीं है जिससे आम नागरिक जल संसाधनों सम्बन्धी कानूनों व नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहा है।

स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों की भावी माँग:

जल संसाधनों का उपयोग प्रायः जैविक-अजैविक क्रियाओं में होता है। परन्तु घरेलू, पेयजल, कृषि उत्पाद, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, वृक्षारोपण, मूत्र विर्सजन, साफ-सफाई, परिवहन, उद्योग नगरीय अपशिष्ट बहाव आदि में जल की माँग व उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2025 तक जीवन-स्तर में सुधार प्रक्रिया के चलते प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपयोग की मात्रा 170 लीटर अनुमानित किया गया है। इस आधार पर घरेलू कार्यों में प्रतिदिन जल की माँग 750 हजार किलोमीटर अनुमानित की गई है। पशुपालन क्षेत्र में 170 हजार किलोमीटर की दैनिक माँग होने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 15 हजार मीटर जल की आवश्यकता होगी। सामाजिक वानिकी में 135 हजार किलोमीटर औद्योगिक क्षेत्र में 150 हजार किलोमीटर एवं नगरीय क्षेत्र में अपशिष्ट बहाव हेतु 165 हजार किलोमीटर जल की आवश्यकता होगी।

स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सुझाव:

जल संरक्षण काफी जटिल और चुनौती पूर्ण कार्य है, विशेषकर मानव बहुलता वाले जनपद हरदोई जैसे क्षेत्र में। भविष्य में जल की बढ़ती मांग और भावी जल संकट को नियन्त्रित करने तथा समस्याओं का निराकरण करने हेतु स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निम्नलिखित सुझावों को अमल में लाना आवश्यक है:-

1. जनपद हरदोई में गहरे व कम उपजाऊ क्षेत्रों में नहरों, नदियों व बरसाती नालों के सहारे-सहारे कृत्रिम पक्के जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. अध्ययन क्षेत्र में ऊसर, बंजर, कृषि हेतु अयोग्य भूमि रेलमार्ग नहरों तथा खेतों की मेढों और नदी तटबन्धों पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करके वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि के साथ-साथ जल सम्भरण

की गति को बढ़ाया जा सकता है।

3. अध्ययन क्षेत्र में खेतों को समतल करके उनकी ऊँची मेढबन्दी ढाल के विपरीत जुताई, बड़े भवनों की छतों का वर्षा का जल एकत्र करके हार्वसटिंग प्रणाली का विकास, सिंचाई में स्पिंकलर प्रणाली के अधिकाधिक प्रयोग से न केवल भूपृष्ठीय जल स्रोतों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अपितु अवमृदा जल की रिचार्ज प्रक्रिया में बढ़ोत्तरी सम्भव है।
4. स्थानीय स्तर पर वायु प्रदूषणकारी तत्वों पर नियन्त्रण तथा ग्लोबलवार्मिक की बढ़ती प्रक्रिया को कम करके वाष्पीकरण की गति में वृद्धि के साथ-साथ वर्षा की मात्रा व दिनों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इससे स्थानीय स्तर पर जल की उपलब्धता व अवमृदा जल स्तर ऊँचा उठाने में सहयोग मिलेगा।
5. स्थानीय स्तर पर बहने वाली नदियों पर ऊँचे अवरोधों का निर्माण, बरसाती नालों पर 2 से 4 मीटर ऊँचे एवं 25 से 35 मीटर, लम्बे कच्चे मिट्टी के अवरोधों का निर्माण करके वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है। यह एकत्रित जल सिंचाई कार्य एवं अवमृदा जल स्तर ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध होगा।
6. स्थानीय स्तर पर जल प्रदूषण पर नियन्त्रण हेतु जल ट्रीटमेन्ट लगाकर गन्दे नालों, प्रदूषित, औद्योगिक जल आदि को ट्रीटमेन्ट के उपरान्त नदियों में बहाया जाना चाहिए।
7. कृषि क्षेत्र में सिंचाई का कार्य पक्की गलों द्वारा प्लास्टिक पाइप से खेतों तक जल पहुँचा कर स्पिंकलर प्रणाली द्वारा सिंचाई कार्य कर जल को संरक्षित किया जा सकता है।
8. कृषि क्षेत्र में फसल-चक्र को अपना आवश्यक है तथा कम सिंचाई वाली फसलों को उगाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
9. जल संरक्षण व संवर्धन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व अन्य संस्थाओं द्वारा जन मानस को जागृत करके जल की उपयोगिता व संरक्षण के प्रति चेतना लाई जा सकती है।
10. जल संरक्षण हेतु सरकारों द्वारा कारगर, प्रभावी व कठोर जल नीति का निर्माण व क्रियान्वित किया जाना अति आवश्यक है। ग्रामीण समाज में जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1. कौशिक, एस0डी0 2003: संसाधन भूगोल, रस्तौगी पब्लिकेशन्स मेरठ, पृष्ठ-3
2. गौतम अलका 2010: आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद पृष्ठ-17
3. मधु सूदन सिंह: गाँवों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वैकल्पिक जल संसाधनों की तलाष कुरु क्षेत्र मासिक पत्रिका जून अंक

पृष्ठ-22

4. पाण्डेय, स्मिता एवं द्विवेदी, धीप्रज्ञ 2016: 'भारत में जल संरक्षण प्रम्परा ए' योजना मासिक पत्रिका, जुलाई अंक पृष्ठ-26
5. मुखर्जी सच्चिदानन्द 2016 : 'आर्थिक विकास में जल संसाधन प्रबन्धन' योजना मासिक पत्रिका जुलाई अंक पृष्ठ-12
6. उपाध्याय, देवाषीश 2017 : 'वाटर शेड' से जल संरक्षण एवं जल प्रबन्धन कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका नवम्बर अंक पृष्ठ-50
7. गौतम, कुमार नीरज 2014 : 'जल कृषि : विविध उद्योगों का आधार' कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका मई अंक पृष्ठ-28
8. वीणा श्री निवासन एण्ड षरदचन्द्र लेले 2016 : 'जल सन्तुलन एवं जल प्रबन्धन', पृष्ठ-10
9. जिला सामाजिक-आर्थिक समीक्षात्मक विकास पुस्तिका हरदोई 2022।
10. जिला सांख्यिकीय पत्रिका अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद हरदोई 2022।

निर्देशक

डॉ० एन० यू० खान

पूर्व प्राचार्य

जी०एफ० (पी०जी०) कॉलिज,

शाहजहाँपुर

शोधार्थी

अशफाक अहमद



सारांश

विपणन भूगोल की वर्तमान समय में और दुनिया के किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने के लिए बहुत प्रासंगिकता है। विपणन भूगोल आर्थिक भूगोल के व्यापक क्षेत्र में उभरा है, जिसे भूगोल की एक प्रमाणित शाखा के रूप में माना गया है और 21वीं सदी में बहुत महत्व प्राप्त कर रहा है। यह एक प्रकार का योजना उन्मुख क्षेत्र है और बुनियादी स्तर के मुद्दों से निपटने के लिए विशेष रूप से शिक्षाविदों और सामान्य रूप से नीति निर्माताओं द्वारा आकर्षित किया गया है। परिवहन नेटवर्क के माध्यम से भौगोलिक स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन की प्रक्रिया में शामिल लोगों को आकर्षित करने के लिए बाजार चुंबक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बाजारों को न केवल आर्थिक गतिविधियों से निपटना है बल्कि भौगोलिक स्थान पर स्थानिक संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए, यह भूगोल की कई परस्पर संबंधित शाखाओं को अनुशासन में ही एकीकृत करता है। विशेष रूप से, आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विनिर्माण भूगोल, परिवहन भूगोल, ग्रामीण और शहरी भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल। विपणन गतिविधियों द्वारा प्रभावी संबंध स्थापित किए गए हैं और विपणन भूगोल के संक्षेप के रूप में उभरे हैं। परिणामस्वरूप, बाजार न केवल भीतरी इलाकों से बल्कि भीतरी इलाकों के अलावा अन्य हिस्सों से भी अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रमुख घटक बन गए हैं।

विपणन भूगोल की वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिकता है, मुख्यतः क्योंकि विपणन मानव गतिविधि का एक हिस्सा है और समाज के अस्तित्व और बेहतरी के लिए अपरिहार्य है, इसलिए इसने शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। विपणन प्रक्रिया किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के रूप में एक भौगोलिक कारक है और भूगोल की समन्वित शाखाओं के रूप में कार्य करती है जैसे आर्थिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विनिर्माण भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल, ग्रामीण और शहरी भूगोल और परिवहन भूगोल। इसलिए सभी शाखाओं के आपस में जुड़े होने के कारण विपणन भूगोल का विस्तार हुआ है। बाजार उभरे हैं और भौगोलिक स्थान पर विपणन गतिविधियाँ कर रहे हैं और लोग वितरण के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से बाजार सूक्ष्म से वृहत स्तर तक भिन्न-भिन्न प्रकार का एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र है। इसलिए यह न केवल बिक्री लेन देन बल्कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अवधारणा

मार्केट शब्द लैटिन शब्द मर्केटस से लिया गया है जिसका अर्थ है खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संपर्क का स्थान या तरीका। विलियम एप्पलबाउम को व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन के क्षेत्र के रूप में विपणन भूगोल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। विलियम एप्पलबाम विपणन भूगोल को परिभाषित करते हैं जिन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से विपणन भूगोल में समर्पित कार्य किया है और इसे विपणन के प्रदूषण और माप के साथ-साथ वितरण के चौराहों से संबंधित ज्ञान की शाखा के रूप में बनाया है जिसके माध्यम से माल आगे बढ़ता है। एबॉट ने कहा कि विपणन में उत्पादन से उपभोग तक वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में शामिल सभी गतिविधियाँ शामिल हैं। होडर ने बाजार को नियमित रूप से एक अनुमोदित स्थान पर वस्तुओं के खरीदारों और विक्रेताओं की बैठक के रूप में वर्णित किया है। अंतराल बेरी परिभाषित करते हैं कि विपणन भूगोल ने भूगोलवेत्ताओं की खुदरा रुचि को निजी व्यावसायिक उद्यमों की सेवा में महानगरीय क्षेत्रों के भीतर अभ्यास में डाल दिया है और देर से विपणन भूगोल शब्द को भूगोल के उस पहलू का वर्णन करने के लिए लिया जाता है जो तृतीयक आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। और विशेष रूप से वितरणात्मक व्यापार। यांग परिभाषित करते हैं कि विपणन आम रोजमर्रा की गतिविधियाँ हैं जिनमें उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान शामिल है। डेविस हालांकि विपणन अनिवार्य रूप से प्रबंधन का एक कार्य है जो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया की देखरेख करता है और विपणन में शामिल रणनीतियाँ और नीतियाँ अनिवार्य रूप से स्थानिक गतिशीलता के किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं। यह देखा गया है कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोगों और सामग्रियों की काफी आवाजाही होती है। वस्तुओं की लागत तय की गई दूरी से प्रभावित होती है और परिवहन के तरीके का वस्तुओं की कीमत के निर्धारण पर असर पड़ता है। इसलिए किसी भौगोलिक स्थान पर उसकी कीमतों की प्रक्रिया के माध्यम से चल रही विपणन गतिविधियों ने विपणन भूगोल के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया है।

विपणन भूगोल का महत्व

विपणन भूगोल ने विशेष रूप से शिक्षाविदों और सामान्य रूप से नीति निर्माताओं को व्यापक रूप से आकर्षित किया है। बाजार उभरे हैं और विपणन गतिविधियाँ कर रहे हैं और न केवल स्थानीय पहलुओं से संबंधित हैं, बल्कि भौतिक-सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं, सामाजिक-आर्थिक कारणों से भी संबंधित हैं।

रामकृष्ण (1931) ने पहली बार भारत में विपणन की अवधारणा पेश की और मालाबार उत्पादों के लिए बाजारों और बाजार

क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। बाद में, कृष्णन (1932) ने मदुरै और रामंद जिले के मेलों और व्यापार केंद्रों पर भी वही प्रकाश डाला। विलियम एप्पलबाउम ने विपणन भूगोल का अध्ययन करने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं और इसे (1954) में संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र के रूप में बनाने का प्रयास किया है, और तदनुसार विद्वान ने अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आर्थिक भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण शाखा के रूप में विपणन भूगोल के मानक को बढ़ाया है। यह न केवल आर्थिक भूगोल के अन्य पहलुओं को मजबूत करने के लिए है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में विपणन क्षेत्र में भूगोलवेत्ताओं की मदद भी करता है। यह विपणन पर वास्तविक व्यवसाय में समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान देता है और बिक्री लेनदेन के प्रभावी ढंग से आगे विकास की योजना भी बनाता है। (1956) में तमसाकर ने पथरिया क्षेत्र में निपटान पैटर्न और साप्ताहिक बाजारों का अवलोकन किया। इसके बाद, मर्फी (1961) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के महानगरीय बाजारों के अध्ययन पर बहुत जोर दिया है। होडर (1965) ने योरबालैंड के एक हिस्से में ग्रामीण आवधिक दिवस बाजारों पर कुछ रोशनी डालकर विपणन भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जॉनसन ई.ए.जे (1965), एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने मार्केट मॉडल तैयार किया है और तदनुसार कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम के रूप में कृषि उपज के थोक लेनदेन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए भारत में 1968 में विनियमित बाजार मॉडल अवधारणा लागू की गई है। मध्य प्रदेश प्लैटू के एक हिस्से में साप्ताहिक बाजारों से संबंधित एक वर्णनात्मक अध्ययन बाजार केंद्रों में आकार, वितरण, वर्गीकरण और उपस्थिति पर केंद्रित था, जिसका अध्ययन तमास्कर (1966), फागरलुंड और आर.एच.टी. द्वारा किया गया था। स्मिथ (1970), प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने घाना में बाजार आवधिकता के प्रारंभिक मानचित्र पर ध्यान केंद्रित किया है। ईग्मी (1972), पश्चिम नाइजीरियाई आवधिक बाजारों के मामले में सबसे निचले क्रम के केंद्रीय स्थानों में देखा गया। बाद में, बताया गया कि विकसित परिवहन केंद्र महानगरीय केंद्रों की पहुंच का विस्तार करते हैं, अल्पविकसित शहरी स्थान अपने ग्रामीण मैट्रिक्स से विकसित होते हैं और तकनीकी नवाचार पूरे क्षेत्रों में और शहरी पदानुक्रम के नीचे फैलते हैं। सेक्सेना (1972) के अनुसार राजस्थान में हाड़ौती पटार के मेलों का भौगोलिक अध्ययन किया।

वेबर और सिस्मास् ने शास्त्रीय स्थान विश्लेषण उपकरणों की सहायता से आवधिक बाजारों की घटनाओं का विश्लेषण किया है। वे आवधिक बाजारों की जांच के लिए स्थान सिद्धांत की अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। 1974 में दोनों ने बाजार चक्र और उसकी जटिलता के बारे में अध्ययन किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बाजार सप्ताह में बाजार के दिनों, बार-बार बाजारों में उपयोग किए जाने वाले व्यापारियों के मार्गों के स्थान, माल के क्रम और आपूर्ति और मांग में अल्पकालिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित

किया। सहायता के रूप में ग्राफ सैद्धांतिक उपकरणों की सहायता से कई जटिल बाजार चक्र प्रकारों की पहचान की गई है। व्यापार विपणन और प्राधिकरण के बीच परस्पर क्रिया के कारण ग्रामीण साप्ताहिक विपणन प्रणाली को अतीत में अस्तित्व में देखा गया है और जारी है। गुड का मत था कि आवधिक बाजार प्रणाली अधिकांश विकास समस्याओं में मौजूद जटिल स्थानिक और लौकिक सुख-सुविधाओं का उत्कृष्ट चित्रण प्रदान करती है। मुख्य फोकस अपेक्षाकृत पूर्णकालिक अंतर्निहित व्यापारियों के संचलन पैटर्न पर है जो युगांडा में आवधिक बाजारों के व्यापक नेटवर्क के भीतर काम करते हैं। श्रीवास्तव, जिन्होंने विकासशील देशों के विशेष संदर्भों के साथ एक व्यक्तिगत बाजार स्थान के अध्ययन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया और सुझाव दिया कि इसमें उत्पत्ति आकारिकी, कार्यात्मक पहलू, बाजार क्षेत्र और बाजार स्थल की अन्य विशेष विशेषताएं जैसे आठ चरण शामिल हों। ब्रोमली का मानना है कि आवधिक बाजार खरीदारों और विक्रेताओं की अधिकृत सभा है जो सप्ताह में कम से कम एक बार एक नियत स्थान पर मिलते हैं, लेकिन दैनिक की तरह बार-बार नहीं। वनमाली द्वारा आदिवासी अर्थव्यवस्थाओं पर किए गए विशिष्ट अवलोकन और भारत में शहरी-ग्रामीण संपर्क और ग्रामीण सेवा केंद्रों के वितरण के स्थानिक व्यवहार पैटर्न के बारे में भी अध्ययन किया गया। ह्यूगर ने कहा कि इसके बाद गडग तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में साप्ताहिक बाजारों की भूमिका में विद्वान ने धारवाड़ जिले में बाजार प्रणाली के स्थानिक विश्लेषण पर जोर दिया है। दीक्षित ने गंगा के मैदानी क्षेत्र की बाजार संरचना का भी अध्ययन किया। ह्यूगर ने गुलबर्गा जिले के विनियमित बाजार और गडग तालुका में ग्रामीण बाजारों की स्थिरता और अस्थिरता पर गहन अध्ययन किया। मुलिमानी 2002 ने इस बात पर जोर दिया है कि विरोधाभासी संपर्क क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक के रायचूर जिले में आवधिक बाजारों के उद्भव के लिए जिम्मेदार है। फिबांखमती रयांगंगा और एल-रिनथियांग ने आवधिकता, व्यापारियों के यात्रा पैटर्न उपभोक्ता व्यवहार और विपणन बस्तियों के पदानुक्रम के संबंध में मेघालय के चिरपूंजी के आवधिक बाजार और ग्रामीण विकास का अध्ययन किया है। बेलगाम ने वितरण के कुशल चौनलों के साथ बाजार और बाजार कार्यों पर चर्चा की है और घाटे वाले क्षेत्रों में कुशल अधिशेष की पहचान की है जो कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले में स्थानिक आंदोलन और बातचीत के लिए जिम्मेदार हैं।

विपणन भूगोल का एकीकरण

विपणन भूगोल 1954 में आर्थिक भूगोल के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भूगोल की एक विशिष्ट शाखा के रूप में उभरा है। यह न केवल आर्थिक गतिविधियों से निपटने के लिए बल्कि भौगोलिक स्थान पर स्थानिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी बहुत महत्व प्राप्त कर रहा है। इसलिए यह भूगोल की कई परस्पर संबंधित शाखाओं को अनुशासन में ही एकीकृत करता है। विशेष

रूप से कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, ग्रामीण और शहरी भूगोल, विनिर्माण भूगोल, जनसंख्या भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल। परिवहन विपणन गतिविधियों और प्रमुखता और स्थानिक इकाइयों को व्यवस्थित करने के लिए मुख्य तंत्र है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विपणन गतिविधियों को पूरा करने के लिए परिवहन प्रमुख कार्य है। इसलिए, परिवहन भूगोल भी विपणन भूगोल के साथ अच्छी तरह से एकीकृत है। विपणन भूगोल मुख्य रूप से बाजार केंद्रों की स्थानीय विशेषताओं से संबंधित है और लोगों और सामग्रियों को अपने कार्यों के लिए अमीर और गरीब के बीच से जाना पड़ता है और यह विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के विकास और किसी दिए गए भौगोलिक स्थान पर सामान्य रूप से अन्य गतिविधियों को प्रतिबिंबित करता है। ग्रामीण क्षेत्र कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए जाना जाता है और इसके लिए विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादों की आवश्यकता होती है। जबकि शहरी क्षेत्र भी परस्पर अनन्य के रूप में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र भी हमेशा कृषि उपज की प्रतीक्षा में रहता है जो दैनिक जीवन के लिए बहुत प्रभावी है। जबकि शहरी क्षेत्र भी अपने दैनिक उपभोग और सामाजिक संयोजन के लिए काफी हद तक ग्रामीण उपज पर निर्भर है। परिणामस्वरूप क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में बाजार जीवंत हैं और न केवल ग्रामीण विकास में बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

विपणन भूगोल के गठजोड़ के साथ मानव और आर्थिक भूगोल का एकीकरण

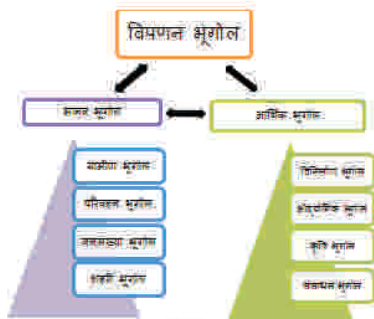


Fig 1

आर्थिक भूगोल की अन्य शाखाओं के साथ विपणन भूगोल नेक्सस का एकीकरण



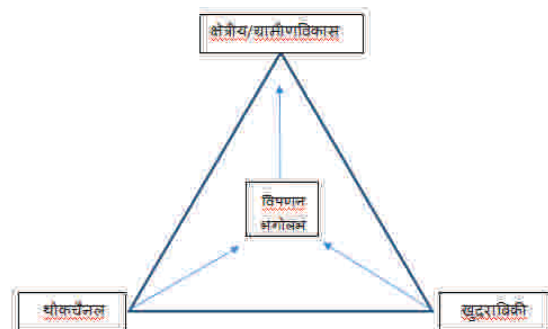
स्थानिक आंदोलन काफी हद तक किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों की

सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से जुड़े विपणन कार्यों के स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए बाजार उन वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन-बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र बिंदु हैं जिनकी बाजार तक पहुंच है। कृषि उपज औद्योगिक विनिर्माण वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही बाजार के बिना उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए बाजार पर्याप्तता वाले क्षेत्रों से लेकर अभाव वाले क्षेत्रों तक उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं के स्थानिक आंदोलनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, विनिमय प्रक्रिया के कारण ऐसे आंदोलन अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बाजार ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तर पर विपणन गतिविधियों से संबंधित है।

विपणन भूगोल न केवल आर्थिक पहलुओं को निर्धारित करने में बल्कि किसी क्षेत्र में सांस्कृतिक और पर्यावरण पहलू पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह लेन-देन के लिए वस्तुओं उत्पादों की मात्रा के आधार पर हमेशा थोक और खुदरा बिक्री दोनों प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाकर काम करता है। बिक्री लेनदेन की प्रकृति किसी दिए गए वातावरण की प्राकृतिक परिस्थितियों से निर्धारित होती है। परिणामस्वरूप मौजूदा माहौल में विपणन भूगोल न केवल लोगों की सेवा करने के लिए बल्कि ग्रामीण-क्षेत्रीय विकास हासिल करने के लिए बिक्री लेनदेन को प्रभावी ढंग से एकीकृत करता है।

विपणन गतिविधियाँ ग्रामीण और शहरी दोनों उत्पादों के परिणाम हैं और किसी भी भौगोलिक स्थान में विनियमित और आवधिक बाजारों के कार्यों के माध्यम से थोक और खुदरा बिक्री दोनों के चैनलों से प्रवाहित होती हैं। मेलों और त्यौहारों में भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से मौसमी ढंग से तरह-तरह की गतिविधियाँ की जाती थीं। ग्रामीण इलाकों में विपणन गतिविधियों की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों ने जो सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार देखा है, वह ग्रामीण विकास के लिए एक अच्छा संकेत है। इसी प्रकार, किसी भी भौगोलिक स्थान के शहरी क्षेत्रों में भी इन गतिविधियों का प्रबल होना क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने का एक संकेतक है। इसलिए, विपणन भूगोल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में विपणन गतिविधियों के दोनों आयामों से संबंधित है।

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास-थोक और खुदरा बिक्री चैनल नेक्सस और मार्केटिंग



निष्कर्ष

विपणन भूगोल ने आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाया है और मानव भूगोल को भी अपने दायरे में ले लिया है और इसके अनुशासन की उप शाखाओं को भी आपस में जोड़ा है। विपणन भूगोल को योजना उन्मुख दृष्टिकोण में से एक माना गया है और तदनुसार ग्रामीण विकास या क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने के लिए दुनिया के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में योजना रणनीतियों को डिजाइन किया गया है। इसलिए, क्षेत्रीय अध्ययनों और भौगोलिक स्थान पर स्थानिक अंतराल को कम करके संतुलन बनाए रखने में इसकी बहुत प्रासंगिकता है। मुख्य चिंता यह है कि समाज को वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया में और सुधार लाने और विपणन गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ऐसी योजना रणनीतियों का लाभ मिल सके।

संदर्भ

- 1) Applebaum, W (1954) : Marketing Geography, In James, P. E and Jones, C.F (eds) . American Geography inventory and prospects, Syracuse University. PP245-251.
- 2) Hugar, S,I (1982) : Role of weekly Markets in the development of rural areas of Gadag Taluk: A Minor Research Project sponsored by U.G.C. New Delhi.
- 3) Hodder, B.W (1965) : The distribution of markets in Yoruba Land; Scottish Geographical Magazine, 18, PP 54 91
- 4) Mulimani.A.A (2002) : Marketing Geography : A Spatio – functional perspective, Premier Publication, Dharwad.
- 5) Saxena, H.M (1972) : A Geographical Study of the fairs of Hodaoti Plateau. The Deccan Geographer.

डॉ० नाज़िया खान

सहा० आचार्य, बरेली कॉलेज,

बरेली

डॉ० ए० सी० त्रिपाठी

आचार्य

रामपुर रज़ा पी०जी० कालेज, रामपुर



सारांश

कृषि मानव का एक प्राचीनतम उद्यम है। परन्तु इसकी प्रविधियाँ एवं प्रणालियाँ समय-समय पर बदलती रहती हैं। जनपद शाहजहाँपुर का अक्षांशीय विस्तार 27° 35' उत्तरी अक्षांश 28° 29' एवं देशान्तरीय विस्तार 79° 31' पूर्वी देशान्तर 80° 23' तक है तथा भौगोलिक क्षेत्रफल 4575 वर्ग किलोमीटर है। सम्पूर्ण क्षेत्र समतल एवं उपजाऊ भूमि के कारण कृषि प्रधान है। कृषि भूमि 351.45 हजार हेक्टेयर, एक से अधिक बार बोई गई भूमि 253.43 हजार एवं सकल कृषि भूमि 604.88 हजार हेक्टेयर है। कृषि गहनता 172 प्रतिशत है। शुद्ध सिंचित भूमि 345.11 हजार हेक्टेयर, एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्रफल 190.76 हजार हेक्टेयर, सकल सिंचित भूमि 535.87 हजार हेक्टेयर एवं सिंचाई गहनता 155 प्रतिशत है। कृषि विकास हेतु नवीनतम तकनीक प्रयोग कर कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना

भारत हजारों वर्षों से एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारतीय समाज भी प्रमुखतः एक कृषि परक समाज है जिसमें लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंशदान 1951 से 60 प्रतिशत से घटकर 2005 में 25 प्रतिशत एवं वर्तमान में 15 प्रतिशत तक पहुँच गया है तथापि यह अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की जनसंख्या के लिए भोजन की आवश्यकताएँ पूर्ण करने के अतिरिक्त कृषि से कृषि परक, उद्योगों के लिए कच्चे माल प्राप्त होते हैं तथा यह श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती है। एवं पर्याप्त बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी प्राप्त करती है। निश्चय ही आर्थिक विकास की रणनीति में कृषि महत्वपूर्ण अंग है।

क्योंकि कृषि से उद्भूत विकास दर, कृषि इतर देशों में विकास दर की तुलना में गरीबी मिटाने में दोगनी प्रभावी होती है। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उन्नत बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में हरित क्रान्ति की सफलता आंशिक रूप से अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग से सम्बद्ध रही है। कृषि फसलों को सुरक्षित रखने एवं कृषकों की स्थिति को देखते हुए सरकार ने सम्पूर्ण फसल सुरक्षा योजना 1985 में लागू की। आज कृषि विश्वविद्यालयों संस्थानों के कृषि सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों के वैज्ञानिकों द्वारा उपयुक्त किस्मों के चुनाव मौसम पूर्वानुमान पर आधारित फसल का उपयोजना फसल और फलोत्पादन प्रबन्धन, नाशीजीव प्रबन्धन, फसलोत्तर प्रबन्धन और उत्पाद के विपणन के क्षेत्रों में प्रदान की गयी परामर्शी सेवाओं से

किसान लाभान्वित हुए हैं।

अध्ययन क्षेत्र:

प्रस्तुत शोध-पत्र का अध्ययन क्षेत्र जनपद शाहजहाँपुर है जो गंगा-रामगंगा मैदान में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 27° 35' उत्तरी अक्षांश से 28° 29' एवं देशान्तरीय विस्तार 79°31' पूर्वी देशान्तर से 80° 23' तक है तथा भौगोलिक क्षेत्रफल 4575 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में पीलीभीत जनपद एवं दक्षिण में जनपद फर्रुखाबाद पूरब में लखीमपुर खीरी जनपद एवं पश्चिम में बदायूँ एवं बरेली जनपदों का विस्तार है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से 01 जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर, 04 तहसील मुख्यालय (तिलहर, पुवायाँ, जलालाबाद, शाहजहाँपुर सदर), 15 विकासखण्ड मुख्यालय, 126 न्यायपंचायत, 922 ग्राम पंचायत और 2331 कुल राजस्व ग्राम है। स्थानीय निकाय एवं प्रशासन के दृष्टिकोण से 03 नगरपालिका परिषद 01 छावनी क्षेत्र एवं 07 टाउन एरिया है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या 30.06 लाख व्यक्ति है जिसमें 16.06 लाख पुरुष एवं 14 लाख स्त्रियाँ शामिल हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखे तो जनपद शाहजहाँपुर 1813-14 में बना। पाचाल क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित इस क्षेत्र की राजधानी अहिछत्र (वर्तमान बरेली-आंवला) थी। महावीर और बुद्ध के समय यह क्षेत्र महाजनपद कहलाता था। शहीद क्रान्तिकारी रामप्रसाद बिस्मिल एवं अशाफाक उल्ला खॉ के पैतृक मकान शाहजहाँपुर में आज भी है।



शोध परिकल्पना

जनपद शाहजहाँपुर कृषि विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण

क्षेत्र है। यहाँ पर निम्न परिकल्पनाये स्पष्ट होती है जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. जनपद शाहजहाँपुर जलोढ़ मिट्टियों से युक्त एक उपजाऊ, क्षेत्र है। 'कृषि' यहाँ की मुख्य आर्थिक क्रिया है।
2. अध्ययन क्षेत्र में कृषि कार्य में तकनीकी साधनों का प्रयोग तेजी से किया जा रहा है जिससे प्रति हेक्टेयर उपज भी बढ़ी है।
3. अध्ययन क्षेत्र में कृषक फसलों का चयन माँग एवं आपूर्ति के अनुरूप कर रहे हैं। कृषि में उन्नतशील बीज रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है।
4. अध्ययन क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करने में सिंचाई की भूमिका सर्वोपरि है।
5. अध्ययन क्षेत्र में कृषक कृषि के अति सजग एवं जागरूक हैं। कृषि फसलों की बुवाई से पूर्व मृदा जाँच पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

प्राकृतिक स्वरूप

जनपद शाहजहाँपुर पूर्णतः समतल मैदानी भू-भाग है, जो रामगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इसकी औसत ऊँचाई 162 मीटर तथा ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व को है। यह मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। वार्षिक औसत तापमान 25.50 सेन्टीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा का औसत 95-100 सेन्टी मीटर है। ग्रीष्म काल गर्म व शुष्क 'लू' गर्म हवाओं से युक्त, शीतकाल ठण्डा व शुष्क बना रहता है। शीतकाल में पाला पड़ता है। वर्षा अन्तिम जून से मध्य सितम्बर तक होती है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति मानसूनी पतझड़ी है। 2.38 प्रतिशत भूमि वन, चारागाह व उद्यान क्षेत्र है। यहाँ पर चीका, चीका दोमट, बालू युक्त दोमट, उदला, कटेहर मिट्टियाँ मिलती हैं। अधिकांश मिट्टियाँ उपजाऊ हैं तथा जलोढ़ प्रकार की हैं जिनको खादर व बांगर में विभाजित किया है। जनपद शाहजहाँपुर में खनिजों का अभाव है परन्तु भूपृष्ठीय जल एवं अवमृदा जल की दृष्टि से धनी है। रामगंगा, बहगुल, सोत, गोमती, झुकना, कथना, भैंसी, गर्गा, कटना, सुखेता एवं गरई मुख्य नदियाँ बहती हैं।

आर्थिक स्वरूप

जनपद शाहजहाँपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की कार्यशील जनसंख्या का 55 प्रतिशत भाग कृषक एवं कृषि श्रमिकों के रूप में रोजगार प्राप्त करता है। कृषि के अन्तर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 351.45 हजार हेक्टेयर है। दो फसली भूमि 253.43 हजार हेक्टेयर एवं सकल कृषित भूमि 504.08 हजार हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित भूमि 345.11 हजार हेक्टेयर है। यहाँ पर गेहूँ, चावल, गन्ना, ज्वार-बाजरा मैन्था मुख्य फसलें हैं। कुल पशुधन की संख्या 10.28 लाख है जिसमें गौवंशीय 2.78 लाख, महिषवंशीय 5.10 लाख एवं अजातवंशीय 2.40 लाख है तथा पशुधन घनत्व 225 किलोमीटर हैं। जनपद शाहजहाँपुर में चीनी एवं खाण्डसारी, कागज व गत्ता निर्माण, मेन्था ऑयल एवं

ब्रॉड क्रिस्टल, आटा मैदा व चावल मिलें, सूती वस्त्र व हथकरघा, इंजीनियरिंग, कृषि यन्त्र विनिर्माण उद्योगों के साथ-साथ हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग - 24 दिल्ली-लखनऊ गुजरता है। इसके अतिरिक्त कोलकाता-अमृतसर दोहरा रेलमार्ग भी गुजरता है। जनपद शाहजहाँपुर में शाहजहाँपुर, तिलहर पुवायों एवं जलालाबाद प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हैं।

भूमि उपयोग

जनपद शाहजहाँपुर में सकल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 437469 हेक्टेयर है जिसमें वन, चारागाह उद्यानों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल 3.30 प्रतिशत, कृषि योग्य बजर एवं कृषि अयोग्य भूमि 2.15 प्रतिशत, परती भूमि 1.70 प्रतिशत, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि 9.52 प्रतिशत एवं कृषि के अन्तर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 83.33 प्रतिशत है। जैसा कि तालिका- में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या - 1

जनपद शाहजहाँपुर में भूमि उपयोग का क्षेत्रीय वितरण, 2021-2022

क्र० सं०	विकासखण्ड	वन, चारागाह, उद्यानों, वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल	कृषि योग्य बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि	परती भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	सकल प्रतिवेदित क्षेत्रफल
1-	बगडा	10.20	1.04	0.80	7.15	80.81	44954
2-	खुटार	15.38	1.29	0.26	7.59	75.48	41314
3-	पुवायाँ	4.79	1.37	2.45	8.96	82.43	28616
4-	सिंहीली	1.15	2.79	2.95	8.30	84.81	29965
5-	खुदागंज कटरा	0.28	1.69	2.75	9.18	86.10	26623
6-	जौतीपुर	0.34	1.50	2.14	11.48	84.54	23738
7-	तिलहर	0.47	1.92	2.05	10.87	84.68	22579
8-	निगोही	0.54	1.69	2.16	10.41	86.20	25438
9-	कांठ	1.32	3.12	2.77	9.92	83.87	26189
10-	ददरोल	1.35	4.11	3.61	12.67	77.26	25613
11-	भावलखेडा	1.14	2.47	2.10	10.43	82.86	28840
12-	कलान	1.18	3.38	2.97	9.31	81.16	28515
13-	निर्जापुर	1.12	2.75	2.78	8.75	81.60	23665
14-	जलालाबाद	0.99	4.15	2.15	8.54	82.17	32269
15-	मदनापुर	0.96	2.64	2.52	9.46	83.42	27955
योग ग्रामीण		3.46	2.33	3.64	9.09	80.48	435873
नगरीय योग		3.85	8.15	4.31	52.12	31.57	1596
योग जनपद		3.30	2.15	1.70	9.52	83.33	437469

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद शाहजहाँपुर 2022।



कृषि भूमि उपयोग

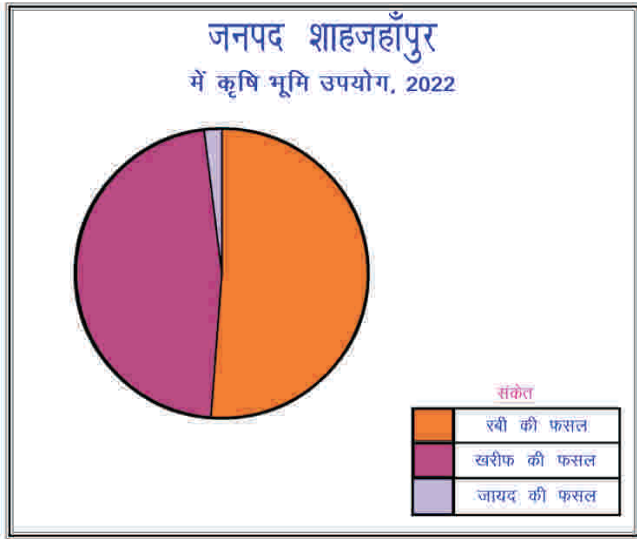
जनपद शाहजहाँपुर में सकल बोया गया क्षेत्रफल 577850 हेक्टेयर है जिसमें रबी की फसल 51.20 प्रतिशत, खरीफ की फसल 46.85 प्रतिशत एवं जायद की फसल 1.95 प्रतिशत है। कृषि गहनता 172 प्रतिशत है। जैसा कि तालिका- में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 02

जनपद शाहजहाँपुर में कृषि भूमि उपयोग का क्षेत्रीय वितरण, 2021-2022

क्र० सं०	विकासखण्ड	रबी की फसल	खरीफ की फसल	जायद की फसल	सकल बोया गया क्षेत्रफल	कृषि गहनता प्रतिशत में
1-	बण्डा	50.92	47.78	1.63	58096	169
2-	खुटार	51.02	47.42	1.56	51906	174
3-	पुवायां	52.20	46.44	1.36	40098	176
4-	सिधौली	50.93	47.56	1.51	42459	177
5-	खुदामज कटरा	50.08	48.44	1.48	40562	179
6-	जैतीपुर	50.60	48.25	1.15	32479	181
7-	तिलहर	50.56	47.67	1.77	31116	180
8-	निगोही	50.04	48.36	1.60	34237	164
9-	कांठ	52.04	46.91	1.05	34702	164
10-	ददरौल	50.92	46.78	2.30	32674	172
11-	भावलखंडा	50.97	48.01	1.02	36460	159
12-	कलान	50.14	47.24	2.62	38584	171
13-	मिर्जापुर	50.48	76.00	3.52	29897	165
14-	जलालाबाद	53.83	43.97	2.20	43530	173
15-	मदनापुर	55.69	42.95	1.36	39821	180
योग ग्रामीण		51.19	46.86	1.95	577089	172
नगरीय योग		49.86	34.24	15.90	761	171
योग जनपद		51.20	46.85	1.95	577850	172

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद शाहजहाँपुर 2022।



सिंचित क्षेत्र

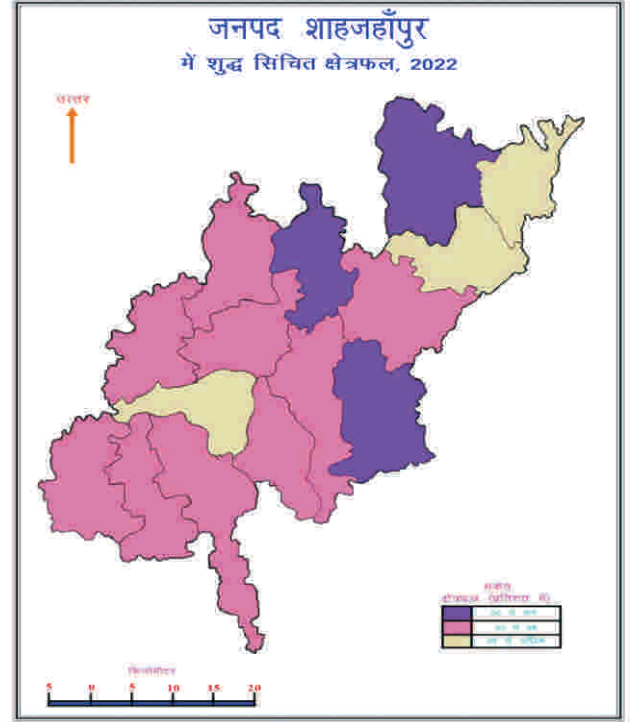
जनपद शाहजहाँपुर में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 345110 हेक्टेयर है। एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्रफल 190760 हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्रफल 535870 हेक्टेयर है। सिंचाई गहनता 155 प्रतिशत है। जैसा कि तालिका- में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 03

जनपद शाहजहाँपुर में सिंचित क्षेत्रफल का क्षेत्रीय वितरण, 2021-2022

क्र० सं०	विकासखण्ड	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल		एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्रफल		सकल सिंचित क्षेत्रफल		सिंचाई गहनता का प्रतिशत
		हेक्टेयर में	प्रतिशत	हेक्टेयर में	प्रतिशत	हेक्टेयर में	प्रतिशत	
1-	बण्डा	33376	88.92	18430	89.63	51806	89.17	155
2-	खुटार	30697	95.05	16451	83.88	47148	90.83	153
3-	पुवायां	23992	95.25	11002	73.81	34994	87.27	145
4-	सिधौली	23708	92.20	14985	95.76	38693	91.13	163
5-	खुदामज कटरा	23783	94.28	11155	67.73	34938	86.13	147
6-	जैतीपुर	18836	94.50	10213	80.37	29049	89.43	154
7-	तिलहर	18890	93.90	10992	92.74	29882	96.03	158
8-	निगोही	20177	87.10	9731	87.90	29908	87.35	148
9-	कांठ	20221	90.50	10456	92.54	30677	88.40	152
10-	ददरौल	20925	94.75	10080	88.30	31005	94.90	148
11-	भावलखंडा	21515	84.98	13765	98.35	35280	96.76	164
12-	कलान	22111	88.80	14215	97.60	36326	94.15	164
13-	मिर्जापुर	18318	90.88	9804	98.39	28122	94.06	153
14-	जलालाबाद	24996	92.11	15773	96.22	40769	93.65	163
15-	मदनापुर	23315	97.07	13490	85.36	36805	92.43	158
योग ग्रामीण		344860	94.40	190542	89.65	535402	92.78	155
नगरीय योग		250	55.30	218	70.55	468	93.30	167
योग जनपद		345110	94.40	190760	89.62	535870	92.73	155

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद शाहजहाँपुर 2022।



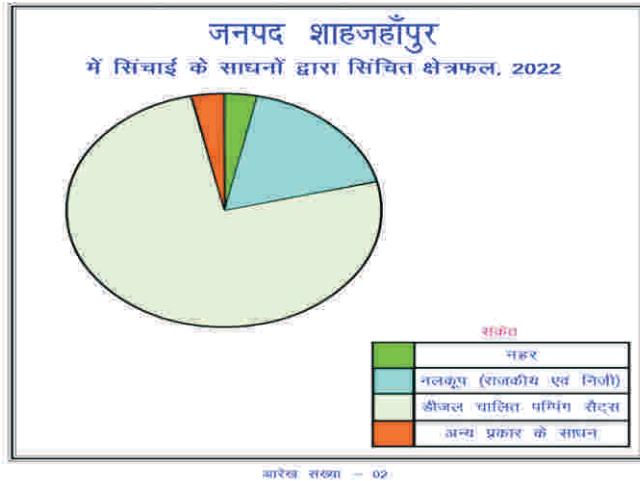
जनपद शाहजहाँपुर में नहरों की लम्बाई 892 किलोमीटर है जिनके द्वारा सिंचित भूमि 11050 हेक्टेयर है। राजकीय नलकूपों की संख्या 451 है जिनके माध्यम से 16120 हेक्टेयर भूमि सिंचित है। निजी नलकूपों की संख्या 4500 है जिनके द्वारा 45775 हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित है। डीजल चालित पम्पिंग सैट्स की संख्या 110105 हेक्टेयर है जिनके द्वारा 260105 हेक्टेयर सिंचित भूमि 12060 हेक्टेयर है जिनकी संख्या 693 है। जैसा कि तालिका- में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 04

जनपद शाहजहाँपुर में सिंचाई के साधन एवं सिंचित क्षेत्रफल, 2021-2022

क्र० सं०	सिंचाई के साधन	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1-	नहर	892	11050	3.20
2-	राजकीय नलकूप	451	16120	4.67
3-	निजी नलकूप	4500	45775	13.26
4-	डीजल चालित पम्पिंग सैट्स	110105	260105	75.37
5-	अन्य प्रकार के साधन	693	12060	3.50
योग		-	345110	100

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग
जनपद शाहजहाँपुर 2022।



कृषि से सम्बन्धित सुविधायें

जनपद शाहजहाँपुर में बीज विक्रय केन्द्र 125, उर्वरक केन्द्र 150, कीटनाशक डिपो 110, शीत भण्डार 27, कृषि सेवा केन्द्र 75, कृषि रक्षा इकाई केन्द्र 20, कृषि यन्त्र एवं उपकरण केन्द्र 125, ग्रामीण गोदाम 50, राजकीय कृषि प्रक्षेप 10 कृषि उत्पादन मण्डी समिति 10, बायोगैस संयन्त्रों की संख्या 2025, क्रय-विक्रय सहकारी समिति 25, प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां 115 वित्तीय संस्थायें 287 एवं सहकारी एवं ग्राम्य विकास बैंक 11 है। जैसा कि तालिका- में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या - 05

जनपद शाहजहाँपुर में कृषि से सम्बन्धित सुविधायें, 2021-2022

क्र० सं०	विवरण	संख्या
1-	बीज विक्रय केन्द्र	125
2-	उर्वरक केन्द्र	150
3-	कीटनाशक डिपो	110
4-	शीत भण्डार	27
5-	कृषि सेवा केन्द्र	75
6-	कृषि रक्षा इकाई केन्द्र	20
7-	कृषि यन्त्र एवं उपकरण केन्द्र	125
8-	ग्रामीण गोदाम	50
9-	राजकीय कृषि प्रक्षेप	10
10-	कृषि उत्पादन मण्डी समिति	10
11-	बायो गैस संयन्त्रों की संख्या	2025
12-	क्रय-विक्रय सहकारी समिति	25
13-	प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां	1150
14-	वित्तीय संस्थायें	287
15-	सहकारी एवं ग्राम्य विकास बैंक	11

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग
जनपद शाहजहाँपुर 2022।

निष्कर्ष

जनपद शाहजहाँपुर कृषि विकास की दृष्टि से अनुकूल क्षेत्र है। मानसूनी जलवायु के कारण प्राकृतिक दशाओं की विविधता एवं विषमता के फलस्वरूप यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती है। अनुकूल स्थिति के बावजूद अध्ययन क्षेत्र में कृषि उत्पादन

की मात्रा पर्याप्त नहीं है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी लाना आवश्यक है। एकल फसल के बजाए बहुफसली प्रणाली अपनाएं। खेती में पढ़े-लिखे युवाओं की दिलचस्पी को बढ़ाना भी आवश्यक, है। मिट्टी परीक्षण के माध्यम से पता करके किसान, ऐसी खेती करें जिसमें उन्हें घाटा न सहना पड़े। किसानों को यह समझाना आवश्यक है कि खेती को लाभदायक रूप में संग्रहित करें। आज ग्रामीण क्षेत्र का पढ़ा-लिखा कुशल नौजवान काम की तलाश में शहरों, में जाकर दर-दर की ठोकर खा रहा है ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि ग्रामीण नवयुवकों के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्थाओं को कम ब्याज दर पर एवं कम समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सिंचाई साधनों में बढ़ोतरी के साथ आधुनिक तरीकों ड्रिप सिप्रिंगकलर विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसान सहायक की नियुक्ति कर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं में आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ अतिरिक्त शाखाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। कृषकों को मण्डी नियमन की व्यवस्था का समुचित लाभ उठाने के लिए स्वयं किसानों को भी जागरूक होना आवश्यक है। पशुधन की उपलब्धता के आधार पर दुग्ध उद्योग को विकसित करने की जरूरत है। जनपद शाहजहाँपुर जैसे विकासशील क्षेत्र के प्रमुख आधारभूत तत्वों में वृद्धि करके ही कृषि विकास में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आधारभूत तत्वों में वृद्धि एवं सिंचाई व कृषि क्षेत्रों में आने वाले सुधारों से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुलभ होंगे, अपितु ग्रामीण समाज का समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी हो सकेगा।

1. तिवारी, आर० सी० एवं सिंह, बी० एन० 2010: कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद पृष्ठ-10
2. शर्मा, बी. एन. एवं भारद्वाज पलक 2023 कृषि भूगोल, रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ पृष्ठ-20
3. गौतम अलका 2009: कृषि भूगोल शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद पृष्ठ-15
4. गुलाटी अशोक एवं जैन सुरभि 2014 : भारत में कृषि संवर्धन में निवेश की महत्ता योजना मासिक पत्रिका जून 7
5. कुमार वीरेन्द्र 2016: कृषि विकास की नवीनतम तकनीक, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका मार्च पृष्ठ-19
6. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र' कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका मार्च अंक 2016 पृष्ठ-20।
7. अयोध्या उपेन्द्र 2018: कृषि में आधुनिक तकनीकों से बदलती तस्वीर कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका मई अंक पृष्ठ 17
- 8- तिवारी के० एन.

2018 :कृषि विकास दर टिका ग्रामीण विकास कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका जून अंक पृष्ठ-18

9. जिला सामाजिक-आर्थिक विकास पुस्तिका अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद शाहजहाँपुर 2022 पृष्ठ-5

10. जिला सांख्यिकीय पत्रिका अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद शाहजहाँपुर 2022 ।

निर्देशक

डॉ० एन० यू० खान

पूर्व प्राचार्य

जी०एफ० (पी०जी०) कॉलिज,

शाहजहाँपुर

शोधार्थी

नवीन जायसवाल



सारांश

सामान्य व्यावसायिक शब्दावली में विपणन का संबंध विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मांग के वितरण और एक कुशल वितरण नेटवर्क के माध्यम से उनकी आपूर्ति की व्यवस्था से है। यह अनिवार्य रूप से प्रबंधन का कार्य है जो किसी फर्म की वस्तुओं की खरीद और बिक्री की देखरेख करता है। विपणन में शामिल रणनीतियाँ और नीतियाँ अनिवार्य रूप से कुछ स्थानिक रूप में प्रकट होती हैं। यह क्षेत्रीय अभिव्यक्ति है जो मांग के स्रोत और आपूर्ति प्रणाली की क्षेत्रीय संरचना को दी जाती है जो विपणन के भौगोलिक अध्ययन के लिए आधार प्रदान करती है। हालाँकि, अगर कोई कामकाजी आबादी के बड़े हिस्से पर विचार करता है जो विशेष रूप से विपणन कार्यों में लगा हुआ है, शहरी परिदृश्य का बड़ा हिस्सा जो थोक और खुदरा व्यापार की संरचनाओं के लिए समर्पित है, और वितरण के जटिल चैनल जो उत्पादन से लेकर उत्पादन तक ले जाते हैं। उपभोग क्षेत्रों में, यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि विपणन भूगोल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह के विकास से न केवल आर्थिक भूगोल के अन्य क्षेत्रों में समझ बढ़ेगी, बल्कि विपणन के क्षेत्र में काम करने वाले भूगोलवेत्ता को विपणन के वास्तविक व्यवसाय में समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान देने में भी मदद मिलेगी।

इस प्रकार, विपणन भूगोल को अंतरिक्ष की इकाइयों के रूप में बाजार स्थानों और आवश्यक वस्तुओं के स्थानिक वितरण से जुड़ी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए भौगोलिक तरीकों और तकनीकों के अनुप्रयोग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विपणन भूगोल की जड़ बाजार है। शब्द बाजार लैटिन शब्द मार्केटस से लिया गया है जिसका अर्थ उस स्थान से है जहाँ खरीदार और विक्रेता मिलते हैं। बाजार स्थानिक इकाइयाँ हैं इस प्रकार उनका स्थान, स्थल, स्थिति, भौतिक विस्तार, आकृति विज्ञान और क्षेत्रीय संयोजन आदि भूगोलवेत्ताओं के लिए स्थानिक महत्व के हैं। संक्षेप में, विपणन भूगोल का संबंध क्षेत्रीय विकास के लिए एक व्यवस्थित योजना तैयार करने के लिए बाजारों के स्थान और वितरण, उनके बुनियादी ढाँचे के पैटर्न, विपणन गतिविधि की माप और सीमा, वस्तुओं की आवाजाही, उपभोक्ता व्यवहार, धारणा और पदानुक्रम सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भूमिका और तर्क के निर्धारण से है।

विपणन भूगोल अब अपने आप में एक विषय के रूप में उभरा है और आर्थिक भूगोल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और एकीकृत विषय के रूप में उभरा है। विपणन न केवल आधुनिक जीवन की एक अनिवार्य विशेषता है बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास का एक

संकेतक भी है। आर्थिक भूगोल में विपणन के अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट है, न केवल आर्थिक भूगोल के विभिन्न पहलुओं को मजबूत करने के लिए, बल्कि विपणन के क्षेत्र में भूगोलवेत्ता को विपणन के वास्तविक व्यवसाय में समस्याओं के महत्वपूर्ण समाधान खोजने में मदद करने के लिए भी। विपणन भूगोल वितरण के उन चैनलों से जुड़ा है जिनके माध्यम से सामान उत्पादक से उपभोक्ता तक जाता है

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन हालाँकि आर्थिक भूगोलवेत्ताओं ने हाल तक संसाधनों और उत्पादन के कारकों के अध्ययन पर काफी ध्यान दिया है, लेकिन उन्होंने संबंधित बाजार-स्थानों और विपणन के अध्ययन की उपेक्षा की है। मनुष्य की आर्थिक गतिविधि एक व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करती है और इसे सामान्यीकृत रूप में वर्णित किया जा सकता है, जबकि कृषि, उद्योग, परिवहन और विपणन जैसी इससे जुड़ी घटनाओं पर न केवल उनकी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए बल्कि विकास और योजना के लिए भी विशेष ध्यान और अध्ययन की तकनीकों की आवश्यकता होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, दुनिया के ग्रामीण और शहरी दोनों केंद्रों में विपणन गतिविधियों पर कुछ छिटपुट चर्चा और सर्वेक्षण किए गए हैं, लेकिन इन अध्ययनों को पिछली शताब्दी के मध्य तक शहरी भूगोल, औद्योगिक भूगोल या कृषि भूगोल का हिस्सा माना जाता था।

हालाँकि, बीसवीं सदी के पांचवें दशक में विपणन भूगोल के नए अनुशासन की शुरुआत देखी गई। विलियम एप्पलबाम ने विपणन भूगोल के क्षेत्र और दायरे को परिभाषित करके इस अनुशासन की नींव रखी। उन्होंने विपणन भूगोल को बाजार के परिसीमन और माप और वितरण के चैनलों से संबंधित है जिसके माध्यम से सामान उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक जाता है के रूप में परिभाषित किया। 1960 और 70 के दशक के दौरान विपणन भूगोल पश्चिमी दुनिया में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विभिन्न वाणिज्यिक फर्मों के स्थान की योजना बनाने के लिए बहुत लोकप्रिय हो गया। विपणन भूगोल और आवधिक बाजारों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन समय के विभिन्न चरणों में विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया है। शुरुआती चरण में विपणन भूगोल के व्यावहारिक महत्व को बेरी, बोहनन, ब्रोमली, होडर, गुड्स, मिंग, स्किनर, स्मिथ, सिमांस्की और अन्य जैसे भूगोलवेत्ताओं द्वारा इंगित किया गया है। बाजार केंद्रों को केंद्रीयता के कार्य के रूप में माना जाता था जो अपने सहायक क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के कार्य और सेवाएँ प्रदान करते हैं। सेंट्रल प्लेस की शुरुआत के साथ थोक और खुदरा बिक्री सहित सेवा केंद्रों का अध्ययन बहुत आम हो गया।

विपणन भूगोल पर अध्ययन अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और

एशियाई देशों में किए गए। एक आर्थिक घटना के रूप में आवधिक बाजारों की उत्पत्ति दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक विनिमय से आधुनिक बाजारों तक विपणन प्रणाली में बदलाव, बाजार केंद्रों में वस्तुओं की मांग निर्धारित करने में दूरी का कारक, बाजार क्षेत्र की सीमा, बाजार केंद्रों से वितरित वस्तुओं के प्रारंभिक मूल्य की अधिकतम सीमा है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि सामान सभी बाजारों में वितरित किया जाता है, लेकिन इस दशक में उच्च ऑर्डर वाले सामान का कारोबार शुरू हो गया है। विनिमय की त्रि-स्तरीय प्रणाली की पहचान की गई, जो अस्थायी रूप से इंटरलॉकिंग थी। उन्होंने ग्रामीण बाजारों को विनिमय प्रणाली के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मध्यवर्ती और केंद्रीय बाजारों से जुड़ी सबसे छोटी इकाई के रूप में मान्यता दी।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन

विपणन और बाजार-स्थान के भू-आर्थिक अध्ययन का प्रारंभिक चरण पिछली सदी के तीस के दशक में बाजार मेलों, आवधिक बाजारों और बाजार केंद्रों पर विभिन्न भारतीय पत्रिकाओं में छपने वाले शोध पत्रों के रूप में शुरू हुआ। कृषि विपणन, बाजार-स्थान व्यापार आदि जैसे अध्ययन के नए विषयों की शुरुआत के साथ यह चरण 1960 तक जारी रहा। इन सभी अध्ययनों ने इस क्षेत्र में आगे के शोध के लिए एक आधार दिया है।



1970 के बाद, उदयपुर, मद्रास, मदुरै, मैसूर, गोरखपुर, नागपुर, इलाहाबाद, जबलपुर, कानपुर और वाराणसी में भूगोलवेत्ताओं द्वारा कई अध्ययन किए गए, जो उनकी क्षेत्रीय सेटिंग में विपणन से संबंधित थे। वास्तव में, यह भारत में व्यावसायिक गतिविधियों के भूगोल की वास्तविक शुरुआत थी। एनसीईआर (नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च) ने भी बाजार केंद्रों के अध्ययन को बढ़ावा देने में मदद की है, ताकि बाजार शहर भारत के स्थानिक विकास की प्रक्रिया को तेज कर सकें

सबसे हालिया कार्य जिसका शीर्षक है सब्जी की खेती और विपणन की स्थिरता: भारतीय किसानों की स्थिति की खोज भी इन विपणन भूगोलवेत्ताओं का एक उल्लेखनीय योगदान है। इन उपर्युक्त योगदानों के अलावा, इन अवधियों के दौरान विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में कई डॉक्टरेट शोध प्रबंध पूरे किए गए।

व्यावसायिक गतिविधियों में, विपणन को दुनिया भर में प्रमुख गतिविधि माना जाता है इसलिए भूगोलवेत्ताओं ने विपणन

भूगोल के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में अधिक रुचि ली है। भूगोलवेत्ताओं ने सामान्य रूप से व्यावसायिक गतिविधियों विशेष रूप से विपणन भूगोल के क्षेत्र में काफी काम किया है। उनका मुख्य जोर क्षेत्रीय अध्ययन के साथ-साथ व्यक्तिगत बाजार शहर के अध्ययन पर भी है। विपणन भूगोल के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य बहुत ही अस्थायी है विशेष रूप से विभिन्न भू-ऐतिहासिक क्षेत्रों में बाजारों की उत्पत्ति के क्षेत्र में अनुसंधान की व्यापक गुंजाइश है,। शहरी क्षेत्रों में खुदरा विपणन का अध्ययन, अध्ययन का एक संभावित क्षेत्र है क्योंकि इससे शहरी वाणिज्यिक योजना बनाने में मदद मिलेगी। किसी क्षेत्र में बाजार केंद्रों की स्थिति प्राप्त करने के लिए विपणन भूगोल में पदानुक्रम की अवधारणा का उपयोग किया गया है। बाजार क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र का परिसीमन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो न केवल बाजार शहर की वर्तमान स्थिति को समझने में मदद करता है बल्कि भविष्य की योजना के लिए आधार भी प्रदान करता है। क्षेत्रीय विकास और योजना में बाजार कस्बों की भूमिका से संबंधित अध्ययन स्थानिक योजना के लिए आधार प्रदान करते हैं। कृषि विपणन जो अर्थशास्त्रियों और कृषिविदों द्वारा निपटाया जाने वाला एक अंतःविषय है। भूगोलवेत्ताओं ने हाल ही में इस विषय पर ध्यान दिया है, लेकिन उनका अध्ययन बाजारों और बाजार प्रांगणों की स्थानिक योजना के लिए महत्वपूर्ण है।

भू-भाग, मिट्टी, वनस्पति, जलवायु, भूमि उपयोग, खनिज संसाधन, उद्योग, बस्तियाँ, खेती के प्रकार, यातायात और परिवहन या संचार प्रणाली जैसी कई घटनाएँ, जो भूगोलवेत्ता विभिन्न प्रकार के अध्ययनों में दर्शाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विपणन पर असर डालती हैं। विपणन भूगोलवेत्ता को अपने भविष्य के अध्ययन में इन सभी महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना चाहिए। भारत में, भूगोल की अन्य शाखाओं की तरह, विपणन भूगोल में दार्शनिक और पद्धतिगत अनुसंधान की ओर ध्यान काफी कम है। चूंकि, दुनिया के विभिन्न देशों की भू-आर्थिक स्थितियाँ अलग-अलग हैं और वे सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक विविधतापूर्ण हैं, इसलिए, प्रत्येक भू-सांस्कृतिक क्षेत्र के बाजारों और विपणन पैटर्न का अध्ययन करने की आवश्यकता है। भूगोल में ठोस पृष्ठभूमि के बिना भौगोलिक तकनीकों में कौशल हासिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए विपणन भूगोलवेत्ता के लिए अर्थशास्त्र, विपणन अनुसंधान, सांख्यिकी और सिद्धांत और अभ्यास के सिद्धांतों और तरीकों का प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद उन्हें इन तकनीकों को भूगोल की तकनीकों के साथ मिश्रित करना चाहिए। विचारों और अनुसंधान विधियों के ऐसे परस्पर-निषेचन से बेहतर अनुसंधान और अधिक मूल्यवान परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान का व्यापक दायरा है और यह कहा जा सकता है कि यह अध्ययन का तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जिसका इतिहास छोटा है और भविष्य लंबा है।

निष्कर्ष

विकासशील देशों में, व्यापार के वैश्वीकरण में बदलाव, व्यावसायीकरण प्रक्रिया और बाजार उन्मुख कृषि के उद्भव के लिए बाजार केंद्रों, शॉपिंग सेंटर्स के साथ-साथ फसलों की भूमि उपयोग योजना के बेहतर और इष्टतम स्थानीयकरण का चयन करने के लिए भौगोलिक अंतर्दृष्टि के तत्काल ज्ञान की आवश्यकता थी। इसलिए, अपने विभिन्न मॉडलों के साथ विपणन भूगोल ग्रामीण, शहरी और साथ ही कृषि विकास और योजना के लिए प्रभावी उपकरण होगा। भूगोल की इस उपशाखा में कृषि, ग्रामीण विपणन, उपभोक्ता व्यवहार, खुदरा बिक्री और कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी व्यापार और विपणन के तुलनात्मक विश्लेषण में बहुत उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं हैं। इसलिए, विपणन भूगोल, बाजारों और विपणन गतिविधियों और संबंधित विशेषताओं के स्थानिक आयाम से संबंधित विषय होने के नाते, आधुनिक दुनिया में इसकी प्रासंगिकता और महत्व की एक विस्तृत श्रृंखला है।

संदर्भ

1. Applebaum W- The Geographer in Business and his Requisite Training] The Professional Geographer] April issue 1947-
2. Saena HM- Marketing Geography, Rawat Publications, New Delhi 2004-
3. Applebaum W- Marketing Geography in James] PE and Jones, CF (eds-), American Geography: Inventory & Prospects, Syracuse University Press, Syracuse 1954-
4. Khan MM, Khan N- Sustainability of Vegetable Cultivation and Marketing: Exploring the State of Indian Farmers] The International Journal of Sustainability Policy and Practice] Common Ground Publishing USA 2014

डॉ० नाज़िया खान

सहा० आचार्य, बरेली कॉलेज,
बरेली

डॉ० ए० सी० त्रिपाठी

आचार्य
रामपुर रज़ा पी०जी० कालेज, रामपुर

जनपद पीलीभीत में कृषि विकास पर सिंचाई का प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन

डॉ० एन० यू० खान, रामाकान्त



सारांश

'कृषि' के अन्तर्गत वे समस्त क्रियायें सम्मिलित हैं। सिंचाई कृषि का प्रमुख अभौतिक तत्व है। जनपद पीलीभीत का अक्षांशीय विस्तार 28° 6' उत्तरी अक्षांश से 28° 53' एवं देशान्तर्रीय विस्तार 78° 57' पूर्वी देशान्तर से 80° 27' है तथा क्षेत्रफल 3765.40 वर्ग किलोमीटर है। अध्ययन क्षेत्र समतल मैदानी भू-भाग है जो रुहेलखण्ड भौगोलिक क्षेत्र का अभिन्न अंग है। कृषि भूमि 231.01 हजार हेक्टेयर है। एक से अधिक बार की भूमि 163.89 हजार हेक्टेयर एवं सकल कृषि भूमि 394.90 हजार हेक्टेयर है। सिंचाई साधनों में नहर 1002 किलोमीटर, राजकीय नलकूप 204, निजी नलकूप 3372, डीजल चालित पम्पिंग सैट्स 63998 एवं अन्य साधन 11899 है। शुद्धसिंचित क्षेत्रफल 229.10 हजार, एक से अधिक बार की सिंचित भूमि 160.89 हजार हेक्टेयर एवं सकल सिंचित भूमि 389.99 हजार हेक्टेयर है। कृषि भूमि में बढ़ोत्तरी के लिए कृषि बंजर भूमि को परिवर्तित किया जाना चाहिए। सिंचाई साधनों में बढ़ोत्तरी के साथ ही सिंचाई तकनीक पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

भूमिका:

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारी अधिकांश आबादी की आय और आजीविका का प्रमुख स्रोत है और कृषि प्रणाली के उन्नयन से देश की अधिकांश आबादी का आर्थिक उत्थान सम्भव है। कृषि उत्थान की पहली आवश्यकता व आधारभूत आगत सिंचाई है जिसकी पर्याप्त सुलभता कृषि में इन्द्रधनुशी क्रान्ति ला सकती है और पर्याप्त सिंचाई के लिए जल का विशाल भण्डार होना आवश्यक है क्योंकि दुनिया की कुल जल खपत का अकेले 69 प्रतिशत कृषि में, शेष 23 प्रतिशत औद्योगिक और 8 प्रतिशत घरेलू कार्यों में प्रयुक्त होता है। कृषि पर निर्भर देश होने के नाते सिंचाई भारत की रीढ़ की हड्डी है। कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक किसान के खेत को सिंचाई का पानी पहुँचाने के उद्देश्य से व सूखे की समस्या को स्थाई रूप से दूर करने के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' की शुरुआत की गई है। इस योजना को वित्तीय मन्त्रिमण्डल समिति ने एक जुलाई 2015 को 5 वर्ष (2015-16 से 2019-20) के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की है। हर खेत को पानी देने पर ध्यान केन्द्रित करने की दिशा में एक सही कदम है। वर्तमान में चल-रही तीन योजनाओं का विलय कर पी०एम०के०एस०वाई० बनाई गई है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय:

प्रस्तुत शोध-पत्र का अध्ययन क्षेत्र जनपद पीलीभीत है जो रुहेलखण्ड भौगोलिक क्षेत्र का लघु भू-भाग है। इसका अक्षांशीय विस्तार 28° 6' उत्तरी अक्षांश से 28° 53' एवं देशान्तर्रीय विस्तार 78° 57' पूर्वी देशान्तर से 80° 27' तक विस्तृत है तथा क्षेत्रफल 3765.40 वर्ग किलोमीटर है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तर में नैनीताल जनपद (उत्तराखण्ड) दक्षिण में शाहजहाँपुर जनपद, पूर्व में जनपद लखीमपुर खीरी तथा पश्चिम में शाहजहाँपुर जनपद स्थित है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से 01 जनपद मुख्यालय (पीलीभीत), 03 तहसील मुख्यालय पीलीभीत, पूरनपुर एवं बीसलपुर, 07 विकासखण्ड मुख्यालय, 78 न्यायपचायत, 599 ग्राम पचायत एवं 1348 राजस्व ग्राम है। स्थानीय निकाय एवं प्रशासनिक दृष्टि से 03 नगर पालिका परिषद एवं 06 टाउन एरिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 20.31 लाख व्यक्ति है जिसमें 10.72 लाख पुरुष एवं 9.59 लाख स्त्रियां शामिल है।

ऐतिहासिक दृष्टि से पीलीभीत कचहरी के रूप में एक गांव था जिसका नाम मुड़िया था। उनकी उपजाति पीरिया थी। पीरिया बंजारों के सरदार ने चोर डाकुओं से रक्षा पाने के लिए गांव के उत्तर की ओर एक पीले रंग की दीवार बनवाई। सरकार की उपजाति पीरिया तथा पीली दीवार (भीत) में मिलकर पीरिया भीत पीलीभीत बना।



क्षेत्रीय कृषि-सिंचाई सम्बन्धी मुख्य संकल्पनाएं

जनपद पीलीभीत में क्षेत्रीय स्तर पर कृषि एवं सिंचाई सम्बन्धी कुछ मुख्य संकल्पनाएं इस प्रकार हैं-

1. यह पूर्णतः कृषि प्रधान क्षेत्र है समस्त आर्थिक क्रियायें कृषि क्षेत्र द्वारा ही निर्धारित है अर्थात् कृषि ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।
2. अध्ययन क्षेत्र में कृषि व्यवसाय की ओर अग्रसर है। खाद्यान्न फसलों की तुलना में अब क्षेत्रीय स्तर पर गन्ना, मेन्हा घास, आलू,

साक-सब्जी, बागवानी व तिलहनी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ा है जिसमें सिंचाई की मांग तेजी से बढ़ी है।

- वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता, वर्षा में कमी के कारण बढ़ती कृषि तकनीकी के कारण 'सिंचाई' कृषि का एक मात्र आधार बनती जा रही है।
- क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई का प्रारम्भिक रूप परिवर्तित हुआ है अर्थात् ढेकुली, रहट, बमकुओं, पक्के कूपों का स्थान अब नलकूपों व डीजल चालित पम्पिंग सैट्स ने ले लिया है जो सस्ते व सर्वसुलभ सिंचाई के साधन है।
- भूपृष्ठीय जल स्रोतों अर्थात् नदियों, नालों, तालाबों तथा सिकुड़ते जाना या लुप्त हो जाना तथा अवमृदा जल रिचार्ज की प्रक्रिया धीमी हो जाना तथा अवमृदा जल का तीव्र गति से दोहन होने के कारण अवमृदा जल स्तर का प्रतिवर्ष 0.50 मीटर नीचे जाना मुख्य समस्या है।

प्राकृतिक दशायेँ

जनपद पीलीभीत एक समतल उपजाऊ भू-भाग है, जो गंगा की ऊपरी घाटी में विस्तृत रुहेलखण्ड भौगोलिक क्षेत्र का उत्तर-पूर्वी भाग है। इस मैदानी भू-भाग का ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व को है। इसकी औसत ऊँचाई 172 मीटर है। यहाँ पर परतदार अवसादी चट्टानों का विस्तार है जिनकी गहराई 1000-1500 मीटर है तथा इनका निर्माण यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाए गए हिमालयन अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। अध्ययन क्षेत्र की जलवायु शुष्क मानसूनी है। वार्षिक औसत तापमान 25.60 डिग्री सेन्टीग्रेड, वार्षिक वर्षा 95 सेन्टीमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता 75 प्रतिशत एवं वायु की गति 5.80 किलोमीटर प्रतिघण्टा है। लघु शीतकाल, लम्बी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में गर्म 'लू' हवाओं का चलना, शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा मुख्य विशेषतायेँ है। शारदा, कटना, खन्नौत, कैमुआ, गोमती, देवहा, खकरा में यहाँ बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र कृषि प्रधान है। उत्तरी भाग में चिकनी, मध्य भाग में जलोढ़ एवं दक्षिणी भाग में दोमट मिट्टी का विस्तार है। मानसूनी पतझड़ी प्राकृतिक वनस्पति वनों का क्षेत्र 37.38 प्रतिशत सामाजिक व कृषि वानिकी में सड़कों, नहरों, मेढों पर वृक्षारोपण अन्य मुख्य विशेषतायेँ है।

आर्थिक दशायेँ:

जनपद पीलीभीत की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। कृषि के साथ पशुपालन यहाँ का दूसरा मुख्य व्यवसाय है। कुल कार्यशील जनसंख्या का 55 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि व पशुपालन क्षेत्र में ही कार्यरत है। कृषि भूमि 62.55 प्रतिशत है। पशुपालन की संख्या 5.45 लाख है जिसमें महिष वंशीय पशुधन 2.72 लाख है। कुल विद्युत उपभोग 258473 हजार किलोवाट घंटा है जिसमें कृषि विद्युत शक्ति में विद्युत उपभोग 19.72 प्रतिशत है। कुल विद्युतीकरण ग्राम 97 प्रतिशत है। ऊर्जाकृत नलकूपों की संख्या 8555 है। परिवहन साधनों की दृष्टि से सड़क एवं रेल की सुविधा उपलब्ध है। सड़क मार्ग की

लम्बाई 3180 किलोमीटर है। जबकि रेल मार्ग की लम्बाई 132 किलोमीटर है जिन पर 20 रेलवे स्टेशन स्थित है। वायु परिवहन की सुविधा नजदीकी शहर बरेली में उपलब्ध है। अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीय कृत बैंक 104, क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक 25 एवं अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक 11 है। कुल बैंकों में जमा धनराशि 26896337 हजार रुपये है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण 85.18 प्रतिशत है। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की कुल संख्या 83 है जिनके द्वारा 2360831 हजार रुपये ऋण वितरित किया गया है।

कृषि भूमि

जनपद पीलीभीत में कृषि भूमि 231010 हेक्टेयर है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में यह भूमि क्रमशः 230446 एवं 564 हेक्टेयर है। एक से अधिक बार भूमि 163896 हेक्टेयर है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में यह भूमि क्रमशः 163557 एवं 339 हेक्टेयर है। सकल बोया गया क्षेत्रफल 394906 हेक्टेयर है जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में इस भूमि का क्षेत्रफल क्रमशः 394003 एवं 903 हेक्टेयर है। जैसा कि तालिका— में दर्शाया गया है।

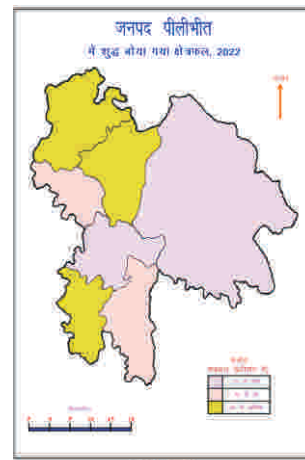
तालिका संख्या – 01

जनपद पीलीभीत में कृषि भूमि का वितरण, 2021-2022

क्रम सं०	विकासखण्ड	भूढ़ बोया गया क्षेत्रफल		एक से अधिक बार बोया क्षेत्रफल		सकल बोया गया क्षेत्रफल
		क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रतिशत	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रतिशत	
1	अमरिया	36270	82.55	28345	78.14	64615
2	मुरौरी	21462	79.85	14842	69.15	36304
3	ललीरीखेड़ा	14675	75.45	8111	55.27	222786
4	बरखेड़ा	22600	72.54	12998	57.51	35598
5	बिलसण्डा	27533	76.83	18289	66.42	45822
6	बीसलपुर	21568	80.63	14295	66.28	35863
7	पूरनपुर	86338	44.77	66677	77.22	153015
	योग ग्रामीण	230446	61.15	163557	70.97	394003
	नगरीय योग	5641	35.76	339	60.10	903
	योग जनपद	231070	61.05	163896	70.95	394906

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग

जनपद पीलीभीत 2022।



कृषि भूमि उपयोग

जनपद पीलीभीत में सकल बोया गया क्षेत्रफल 394906 हेक्टेयर है जिसमें 166925 हेक्टेयर रबी की फसल, 222219

हेक्टेयर, खरीफ की फसल एवं 5762 हेक्टेयर जायद की फसल उगाई जाती है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में रबी की फसल 166427 हेक्टेयर, खरीफ की फसल 221825 हेक्टेयर एवं जायद की फसल 5751 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। जिसका सकल बोया गया क्षेत्रफल 394003 हेक्टेयर है। जबकि नगरीय क्षेत्र में सकल बोया गया क्षेत्रफल 903 हेक्टेयर है जिसमें रबी की फसल 498 हेक्टेयर, खरीफ की फसल 394 हेक्टेयर एवं जायद की फसल 11 हेक्टेयर पर उगाई जाती है। जैसा कि तालिका- में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 02
जनपद पीलीभीत में कृषि भूमि का वितरण, 2021-2022

क्रम सं०	विकासखण्ड	सकल बोया गया क्षेत्रफल			योग	कृषि गहनता
		रबी की फसल	खरीफ की फसल	जायद की फसल		
1	अमरिया	29787	33940	888	64615	178
2	मरौरी	13847	21469	988	36304	169
3	ललौरीखेड़ा	6798	15484	504	22786	155
4	बरखेड़ा	13905	21482	211	35598	157
5	बिलसण्डा	19929	25721	172	45822	166
6	बीसलपुर	15135	20617	111	35863	166
7	पूरनपुर	67026	83112	2877	153015	177
	योग ग्रामीण	166427	221825	5751	394003	170
	नगरीय योग	498	394	11	903	160
	योग जनपद	166925	222219	5762	394906	180

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद पीलीभीत 2022।

जनपद पीलीभीत में कृषि गहनता 180 प्रतिशत है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में कृषि गहनता क्रमशः 170 एवं 160 प्रतिशत है।

सिंचाई:

जनपद पीलीभीत में सिंचाई साधनों में नहरों की लम्बाई 1002 किलोमीटर है। राजकीय नलकूपों की संख्या 204 है। निजी नलकूपों की संख्या 3372 है। डीजल चालित पम्पिंग सेट्स की संख्या 63998 है। जबकि इसके साथ ही अन्य प्रकार के साधनों की संख्या 11899 है। जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 03
जनपद पीलीभीत में सिंचाई साधनों का वितरण, 2021-22

क्रम सं०	विकासखण्ड	नहर लम्बाई किलोमीटर में	राजकीय नलकूप	निजी नलकूप	डीजल चालित पम्पिंग सेट्स	अन्य प्रकार के साधन
1	अमरिया	126	42	915	9530	246
2	मरौरी	73	62	317	7836	3847
3	ललौरीखेड़ा	97	15	42	6112	652
4	बरखेड़ा	117	18	66	8531	174
5	बिलसण्डा	129	23	296	7229	837
6	बीसलपुर	95	19	53	7053	449
7	पूरनपुर	365	25	1683	17707	5694
	योग ग्रामीण	1002	204	3372	63998	11899
	नगरीय योग	-	-	-	-	-
	योग जनपद	1002	204	3372	63998	11899

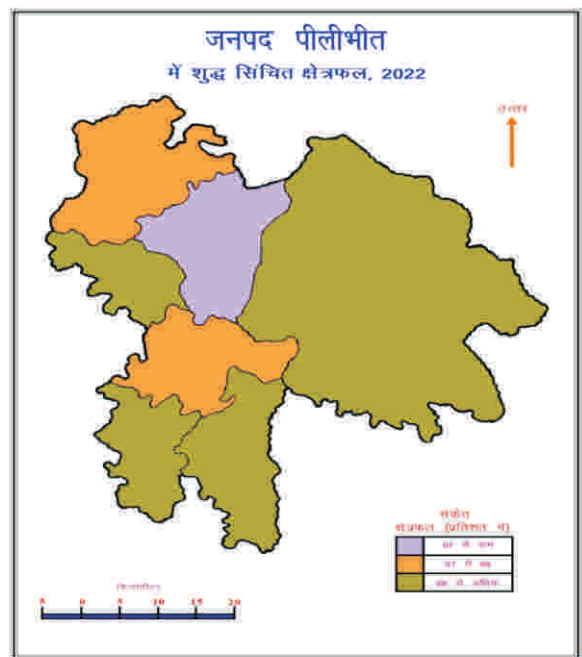
स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद पीलीभीत 2022

जनपद पीलीभीत में शुद्धसिंचित भूमि 229100 हेक्टेयर है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में क्रमशः यह भूमि 228538 एवं 562 हेक्टेयर है। एक से अधिक बार सिंचित भूमि 160891 हेक्टेयर है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में यह भूमि क्रमशः 160555 एवं 336 हेक्टेयर है। सकल बोया गया क्षेत्रफल 389991 हेक्टेयर है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में यह भूमि क्रमशः 389033 एवं 898 हेक्टेयर है। सिंचाई गहनता 170 प्रतिशत है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में सिंचाई गहनता क्रमशः 170 एवं 160 प्रतिशत है। जैसा कि तालिका- में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 04
जनपद पीलीभीत में सिंचाई क्षेत्रफल का वितरण 2021-2022

क्रम सं०	विकासखण्ड	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल		एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्रफल		सकल क्षेत्रफल		सिंचाई गहनता प्रतिशत में
		हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	
1	अमरिया	36093	99.51	27946	98.60	64039	99.10	156
2	मरौरी	21349	99.47	14604	98.40	35953	99.03	159
3	ललौरीखेड़ा	14623	99.10	7913	97.55	22536	98.90	158
4	बरखेड़ा	22397	99.50	12860	98.93	35257	99.04	157
5	बिलसण्डा	27325	98.25	18130	99.13	45455	99.20	166
6	बीसलपुर	21466	99.05	14166	99.09	35632	99.35	165
7	पूरनपुर	85285	98.78	64936	97.38	150221	98.17	176
	योग ग्रामीण	228538	99.17	160555	98.16	389093	98.75	170
	नगरीय योग	562	99	336	99.11	898	99.45	160
	योग जनपद	229100	99.18	160891	98.17	389991	98.75	170

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद पीलीभीत 2022।



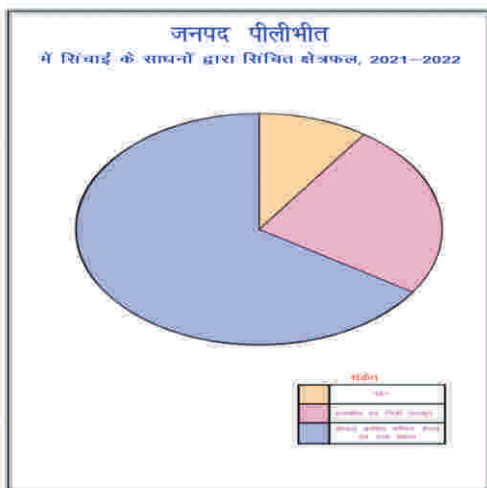
जनपद पीलीभीत में शुद्धसिंचित क्षेत्रफल 229100 हेक्टेयर है जिसमें नहरों द्वारा 9548 हेक्टेयर नलकूपों द्वारा 27345 हेक्टेयर, डीजल

चालित पम्पिंग सैट्स द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 190083 हेक्टेयर एवं अन्य प्रकार के साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 2124 हेक्टेयर है। ग्रामीण क्षेत्र में शुद्धसिंचित क्षेत्रफल 228538 हेक्टेयर है जिसमें नहरों द्वारा 9485 हेक्टेयर, नलकूपों द्वारा 27060 हेक्टेयर, डीजल द्वारा 2124 हेक्टेयर सींचा जाता है। जबकि नगरीय क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 562 हेक्टेयर है जिसमें नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 63 हेक्टेयर नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 285 हेक्टेयर एवं डीजल चालित पम्पिंग सैट्स द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 214 हेक्टेयर है। जैसा कि तालिका- में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 05
जनपद पीलीभीत में सिंचाई क्षेत्रफल का वितरण
2021-2022

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल हेक्टेयर में						
क्रम सं०	विकासखण्ड	नहर	नलकूप	डीजल चालित पम्पिंग सैट्स	अन्य प्रकार के साधन	योग
1	अमरिया	791	2890	32158	254	36093
2	मरौरी	815	2770	17454	310	21349
3	ललीखेड़ा	1863	3225	9140	395	14623
4	बरखेड़ा	1093	2990	18024	290	22397
5	विलसण्डा	1313	3105	22582	325	27325
6	बीसलपुर	336	3005	17855	270	21466
7	पूरनपुर	3274	9075	72656	280	85285
	योग ग्रामीण	9485	27060	189869	2124	228538
	नगरीय योग	63	285	214	—	562
	योग जनपद	9548	27345	190083	2124	229100

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद पीलीभीत 2022।



निष्कर्ष:

जनपद पीलीभीत में 'कृषि' क्षेत्रीय विकास की मुख्य धुरी है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं के विकास के लिए प्रयुक्त भूमि, प्राकृतिक आपदायें एवं दुर्लभ सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप कृषि भूमि को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में वास्तविक कृषि क्षेत्र 231.01 हजार हेक्टेयर है जो सकल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 61.05 प्रतिशत है। कृषि

क्षेत्र के परिमाणात्मक वृद्धिहेतु किए जा रहे प्रयासों के चलते वर्ष 2025 में 240.10 हजार हेक्टेयर होने का अनुमान है। एक से अधिक बार क्षेत्रफल 163.89 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 165 हजार हेक्टेयर हो जायेगा। सकल बोया गया क्षेत्रफल 394.90 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 405.10 हजार हेक्टेयर का अनुमान है। भावी अनुमानित कृषि क्षेत्र की भाँति ही जनपद पीलीभीत में सिंचाई क्षेत्र में भी बढ़ोत्तरी होगी। यह तभी सम्भव है जबकि सिंचित जैसे कृषि संसाधनों को क्षेत्रीय स्तर पर तीव्रता से विकसित किया जा सकता है जिसका विवरण इस प्रकार है—

1. जनपद पीलीभीत में कृषि के अन्तर्गत शुद्धभूमि 61.05 प्रतिशत है जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। बंजर, ऊसर एवं परती भूमि को कृषि में परिवर्तित किये जाने की जरूरत है।
2. मिट्टियाँ कृषि कार्य के लिए भौतिक आधार बनाती है। जनपद पीलीभीत में मिट्टियाँ उर्वरता लिए हुए है किन्तु समय-समय पर इनका परीक्षण आवश्यक है।
3. कृषि कार्य में बड़े पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। कृषि को सस्ती दर पर ऋण उपलब्धता प्रदान किए जाने की जरूरत है।
4. कृषीय पदार्थों के मूल्यों में भिन्नता कृषि में जोखिम तथा अनिश्चितता का मूल कारण है। अध्ययन क्षेत्र में कृषकों को फसलों का उचित समर्थन मूल्य दिलाने की जरूरत है।
5. कृषि फसलों की बुवाई के समय खाद, बीज एवं कीटनाशक की उपलब्धता आवश्यक है। इसके साथ ही कृषि में मशीनीकरण पर जोर देने की जरूरत है।
6. क्षेत्रीय स्तर पर जल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु खेतों की ऊँची मेढ़बन्दी, नदियों व नालों पर छोटे-छोटे अवरोध व बांधों का निर्माण जिनकी ऊँचाई 4 से 6 मीटर हो तथा मिट्टी से बने हो ताकि वर्षा का जल रूककर रिचार्ज हो सके।
7. जनपद पीलीभीत में वर्तमान शुद्धसिंचित क्षेत्र 240.10 हेक्टेयर को भावी मांग को दृष्टिगत करते हुए नहरों, नलकूपों, डीजल चालित पम्पिंग सैट्स तथा अन्य प्रकार के साधनों की क्षमता में सुधार करके क्षेत्र को सिंचित किए जाने का प्रस्ताव है।
8. जनपद पीलीभीत में वर्तमान नहरों की क्षमता में वृद्धि करके राजकीय नलकूपों एवं निजी नलकूपों एवं निजी नलकूपों को कम से कम 15 घन्टे विद्युत आपूर्ति करके, उनके रख रखाव में सुधार करके खुली नालियों व गूलों के स्थान पर पाइपों से जल पहुँचा कर न केवल संरक्षण किया जा सकता है, अपितु उनकी सिंचन क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
9. लघु सिंचाई योजना के तहत राजकीय अनुदान, सिंचाई उपकरण प्रशिक्षण व अनुसन्धान हेतु समुचित कदम उठाये जाने आवश्यक है।
10. वर्तमान समय की सिंचाई पद्धतियों की अपेक्षा स्पिंकल एवं स्प्रेयर सिंचाई पद्धतियों के प्रचलन पर बल दिए जाने की आवश्यकता है ताकि कम से कम जल का उपयोग करके अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है।

सन्दर्भ

1. तिवारी, आर0सी0 एवं सिंह, बी0एन0 2010:कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद पृष्ठ-10
2. गौतम, अलका 2010: कृषि भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद पृष्ठ-25
3. कुमार, ब्रजेश 2011:बेहतर कृषि प्रबन्धन समय की आवश्यकता, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका अगस्त अंक पृष्ठ-6
4. मीणा, वासुदेव 2017:सिंचाई प्रणालियों की आवश्यकता और उनके प्रकार, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका नवम्बर अंक पृष्ठ-16
5. मुखर्जी, सच्चिदानन्द 2016 आर्थिक विकास में जल संसाधन, योजना मासिक पत्रिका जुलाई अंक पृष्ठ-10
6. सिंह, गजेन्द्र मधुसूदन 2017:भारत में सिंचाई परियोजनाओं का आंकलन, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका नवम्बर अंक पृष्ठ 37
7. सिरोही, नरेश 2018: कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां और चुनौतियां, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका जून अंक पृष्ठ-22
8. चौहान, पी0आर0 एवं प्रसाद 2004:भारत का वृहद भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर पृष्ठ-65
9. जिला विकास पुस्तिका, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जनपद पीलीभीत 2022 ।
- 10.जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद पीलीभीत 2022 ।

निर्देशक

डॉ0 एन0 यू0 खान

पूर्व प्राचार्य

जी0एफ0 (पी0जी0) कॉलिज,

शाहजहाँपुर

शोधार्थी

रामाकान्त

सारांश

विद्रोही अपनी कविताओं के माध्यम से धर्मसत्ता, राजसत्ता व पितृसत्ता के विरुद्ध पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। वे जनकवि हैं, इसलिए जनता के दुख-दर्द को अपनी कविताओं में प्रमुखता से स्थान देते हैं। इन कविताओं में 'विद्रोही' का वैयक्तिक दुख नहीं है, उनका दुख पूरे वंचित समुदाय का है। वे राजा के साथ नहीं रह कर प्रजा के साथ तथा रानी के साथ न रह कर नौकरानी के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें बेगुनाह शोषित जनता और नौकरानियों की चिंता भी बहुत है, जो इस धर्मसत्ता और राजसत्ता के सामूहिक शोषण के शिकार हैं। उनकी चिंता में समाज का हर शोषित और वंचित तबका शामिल है जिस पर अकारण ही जुल्म और ज्यादाती की जाती है। वे अपने दुखों को कहीं भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनमें आपस में भी एकता का अभाव है। यदि इन वंचितों, शोषितों में एकता हो जाए और उन्हें कोई नेतृत्व मिल जाए तो निश्चित रूप से वे शोषकों का समूल नाश कर देंगे। लेकिन उनका शोषक भी बहुत शातिर है। वह इन्हें जाति, धर्म, सम्प्रदाय में बाँटकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। वे भी धर्म रूपी इस 'अफीम' के मकड़जाल में उलझे हैं, उन्हें इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। विद्रोही इस शोषित जनता को इसी मकड़जाल से निकालने का प्रयास अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं।

विद्रोही की कविताएँ महिला मुक्ति का 'मैग्नाकार्टा' हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि स्त्रियों का सबसे ज्यादा शोषण धर्म ने किया है। इन्हीं धर्मग्रंथों में वेद, पुराण, स्मृतियों, टीकाओं एवं उनके व्याख्याकारों ने औरतों को बेड़ियों में जकड़ने तथा उन्हें गुलाम बनाए रखने का हर हथकंडा अपनाया। सदियों से इन जुल्मों और ज्यादातियों को महिलाओं ने सहा तथा अपने आँसुओं को आँखों से बाहर भी नहीं आने दिया। विद्रोही ने औरतों के ऊपर हो रहे इन जुल्म और ज्यादातियों को बचपन से ही देखा था। वे बड़े हुए, समय बदला, स्थान बदला लेकिन नहीं बदल रहा था तो स्त्रियों के ऊपर हो रहा जुल्म। इसी कारण विद्रोही अपनी कविताओं के माध्यम से औरतों के ऊपर हो रहे अमानुषिक अत्याचार के खिलाफ डट कर खड़े ही नहीं हैं बल्कि दो दो हाथ करने को भी तैयार हैं। औरत नामक अपनी कविता में इस शोषणकारी और अत्याचारी पूरी व्यवस्था का पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, क्योंकि बिना पोस्टमार्टम के हकीकत सामने आने से रही। वे औरतों के ऊपर हो रहे इस मामले में कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखलाना चाहते हैं। वे पूरी तरह तहकीकात करके मामले की जड़ तक जाना चाहते हैं। स्त्रियों को जानते हैं, उनकी बेबसी को भी समझते हैं। इसलिए उन्हें यह भी पता है कि समाज में दुराचार या दहेज के नाम पर आज भी स्त्रियों

को जलाया जाता है या उन्हें कुएँ में भी धकेल कर मार दिया जाता है। कभी-कभी तो स्त्रियों को मारकर रेल की पटरियों पर छोड़ दिया जाता है और इसे 'आत्महत्या' करार दे दिया जाता है। विद्रोही ऐसे मामलों के पुनः पड़ताल के पक्ष में मुखरता से खड़े हैं। वे इतने पर ही नहीं रुकते हैं। वे आगे कहते हैं कि मैं उन औरतों को – "जो / कुएँ में कूदकर या चीता में जलकर मरी हैं / फिर से जिंदा करूँगा / और उनके बयानों को दोबारा कलमबंद करूँगा / कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया / कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया / कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई।"¹ वे अपने पास-पड़ोस, गाँव गिराँव की तमाम औरतों को बचपन से ही जानते थे और देखते ही आए थे कि इनमें तमाम औरतों ने तो ताउम्र कभी अपने घर के आँगन और चहारदीवारी को भी पार नहीं किया था। घर से बाहर वे नहीं अपितु उनकी लाश ही निकली। उनकी मृत्यु के कारण भी अज्ञात ही रहे। इन्हीं सब कारणों से विद्रोही फिर से पूरी तहकीकात करना चाहते हैं, ताकि कहीं भी कुछ छूट न जाए।

'विद्रोही की कविताओं में भूख, भय की बात, व्यवस्थागत जुल्म, संवेदना की सतह पर दर्ज की गई है इसलिए किसी मोहभंग, प्रामाणिक अनुभव, भोगा हुआ यथार्थ अस्मिता का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ हर सभ्यता मुहाने पर औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ पाई जा रही हैं इसलिए काव्य में स्त्री के पक्ष को सिनेमाई प्रेमालाप, जेंडर या यौनिकता में उलझाने की जरूरत नहीं पड़ी।' विद्रोही तीन-तीन बहनों के भाई थे। उन्हें बखूबी पता था कि समाज में स्त्रियों के प्रति क्या सोच है? इसीलिए पूँजीवादी और सामंतवादी समाज में औरतों का तन और मुर्द का कफ़न बिकता देखकर उनके प्यार का सोता सूख जाता है। ऐसी स्थिति में प्रेमालाप कैसे हो सकता है? इन्हीं कारणों से विद्रोही कहते हैं –

"मैं तुम्हें इसलिए प्यार नहीं करता

कि तुम बहुत सुन्दर हो

और मुझे बहुत अच्छी लगती हो,

मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ।

मुझे लगता है / क्रांति होगी / तुम्हारा सौन्दर्य मुझे / बिस्तर से समर की ओर ढकेलता है।

और मेरे संघर्ष की भावना / सैकड़ों तो क्या / सहस्त्रों गुना बढ़ जाती है।"²

विद्रोही औरत को अपनी ताकत बना लेना चाहते हैं और इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए कहते हैं कि तुम कहो तो मैं तलवार उठा लूँ / तुम कहो तो मैं दुनिया को पलट दूँ / विद्रोही की कल्पना

‘स्त्री’ को याचक बनाने की नहीं है, अपितु वे उनके हाथों में सीधा बंदूक देखना चाहते हैं। जिससे वे खुद अपने शोषकों से निपट लें। ठीक उसी तरह जिस तरह वीरांगना फूलन देवी ने अपने सामंतवादी शोषकों के खिलाफ बंदूक उठाकर, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। जब आपके ऊपर जुल्म की इतना हो जाए, न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाएँ, तो स्वाभाविक है कि अंतिम रास्ता हथियार उठाना ही तो बचता है।

विद्रोही धर्म नामक कविता में बाकायदे स्त्रियों के शोषण से जुड़े कई मुद्दे हमारे सामने रखते हैं। इनमें एक प्रमुख मुद्दा है ‘स्त्री-स्वास्थ्य’ का गाँवों में आज भी देशी घी, गुड़ या अन्य कई घरेलू उत्पाद खासकर मेहमानों के लिए बचाकर रखा जाता है। जब कभी अतिथियों का घर पर आगमन होता है तो महिलाओं द्वारा उन्हें विशिष्ट व्यंजन बनाकर परोसा जाता है, जिसमें देसी घी की पूड़ी, खीर या ऐसे ही अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं। विशेष बात यह भी है कि इन देसी अमूल्य उत्पादों को स्त्रियाँ अपने बेटे-बेटियों एवं अन्य परिजनों से भी छुपाकर रखती हैं ताकि ऐन मौके पर घरवालों की इज्जत ना जाने जाए। आखिर मेहमान तो ‘अतिथि’ है। उसके आने का दिन व समय तो ज्ञात रहता नहीं? लेकिन धर्म के मकड़जाल में उलझे लोग धर्म के नाम पर खुशी-खुशी पूजा-पाठ में, मंदिरों में अपने इन अनमोल देशी उत्पादों दूध एवं घी इत्यादि को चढ़ा देते हैं। कबीर ने इसी पर कटाक्ष करते हुए बहुत पहले ही लोगों को आगाह करते हुए कहा था कि लाडू लावर लापसी पूजा चढ़े अपार। पूजी पुरारा ले चला दे मूरति के मुख छार। लोगों की इसी मूर्खता पर विद्रोही भी कहते हैं – “एक शंख बजता है। और बेटे से छिपाया घी/उधार का गुड़/ मेहमानों का अरवा/ चढ़ जाता है शंकर जी के लिंग पर।”³ इन अनमोल पदार्थों के बदले इन दानशील वंचितों को क्या मिलता है? उन्हें मिलते हैं उन्हीं के दूध से बनी खीर से पैदा हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके वंशज! जो उन्हीं श्रमजीवी शूकों का वध करते हैं और उनके ही गाँवों को उखाड़ फेंकने पर है अमादा रहते हैं। वही धर्म और अंधविश्वास तथा ईश्वर का भ्रमजाल और शोषणतंत्र की संरचना। जिसमें फंसकर गरीब तथा निरीह जनसमुदाय फड़फड़ा कर तड़प रहे हैं। उनकी मुक्ति के सारे दास्ते उसी में उलझते जाते हैं।

यूनिसेफ ने अक्टूबर 2019 में जारी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन 2019 नामक अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में हर पाँच में से दो बच्चे खून की कमी से ग्रस्त हैं। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 69 प्रतिशत मौतों का कारण कुपोषण है। भारत में हर दूसरी महिला में खून की कमी है। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में खून की कमी सबसे अधिक व्याप्त है। किशोर लड़कियों में खून की कमी किशोर लड़कों से दोगुनी है। इस प्रकार भारत में करोड़ों महिलाएँ व बच्चे ‘कुपोषण एवं एनीमिया’ से असमय काल के गाल में समा जाते हैं और उसी तथाकथित विश्वगुरु ‘भारत’ में

प्रतिवर्ष करोड़ों लीटर दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जो बहकर चला जाता है। और जीवाणु-विषाणु पैदा करता है। निश्चित ही यह दूध लाखों महिलाओं और बच्चों को ‘कुपोषण और एनीमिया’ से बचा सकता था। लेकिन बकौल ‘विद्रोही’ “धर्म आखिर धर्म होता है/ जो सुअरों को भगवान बना देता है/ चढ़ा देता है नागों के फन पर / गायों का थन।”⁴ विद्रोही धर्म की विकृति में फँसे लोगों को इन्हीं कारणों से सिर्फ निकालना ही नहीं चाहते बल्कि वे इस धरती पर से भगवान को ही उखाड़ फेंकने की बात करते हैं।

वंचित तबकों की यह सभी महिला पात्र विद्रोही की कविताओं में एक प्रतीक हैं। ये सभी उस शोषित, वंचित, सर्वहारा तबके का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अपने श्रम के बल पर जीवित हैं। जिनके यहाँ इज्जत से मिली ‘दो जून’ की रोटी ज्यादा महत्व रखती है। यहाँ पर जाति, धर्म या सम्प्रदायगत कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। इन्हीं कारणों से विद्रोही इनके पक्ष में मुखरता से खड़े हैं। इन्हें बचाने को विद्रोही प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वे कहते हैं कि “भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी/जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा/ मैं नहीं जानता/ लेकिन जो भी होगी/ मेरी बेटि होगी/ मैं यह नहीं होने दूँगा।”⁵ समकालीन कविता में स्त्रियों के पक्ष में खड़ी इस प्रकार की कविताओं का हम अभाव पाते हैं, जिसमें कोई भी कवि इन शोषित और पीड़ित स्त्रियों के पक्ष में इतनी मुखरता से खड़ा हो और इतना मारक प्रहार करता हो।

“विद्रोही की कविताओं में जिस तरह के बिंब देखने को मिलते हैं, अन्यत्र हिंदी साहित्य में दुर्लभ है।... विद्रोही अकेला कवि है जिसने ‘निजी सम्पत्ति’ के सारे मानकों को तोड़ फोड़कर फेंक दिया और जीवन भर मजलूमों की आवाज को कुव्वत दी।”

“विद्रोही आजीवन उपेक्षित रहे। उनके किसी भी पक्ष का मूल्यांकन नहीं हो सका है। विद्रोही खुद कहते हैं कि जो कोहिनूर होते हैं वे बेनूर होते हैं। करीब तीन दशकों से विद्रोही अघोषित तौर पर जेएनयू के स्थायी नागरिक बने हुए थे। उनकी झुर्रियाँ जनपक्षधरता, संघर्ष और जिजीविषा का लंबा इतिहास समेटे हुए थीं।”⁶

यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि जिस जेएनयू में विद्रोही ‘कविता के नए प्रतिमान’ गढ़ रहे थे, उसी जेएनयू में हिंदी विभाग सहित अन्य विभागों के प्रख्यात वामपंथी प्रोफेसरों ने भी उन्हें उपेक्षित किया। कविता के नए प्रतिमान गढ़ने वाले पर कविता के नए प्रतिमान लिखने वालों ने भी नजर-ए-इनायत नहीं की। यहाँ विशेष रूप से यह भी विचारणीय है कि जिस ‘विद्रोही’ की कविताओं से जेएनयू का एक एक विद्यार्थी न केवल परिचित था बल्कि प्रायः सभी विरोध प्रदर्शनों में उनकी कविताओं का पाठ भी होता था, आखिर उसी जेएनयू के प्रोफेसरों की निगाह विद्रोही की कविताओं

पर कैसे नहीं पड़ी या उन्होंने जानबूझकर अनदेखा किया था? खैर इन प्रोफेसरों एवं बड़े-बड़े आलोचकों से इतर जेएनयू सहित देश भर के छात्रों, छात्र संगठनों, कविता प्रेमियों ने विद्रोही की कविताओं में अपना दर्द देखा, अपनी समस्याओं को देखा, अपनी मुसलसल जिंदगी के फसानों को देखा। उन्होंने इन कविताओं में अपने शोषणकर्ता को पहचाना और उसे बेनकाब होते देखा। इसीलिए विद्रोही की कविताएँ आमजन के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और दिनों-दिन उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। विद्रोही जैसे विशाल व्यक्तित्व वाले तथा लोकमानस में समाए हुए कवि को इन प्रोफेसरों और आलोचकों की दरकार भी नहीं है। वे इनसे बहुत आगे हैं। विद्रोही की मृत्यु पर दिलीप मंडल द्वारा व्यक्त किया गया विचार ही विद्रोही की लोकप्रियता की ऊँचाइयों को दर्शाने के लिए काफी है 'रमाशंकर यादव नाम का वह मासूम लड़का सुल्तानपुर, यूपी से पढ़ाई करने के लिए जेएनयू, दिल्ली आया था। तुमने रमाशंकर यादव को पढ़ाई पूरी नहीं करने दी। वह अपनी डिग्री कभी नहीं ले पाया। क्या विद्रोही की प्रतिभा से डरते थे तुम? अपने निठल्लेपन का अहसास था तुम्हें? अपने बौद्धिक बौनेपन का भी? लेकिन यह तो तुम्हें दिख रहा होगा प्रोफेसर कि एक तरफ अपार लोकप्रियता बटोरे विद्रोही की रचनाएँ हैं और दूसरी तरफ हैं तुम्हारी किताबें, जो सिलेबस में न हों, तो चार लोग उन्हें नहीं पढ़ेंगे। विद्रोही बिना डिग्री के तुमसे कोसों आगे निकल गया। छूकर दिखाओ। लिखो वैसी एक रचना.. है दम?'"

निष्कर्ष:-

इस तरह विद्रोही की कविताओं सामाजिक और आर्थिक तथा लैंगिक विषमता और भेद-भाव के सभी तंत्र और उसके रूपों बेबाकी से चित्रण भी है और शोषण के शिकंजों को उमेटकर मरोड़कर तोड़ फेंकने की ललकार भी है।

संदर्भ-सूची : -

1. रमाशंकर यादव, विद्रोही (2011) नयी खेती, इलाहाबाद: जसम प्रकाशन, पृष्ठ 27
2. वही, पृष्ठ 121
3. वही, पृष्ठ 06
4. वही, पृष्ठ 07
5. वही, पृष्ठ 39
6. प्रणय कृष्ण, नयी खेती, जसम प्रकाशन वर्ष 2011 की भूमिका पृष्ठ 3
7. दिलीप मंडल, वरिष्ठ पत्रकार, रमाशंकर 'विद्रोही' के निधन उपरान्त बी०बी०सी० हिन्दी को साक्षात्कार के दौरान, 09 दिसम्बर 2015।

शोध निर्देशक -

सुरेंद्र प्रसाद 'सुमन'

एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी - विभाग
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
कामेश्वर नगर, दरभंगा।

शोधार्थी -

जितेन्द्र नाथ 'ललन'

हिन्दी - विभाग
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
कामेश्वर नगर, दरभंगा।
ग्राम-गजवा, पोस्ट-भोजपुरौल,
पी०एस०-बिस्फी, जिला-मधुबनी,
बिहार, पिन कोड - 847121
मो०नं०-9122435754
जीतेंद्र नाथ ललन



ONE NATION ONE ELECTION: DOES INDIA NEED IT?

Ajit Singh



Abstract:

In today's world where functions of government are much complex and covers almost every aspect of the individual life, the accountability of the government toward the citizens is also increased. Anything which reduces the accountability of the government should be opposed and measures should be taken to held elected government more responsible and accountable to the common man. Holding elections in such a diverse and large country is not a duck soup, the politics played behind the organisation of elections make it a highly complex activity resulting in huge resource consumption and unnecessary oratory tussle between the leaders to delay in developmental projects. Opposition alleges the Modi government of trying to gain votes and manipulating the ordinary functioning of political system.

Key words: election, democracy, government, nation, commission, political parties

Introduction:

India, the world's largest democracy comprises of 28 states and 8 union territories where elections are held asynchronous from 1967 onwards, making it a never ending activity each year several states are geared for an election. There is a heated debate over this issue when the idea of holding simultaneous elections is floated by Prime Minister Narendra Modi, prior to him the idea of holding simultaneous elections is raised by many from time to time. *What does 'one nation one election' mean?* According to this notion direct elections which are held for lok sabha and state assemblies should be conducted simultaneously within a particular duration and phases. The tenure of these both is 5 years, so it asks for single voters list for both the elections and hence voters will cast their vote for both lok sabha and state assemblies on same day.

Historical Background:

Till 1967, elections for lok sabha and state assemblies were held simultaneously later when state assemblies of certain states were dissolved pre maturely by any reason, so it necessitated midterm elections and made the cycle of holding simultaneous elections desynchronised. Later demands were raised from time to time of holding elections at same time. For the first time law commission of India in 1983 in its annual report raised the possibility of returning to simultaneous elections.

- Later the 170th law commission under justice B P Jeevan Reddy in 1999 stated that “cycle of election every year

and in the out of season should be put to an end to”. Commission strongly suggested one election for lok sabha and all state assemblies once in 5 years.

- On 17th of December 2015, parliamentary standing committee on personnel, public grievances, law and justice submitted its report on “feasibility of holding simultaneous elections to the house of people (lok sabha) and state legislative assemblies. Under the chairperson Dr EM Sudarsana Natchiappan committee suggested that simultaneous elections would reduce massive expenditure incurred for conducting separate elections, will prevent policy paralysis because of imposition of model code of conduct and delivery of essential services would not be effected.

- On 8th of august 2018, law commission's chairperson justice BS Chauhan, addressed this issue of simultaneous elections and said it could not be held within existing constitutional framework and suggested appropriate amendments in Representation of Peoples act of 1951 and Rules of Procedure of lok sabha and state assemblies. However several benefits of holding simultaneous elections were also enumerated by commission.

Recent developments:

Prime Minister Narendra Modi on several occasions have raised the issue of holding simultaneous elections and called it a necessity for country. He supported elaborate discussions on election reforms including significance of having a single voters list in order to save unnecessary expenditure. Central government has constituted a committee of eight members headed by former president Ram Nath Kovind in order to explore the possibility of one nation one election on recently which has to examine this issue.

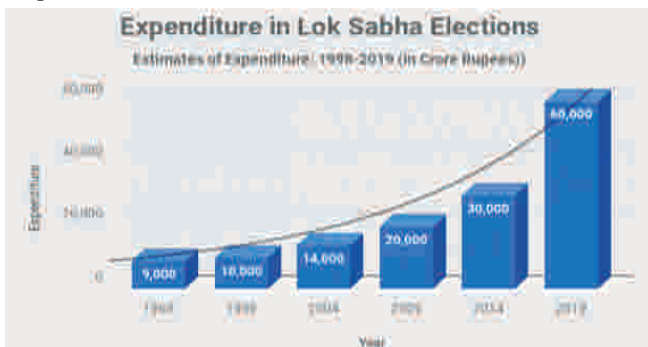
Opposition's stand over one nation one election:

Opposition went furious over this move of the central government and several political parties blamed ruling party of diverting the attention from actual issues of common man. **Aam Aadmi Party** leader Arvind Kejriwal accused the central government of floating unnecessary blandishments, he even asked of having more frequent elections as elections held leaders accountable for their actions and doing elections for lok sabha and all state assemblies once in 5 years would lead to

a delinking of leaders from masses. **Indian National Congress** declares this move as attack on the federal structure of the country. Party accused the intentions of the government over a fair discussion as the members of the committee made by central government have close affinity with the government.

Why one nation one election?

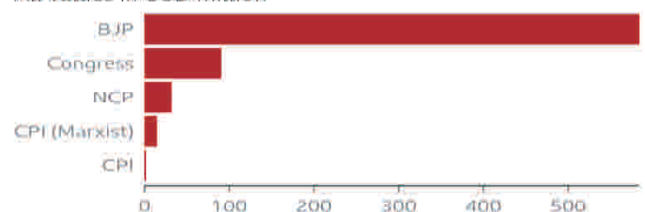
1. Massive expenditure: Elections in India are getting more and more expensive, centre for media studies in 2019 presented a report about the expenditure incurred by various political parties in 17th general elections and discovered that these are the costliest elections in world having expenditure of 55000 crore rupees. The report admits that this is only a fraction or a tip of iceberg of what actually have been spent. Apart from this amount, the expenditure incurred on assembly elections make the whole gamete of elections a very expensive activity. So it is said that if assembly elections are held simultaneously with lok sabha elections much expenditure could be averted.



Source: centre for media studies

1. Election funding and corruption: Substantial amount of research work has been published indicating a nexus between politicians and big business magnets for election funding. No mass party in today's date could contest election on subscription paid by members as it is very meagre. So ultimately the very nature of democracy changes and it become 'bourgeois democracy' from 'people's democracy'. Hence if the frequency of elections is somewhat reduced it will led to a decrease in recourse expenditure.

Donations received by Indian political parties in 2020-21
All values in USD million



have been seen in exercise of party politics would also be reduced if there is a fewer number of elections.

2. Voters list: A single voter list could serve in case of one nation one election and would prevent unnecessary expenditure as there is just duplication of effort and expenditure while preparing voters list each time for state and general elections.

3. Burden on administrative structure: Frequent elections effect the working of both civil staff and citizens. As a large number of government employees are involved in electoral process.

4. Save time and cost: From the perspective of common citizen it would save time for casting both the votes at same time and nobody can deny the expenditure on elections is increasing day by day. The time will also be reduced as model code of conduct will be imposed once for both the elections.

5. Effect on development: Political leaders spends a lot of time in campaigning for elections of one state or another therefore one election at a time for all states and lok sabha would give enough time to leaders for policymaking While other benefits of conducting simultaneous elections include increase in voters turnout, will reduce the circulation of black money, save governments unnecessary expenditure and other.

Why not 'one nation one election'?

1. Against federal structure of country: India has a multi-level government system and such a democratic set up allow people to choose the best suited representative at each level. Such choices of the voters could be based on their affinity to the party, the ideological aspect and belief in the candidate but assimilating all the aspects of these choices on certain broad national level issues would effect democratisation process and eventually the federal structure of the country.

2. Issue of political accountability: Another important consideration in this regard is the decrease in the accountability of the leaders, it is seen that in the process of frequent elections in one state or another government have the constant pressure from the people and opposition parties for their actions but while conducting elections once in a five years leader will be unreachable by the people and would appear after 5 years for being accountable for their actions.

3. Affect on state autonomy:It can easily be

concluded that in such a system of simultaneous elections if in any case a state government suffers no confidence in between the term than what would be done, imposing president rule for rest of the term will curb the very democratic spirit of people.

4. The case of regional parties: This is also the major concern of various political parties that conducting simultaneous elections would decrease the stature of regional parties as issues will be national and hence national parties could have an upper hand in that scenario. It is also claimed that Indian voters have a tendency of choosing same party in centre and state in case the elections are held together Haryana could be the best example and it is very much obvious that national parties with huge resources can easily mute the voices of smaller regional parties

5. Constitutional difficulty: The proposal for one nation one election is expected to pose significant challenge because it would demand amendment in the constitution to modify existing laws. Further it would require rectification by half of the states as it changes the federal arrangements of the constitution. Various articles of the constitution will be amended for this such as article 172 dealing with the duration of state legislature and dissolution of legislative council, article 174 which empowers the governor to dissolve the state assembly, article 365 regarding the imposition of president's rule in a state and various other articles might be changed in order to implement this.

6. Inadequate machinery: Holding simultaneous elections for centre and states would require as much the double the present number of Electronic Voting Machines (EVM) and the Voter Verified Paper Audit Trails (VVPAT).

7. Local issues will be overshadowed by national issues: It is also a concern of various political thinkers that in such a situation of conducting simultaneous elections local issues will be overshadowed by the national issues and will eventually decrease the accountability of state government for their actions.

A Comparative Perspective:

- **South Africa:** In South Africa elections to national assembly and provincial legislatures are held simultaneously in every 5 years. Since the end of apartheid regime the country had witnessed tough competitive elections having key issues such as inequality, land reforms and corruption. Economic inequality is the main issue in South Africa having simultaneous electoral system ruling party have been accused of biasness. Hence the focus of the elections area the national issues in the 2019 presidential elections of South Africa, it seems that local issues are somewhat behind the scene. Voters

apathy is also a major concern regarding South African electoral system despite more than 26 million registered voters local surveys suggest that 6 million people under the age of 30 are not on electoral rolls. Discontent over poor basic services can easily be observed among people but are not in the political agendas of political parties.

- **Sweden:** Sweden is a small country having a total population around 10 million. Elections to parliament, provincial legislature/county council and municipal assemblies are held concurrently in Sweden on the second of Sunday in September. Voters turnout is generally high in Sweden crossing over 80 percent. Being such a small country there leaves hardly any matter of local issues and national issues.

- **Belgium:** In Belgium elections for local, national and European level are held on same day and voters are obliged to vote. Population of Belgium is around 11 million. As the population is not so large, so there is no such observable pattern of local and national perspective in the elections of Belgium.

If India adopts simultaneous elections, then it would be the fourth country to do so. Perhaps India would be the first largest country because all other are very small countries, Belgium and Sweden having population around 140 times less than India. Most other large democracies do not have such system of concurrent elections.

Challenges and the way forward:

In India simultaneous were held for around 16 years but those times could not be taken into account while considering simultaneous in present times, as due to the advancement of the technology and other developmental aspects the issues and demand of those time cannot be compared to that of today's. However, it should not be the reason behind denying the idea that aims to reduce the unnecessary expenditure and claims to be development oriented. Reports of various law commissions should be taken into consideration while debating the issue of simultaneous elections. It is also a well known fact that implementation of Model Code of Conduct hampers the developmental works every few months. All political parties need to have a consensus whether country needs simultaneous elections or not, latest discussions should be held on this issue.

References:

1. https://lawcommissionofindia.nic.in/report_twentyfirst/
2. <https://thinkindiaquarterly.org/index.php/think-india/article/view/9479>

3. <https://thinkindiaquarterly.org/index.php/think-india/article/view/9479/5229>
4. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=one+Nation+one+election+India&btnG=#d=gs_qabs&t=1694585263302&u=%23p%3DRebb0tIKdUcJ
5. <https://www.thehindu.com/news/national/explained-what-is-the-debate-around-one-nation-one-election/article67267721.ece>
6. <https://www.thehindu.com/news/national/one-nation-one-election-need-of-india-says-pm-modi/article33183867.ece>
7. <https://www.thehindu.com/news/national/shah-meghwal-meet-kovind-days-after-he-was-appointed-head-of-one-nation-one-election-panel/article67277659.ece>
8. www.financialexpress.com%2Fopinion%2Fdangers-of-one-nation-one-election%2F3239864%2F
9. https://lawcommissionofindia.nic.in/cat_electoral_reforms/
10. https://www.researchgate.net/figure/The-Main-Ruling-Political-Partys-Seat-Share-Vote-Share-and-the-Difference_tbl2_259196370
11. <https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-62991256.amp>
12. <https://adrindia.org/content/election-expenditure-report>
13. https://indianexpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/indianexpress.com/article/opinion/columns/one-nation-one-election-cost-effective-blueprint-8924172/lite/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16945985946180&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.financialexpress.com%2Farticle%2Fopinion%2Fcolumns%2Fone-nation-one-election-cost-effective-blueprint-8924172%2F
14. <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/one-nation-one-election-will-bring-stability-says-uttar-pradesh-chief-minister-samajwadi-party-calls-it-a-malicious-attempt-to-establish-monarchy/article67260448.ece>
15. https://www.financialexpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.financialexpress.com/opinion/dangers-of-one-nation-one-election/3239864/lite/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16945985946180&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.financialexpress.com%2Fopinion%2Fdangers-of-one-nation-one-election%2F3239864%2F
16. <https://www.thehindu.com/news/national/not-worried-over-one-nation-one-election-biju-janata-dal/article67260924.ece>
17. https://www.indiatoday-in.cdn.ampproject.org/v/s/www.indiatoday.in/amp/india/story/one-nation-one-election-simultaneous-polls-law-commission-parliamentary-reports-2429834-2023-09-01?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16946552719230&_ct=1694655319230&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s
18. https://www.indiatoday.in/law-today/story/one-nation-one-election-simultaneous-polls-impact-on-constitution-laws-2429850-2023-09-01?_gl=1*11vf1zj*_ga*Y2h6MlIUUNm0tV3pYWFNGbURiWUNnT3RHATJpbDJYV0c5cGd3SIZZazkzX2JKZINXMXJkOEh4bEVBnFNkQy03eA..*_ga_6PTEQ0MXGP*MTY5NDY1NTMyMS4xLjEuMTY5NDY1NTMyMS4wLjAuMA
19. https://www.bqprime-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bqprime.com/amp/elections/india-election-expenditure-2019-lok-sabha-elections-was-the-worlds-costliest?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16946920784105&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.bqprime.com%2Felections%2Findia-election-expenditure-2019-lok-sabha-elections-was-the-worlds-costliest

Ajit Singh,
Research Scholar
Department of Political Science,
MDU Rohtak.



सारांश

भारत एक विशाल देश है इसकी सीमाएं दूर-दूर तक फैली हुई हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा 15200 किलोमीटर तथा कुल समुद्र की तटीय लम्बाई 7516 किलोमीटर है। भारत में अंडेमान निकोबार व बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की संख्या 572 है तथा देश में कुल 1208 द्वीप हैं। भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सन 1947 में भारत-पाकिस्तान का विभाजन जाति धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, जो बाद में इनमें भी आपसी विवाद रहने लगा। पाकिस्तान द्वारा बार-बार भारतीय सीमावर्ती इलाकों में घुसने के प्रयास करने की घटनाओं के कारण भारत को सख्त कदम उठाने पड़े। पाकिस्तान के टूटने और बांग्लादेश के जन्म से साबित हो गया है कि भारत देश का नेतृत्व मजबूत है और आज भी भारत की शान विश्व में अपनी साख जमाये हुए है। विश्व के राष्ट्र अपने देश के हित के लिए हमारे देश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। स्वतंत्रता पर भारतीय राज्य को केवल भौतिक आधार विरासत में मिला था जिसमें क्षेत्र और लोग शामिल थे, राज्य और इसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं को भारत को एक राष्ट्र राज्य के रूप में जोड़ने के लिए सामंजस्य प्रदान करना था। हालांकि हम काफी हद तक सफल हुए हैं लेकिन इस संबंध में असफलताएं भी हैं जिन्हें सरकार सही करने में प्रयासरत है।

परमाणु अस्त्रों की होड़ को उपमहाद्वीप में रोकना होगा। इस पर धन बहुत अधिक खर्च होता है, अतः आपसी मेल मिलाप से विकास के कार्य के लिए सार्थक प्रयास करने चाहिए। भारत-पाक संकट और कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। उपमहाद्वीप में बहुलतावादी लोकतांत्रिक सरकारों और गैर-बहुलतावादी सरकारों के एकात्मक रूप के बीच तनाव असंतुलन और तनाव को और बढ़ाता है। परिणामस्वरूप दक्षिण एशियाई संघर्षों में अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों की भागीदारी हुई है, इस प्रकार स्थिति ने अंतर क्षेत्रीय संबंधों को जटिल बना दिया है। आपसी अविश्वास के कारण ही उनके संबंधों में कटुता उत्पन्न हो रही है जो कि अभिशाप है। यह अविश्वास न केवल भारत और पाकिस्तान और भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के बीच संबंधों को बल्कि क्षेत्र के देशों के बीच संबंधों को भी प्रभावित करता है। इस क्षेत्र ने चार बड़े युद्ध देखे हैं। युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता है।

भारत और पड़ोसी देश

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भुटान, श्रीलंका, और मालदीव है। पड़ोसियों के बीच

की सीमाएँ भौगोलिक और जातीय दोनों दृष्टि से स्वाभाविक नहीं हैं। इसलिए सामाजिक तनावों का सीमा पार प्रभाव होना तय है। लोगों के बीच मित्रता और मेल-जोल के पारंपरिक संबंध तोड़फोड़, आतंकवाद और उग्रवाद को सहायता और बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी व्यवस्था बन गए हैं। क्षेत्रीय भू-राजनीतिक वातावरण के अशांत रहने की संभावना है, जो दक्षिण एशिया के भीतर संरचनात्मक राजनीतिक और सुरक्षा टकरावों के साथ मिलकर हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता रहेगा। सामाजिक तनाव विशेष रूप से जातीय और धार्मिक क्षेत्र में इसके सीमावर्ती चरित्र के कारण हमारे विरोधियों द्वारा शोषण के मुख्य क्षेत्र बने रहेंगे। दुनिया के तीन प्रमुख नारकोटिक केंद्रों में से दो, उत्तर पश्चिम में गोल्डन क्रीसेंट और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल ने दक्षिण एशिया को मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति संवेदनशील बना दिया है। तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए सीमा पार सांठगांठ ने पर्यावरण को हिंसा और संघर्ष के अनुकूल बना दिया है।

दक्षिण एशिया अन्य प्रायद्वीपों की तरह एक क्षेत्र या एक महाद्वीप तक ही सीमित नहीं है। उत्तरी पर्वतमाला इसे मध्य एशिया और चीन से जोड़ती है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप हिंद महासागर को छूती है और इसे दक्षिण अफ्रीकी देशों के आसपास मलक्का जलडमरूमध्य से दक्षिण अटलांटिक तक के समुद्री मार्गों की देखरेख करने की स्थिति में रखती है। पश्चिम में यह मध्य पूर्व पर स्थित है, जिसके साथ इसके ऐतिहासिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंध हैं और पूर्व में यह चीन और म्यांमार के युन्नान प्रांत से जुड़ा हुआ है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक प्राकृतिक पुल है, भारत के उत्तर पूर्व के साथ घनिष्ठ जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक संबंध हैं। दक्षिण एशिया का बहुमहाद्वीपीय आयाम एक वास्तविकता है, जिसकी गतिशीलता दक्षिण एशिया के देशों को प्रभावित करती रहेगी।

आंतरिक सुरक्षा समस्याएं और आतंकवाद

भारत की आंतरिक सुरक्षा की घरेलू गतिशीलता इसके सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में परिलक्षित होती है, जिसकी मुख्य विशेषता इसकी विविधता है। यह इसके समुदायों और जातियों, नस्लों और जातीय समूहों, भाषाओं और बोलियों, धार्मिक विश्वासों और रीति-रिवाजों और परंपराओं की विविधता में परिलक्षित होता है, संस्कृति की विभिन्न अभिव्यक्तियों के साथ, सभी एक गतिशील वातावरण में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य जटिल और विविध बना रहेगा। आतंकवाद, नशीले पदार्थों और ड्रग्स के कारण खतरे, छोटे हथियारों का प्रसार, ऊर्जा की आवश्यकता में कमी और अंग्रेजों ने भारतीय समाज में विविधता का फायदा उठाकर इसे सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर बांट दिया। 1960 के दशक में

धर्मनिरपेक्षता की राज्य नीति खतरे में आ गई जब राजनेताओं ने समुदायों की भावनात्मक संवेदनाओं में हेरफेर करना शुरू कर दिया और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक शब्दों को औपचारिक रूप से पेश किया गया और सांप्रदायिक वर्धार्मिक संप्रदायों पर समुदायों के वोट बैंक बनाए गए। एकता और धर्मनिरपेक्षता का माहौल बिगाड़ दिया गया है। यह इस संतुष्टि का अभाव है जो प्रभावित समूहों को खुद को मुखर करने के लिए प्रेरित करता है। टकराव की ऐसी स्थिति में समूह हितों की अभिव्यक्ति अपने आप में नृजातीय समुदायों की राजनीतिक लामबंदी का परिणाम होती है, जैसा कि इसका शोषण करता है। मूल कारण सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा है।

उत्तर पूर्व के प्रदेश और तनाव

असम और उत्तर पूर्व के अन्य क्षेत्रों में समस्याओं के लिए बांग्लादेश से सीमा पार प्रवास एक प्रमुख कारक है। यह बात कि बांग्लादेश के अप्रवासी सांप्रदायिक और जातीय तनाव का स्रोत है, असम आंदोलन और उसके बाद की घटनाओं से अच्छी तरह साबित हो गया था। भारत में 15 से 18 मिलियन अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी होने का अनुमान है, जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों में फैल गए हैं, जिनमें से अधिकांश असम में हैं। इनमें से 3 से 5 मिलियन अनुमानित अनुपात बिहार और पश्चिम बंगाल के अन्य पूर्वी राज्यों और उत्तर में दिल्ली और उससे आगे तक फैल गया है। जब तक जाँच नहीं की जाती है और पहले से पहचाने गए लोगों को निर्वासित नहीं किया जाता है, तब तक समस्या का हल सम्भव नहीं है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और चुनावी राजनीति ने आंदोलन और अशांति को जन्म दिया है। 1980 के दशक से चुनावी राजनीति के परिणामस्वरूप राज्य और राजनीति दोनों का प्रसार हुआ है, शासन की संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया है। जहाँ एक ओर इसने राजनीति के सामाजिक आधार का विस्तार किया है, वहीं दूसरी ओर कुत्सित राजनीति के कारण इसका राजनीतिकरण हुआ है और सभी समस्याएँ बढ़ी हैं। आर्थिक और विकासात्मक क्षेत्र में इसका परिणाम भटकाव, प्रणाली के विध्वंस, अनुदारता और भ्रष्टाचार के प्राकृतिक परिणाम के रूप में व भ्रष्टाचार के रूप में हुआ है।

किसी भी अन्य कारक से अधिक, विविधताओं के शोषण के परिणामस्वरूप समाज की एकजुटता टूट गई है, सांस्कृतिक पहचान की असुरक्षा पैदा हुई है, धार्मिक पुनरुत्थानवाद को उसके कट्टरपंथी रूप में बढ़ावा मिला है, जातीयता बढ़ी है और उप-राष्ट्रीय समूहों और राष्ट्रवाद के बीच की खाई को चौड़ा किया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ने युद्ध में क्रांति ला दी है और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में इसने अंडरवर्ल्ड को प्रत्यक्ष शारीरिक भागीदारी के बिना आपराधिक गतिविधियों के लिए अपनी पहुंच का विस्तार करने के साधन प्रदान किए हैं। पाक आईएसआई ने बॉम्बे अंडरवर्ल्ड से संबंध जोड़कर इसका पूरा फायदा उठाया है। हमारी प्रतिक्रियाएं तेज होनी चाहिए। इसके लिए सुरक्षा बलों में शैक्षिक स्तर को अध्ययन करने और तकनीकी स्वभाव विकसित करने की आवश्यकता होगी।

हमारी आंतरिक कमजोरियों और अस्थिरता ने बाहरी खतरों को बढ़ावा दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश की है। सामाजिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि तीसरी दुनिया के कमजोर राज्यों में सुरक्षा के लिए घरेलू रूप से उत्पन्न खतरों के साथ उच्च स्तर की चिंता है क्योंकि वे एक प्रमुख तत्व के रूप में बड़े पैमाने पर बल के उपयोग को खत्म करने के लिए पर्याप्त शक्ति की घरेलू राजनीतिक और सामाजिक चेतना पैदा करने में सक्षम नहीं हैं। चीन भारत की सुरक्षा धारणाओं में एक महत्वपूर्ण कारक है और अपने संबंधों को खराब करता है। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में, उत्तर पूर्व में चीन की दिलचस्पी और उग्रवादियों की मदद पर हमें लगातार ध्यान देना चाहिए। यह आपको रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से व्यापक विकल्प दे सकता है।

हमें 1969 में चीनी और पाकिस्तानियों द्वारा पूर्वोत्तर में विद्रोहियों के प्रशिक्षण, वित्त पोषण और हथियारबंद करने के समन्वय के लिए स्थापित समन्वय ब्यूरो को नहीं भूलना चाहिए। इसके आयाम अधिक परिष्कार के साथ विस्तारित हुए हैं और यह एक व्यवहार्य कम लागत वाला विकल्प बना हुआ है। सीमा विवाद को सुलझाने में बिना किसी प्रगति के संबंधों को सामान्य करने की बातें चीन के इरादों को संदिग्ध बनाती हैं। पाकिस्तान ने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मध्य पूर्व में ठिकाने स्थापित किए हैं, इस योजना का उद्देश्य भारत को घेरना है। यह मध्य एशियाई गणराज्य, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपने उपरिकेंद्र के साथ वैश्विक स्तर पर इस्लामी आतंकवाद में वृद्धि के साथ संयुक्त रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा पर लगातार प्रभाव डालने की संभावना है।

पाकिस्तान वर्षों से अपने भारत विरोधी रुख को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में राज्य प्रायोजित आतंकवाद का उपयोग करता रहा है। आईएसआई से खतरा वास्तविक और गंभीर है और इसका प्राथमिक ध्यान भारत की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करना है। भारत की खुली लोकतांत्रिक प्रणाली, न्यायपालिका और सामाजिक-राजनीतिक सेटिंग विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों और स्थानीय तनावों का फायदा उठाने के लिए शत्रुतापूर्ण एजेंसियों को व्यापक अवसर प्रदान करती है। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को लागू करने के लिए आईएसआई का इस्तेमाल सांप्रदायिक गड़बड़ी भड़काने, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने, उग्रवादियों और भाड़े के सैनिकों की घुसपैठ कराने और भारत में हथियारों और विस्फोटकों को शामिल करने के लिए विध्वंसक गतिविधियों के लिए किया है। हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचयूएम), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जम्मू और कश्मीर इस्लामिक फ्रंट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हरियाणा और पंजाब में अपने अभियान का विस्तार किया है। आईएसआई एजेंटों ने पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के माध्यम से हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के लिए ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशनों और कोरियर की भी खेती की है। इसने देश के

विभिन्न हिस्सों में जासूसी नेटवर्क भी स्थापित किए हैं। आईएसआई दक्षिणी राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय की वफादारी को कम करने के लिए उन्हें तेजी से निशाना बना रहा है, जबकि कर्नाटक और केरल तस्करी के शिकार हो गए हैं तोड़फोड़ के लिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को निशाना बनाया गया है। तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक गड़बड़ी और मद्रास और कोयम्बटूर में बम विस्फोट आईएसआई की मिलीभगत के गवाह हैं। उत्तर पूर्व में, सिलीगुड़ी गलियारा बांग्लादेश और नेपाल के साथ अपनी झरझरा सीमाओं के साथ आईएसआई विध्वंसक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख मार्ग बन गया है। भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश की सीमा पर मदरसों की बढ़ती संख्या आईएसआई द्वारा बांग्लादेश में सहानुभूति रखने वाले तत्वों की मदद से उत्तर पूर्व में विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना है। माफिया, नार्को-तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा का प्रवाह और आतंकवादी गतिविधियां, बंदूक चलाने, हवाला लेन-देन के लिए मुस्लिम पॉकेट प्रजनन स्थल बन गए हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया और कट्टरपंथी संगठन

बांग्लादेश के अधिकारियों के कुछ तत्वों पर भी आईएसआई के साथ मिलीभगत होने का संदेह है। बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों की उपस्थिति विध्वंसक गतिविधियों के लिए एक उर्वर समर्थन आधार प्रदान करती है। आईएसआई अपने संरक्षण में बांग्लादेश के जेईआई, कौमी मदरसों और इस्लामिक एनजीओ जैसे कट्टरपंथी संगठनों के माध्यम से भंडारण और ट्रांसशिपमेंट के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में हथियारों के बाजारों से उत्तर पूर्व के विद्रोहियों द्वारा प्राप्त हथियारों और गोला-बारूद के ट्रांसशिपमेंट के लिए बांग्लादेश एक नोडल बिंदु भी बन गया है। पूर्वी विद्रोहियों ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिक और जातीय विभाजन को भड़काया। ISI ने पहले ही उत्तर पूर्व के विद्रोहियों (छेच्छ (IM) ULFA, PLA, बोडो सुरक्षा बल, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (नछस्थ) और मुस्लिम चरमपंथी संगठनों जैसे मुस्लिम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ असम (डस्ज) और मुस्लिम यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ असम के साथ संबंध स्थापित कर लिए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के बीच सीधा संबंध है। आईएसआई हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के लिए इन स्थापित चैनलों का उपयोग कर रहा है, जिसने आतंकवाद को अधिक ताकत प्रदान की है। वाशिंगटन पोस्ट (12 सितंबर 1994) को दिए एक साक्षात्कार में नवाज शरीफ ने उग्रवाद का समर्थन करने के लिए ड्रग मनी का उपयोग करने की आईएसआई की योजनाओं का उल्लेख किया। जनरल मिर्जा अफजल बेग और केएम आरिफ दोनों ने अफगानिस्तान में युद्ध के लिए पाकिस्तानी सेना को दान की पुष्टि की। ब। की रिपोर्ट पाकिस्तान में हेरोइन, पाक खुफिया एजेंसियों द्वारा पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद को वित्तपोषित करने के लिए ड्रग मनी के उपयोग की पुष्टि करती है।

पाकिस्तान के शासकों ने भारत के खिलाफ एक व्यवस्थित छद्म युद्ध छेड़ रखा है, जिसमें तोड़फोड़ और आतंकवाद मुख्य हथियार हैं। इसका उद्देश्य सीधे तौर पर तोड़फोड़ और धर्मनिरपेक्ष भारतीय समाज में प्रवेश करके भारत को अस्थिर करना है। हमें पाक आईएसआई के प्रभाव में आने वाले कट्टरपंथी तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए। इससे हमारे मुसलमानों के विशाल अल्पसंख्यक वर्ग का अलगाव नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में अधिकारियों को इस तथ्य के बारे में सचेत रहने की आवश्यकता है कि 1992 के बाद से भारतीय मुसलमानों का अलगाव हो गया है, और यह इस वजह से है कि आईएसआई कुछ भारतीय मुसलमानों की वफादारी को कम करने और पूरे देश में फ्रंट संगठन स्थापित करने में सक्षम हो गया है।

नक्सलवाद और तस्करी

मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को आतंकवाद के आयाम तस्करी और तस्करी से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। यह काले धन, हवाला लेन-देन, मनी लॉन्ड्रिंग और सबसे बड़ी नकदी अर्थव्यवस्था के अस्तित्व से भारत की वित्तीय सुरक्षा को कमजोर करता है, सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को सक्षम बनाता है और अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक स्थापित करता है क्योंकि हवाला मार्गों के माध्यम से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आईएसआई ने विध्वंसक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और जाली मुद्रा की विशाल हानिकारक क्षमता का एहसास किया है। 1992 में पाकिस्तान के राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने अनुमान लगाया था कि पाकिस्तान की काले धन की अर्थव्यवस्था गोल्डन क्रीसेंट से अवैध नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और तस्करी से सालाना 32.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करती है, जो पश्चिमी यूरोप को आपूर्ति की जाने वाली सभी हेरोइनों का 75: और 50: प्रदान करती है जो अमरीका जाता है। भारत का उपयोग ड्रग्स के लिए यूरोप और अमेरिका के लिए एक पारगमन मार्ग के रूप में किया जा रहा है। भारत के रास्ते हर साल 5000 करोड़ की तस्करी की जा रही है। स्वर्ण त्रिभुज 1000 टन से अधिक अफीम का उत्पादन करता है जिसे बहुत उच्च श्रेणी की हेरोइन में परिष्कृत किया जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, में नशीले पदार्थों की बढ़ती मात्रा और दुरुपयोग पूर्वोत्तर में संभावित अवैध मादक पदार्थों के व्यापार का एक स्पष्ट संकेत है। इसी तरह खुली भारत-नेपाल सीमा हशीश का मुख्य स्रोत है।

मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया दूषित धन को किसी भी संघ से उसके आपराधिक स्रोत से अलग करने में मदद करती है और लेन-देन की लंबी श्रृंखला मूल स्रोत का पता लगाना असंभव बना देती है। इसके बाद उपहार, दान और व्यापार खातों के माध्यम से पैसा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भेजा जाता है। यह कर चोरी में भी मदद करता है और चार्टर्ड एकाउंटेंट, लेखा परीक्षक, वकील और व्यापारियों जैसे पेशेवर सहायकों द्वारा अच्छी तरह से हेरफेर किया

जाता है। हमारी बैंकिंग प्रणाली में थकाऊ प्रक्रियाओं और देरी के कारण हवाला ने अपनी सहजता, गति और गुमनामी के साथ इसे प्रवासियों के लिए भी आकर्षक बना दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर चोरी और हवाला एक दूसरे के पूरक हैं।

इसी प्रकार, पाकिस्तानी आगंतुकों के लिए लागू वीजा व्यवस्था के हमारे प्रवर्तन को एक नए मूल्यांकन की आवश्यकता है क्योंकि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आगंतुक वापस नहीं आते हैं और लापता रहते हैं। आईएसआई और उसके साथियों द्वारा विदेशों में शिपमेंट से प्राप्त ड्रग मनी को ड्रग पुशिंग कार्टेल से एकत्र किया जाता है, जिसे विभिन्न प्लेसमेंट के माध्यम से लॉन्च किया जाता है और खाड़ी और अन्य देशों में इसके विश्व लिंक के तहत उपलब्ध कराया जाता है, जहां से यह बैंकिंग और अन्य चौनलों के माध्यम से इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों तक जाता है। जब तक हमारे विदेशी मुद्रा प्रबंधन, नारकोटिक नियंत्रण और मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्थाओं को खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं बनाया जाता, तब तक नार्को आतंकवाद के प्रभाव की जांच नहीं की जाएगी। जम्मू और कश्मीर में संघर्ष के अपने अलग बाहरी और आंतरिक मापदंड हैं। कश्मीर पाकिस्तान की भारत नीति का केंद्र बिंदु था, है और रहेगा, क्योंकि भारत विरोधी मुद्रा और कश्मीर दोनों ही उसकी पहचान के लिए आवश्यक औचित्य हैं।

1998 में दोनों देशों का परमाणुकरण, परमाणु प्रतिरोध और इस प्रकार परमाणु क्षेत्र में स्थिरता का संतुलन ला सकता है, लेकिन यह पाकिस्तान को छद्म युद्ध जारी रखने से रोकने की संभावना नहीं है, जैसा कि कारगिल घुसपैठ और बाद में उग्रवाद में वृद्धि से साबित हुआ था। छद्म युद्ध के लिए एकमात्र निवारक इसकी लागत को पाकिस्तान के लिए निषेधात्मक बनाना है। कश्मीर पर भारत-पाक संघर्ष को प्रभावित करने वाला अन्य प्रमुख कारक जिया के समय से पाकिस्तान का इस्लामीकरण है और पाकिस्तान इस क्षेत्र में इस्लामी पुनरुत्थान की अगुआई करने का दावा करता है।

विश्व समुदाय स्थिति को उच्च तीव्रता के पारंपरिक संघर्ष में बदलने की अनुमति नहीं देगा, जहां किसी भी स्तर पर परमाणु टकराव या आदान-प्रदान का खतरा हो। अंतरराष्ट्रीय धारणा में, खतरा बहुत वास्तविक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु नियंत्रण व्यवस्था से बाहर हैं। इसलिए भगोड़े हमले और परमाणु हथियारों के गुपचुप तरीके से इस्लामिक आतंकवादियों को दिए जाने का खतरा वास्तविक है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव को रोकने और कम करने के कूटनीतिक क्षेत्र में प्रयासों को विश्व समुदाय से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। चीन और दक्षिण तथा मध्य एशियाई देशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। आंतरिक रूप से, प्रमुख अस्थिर कारक मुसलमानों का उनके पारंपरिक क्षेत्रों से परे जनसांख्यिकीय प्रसार, कट्टरवाद और लोगों का अलगाव है। अल्पसंख्यक समुदाय के आगे किसी भी तरह के पलायन और उन्हें

निशाना बनाए जाने से मुस्लिम वर्चस्व का विस्तार होगा।

देश में सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने से भी परिवर्तन की आशा जगी है। जम्मू और कश्मीर में आगे की राह बाधाओं से भरी हुई है, जिसे समस्या के राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और कानून और व्यवस्था के आयामों की पहचान के आधार पर एक समग्र नीति से ही दूर किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर में अलग-अलग भावनाओं का मूल एक दूसरे के साथ और भारत के हित के साथ सामंजस्य होना चाहिए। अलगाव का दूसरा पहलू भ्रष्टाचार है जिसने जम्मू-कश्मीर के लोगों को आर्थिक विकास के लाभ और लोकतांत्रिक और विकासात्मक प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी से वंचित कर दिया है। राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में स्थिति को भुनाने और मजबूत करने के उद्देश्य से दलगत राजनीति से ऊपर की रणनीति का उद्देश्य होना चाहिए। मूल कार्य कश्मीर घाटी और जम्मू-कश्मीर के अन्य हिस्सों के लोगों की अलगाव की भावना को दूर करना होगा। मार्गदर्शक सिद्धांत समाज के सभी वर्गों के स्वाभिमान और विश्वास की बहाली होना चाहिए। सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में, मुख्य चुनौती कट्टरवाद है, जिसके लिए जमात-ए-इस्लामी (कश्मीर) के समर्थन आधार को भंग करने, सांप्रदायिक विभाजन और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को उलटने और कश्मीरियत की भावना को पुनर्जीवित करने की इंजीनियरिंग की आवश्यकता होगी।

उत्तर-पूर्व में हमारी नीतियों की प्रतिक्रियाशील प्रकृति ने इस विश्वास को प्रोत्साहित किया है कि आंदोलन और हिंसा केवल ध्यान आकर्षित करती है क्योंकि हमारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आम तौर पर आंदोलन और विद्रोह का अनुसरण करती हैं जो नागालैंड में अंकुरित हुए, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम तक फैल गए। इसी तरह, हमारा विश्वास है कि संघर्ष अपने प्राकृतिक पाठ्यक्रम को चलाते हैं, इसलिए, अकेले सशस्त्र बल के साथ विद्रोह का सामना करें और जब उग्रवाद कमजोर हो जाए, तो बातचीत और संवैधानिक रियायतें प्रदान करें, जिसके परिणामस्वरूप समझौते होते हैं, यह गलत है। मिजोरम को छोड़कर इन सभी ने न तो उग्रवाद को समाप्त किया है और न ही पर्यावरण में सुधार किया है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में घटनाओं को प्रभावित करने के लिए जातीय बंधनों का फायदा उठाने पर जोर दिया गया है। विद्रोहियों का समर्थन आधार ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गया है क्योंकि यही वह जगह है जहां भौतिक और वित्तीय संसाधन हैं और सरकारी धन मुख्य स्रोत है। जनसंख्या केंद्रों में उनकी परिवर्तित उपस्थिति न केवल प्रभावी होनी चाहिए बल्कि विविध स्रोतों, निजी और सरकारी दोनों का दोहन करने के लिए परिष्कृत होनी चाहिए। ठेकेदारों और सरकारी विभाग भुगतान प्रमुख लक्ष्य हैं। सीमित अवधि के लिए उच्च तीव्रता वाली हिंसा और लंबे समय तक नियंत्रण में रहने के साथ उत्तर पूर्व

में उग्रवाद अपनी निम्न महत्वपूर्ण स्थिति को बनाए रखते हुए फलता-फूलता रहेगा।

विद्रोहियों का मूल अलगाववादी और सत्ता-विरोधी और लोगों के बीच समर्थन के लिए जातीय रहेगा। उत्तर-पूर्व में विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में राजनेता-नौकरशाह-अभिजात वर्ग-विद्रोही सांठगांठ को जब तक रोका नहीं जाता है, तब तक वे अपने विविध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्रोह को समर्थन देना जारी रखेंगे और लोगों के अभाव और अलगाव को और तेज करेंगे। उत्तर-पूर्व उच्च स्तर की जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता वाला एक अत्यंत विषम क्षेत्र है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय और राजनीतिक-आर्थिक परिवेश और क्षेत्र के वातावरण में बदलाव का प्रतिबिंब है। इसी तरह, उत्तर पूर्व में राजनीतिक विकास अपने अलग-अलग ऐतिहासिक अनुभव, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-राजनीतिक तनाव और अस्थिरता के कारण होने वाली विशिष्टता से प्रभावित है, जो फिर से समस्याओं और हिंसा के लिए आंदोलनकारी दृष्टिकोण का परिणाम है। इनमें से, जातीय लामबंदी की हालिया घटना स्वचालित रूप से विरोधियों के लिए खतरा पैदा करती है जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष की स्थिति पैदा होती है।

उत्तर-पूर्व में संघर्ष मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार के अभावों से पैदा हुई मानव हताशा के इर्द-गिर्द है, संभवतः नागाओं के अपवाद के साथ जो बिना किसी राजनीतिक, सांस्कृतिक के अलग होने की भावना में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। पहाड़ी जनजातियों (आदिवासियों के लिए आरक्षण के कारण) की तुलना में मेइती आर्थिक और रोजगार के क्षेत्र में खुद को वंचित महसूस करते हैं। इसी तरह, असमिया शेष भारत की तुलना में वंचित महसूस करते हैं, जैसा कि असमियों की तुलना में बोडो करते हैं-मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्रों में। त्रिपुरा में जनजातीय विद्रोह बंगाली बाढ़ के कारण जनजातीय भूमि के अलगाव का परिणाम है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक और सामाजिक अभाव है। मिजोरम अपनी भौगोलिक स्थिति और 1959 में अकाल के अनुभव के कारण विवश महसूस करता है, फिर मूल रूप से इसका कारण आर्थिक अभाव है। उत्तर पूर्व में संघर्षों का समाधान राजनीतिक क्षेत्रों में निहित है, जिसमें सुशासन पर प्रमुख जोर दिया गया है और लोगों की अभाव की भावना को दूर किया गया है।

मणिपुर में भी जातीय दंगे और लोग अपने जनसांख्यिक आधार पर अधिकार के लिए संघर्षरत है। प्रशासन के पूर्ण अभाव और संकीर्णता के लाभ के लिए राज्य तंत्र के हथकंडे अपनाए जाने से स्थिति और भी खराब हो गई है। नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में स्थिति अनिश्चित है। महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी नक्सली न्यूनतम सक्रिय हैं, जबकि मध्य प्रदेश वामपंथी चरमपंथी हिंसा के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। वामपंथी उग्रवाद वर्तमान में सशस्त्र कृषि हिंसा के लंबे इतिहास के साथ आंध्र प्रदेश और बिहार तक ही सीमित

है। आंध्र प्रदेश में सीपीआई-एमएल (पीपुल्स वॉर ग्रुप) और बिहार में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) सीपीआईएमएल (जनता एकता) और सीपीआईएमएल (विनोद मिश्रा ग्रुप) जैसे नक्सली समूह दक्षिण पूर्व में हथियारों के बाजारों से हथियार प्राप्त कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में, पिड़ब्लूजी 1500 से अधिक क्रांतिकारियों और 3000 से अधिक प्रतिबद्ध समर्थकों के साथ प्रमुख नक्सली गुट है, इसने अपना प्रभाव राज्य के दो तिहाई से अधिक तक फैला लिया है, जिसमें सबसे अधिक हिंसा तेलंगाना क्षेत्र में हो रही है। आंध्र प्रदेश के विपरीत बिहार में नक्सली कैडर अधिक फैला हुआ है, इसलिए उनके द्वारा की जाने वाली हिंसा भी है। अधिकांश नक्सली समूह दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों की रक्षा के बहाने वर्गधजाति के युद्धों में लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश से मार्क्सवादी आंदोलन के प्रभाव के कारण मध्य प्रदेश में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है। हमारा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की नींव कई तूफानों से बची है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसे पूरी तरह से स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से ही हम राष्ट्रीय प्रयास को एकमत समर्थन दे सकते हैं। उत्तर पूर्व में राजनेता-नौकरशाह-अभिजात वर्ग-विद्रोही गठजोड़ जब तक क्रूरता से नहीं रोका जाता, तब तक आपसी लाभ के लिए विद्रोह का समर्थन करना जारी रहेगा। आईएसआई के डिजाइन को अब प्रतिक्रियात्मक और रक्षात्मक नीति के माध्यम से नहीं रोका जा सकता है।

निष्कर्ष

इन वातावरणों में नीति कार्यान्वयन, प्रशासन का कार्याकल्प, आर्थिक विकास और सुरक्षा प्रबंधन शासन के आवश्यक तत्व हैं, जबकि सुशासन हर जगह एक प्रमुख आवश्यकता है, यह अशांत वातावरण में एक प्रमुख तत्व बन जाता है। चूंकि अंतिम लड़ाई लोगों के दिल और दिमाग के लिए है और वंचितता मूल है, इसलिए शासन के लिए चिंता का प्रमुख क्षेत्र बुनियादी नागरिक सुविधाओं, सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य, संचार और परिवहन, आवास और पुनर्वास और बहाली का प्रावधान है। लोगों को सरकार को महसूस करना और देखना चाहिए न कि केवल उसके बारे में सुनना चाहिए। यहीं पर आम आदमी को राजनीतिक इच्छाशक्ति और शासन दिखाई देता है। मुख्य चिंता राज्य और उसके संस्थानों की विश्वसनीयता और वैधता स्थापित करने की होनी चाहिए। यह केवल एक व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य नीति, संस्थागत दृष्टिकोण और विश्वसनीय लोगों द्वारा एक ईमानदार और पारदर्शी कार्यान्वयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जातीय और सांप्रदायिक संघर्षों का प्रबंधन और उनका समाधान शासन और प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। शासन के बिना न तो हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं और न ही लोगों की कठिनाइयों

को दूर करने वाली नीतियों को लागू कर सकते हैं। शासन के बिना अन्य सभी क्षेत्रों को नुकसान होता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कारक है।

धार्मिक कट्टरवाद, जातीय हिंसा, आर्थिक विषमताओं और अभावों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीसरे चेहरे की केवल बात की जाती है लेकिन शायद ही कभी और लगातार देखा जाता है। हम अब इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं, खासकर जब वैश्वीकरण और आईटी तेजी से, उग्र और सबसे हानिकारक और अप्रत्याशित परिवर्तन कर सकते हैं। हमारी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं पर बहस और आम सहमति की आवश्यकता है। टाडा का राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन तोड़फोड़, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए कानूनों का न होना आपदा को आमंत्रित कर रहा है। आतंकवाद, तोड़फोड़ और ड्रग्स से निपटने के लिए टाडा की तुलना में दुनिया के अधिकांश लोकतंत्रों में अधिक कड़े कानून हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के स्वतंत्र कामकाज और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और कानून और व्यवस्था पहलुओं को शामिल करते हुए एक समग्र नीति सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हैं। इसके लिए सबसे अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी।

लोकतांत्रिक प्रणाली से भारत का नाम विश्व में विख्यात है और अपने लोगों के लचीलेपन के कारण प्रगति कर रहा है। पाकिस्तान ने पंजाब को एक परीक्षण मैदान के रूप में इस्तेमाल किया और जैसे-जैसे जम्मू-कश्मीर के साथ उसकी भागीदारी बढ़ी, वह टंडा पड़ गया। पंजाब उग्रवाद को आतंकवाद के रूप में देखा जाना चाहिए और मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था के दायरे में निपटा जाना चाहिए। इसे सिख शिकायतों और चंडीगढ़ के हस्तांतरण और नदी जल विवाद जैसे राजनीतिक मुद्दों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। राज्य और केंद्र दोनों को मजबूत होना है, एक कमजोर केंद्र, राज्यों को बाहरी खतरों और आंतरिक खतरों से नहीं बचा सकता है। केवल एक प्रभावी राज्य ही अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। राजनीतिक दल अराजकता की स्थिति की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि यह बिहार में राजनीतिक औचित्य और लोकतंत्र की आड़ में मौजूद था। हाल के दिनों में आईएस की हर नई स्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया सुरक्षा बलों के प्रकार और संख्या में वृद्धि रही है, पंजाब ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध को राष्ट्रीय राइफल्स को जन्म दिया। भारत में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यायपूर्ण और विश्वसनीय ढंग से कार्य करने वाले समाज और राज्य के प्रबोधन से स्थिति को भुनाया जा सकता है। हमारी सुरक्षा स्वदेशी और बाह्य दोनों तरफ से उत्पन्न होने वाले खतरों, तनावों और संघर्षों के प्रति संवेदनशील है। इसके साथ ही देश की कमान कुशल नेतृत्व एवम निर्णय लेने वाले अनुभवी व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिये जो देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सभी राजनीतिक मुद्दों से

निपटने के लिए समान नीतिगत फैसले लेने की आवश्यकता है। राज्य को संगठित अपराध, तोड़फोड़, आतंकवाद और नशीले पदार्थों से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से तैयार करना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. डा. सुरेंद्र कुमार – राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा माड्रन पब्लिशर्स नई दिल्ली 2015
2. महेंद्र कुमार-अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष-शिवलाल अग्रवाल एंड कम्पनी आगरा-3 दृ 1997,
3. भसीन अवतार सिंह भारत के विदेशी संबंध – 2008 दस्तावेज भाग सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग विदेश मंत्रालय गीतिका प्रकाशक, नई दिल्ली 1546-1549 (2008)
4. दैनिक जागरण 22 जून 2023
5. राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध – डा.बी.आर.पाण्डेय- प्रकाश बुक डिपो, बरेली

डॉ० एम.एस.मांजू

एसोसिएट प्रोफेसर रक्षा अध्ययन
राजकीय महाविद्यालय हिसार
पता- 313 डिफेंस कालोनी हिसार- 125001.
msmanjhu@gmail-com
Contact No. 9416625855



सारांश

सृष्टि परिवर्तन शील है। काल चक्र के साथ-साथ परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं और बदलती परिस्थितियों के प्रभाव से व्यक्ति की रुचियाँ भी प्रभावित हो जाती हैं। मानव जीवन के रुचि परिवर्तन के साथ-साथ युग धारा नई करवट लेती है। सृष्टि का अटल नियम है कि कोई भी साहित्यकार अपने युग की परिस्थितियों का पूरी तरह से बहिष्कार नहीं कर सकता। समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों से ही सभ्य समाज के परिवेश का गठन होता है। किसी भी युग की रचना को समझने के लिए युगीन चेतना को समझना नितान्त आवश्यक है। युग परिप्रेक्ष्य न समझने पर युगीन यथार्थ और रचनाकार के सर्जनात्मक व्यक्तित्व के सम्बन्ध अन्वेषण प्रायः नहीं हो पाता।

श्रेष्ठ साहित्य युग के सम्पूर्ण बोध को रेखांकित करता है। प्रत्येक युग के साहित्य की कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं, जो उसी युग की सामयिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। यदि लेखक तीव्रता के साथ युग सत्य से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, तो वह मार्मिक व शाश्वत साहित्य का प्रणयन नहीं कर सकता।

मुख्य शब्दः— साहित्य, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति। राजनैतिक परिस्थिति। आर्थिक परिस्थिति, समाज आदि।

अध्ययन के उद्देश्यः—

इस प्रपत्र का उद्देश्य विद्यानिवास मिश्र जी व युगीन परिस्थितियों का समग्र अध्ययन करना है। साहित्य समाज की उपज होता है और समाज से कटकर साहित्य की कोई उपयोगिता नहीं रहती। साहित्यकार स्वयं भी समाज की उपज होता है और सामाजिक परिस्थितियाँ उसे बनाती हैं। किसी भी युग के साहित्य को जानने के लिए उस युग की परिस्थितियों को जानना नितान्त आवश्यक माना गया है। "परिवेश की चेतना से विहीन आत्मा निर्जीव है, अभिव्यक्ति के सर्वथा अयोग्य है। परिवेश विभिन्न ऋतुओं के समान है। इससे रचना रूपी पौधे को अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होने में सहायता मिलती है। परिवेश काल का वह सामयिक अंश है, जिससे प्रताड़ित पीड़ित अथवा आनन्दित—उद्वेलित और प्रेरित होकर कोई रचनाकार किन्हीं उज्ज्वल शुभ उद्देश्यों की सृष्टि करता है और इस प्रकार अपनी कृति को, सामयिकता की सीमा से परे, काल की परिधि में ले जाता है।"

विषयः—

विलक्षण बौद्धिक एवं सृजनात्मक प्रतिभा सम्पन्न आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी हिन्दी के अद्वितीय निबन्धकार हैं। मिश्र जी का साहित्य भी युगीन परिस्थितियों से विलग नहीं है। इनके निबन्धों में भी युग प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। उनके निबन्धों का विशद विवेचन करने

के लिए उनके युग की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक परिस्थितियों पर एक दृष्टि निक्षेप परम आवश्यक है।

1. सामाजिक परिस्थिति
2. आर्थिक परिस्थिति।
3. राजनैतिक परिस्थिति।
4. सांस्कृतिक परिस्थिति।

सामाजिक परिस्थितिः—

जिस युग से साहित्यकार गुजरता है, उस युग की सामाजिक दृष्टि उसके लेखन में विद्यमान रहती है। वह समाज से प्रेरणा ग्रहण करता है। किसी भी साहित्यकार को दो रूपों में सामाजिक परिस्थिति प्रभावित करती है। एक और साहित्यकार सामाजिक रीति-रिवाजों से प्रभावित होता है। दूसरे वह अर्थव्यवस्था और समाज निर्माण की मुख्य पीठिका से भी प्रभावित रहता है। संसार के सिरमौर भारत की सामाजिक व्यवस्था को पुर्तगाली डच, शक, हूण, फ्रांसीसी व अंग्रेजों ने प्रभावित किया। अंग्रेजों ने राजनीति पर ही अपना अधिकार स्थापित नहीं किया बल्कि सामाजिक जीवन को भी पूर्णतया प्रभावित किया। उन्होंने जनता पर अनेक अत्याचार किये व जमीन को लगान में नीलाम करा लेते थे। हमारे समाज में नारियों की स्थिति दयनीय हो गयी थी उसे अब अबला कहा जाता था। उनके हृदय में परम्पराओं को तोड़ने की आग सुगबुगा उठी पथ थी पर तोड़ने का साहस नहीं कर पा रही थी। लेकिन बीसवीं शताब्दी में नारी सुधार आन्दोलनों की बाढ़ सी आग थी समाज में प्रचलित बुराईयाँ जैसे—सतीप्रथा, बालविवाह का कड़ा विरोध हुआ। नारी की दीन हीन दशा के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंत का आक्रोश इस प्रकार व्यक्त हुआ है।

मुक्त करो नारी को मानव द्य चिरवन्दिनी नारी को ॥

आज नारी को पुरुषों के समान अधिकार मिलने के बाद भी वह सुरक्षित नहीं है। आज धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं रह गये हैं वे भी आतंकवादियों के घर बन गये हैं द्य आज व्यक्ति के सामने अनेक समस्याएँ मनुष्य के जीवन में ताने बाने की तरह बुग गयी हैं। समाज में व्याप्त, कुंठाओं, निराशा, बेरोजगारी, तीव्रमूल्यवृद्धि और जनसंख्या में निरन्तर होती बढ़ोतरी जैसी समस्याओं ने साहित्यकार के मासूम हृदय को बेध डाला। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में काका कवि ने सत्य ही कहा है—

कह काका कवि कॉप रहा क्यों रिश्वत लेकर।

रिश्वत पकड़ी जाये, छूट जा रिश्वत देकर ॥

हमारे समाज में बेरोजगारों की संख्या दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। किसी ने सत्य ही कहा है— हाथों में डिगरी, आंखों में निराशा, बेरोजगारों की पीड़ा, को जाने कौन भाषा इस प्रकार से विश्रृंखलित सामाजिक परिस्थितियों के परिवेश में डॉ० विद्यानिवास

मिश्र ने निबन्धों का प्रणयन किया है। सामाजिक परिस्थितियों पर कटाक्ष करते हुए सुदृढ़ समाज के लिए मानदंड प्रस्तुत किये हैं।

आर्थिक परिस्थिति:—

हमारे देश की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर रहती थी। भारत में जोत की भूमि कम थी। यह भी महाजन पूंजीपतियों और जमींदारों ने अपने अधिकार में ले ली। कृषकों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गयी थी कि आजीवन कर्ज में डूबे रहते थे।

महाजनों ने ब्याज पर रुपये देकर जनता का शोषण आरम्भ कर दिया था, जो किसान उनके चंगुल में फँस जाता था वह फिर उसमें से निकल नहीं पाता था।

अंग्रेजों ने यहां का कच्चा माल अपने देश भेज दिया जिससे यहाँ के उद्योग धन्धे समाप्त हो गये। यहाँ के लोग भूखे मरने लगे, परस्पर विषमता फैल गई और लोग दीन एवं निरीह जीवन व्यतीत करने लगे।

अंग्रेजों की दोषपूर्ण शोषण नीति के परिणाम स्वरूप देश में जो दरिद्रता आयी, अकाल के दृश्य बार-बार उपस्थित हुए। १३३३ प्रकार भारत कच्चे का निर्यात और इंग्लैण्ड निर्मित माल का आयात बना। इसमें सन्देह नहीं, अंग्रेजों का भारत के प्रति यह रुख भारत के हक में विनाशक था।

जब हमारा देश आजाद हो गया तब भी देश की आर्थिक स्थितियों को गहरा धक्का लगा और भारत का उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। भारत को बड़ी रकम पाकिस्तान को देनी पड़ी और शरणार्थियों के लिए आवास में भी काफी धन खर्च हो गया था। उद्योगपति व पूँजीपति चाहे भारत के ही थे लेकिन वे आम जनता पर अत्याचार करते थे। इस सम्बन्ध में हरिचरण शर्मा लिखते हैं— षट्द्योगों के द्वारा एकत्रीकरण ने दुष्टों को जन्म दिया और इन दुष्टों ने सारे उद्योगों को अपने तक सीमित कर लिया। परिणामतः देश की पूंजी के कुछ ही लोग मालिक बन बैठे। पूँजीपतियों ने अपना दमन चक्र आरम्भ कर दिया। यह अत्याचार और शोषण इतना बढ़ा की स्वाधीनता के उपरांत भी इस में कोई कमी नहीं आई।

भारत सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। इन योजनाओं लाभ आम जनता को नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में डॉ० कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने कहा है कि—सबसे अधिक दूरवस्था स्थिर आय वाले मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग की रही है, जिसकी चढ़े हुए मूल्यों ने कमर तोड़ दी है। सामुदायिक विकास तथा अन्य योजनाओं का पूरा लाभ नौकरशाही के भ्रष्टाचार के कारण सामान्य जनता तक नहीं पहुंच सका है। राष्ट्रीय नेतृत्व जनता का जीवन स्तर उठाने तथा सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन में सहयोग लेने में अक्षम रहा है एक नवीन त्रिकोणात्मक शोषण का मंत्र स्वाधीनता के बाद पनपा है जिसके कोण क्रमशः पूंजीपति वर्ण, नौकरशाही और अवसरवादी नेतागिरी है दृष्टमारे देश पर सन् 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण फिर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण से हमारी आर्थिक स्थिति और अधिक

डावाडोल हो गई। पाकिस्तानी आक्रमण के विषय में देवी शंकर अवस्थी ने लिखा है :—पाकिस्तान से होने वाला युद्ध इसी पिछले युद्ध की अगली कड़ी बनकर आया ३३जो कभी राजनीति की बात नहीं करते थे, जिनके लिए चारों ओर से घेरता अकेला पान ही था, वे भी अचानक जैसे झंझोड़ दिये गये और युद्ध की मोर्चे बंदियों की ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दल पंचों की चर्चा करने लगे।
.... इस लड़ाई ने बुद्धिजीवी को बदला। भारत में बढ़ती जनसंख्या और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण मुद्रास्फीति बढ़ गई है यह यदि देश का आर्थिक पक्षधर सु दृढ़ नहीं है, निर्धनता से आक्रांत जनता और सड़कों पर पहले पलते लोग जब महंगाई के राक्षस के आतंक से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक भारत के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना कैसे की जा सकती है दृष्टमारे देश की आर्थिक प्रगति ही देश की सर्वांगीण उन्नति का आधार माना जाता है
राजनैतिक परिस्थितियाँ।

हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी कारण भारत विदेशियों आकर्षण का केन्द्र सदैव से रहा है। अनेक देश व्यापार करने के उद्देश्य से आये और धीरे-धीरे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 18 वीं शताब्दी में अंग्रेज जो व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आये थे किन्तु उन्होंने धीरे-धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। प्रारम्भ में अंग्रेजों में भारतीयों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया। परन्तु, बाद में भारतीयों के साथ कठोरता व क्रूरता का व्यवहार करने लगे। अंग्रेजों ने छोटी-बड़ी एक सौ ग्यारह लड़ाइयाँ लड़कर समस्त भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था।

प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहायता मांगी और उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्ति का आश्वासन दिया। इस कारण भारतीयों में अंग्रेजों की खूबसहायता की ताकि प्रसन्न होकर भारत को मुक्त कर सकें। यह आश्वासन केवल पत्रों तक ही सीमित रहा। इससे दुखी होकर भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया।

सन् 1919 मे रौलट-एक्ट पास करके ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों की रही सही आशाओं पर पानी फेर दिया। अंग्रेजों में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निर्दोष भारतीयों पर गोली चलाई। गांधी जी ने हिन्दुओं और मुसलमानों को सम्मिलित कर असहयोग आन्दोलन शुरू कर दिया। इस आन्दोलन का मूल मंत्र सत्य और अहिंसा था।

द्वितीय विश्वयुद्ध में इंग्लैण्ड ने भारतीयों से सहायता मांगी और गांधी जी ने ना एक पाई ना एक भाई का नारा लगा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध से अंग्रेजी की काफी हानि हुई। इसी बीच सुभाष चन्द्र बोस ने शआजाद हिन्द फौज की सेना संगठित कर ब्रिटिश सरकार से लड़ाई आरम्भ कर दी। अंग्रेजी सरकार भारतीयों के प्रबल प्रतिरोध और अपनी कमजोर होती स्थिति के कारण भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने की सोच ली थी। लेकिन चालाकी

से उन्होंने सांप्रदायिकता की आग लगा दी द्यउन्होंने भारत के अनेक टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान को अलग स्वतंत्रता प्रदान की द्यभारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी रियासतों की क्योंकि उन्होंने उन्हें भी अलग-अलग स्वतंत्र किया था लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने अथक परिश्रम और साहस से भारत को एकता प्रदान की। और हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर अंग्रेज अपने देश लौट गए द्यहमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देश के विभाजन के संबंध में डॉ रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि- भारत स्वतंत्र तो हो गया पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश के विभाजन की समस्या ने देश को झकझोर डाला भारत विभाजित हुआ और हम स्वतंत्र हुए किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति पर हमारे उत्सव भी समाप्त न हो पाए थे कि पंजाब पारस्परिक रक्त लाप्सा के मद से कुंठित हो उठा ऐसा नरसंहार भारत में चंगेज खां की टोली के बाद कभी नहीं देखा गया था।

स्वतन्त्रता के बाद भारत में भ्रष्टाचार शोषण आदि भी बना रहा और अर्थव्यवस्था की अनेक समस्याएं भारत हमें उत्पन्न हुई। जिन नेताओं ने देश की स्वतन्त्रता के लिए अनेक त्याग और बलिदान किए थे, वे भी लालची और बन गये थे और देश की जनता को न्याय नहीं मिला। देश में न तो पूँजीवादी व्यवस्था ही समाप्त हुई न शोषण समाप्त हुआ और भारत स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी जर-जर रूप में प्रकट हुआ।

सांस्कृतिक परिस्थिति:-

आज का युग मूल्यों के विघटन का युग है। यह विघटन भारत में ही नहीं विश्व भर में व्याप्त है। समाज में सत्य, अहिंसा, परोपकार, ईमानदारी, मित्रता, सहानुभूति, दया, करुणा, सहयोग जैसे नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था खत्म होती जा रही है।

स्वाधीनता के बाद भारतीय संस्कृति निरन्तर पतनावस्था की और उन्मुख होती जा रही है। वर्तमान समय में संस्कृति पर सर्वाधिक प्रभाव पश्चिमीकरण का पड़ा है। सभ्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग शिष्टाचार माना जाता है। युग परिवर्तन और पीढ़ियों के अन्तर के कारण आज शिष्टाचार की भावना लुप्त हो गयी है। अंग्रेजों ने भारतवासियों के लिए जो शिक्षा प्रणाली चलाई थी उससे केवल लिपिक की तैयार होते थे। इससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी। आज की शिक्षा तो प्रदान करती है नौकरी नहीं। शिक्षा और संस्कृति का घनिष्ठ सम्बन्ध है। राष्ट्रीय संस्कृति को विकसित करने के लिये शिक्षा भी राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद परिवार, विवाह, जाति- आदि में निरन्तर परिवर्तन आ रहा है। संयुक्त परिवार निरन्तर टूटते जा रहे हैं। उनका स्थान एकांकी परिवार ले रहे हैं द्य जब अनेक प्रकार के मूल्य और विचार आपस में भिड़ते हैं तब सनक, संशय, आस्था और अलगाव पनपता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में जीवन मूल्यों, शैलियों, भावात्मक प्रक्रियाओं और बौद्धिक अभियानों की विशेष सक्रियता है। यह व्यक्ति

व समाज के पारम्परिक सम्बन्धों और सृजनात्मकता शक्तियों को गहरा प्रभावित करती है। पुराने समाज और संस्कृति को नये औद्योगिक यांत्रिक युग के अनुकूल बनाने की चेष्टा की जा रही है। यह लडाईं इतनी तेज है कि सम्बन्धो व मूल्यों के क्षेत्र में अराजकता सी नजर आती है।

वर्तमान हिन्दी साहित्य यथार्थ के धरातल पर अवस्थित होकर सामान्य जन की आशाओं, आकांक्षाओं, संघर्षों आदि को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है द्य सम्वेदना के स्तर का हिन्दी साहित्यसमस्त मानवीय गरिमा का सम्मान एवं उससे आहत करने वाले तत्वों का विरोध कर रहा है। इसी से यहाँ दलित विमर्श और नारी विमर्श जैसे चिंतन से प्रेरित साहित्य का सृजन दिखाई दे रहा है द्य अंग्रेजों के शासन में पहले तो शासकों की उपेक्षा तथा शिक्षितों पर पाश्चात्य कला का गहरा प्रभाव होने के कारण भारतीय शिल्प और कलाओं की दशा अत्यन्त शोचनीय रही लेकिन राष्ट्रीय जागरण के बाद शिल्प और कलाओं का पुनरुज्जीवन प्रारम्भ हुआ। वस्तु कला पर पाश्चात्य शैली का अत्यधिक प्रभाव पड़ा और यहाँ बड़े-बड़े नगरों में भारत की प्राचीन वस्तुकला की ओर ध्यान न देकर, पश्चिमी ढंग की हजारों इमारतें बनवाई गईं।

मूर्तिकला में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने प्राचीन परम्परा को स्थिर रखा द्य चित्रकला में रवि वर्मा ने पाश्चात्य शैली को अपनया परन्तु अवनीन्द्र ठाकुर ने नई चित्रण शैली का प्रवर्तन किया, जिसमें पाश्चात्य शैली की अनेक बातें होते हुए भी भारतीयता विद्यमान थी। संगीत के क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत की परम्परा संरक्षण के उद्देश्य से विष्णु दिगम्बर ने गहन और वैज्ञानिक अध्ययन किया है। कला के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ ने कला का एक नवीन रूप समाज के सामने प्रस्तुत किया जिसे रवीन्द्र आर्ट नाम से जाना गया और भविष्य में कलाकारों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ।

जीवन और जगत के परम सत्य की खोज का नाम ही दर्शन है। इस प्रयास के फलस्वरूप मानव ने जो भी विचार व्यक्त किये उन्हें दार्शनिक, चिन्तन की संज्ञा दी जाती है। भारत में दार्शनिक चिन्तन की गहराईयां व ऊचाईयाँ बेजोड़ हैं। इस प्रकार का चिन्तन भारतीय की अक्षय पूंजी है। प्राचीन दर्शन वैदिक, बौद्ध, जैन स्थान पर स्थिर थे द्य नाथ पंथियों का प्रभाव नेपाल के आस-पास अधिक था लेकिन सिद्धों की परम्परा में परिवर्तन आ गया। तंत्र-मंत्र के झूठे प्रभाव और प्रयोग और प्रयोग पाखंड बड़ा था यह इतिहास विदित है कि नाथों और सिद्धों का प्रभाव अशिक्षित जनता पर अधिक रहा है उत्तर भारत में कबीर के मत से प्रभावित संत व संतों के उपासकों की संख्या सर्वाधिक थी कश्मीर हिमाचल आदि प्रदेशों हमें शैवमत का प्रत्यभिज्ञान दर्शन और आनंदवाद का सर्वाधिक प्रभाव था द्य छायावाद के शिर्षस्थ महाकवि जयशंकर प्रसाद शैव मत से प्रभावित थे। उनकी प्रसिद्ध रचना शकामायनी शका मूल दर्शन ही शैवमत का प्रत्यभिज्ञान दर्शन है जिसमें आनंदवाद

की प्रतिष्ठा की गई । श्री अरविंद ने सावित्री नामक ग्रंथ लिखकर जिस दर्शन को स्थापित किया, उनकी प्रसिद्ध देश विदेश में हुई द्यमहापुरुष रविंद्र नाथ के मानवतावादी दर्शन का विद्वानों द्वारा व्यापक स्वागत हुआ ।

निष्कर्ष—

प्रत्येक साहित्यकार अपने समय से अवश्यमेव में सम्पृक्त होता है ,अतः उसके साहित्य को समझने के लिए युगीन परिस्थितियों का ज्ञान आवश्यक है डॉक्टर विद्या निवास मिश्र के निबंधों में स्वतंत्रता से पूर्व और बाद की सामाजिक, राजनीतिक ,आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां प्रतिबिम्बित हुई है। स्वतंत्रता से पूर्व भीतर से दीप्त किंतु सादियों का गुलाम, दबा, कुचला ,विपन्न,भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए जूझ रहा था द्यस्वतंत्रता ने उसके मन में अनंत सपनों का संचार किया किंतु शीघ्र ही मोह भंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है द्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कारण वोटो की राजनीति चली । राजनीति सर्वप्रमुख हो गयी । इसने पूरे देश को अपने प्रभाव में ले लिया । इसकी शुचिता धीरे-धीरे समाप्त होती चली गयी । यह लोक सेवा के लिए न होकर स्वार्थ सेवा का साधन बन गयी । इसी से आज तो राजनीतिक ने अपराध से गठजोड़ भी कर लिया । देश के आर्थिक विकास के लिए बड़े-बड़े उद्योग लगाए गए और बीसवीं सदी के नवें दशक में उदारीकरण की नीतियों को अपनाने से बाजार बाद का बोलबाला हो गया है । जिससे लघु उद्योग धन्धे चौपट होने के कगार पर हैं तथा महँगाई, गरीबी और बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि हो रही है द्य सामाजिक क्षेत्रों में नारी, दलितों एवं पिछड़ों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक कानून बने हैं । यद्यपि इन की स्थितियों में सुधार आया है तथापि समाज अभी शोषण मुक्त नहीं हो पाया है । समानता लाने की आड़ में राजनीति ने सम्प्रदाय, जाति, प्रान्त एवं भाषा आदि के आधार पर समाज को विभाजित करने का चक्र किया है । भौतिकता प्रधान भोगवादी पश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण समाज में व्यक्तिवादिता नहीं है और प्रेम ,त्याग आदि मानवीय मूल्यों क्षरण हुआ है और संस्कृति विघटन की स्थिति है । इन सभी स्थितियों को डॉ० विद्यानिवास मिश्र जी ने अपने निबन्धों में अभिव्यक्त किया है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 डॉ० वचनदेव कुमारः— लेखक और परिवेश, पृष्ठ संख्या 9 ।
- 2 दिनकरः—संस्कृति के चार अध्याय,पृष्ठ संख्या405 ।
- 3 पंडित जवाहर लाल नेहरू— इण्डियाज फ्रीडम, पृष्ठ संख्या 24 ।
- 4 हरिचरण शर्मा— नई कविता का मूल्यांकन, पृष्ठ संख्या 89 ।
- 5 डॉ० कृष्ण बिहारी मिश्रः— आधुनिक, सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य, पृष्ठ संख्या 318 ।
- 6 डॉ० देवी शंकर अवस्थीः— लहर जीवन,पृष्ठ संख्या 24,26 ।

7 रामकुमार वर्मा— राजनीतिक भारत, पृष्ठ संख्या 267 ।

डॉ० अनीता

मोबाइल नम्बर 9368775452

ग्राम व पोस्ट भाऊपुर पी० टी० सी०

अम्बाला रोड सहारनपुर

पिन – 247002

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानियों में नारी जीवन है। आज के वर्तमान समय में नारी पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है वो हर जगह समान उपस्थिति दर्ज करा रही है। मनीषा कुलश्रेष्ठ एक महिला है तथा अपने साहित्य में भी महिलाओं के जीवन में आने वाली कठिनाइयों तथा उनसे उबरने की क्षमता का वर्णन बड़े ही सटीक ढंग से किया है। समाज का यथार्थ चित्रण पाठकों के सामने प्रस्तुत करती हैं कि किस रूढ़िवादिता तथा हीन मानसिकताओं के कारण नारी आज भी बाहर ही नहीं बल्कि अपने घर में भी शोषण का शिकार हो रही है। आज के वर्तमान समय में जब हम आधुनिक भाव-बोध तथा आधुनिक विचारधारा की बात करते हैं पर जब बात महिला वर्ग की आती है तो आज भी उसकी स्थिति उस कठपुतली की भाँति है जिसकी डोरी समाज के हाथों में हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ ने अपनी कहानियों से चाहे वह 'कठपुतलियाँ' शीर्षक हो या 'कुरजा' तथा फॉस कहानी द्वारा नारी जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। मनीषा जी ने अपनी कहानी 'रंग-रूप-रस-गंध' के माध्यम से स्त्री की विडम्बना को व्यक्त किया है। अधिकांश स्त्री विधवा होने को अपने जीवन का अन्तिम पड़ाव मान लेती हैं। अपना बचा हुआ जीवन काशी में ईश्वर की स्तुति को सौंप देती हैं। विडम्बना, यह है कि चाहे काशी हो या बनारस कोई भी आध्यात्मिक स्थल हो महिलाओं का शोषण हर जगह होता है। बड़े-बड़े मौलवी, पंडित भी इससे अछूते नहीं हैं।

आदिवासी लड़कियाँ ही नहीं बल्कि समाज में बहुत सी लड़कियों को समाज में प्रचलित अव्यवस्था के कारण यौन शोषण का शिकार बनाया जाता है। यदि कोई महिला या लड़की कहीं पर इसकी शिकायत दर्ज करवाना चाहे तो उसे जीते जी मरवा दिया जाता है। अनेक प्रकार के भय दिखाय जाते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं। स्त्री को स्वावलम्बी बनाने के लिए स्त्री शिक्षा तथा रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं हर क्षेत्र में महिला अग्रसर हैं रसोईघर से सरकार चलाने तक परन्तु अब भी अधिकतर महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं। अपने कथा साहित्य में मनीषा कुलश्रेष्ठ ने नारी जीवन को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। मनीषा जी ने स्त्री की हर स्थिति का वर्णन किया है किस प्रकार से नारी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा मानसिक पहलुओं से शोषित होती जा रही हैं। किस प्रकार से नारी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई जा रही है।

मनीषा जी ने अपनी कहानियों में नारी की मनोस्थिति को परखते हुए उनके मरते स्वाभिमान, दुख-दर्द, आर्थिक तंगी,

बेमेल-विवाह आदि को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मनीषा जी की कहानी 'कठपुतलियाँ' दहेज प्रथा को उजागर करती नारी के दुखों से ओत-प्रोत कहानी है। जिसमें आर्थिक मजबूरी तथा अनमेल विवाह तथा प्रेम का वर्णन बहुत ही यथार्थपरक ढंग से किया गया है। कहानी सुगना, रामकिशन तथा जोगिन्दर इन तीन पात्रों के ईर्द गिर्द घूमती हैं। सुगना तथा रामकिशन कहानी के मुख्य पात्र हैं। सुगना को कैसे 'कठपुतली' की तरह नचाया जाता है। जीवन में आए उतार-चढ़ाव कैसे पूरी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देते हैं। कहानी जैसलमेर के ग्रामीण परिवेश की है। सुगना के पिता के गुजर जाने से जोगिंदर से उसका रिश्ता टूट जाता है लेन-देन न हो पाने से। तेरह साल की सुगना तीस साल के रामकिशन के साथ ब्याह दी जाती है। जो विधुर तथा अपाहिज व दो बच्चों का पिता है। सुगना अपने प्रेमी जोगिंदर द्वारा गर्भवती हो जाती है, इससे उसे सामाजिक क्रूरताओं का सामना करना पड़ता है तथा अग्नि परीक्षा तक देने तक की नौबत आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में उसका पति रामकिशन उसका साथ देता है तथा अपने बच्चे के हाथ सुगना को बचाने के लिए तेल भेजता है – "बाई देख न इधर ... ये बापू ने भेजा है. तेल है ये..... कब्रों पर उगने वाले ग्वारपाठे और रेत की छिपकली का तेल मल ले हाथ पे ... हाथ नहीं जलेगा न ही फफोले होंगे। परसों चार घंटे साइकिल चलाकर सीमा पार के नजदीक डटे हुए गाड़िया लोहारों से लाया है, बापू।" इससे यह साबित हो जाएगा कि बच्चा रामकिशन का ही है। यहाँ पर एक और पुरुष स्त्री के शारिरिक व मानसिक शोषण का कारण है तो दूसरी और प्रेम व मानवीय भावना को दर्शाता है। स्त्री को ही क्यों आज भी अग्निपरीक्षा देने पड़ती है। पंचायतों द्वारा न्याय के नाम पर आज भी शोषण जारी है।

साहित्यकार कभी-कभी ऐसी कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है जो उनकी आत्मा को झकझोर देती है 'फॉस' कहानी भी कुछ इसी तरह की है। एक बिना मां की अविवाहित लड़की अंतिमा की कहानी है जो अपने ही घर में अपने ही पिता द्वारा बलात्कार की शिकार होती है। यह कहानी एक बाप व बेटी के पवित्र रिश्ते पर सवाल पैदा करती है जब एक लड़की अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर हम क्या आशा रख सकते हैं सुरक्षा की। यह भरोसा तथा बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करती है। कहानी में अन्तिमा को पिता के मरने का न तो सुख था, न दुख था, न शोक न उल्लास। उसके पिछले घावों के खुरंद अभी हरे ही थे..... वह अपमान और पीड़ा दोनों की भयावह और धिनौनी कल्पना से सिहर गई। मन में छिपे क्रोध की एक चिंगारी

सुलग कर पूरे वजूद को दावानल की तरह सुलगाने लगी। उसने अपनी कोहनी से पूरे दमखम के साथ उसकी पसलियों पर वार किया, वह चीख कर वही बैठ गया। तब का जो बिस्तर से लगा तो फिर उठा ही नहीं।¹² कहानी में मानसिक तथा शारिरिक पीड़ा के साथ-साथ घर में ही असुरक्षा को दिखाया गया है जहां पर पिता ही अपनी पुत्री के दुःख का कारण बना है।

‘कालिंदी’ कहानी में वेश्यावृत्ति से ग्रस्त जीवन को दिखाया गया है कि कालिंदी की मां भी धंधा करती थी। कालिंदी ने उसका विरोध किया तो मां ने कहा कि वह यह काम न करेगी तो बच्चों को क्या खिलाएगी वह इस माहौल में बदनाम हो चुकी है उसे कोई अच्छा काम भी नहीं देगा। वेश्यावृत्ति समाज की बहुत बड़ी समस्या है। एक बार धकेल देने से स्त्री वहीं फसकर रह जाती है। कहानी बयां करती है कि वहा पैदा होने वाले बच्चों का भविष्य भी अंधकार में चला जाता है। कालिंदी इस जीवन से बचना चाहती थी। एक युवक ने उसे शादी के सपने दिखाकर इस माहौल से दूर ले जाने का व सम्मान पूर्वक जिंदगी बिताने का वादा करके उसका शोषण करता रहा। जो पहले से ही शादी-शुदा था तथा वह युवक कालिंदी को अजन्मे बच्चों के साथ वापस उसके घर छोड़ देता है मां द्वारा पीटे जाने से वह सात माह के बच्चे को जन्म दे देती है। कालिंदी अपने बच्चे को पालने के लिए वेश्याओं की मालिश करने का काम करती है वह न्यू मॉडलिंग का काम करती है जहां नग्नता को नहीं बल्कि कला को महत्व दिया जाता है। जो बहुत ही कठिन काम है। कालिंदी का बच्चा भी उस पर शक करता है परन्तु कालिंदी अपना तथा अपने बच्चे की जीविका चलाने के लिए एक सही दिशा चुनती है न कि वेश्यावृत्ति को। स्त्री के दर्द को यहां दिखाया गया है कि किस मजबूरी में वह स्वयं को बेचती है। तथा उनको कितनी शारीरिक व मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ता है।

‘मास्टरनी’ कहानी स्त्री समस्याओं को उजागर करती है। कहानी की पात्र ‘सुषमा’ आर्थिक रूप से मजबूत है दोनो पति पत्नि नौकरी करते हैं अलग – अलग क्षेत्र में ‘सुषमा’ तथा उसका पति एक-एक बच्चे को अपने साथ रखते हैं। सुषमा अपना तबादला करवाना चाहती है वह पति तथा बच्चे की परवाह करती है ताकि सभी साथ में रहे। पति से तबादला के लिए कहती है परन्तु वह आलस्य के कारण नहीं जाता स्वयं जाएगी तो लोगों की गलत नजरें उनको घुरेगी। पति उस पर ही धौंस जमाता है तथा कहता है छुट्टियों में आई है महारानी यू नहीं कि ठीक से खाना- वाना बना कर खिलाये, साल भर तो खुद ही ठेपते हैं अपनी और तेरे लाडले की रोटी अभी आई हैं, आते ही साली ट्रांसफर के चक्कर में पड़ गयी।¹³ सुषमा परिवार के साथ रहना चाहती है। पति तथा सास के ताने भी सुनती है जिस परिवार पर वह न्यौछावर होना चाहती है वह उसकी जरा भी चिंता नहीं करता। नारी आज भी घर व नौकरी के बीच मझधार में है आज

भी उसे स्वतंत्रता नहीं मिली है जबकि वह आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। सुषमा के पति का चरित्र अच्छा नहीं है इसी कारण कोई कामवाली टिक नहीं पाती? उसकी गैरमौजूदगी में पड़ोस की दीपा भी उसके घर आती है। यह बात बेटा द्वारा सुषमा को पता चलती है। एक नारी की मानसिक तथा शारीरिक पीड़ा को यथार्थरूप से इस कहानी में दिखाया गया है। सुषमा शादी से पहले कितना अलग थी। अब वह पूरी बदल चुकी थी। परिस्थितियों ने उससे उसकी चंचलता, हंसना, गाना, बजाना सब छीन लिया था। उसे वैसा दाम्पत्य जीवन नहीं मिला जैसा वो चाहती थी। इस कहानी में दहेज की समस्या को भी चित्रित किया गया है? आज दहेज प्रथा ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया है, जो दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है।

‘कुरजा’ कहानी में एक नारी को डायन बताकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। गाँव में फ़ैली बिमारी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। ‘क्या यही है वैराग्य’ कहानी में दिखाया गया है कि सुमेधा कायस्थ परिवार की बेटे तथा जैन खानदान की वधु है। एक महिला डाक्टर होने के पश्चात् भी वह ससुराल की परम्पराओं को खुश होकर निभाती है। रहन-सहन के तौर तरीके तथा खान पान में परहेज तथा संस्कृति का निर्वहन करती हैं। यहाँ पर महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वह खुद के स्वस्थ का ध्यान ही नहीं रख पाती। ग्रामीण महिलाएं महिला डाक्टर न होने पर पुरुष डाक्टर के सामने अपनी परेशानी नहीं बता पाती। यहाँ पर महिलाएं तब तक ध्यान नहीं देती जब तक वह बिमारी गंभीर रूप धारण न कर ले। इस तरह का समर्पण इन्हें बड़ी बिमारी का शिकार बना देता है। “अधिकतर भारतीय महिलाएँ अपने स्वास्थ्य को तब तक अहनियत नहीं देती जब तक वह बड़ी बिमारी बन कर सामने न आ जाए, उस पर आंतरिक समस्याएं तो सबसे ज्यादा छिपाई और उपेक्षित की जाती है।¹⁴ कभी-कभी इन महिलाओं के लिए स्वास्थ्य से बड़ा धर्म हो जाता है। ये सामाजिक आडम्बर इनकी जान का खतरा बन जाता है। आज भी महिलाएं अपनी अंदरूनी बिमारी को महिला डाक्टर न होने पर पुरुष डाक्टर से नहीं बता पाती। बिमारी होना कोई अपराध नहीं है। किसी को भी हो सकती है।

निष्कर्ष :-

मनीषा जी ने अपने कथा साहित्य में नारी जीवन की हर स्थिति का वर्णन हमारे सामने एक शीशे की भांति किया है। मनीषा जी नारी के लचीले तथा सरस स्वभाव को पढ़ने में अग्रणी रही हैं। कहानियों में मनीषा जी ने नारी जीवन के यथार्थ से हमें अवगत कराया है। उनका जीवन भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से किस प्रकार से गुजरा है जहाँ पर शारीरिक, मानसिक तथा हर प्रकार का शोषण

उनके साथ हुआ है। यदि नारी घर में कमा भी लाए हो उसकी स्वतंत्रता पुरुष के हाथ में ही रहती है। पित्रसत्तात्मक समाज आर्थिक दृष्टि से मजबूत स्त्री को भी अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। मनीषा जी समाज समय तथा चुनौतियों के प्रति भी सचेत रहती है।

संदर्भ सूची

1. मनीषा कुलश्रेष्ठ : 'कठपुतलियां' भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली संस्करण-2010, पृ. 20
2. मनीषा कुलश्रेष्ठ, 'कुछ भी तो रूमानी नहीं' (2008) 'अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद पृ. 43
3. मनीषा कुलश्रेष्ठ, 'कुछ भी तो रूमानी नहीं' (2008) 'अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद पृ. 69
4. मनीषा कुलश्रेष्ठ कुरंजा (कहानी)
5. मनीषा कुलश्रेष्ठ, 'कुछ भी तो रूमानी नहीं' (2008) 'अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद पृ. 57

ममता यादव

शोधार्थी, हिन्दी विभाग
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर,
रोहतक



सारांश

सुदामा पांडे 'धूमिल' उन कवियों में से एक हैं जो आजादी के बाद के कवियों में गिने जाते हैं। उनकी कविताएँ जनतंत्र से प्रभावित रही हैं। आजादी के बाद के बदलते भारत का जनतंत्र उनकी कविताओं का मूल्यबोध रहा है। सुदामा पाण्डे धूमिल हिन्दी साहित्य जगत में जितने लोकप्रिय कवि रहे हैं। उससे कहीं ज्यादा वे विवादों में गिने जाते रहें हैं। उन्होंने आजादी के स्वप्न और उसके स्वप्न भंग की पूरी प्रक्रिया को कविताओं के माध्यम से संसदीय नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया है। धूमिल की 'पटकथा' जनतंत्र पर लिखी गई एक कविता है। धूमिल की 'पटकथा' पढ़ते ही मुक्तिबोध की 'अंधेरे में' ध्यान हो आती है। 'पटकथा' में संसदीय लोकतंत्र की कथा चुनावी राजनीति की जबानी और आम आदमी यानी जनतंत्र की विवशता है। जबकि 'अंधेरे में' आजादी के बाद दिखने वाले आम आदमी के अंधेरे की घुटन से त्रस्त छिपी वेदना है।

'पटकथा' जनतंत्र के आवेग के उतार-चढ़ाव की कथा है। जिसमें काव्य-नायक 'मैं' आम व्यक्ति है। वह सपने में हमशक्ल से भेंट करता है। वह हमशक्ल हिंदुस्तान है। स्वप्न और जागृति की इस बुनावट और कविता में अनुभव के खास ढंग के फैलाव से मुक्तिबोध के जनतंत्र की याद आती है।

"हमशक्ल खड़ा है

तुमने पहचाना नहीं-मैं हिंदुस्तान हूँ।"

यह हिंदुस्तान आजादी, जनतंत्र, संसद, जनता की परिभाषा को गढ़ता है और देश की तत्कालीन सत्ता-व्यस्था के विरुद्ध यह हमशक्ल जनता को जागृत करते हुए मूर्च्छित हो जाता है। इसमें यह पात्र हमशक्ल लोक सत्ता का हिस्सा है। कवि कहता है कि-

"मासूमियत के हर तकाजे को

टोकर मार दो।

अब वक्त आ गया है कि तुम उठो

और अपनी ऊब को आकार दो।"

धूमिल का हमशक्ल एक सुंदर स्वप्न की तरह है। जिसमें वह आजादी के बारे में कहता है। वह आजादी भी उसे स्वप्न जैसी लग रही है। धूमिल कहते हैं कि-

"खुद मेरा स्वर

मुझे अजनबी लग रहा था

मैंने कहा-आ-जा-दी"

देश की आजादी के सुनहरे स्वप्नों को सभी ने देखा और ये स्वप्न कुदकुदाने लगते हैं। 1960 ई. के बाद आजादी के वही स्वप्न भयावह रूप ले लेते हैं। भारतीय जनतंत्र पर राजतंत्र हावी होता प्रतीत

होने लगता है। एक अजीब सी बेबसी जन्म लेती है। जिसमें जनता कुछ नहीं कर सकती और वह निरीह बन जाती है।

"ऐसा जनतंत्र है जिसमें

जिंदा रहने के लिए

घोड़े और घास को

एक जैसी छूट है

कैसी विडंबना है

कैसा झूठा है

दरअस्ल, अपने यहाँ जनतंत्र

एक ऐसा तमाशा है

जिसकी जान

मदारी की भाषा है।"

कवि धूमिल विश्वोभ के भी कवि हैं। यह विश्वोभ सहन न कर पाने की यातना से जन्मा है। उनका विश्वोभ दो यातनाओं से जन्मा है एक तो आजादी से मोहभंग होना दूसरा जनतंत्र की असफलता। आजादी से पूर्व नेहरू युग था उसके खास मूल्य और आदर्श थे। लेकिन आजादी के बाद नेहरू-युग से ही मोहभंग हो जाता है। परमानंद श्रीवास्तव कहते हैं कि "नेहरू-युग का अर्थ था-कुछ खास मूल्य और आदर्श, जिसके पीछे थी इतिहास की उनकी अवधारणा। प्रगति और विकास की ऐतिहासिक परिकल्पना, सत्य अहिंसा, सामाजिक न्याय जैसे शील और विचार। नेहरू-युग का अंत जिस मोहभंग के साथ हुआ उसका व्यापक अहसास समूची भारतीय कविता में किसी न किसी रूप में होना चाहिए।"

कवि धूमिल ने लोक सत्ता के प्रत्येक पक्ष पर पैनी दृष्टि रखी है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं और सरकारी तंत्र की कमियों पर गहरी चोट की है। वे बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार व सरकारी तंत्र की उदासीनता पर तंज कसते हैं। धूमिल की कविताओं में आम जनता को स्थान दिया गया है। उनकी कविताओं में सौंदर्य बोध न होकर यथार्थवाद मौजूद है। वे कविता के प्रति सीधी प्रतिक्रिया रखते हैं। केदारनाथ सिंह कहते हैं कि "सौंदर्यवादी रुझानों के विरुद्ध एक सीधी प्रतिक्रिया हुई। सृजनात्मक विद्रोह के वे तत्त्व जो अज्ञेय आदि की कृतियों से गायब हो गए थे, इन रचनाकारों की कृतियों में उभरकर आने लगे। इस अंतर के साथ कि इनके विद्रोह के पीछे काम करने वाला मानसिक विश्वोभ 'साहित्यिक' कम और 'ऐतिहासिक' अधिक है।" यथार्थवाद में मोहभंग की प्रक्रिया है। यह मोहभंग हमें अज्ञेय के बाद के कवियों धूमिल, पूर्ववर्ती रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मुक्तिबोध की कविताओं में देखने को मिलता है। आजादी के बाद की मोहभंग प्रक्रिया से जन्मी कविता की उपयुक्तता धूमिल में

मिलती है। प्रगतिवाद का आरम्भ प्रगतिशील आंदोलन से माना जाता है। प्रगतिशील कविताएं लिखी जाने लगी। कविता में राजनैतिक विचारधारा का प्रश्न उपेक्षित हो अपेक्षित था।

कविताओं में राजनैतिक विचारधारा का प्रश्न उपेक्षित हो गया था। प्रयोगवाद के बाद प्रभाव कम होने लगता है। मुक्तिबोध की 'अंधेरे में' धूमिल की 'पटकथा' राजनैतिक प्रश्न को फिर से उठा देते हैं। अंधेरे में फँटेसी है। पटकथा में लोकतंत्र और विकास के मुद्दे को प्रतिरोध की भाशा में एक नए तेवर के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी कविता लोक सत्ता पर आधारित संसदीय राजनीति यानी जनतंत्र के नाम पर सिर्फ बहुमत की शर्तों को पूरा करती हुई राजनीति की सबसे पुरजोर आलोचना है। आजादी के बाद जनतंत्र को सिर्फ चुनाव का पर्याय बना दिया था। धूमिल जनतंत्र को जनता का पर्याय मानते हैं। आज जनतंत्र की भयावह स्थिति देखने को मिलती है। वहाँ पहले लिखी धूमिल की पटकथा में वही स्थिति देखने को मिलती है। स्वतंत्र भारत देश में जनतंत्र को महज ऊपरी पौशाक की तरह माना जा रहा है। धूमिल की कविताओं में लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध एक प्रतिरोधी चिन्कार है—

“उस मुहावरे को समझ गया हूँ
जो आजादी और गाँधी के नाम पर चल रहा है
जिससे न भूख मिट रही है, न मौसम
बदल रहा है।
लोग बिलबिला रहे हैं
पत्ते और छाल
खा रहे हैं।”

सुदामा पांडे जनतंत्र देश के राजतंत्र से बिल्कुल अलग है। कविता में व्यक्तिवाचक नायक का प्रयोग करते हुए राजतंत्र की पोल खोलते हैं—

“अब भेंट देखते हैं
कल सुदामा पांडे मिले थे
हरहुआ बाजार में। खुश थे। बबूल के
वन में बसंत से खिले थे।
फटकारते हुए बोले, यार! खूब हो
देखते हो और कतराने लगते हो,
गोया दोस्ती न हुई, चलती—चलती हुई ऊब हो
आदमी देखते हो, सूख जाते हो
पानी देखते हो गाने लगते हो।
वे जोर से हँसे! मैं भी हँसा।
संत के साथ—
बुरा आ फँसा”

साठोत्तरी हिंदी कविता के विलग कवि धूमिल रहे हैं। उन्होंने हिंदी कविता को अकविता के अंधकार से निकालकर सामाजिक—राजनीतिक प्रतिबद्धता से जोड़ने का कार्य किया। जनतंत्र की त्रासदी को भोगते हुए एक आम भारतीय नागरिक की

पीड़ा, बेचैनी और आक्रोश को कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है। धूमिल का मन लोक सत्ता में रमा है। वे कहते हैं कि—

“बाहर हवा थी
धूप थी
घास थी
मैंने कहा आजादी.....
मुझे अच्छी तरह याद है—
मैंने यही कहा था
मेरी नस—नस में बिजली
दौड़ रही थी
उत्साह में
खुद मेरा स्वर
मुझे अच्छी तरह याद है—
मैंने यही कहा था
मेरी नस—नस में बिजली
दौड़ रही थी
उत्साह में
खुद मेरा स्वर
मुझे अजनबी लग रहा था.....
मैं अपनी सम्मोहित बुद्धि के नीचे
उसी लोकनायक को
बार—बार चुनता रहा
मगर एक दिन स्तब्ध रह गया।
हर तरह धुआँ है
हर तरह कुहासा है”
‘रोटी और संसद’ कविता में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो खाई दिखाई पड़ती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण संवादहीनता भी है। जनता से बार—बार संवाद की कोशिश और जनता के लिए उद्बोधन उनकी कविता की बनावट में घुले—मिले हैं। संसद के मौन के अलावा उन्हें जनता की तटस्थता भी परेशान करती है। संसद के मौन और जनता की तटस्थता के फर्क को धूमिल बखूबी जानते हैं। वहीं जनता की तटस्थता उनकी दहनीय स्थिति और निस्सहायता का परिणाम है। वे कहते हैं कि—
‘वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं’
जनता से उनकी अपेक्षाएँ हैं वे कहते हैं कि—
“मैं फिर कहता हूँ कि हर हाथ में
गीली मिट्टी की तरह हॉ—हॉ मत करो
तनो
अकड़ो”

अमरबेलि की तरह मत जियो जड़ पकड़ो धूमिल के लिए नंदकिशोर नवल कहते हैं कि “वे नहीं चाहते कि जनता गीली मिट्टी की तरह लिजलिजी हो, जिसे जो चाहे अपने अनुसार दे दे। इसी तरह जनता को अमरबेलि की तरह परनिर्भर भी नहीं देखना

चाहते। वे चाहते हैं कि जनता तने और अपनी जमीन पर मजबूती से पांव रोपकर खड़ी हो।”

धूमिल को जनवादी कवि कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी वे अपनी कविताओं में लोक सत्ता की तलाश करते हैं इसके लिए वह अन्य जनतंत्र को ढूँढते नजर आते हैं।

“मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है।”

अशोक वाजपेयी कहते हैं कि “भारतीय मनुष्य की समकालीन तलाश का, उसकी नई आक्रामकता का, सीधा पर नाटकीय वक्तव्य माना है।” जनतंत्र की विसंगतियाँ उस समय के आसपास लिख रहे कवियों की चिंता का मूल स्वर है। रघुवीर सहाय की कविताओं में लोकतंत्र को लेकर चिंता, क्षोभ और आक्रोश का भाव है। संसद की कार्य प्रणाली की निरर्थकता को देखते हुए कवि लिखते हैं कि –

“जितनी देर गोल गुंबद गूँजता रहे, उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से गूँज थमते—थमते फिर हँसना”

अतः सुदामा पाण्डे धूमिल ने कविता में जनतंत्र की विसंगतियों के महीन रेशे बुने हैं। इस कविता की परतों को खोलकर देखे तो भारत की लोक सत्ता की मजबूती का पता चलेगा लेकिन भारत की सामाजिक संरचना और राजनीतिक व्यवस्था की विडंबनाओं की अनगिनत परतों को खोलती है। धूमिल की कविता आदमी होने की तमीज है। भाशा ही वह जमीन है, जहाँ खड़े होकर वे अपनी लोक यात्रा जारी रखते हैं। उनकी भाशा में आक्रोश, खीझ और क्षोभ का स्वर सुनाई देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

संसद से सड़क तक, सुदामा पाण्डे धूमिल, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008

मेरे समय के शब्द, केदारनाथ सिंह, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2016

प्रतिमानों के पार, परमानंद श्रीवास्तव, शैवाल प्रकाशन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, संस्करण 2009

हँसो हँसो जल्दी हँसो, रघुवीर सहाय, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2001

1. अंधेरे में, मुक्तिबोध, पृष्ठ 25
2. पटकथा, धूमिल, पृष्ठ 12
3. पटकथा, धूमिल, पृष्ठ 29
4. पटकथा, धूमिल, पृष्ठ 21
5. कविता का उत्तर जीवन, परमानंद श्रीवास्तव, पृष्ठ 211
6. साठोत्तरी हिंदी कविता और धूमिल, केदारनाथ सिंह, पृष्ठ 39
7. पटकथा, धूमिल, पृष्ठ 32

8. वही, पृष्ठ 33

9. पटकथा, धूमिल, पृष्ठ 12

10. संसद और रोटी, धूमिल, पृष्ठ 22

11. प्रतिमानों के पार, परमानंद श्रीवास्तव, पृष्ठ 33

12. संसद और रोटी, धूमिल, पृष्ठ 53

13. कभी—कभी, अशोक वाजपेयी, पृष्ठ 5

डॉ० सुनील कुमार
सहायक प्रोफेसर,
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
जसौर खेड़ी, झज्जर

सारांश

आज उड़ान भरी है देखो
सपनें हों साकार
धीरे—धीरे रूप को अपने
दे रही वो आकार।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। इसी 33 फीसदी में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है।

ऐसे बदलेगी लोकसभा की तस्वीर

- ❖ कुल सदस्य—543
- ❖ मौजूदा सदन में महिलाएँ—82
- ❖ नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रभावी होने के बाद महिला सांसद होंगी—181

बदलाव की बड़ी कोशिश—महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने के लिए बरसों से मांग की जा रही है महिलाओं के हेतु 1/3 एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था करने वाला 128वाँ संविधान संशोधन विधेयक आ चुका है। लोकसभा से सर्वसम्मति से पास भी हो चुका है। लोकसभा जहाँ इसके पक्ष में 454 मत पड़े वहीं विरोध में केवल 2 ही मत पड़े। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सबसे बड़ी बात यह है कि हर दल इसके महत्व को स्वीकार करता है यह सच है कि हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें महिलाओं को असमानता का देश झेलना पड़ता है। और इसकी वजह यही है कि एक वर्ग शक्तिशाली है और दूसरा कमजोर। लेकिन कोई भी देश या समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जबतक कि उसकी आधी आबादी अर्थात् महिलाओं की स्थिति में सुधार ना आए। इसी ध्येय को समझते हुए आज समाज का हर तबका महिला आरक्षण को आवश्यक बताता है।

नए संसद भवन में 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ। 20 सितंबर को लोकसभा में पास होने के बाद 21 सितंबर को यह राज्यसभा से पारित हुआ। अब राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्मु ने विधेयक को मंजूरी दे दी है जिससे यह कानून में बदल गया।

कानून में अमल लाने के लिए क्या करना होगा?—इसको मूर्त रूप लेने से पहले कई अवरोध पार करने होंगे। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का समर्थन पाने के साथ जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

क्या होता है परिसीमन ?

यह जनसंख्या में बदलाव को दर्शाने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को धिरे से निर्धारित करने की प्रक्रिया है।

महिला आरक्षण से संबंधित संविधान (128वाँ संशोधन) विधेयक के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसके कानून बनने के बाद होनेवाली जनगणना के आंकड़ों को पूरा होने या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः सीमांकन होने के बाद ही यह प्रभाव में आएगा।

संविधान विशेषज्ञों की राय—संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के बाद इसे कानून का रूप देने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं की मंजूरी जरूरी होगी। संविधान में अनुच्छेद 334 के बाद जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए अनुच्छेद 334 ए के अनुसार पहली जनगणना के संगत आंकड़े प्रकाशित होने और परिसीमन की कवायद पूरी होने पर ही यह विधेयक प्रभाव में आएगा। संविधान के अनुच्छेद 82 (2002 में यथासंशोधित) के अनुसार 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस लिहाज से 2026 के बाद पहली जनगणना 2031 में होगी जिसके बाद परिसीमन किया जाएगा। सरकार ने 2021 में जनगणना की प्रक्रिया पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रोक लगा दी थी। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण को वास्तविक रूप देने के लिए सरकार को इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराना होगा।

- ❖ भारत के अलग-अलग राज्यों में विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी—

यूपी—403 / 134

मध्यप्रदेश—230 / 77

राजस्थान—200 / 67

महाराष्ट्र—288 / 96

तमिलनाडु—234 / 78

पं० बंगाल—294 / 98

पंजाब—117 / 39

कर्नाटक—224 / 75

केबल—140 / 47

आंध्रप्रदेश—175 / 58

तेलंगाना—119 / 40

असम—126 / 42

गुजरात—182 / 61

हरियाणा—90 / 30

जम्मू कश्मीर—90 / 30

गोवा—40 / 13

हिमाचल—68 / 23

उत्तराखंड—70 / 23

दिल्ली—70 / 23

ओड़िसा—147 / 49

झारखंड—81 / 27

बिहार—243 / 81

मणिपुर—60 / 20

नागालैंड—60 / 20

अरुणाचल प्रदेश—60 / 20

मेघालय—60 / 20

त्रिपुरा—60 / 20

पडुचेरी—30 / 10

सिक्किम—32 / 11

मिजोरम—40 / 13

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सारी दुनिया में सम्मान होता है तो वह इसलिए कि वहाँ बहस की गुंजाइश रहती है। स्वस्थ बहस की उस परंपरा को कायम रखते हुए महिला आरक्षण के मामले पर हर दल को एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए बदलाव की ओर बढ़ने का प्रयास जारी रखना चाहिए महिलाओं को आरक्षण से निश्चय की बड़ा सामाजिक बदलाव आएगा।

इसके उद्देश्य—

- (i) प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएँ हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं नीति निर्धारण में भी माता-बहनों के योगदान की जरूरत है।
- (ii) संविधान संसद विधेयक को संसद के विशेष सत्र में पेश करते हुए पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की घोषणा की।

- (iii) इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को विस्तार देना है।
- (iv) इस विधेयक के पास होने पर महिलाओं को लोकसभा में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
- (v) नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी।

करीब 27 साल से यह बिल लटका हुआ था। करीब 8 बार संसद में पेश हुआ लेकिन हर बार रिजेक्ट हुआ 9वीं बार मोदी सरकार ने इसे संसद में पास कराया।

फायदे हेतु कुछ साल का इंतजार अभी बांकी — संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हो गया लेकिन इसके लिए अभी देश की महिलाओं को 5 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। आरक्षण 15 साल के लिए होगा लेकिन आरक्षण परिसीमन अनिवार्य है। और 2021 में जनगणना कोविड की वजह से नहीं हो पाई। जनगणना होने के बाद परिसीमन होने पर ही आरक्षण का फायदा मिलेगा। दोनों कामों में करीब 2-3 साल लगेंगे। ऐसे में 2029 तक ही आरक्षण मिल पाएगा।

आवश्यकता—

- ❖ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में भारत के प्रदर्शन में गिरावट आई है तथा महिला मंत्रियों की संख्या वर्ष 2019 में 23.1: से घटकर 2021 में 9.1: तक पहुँच गई है।
- ❖ सरकार के आर्थिक सर्वेक्षणों में भी माना गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है।

विभिन्न सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों ने गाँवों में समाज के विकास और समग्र कल्याण में सराहनीय कार्य किया है तथा उनमें से कई निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर काम करना चाहेगी हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में हैं—

- 1) उचित राजनीतिक शिक्षा की कमी
- 2) समाज में महिलाओं की कम वित्तीय शक्ति
- 3) यौन हिंसा
- 4) महिला और पुरुषों के बीच घरेलू कार्य का असमान वितरण।

महत्वः—महिला राजनीतिक सशक्तिकरण तीन मूलभूत सिद्धांतों पर

आधारित है।

डॉ० रेणुका पोद्दार
राजनीति विज्ञान विभाग
आरकेडीएफ युनिवर्सिटी
राची, झारखण्ड।

- (i) महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता
- (ii) महिलाओं को उनकी क्षमता के पूर्ण विकास का अधिकार।
- (iii) महिलाओं को आत्म प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्णय का अधिकार।

आगे की राह—पंचायती राज संस्थाओं ने महिला प्रतिनिधियों को जमीनी स्तर पर व्यवस्था में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई राज्यों ने चुनाव में 50: आरक्षण दिया है। यह सदियों से जारी उत्पीड़न को रोकने के लिए एक जरूरी उपकरण है।

निष्कर्ष:—

1996 में पहली बार एच०डी० देवेगौड़ा की सरकार में यह महिला आरक्षण बिल लाया गया था। परन्तु भारी विरोध होने के कारण यह पास नहीं हो सका। जिसके बाद कई बार यह बिल संसद में पेश किया गया और हर बार असफल ही रहा। इसके बाद साल 1998—1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा यह बिल संसद में पेश किया गया लेकिन प्रचंड बहस के बाद कानून मंत्री के हाथ से छीन कर एक सांसद द्वारा बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं। इसके बाद 2008 में UPA सरकार ने बिल को संसद में पेश किया गया तो राज्यसभा में इस बिल को सरकार ने पास करवा लिया लेकिन लोकसभा में विरोध के कारण यह पास नहीं हो सका अतः महिला आरक्षण बिल नहीं हो सका अतः महिला आरक्षण बिल 27 सालों से अधर में लटका रहा था।

महिला आरक्षण बिल के फायदे—

- (1) महिला आरक्षण बिल के द्वारा देश में नारी सशक्तिकरण को अधिक बढ़ावा मिलेगा।
- (2) देश की राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को और मजबूती मिलेगी।
- (3) यह अधिनियम हर महिला को आगे बढ़ने का अवसर देगी।
- (4) इससे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी जो कि अभी 81 है।
- (5) नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र मजबूत हो सकता है।

संदर्भ:

- (i) ह हिन्दू
- (ii) प्रभात खबर संपादकीय प्रभात 22/09/2023
- (iii) प्रभात खबर राँची 20/09/2023
- (iv) महिला आरक्षण बिल दृष्टि आई ए एस



सारांश

भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारतवासी प्रातः से लेकर संध्याकाल तक धर्म के बंधन से बंधे होते हैं। उनका प्रत्येक कार्य धर्म और ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। भारतीय धर्म ग्रंथों की संख्या अत्यधिक है लेकिन सभी धर्म ग्रंथ एक-दूसरे से मेल खाते हैं और ईश्वर तथा अध्यात्म के प्रति समर्पित हैं।

“ धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा”¹ (नारायणौनिषत , 89)

अर्थात् धर्म संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है। धर्म केवल भारत की ही प्रतिष्ठा नहीं है, संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है ऐसा भारतीय मत है। हम धर्मनिरपेक्ष होकर भी धर्म से अलग नहीं हो पाते हैं।

कोई भी साहित्यकार भारतीय जीवन दर्शन का समाज-दर्शन और संस्कृति-दर्शन करता है तो अनायास ही धर्म के संबंध में अपने पात्रों के माध्यम से दिग्दर्शन करा देता है। अमृतलाल नागर की गिनती प्रगतिशील कथाकारों से होती है लेकिन उनके सभी कृतियों में धार्मिक विचारों, क्रियाकलापों की छवि दिखायी पड़ती है। उनका संबंध आर्य समाज से रहा है। अतः स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी कृतियों में भारतीय धर्म और संस्कृति का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने उपन्यास 'एकदा नैमिषारण्ये में पौराणिक कथाओं के साथ भारतीय धर्म और विश्व की प्रमुख धर्मों पर प्रकाश डाला है।

आज धर्म के प्रति विभिन्न धारणाएं और विचार व्यक्त किए जाते हैं। भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पाश्चात्य जगत के लोग आध्यात्मिक खोज के लिए भारत आते हैं परंतु यहाँ का युवक अपनी अज्ञानता के कारण भटका हुआ है। वह सही मार्ग खोज नहीं पाता है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है।

“वर्तमान युग का हिंदू युवक सनातन धर्म के अनेक पंथों की भूलभुलैया में भटका हुआ, उस एकमात्र हिंदू धर्म को जिसकी सार्वजनीन उपयोगिता तदुपदिष्ट “अणोरणीयान् महतो महीयान ईश्वर का यथार्थ प्रतिबिंब है उस धर्म के मर्म को, अपने भ्रमात्मक पूर्व-धारणाओं और दुराग्रहों के कारण, ग्रहण करने में असमर्थ होने से, जिन राष्ट्रों ने निरी भौतिकता के सिवाए कभी भी और कुछ नहीं जाना उनसे आध्यात्मिक सत्य का पुराना पैमाना उधार लेकर अंधेरे में टटोलता हुआ, अपने पूर्वजों के धर्म को समझने का व्यर्थ का कष्ट उठाता हुआ अंत में उस खोज को बिल्कुल त्याग देता है और या तो वह निपट अज्ञेयवादी बन जाता है या अपनी धार्मिक प्रकृति की प्रेरणाओं के कारण पशु जीवन बिताने में समर्थ नहीं हो पाता और पाश्चिमात्य भौतिकता के पौरात्यगंधधारी कषायों का असावधानी के साथ पान करके श्रुति की भविष्यवाणी “परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धारु” चरितार्थ करता है।”²

धर्म के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए डॉ. बृज कुमार मिश्र ने लिखा है।

“मनुष्य की नैसर्गिक भावनाएँ एवं आध्यात्मिक क्रियाकलाप धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। धर्म कभी भी नैतिकता एवं ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता है। धर्म का स्वरूप भिन्न होने पर भी एक रूप रहता है।”³

हम भारत के प्रमुख धर्मों की स्थिति और उनके स्वरूप पर जब विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि यहाँ अनेक धर्मोवलंबी है। यहाँ पर अनेक धर्मों ने जन्म लिया और अपने विचारों, सिद्धांतों और क्रियाकलापों को केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैलाया। धर्म के प्रति भारत में कभी कट्टरता नहीं रही। भारत के लोग सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु एवं उदार रहे हैं। भारत का प्राचीन धर्म सनातन धर्म रहा है। सनातन धर्म से ही अनेक मत एवं संप्रदायों का उदय हुआ है। बौद्ध, जैन और सिक्ख आदि धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुई है। भारत का बौद्ध धर्म विश्व के अनेक देशों में फैला हुआ है। आज श्रीलंका, चीन, वर्मा, मलेशिया, जावा, सुमात्रा आदि देश बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये देश आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तुर्को, पठानों, मुगलों आदि के आने और उनके शासन के कारण भारत में इस्लाम धर्म फैला। पाश्चात्य देशों के व्यापारियों और धर्म प्रचारकों के आने से भारत में ईसाई धर्म फैला। पूरे विश्व के सताए जाने पर पारसियों ने भारत में शरण लिया और अपने धर्म को सुरक्षित रखा। भारतवासियों ने कभी भी उन पर अपना धर्म नहीं थोपा। सभी धर्मों का उपदेश और संदेश एक ही है। सभी ईश्वर को मानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। कोई भी धर्म को कुमार्ग पर नहीं ले जाता है। सभी धर्म सद्भाव से युक्त है।

‘एकदा नैमिषारण्यैश्च में अमृतलाल नागर ने लिखा है –

“ वासुदेव, पार्श्व, महावीर, बुद्ध बल अहुर्मज्ज, शिव, लात, वासुकी रूपों की अनेकता से क्या अंतर पड़ता है, श्रद्धा एक है।”⁴

ईश्वर का स्वःप विराट है। विराट में सभी रहस्य; और भाव समाहित है जो भक्ति के मन में अपनी छाप बनाये रहती है। अमृतलाल नागर ने ‘बूंद और समुद्र’ में अपने पात्र बाबा राम जी के मुख से अभिव्यक्त कर आया है। यथा।

“राम जी, सत्य मानना। रहस्य मेरा नहीं, मेरे विराट का है। मैं तो छण-प्रित-छण साधारणता-सहजता को ही साधता रहता हूँ।”⁵ सनातन धर्म

भारत ही नहीं विश्व का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। वर्तमान में सनातन धर्म हिंदू धर्म के रूप में प्रचलित हो गया है, लेकिन सनातन धर्म की जो व्यापकता है वह सनातन शब्द में ही निहित है। विश्व में

अनेक धर्मों का उदय हुआ और वे समाप्त हो गए। सनातन धर्म की उदारता, व्यापक दृष्टिकोण और अनेक मतों और विचारों को अपने में समाहित करने की शक्ति ने इसे अक्षुण्ण बनाए रखा। सनातन धर्म की विराट परिकल्पना है। सनातन धर्म को मानने वाले कहीं भी अपने उपासना और चिंतन कर सकते हैं। सनातन धर्म की कोई सीमा रेखा नहीं है। अनेक देवी देवता यह पूजे जाते हैं। धर्म ग्रंथों में तैंतीस कोटि देवी-देवता माने गए हैं। इनमें कोई कम नहीं होता है बल्कि वृद्धि होती रहती है। सनातन धर्मों में देवी-देवता के साथ ही मनुष्य, प्रकृति, पशु-पक्षी भी पूजे जाते हैं। यहाँ का कक्कड़ भी शंकर है। यहाँ विषैले सर्प की भी पूजा होती है। शेर, बंदर, हाथी, मत्स्य और शूकर भी पूजे जाते हैं। श्वान भी भैरव देवता का वाहन है। यहाँ चींटी को भी आटा और गुड़ खिलाया जाता है। नदी, समुद्र, पर्वत, वायु और अग्नि सभी पूजित हैं। सूर्य, चंद्र और सभी नवग्रह सनातन धर्म में पूजित हैं। सूक्ष्म जीव से लेकर विराट प्रकृति की पूजा सनातन धर्म में होती है। बहुत से विदेशी धर्म प्रचारक जब भारत आए तो सनातन धर्म की व्यापकता और उदारता देखकर के आश्चर्यचकित हो गए और सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानने लगे।

भारतीय दार्शनिकों एवं चिंतकों ने सनातन धर्म को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। आदिगुरु शंकराचार्य ने चार धर्मों की स्थापना की और उनके प्रमुख को शंकराचार्य का पद दिया। कालांतर में अनेक मतों और उपधर्मों की भी स्थापना हुई जो धर्म और संस्कृति का केंद्र बने। आज भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, काशी विश्वनाथ, सेतुबंधु रामेश्वरम, प्रयागराज संगम, वैष्णव देवी, महाकालेश्वर उज्जैन, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन आदि सनातन धर्म के आस्था के केंद्र बने हुए हैं। यह तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं एवं भक्तों की भीड़ दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। समय के साथ भारत में धार्मिक क्रियाकलापों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। धर्म के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। यह के आध्यात्मिक केंद्र उदात्त भावना और श्रेष्ठ नीतियों के कारण प्रसिद्ध रहे हैं। यह की भूमि देवभूमि है। गंगा, यमुना, सरस्वती देव नदियां हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत अध्यात्म का जन्म स्थान रहा है। यह ऋषिगण विचरण करते हैं। यह के मनुष्य देवतुल्य हैं। यथा।

“वह भारत जो प्राचीन काल से सभी उदात्ततानीति और अध्यात्मका जन्मस्थान रहा है, वह देश जिसमें ऋषिगण विचरण करते रहे हैं, जिस भूमि में देव तुल्य मनुष्य अभी भी जीवित और जाग्रत है।”⁶

महाभारत में धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहा जाता है। अतः जो धारण रूप प्राण रक्षण से युक्त हो जिससे किसी जीव का उत्पीड़न, शोषण और अहित न हो वह धर्म है। यथा।

“धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः।

यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः” (महाभारत कर्णपर्व ६२.५८) 7

धर्म की व्याख्या करते हुए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि आदर्शों की रक्षा करके अधोगति से बचाता है। धर्म से धारण और पोषण सिद्ध होता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘धर्म और सिद्धि में लिखा है।

यथा कृ” धर्म धारण करता है

अर्थात् अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर अधोगति से बचाता है इसलिए उसे धर्म कहा गया है। धर्म ने ही सारी प्रजा को धारण कर रखा है। अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता हो, वही धर्म है, ऐसा सत्पुरुषों का निश्चय है।”⁸

हिंदू धर्म ग्रंथों का भारतीय समाज पर अमिट छाप है। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस आदि धार्मिक ग्रंथों का व्यापक प्रभाव भारतीय जनमानस पर है। भारतीय जीवन पद्धति में इन धार्मिक ग्रंथों की शिक्षाएं और विचार समाहित हो गयी है। भारतीयों के संस्कार, विचार, भाव इन ग्रंथों से ओतप्रोत है। सनातन धर्म में ऐसी धारणा है कि धर्म ही मोक्ष प्रदान करता है। प्रत्येक भारतीय मोक्ष की कामना करता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके सभी कार्य और संस्कार मोक्ष से संबंधित होते हैं। पापी व्यक्ति भी मोक्ष की कामना करता है। ऐसी धारणा है कि सब कुछ सामान्य रहे और सद्विचारों के साथ जीवन को जिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। वर्तमान स्थिति भले ही अच्छी न हो लेकिन मरणोपरांत भारतीय स्वर्ग लोक की सुखद कामना करता है। अमृतलाल नागर ने व्यंग्य कसते हुए लिखा है। यथा कृ “हिंदुस्तान इहलोक से अधिक परलोक में रहता है”⁹

हिंदू धर्म समन्वयवादी रहा है। अनेक धर्मों, मतों की श्रेष्ठ बातों को आत्मसात करने की क्षमता हिंदू धर्म में है। भारत में ऐसी धारणा है दूसरे धर्म की श्रेष्ठ बातों को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। यह अनेक देवी-देवताओं के बीच यदि कुछ वृद्धि हो जाती है या यदि कुछ अच्छे मत प्राप्त हो जाते हैं तो कोई हानि नहीं है। अमृतलाल नागर का इस विषय में उदार दृष्टिकोण है। वे हिंदू धर्म की उदारता और लोचकता के समर्थक हैं। धर्म वहीं चिरंजीवी है जो उदार हो, व्यापक हो और उसमें लोचकता हो। नागरजी कहते हैं।

“करोड़ों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस देश भर में ऐसे भी थे जिन्होंने राम के साथ-साथ अल्लाह को भी जोड़ लिया। तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं में सैकड़ों अलिया, पीर, शहीद और भी जुड़ गए उनकी तनिक भी धार्मिक हानि न हुई।”¹⁰

भारतीय समाज में वेदों और उपनिषदों को उच्च कोटि का धार्मिक ग्रंथ माना गया है। गीता को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए पूजा जाता है। कर्म करने की प्रेरणा गीता से मिलती है। इन श्रेष्ठ ग्रंथों के होते हुए भी हनुमान चालीसा भी प्रसिद्ध है। अनपढ़ हिंदू भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है। हनुमान भारतीय जीवन के प्रेरणास्रोत है। राम और कृष्ण जन-जन के पूज्य बने हुए हैं। राम और कृष्ण के बिना हिंदू का जीवन व्यर्थ दिखाई पड़ने लगता है। राम के भक्त

तुलसीदास ने राम के विराट छवि और मर्यादा के रूप में चित्रित किया है। राम ही जीवन है और राम ही सत्य है ऐसा तुलसी की धारणा है। रामचरितमानस लिखने वाले तुलसी के जीवन और उनके विचार पर अमृतलाल नागर ने औपन्यासिक शैली में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'मानस का हंस में तुलसी की जीवन गाथा का वर्णन किया है। नागर जी ने कृष्ण के भक्त सूरदास के जीवन पर भी 'खंजन नयन' नाम की पुस्तक लिखी है।

सनातन धर्म का प्रभाव कभी रुका नहीं। भारतीय दर्शन का सिद्धांत है 'चौरेवति-चौरेवति' समय के अनुसार जिस धर्म और मत ने अपनी उदारता और लोचकता का परिचय नहीं दिया उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। भारत में राम और कृष्ण के अनेक समर्थक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। धर्म में रुढ़िता और संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियों के आधार पर भी धर्म का स्वरूप निश्चित होता है। यदि परिस्थितियों के अनुकूल धर्म का स्वरूप निश्चित नहीं हुआ तो मनुष्य जाति की रक्षा असंभव हो जाती है। विभिन्न काल में, विभिन्न स्वरूप में धर्म का स्वरूप निश्चित होता है। अमृतलाल नागर लिखते हैं कि युग के अनुरूप ही धर्म का स्वरूप निश्चित होता है। उन्होंने 'मानस के हंस में लिखा है।।

"भारतीय जनमानस में राम-श्याम में कोई भेद नहीं है। असुरी प्रवृत्तियों की जब बाढ़ आ जाती है तब इनका युगानुकूल अवतार होता है। देश काल के अनुरूप ही धर्म बोध ढलता है।"¹¹

समय के साथ ईश्वर के विविध रूपों में से किसी एक का चयन करना पड़ जाता है। जब दीन-हीन होकर विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों से भारतीय जनता त्रस्त हो जाती है उन्हें कोई उन्हें कोई संबल नहीं दिखाई पड़ता है त्राहि-त्राहि मच जाती है तो वैसी स्थिति में लोकनायक तुलसी ने मुरलीधर गोपीरूप भगवान कृष्ण का वर्णन न करके धनुर्धारी असुर संघारक भगवान राम के वीर स्वरूप का वर्णन करके भारतीय जनमानस में विरक्त भाव का संचार करते हैं। जब असुरी प्रवृत्तियों की वृद्धि होने लगती है और जनता में त्राहि-त्राहि मच जाती है तो भारत में युग के अनुरूप भगवान का अवतार होता है। कृष्ण ने गीता में आदेश दिया है।।

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।" (श्रीमद्भागवत गीता, अध्याय 4, श्लोक 7)

अमृतसर नागर भी युग और परिस्थिति के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे राम और कृष्ण में कोई भेद न मानते हुए भी समय के अनुरूप उनकी छवि का वर्णन करना ही श्रेयस्कर मानते हैं। उन्हें लिखा है :-

"राम-श्याम में भेद नहीं है। पर इस समय मुझे इनका मुरलीधर गोपीरमण रूप नहीं लुभाता। मैं इन्हें धनुर्धारी, असुर संघारक और रामराज्य प्रतिष्ठापक के रूप में निहारना चाहता हूँ।

हिंदू धर्म की जड़ें बहुत ही मजबूत हैं। इसका दर्शन बहुत गहरा है। वेद मंत्रों का जाप, भजन-कीर्तन या राम-कृष्ण का ध्यान ही

धर्म नहीं है, धर्म और सेवा अलग नहीं है, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तुलसी ने भी लिखा है "परहित सरिस धर्मनहिं भाई"¹²

धर्म का सत्य केवल आत्मोन्नति नहीं है, अध्यात्म-चिंतन, ध्यान आदि व्यक्तिगत उत्थान के लिए आवश्यक है लेकिन ईश्वर वहाँ है, धर्म वहाँ है, जहाँ दीन-दुखियों की सेवा करने का संकल्प और भाव है। यदि पर पीड़ा को दूर नहीं किया तो धर्म और कर्म व्यर्थ है। 'मानस का हंस में नागर जी ने धर्म के व्याख्या इस प्रकार की है कृदृ।

"दीन-दुर्बल और रोगी की सेवा करना मैं राम की सेवा करना ही मानता हूँ।"¹³

ईश्वर का स्वःप

ईश्वर सर्वोक्तिमान और अनंत है। ईश्वर ही सृष्टि के आदि व अंत का कारण है। वह अनंत है, निराकार है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, वह अविनाशी है, अव्यक्त है, सांसारिकता से ऊपर है, वह परमात्मा है। वहीं दूसरों के मतों के अनुसार ईश्वर निराकार होते हुए भी साकार है। सभी प्राणी उसके अंश हैं जो आत्माओं के रूप में जन्म लेते हैं। यह परमात्मा निर्गुण होते हुए भी सगुण है। ईश्वर अवतार के रूप में मृत्युलोक में जन्म लेता है और संसार में आकर लोकधर्म का निर्वाह भी करता रहता है। ईश्वर की विभिन्न स्वरूप हैं जो जिस रूप में देखना चाहे देख सकता है।

भारत में ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की पूजा की जाती है। हिंदी साहित्य में राम, कृष्ण, शिव सभी की पूजा की गई है। ये सभी ईश्वर के सगुण रूप हैं। मध्यकाल में कवियों ने ईश्वर के सगुण रूप की विभिन्न रूपों में वर्णित किया है। कृष्ण के शिशु रूप से लेकर उनके किशोरावस्था तक का बड़ा-ही मोहक, रंजक और सुंदर स्वरूप का चित्रण किया गया है। किशोरावस्था की पश्चात कृष्ण सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। वे अपनी गोपिकाओं को सांत्वना देने के लिए अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेजते हैं। उद्धव गोपिकाओं को ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की शिक्षा देते हैं परंतु गोपिकाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। वे कृष्ण को सगुण स्वरूप में खोई हुई है। प्रायः सभी कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के मधुर छवि का ही वर्णन किया है। कृष्ण और राधा के सौंदर्य का वर्णन मोहक होते हुए भी अध्यात्मिक चेतना से भरा हुआ है। दूसरी ओर हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति के रूप में राम की पूजा की गई है। यहाँ ईश्वर का स्वरूप मोहक और लीलाधारी के रूप में नहीं मिलता है। धनुर्धारी राम असुरों का विनाश करके रामराज्य की स्थापना करते हैं। राम भक्त कवियों में तुलसी और केशव का नाम सर्वोपरि है।

सगुण भक्ति के क्रम में भक्तिकाल में या उसके पूर्व कबीर का उल्लेख करना भी आवश्यक है। वे राम की पूजा करते हैं लेकिन उनके राम दशरथ पुत्र न होकर के निर्गुण राम है। उन्होंने भी निर्गुण रूप में राम की आराधना करते हुए ईश्वर मिलन की कामना व्यक्त

की है। उनकी यह पंक्तियाँ उनके लालित्य भाव को व्यक्त करती हैं।
यथा
“दुलहिनि गावहु मंगलचार,
हमरे घर आयेहै राजा राम भरत।”¹⁴

ईश्वर के विविध स्वरूप को देखते हुए वर्तमान में आर्य समाज में ईश्वर के निराकार स्वरूप का ही समर्थन किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद-उपनिषद् को मानते हुए ईश्वर को निराकार ही माना है।

ईश्वर के द्वैत और अद्वैत स्वरूप की भी चर्चा है। जीव परमात्मा का ही अंश है। देह त्याग के उपरांत आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। ईश्वर अविनाशी है तो कविता की यह पंक्ति उल्लेखनीय है ‘ईश्वर अंश जीवअविनाशी।

ब्रह्म एक है। कहा भी गया है ‘एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति’ अर्थात् ब्रह्म एक है सभी जीव उसकी माया है। अमृतलाल नागर ने ईश्वर के संबंध में अपने पौराणिक उपन्यास ‘एकदा नैमिषारण्ये’ में लिखा है। यथा:—
“किसी एक ही परमतपोनिष्ठ ज्ञान गुरुचेतन मानव-समूह ने सारी पृथ्वी के मानवों को सभ्यता के संस्कार दिए थे”.....

..... वह एक जिह्व महाबाहु परम गुरु ज्ञान नारायण ही आज अनंत जिह्व अनंत बाहु लेकर सब लोको में व्याप्त है। सर्वत्र उसी का माया है”¹⁵

अमृतलाल नागर जहाँ ईश्वर के साकाररूप को स्वीकार करते हैं वहीं ‘करवट्ट उपन्यास में ईश्वर के स्वरूप को निराकार बताते हैं। यथा :-

“ भगवान तो अनंत, अखंड, अभेद और निराकार स्वरूप है”¹⁶

गीता में भी ईश्वर के अविनाशी स्वरूप को स्वीकार किया गया है। आत्मा या परमात्मा शाश्वत और पुरातन है। नयहजन्मता है और न मरता है। यह नित्य है। यथा कृष्ण

“न जायते म्रियते वा कदाचि

नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे”¹⁷

ईश्वर निराकार है, अव्यक्त है किंतु भारत के करोड़ों जनता ईश्वर को सगुण रूप में ही देखती है। निराकार रूप उसके समझ में नहीं आता है। गोपिकाएँ भी कहती हैं ‘निर्गुण कौन देश को वासीश’। भारत के करोड़ों लोग राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गणेश, पार्वती, दुर्गा, काली आदि देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और अपना आध्यात्मिक विकास करते हैं। मूर्तिपूजा आस्था और विश्वास का केंद्र बन गया है। हनुमान की वंदना, शिव पर जल चढ़ाना करोड़ों भारतीयों की दिनचर्या बन चुकी है। सगुण पूजा जहाँ दिन-प्रतिदिन जनता पर अपना प्रभाव छोड़ती जा रही है, आकर्षक बनते जा रही है, भक्तों को भक्ति में सरोबार कर रही है, वहीं कहीं-कहीं मूर्तिपूजा का यह रूप विकृत होता भी दिखाई पड़ रहा है। कलकत्ता के कालीबाड़ी के दृश्य

का वर्णन करते हुए नागरजी ने ‘करवट्ट उपन्यास में लिखा है कृष्ण
“माँ की भयावनी मूर्ति की आगे श्रद्धा से सिर झुकाता है, नारियल फोड़े जा रहे हैं, दारु की बोतलों पर बोतलें चढ़ाई जा रही है और बगल में बली वेदी पर बकरे और भैंसे.....”¹⁸

ईश्वर का यह रूप अग्राह्य हो जाता है। यह रूप वैष्णव भक्तों को नहीं सुहाता है। आज का सभ्य समाज इसे नहीं स्वीकार कर पाता है। फिर भी पूर्वोत्तर भारत में देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर बलि प्रथा आज भी विद्यमान है। इन्हीं धर्म स्थलों पर बकरे भैंसे के कटे हुए मुँहों के बीच देवी देवता पूजित होते हैं। जनजातियों में मुँहों की भी बलि दी जाती है। नागरजी ने कभी भी बलि प्रथा का समर्थन नहीं किया है। व्यक्ति साकार और निराकार रूप में भटकता हुआ साकार रूप से ही संतोष प्राप्त करता है।

अमृतलाल नागर के उपन्यास ‘करवट्ट में नायक वंशीधर ईश्वर के निराकार रूप को ही मानता है क्योंकि वह आर्य समाज से प्रभावित है परंतु उसकी आस्था चंद्रिका देवी पर है। उसका दृढ़ विश्वास है कि चंद्रिका देवी की कृपा से ही उसे जीवन में सफलता मिली है। ह सदैव चंद्रिका देवी के मंदिर में दर्शन हेतु जाता है और प्रसाद चढ़ाता है”¹⁹

ईश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप को जानने के लिए साकार रूप का माध्यम आवश्यक है। भक्ति और आस्था सगुण स्वरूप के सामने प्रकट होकर समर्पित हो जाती है। भक्त कवियों को निर्गुण रूप समझ में नहीं आता है।

धर्मों की एकरूपता

सभी धर्म ईश्वर के सत्ता पर विश्वास करते हैं। ईश्वर से साक्षात्कार करने की विधि और पद्धति भिन्न-भिन्न है। मूल उद्देश्य एक होने के कारण एकरूपता भी दिखाई पड़ती है। मतांतर होने के बाद भी ईश्वर एवं उसके विधान में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अमृतलाल नागर ईश्वर और अल्लाह को एक ही मानते हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास ‘नाच्यो बहुत गोपलश में मेहतरों के संबंध में लिखा है :-

“ मेहतरों की कोई जाति नहीं होती है इनमें हिन्दू और मुस्लिमान दोनों होते हैं। मेहतरों की जात अल्ला की जुठन भी खाती हैगी और रामजी की भी”²⁰

अपने उपन्यास ‘अमृत और विष’ में भी नागरजी ने हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही बताया है। उनका विचार है कि

“राहे दोनों सच्ची है। महज तरीके ही अलग-अलग है”।

‘एकदा नैमिषारण्ये’ में नागरजी ने लिखा है कि

“जरथरुस्त्र धर्म और वैदिक धर्म दोनों में इतना साम्य है कि प्रार्थनाएँ भी एक ही हैं केवल उच्चारण का अंतर है”²¹

मनुष्य, मनुष्य ही होता है। जन्म और मृत्यु के समय पर भी एक जैसा ही होता है। मनुष्य की एकरूपता ही धर्म की एकरूपता को सिद्ध करती है। ‘करवट्ट’ में लिखा है

“ आडरे जब मारिगा तब कहाँ हिंदू कहाँ मुसलमान और कहाँ

किरिस्तान । मनुष्य जब जन्मत है और जब मरत है तब मनुष्यैहोतहै”
|²²
हिंदू, मुसलमान और ईसाई का भेद जन्म और मृत्योपरान्त नहीं
दिखाई पड़ता है ।

लोक धर्म

धर्म का रूप कल्याणकारी होता है । धर्म कभी रुढ़ नहीं हो सकता है ।
देशकाल के अनुसार धर्म की मान्यताएँ बदलती है । पुरानी मान्यताएँ
समाप्त हो जाती है और उनकी जगह नयी मान्यताएँ स्थान बना लेती
हैं । धर्म में लोचकता बनी रहनी चाहिए अन्यथा वह समाप्त हो जाता
है । धर्म की उदारता और समन्वय की प्रवृत्ति उसे चिरंजीवी बना देती
है । अमृतलाल नागर ने 'एकदा नैमिषारण्ये' में लिखा है कि धर्म को
देशकाल के अनुसार अपनी समीक्षा करनी चाहिए । यथा कृ

“धर्म को देशकालानुसार अपनी समीक्षा करनी ही चाहिए अन्यथा वह
रुढ़ होकर अर्थहीन हो जाता है” ।²³

लगभग सभी धर्मों और मतों ने लोक कल्याण पर बल दिण है । तुलसी
ने तो लोक कल्याण को ही सबसे बड़+ k /न माना है और परपीड-
न को अधर्म में माना है । रामचरितमानस की इस चौपाई में स्पष्ट है
परहित सरिस धर्म नहीं भाई परपीड+ k सम नहीं अधमाई ।

धर्म कभी भी ,कांगी नहीं होता है । केवल भक्ति या केवल
ज्ञान लोक का कल्याण नहीं कर सकता है । भक्ति और ज्ञान से स्वयं
की संतुष्टि हो सकती है लोक कल्याण नहीं हो सकता है । अमृतलाल
नागर ने लिखा है ।

“भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का समन्वय ही लोक धर्म है” ।²⁴

अमृतलाल नागर के अनुसार यदि कोई धर्म मानवता के मार्ग में
बाधक है तो उसका निषेध होना ही चाहिए । कोई भी धर्म मानव धर्म से
बढ़कर नहीं हो सकता है । धर्म संकुचित नहीं होना चाहिए । 'मानस का
हंस' में तुलसी धर्म और समाज के विरोध के बाद भी भूख एवं प्यास से
पीड़ित ब्रह्म हत्यारे चमार का पैर धोते हैं एवं अपने कटोरे में उसके
लिए भोजन परोसते हैं” ।²⁵

'मानस का हंस' में अमृतलाल नागर ने तुलसी के मुख से कहलाया है
“जाति-पाति, वर्ण-वर्ग आदि सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, पर
एक जगह मनुष्य केवल मनुष्य होता है घघ-घट में एक ही राम रामते
हैं” ।²⁶

अमृतलाल नागर ने तुलसी के माध्यम से धर्म के सत्य रूप को चित्रित
किया है । धर्म वह है जो सबके लिए सुलभ है । तुलसी 'मानस का
हंस' में लोकधर्म रक्षक और लोकधर्म की व्याख्या करते हैं । नागरजी
पूरे समाज को धर्ममय देखना चाहते हैं । उन्होंने तुलसी के द्वारा
कहलाया है । यथा

“ मैं अकेले नहीं पूरे समाज के साथ राममय होना चाहता हूँ” ।²⁷

अमृतलाल नागर का धार्मिक दृष्टिकोण

अमृतलाल नागर अपने साहित्य में किसी धर्म विशेष के प्रति पूर्वाग्रह
नहीं रखते हैं । वे सनातन धर्म के साथ-साथ आर्य समाज से भी

प्रभावित थे । उन्होंने अपने उपन्यासों में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म,
ईसाई धर्म, यहूदी धर्म आदि में समन्वय स्थापित करने का कार्य
किया है । उनका विचार है कि धर्म की उदारता उसे स्थायी बनाती
है । धर्म केवल मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु पशुओं के प्रति व्यवहार
में भी धर्म का पालन होना चाहिए । पशुओं के प्रति क्रूरता क्षम्य नहीं
है । अमृतलाल नागर अपने उपन्यास 'सुहाग के नुपुर' में चोल राजा
के धर्म और न्याय की प्रशंसा उपन्यास की नायिका कन्नदी से
कहलवाया है । यथा कृ

“मैं उन परमन्यायी चोल महाराजा की प्रजा हूँ जिन्होंने गाय तक को
न्याय देने के लिए उसके बछड़े को रथ से कुचल देने वाले अपने
पुत्र को स्वयं अपने हाथों से मृत्युदंड दिया था” ।²⁸

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत धर्म के प्रति आस्थावान रहा है ।
अमृतलाल नागर ने धार्मिक क्रियाकलापों का वर्णन अपने सभी
उपन्यासों में किया है । धर्म मनुष्य के उन्नति में सहायक होता है
बाधक नहीं । नागरजी ने लोकधर्म को ही श्रेष्ठ धर्म माना है । बाह्य
आडंबरो से दूर रहकर समन्वयकारी नीति को ही माना है । मन, कर्म
और वचन से सत्य की राह पर चलना ही धर्म है । नागरजी इस
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भी भिन्न धर्म आपस में बैर भाव रखना
नहीं सीखाता है । एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना ही सच्चा
धर्म है । धर्म समाज के लिए ही होता है । अतः धर्म कभी भी
अहितकारी नहीं हो सकता है ।

संदर्भ संकेत :-

1. नारायणोपनिषत् (७८)
2. स्वामी विवेकानंद, हिंदू धर्म के पक्ष में, रामकृष्ण मठधन्तली
नागपुर, 2006, पृ.3-4
3. डॉ० बृज कुमार मिश्र, उपन्यासकार अमृतलाल नागर, प्रिय
साहित्य सदन गली न. 33 पहला पुस्ता सोनिया विहार दिल्ली,
पृ.106
4. अमृतलाल नागर, एकदा नैमिषारण्ये, लोकभारती इलाहाबाद,
1975, पृ.277
5. अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र, किताब महल इलाहाबाद,
1956 पृ.472
6. स्वामी विवेकानंद, हिंदू धर्म के पक्ष में, रामकृष्ण मठ धन्तली
नागपुर, 2006, पृ.-22
7. 'महाभारत कर्णपर्व' (६२.५८)
8. स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, धर्म सिद्धि, गोवर्धन मठ पुरी,
2018, पृ.26-27
9. अमृतलाल नागर, अमृत और विष, लोकभारती इलाहाबाद,
1966, पृ.406
10. अमृतलाल नागर, अमृत और विष, लोकभारती इलाहाबाद,
1966, पृ.467

11. अमृतलाल नागर,मानस का हंस, राजपाल एंड संस दिल्ली,1973,पृ.331
- 12.श्रीमद्भागवत गीताअध्याय दृ4, श्लोक दृ7, गीताप्रेस गोरखपुर, पृ.32
- 13.अमृतलाल नागर,मानस का हंस, राजपाल एंड संस दिल्ली, 1973,पृ.332
- 14.अमृतलाल नागर, मानस का हंस, राजपाल एंड संस दिल्ली,1973,पृ.333
- 15.अमृतलाल नागर, एकदा नैमिषारण्ये,लोकभारती इलाहाबाद,1975,पृ.38-39
- 16.अमृतलाल नागर, करवट, राजपाल एंड संस, 1985,पृ.115
- 17.श्रीमद्भागवत गीताअध्याय दृ2,गीताप्रेस गोरखपुर,पृ.31
- 18.अमृतलाल नागर,करवट, राजपाल एंड संस, 1985, पृ.116
- 19.अमृतलाल नागर,करवट', राजपाल एंड संस, 1985,पृ.178
- 20.अमृतलाल नागर,नाच्यौ बहुत गोपाल, राजपाल एंड संस दिल्ली, 1981, पृ.111
- 21.अमृतलाल नागर, अमृत और विष, लोकभारती इलाहाबाद, 1966पृ.467
- 22.अमृतलाल नागर, एकदा नैमिषारण्ये, लोकभारती इलाहाबाद, 1975,पृ.280
- 23.अमृतलाल नागर, करवट, राजपाल एंड संस, 1985,पृ.359
- 24.अमृतलाल नागर,एकदा नैमिषारण्ये, लोकभारती इलाहाबाद, 1975,पृ.280
- 25.अमृतलाल नागर,मानस का हंस, राजपाल एंड संस दिल्ली, 1973,पृ.325
- 26.अमृतलाल नागर, मानस का हंस, राजपाल एंड संस दिल्ली, 1973,पृ.325
- 27.अमृतलाल नागर,मानस का हंस, राजपाल एंड संस दिल्ली, 1973, पृ.322
- 28.अमृतलाल नागर,सुहाग के नुपूर, राजकमल प्रकाशन, 1973, पृ. 263

समीक्षा मिश्र

शोध-छात्रा

हिंदी विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची

मो. 9431768199

ईमेल- samikshamishra661@gmail-com

Address & 110 abhinandan srinagar beside
vidyanagar road no-3 harmu Ranchi Jharkhand
834002

सारांश

किसी भी समाज एवम् राष्ट्र के विकास के लिए नारियों का सशक्त होना पूर्व शर्त है। देश के सतत विकास को सुनिश्चित एवं सुदृढ़ करने के लिए महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता प्राप्त करना हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण शताब्दियों से एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। आज वर्तमान युग में हम कई क्षेत्रों में अभुतपूर्व विकास कर चुके हैं। भारत चाँद पर अपना आशियाना बनाने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी, हमारे सामने लैंगिक असमानता एक गम्भीर प्रश्न है।

सरदार पटेल के कार्यों एवं विचारों में भारतीय समाज से सम्बन्धित कई मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टिकोण निहित है। उन्होंने न केवल देश के एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए अतुलनीय ऐतिहासिक कार्य किया। साथ ही, उन्होंने दबे-कुचले वर्गों की मुक्ति और महिलाओं के उत्थान और उनके राजनीतिक भागीदारी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश की चौमुखी विकास में महिलाओं की भूमिका के संबंध में सरदार पटेल के विचार अति प्रगतिशील थे, जो आज भी प्रासंगिक हैं। प्रस्तुत पेपर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के संदर्भ में महिलाओं पर सरदार पटेल के विचारों को समझने का प्रयास किया गया है।

मुख्य भाव — महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, लैंगिक समानता, राजनीतिक भागीदारी।

वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य :-

- महिलाओं के सशक्तिकरण में सरदार पटेल की भूमिका को समझना।
- महिला सशक्तिकरण के लिए उनके दिखाए गए मार्ग से वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को परिचित कराना।

अनुसंधान क्रिया विधि :-

- वर्तमान अध्ययन पुस्तकों, पत्रिकाओं, सोशल मीडिया जैसे द्वितीय स्रोतों पर आधारित है।

परिचय :-

सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो लोगों को सभी क्षेत्रों में उनकी पूर्ण पहचान और निर्णय लेने की शक्तियों का एहसास कराती है। महिलाओं का सशक्तिकरण कई सामाजिक समस्याओं को हल करने और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया भर में महिलाओं के लिए इतिहास की शुरुआत से ही परिस्थितियाँ चुनौती पूर्ण रही हैं। हाल के वर्षों में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख मुद्दा रहा है।

सरदार पटेल ने 20वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश की थी। सरदार पटेल ने भारतीय समाज में मौजूद महिलाओं के खिलाफ सामाजिक बुराइयों जैसे बाल

विवाह, लिंग भेदभाव, पर्दा प्रथा खत्म करने के लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि समाज और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक महिला और पुरुष की भागीदारी हो।

महिलाओं के संबंध में सरकार पटेल का दृष्टिकोण :-

सरदार पटेल एक सकारात्मक और प्रगतिशील विचारों वाले थे। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि भारतीय समाज के पुनर्निर्माण और विकास हेतु महिलाओं की भूमिका अपरिहार्य है। वे महिलाओं का स्वावलम्बन, उनकी आत्मनिर्भरता और लैंगिक समानता के पक्षधर थे।

सरदार पटेल ने कहा था — “जब तक महिलाएँ समाज और देश के लिए पुरुषों के समान कार्य नहीं करती; प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी से, वह क्षेत्र कृषि का हो, पशुपालन अथवा उद्योग का, शिक्षा का या कोई और उत्पादन, निर्माण और सृजन के लिए महिलाएँ आगे नहीं आती हैं, तब तक देश का विकास गति नहीं पकड़ सकता।” और आगे कहा था — “हमारे समाज को यह समझ लेना होगा कि हमारी महिलाएँ किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं हैं। इसलिए, समाज के उत्थान और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में महिलाओं का सहयोग आवश्यक है।”¹

सरदार पटेल नारी शक्ति के कायल थे। उनका मानना था कि पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में बहुत ज़्यादा सहनशक्ति होती है इसलिए, महिलाएँ अपनी रक्षा खुद करें। इसके लिए जरूरी है — “स्त्रियों को अपने पर आत्मविश्वास हो और वह समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करे। ऐसे सुधार कानून से ना हुए हैं और ना होंगे।”²

उनके कार्यों और विचारों में निहित था कि आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए, सामाजिक क्षेत्र की कुरीतियों, कुप्रथाओं से मुक्त महिलाएँ ही आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकती हैं। उन्होंने महिला वर्ग को दहेज जैसे अभिशाप को पूर्णतः नकार देने का आह्वान किया। सरदार पटेल ने कहा, “दहेज जैसी सामाजिक बुराई और महिलाएँ उत्पीड़न से जुड़ी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकिए। यह आपके आत्मनिर्भरता के मार्ग की बाधा है; इसलिए, इससे बाहर निकलिए।”³ भारतीय ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर सन् 1929 में अपनी बिहार यात्रा में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था : “आपको शर्म नहीं आती कि आप अपने स्त्रियों को पर्दे में रखकर खुद ही अर्धांगवायु से पीड़ित हैं, यह स्त्रियाँ कौन हैं? आपकी माँ, आपकी बहन, पत्नी! उन्हें पर्दे में रखकर क्या आप यह मानते हैं कि आप उनके सतीत्व की रक्षा कर सकेंगे? उन पर इतना अविश्वास क्यों? या आप इसलिए डरते हैं कि वह बाहर आकर आपकी गुलामी को देख लेंगी? आपने उन्हें गुलाम पशुओं की तरह रखा है, इसलिए उनकी औलाद आप भी गुलाम की तरह हो गए हैं। मेरी चले तो मैं बहनों से कह दूँ कि ऐसे डरपोक और नामर्दों की स्त्रियाँ बनने से तो उन्हें तलाक दे देना अच्छा है।”⁴

सरदार पटेल नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। परिवार की धुरी कही जाने वाली महिलाएँ आज भी शिक्षा प्राप्ति से वंचित हैं। सरदार पटेल नारी सशक्तिकरण में शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान से पूर्णतः सहमत थे। उनका मानना था कि महिला आत्मनिर्भरता के लिए एवं उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा एक अनिवार्य एवं निर्णायक भूमिका निभाती है। इसलिए, उन्होंने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए एवं अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। 14.06.1939 को अहमदाबाद में स्वयंसेविकाओं के समक्ष अपने भाषण में उन्होंने कहा था, "प्रत्येक युवती को इतनी शिक्षा लेनी चाहिए कि वह राष्ट्र की रचना में राष्ट्रीय जीवन में अपनी भागीदारी कर सकें।"⁵ इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में पुरुषों के समान ही महिलाओं को आवश्यक रूप से शिक्षित करने के पक्षधर थे। ताकि महिलाएँ भी आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। शिक्षा के माध्यम से महिला स्वावलम्बन का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे।

महिला स्वावलम्बन और राजनीतिक भागीदारी के लिए उठाए गए कदम :-

सरदार पटेल का मानना था कि महिलाओं को रचनात्मक कार्यों में समान अवसर प्राप्त हो तो वह कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी। वह इस वास्तविकता से पूर्ण परिचित थे कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किए बिना, उनकी आत्मनिर्भरता संभव नहीं है। इसलिए, उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए हर प्रकार से प्रोत्साहित करते थे। उनकी प्रेरणा से सैकड़ों महिलाएँ सार्वजनिक क्षेत्र में आईं। "वर्ष 1938 इस्वी में कॉंग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हरिपुरा गाँव में सरदार पटेल के सम्पूर्ण देखरेख में हुआ था।"⁶ एक प्रयोग करते हुए, सरदार पटेल ने अधिवेशन की पूरी व्यवस्था संभालने का दायित्व लगभग 800 महिलाओं को सौंप दिया। महिलाओं ने भी भरपूर उत्साह, कौशल एवं दृढ़ता का परिचय देते हुए, अति श्रेष्ठ व्यवस्था कराई। जो आने वाले समय में अति अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हुए, महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के सम्बन्ध में सरदार पटेल के विचार अति प्रगतिशील थे। 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं को शामिल करने की पहल की। सरदार पटेल के आह्वान पर बारडोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आन्दोलन सहित अन्य सत्याग्रहों में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में महिलाएँ उम्मीदवार नहीं हो सकती थीं। "अहमदाबाद म्युनिसिपल एक्ट के सेक्शन-15 (1) (सी) के प्रावधान के अनुसार महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोका गया था। सरदार पटेल का मानना था कि महिलाओं को चुनाव से दूर रखकर देश की आधी आबादी के साथ नाइंसाफी की जा रही है। सरदार पटेल के विद्रोह के वजह से सेक्शन-15 (1) (सी) के कमियों को दूर किया गया और महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई।"⁷

हमारे देश में महिला के लिए आरक्षित सीट का चर्चा स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की है। आज 21वीं सदी में (2023) सरदार

पटेल के विचारों और कार्यों का ही विजय है कि कई मुश्किलों के बावजूद 33% सीट सर्वसहमति से "नारी भाक्ति वंदन अधिनियम" नाम से महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित हो गया है। भारतीय संविधान में 128वाँ संशोधन, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व करने के लिए निश्चित रूप से परिस्थितियाँ तैयार करेगा।

निष्कर्ष :-

सामान्यतः सरदार पटेल की पहचान एक राष्ट्र निर्माता और एकीकरण कर्ता के रूप में है। लेकिन, बहुत कम लोग जानते हैं कि सरदार पटेल एक व्यवहारिक समाज सुधारक भी थे। समाज सुधार से जुड़े विचारों में महिला सशक्तिकरण का विचार सबसे केन्द्र में था। महिला वर्ग के उत्थान एवं आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में सरदार पटेल के कार्य और विचार आज भी विचारणीय एवं प्रासंगिक हैं।

वर्तमान समय और परिस्थितियों की माँग है कि महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदला जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें लैंगिक भेदभाव न हो और महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक निर्णय लेने का पूरा मौका मिले ताकि राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को उच्चतम स्तर तक ले जाया जा सके।

सन्दर्भ ग्रंथ :-

1. कुमार, रवीन्द्र, सरदार वल्लभभाई पटेल युवा वर्ग और महिला सशक्तिकरण, ग्लोबल अकादमिक, नई दिल्ली 2022, पृष्ठ 55-56
2. शरण, गिरिराज, पटेल ने कहा था, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 1982 पृष्ठ 138
3. कुमार, रवीन्द्र, सरदार वल्लभभाई पटेल युवा वर्ग और महिला सशक्तिकरण, पृष्ठ 74
4. मेहरोत्रा, एन०सी० कपूर, रंजना, सरदार वल्लभभाई पटेल, व्यक्ति एवं विचार, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली 2020, पृष्ठ 194
5. पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद 1950, पृष्ठ 424
6. कुमार, रवीन्द्र, सरदार वल्लभभाई पटेल युवा वर्ग और महिला सशक्तिकरण, उपरोक्त पृष्ठ 76
7. Hindi.news18.com, oct31.2019

गीता कुमारी

बिरसानगर, जौन नम्बर-1/बी०,
मकान संख्या-3, कौशल्यानन्द निवास,
रोड नम्बर-1, आन्धा समिति के नज़दीक,
जमशेदपुर-831019, झारखण्ड।
मो०नं०-9507187423

Email ID : geetakumari853@gmail.com



सारांश

हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य लेखक मोहन राकेश नाटकों में दिये गये अपने योगदान के कारण हमेशा याद किये जाएंगे। आधुनिक नाटकों के अग्रदूत कहलाने वाले एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी मोहन राकेश का पूरा नाम 'मदन मोहन गुगलानी' था। इनका जन्म 8 जनवरी, 1925 को अमृतसर में हुआ था। प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के कारण इन्हें अभाव का मुँह नहीं देखना पड़ा, परन्तु पिता की अकस्मात् मृत्यु ने इनके जीवन में गहरी संवेदनशीलता और अनुभावों को विस्तार दिया। नई कहानी आंदोलन से जुड़े साहित्यकार राजेंद्र यादव, कमलेश्वर के साथ-साथ इनका नाम भी था। इन्होंने लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलायी जैसे कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, नाटक आदि।

इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी रचनाएँ न केवल अपने युग तक सीमित हैं बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इन्होंने कुल चार नाटक लिखीं, इनमें से एक नाटक 'पैरों तले की जमीन' अधूरा रह गया जिसे कुछ समय पश्चात कमलेश्वर द्वारा पूर्ण किया गया। इनके सभी नाटकों की मूल कथावस्तु मानव के अस्तित्व की खोज पर ही आधारित होती है, जैसे 'आषाढ़ का एक दिन' (1958) में कालिदास का चरित्र, 'लहरों के राजहंस' (1963) में नन्द का चरित्र व 'आधे-अधूरे' (1969) में सावित्री का चरित्र।

'आषाढ़ का एक दिन' नाटक में कुल तीन अंक हैं। इस नाटक का पूरा दृश्य मल्लिका (जो कि इसकी मुख्य चरित्र है) के घर में ही घटित होता है एवं जैसे-जैसे यह नाटक एक अंक से दूसरे अंक की ओर बढ़ता है और दूसरे से तीसरे अंक तक पहुंचता है वैसे-वैसे मल्लिका की स्थिति में उत्तरोत्तर ह्रास को दर्शाता है। मल्लिका इस पूरे नाटक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है। मल्लिका का चरित्र गाँव की सीधी-सरल, भावयुक्त व समर्पण भाव से भरा हुआ होता है। यह पूरा नाटक मल्लिका के कालिदास के प्रति निःस्वार्थ प्रेम व समर्पण से परिपूर्ण रहता है।

नाटक का प्रारम्भ आषाढ़ के एक दिन से व अंत भी आषाढ़ के एक दिन में ही होता है। इस नाटक की शुरुआत में ही मल्लिका आषाढ़ की पहली बारिश में कालिदास के संग भीगकर आती है एवं उस अनुभव को माँ अम्बिका के साथ साझा करती है। वह अम्बिका से कहती है कि—

"मैं जीवन में पहली बार समझ पायी कि क्यों कोई पर्वत-शिखरों को सहलाती मेघ-मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन-मन कि अपेक्षा आकाश में बनते-मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है।"¹

उक्त कथन मल्लिका के प्रकृति के प्रति उस असीम प्रेम को दर्शाती है जो प्रकृति में घटित हर पल को जी भरकर जीना चाहती हो। बारिश उसे सिर्फ बाहर से ही नहीं भिगोती बल्कि उसे आंतरिक अनुभव

भी दे जाती है। मल्लिका भावना को ही सर्वोपरि मानती है। वह अपने व कालिदास के संबंध को सभी सम्बन्धों में सर्वश्रेष्ठ मानती है। अपने पूरे जीवन की आहुति देकर भी वह कालिदास को ऊँचे से ऊँचे शिखर तक पहुँचाना चाहती है। कालिदास को उज्जयिनी के राजकवि के पद के लिए चुना जाता है, इसके उपरांत कालिदास जब मिली हुई प्रतिष्ठा व पद के प्रति उदासीन भाव दिखलाता है तब मल्लिका ही उसे प्रोत्साहित करती है। वह कहती है कि—

"तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे, तो मुझे सुख होगा? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं रही। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए।"²

उल्लिखित कथन इस बात का द्योतक है कि मल्लिका खुद अंदर से जितनी टूट जाये, बिखर जाये पर कालिदास को बनते हुए देखना चाहती है। वह उसे अपने प्रेम में बांधना नहीं बल्कि उन्मुक्त अथवा स्वच्छंद रखना चाहती है।

कालिदास के प्रति उसका निश्चल प्रेम हर दृश्य में विदित होता है। कालिदास द्वारा लिया गया यह प्रण कि वह जीवन भर अविवाहित रहकर, साहित्य सृजन को ही अपना सर्वस्व मानेगा। मल्लिका उसके द्वारा लिए गये प्रतिज्ञा का सम्मान करती है व समाज द्वारा लगाए गये तमाम लांछनों को हँसकर झेल लेती है क्योंकि वह विवाह को ही जीवन कि अंतिम परिणति नहीं मानती। वहीं कालिदास उज्जयिनी जाकर राजकवि की पदवी धारण कर प्रियंगुमंजरी नामक राजकन्या से विवाह कर लेता है। उसे इस बात की भी सुध नहीं रहती कि उसके पीछे किसी ने अपना पूरा जीवन तिरोहित कर दिया है। यह इस दृश्य को उद्घाटित करता है कि किस प्रकार एक स्त्री किसी के नाम पर ही अपना पूरा जीवन बिता देती है, वहीं पुरुष सिर्फ अपने तक सीमित रहता है, उसके लिए अपनी आशाएँ-आकांक्षाएँ ही सर्वोपरि हैं।

नाटक का अंतिम अंक ही मल्लिका कि यथार्थता का बोध कराता है। प्रियंगुमंजरी उसके टूटे हुए घर को पक्का करवाना चाहती है, उसके लिए महंगे वस्त्र व स्वर्ण मुद्राएँ भिजवाती है पर मल्लिका इन सबको लौटा देती है। कालिदास से किया गया उसका प्रेम उसकी नजर में अमूल्य है, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। तीसरे अंक में वर्णित किया गया दृश्य उसके जीवन के अभाव का यथार्थ वर्णन है।

जब उसे यह पता चलता है कि कालिदास कश्मीर का शासक बना दिया गया है और वहाँ के राजनीतिक उथल-पुथल कि वजह से कालिदास उस प्रदेश को छोड़कर भाग गये हैं, यह सुनकर बहुत छुब्ध होती है। उसे यह लगता है कि यह हार कालिदास कि न होकर उसकी हुई है। आखिर उसने अपने जीवन कि तीलांजलि देकर बदले में पाया क्या, एक हारा हुआ कालिदास!

मल्लिका की माता का देहांत हो चुका है, अब माँ का स्थान उसने ग्रहण कर लिया है। अब उस घर में वह अकेली नहीं, उसके साथ एक बच्ची भी है। जिसका परिचय वह इस प्रकार से कराती है

“यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे, वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी-कितनी आकृतियाँ हैं!”³

इसका आशय यह हुआ कि उस बच्ची के पिता का कोई नाम नहीं। एक स्त्री का शरीर भी स्पर्श का भूखा होता है, उसी का नतीजा है वह बच्ची। मल्लिका का यह कहना कि अभाव में न जाने कितने चित्र थे! यह कथन उसके कई पुरुषों के साथ सम्बन्ध को दर्शाता है। उसे लोग ‘वारांगना’ शब्द से अभिहित करते हैं। ‘वारांगना’ जिसका अर्थ हुआ वेश्या। जीवन में आये अभाव कि पूर्ति के लिए मल्लिका को इस विशेषण को उपार्जित करना पड़ता है।

विलोम का कालिदास से यह कहना कि अष्टावक्र कहता है कि बच्ची कि आकृति सचमुच मुझसे मिलती है या.....। यह इस ओर संकेत करता है कि मल्लिका अविवाहित रहते हुए भी कई पुरुषों से सम्बन्ध बनाती है। कालिदास जब वापस लौट कर आता है तो उसे लगता है कि वह आज भी मल्लिका को उसी स्थान पर खड़ा पाएगा जहाँ पर उसे छोड़ गया था। लेकिन जब उसका यथार्थ के साथ परिचय होता है तब उसकी आंखें खुलती हैं। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि समय किसी के लिए नहीं ठहरता, उसी प्रकार जिस प्रकार से हम रेत को मुट्टी में नहीं भर सकते। जब कालिदास मल्लिका के वर्तमान से अवगत होकर उसके घर से निकलता है तो उसके पीछे-पीछे मल्लिका भी निकलती है लेकिन गोद में बच्ची को देखते ही उसके पाँव जहाँ के तहाँ रुक जाते हैं, व उसे अपने वर्तमान का बोध हो जाता है।

निष्कर्ष-

इस नाटक में मल्लिका की अंतिम परिणति को पाठक की सोच पर छोड़ दिया गया है। नाटक के अंत तक जाते- जाते लेखक पाठक के मन पर कई सारे अमिट प्रश्न छोड़ जाता है। किस प्रकार से उत्साह से भरी हुई स्त्री उत्साहहीन हो जाती है व यौवनावस्था से उस स्थिति तक पहुँच जाती है, जहाँ यौवन का नामोनिशान तक नहीं बचता है। यह पूरा नाटक मल्लिका के प्रेम के उस अविरल भाव को दर्शाता है जो अपने जीवन का अपकर्ष कर कालिदास को उत्कर्ष तक पहुंचाना चाहती है। प्रेम के उस रूप का जीवंत चित्रण है जो सिर्फ देना जनता हो।

संदर्भ सूची-

1. मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, संस्करण 2016, राजपाल एंड संज, पृ.सं- 10
2. आषाढ़ का एक दिन, पृ.सं- 45
3. वही, पृ.सं- 93
4. गिरीश रस्तोगी, मोहन राकेश और उनके नाटक, 5वां संस्करण, लोकभारती प्रकाशन, 2015, पृ.सं-47
5. गोविंद चातक, आधुनिक नाटक का अग्रदूत मोहन राकेश, पहला संस्करण, राधाकृष्ण प्रकाशन, 2003, पृ.सं- 62

सारांश

भाषा और संस्कृति के सम्बन्ध में जब हम विचार करते हैं तो यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि भाषा में संस्कृति का भावानुवेश और समाज का युगानुरूप प्रतिबिम्ब सहज ही दर्शनीय है। चिरकाल से अद्यावधि भाषा समाज में मानवीय मूल्यों की संस्थापना का साक्षात् सम्प्रेरक रहा एवं शाश्वद्रूपेण सदैवच अभिसिञ्चित भी किया है।

मानव जाति के उद्भव एवं विकास में भाषा का विशिष्ट महत्त्व है। भाषा मानव की अनुभूतियों, भावनाओं, उद्गारों, आकांक्षाओं, स्वप्न या आदर्शों का वाहक है। इसी कारण से भाषा के माध्यम से लिखे गये जो साहित्य है, वह मानव की अपनी-अपनी स्वयं संस्कृति का दर्पण होता है। भाषा के माध्यम से हमारे आचार विचार-संस्कार आदि परिलक्षित होते हैं।

वैसे तो अनुसंधानों के आधार पर भारतीय परम्परा में भाषा का उद्गम वैदिक भाषा से ही माना जाता रहा है। स्वयं 'ऋग्वेद' और 'काव्यादर्श' में इसे 'दैवीवाक्' कहा गया है। भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि 'रामायण' में पाया गया है।

आचार्य पारिणि के समय में छन्दस् (वैदिक) एवं भाषा (लौकिक) का स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है। पाणिनि के बाद प्रकृत एवं द्रविड़ भाषाओं के अनेक तत्त्वों का सम्मिश्रण इसमें होता रहा, इसलिए आचार्य कात्यायन को संस्कृत में आगत इन नये शब्दों एवं प्रयोगों की सिद्धि के लिए पाणिनि के सूत्रों का वार्तिक लिखकर प्रमाणिकता प्रदान करनी पड़ी।

भाषा और संस्कृति एक दूसरे के सहायक एवं पूरक है। संस्कृति भाषा को गति देती है और भाषा संस्कृति के विकास में योगदान देता है। भाषा और संस्कृति पर विचार करने से पहले हमें सम्यक् रूप से भाषा और संस्कृति के विषय में जानना आवश्यक है, क्योंकि हर समाज की अपनी भाषा और संस्कृति होती है।

भाषा मनुष्य के परस्पर विचार विनिमय का साधन है। 'भाषा व्यक्तायां वाचि' भाषा किसी भी समाज के सदस्यों के बीच परस्पर सम्पर्क और संवाद का माध्यम माना गया है सम्पर्क और संवाद के बिना किसी समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव-इतिहास और इस प्रकार भाषा मनुष्य के लिए विचार-विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण साधन है।

हम श्रेष्ठ प्राणी क्यों हैं? आहार, निद्रा, भय मैथुन आदि ये सारे गुण तो मनुष्य और पशु-पक्षी दोनों में समान रूप से पाये जाते हैं, किन्तु हमारे पास विचाराभिव्यक्ति के लिए सार्थक ध्वनि समूह है, शब्द

है, विचार है, सोचने समझने की क्षमता है, विवेक है। यद्यपि अन्य प्राणी भी बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा और मानवीय भाषा में मूलभूत अन्तर यह है कि हमारी भाषा रचनात्मक है और उनकी भाषा रचनात्मक नहीं है।

यद्यपि भाव अभिव्यक्ति के अन्य साधन भी हैं। जैसे- नेत्रों की भाषा, संकेत की भाषा, स्पर्श की भाषा, हाव-भाव की भाषा आदि। अपने व्यवहार से भी हम बहुत कुछ व्यक्त करते हैं। हमारी वेश-भूषा, हमारा पोशाक, हमारी मुद्रा सब कुछ बोलती है और भाषा को हम नहीं बोलते, भाषा हमें अभिव्यक्त कराती है। जैसे ही हम बोलते हैं, हमारा परिचय प्रत्यक्ष हो जाता है। भाषा के बिना मानवीय चिन्तन ही संभव नहीं है। मानवीय बोध का पारस्परिक सम्प्रशण भाषा ही है। अगर भाषा नहीं होती तो मानव व्यवहार कहाँ से आता, इसलिए कहा गया है-

“वाचां प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते।”³

भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं, एक चेतना है। बच्चा जब पैदा होता है तब रोता है, यदि वह नहीं रोता है तो उसे रूलाया जाता है और उसके बाद भी जब वह नहीं रोता है तो उसे निष्प्राण मान लिया जाता है।

भाषा में अर्थ-प्रकाशन की अद्भुत क्षमता को देखकर दण्डी 'काव्यादर्श' में कहते हैं।

“इदमन्धतमः कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम् ।

यदि शन्दहयं ज्योतिरासारं न दीप्यते ॥”⁴

यानि यह सम्पूर्ण संसार अन्धकारमय होता यदि शब्द नामक ज्योति नहीं होती। शब्द नामक ज्योति से ही यह समग्र संसार स्थावर, जंगम देदीव्यमान है। भर्तृहरि वाक्यपदीय में भी कहते हैं।

“अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं ।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥”⁵

अर्थात् शब्द रूपी ब्रह्म अनादि, विनाशरहित तथा अक्षर है एवं कभी नष्ट नहीं होने वाला है तथा उसकी विवर्त क्रिया से ही यह सम्पूर्ण जगत् भासित होता है। अन्ततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस सृष्टि में जो समस्त हलचलें हो रही हैं, वह कहीं न कहीं भाषा का ही रूप है। पक्षी कलरव करके, पेड़-पौधे हिलकर वायु कम्पन कर, समुद्र अपनी गर्जना से तो मेघ गर्जन करके नदियाँ कल-कल करके भाषा व्यक्त करती है। उनकी यही भाषा है। इस प्रकार भाषा विभिन्न माध्यमों से हमारी संस्कृति की वाहिका भी है।

संस्कृति शब्द सम् उपसर्ग पूर्वक कृञ् धातु से क्तिन् (ति) प्रत्यय, सुडागम आदि होकर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है - सजाना, सँवारना, सुशिक्षित करना और पवित्र करना। भूषणभूतसम्यक् कृति चेष्टा वा अर्थात् संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है- सम्यक् प्रकार से

किया जाने वाला व्यवहार अथवा क्रिया है। अंग्रेजी भाषा में संस्कृति के लिए Culture 'कल्चर' Culture शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द लैटिन भाषा के कलचुरा तथा 'कोलियर' से निकला है जिसका अर्थ क्रमशः उत्पादन तथा परिष्कार है। संस्कृति में व्यक्ति तथा समाज की वे क्रियाएँ, उत्पादन, व्यवहार, संस्कार तथा परिष्कार सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति तथा समाज के लक्षणों को पहचाना एवं परखा जा सकता है। सच कहा जाए तो संस्कृति मानव के आदि काल से लेकर आज तक की वह संचित निधि है जो उत्पादन तथा परिष्कार द्वारा निरन्तर प्रगति करती हुई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त होती चली आई है तथा भविष्य में भी उसकी यही गति रहेगी किन्तु विकास के क्रम में उसमें परिवर्तन देखा जाता है।

इस संस्कृति को जाने और समझने का सबसे सशक्त उपकरण है – भाषा। भाषा हमारे सांस्कृतिक प्रतिफलन का ही विस्तार है और उसी के अनुरूप शब्द अपना आकार ग्रहण करते हैं। संस्कृति के कारण ही हम अपनी भाषा का विस्तार देते हैं। भाषा के माध्यम से ही मिथक और उनकी कथाएँ रची जाती हैं और हर भाषा अपने अन्दर सांस्कृतिक आयाम छिपाए रहती है। भाषा के साथ समाज का सांस्कृतिक आचरण जुड़ा हुआ है। शब्दों के भीतर यह सांस्कृतिक आचरण दिखाई पड़ता है। अभिवादन, व्यवहार, सम्बोधन, क्रिया-कलापों, शब्दिक प्रयोगों, रिश्ते-नाते की शब्दावली में सांस्कृतिक आचरण ही दिखाई पड़ता है।

संस्कृति के विकास में भी भाषा का बड़ा योगदान होता है। भाषा के द्वारा ही सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति होती है एवं भाषा के माध्यम से सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानकों की स्थापना भी होती है। भाषा मनोभावों की अभिव्यक्ति के माध्यम होने के कारण संस्कृति का अंग होती है और उसे निरूपित भी करती है। अतः भाषा का विकास संस्कृति के विकास का एक बड़ा कारक होता है। संस्कृत भाषा में निहित मूल्यों आदर्शों का जब अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया और वहाँ के लोगों को जब उसके गूढ़-तत्त्वों का ज्ञान हुआ तब उसके कारण वहाँ की संस्कृतियों में परिवर्तन देखा गया और वहाँ के लोग भारतीय वेश-भूषा और दर्शन की ओर आकृष्ट होने लगे।

ऐसा देखा जाता है कि समाज में जब दो संस्कृतियाँ टकराती हैं तो भाषा उसमें सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है। दो भिन्न-भिन्न समाजों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ जब एक दूसरे को प्रभावित करती हैं तो दोनों का रूप ही बदल जाता है। किसी भी भाषा का स्वरूप एक सा नहीं रहता। दूसरी भाषाओं के प्रभाव से उसमें निरन्तर बदलाव आता रहता है। सोलवी शताब्दी में अनेक यूरोपीय देशों का भारत के साथ व्यापार स्थापित हुआ और यहाँ उपनिवेश स्थापित किये। फलस्वरूप हिन्दी भाषा, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से प्रभावित हुए और उन भाषाओं में इतर भाषाओं के शब्दों का प्रचलन बढ़ा। हिन्दी और संस्कृत ग्रन्थों का

यूरोपीय भाषा में और यूरोपीय भाषाओं के विशेषकर अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं के ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद हुआ।

स्वतन्त्रता संग्राम के पहले अंग्रेजों के द्वारा भारतीय उग्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं के लिए Bad Mass शब्द का प्रयोग किया जाता था। वह 'बदमाश' शब्द बुरे लोगों के लिए इस समय प्रचलित हो गया है। इसी तरह कितने अंग्रेजी शब्द भी ब्रिटिश शासन काल में लोक प्रचलन में आ गये। जैसे – स्टेशन, प्लेटफार्म आदि।

इसी प्रकार भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के पश्चात् भारतीय और अरबी संस्कृति जब एक दूसरे के सम्पर्क में आई तब एक दूसरी की भिन्न संस्कृति होने के कारण भाषा को समझना अनिवार्य समझा गया। तदनन्तर भारत में अरबी-फारसी के बोल-बाला होने से इनके शब्दों का यहाँ प्रवेश हुआ। तब फारसी से हिन्दी एवं संस्कृत से फारसी में अनुवाद होने लगा। इन्हीं अनुवादों के कारा दो भिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक सम्पर्क से एक ऐसी भाषा विकसित हुई जो आगे चलकर 'उर्दू' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस उर्दू भाषाओं में फारसी शब्दों का बाहुल्य था। आरम्भिक हिन्दी और उर्दू में इतना ही अन्तर है कि उर्दू में फारसी शब्दों का और हिन्दी में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। शनैः-शनैः उर्दू और हिन्दी अलग-अलग भाषाओं के रूप में विकसित हुई। दोनों की अपनी-अपनी विधा में साहित्य का विकास हुआ।

इसी प्रकार संसार की उपलब्ध भाषाओं में प्राचीनतम संस्कृत भाषा की रचनाएँ हमारे देश की व्यापकता सिद्ध करती है। 'वसुधैव कुटुम्बम्'⁸ का उद्घोष संस्कृत भाषा साहित्य की ही देन है। विष्णु पुराण की यह उक्ति –

“उत्तर यत्समुद्रस्य हिमद्रेश्चैव दक्षिणम्।।

वर्ष तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः।।”

अर्थात् जो देश समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, इसे पहले के लोगों ने 'भारत' कहा है और वहाँ की प्रजा 'भारती' कहलाती है।

संस्कृति युग-युगीन मानव आत्माओं के संस्कारों की विशाल गाथा है। भारतीय संस्कृति की गाथा उतना ही पुरातन है जितना कि बहुसंख्यक वेदमन्त्रों की संहिताओं के रूप में परिणत करने की स्वर्णिम क्षण। भारतीय भूखण्ड में पल्लवित होने वाली संस्कृति को 'सा प्रथम' संस्कृतिर्विश्ववारा⁹ अर्थात् विश्व की प्रथम संस्कृति कहकर सम्पूर्ण विश्व के लिए वरणीय बतलाया।

संस्कृति का पहला घटक है— जहाँ से हम अपने सांस्कृतिक जीवन का प्रारम्भ करते हैं जैसे— जीवन में सत्य को आत्मसात् करना, सत्य बोलना, सदाचार के लिए मन्त्रों और वाक्यों से बोध आदि को हमारे ऋषियों ने संस्कृति के गुण आचारण को बढ़ा ही सुन्दर ढंग से सजाया है— 'सत्य वद', 'धर्म चर', 'मातृदेवो भव', 'पितृदेवो भव', 'अहिंसा परमो धर्मः', 'आत्मवत् सर्वभूतेशु', 'परोपकारः पुण्याय' आदि। एक तरफ भगवद्गीता में निश्काम कर्म,

ज्ञान और भक्ति का संदेश है तो दूसरी और समन्वय और सामञ्जस्य की निपुणता भी स्पष्टरूपेण दीखती है। योग तो भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य देन है जो शरीर के साथ मन को स्वस्थ, शान्त और आत्मा को सशक्त बनाती है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार भाषा और संस्कृति का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। भाषा का सम्बन्ध व्यक्ति के ज्ञान से न होकर उसकी सांस्कृतिक पहचान से होती है। प्राचीन ग्रन्थों से हम अपनी संस्कृति का अवलोकन करते हैं। अतः संस्कृति को समझने के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। जब कोई भाषा मरती है तब समाज के सोचने समझने और व्यक्त करने के तौर तरीके भी मर जाते हैं जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सामाजिक जीवन-शैली भी मर जाती है। उदाहरण स्वरूप आज संस्कृत भाषा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम हो गई और इसका प्रभाव हमारे सामाजिक परिवेश पर भी दीख रहा है यानि हमारे समाज में जो नैतिक मूल्य स्थापित थे वह आज विघटन की ओर अग्रसर है। संस्कृति में आपसी सामञ्जस्य एवं समन्वय स्थापित करने के लिए भाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

सन्दर्भ-ग्रन्थ :

1. (क) दैवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । ऋग्वेद 8/100/11।
- (ख) संस्कृतं नाम दैवीवागन्वख्याता महर्षिभिः । - काव्यादर्श - 1.1. 33
2. आहार निद्रा भय मैथुनानि - नारायण पंडित
3. काव्यादर्श-दण्डी
4. काव्यादर्श-दण्डी
5. भर्तृहरि - वाक्यपदीय - 1
6. हितोपदेश - नारायण पंडित
7. विष्णुपुराण - पराशर ऋषि
8. यजुर्वेद - 7.14
9. तैत्तिरीयोपनिशद् ।

पत्राचार का पता-

Dr. (Prof.) Niva Sharma

House No. - 08,

Road No. - 01,

Professor Colony

Aghoria Bazar Chowk,

Muzaffarpur - 842002

सारांश

अठ्ठारह सौ सत्तावन ईसवी में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की विजय अवश्य हुई, किंतु इस संग्राम से देशवासियों में स्वाधीनता की चेतना जागृत हो गई और अंग्रेजों को भी यह लगने लगा कि अब इस देश में शासन करते हुए हमें प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल विभाजन का प्रबल विरोध हुआ तथा गोखले, लाला लाजपत राय, तिलक और फिर गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बज गया। गांधीजी सत्याग्रह, अहिंसा, एवं सविनयज्ञा के जिन अस्त्रों का आविष्कार एवं उपयोग दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन में करके प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उन्ही अस्त्रों का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने किया। गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक आंदोलन से मे न केवल अंग्रेजी शासन की जड़े हिला दी अपितु भारतीय जन चेतना को व्यापक रूप में जाग्रत किया। जितना प्रभाव भारतीय जनता पर गांधी जी का था संभवतः उतना किसी अन्य नेता का नहीं था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन एक और तो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था तो दूसरी ओर सुभाष चंद्र शेखर आजाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी अपने ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। सन् 1942 में प्रारंभ किए गए 'भारत छोड़ो आंदोलन' की व्यापकता से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए और उन्हें लगने लगा कि अब भारतीयों को स्वाधीनता तो देनी ही पड़ेगी अंततः देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, किंतु अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक चाल से देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। विभाजन की इस त्रासदी को लाखों लोगों ने झेला और द्विराष्ट्र की अवधारणा से उत्पन्न संकटों को हम आज भी झेल रहे हैं।

स्वाधीनता आंदोलन से हिंदी के कई लेखक एवं उपन्यासकार प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं। गांधी जी के आह्वान पर अनेक लोगों ने सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया तथा हजारों लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। प्रेमचंद भी उनमें से एक थे। उनके कहानी संकलन 'सोजे वतन' को अंग्रेजी सरकार पहले ही जब्त कर चुकी थी। जैनेंद्र कुमार, विष्णु प्रभाकर ने तो सत्याग्रह में प्रत्यक्ष भाग लिया था जबकि यशपाल अज्ञेय, मन्मथनाथ, गुप्त जैसे साहित्यकारों ने क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया था। इन्हें कई वर्षों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। फणीश्वर नाथ 'रेणु' एवं विवेकी राय की गतिविधियां भी स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी रही थी। स्वाभाविक रूप से इन सभी लेखकों ने अपनी कृतियों में उस काल का प्रामाणिक विवरण औपन्यासिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया।

हिंदुस्तान के इतिहास में स्वाधीनता आंदोलन का काल

विशेष स्थान रखता है यह काल राष्ट्रीय और सामाजिक उथल-पुथल का काल था रामदरश मिश्र की सम्मति में यह सक्रांति काल दो प्रकार की संस्कृतियों का दो प्रकार के मूल्यों का साथ ही साथ संघर्ष काल था साम्राज्यवाद से राष्ट्रवाद का सामन्ती सभ्यता से महाजनी सभ्यता का एवं शांति एवं महाजनी दोनों सभ्यताओं से शोषित किसानों और मजदूरों की शक्तियों का राजनीतिक क्षेत्र में उथल-पुथल मची थी। पराधीन भारत साम्राज्यवादी ब्रिटिश राज्य से मुक्त होने के लिए तड़प रहा था अठ्ठारह सौ सत्तावन ईसवी से शुरू हुए विद्रोह के स्वर मुक्ति के स्वर साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रबल होने के बावजूद सक्रिय रहे प्रतिरोध का क्रम टूटा नहीं। प्रथम तिलक गोखले और लाला लाजपत राय एवं बाद में महात्मा गांधी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की शहादत ने इस मुक्ति संग्राम में आग में घी का काम किया।

हिंदी उपन्यासों पर स्वाधीनता आंदोलन का दो प्रकार से प्रभाव पड़ा कुछ एक उपन्यासकार तो गांधीजी के प्रभाव से स्वदेशी के प्रभाव और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त सरकारी सेवाओं को त्याग कर आजादी की जंग में शिरकत करने लगे जैसे प्रेमचंद ने गांधी जी के आह्वान पर स्वयं नौकरी छोड़ दी और सोजे वतन से दृष्य कहानी संकलन पर शासक सत्ता का कोप भाजन बने जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर आदि उपन्यास सर्जकों ने असहयोग आंदोलन आदि में सकारात्मक रूप से भाग लिया। यशपाल मन्मथ नाथ गुप्त आदि सशस्त्र क्रांतिकारियों के संगठन के सदस्य थे। उन्हें कई वर्षों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा अज्ञेय का उपनाम 'अज्ञेय' जेल में ही पड़ा तथा फणीश्वरनाथ रेणु विवेकी राय सभी स्वाधीनता संग्राम से संबंध है। इसके अलावा अन्य सर्जकों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वाधीनता आंदोलन को अभिव्यक्ति दी और आजादी की लड़ाई को अपनी सर्जना का उपजीव्य बनाया प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि, रंग भूमि और गबन में मुक्ति संग्राम के दौरान जनसहयोग, नेतृत्व, क्षमता और शासकों की भेद नीति आदि का प्रामाणिक वर्णन है। कर्मभूमि में बीसवीं शती के दशक का यथार्थ, रंगभूमि संघर्ष के दौरान, हिंसा की ताकत का बयान है। इस उपन्यास में सूरदास का अंत उसी प्रकार दिखाया गया है जिस प्रकार महात्मा गांधी का हुआ गबन में देशभक्तों के विरुद्ध उपनिवेशवादियों के षड्यंत्र को विषय बनाया गया है इस उपन्यास में प्रेमचंद ने दोनों स्तरों पर मुक्ति की बात की है देसी सामंतवाद से विदेशी साम्राज्यवाद से।

जैनेंद्र व्यक्ति के मानस के रचनाकार हैं। उनके उपन्यासों में स्वाधीनता संघर्ष का विषय एवं बाह्य चित्रण नहीं हुआ है। उनके

उपन्यास सामाजिक जीवन की असंगतियों, विसंगतियों गिरते मानव मूल्यों स्त्री की स्थिति आदि को लेकर चलते हैं। यशपाल और अज्ञेय की उपन्यास सर्जना में क्रांतिकारी जीवन के अनुभव के अभिव्यंजना है अज्ञेय द्वारा रचित 'शेखर एक जीवनी' में 'शेखर' को राजद्रोह के अपराध में फांसी की सजा मिलती है यह कारावास की कोठरी में बैठकर अपने अनुभव को व्यक्त करता है अज्ञेय अपने जीवन का बहुत कुछ प्रतिबिंब शेखर में दिखाई पड़ता है। उसका बहुत समय क्रांतिकारियों के बीच व्यतीत हुआ तथा वह क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहा इन सब घटनाओं में स्वाधीनता आंदोलन का वह पक्ष दिखाई देता है जो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। स्वतंत्रता को लेकर अज्ञेय उस समय तक आश्वस्त नहीं थे। स्वतंत्रता को लेकर वह कहता है कि मुक्ति स्वराज स्वतंत्रता कितने सुंदर शब्द है किंतु कहां है इनके पनपने के लिए खाद्ययुक्त मिट्टी जनता यशपाल ने उपन्यासों में आजादी को 'झूठा सच' कह कर व्यक्त किया है। देशद्रोही, दादा कामरेड आदि सिहालोकन में भी आजादी के संघर्ष के पदच्युत होने से चिंतित हैं। लेकिन आजादी मिल जाने के बाद कि उनकी निराशा झूठा सच (भाग 2) में व्यक्त हुई है झूठा सच इस कड़वी सच्चाई को उकेरता है कि अंग्रेजी अंग्रेजों के शासन में संप्रदायिकता की जो फली फूली वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक विकराल रूप में सब के गले में फंस गई तमस के लेखक भीष्म साहनी ने भी आजादी मिलने के समय के सक्रमण कालीन यथार्थ को व्यक्त किया है साम्राज्यवाद सांप्रदायिक विभाजन की त्रासदी पर इन्होंने कलम चलाई है।

कमलेश्वर के उपन्यास सुबह, दोपहर शाम में भी स्वाधीनता आंदोलन की झलक है बड़ी कुशलता से कमलेश्वर ने दादी के माध्यम से इस आंदोलन को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है अंग्रेजों के अत्याचार से भारतीय युवक किस प्रकार लोहा लेते हैं इसका चित्र इसमें बखूबी मिलता है।

भीष्म साहनी के प्रसिद्ध उपन्यास 'तमस' में भी उस घृणा को चित्रित किया गया है, जो हिंदू मुसलमानों के मन में सुलग रही थी। किस प्रकार कुछ कट्टरपंथी लोग धार्मिक उन्माद सुलगाकर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकते थे। इस का कच्चा चिह्न इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार उन्होंने अपनी एक कहानी 'अहम ब्रह्मास्मि' तत्कालीन भारतीयों की मानसिकता को अभिव्यक्ति दी है। एक और तो वे भारतीय थे जो गांधी जी के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे तथा उसे सही बता रहे थे तो दूसरी ओर 'भाटिया' जैसे लोग भी थे जो अंग्रेजी मानसिकता एवं रहन सहन में इस प्रकार रंग गए थे कि आंदोलन करने वालों को मूर्ख मान रहे थे। किंतु जब अंग्रेजों से उसका मोह भंग हुआ तब उसे लगा कि सार्थक जीवन तो उस डुगडुगीवाले का है जो झंडा हाथ में लिए अंग्रेज सिपाहियों के जुल्म के आगे जान दे देता है।

हिंदी के अन्य अनेक उपन्यासकारों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की सूचना और उसके साथ जुड़े भले बुरे परिवर्तनों के उल्लेख के साथ समाप्त हुए हैं। इनमें स्वाधीनता संघर्ष के दौरान शासकों एवं शासितों के मध्य के संघर्ष को विवृति मिली है विस्तृत विवरण के साथ 'मैला आंचल' में बावन दास चोला उतारने वाला मुखोटा बदलने वाला पात्र है। रामदरश मिश्र के उपन्यास 'पानी के प्राचीर' में आजादी किसको मिली है का वर्णन है। आम आदमी की आजादी को लेकर प्रश्नाकुलता है 'आधा गांव' में मुस्लिम सामंती शक्तियों की चर्चा है।

कुछ एक उपन्यास और हैं जिनमें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की अनुगूंज सुनाई पड़ती है प्रताप नारायण श्रीवास्तव कृति 'ब्यालीस नामक' उपन्यास में भारतीयों की स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तथा अंग्रेजों द्वारा सत्ता कायम रखने के लिए किए गए निर्मम अत्याचारों का यथार्थ अंकन किया गया है। 'श्वेत पत्थर' विवेकी राय, देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात अमृतराय की 'जीच' मन्मथ नाथ गुप्त 'बलिदान' रघुवीर शरण मिश्रा 'सीधी सच्ची बातें' भगवती चरण वर्मा आदि ने इस विद्रोह को दिखाया है। इसके अलावा बाणभट्ट की 'आत्मकथा' एवं गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया भी इसी उपजीव्य को लेकर सृजित है पाहीघर पर छाई नाच काल कथा आदि मुक्तिसंग्राम को व्यक्त करते हैं। यशपाल ने अपने उपन्यास 'मनुष्य के रूप में' पुलिस के उत्पीड़न का चित्रांकन किया है तो देशद्रोही में कम्युनिस्ट पार्टी की स्वाधीनता आंदोलन संबंधी नीति का प्रामाणिक उल्लेख है।

विवेकी राय ने बलिया जनपद में स्वाधीनता आंदोलन की अलख जगाई थी जिसका प्रामाणित विवरण उनके उपन्यास 'श्वेत पत्र' में मिलता है गांधीजी के अहिंसा सिद्धांत का उल्लेख इस उपन्यास में उपलब्ध होता है। उपन्यास का एक पात्र तिवारी अपने सहयोगियों को सचेत करते हुए कहता है:— "आवेश में यह नहीं भूल जाना है कि हम लोगों के युद्ध नायक महात्मा गांधी हैं और पूरी लड़ाई में सत्य, अहिंसा रहित भाव में कुछ सोचना भी नहीं है, बाहर 'करो या मरो' का उत्साह और भीतर आवेश में यह नहीं भूल जाना है कि धारणा है।

गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास पहला 'गिरमिटिया' तो स्पष्ट रूप से दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह को केंद्र बनाकर लिखा गया उपन्यास है। गांधीजी को केंद्र बनाकर ऋषभ चरण जैन 'सत्याग्रह' नामक उपन्यास लिख चुके थे। कमल कांत त्रिपाठी का 'पानीघर' तथा कामतानाथ का 'कालकथा' की स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास है।

निष्कर्ष

इस विवेचन के आधार पर यह कहना उचित होगा कि स्वाधीनता आंदोलन के अनेक हिंदी उपन्यासों की रचना के लिए उपन्यास कारों को प्रेरित किया स्वतंत्रता आंदोलन को आधार बना कर लिखी गई कृतियों में तत्कालीन निवेश का अंकित हुआ है। साहित्यिक गतिविधियों को तत्कालिक गतिविधियां प्रभावित एवं परिचालित करती है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किए गए संघर्ष को हिंदी उपन्यासों में चित्रित किया गया। निसंदेह इन उपन्यासों में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना के आंतरिक और बाह्य स्वरूप को विकसित किया। देशभक्ति पूर्ण इन उपन्यासों में इन उपन्यासों में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना के आंतरिक और बाह्य स्वरूप को विकसित किया देशभक्ति पूर्ण इन उपन्यासों ने जनमानस को अंदर तक झकझोर दिया लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हुए प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय जैसे उपन्यास कारों की रचनाओं ने जनमानस को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई इस युग के उपन्यास कारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन रूपी यज्ञ की अग्नि को और अधिक प्रचलित करने में महती भूमिका निभाई।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1 हिंदी उपन्यास श्री नारायण श्रीवास्तव पृष्ठ 135
- 2 कर्म भूमि प्रेमचंद पृष्ठ 61 संस्करण 1965
- 3 रंगभूमि प्रेमचंद पृष्ठ 542 प्रेमचंद संस्करण 1965
- 4 गबन प्रेमचंद पृष्ठ 171 17 संस्करण 1967
- 5 गोदान प्रेमचंद पृष्ठ 572
- 6 प्रेमाश्रम प्रेम चंद 279 संस्करण 1962
- 7 दादा कामरेड यशपाल पृष्ठ 53
- 8 झूठा सच यशपाल पृष्ठ 118
- 9 हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार वर्मा
- 10 हिंदी उपन्यास का परिचयात्मक इतिहास डॉक्टरताप नारायण टंडन 231 232
- 11 हिंदी उपन्यास का परिचयात्मक इतिहास डॉ प्रताप नारायण टंडन हिंदी पृष्ठ 268
- 12 हिंदी उपन्यास का परिचयात्मक इतिहास डॉ प्रताप नारायण टंडन पृष्ठ 303

डॉ. अनिल कुमारी

सहायक प्राध्यापिका,

दर्श शिक्षण संस्थान, गोहाना, सोनीपत

हरियाणा—131301

सारांश

शोधसार— स्वदेशी का सार है—सेवा की पवित्रता। गांधी जी ने स्वदेशी का सम्बंध सेवा की सार्वभौमिकता से किया था। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी का अर्थ है सेवा। सेवा की क्षमता हमारे ज्ञान की सीमा में बन्ध जाता है। अतः हमें तत्काल पड़ोसियों जिन्हें हम जानते हैं की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। साथ ही वे जो अपने पड़ोसी की सेवा की अवहेलना करता है, वह दोषी है। उसकी सेवा एक धर्म है। हमें अपने पड़ोसी की सेवा का दावा नहीं करना चाहिए। जब हम अपने पड़ोसी की सेवा नहीं कर रहे हैं और दूर दराज के लोगों की सेवा का दम भरते हैं, यह अज्ञानता और घमंड है। स्वदेशी सेवा के मानवीय क्षमता के वैज्ञानिक सीमाओं को स्वीकार करता है।

मूलशब्द— स्वदेशी, विदेशी, स्वराज्य, आर्थिक, कार्य—कुशल, इस्तेमाल, सन्कीर्णता, स्थानीयता, उत्पादन एवं उपभोग, अर्थव्यवस्था, लघु व कुटीर, गुणवत्ता, खामियां, यन्त्र और मशीन !

स्वदेशी की व्यापक परिभाषा

1. घर में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग और विदेशी चीजों का वर्जन जो भारतीय गृह उद्योगों को संरक्षण प्रदान करेगा। इन उद्योगों के संरक्षण के बिना भारत खुशहाल नहीं हो सकता। अक्टूबर 1917 गोधरा में आयोजित पहली गुजरात प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में गांधी जी ने कहा कि हमें शिकायत है कि भारत के लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि स्वराज्य हमें स्वदेशी से ही प्राप्त होगा। 1।

2. स्वदेशी वह भावना है जो हमें दूरदराज के इलाकों को छोड़कर अपने नजदीकी क्षेत्रों का उपयोग करने और उनकी सेवा करने तक सीमित करती है... जहां तक आर्थिक क्षेत्र का सम्बंध है! मुझे उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनका उत्पादन मेरे नजदीकी पड़ोसी करते हैं। और यदि मुझे वहां के उद्योगों में कोई कमी दिखाई देती है तो मुझे उन्हें अधिक कार्य—कुशल और पूर्ण बनाने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए! 2।

3. स्वदेशी के अन्तर्गत सबसे पहले स्थानीयता को महत्व दिया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में इसका आशय है कि स्थानीय स्तर पर उत्पादन एवं उपभोग हो। एक प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या ऐसा करना या मानना संकीर्णता नहीं कहा जा सकता? यह प्रश्न गांधीजी के सामने भी था। इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरा इस सत्य में अडिग विश्वास है कि व्यक्ति एक ही साथ अपने पड़ोसियों और मानवता की सेवा कर सकता है।

स्वदेशी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:— भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के दरमियान स्वदेशी के विचार का जन्म हुआ। गांधी जी से पूर्व मध्य 19वीं सदी में कारीगर आधारित भारतीय उद्योग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की

बर्बादी, गरीबी व ब्रिटिश शासन काल में बार-बार अकाल की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी आया। हालांकि एक जन-आन्दोलन के रूप में स्वदेशी सर्वप्रथम बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 से 1911 के आन्दोलन में आया। इसके दायरे में राजनीतिक प्रतिरोध, भारतीय कुटीर व ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, विदेशी आयातित मालों के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, कला, विज्ञान और साहित्य को पुनर्जीवित करने, सरकारी नौकरी के छोड़ने तथा सामाजिक सुधारों से था। बहन निवेदिता के सन्देश में स्वदेशी की भावना ओत-प्रोत है! अपने नैतिक सम्बद्धता में विश्वास करो। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जिसमें सभी के हित समान हों। इसे ही स्वदेशी अभिव्यक्ति कहेंगे।

1915 के बाद गांधीजी के गतिशील नेतृत्व के तहत स्वदेशी की अवधारणा ने एक नए आयाम को हासिल कर लिया। गांधी जी इसे एक विचारधारा के रूप में परिभाषित करते हैं। जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना ध्यान रखता है फिर अपने पड़ोसियों का तथा इस प्रकार यह कभी न घटने वाला घेरा तब तक बढ़ता है जब तक अपने दायरे में संपूर्ण विश्व को शामिल न कर लेता है। उनके अनुसार स्वदेशी के आंदोलन का लक्ष्य भारतीयों द्वारा भारत में उपयोगी सामानों का निर्माण लघु उद्योगों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देना था। गांधी जी स्वयं स्वदेशी को इस प्रकार परिभाषित करते हैं! बहुत सोचने के बाद मैं स्वदेशी का सही अर्थ निकाल सका हूँ कि स्वदेशी से तात्पर्य उस भावना से है जो हमें अपने आसपास में निर्मित वस्तुओं के उपयोग तक से है। यह बाहर की वस्तुओं के प्रयोग को निषेध करता है। स्वदेशी एक धर्म है, एक कर्तव्य है जो हमें अपने पैतृक धर्म की सीमा में अनुबंधित करता है। अगर इसमें कोई दोष है तो इसे सुधारना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में केवल स्वदेशी संस्थाओं के प्रयोग से है तथा उसमें जो खामियां हैं उसे हटाकर उसके उपयोग से है। आर्थिक क्षेत्र में उन्हीं वस्तुओं के उपयोग से है जो आस-पास में निर्मित होती है तथा पड़ोस में बनने वाली चीजों की गुणवत्ता में सुधार व उपयोग से है। 3।

स्वदेशी आर्थिक विकल्पों को नैतिक दिशा प्रदान करता है तथा आत्म प्रावधानीकरण से एक मानवीय और समतावादी सामाजिक व्यवस्था का आधार बनता है। यह भाईचारे और सहयोग को मजबूती प्रदान करता है। 23 फरवरी 1935 को नागपुर में ग्रामीण कार्यकर्ताओं की बैठक में गांधी जी ने कहा अगर आप अपनी तरह अपने पड़ोसी को प्रेम करेंगे तो वह भी आपको वैसा ही प्रेम प्रदान करेंगे। आगे गांधी जी आगे कहते हैं कि—वास्तव में स्वदेशी ही एक ऐसा सिद्धान्त है जिसमें मानवता व प्रेम समाए हुए हैं। वास्तव में, स्वदेशी प्रेम और मातृभूमि की सेवा में है। मानव की सेवा हम अपने ज्ञान तथा जिस संसार में हम रहते हैं के दायित्व से अलग नहीं है। इसका मतलब है

कि हम जिसे जानते हैं तथा पड़ोसी की सेवा के द्वारा देशवासियों की सेवा कर रहे हैं सही मायने में यह मानवतावाद या मानवता से प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है।

स्वदेशी पर महात्मा गांधी के विचार-अर्थव्यवस्था वही सही कही जा सकती है जो उपभोक्ताओं की जरूरतों को सही तरीके से पूरी करती हो। वह तरीका अहिंसक होना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्र हमें इसके विपरीत दिखाई देता है। उसके लिए उपभोक्ता एक मनुष्य नहीं बल्कि एक वस्तु है। उसकी महत्ता तभी तक होती है, जब तक वह उपभोग करता रहता है। अर्थव्यवस्था का मकसद यह जानना कभी नहीं होता कि उस उपभोग का उस उपभोक्ता समाज और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास जरूरतों की पूर्ति के साथ-साथ कृत्रिम जरूरतों को भी पैदा करना और उपभोक्ता को उपभोग हेतु मजबूर करना है। हरबर्ट मार्क्यूज ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। यह अर्थव्यवस्था मनुष्य को मात्र उपभोक्ता मानने तथा लगातार उपभोग बढ़ाने के कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंसा को जन्म दे ही रही है, बल्कि लगातार उपभोग बढ़ने के कारण प्राकृतिक संसाधनों और समस्त पारिस्थितिकी के प्रति भी हिंसक है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था में उपभोग भी हिंसक हो सकता है और इस हिंसक प्रक्रिया को समर्थन देने लगता है।

महात्मा गांधी इससे आगे बढ़कर सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली के ढांचे को ही अहिंसक आधार देने की बात करते हैं। वह व्यक्तिगत प्रयास (अपरिग्रह) एवं संस्थागत परिवर्तन की ऐसी अहिंसक प्रक्रिया को जन्म देते हैं, जिससे एक नैतिक एवं अहिंसक अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो सके। और गांधीजी उत्पादन पद्धति पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। इस सम्बंध में गांधीजी को मशीन विरोधी अप्रगतिशील आदि कहा जाता है। गांधीजी कभी मशीन के विरोधी नहीं रहे। उनका आशय मशीन के मूल में छिपे हुए लोभ एवं अनियंत्रित लाभ कमाने की आशंका को समाप्त करने से था। उद्योग मशीनों के सम्मेलन में भाग लेते हुए उन्होंने मशीन की तीन महत्वपूर्ण विशेषता बताई है जो कि इस प्रकार हैं:

1. मैं इस शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहा हूँ बल्कि एक उपकरण के रूप में कह रहा हूँ कि जो मानव का पूरक होने या उसकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के बजाय उसको विस्थापित करने का कार्य करता है।
2. इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसकी वृद्धि या विकास की कोई सीमा नहीं है। यह बात मानव श्रम के बारे में नहीं कही जा सकती। उसके ऊपर अपनी ही इच्छा अथवा प्रतिभा सवार मालूम होती है। यह मानव श्रम का विरोधी है।
3. लाखों-करोड़ों लोगों का दमन और शोषण करने के लिए मशीन एक ऐसा दानव है जिसका कोई जवाब नहीं है यहां समाज में सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाना है तो मानो अर्थव्यवस्था में मशीन का कोई स्थान नहीं हो सकता! 4 मशीनों के सम्बंध में

गांधीजी की दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट थी कि मशीन का प्रयोग मनुष्य को विस्थापित करता है।

अतः उसका विरोध करना चाहिए। वह मानव को सर्वोपरि मानते हैं और मशीन को उससे नीचे स्थान प्रदान करते हैं। वह चाहते हैं कि मशीन के जरिए मनुष्य को मशीन में परिवर्तित कर दिया है। वह मनुष्य को पुनः अपने मूल स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं।

अपनी स्थिति को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए गांधीजी यह कहते हैं कि मेरा विरोध यन्त्रों के लिए नहीं है बल्कि यन्त्रों के पीछे जो पागलपन चल रहा है उसके लिए है समय और धन की बचत तो मैं भी चाहता हूँ और यह किसी खास वर्ग के लिए नहीं सारी मानव जाति की होनी चाहिए। यन्त्रों के पीछे जो प्रेरक कारण है वह श्रम की बचत नहीं बल्कि धन का लोग है आज की इस चालू अर्थव्यवस्था के खिलाफ मैं अपनी तमाम ताकत लगाकर युद्ध चला रहा हूँ मेरा उद्देश्य तमाम यन्त्रों का नाश करने का नहीं बल्कि उनकी हद बांधने का है। 5

गांधी जी इसलिए यह स्पष्ट करना चाह रहे थे कि इस प्रौद्योगिकी के बारे में लगातार सावधान रहना जरूरी है और यह आवश्यक हो जाता है कि इसे नियंत्रण में रखा जाए और मनुष्य को केन्द्र में रखा जाए। जब वह यन्त्रों के पीछे पागलपन के आधार पर तथा यन्त्रों के मूल में लोभ की प्रेरणा को आधार बनाकर प्रौद्योगिकी का विरोध कर रहे होते हैं और मानव मानवीय श्रम को उसका उचित स्थान प्रदान करने की बात कह रहे होते हैं। तब इसी प्रद्योगिकीय निर्धारणवाद को नकार देते हैं न केवल प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद को, बल्कि मनुष्य को उपभोक्ता मात्र बना देना, हिंसक उत्पादन व्यवस्था और केन्द्रीकरण को भी अस्वीकार कर रहे होते हैं।

यह दृष्टि हमें इस बात की ओर ले जाती है कि क्या वास्तव में ऐसी कोई प्रौद्योगिकी सम्भव हो सकती है जो अहिंसक समाज की ओर ले जा सके? प्रोफेसर नन्दकिशोर आचार्य (1995) के अनुसार इस बारे में गांधीजी कार्ल मार्क्स से अधिक नैतिक एवं वैज्ञानिक हो जाते हैं। मार्क्स अपनी मानवीय संवेदनाओं के बावजूद भी एक हिंसक एवं केन्द्रीकृत उत्पादन प्रणाली पर साम्यवादी समाज खड़ा करना चाहते थे जबकि गांधीजी ने अपने साध्य एवं साधन एकता के आधार पर एक अहिंसक एवं न्याय पूर्ण तकनीकी के आधार पर एक अहिंसक एवं न्याय पूर्ण समाज को खड़ा करने का प्रस्ताव किया।

गांधीजी इस उदाहरण के जरिए अपनी बात को दृढ़ता से रखते हैं कि वृहद उत्पादन लगातार बढ़ती अनावश्यक जरूरतें वितरण हेतु जटिल व्यवस्था एक शब्द में कहे तो उद्योगवाद विश्व शान्ति के लिए ही खतरनाक है। गांधीजी अपनी प्रौद्योगिकी में मनुष्य तथा मनुष्य प्रकृति के बीच एक अहिंसक सम्बंध की स्थापना का प्रयास करते हैं। ये प्रौद्योगिकी का भी विरोध करते हैं, जो श्रम

को विस्थापित करती है। मैं ऐसी मशीनों का बिल्कुल भी हिमायती नहीं हूँ जो या तो बहुत से लोगों को गरीब बनाकर लोगों को अमीर बनाती हैं या अनेक लोगों के उपयोगी श्रम को अकारण विस्थापित कर देती है! 6

निष्कर्ष—

गांधीजी है यह मानते हैं कि मानवता की सेवा कहीं भी रहकर की जा सकती है। एक भौतिक शरीर होने के कारण हर व्यक्ति की मर्यादा होती है, परन्तु वह अपने पड़ोसी की सेवा करके इस कार्य की शुरुआत कर सकता है। किसी व्यक्ति की सेवा कर मानवता की सेवा करने की अमूर्त दर्शन की तुलना में स्वदेशी सिद्धान्त ज्यादा प्रासंगिक है। स्वदेशी का अर्थ यहां भारतीय न होकर एक ऐसी विकेन्द्रीकृत एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था से हो जाता है जो स्थानीय आवश्यकता, श्रम संसाधन एवं प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित होती है। यहां विकेन्द्रीकरण उत्पादन व उपभोग दोनों का ही है। जो आगे चलकर वितरण एवं स्वामित्व में बदल जाता है। जब गांधी जी चरखा एवं खादी को स्वदेशी अर्थव्यवस्था के प्रतीक रूप में प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो उनके पीछे उनका उद्देश्य शरीर-श्रम की स्थापना एवं विकेन्द्रीकरण ही हो जाता है। चरखे का सन्देश है ! मानव जाति की सेवा कर इस प्रकार जीना कि दूसरों को कष्ट न पहुंचे! 7.

सन्दर्भ सूची—

1. यंग इंडिया 17०2१956, पृष्ठ संख्या: 218.
2. स्पोचेज एंड राइटिंगज ऑफ महात्मा गांधी जी.ए. नटेसन एंड कंपनी मद्रास 1933 पृष्ठ संख्या 336.
3. लेख, चौथा एडिशन, मद्रास 1922 जी.ए. नाथनय महात्मा गांधी के भाषण व पृष्ठ संख्या: 336.
4. हरिजन 25०8६ 1946: पृष्ठ संख्या 281.
5. हिंद स्वराज : पृष्ठ संख्या 14.
6. हरिजन: 22०6६ 1955: पृष्ठ संख्या —146.
7. (यंग इंडिया 17० 9६ 1925, पृष्ठ संख्या 321).

Sh. Takdeer Singh

(8930874165)

Assistant Professor in Sociology

Bandhu Gupta Govt-College

Sector-18, Panipat-(Haryana)



सारांश

19-20वीं सदी का समय साहित्यिक विमर्शों के प्रादुर्भाव का समय था। स्त्री-अस्मिता की स्थापना, स्त्री-जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं, उसकी पीड़ाओं के साथ-साथ अनेक मुद्दों पर विचार करने के लिए एक नवीन विमर्श स्त्री विमर्श के रूप में उभरा। जिसमें पाश्चात्य विचारकों मेरी वॉस्टनक्राफ्ट, जॉन स्टूअर्ट मिल, सार्त्रे, सिमोन द बोउवा इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं भारत में सामंतनी उपदेश तथा शृंखला की कड़ियाँ जैसी पुस्तकों ने घर में बंद स्त्री सहित, स्त्री विमर्श विरोधी लोगों के दिलो-दिमाग के कपाट खोले। इस विमर्श में स्त्रियों के लिए परंपरागत जीवन से भिन्न, पुरुषवादी मानसिकता से अलग अस्तित्व को महत्व दिया गया है। समकालीन रचनाकार मुद्राराक्षस समय सापेक्ष चलने वाले इस आंदोलन को नवीन दिशा प्रदान करते हैं। वे अपने कहानी साहित्य में स्त्री विमर्श को स्वानुभूति तथा सहानुभूति से परे स्त्री-अस्मिता को महत्व देते हैं। मुद्रा नारी विमर्श की उलझनों से अलग पुरुष की दृष्टि में नारी को रखते हैं तो दूसरी ओर स्त्री की मानसिक प्रतिद्वंद्विता का भी उल्लेख करते हैं।

शोध-आलेख

प्रकृति मानव की सहचरी है। जहाँ एक ओर मनुष्य प्रकृति के आँचल में पल कर बड़ा होता है वहीं दूसरी ओर प्रकृति मनुष्य को जीवन देने तथा प्राण-वायु का संचार कर मानवीय जीवन-वृक्ष को सींचती है। अपने पंच तत्व रूपी संसाधन प्रदान कर मानव के सामाजिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास को गति प्रदान करती है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त यह सामाजिक परिवेश व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। व्यक्ति समाज में रहकर स्वयं का विकास करता है तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप समाज-निर्माण की प्रक्रिया में महती भूमिका निभाता है। इस प्रकार मानव तथा समाज का संबंध अन्योन्याश्रित है। मनुष्य जब अपने सामाजिक परिवेश को आधार बनाकर तथा हृदयगत भावों को एक लिपिबद्ध रचना में परिवर्तित कर अपने विचारों को व्याख्यायित करता है जिसे साहित्य की संज्ञा दी गई है। साहित्य मानवीय विचारों एवं कल्पनाओं का एक ऐसा पुंज है जो व्यक्ति के समाज, उसकी प्रकृति, भाषा तथा उसके मानसिक एवं हृदयगत भावों को अभिव्यक्ति प्रदान कर न केवल एक कृति का साक्षी बनता है अपितु समसामयिक अथवा किसी कालखण्ड विशेष की अवधि एवं सामाजिक दशा-दिशा से भी पाठक जगत् को परिचित करवाता है।

समाज में सापेक्षता का सिद्धांत निरंतर गतिमान रहता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वह समाज में पूर्ण स्वतंत्र है या रह सकता है तो ये असंभव है। क्योंकि, सापेक्षता ही सामाजिक संबंधों का मूलाधार है। प्रत्येक व्यक्ति उसी मात्रा में दूसरे पर निर्भर रहता है जिस मात्रा में

दूसरा उसकी अपेक्षा रखता है। सापेक्षता का यही सिद्धांत स्त्री-पुरुष के संबंधों में भी विद्यमान है जिसके द्वारा अपने विकास के लिए वे एक-दूसरे के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। किंतु जब एक व्यक्ति दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता आरोपित करे, उसके अधिकार सीमित कर द्वंद्वत्मक परिवेश को जन्म देता है। भारतीय समाज में नारी की स्थिति कुछ इसी प्रकार की रही है। समाज को आगे बढ़ाने में स्त्री और पुरुष की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी एक के अभाव में न तो दूसरे का विकास संभव है न दूसरे की अनुपस्थिति में पहला ही पूर्ण है। स्त्री-पुरुष समान रूप से समाज-निर्माण की प्रक्रिया में सहायक है। महादेवी वर्मा स्त्री-पुरुष को विद्युत तथा धरा के प्रतीक के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहती हैं— “एक से शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, बड़े-बड़े कार्य किए जा सकते हैं, परंतु पशुबल की उत्पत्ति संभव नहीं। दोंनों के व्यक्तित्व, अपनी पूर्णता में समाज के एक ऐसे रिक्त स्थान को भर देते हैं जिससे विभिन्न सामाजिक संबंधों में सामंजस्य उत्पन्न होकर उन्हें पूर्ण कर देता है।”¹

भारतीय समाज में नारी को पर्याप्त महत्व दिया गया है। कहा भी गया है— ‘यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवताः’ अर्थात् जहाँ नारी पूजनीय है वहाँ देवता वास करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ नारी को आदर, सम्मान तथा अधिकार सहित महत्व प्राप्त है वहीं विकास रूपी देवता प्रसन्नोचित वास करते हैं। किंतु वर्तमान स्थिति इसके ठीक विपरीत है जिसके परिणामस्वरूप आज स्त्री-विमर्श का प्रादुर्भाव के रूप में हमारे सम्मुख है।

स्त्री विमर्श का प्रारंभ मुख्यतः 19वीं तथा 20वीं शताब्दी से माना जाता है। स्त्री विमर्श के मूल में पुरुष के समकक्ष स्त्री के प्रति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक असमानता, शोषण, हिंसा का भाव समाहित है। सन् 1792 में ब्रिटेन की मेरी वॉस्टनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक ‘अ विन्डिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वूमन’ में नारी की स्थिति पर प्रकाश डाला। अपने समाज में स्त्री की हीन दशा से विक्षिप्त ‘जॉन स्टूअर्ट मिल’ ने सन् 1861 में ‘द सब्जेक्शन ऑफ वूमन’ पुस्तक लिखी जिसका प्रकाशन 1869 में किया गया। अपनी पुस्तक में मिल ने नारी की सामाजिक स्थिति के साथ-साथ उसके कारणों पर भी ध्यान केंद्रित किया— “जब हम इन तीन चीजों को साथ रखते हैं— पहला, दो विपरीत सैक्सज में स्वाभाविक आकर्षण, दूसरे, पत्नी की पति पर पूर्णतः निर्भरता, उसकी हर सुविधा व सुख या तो पति का इनाम होता है, या पूरी तरह से उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, और अन्तिम— कि मानव इच्छा की जो मुख्य वस्तुएँ हैं, सम्मान और सामाजिक महत्वाकांक्षा की सभी चीजें, सामान्यतः एक स्त्री पति के जरिए ही पाती है या पाने की कोशिश करती है— इन तीनों चीजों को साथ रखकर

देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्री की शिक्षा व उसके चरित्र निर्माण की प्रक्रिया के केन्द्र में पुरुष के लिए आकर्षक बनने का उद्देश्य न होना एक चमत्कार ही होता। महिलाओं की, बुद्धि पर साधनों के इस महान प्रभाव को हासिल कर, पुरुषों के स्वार्थी स्वभाव ने इसका पूरा-पूरा प्रयोग महिलाओं को अधीन रखने के लिए भी किया।² इस प्रकार मिल ने नारी की समाज में स्थिति तथा उसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए पर्याप्त समाधानों की ओर भी संकेत किया है। वर्ष 1949 में सिमोन द बोउवा की 'द सेकेण्ड सेक्स' प्रकाश में आई जिसने नारीवादी आंदोलन को नवीन ऊर्जा प्रदान की। इसी दौरान भारत में स्त्री विमर्श के दस्तावेज के रूप में 'सामंतनी उपदेश' अस्तित्व में आई जो स्त्री से संबंधित ज्वलंत विषयों को रेखांकित करती है।

छायावाद के चार स्तंभों से एक महादेवी वर्मा ने 1942 से अपनी पुस्तक 'शृंखला की कड़ियां' में स्त्री-पुरुष के मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया तथा स्त्री के प्रति पुरुष की सहानुभूति तथा स्वानुभूति के द्वंद्व के मध्य में भिन्नता को दर्शाते हुए कहा है। "स्त्री का साहित्यिक सहयोग साहित्य के एक आवश्यक अंग की पूर्ति करता है। साहित्य यदि स्त्री के सहयोग से न हो तो उसे आधी मानव-जाति के प्रतिनिधित्व से शून्य समझना चाहिए। पुरुष के द्वारा नारी का चरित्र अधिक आदर्श बन सकता है, परंतु अधिक सत्य नहीं, विकृति के अधिक निकट पहुँच सकता है, परंतु यथार्थ के अधिक समीप नहीं। पुरुष के लिए नारीत्व अनुमान है, परंतु नारी के लिए अनुभव। अतः अपने जीवन का जैसा सजीव चित्र वह हमें दे सकेगी वैसा पुरुष बहुत साधना के उपरांत भी शायद ही दे सके।"³ इस प्रकार नारी-विमर्श या विमर्श नारी के आत्मिक भावों की अभिव्यक्ति स्वानुभूति के साथ-साथ स्वयं हिताय के भाव से परिपूर्ण है।

21वीं सदी में कुछ विशिष्ट रचनाकार हुए हैं जो स्त्री विमर्श को स्वानुभूति तथा सहानुभूति से परे स्त्री-अस्मिता को आधार बनाते हैं। इन्हीं रचनाकारों में से एक आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर मुद्राराक्षस रहे हैं। मुद्राराक्षस नारी विमर्श की उलझनों से परे पुरुष की दृष्टि में नारी को रखते हैं जहाँ वे एक ओर पुरुष के मानसिक दृष्टिकोण को तो बताते हैं तो दूसरी ओर स्त्री की मानसिक प्रतिद्वंद्विता को भी उल्लेखित करते हैं। इसका सशक्त उदाहरण उनकी कहानियाँ हैं। वे एक पुरुष होकर पुरुष के मन में व्याप्त नारी के प्रति हीन भावना एवं शोषण का सजीव तथा निष्पक्ष चित्र अंकित करते हैं जोकि किसी पुरुष के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे वे बिना किसी भय या शंका के करते हैं। स्त्री हो या पुरुष, शहरी हो या ग्रामीण, देहाती स्त्री हो या कामकाजी महिला वे सभी को अपने साहित्य में स्थान देते हैं।

व्यक्ति के मनोभाव उसके परिवेश, ज्ञान तथा बौद्धिक क्षेत्र का प्रतिबिम्ब होते हैं। कोई व्यक्ति क्या विचार करता है, उसके विचार समाज के विकास में कितने सहायक हो सकते हैं। ये उसके ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है। एक ग्रामीण व्यक्ति शहरी व्यक्ति से

भिन्न विचार रखता है। उदाहरण के लिए मुद्राराक्षस द्वारा कृत 'रसकही' कहानी को देख सकते हैं जिसमें गांव-घर में अन्य स्त्रियाँ क्या कर रही हैं, उनके निजी जीवन में क्या चल रहा है— ये सब खबरें ग्रामीण स्त्रियों के मध्य बतरस का विषय होती हैं। किंतु जब यही घटना उनके साथ होती है तब उन्हें आप-बीती तथा जग-बीती का अंतर पता चलता है। कहानी 'रसकही' में पदन की बहू के चले जाने के बाद अम्मा की भी यही मनःस्थिति भी समाज सापेक्ष परिवर्तित होती है।

ग्रामीण समाज में उच्चवर्ग तथा निम्नवर्ग के मध्य प्रतिद्वंद्विता सदैव गतिमान रहती है। सामंत, ठाकुर, जमींदार तथा साहूकार आदि समाज के ठेकेदार रहे हैं। अपने से निम्न तबके का खून चूसकर स्वयं को पोषित करना उनका सामाजिक कार्य रहा है। किंतु जब शोषण एवं अत्याचार अपनी हद से परे व्यक्ति के वक्ष एवं मानस पटल को झकझोर कर रख देता है तब प्रतिहिंसा अथवा प्रतिरोध की ज्वालाग्नि का आविर्भाव होता है जो पूरे कुल को विनाश के घाट पहुँचा देता है। इसी जातीय दंश का विश्लेषण मुद्राराक्षस की कहानी 'मल्लावां माई राजा से बदला लेगी' में किया गया है। कहानी की कथावस्तु पुरानी रूढ़िवादी जातीय मान्यता को आधार बनाकर लिखी गई है। इसमें निम्न जाति की बहू-बेटियों को विवाहोपरांत पहली रात उच्चवर्ग के सत्ताधीशों के यहाँ बितानी होती थी। यह परंपरा निम्न वर्ग को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए बनाई गई थी जिसके जरिए सुखासीन समाज उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने तथा उनमें हीन भावना को बनाए रखना चाहता था। किंतु गांव की मल्लावा नामक स्त्री इस परंपरा को तोड़ने में स्वयं की आहुति दे देती है और वह गांव वालों के मध्य माता के रूप में प्रसिद्ध हो जाती है।

भारतीय ग्रामीण समाज के समान शहरी समाज में भी स्त्री का शोषण समान रूप से होता रहा है। मध्यकालीन युग में जहाँ स्त्री अपने घर में ही दासी मात्र थी। आधुनिक युग में भी वह स्वतंत्र नहीं है। घर और बाहर दोनों जगह वह स्वतंत्र स्त्री के नाम पर जिम्मेदारियों का दोहरा बोझ ढो रही है। उसे सुबह दफ्तर जाने से पहले परिवार के लिए भोजन बनाना पड़ता है। दफ्तर में भी दिनभर वह कार्यों में उलझे रहती है और शाम को घर पर अधूरे कार्यों के अलावा भोजन आदि कार्य उसकी राह बटोहते प्रतीत होते हैं। इसलिए कहा भी जाता है— 'स्त्री काम पर से, काम पर लौटती है।' यह दशा आज लगभग सभी कामकाजी महिलाओं की है। किंतु विंडबना यह है कि उसे न तो घर पर सम्मान मिलता है, न ही कार्यालय में। कार्यालय में अधिकारी तथा अन्य सहकर्मी उस पर भूखे भेड़ियों की तरह घात लगाए रहते हैं। इस प्रकार एक स्त्री दोहरे शोषण के साथ-साथ लोगों की विकृत मानसिकता की शिकार है। उनकी प्रमुख कहानियाँ 'नी', 'केंचुल', 'युद्ध' तथा 'खरगोश' इत्यादि आधुनिक नारी के मानसिक पर्यावरण को उकेरती हैं। वहीं 'मातमपुर्सी', 'युद्ध' एवं 'एग्जिमा' कहानियों में

पुरुषों की स्त्री को वस्तु मानने की दूषित प्रवृत्ति का तित्त चित्रण उनकी कहानियों की विशेषता रही है।

सामाजिक मान्यता है कि घर में यदि कोई पुरुष न हो तो घर की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए स्त्री को काम करना पड़ता है। किंतु वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है अब घर का पुरुष ही स्त्री को घर और बाहर के काम करने के लिए विवश करता है। इतना ही नहीं वह स्त्री द्वारा कमाए जाने वाली मेहनत की कमाई को उससे छीनकर जुए तथा शराब में उड़ा देता है। ऐसे में स्त्री की स्थिति शोचनीय हो जाती है। उसकी पूंजी पर पति, पिता या पुत्र आधिपत्य जमा लेते हैं। मुद्राराक्षस की 'नी' कहानी ऐसी ही कई स्त्रियों की कथा कहती है। इसमें वे डेजी, मेरी सिक्किम, रुबी तथा नी आदि पात्रों के माध्यम से 'बार-गर्ल' की स्थिति को रेखांकित करते हैं:- "इसी 'बार' में पहले वह अपने पिता के साथ नाचा करती थी जो गनोरियो मे चल बसाय दो साल से वह अपने भाई के साथ नाचती है जो आजकल एक हिन्दुस्तानी स्कूल मास्टरनी के साथ भाग निकलने की फिराक में रहता है। शायद दो महीने बाद रुबी अपने बेटे के साथ नाचकर काम चलाना शुरू कर देगी।" 4 यहाँ देखा जा सकता है कि पिता भाई और पुत्र स्त्री के सम्मान के रक्षक होते हैं किंतु यहाँ स्त्री की दशा दयनीय है तथा उसे पर अतिरिक्त भार है। इसी प्रकार कहानी की एक अन्य पात्र 'नी' का वर्णन करते हैं जिसका पति चाहता है कि वह उसकी पत्नी बन कर रहे तथा उसके बच्चे को संभाले किंतु घर का खर्च भी वही चलाए। वह पुरुष होने का रौब दिखाता है साथ ही अपने बच्चे को संभालने में उसे कष्ट होता है। वह स्वयं को हीन समझता है- "बिलकुल गलत बात है। मैं गृहसेविका नहीं हूँ। रात को खटोले पर बच्चे की देखभाल के बजाय किसी पलंग पर औरत के साथ बिताने की जरूरत मुझे भी होती है।" 5 उपरोक्त पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि पुरुष पिता तो बनना चाहता परंतु अपने ही बच्चे को पालन-पोषण नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि कोई उसके पुरुषबल का प्रमाण भी रहे, उसका वंश आगे बढ़े परंतु उसके पालन-पोषण के अहम् दायित्व की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है।

'मातमपुर्सी' कहानी घटते मानवीय मूल्यों को उद्घाटित करती है। कहानी में चार मित्र किसी के मातम में जाते हैं जहाँ कायदे से उन्हें शोक प्रकट करना चाहिए। किंतु उनका मन वहाँ न लगकर भोग-वासना में लिप्त है। अतः वे शोक-सभा को बीच में छोड़कर लड़की का प्रबंध करते हैं। यह कहानी घटते मानव-मूल्यों के साथ-साथ यांत्रिक मानव की जड़ मानसिकता को रेखांकित करती है।

'युद्ध' कहानी में मुद्राराक्षस बताते हैं कि जहाँ कहीं भी युद्ध जैसी विषम परिस्थिति जन्म लेती है वहाँ सबसे ज्यादा शोषण का शिकार स्त्री ही होती है। फिर चाहे शोषण अपने देश की सेना करे या शत्रु देश की सेना, फर्क नहीं पड़ता! उनके लिए स्त्री केवल एक संपत्ति है जिसे लूट कर वे तृप्त होना चाहते हैं- "यह लूट का माल है। हम इसे लेंगे ! वे चिल्लाए।" 6 इन पंक्तियों में पुरुष द्वारा स्त्री को

निर्जीव तथा निष्प्राण उपभोग की वस्तु के समान समझने की मानसिकता दृष्टिगोचर होती है। इसी कारण स्त्री को पुरुष से मिलने वाली सहानुभूति भी स्वीकार्य नहीं है- "बलात्कार! लेकिन उन्होंने हमें गोली तो नहीं मारी! बलात्कार तुम नहीं करते... बलात्कार? बोलो, तुमने नहीं किया बलात्कार और इस उजड़े शहर में कौन नहीं करता यह?" 7

'केंचुल', 'खरगोश' तथा 'काक्रोच' कहानी आधुनिक स्वच्छंद स्त्री के साथ स्त्री-पुरुष के द्वंद्वत्मक संबंधों को उठाया गया है। 'खरगोश' कहानी में स्त्री अपने पति से असंतुष्ट है। अपनी इस कहानी में वे पति-पत्नी के बीच अधूरेपन को दर्शाते हैं, जिसके कारण उनके संबंधों में विच्छेद आना स्वाभाविक है। 'काक्रोच' में जहाँ स्त्री के पर-पुरुष से संबंध होने पर स्त्री-पुरुष के मध्य उठते द्वंद्वएवं एकाकीपन को उजागर किया है वहीं स्त्री के गर्भ में पलने वाले बच्चे का पिता कौन है-जैसे गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इसके विपरीत 'केंचुल' कहानी में पुरुष का अपनी पत्नी को आचार्य के पास ले जाना तथा संतान उत्पत्ति के लिए आचार्य द्वारा नियोग करवाना तथा स्त्री का संतान उत्पत्ति से मना करना विभिन्न सामाजिक पक्षों एवं द्वंद्वों को उजागर करता है।

मुद्राराक्षस की कहानियों में आधुनिक नारी का प्रतिरोध भी शामिल है। उनकी कहानियों के नारी पात्र पुरुष की विकृत मानसिकता का प्रतिरोध करती हैं। उदाहरण के लिए 'केंचुल' कहानी को देखा जा सकता है जिसमें स्त्री पर-पुरुष से संबंध में प्राप्त होने वाली संतान से इंकार करती है। दूसरी ओर 'नी' कहानी की मुख्य पात्र नी मनुष्य के पाप-पुण्य की व्याख्या कर तर्कशील ढंग से प्रस्तुत करती है- "पर इत्तफाक से भिखारी को दान देकर पुण्य कमाने वाले और रंडी के पास जाकर पाप करने वाले में मैं फर्क नहीं करना चाहती।" 8 इसी प्रकार युद्ध कहानी की प्रमुख पात्र स्त्री सेना तथा अफसर द्वारा किए जाने वाले शोषण का विरोध करती है, जबकि उसका पति निर्विरोध रूप से उनकी खिदमत में हाजिर होता है।

निष्कर्ष

सारांशतः कहा जा सकता है कि नारी की स्थिति चाहे भारतीय समाज हो या पाश्चात्य, शिक्षित हो या अशिक्षित सभी स्थानों पर दयनीय, पीड़ित एवं शोषित ही रही है। आधुनिक नारी भी स्वतंत्रता के नाम पर घर तथा बाहर के दोहरे चरित्र एवं जिम्मेदारियों से घिर चुकी है अथवा छली जा रही है। वह घर की ग्रहणी की भूमिका निभाते-निभाते गृह-सेविका बन कर रह गयी है। जबकि शिक्षिक कामकाजी महिला अपनी भूमिका का निर्वाह करते-करते मात्र वर्किंग वूमन बन कर रह गई है। इन दोनों ही स्थितियों में वह स्वयं को भूल गई है। यही नारी जीवन की विडंबना है जिसका उत्कृष्ट उदाहरण मुद्राराक्षस की कहानियां हैं। अपनी इन्हीं भूमिकाओं का निर्वाह करने वाली मुद्राजी के नारी पात्र अपने

शोषण, दमन, पीड़ा, सम्मान तथा अस्तित्व को लेकर सचेत दिखाई देते हैं जिसका सशक्त उदाहरण उनके पात्रों में शोषण के प्रति विरोध-प्रतिरोध भी दिखाई देता है। अपने आकाशवाणी में दिए गए एक साक्षात्कार में वे स्वयं कहते हैं- "मेरा समूचा लेखन और चिंतन अन्याय और अत्याचार और गैर-बराबरी के प्रति प्रतिहिंसा का है।"9

संदर्भ सूची

1. महादेवी वर्मा, शृंखला की कड़ियां, लोकभारती प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2006, पृ.-12
2. जॉन स्टूअर्ट मिल, स्त्रियों की पराधीनता, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2016, पृ-47
3. महादेवी वर्मा, शृंखला की कड़ियां, लोकभारती प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2006, पृ.-12
4. मुद्राराक्षस, मेरी कहानियाँ, दिशा प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-1983, पृ-26
5. वही, पृ-29
6. मुद्राराक्षस, शब्द दंश, लिपि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण-1984, पृ-70
7. वही, पृ-27
8. मुद्राराक्षस, मेरी कहानियाँ, मेरी कहानियाँ, दिशा प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-1983, पृ-85
9. साक्षात्कार

चंचल

(शोधार्थी)ए हिंदी विभाग
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
संपर्क-9013033937
पता:- मकान नं.- 263,
गली नं.- 06, ब्लॉक- डी1, हर्ष विहार,
दिल्ली-110093

डॉ० कुलभूषण शर्मा

सहायक आचार्य,
हिंदी विभाग
पंजाब केंद्रीय
विश्वविद्यालयए
घुद्दा, बठिण्डा-151401

सारांश

रेणु को आंचलिक कथा-साहित्य का मर्मज्ञ हस्ताक्षर माना जाए अथवा मानवीय संवेदनाओं, पीड़ाओं, संघर्षों का सशक्त शब्द-शिल्पी माना जाए ? उन्हें प्रगतिशील प्रिवृत्तियों का रचनाकार माना जाए अथवा रोमांटिक कथाकार?? रेणु ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से समाज में एक नई जागृति, एक नई चेतना का मंत्र फूँका। वर्षों से सोई अंधविश्वासों के जात में जकड़ी गरीबी और भुखमरी की थपेड़े खाती, साम्प्रदायिकता और जातिवाद की चक्की में पिसती गांव के अनपढ़-अशिक्षित जनता में चेतना चिंगारी प्रज्वलित की है। रेणु ने अपने कथा साहित्य में उन सभी बुराइयों और कमीनगियों का इस तरह चित्रण किया है कि आम आदमी उनके कुपरिणामों को दिखाते हुए अपनी चेतना को सुदृढ़ कर सके तथा शोषण और अत्याचार के प्रति आवाज उठा सके।

विषय

युगीन परिस्थितियों के साथ-साथ साहित्यिक विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता है। कभी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा गया है तो कभी जन समूह के हृदय का विकास आचार्य शुक्ल ने उसे जनता के चिंतवृत्तियों का प्रतिविम्बित माना है तो प्रेमचंद ने उसे समाज का प्रतिविम्ब माना है। इस प्रकार समाज की तरह साहित्य की धारणा विकासशील है। वैचारिकता से सम्बन्ध कोई एक सामाजिक पक्ष को चाटुकारिता से निरीक्षण कर अपने उद्देश्य को प्रेषित करते हुए दूरदृष्टि रखना कि उस देश की परिवेश व विश्वसाहित्य की समय, युग चेतना, नैतिक मूल्य तथा मानवीय अंतर्विरोध की क्या स्थिति है। यह क्षणिक नहीं होती इसमें युगों की अनुभव भी जुड़े होते हैं जो परंपराओं, मान्यताओं और लोक तत्व के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। साहित्य में वैचारिकता का प्रतिफलन किसी एक विशेष विषय व वर्ग से जुड़ी हुई चिंतन पद्धति और समझ को कहते हैं और इन आधार पर किसी विशेष समय पर वस्तुस्थिति का जो विश्लेषण किया जाता है वही वैचारिकता का आधार बनता है। साहित्यकार युगद्रष्टा होता है वह न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतराष्ट्रीय गतिविधियों पर नजर रखता है। वह जिस सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश में जीता है उसे समझाना और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी कृति में विचारव्यक्त करना, उसके विचारधारा को प्रतिफलित करता है। रचनाकार एक और जहां विचारधारा को जीवन और जगत की बेहतर प्राप्त करने के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में दिखते हैं वहां दूसरी ओर से संघर्षशील जनता से जुड़ने के माध्यम एवं अपनी पक्षधरता निर्धारित करने के रूप में देखते हैं।

जहाँ तक रेणु की वैचारिकता का सम्बन्ध है, हम उसे किसी

एक धारा में नहीं रख सकते। रेणु का रचनाकाल सन १९४२ से लेकर १९७७ तक का काल है। रेणु राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं क्रांतिकारी आंदोलनों में भी जुड़े हुए थे। उस समय समाजवादी, साम्यवादी और गांधीवादी विचारधारा जोरोपर थी। साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी, जमींदारी पा सामंति व्यवस्था का घोर विरोध करती थी। अहिंसा और शांति के बजाय संघर्ष को बल देती थी। परंतु रेणु जी का संकल्प सदैव समाज में समता स्थापित कर मानव निर्धारित वर्ग को समूल नष्ट करना था। रेणु के कथा साहित्य तो मानवीयता की तलाश का रचनात्मक प्रयास है ही। रेणु के समाजवाद के बाद गांधीवाद को अपनाया और मानवतावादी बने। वे कहीं भी किसी एक तत्व का या समूह का प्रचार नहीं करते वरन मानवमूल्यों को स्थापित करना उचित समझते हैं।

डॉ सूर्यप्रसाद दीक्षित के शब्दों में जनता का साहित्य जनता के बीच, जनता द्वारा लिखा जाता है। रेणु ने अपने साहित्य में आजीवन इसीकी पुष्टि की है। अतः यह कहना संकोच नहीं होगा कि रेणु जैसा अंचलजीवी, ग्रामीण व्यवस्था से समर्पित दूसरा कोई जनवादी कथाकार हिंदी में नहीं है। मनुष्य को सामाजिक और समाज को मानवीय बनाना ही रेणु के कथा साहित्य का मूल संवेदना है। जो उनकी वैचारिकता में तत्व के अन्वेषण की अमूल्य धरोहर है।

रेणु जी वस्तुतः अद्भुत किस्सागो थे। कहने की आदत कुछ प्रेमचंद और शरदचंद से मिलती-जुलती प्रतीत होती है। इस तरह उनके लेखन में किस्सागोई अथवा कथावाचन की झलक दिखलाई पड़ती है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में कथा के भीतर कथा और अतीत और वर्तमान को एक दूसरे से जोड़ते हुए एक ऐसे कथा वृत्त का सृजन करते हैं कि वह आँखों देखी घटना प्रतीत होने लगती है।

विद्या सिन्हा ने अपने एक आलेख में लिखा है कि रेणु अद्भुत किस्सागो थे-कुछ हद तक शरद की तरह। रेणु ने किस्सागोई या कथा वाचन के साथ खुलकर प्रयोग किए हैं। अपने उपन्यासों और कहानियों में भी। कथा के भीतर कथा और अतीत के भीतर धड़कते हुए वर्तमान को रेणु बड़ी सहजता से प्रस्तुत करते हैं। कथा वाचन के अनेक स्तरीयता में मौजूद जातीय संभावनाओं का उपयोग रेणु जी ने अपने आशय को व्यक्त करने के लिए किया है।

इसके अलावे रेणु जी की रचनाओं में भारतीय नवजागरण काल में अपनी कारयित्री और भावयित्री प्रतिभा से समाज एवं देश स्तर पर अलख जगानेवाले महापुरुषों की विचारधारा का जुड़ाव भी मिलता है। डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद लिखते हैं, रेणु जी की रचनाओं में वैचारिकता नवजागरण के दूत विवेकानंद, स्वाधीनता आंदोलन के पुरोध महात्मा

गाँधी और भारतीय समाजवाद के प्रकाश पुरुष जयप्रकाश नारायण के चिंतन पर आधारित है। विवेकानंद का अद्वैत समाज चेतना, गाँधीजी की हिंसक संघर्षशीलता और जयप्रकाश जी समाजवादी चेतना ने रेणु जी के वैचारिक व्यक्तित्व को अनुप्राणित किया है।

मनुष्य को मानवतावादी जीवन-दर्शन के केन्द्र में रखकर उसका विश्लेषण करना रेणु जी का लक्ष्य है। रेणु जी गांधीवाद से प्रभावित तो हैं परन्तु समाजवादी आदर्श से आक्रान्त हैं। मैला आंचल और कितने चौराहे जैसे उपन्यासों में गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले पात्रों के क्रिया-कलाप से लेखक के गांधीवादी विचार का आभास मिलता है। मैला आंचल का बावन दास तो गांधीवाद का सच्चा साधक है। वह गांधी के सिद्धांत को हर स्थिति में पालन करता है। गांधीजी की नीति, अनशन, सत्याग्रह, प्रायश्चित आदि बावन दास के जीवन के प्रमुख अंग हैं। वह अन्याय और अनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। कूट, कपट, अन्याय और दुर्नीति में लिप्त कांग्रेसी कर्मकर्ताओं का मुख खोल देता है। अंत में दुर्नीति रोकने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर देता है। लेखक खुद अपने बचपन से ही गांधीजी की नीति और प्रेरणा से प्रभावित थे। इसकी सत्यता उनके शमेरा बचपन शीर्षक लेख से प्राप्त होती है। कितने चौराहे उपन्यास के गांधीजी की अहिंसा नीति और आदर्श को समर्थन करने वाले मनमोहन गांधीजी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए हड़ताल करता है। उसे स्कूल के मैदान में भरी जनता के सामने दंड दिया जाता है। फिर भी उसमें जो उत्साह और नैतिक आदर्श की झलक मिलती है, उससे उसकी गांधी भक्ति और आदर्श का परिचय मिलता है। अररिया कोर्ट के यहाँ लोग गांधीवादी चिंतन और वाणी से प्रभावित हैं। तकली से सूत कातते हैं। अपने हाथ से काते हुए सूत का कपड़ा पहनते हैं। शमैला आंचल में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का हृदय परिवर्तन भी गांधीवादी आदर्श और दर्शन का परिणाम है। तभी तो वह गाँव के लोगों के जीवन में खुशी भरने के लिए प्रत्येक परिवार को पांच बीघे जमीन वापस कर देता है।

परती परिकथा उपन्यास में लेखक ने समाजवाद के जरिये क्रांतिकारी चेतना जगाने की कोशिश की है। जितेन्द्र समाजवादी आदर्श का पोषक है। प्रेमचंद के गोदान और प्रेमाश्रम में भी समाजवाद आया है। गोदान का राय साहब कहता है— मैं इसे स्वीकार करता हूँ, किसी को दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसें और खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती। जिन्हें पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उनके अफसर और नियोजक दस-दस, पाँच-पाँच हजार फटकारें, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। (गोदान, पृ. ४७) परती परिकथा में वर्ग संघर्ष तीव्र और भयंकर है। भूमिहीन किसान वर्ग के लोग बड़े-बड़े किसान जमींदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। समाजवाद के प्रबल पक्षधर यशपाल के दादा कामरेड की तरह इस उपन्यास में शोषण के खिलाफ होने वाला संघर्ष मार्क्सवाद (समाजवाद) को लेकर ही

चलता है।

रेणु जी समसामयिक काल की जीवन धारा से ओत-प्रोत होकर चलने वाले हैं। वे सामाजिक यथार्थ पर जोर देते हैं। उनका स्वर आदर्शवादी और यथार्थवादी व्यंजना में एक जैसा है। मनुष्य को मानवतावादी जीवन दर्शन के केन्द्र में रखकर उसका कल्याण करना चाहते हैं। मैला आंचल का नायक डॉ. प्रशान्त समाज-सेवा का संकल्प लेकर अपना समस्त जीवन कर्तव्यस्त रहता है। जेल से लौटने के बाद वह अपने संकल्प को फिर दोहराता है। ममता के पास पत्र लिखते हुए कहता है. ममता! मैं फिर काम शुरू करूँगा। यहीं इसी गाँव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। गाँव के कुछ प्राणियों के मुरझाये ओठों पर मुस्कराहट लौटा सकूँ, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूँ। इससे लेखक का महान उद्देश्य स्पष्ट होता है कि भारतीय डाक्टर विदेशों में न जाकर भारत के गाँव में सेवा करें जिससे देशवासी स्वस्थ और निरोग जीवन व्यतीत कर सकें। ग्रामवासिनी भारत माता का मैला आंचल स्वच्छ हो सके। रेणु के उपन्यासों में आदर्शवाद की अपेक्षा यथार्थ का अधिक खुरदरा चित्रण है। इनके उपन्यास जीवनगत यथार्थ के चित्रों से पूर्ण हैं। लेखक की दृष्टि ने देहाती जीवन की समस्त कटुता और संगति को सरलता और विकृति को स्वार्थपरता और सामाजिक एक-सूत्रता को संजोया है। भारतीय समाज के संगठन में उनकी यथार्थ परक समाज-निरीक्षण शक्ति का परिचय मिलता है।

स्वतंत्र भारत की बहुउद्देश्यीय योजनाओं का प्रभाव रेणु के उपन्यासों में आता है। सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन को रेणु ने देखा है। सरकार की विविध योजनाओं को कैसे कार्यक्षेत्र में रूप दिया जाता है। तथा इन योजनाओं की प्रभावहीनता का रेखांकन इनके उपन्यासों में हुआ है। परती परिकथा में इसका प्रत्यक्ष रूप प्रस्तुत है। कोसी योजना का काम शुरू होता है। अनपढ़ ग्रामीणजनों की दृष्टि में इस योजना का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। बाद में गाँव वाले प्रगतिशील शिक्षित युवक जितेन्द्र नाथ से योजना का असल उद्देश्य समझकर आशान्वित होते हैं। इस योजना से जनता को भारी लाभ मिलता है। कलक मुक्ति उपन्यास में लेखक ने स्वाध् तीनोत्तर नारी शिक्षा का प्रचार-प्रसार तथा वर्किंग वीमेन्स बोर्ड के द्वारा नारियों की कर्म नियुक्ति योजनाओं के विविध रूप दिखाये हैं।

वैसे स्वातन्त्र्योत्तर काल में शिक्षा का व्यापक प्रसार और प्रभाव दृष्टिगत है। पर शिक्षा के प्रसार के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में एक नयी आत्म-चेतना जाग्रत होती है। ग्रामीणजनों की शिक्षा संबंधी पुरानी धारणा बदल जाती है। गाँव में निरक्षरता विरोधी आंदोलन होता रहा है। गाँव में शिक्षा के प्रति सबके मन में आग्रह है। परती परिकथा में लुत्तो भी शिक्षा का महत्व समझकर ए फ़ैट कैट सेट आन देट मैट की पढ़ाई करता है। मोचीकन्या मलारी विधवा होकर भी गाँव के स्कूल में मिडिल पास कर गर्ल स्कूल में मास्टरनी

बन जाती है। ब्राह्मण युवक सुवंशलाल से शादी कर सरकार की ओर से छात्र वृत्ति पाकर अपनी शिक्षा पूरी कर लेती है। परानपुर गाँव के सभी में आधुनिक शिक्षा के प्रति एक ललक है। इसलिए वहाँ पुस्तकालय, कन्या पाठशाला और अंग्रेजी हाईस्कूल हैं। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव व्यापक स्तर पर दिखाई पड़ता है। वह व्यक्ति को क्रांति-धर्मी व्यक्तित्व प्रदान करती है। रेणु के उपन्यासों के अनेक पात्र प्रगतिशील और शिक्षित हैं। यह आधुनिक शिक्षा का परिणाम है। समाज के कुसंस्कारों, रुढ़ियों, अंध-विश्वासों, संकीर्ण विचारों को हटाने के लिए ये पात्र प्रतिबद्ध हैं। एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करना ही उनका लक्ष्य है। उनमें विश्व-बंध गुत्व और संपूर्ण मानवीय एकता की भावना है। तभी तो ये पात्र समाज-सुधर, सेवा, कर्तव्यनिष्ठा की ओर उन्मुख दिखाई देते हैं। वे सभी प्रायः आधुनिक शिक्षा प्राप्त हैं। परिणाम स्वरूप वे प्राचीन रुढ़ियों के प्रति क्षुब्ध और असहिष्णु हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली और विभिन्न स्तरों पर होनेवाली प्रगतिशीलता तथा उनके विकास के अवरोधक तत्वों को श्रेणु ने व्यापकता से रेखांकित किया है। परन्तु इससे हमारी परंपरा के कुछ सूक्ष्म तंतु छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। यह भी एक त्रासद स्थिति है।

रेणु ने समाज निर्माण में आधुनिक युग में स्त्रियों की सेवा, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा आदि का वर्णन करते हुए नारी जाति के प्रति यथोचित सम्मान दिखाया है। यह उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और गौरव वृद्धि का लक्ष्य और आदर्श है। इतना ही नहीं उन्होंने प्रगतिशील आदर्श समाज के निर्माण में युवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः स्वाधीनोत्तर भारत को शिक्षा और संस्कृति से समृद्ध और गौरवमयी बनाना श्रेणु का प्रमुख लक्ष्य है।

फणीश्वरनाथ रेणु आधुनिक हिंदी कथा साहित्य के एक प्रमुख रचनाकार है। सम्भवतः जितने विशेषण रेणु की लेखनी, सृजनकार्य, रचनाप्रक्रिया, अभिव्यक्ति क्षमता और यथार्थ के प्रतिफलन के लिये प्रयोग किये गए हैं। उतने शायद किसी अन्य समकालीन कथा साहित्य के हस्ताक्षर के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं। कतिपय आलोचक उन्हें सोने की कलम वाला हिरामन कहते हैं तो कोई नया रचनाकार आलोचक उन्हें आंचलिक कथाकार होने का फतवा देता है।

सम्पूर्ण उपन्यासों की भावभूमि

मैला आँचल में कालीचरण तो आजादी के बाद देश के दलित शोषित सर्वहारा वर्ग में उत्पन्न होनेवाली नई अधिकार भावना, वर्ग संघर्ष और साम्यवादी जीवन-दृष्टि का प्रतीक ही बन गया है। ग्रामीण समाज में व्याप्त परम्परागत जाति व्यवस्था की वह नई व्याख्या करते हुए कहता है जात केवल दो है एक गरीब और दूसरी अमीर। आर्थिक आधार पर कायम होने वाली समाजवादी व्यवस्था की रूपरेखा उनके सामने स्पष्ट हो चुकी है। जो जोतेगा वह बोएगा, जो बोएगा वह काटेगा कमानेवाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो। 18 गाँव में मलेरिया सेंटर, चरखा सेंटर, गुलना, जमीन हथिया लेनेवाले जमींदार

खविश्वनाथ का गरीबों को उनकी जमीन लौटा देना, प्रशांत और कमली के विवाह से अन्तर्जातीय विवाह की समाज द्वारा स्वीकृति मिलना आदि प्रगतिशील चेतना का ही तो परिचायक है।

परती परिकथा में प्रगतिशील चेतना का स्वरूप और भी निखरा है। इसमें रेणु ने सदियों से बंजर पड़ी भूमि को वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से उर्वर बनाने का ही प्रयत्न नहीं किया है बल्कि मनुष्यों की मन रूपी बंजर परती को भी शिक्षा की सहायता से उर्वर बनाने का सफल प्रयास किया है। परती परिकथा में जहाँ एक और लैंड सर्वे, चकबंदी आदि के कारण गांव को अलग-अलग इकाइयों में टूटते बिखरते दिखाया गया है, वही दूसरी ओर परानपुर के नव-निर्माण के पीछे काम करने वाली प्रगतिशील चेतना तथा नई मानसिकता का भी विस्तृत वर्णन हुआ है।

कलंक मुक्ति एक ऐसी नारी की कहानी है जो देशसेवा रूपी तपस्या को अपना ध्येय मानकर अपने को समर्पित करती चलती है। वही दीर्घतपा कुमारी बेला गुप्ता देश की आजादी के नाम पर सब कुछ सह लेती है। अपना सर्वस्व बलिदान करने के बाद स्वतंत्र भारत में अपने कार्य में पद-पद पर अनेक संकट, बाधा-विघ्नों का सामना करती है। भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अन्याय और कुसंस्कार आदि के दिनों-दिन की वृद्धि उसे विचलित और चिंतित करती है। उसने मन में स्वतंत्र भारत की जो कल्पना रखी थी और जिसके लिए हजारों देशसेवियों ने खून बहाया था, ये सब व्यर्थ हो गया है। स्वातन्त्र्योत्तर भारत की ऐसी दुर्गति देखकर न उससे वह आंखें मूँद लेती न भाग चली जाती। उसकी स्थिति न ययौ न तस्थौ की है। वहीं बेला गुप्ता बाँकीपूर वीमेन्स हॉस्टल की प्रबंधक बनती है। इतना ही नहीं वह इससे जुड़ी अन्य संस्थाओं जैसे मेटरनिटी सेंटर, शिल्प केन्द्र और मिल्क सेंटर की केयर टेकर भी बनती हैं। इन सारी संस्थाओं की देखभाल वह बडी ईमानदारी से करती है। परन्तु मिसेज आनन्द जैसी गिरी हुई नारी के काले कारनामों का शिकार बनकर जेल जीवन व्यतीत करती है। फिर भी बेला इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। वह राजनीतिक दाव-पेंच तथा झूठ आरोपों को चुपचाप स्वीकार कर लेती। समाज के प्रतिष्ठित पूंजीपतियों सरकारी कर्मचारियों या मिसेज आनन्द जैसी दुर्नीतिग्रस्त नारी की पोल नहीं खोलती है। वह ऐसी दीर्घतपा नारी है जिसका संपूर्ण जीवन संघर्षमय और दुःखपूर्ण है। यह संघर्ष उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देशवासियों के लिए है।

जुलूस रेणु का चौथा उपन्यास है। इस उपन्यास में स्वातन्त्र्योत्तर भारत की चरम दुर्गति का सजीव चित्र है। स्वतन्त्रता के बाद सांप्रदायिक भेद-भाव, जातिवाद, प्रांतीयता तथा संकीर्णता आदि से ग्रस्त लोगों से कलुषित समाज दिनों-दिन बुरी दशा प्राप्त करता है। पूंजीपतियों का शोषण और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लोक-संस्कृति और लोक-जीवन की अधोगति हो रही है। उपन्यास की उदात्त चरित्र वाली नायिका पवित्रा, प्रेम और

सहानुभूति के द्वारा संपूर्ण जन-मानस को प्रभावित करके जाति-पाँति, ऊँच-नीच, भेद-भाव, सांप्रदायिकता और प्रांतीयता जैसी संकुचित भावना को हटाकर सामाजिक स्तर पर शुद्ध मानवता को प्रतिष्ठित कर देती है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में अपनी तटस्थतावाली मनः स्थिति को प्रकाशित करते हुए लिखा है, षपछले वर्षों से मैं एक अदभुत भ्रम में पड़ा हुआ हूँ। दिन-रात सोते-बैठते, खाते-पीते मुझे लगता है कि एक विशाल जुलूस के साथ चल रहा हूँ। अविराम। यह जुलूस कहाँ जा रहा है, ये लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चाहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। इस महा-कोलाहल में अपने मुँह से निकला हुआ नारा, मुझे नहीं सुनाई पड़ता। चारों ओर एक बंवडर चल रहा है, धूल का। इस भीड़ से निकलकर राजपथ के किनारे सुसज्जित बॉलकनी में खड़ा होकर जुलूस देखने की चेष्टा की है। किन्तु इससे अलग होने का सामर्थ्य मुझमें नहीं। इस जुलूस में चलने वाले नर-नारियों से अपने आस-पास के लोगों से मेरा परिचय नहीं। लेकिन उनकी माया... ममता...मैं छिटककर अलग नहीं हो सकता। (जुलूस, भूमिका)।

कितने चौराहे रेणु का पाँचवाँ उपन्यास है। यह एक मर्मस्पर्शी लघु उपन्यास है। अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए शहीद होनेवाले किशोरों की अमर कहानी इस उपन्यास की मुख्य कथा है। गांधीजी की सत्य, सेवा एवं अहिंसा आदि से प्रभावित तथा १९४२ में उनके आह्वान पर देशभक्तों का बलिदान और भगतसिंह तथा उनके उग्र क्रांतिकारी देशभक्त साथियों के आत्मोत्सर्ग से लेकर १९६५ के पाकिस्तानी आक्रमण तक की घटनाओं पर यह उपन्यास लिखा हुआ है। रेणु ने यह उपन्यास किशोर शहीद धरुव कुंड को समर्पित किया है, जिसने देश का झंडा फहराते समय गोली खाकर जान दे दी।

अररिया कोर्ट का अंचल ही उपन्यास का केन्द्रस्थल है। उपन्यास के सभी प्रमुख पात्र किशोरावस्था के हैं। उपन्यास का प्रमुख पात्र मनमोहन है। वह देहात का होनहार बालक है। देशसेवा ही उसके जीवन का परमधेय है। किशोरवस्था से जीवन के अंत तक वह देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करता जाता है। उसके जीवन में कई विकल्प आने पर भी वह दाहिने या बायें मुड़े बिना अनेक चौराहों को लॉघ कर अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंच जाता है। इस मुख्य कथा के साथ प्रियोदा, कृत्यानन्द, आशर्फी, भोला और तपु जैसे पाँच क्रांतिकारियों का निधन, हाफीज को आग में जिन्दा जला देना, सूर्य नारायण के हिन्दू-मुस्लिम दंगे में मारा जाना आदि मार्मिक कथाएँ भी उपन्यास को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। लेखक ने बड़ी आत्मीयता से इन किशोरों की बलिदान गाथा को इस उपन्यास में मार्मिकता से उभारा है। वास्तव में यह उपन्यास देशसेवा और त्याग का सफल रूपायन है।

पल्टू बाबू रोडर उपन्यास का कथा सूत्र अमलेन्दु राय (लडू बाबू) की कोठी फल बागान पर आधारित है। अमलेन्दु बाबू बिहार के पूर्णिया जिले के बैरगाछी कस्बे में बुनियादी परंपरा वाले राय परिवार

के हैं। माँ बाप, दो भाई और भाभियों की मृत्यु के बाद घर का संपूर्ण बोझ उस पर ही है। बड़े भाई विमलेन्दु की बीस साल वाली कन्या बिजली और मँझले भाई निर्मलेन्दु की पन्द्रह साल की कन्या छवि भी उसके साथ रहती हैं। राय परिवार के साथ पल्टू सिंह नामक एक व्यक्ति का संबंध जुड़ा है। अमलेन्दु बाबू के पिताजी ने उसे सभ्य समाज में प्रतिष्ठित किया था। कमल बाबू के समय से ही पल्टू बाबू के प्रति उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की गहरी अनुरक्ति है उसका फायदा पल्टू बाबू उठाते हैं। यहाँ तक कि पल्टू सिंह इस परिवार के सदस्यों से अपनी काम वासना भी पूरा करता है। पल्टू बाबू के लिए प्रेम सिर्फ सेक्स है, नारी केवल भोग्या उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, काम वासना की पूर्ति का साधन पैसा है। वहाँ के सब के सब आदमी उनकी मुट्टी में हैं।

निष्कर्ष:-

राय परिवार की कन्या बिजली और कुन्तला के प्रति अनेक व्यक्ति आसक्त हैं। काम वासना की पूर्ति के लिए लोग उनसे अनुचित संबंध स्थापित करते हैं। बिजली के जीवन में छागमल का प्रवेश और उससे उसके रूप यौवन के प्रति तिरस्कृत की भावना बिजली के मन में छागमल के प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावना जगाती है। इसी से प्रेरित होकर बिजली जिला कांग्रेस के प्रभावशाली मंत्री मुरली मनोहर से संबंध स्थापित कर राजनीति में अपना स्थान बना लेती है। साथ ही छागमल को अपने से छोटा बनाकर रखती है। इसकी आड़ में वह मुरली की समीपता की कामना चाहती है। दूसरी ओर कस्बे के प्रसिद्ध वकील भोला सहाय की बेटी कुन्तला कोलकता से वकालत पूरी करके लौटती है। इसका प्रेमी हीरालाल महाजन का इकलौता बेटा गोधन है। जिसे वह प्रेम में धोखा देकर कोलकाता भाग जाती है। उसी के कारण गोधन शराबी और डाकू बनता है। इस घटना के उपरान्त कुन्तला के मन में उसके प्रति डर ही लगा रहता है। परन्तु गोधन, पल्टू बाबू के परामर्श के अनुसार सोशलिस्ट पार्टी में नेता बन कर अपना स्थान जमा लेता है। वह राय परिवार की छवि के प्रति आकृष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में कुन्तला पचासी वर्षीय पल्टू बाबू से कचहरी में विवाह कर सभी से बदला लेना चाहती है। परन्तु विवाह की पहली रात में पल्टू बाबू की आकस्मिक मृत्यु उसके जीवन की दुखद परिणामिता बनती है। असफल प्रेम जनित प्रतिशोध परायण दो युवतियों की ये कहानियाँ उपन्यास के प्रमुख पात्र-पात्राओं की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करती हैं।

संदर्भ सूची

1. नेमिचन्द्र जैन – अधूरे साक्षात्कार
2. फणीश्वरनाथ रेणु – मैला आँचल
3. भारत यायावर – रेणु रचनावली, भाग-2-सं
4. भारत यायावर – रेणु रचनावली, भाग-2-सं
5. भारत यायावर – रेणु रचनावली, भाग-2-सं
6. फणीश्वरनाथ रेणु – मैला आँचल

7. फणीश्वरनाथ रेणु – आत्मसाक्षी
8. फणीश्वरनाथ रेणु – परती परिकथा
9. सुरेन्द्र चौधरी – फणीश्वरनाथ रेणु

मणिक पंडा

शोधार्थी—रामादेवी महिला विश्वविद्यालय,
भुवनेश्वर, ओडिशा

मोबइल नः9337741080

पता– at/po&tamamura,dist & soneput

Pin–767023

सारांश

'महाभोज' उपन्यास सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का एक राजनीतिक उपन्यास है। भारतीय समाज में राजनीतिक प्रभाव प्रारंभ से ही रहा है। इस उपन्यास में भारतीय राजनीति का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। लेखिका ने देश में व्याप्त समकालीन भ्रष्टाचार के आधार पर कथानक की परिकल्पना की है, उनकी परिकल्पना कोरी कपोल कल्पित नहीं बल्कि यथार्थ के धरातल पर खड़ी हुई है। उस समय की राजनीति में कौन-कौन से मुद्दे हावी थे, विपक्षी दल के नेता सत्ता को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से हथकण्डों का प्रयोग कर रहे थे, गरीब व दुर्बल वर्गों का किस प्रकार शोषण किया जाता था। इन सभी बातों की गहराई से पड़ताल 'महाभोज' उपन्यास में की गई है। बिसेसर नामक एक दलित युवक की मौत पर नेता लोग, पुलिस विभाग और अखबार तंत्र वाले महाभोज करते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। देश की व्यवस्था सुधारने में सरकार अपने स्वार्थ के चलते नाकामयाब रहती है।

राजनीति का अर्थ है 'राज्य की नीति'। किसी देश या राष्ट्र की सत्ता को सही और सुचारु रूप से चलाने के लिए राजनीति जरूरी है। यह जनता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। वर्तमान में राजनीति निजी स्वार्थों को साधने का एक सरल और सफल साधन बन गई है। आज जनता के विकास के स्थान पर स्वयं का विकास करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। राजनीतिक समस्याओं पर विचार करने से पहले राजनीति शब्द पर विचार करना आवश्यक है।

मानक हिन्दी शब्दकोश के अनुसार, "राजनीतिक 1. वह नीति या पद्धति जिसके अनुसार किसी राज्य का प्रशासन किया जाता या होता है। 2. गुटों वर्गों आदि की पारस्परिक स्पर्धावाली तथा स्वार्थपूर्ण नीति।"¹

अनूपचंद कपूर के अनुसार, "वर्तमान प्रयोग में (Politics) शब्द का सर्वथा भिन्न अर्थ लिया जाता है। अब साधारणतया इसका अर्थ है वह सब वर्तमान राजनीतिक समस्याएँ जो किसी देश या उसकी सरकार के सम्मुख उपस्थित हो।"²

डॉ० रामेश्वर प्रसाद गुप्त के अनुसार, "राजनीति नीति और धर्म से संबंधित राज्य की नीति है। इसका उद्देश्य राज्य में नैतिकता का प्रसार और उसकी रक्षा एवं उत्तम नागरिकों का निर्माण करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है।"³

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है की राजनीति शब्द का अर्थ राज्य, प्रशासन, नीति आदि से लिया जाता है।

राजनीति का संबंध ऐसी व्यवस्था से है, जिसके द्वारा समाज के सभी कार्यों को संचालित किया जाता है। आम जनता को शासन प्रणाली के द्वारा ही सरकारी गतिविधियों का पता चलता है। देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ विशेष नीतियों को निर्धारित किया जाता है, ये नीतियाँ ही राजनीति कहलाती है।

वर्तमान में राजनीति में भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता, अराजकता भरी पड़ी है। राजनेता लोग अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए जनता की समस्याओं व अधिकारों की बात करते हैं। राजनीति से जुड़े लगभग सभी व्यक्ति सक्षम लोगों द्वारा खरीदे वबेचे जाते हैं और आम जनता इसका परिणाम भुगतती है। भ्रष्ट राजनीति युवा शक्ति का दुरुपयोग कर उसे पतन की ओर ले जा रही है। साधारण से साधारण पाठक भी मन्नू भंडारी के नाम से परिचित है। उनके साहित्य में समकालीन सामाजिक और राजनीतिक जीवन मूल्य बहुआयामी रूप में उभरे हैं। महाभोज राजनीतिक विडंबनाओं का खुला दस्तावेज है। इस उपन्यास के द्वारा हमें राजनीति के कई चेहरे देखने को मिलते हैं किस प्रकार नेता लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए हथकण्डे अपनाते हैं, कैसे आम जनता को भ्रमित किया जाता है, पुलिस का विकृत रूप, पत्रकारों की अवसरवादिता आदि सभी बातों की गहन पड़ताल इस उपन्यास में की गई है।

समाज में एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए राजनीति का सहारा लिया जाता है। राजनीति ने व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। आज राजनीति में अनेक विसंगतियाँ आ चुकी हैं। राजनीति में आम जनता के साथ न्याय के स्थान पर अन्याय हो रहा है। राजनेता लोग उच्च अधिकारियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। ये नेता कुछ गुंडों को भी पाले हुए रहते हैं, जिसके कारण वे समाज में खुलेआम गरीब व्यक्तियों पर अत्याचार करते हैं लेकिन कोई भी इन गुंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। 'महाभोज' उपन्यास में जोरावर नामक गुंडा बिसेसर नामक गरीबी युवक की हत्या कर देता है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलती। वह दोषी होते हुए भी खुलेआम घूमता फिरता है। नेता लोग एवं सभी गाँव वालों को पता है कि बिसेसर के हत्या किसने की है, लेकिन गाँव वालों में इतना साहस नहीं है कि उसका नाम अपनी जुबान पर लाए। बिंदा जो बिसेसर का दोस्त है वह एस.पी.सक्सेना साहब के सामने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहता है कि "तहकीकात क्यों कहते हैं, कहीएँ बेवकूफ बना रहे हैं सबको!" और बिंदा का चेहरा और स्वर बुझ- सा गया। याचना भरे स्वर में उसने कहा, 'क्यों झूठमूठ गाँव वालों के साथ मजाक कर

रहे हैं ?दा साहब से लेकर आप तक की शतरंज में आज बिसू की मौत का मोहरा फिट बैठ रहा है; इसलिए इतने जोर-जोर से तहकीकात हो रही है- बड़े प्यार से बुला बुलाकर बयान लिए जा रहे हैं ! पर होना जाना कुछ नहीं है।' फिर एकाएक आवाज को सप्तम स्वर पर ले जाकर चिल्लाया, 'क्या हो गया आप सब लोगों को... कोईईमान धरम नहीं रह गया है किसी का भी... लानत है सब पर !'"

राजनीति में ईमानदार व कुशल नेता नजर नहीं आते। इस भ्रष्ट राजनीति के विविध अंग हैं। राजनीतिक लोग चुनाव के समय जनता के पास जाते हैं और जब वे चुनाव जीत जाते हैं, तो अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं। न्याय व्यवस्था खोखली होती जा रही है। इसलिए आम आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। बिसू के दोस्त बिंदा को पुलिस की मार खानी पड़ती है, "आखिरी इच्छा पूरी करेगा ?ले कर... ले कर !' और पुलिसवालों की मार की रफ्तार और बढ़ जाती है। लेकिन बिंदा का चिल्लाना बंद नहीं होता। आवेश में थरथराता हुआ चीखता है- 'मार डालो, मार डालो। तुमने बिसू को मार डाला, मुझे भी मार डालो, लेकिन देखना बिसू की इच्छा को कोई नहीं मार सकता।'"

समाज में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे समाज में जब भी कोई अप्रिय घटना घटती है, तो पुलिस को पीड़ित की सुरक्षा और अपराधी को सजा दिलवाने का कार्य सौंपा जाता है, लेकिन आज पुलिस भी अपने कर्तव्य से पीछे हटकर अपनी स्वार्थपूर्ति में लगी रहती है। वर्तमान में पुलिस के कारनामों और भ्रष्ट आचरण से सभी भली-भाँति परिचित हैं। पुलिससमाज में नेताओं के आगे पीछे डोलती हुई दिखाई पड़ती है। पुलिस का रवैया नेताओं के साथ चापलूसी और गरीबों के साथ अहंकारपूर्ण का रहता है। जिसका परिणाम यह होता है कि गरीब आदमी उनका विरोध करने में स्वयं को समर्थ नहीं समझते।

'महाभोज' उपन्यास में दा साहब डी.आई.जी. सिन्हा को समझा रहे हैं कि पुलिस वालों को अपना काम निष्पक्ष और तटस्थ होकर करना चाहिए, लेकिन अपना स्वार्थ साधने के लिए वे निर्दोष व्यक्ति बिंदा को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। इसीलिए वे सिन्हा से कह रहे हैं कि "घटना वाले दिन बिंदा का गाँव से अनुपस्थित होना और घटना के बाद उसका अतिरिक्त रूप से आक्रामक रवैया ?संदेह के लिए बहुत गुंजाइश नहीं रह जाती। '... आश्चर्य है, सक्सेना या आपको यह बात सूझी तक नहीं। खैर, एक बार फिर सारे मामले पर नजर डालिए- खुले दिमाग और पैनी नजर से ! मुझे बिसू के हत्यारे को पकड़वाना है... वचन दिया है मैंने गांववालों को और आप पर छोड़ रहा हूँ यह काम...।'"

दा साहब की कही हुई बात सिन्हा को समझ में आ जाती है। सिन्हा जैसे अफसर को पदोन्नतिका प्रलोभन देकर खरीद लिया जाता है और दा साहब जैसे नेता सिन्हा जैसे अफसर की सहायता से

पुलिस प्रशासन में अपनी मनमानी करते हैं। अतः डी.आई.जी. सिन्हा अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु जी-हजुरी करने वाला अधिकारी प्रमाणित होता है।

लेखिका ने 'महाभोज' में 'मशाल' पत्र के संपादक दत्ता बाबू के क्रियाकलापों के जरिए मीडिया के बदलते हुए स्वरूप को उजागर करने का प्रयत्न किया है कि आज मीडिया भी किस प्रकार बिकाऊ हो चुका है। जनता की आवाज समझे जाने वाले समाचार पत्र भी अब नेता की आवाज बने हुए हैं। मुख्यमंत्री दा साहब दत्ता बाबू को भी खरीद लेते हैं और उनसे अपनी मनचाही बात छपवाते हैं। दा साहब दत्ता बाबू को विज्ञापन और अखबारी कागज का डबल कोटा कर देने का प्रलोभन देते हैं। दा साहब के आदेश पर अखबार में खबर छपती है कि "दोस्ती की आड़ में बिसू की हत्या करने वाला बिंदा गिरफ्तार ! फिर बड़े सनसनीखेज और रोचक ढंग से विस्तृत वर्णन दिया गया था कि किस प्रकार नए सिरे से बयान लेने और गहरी छानबीन करने पर कुछ ऐसे विस्मयकारी तथ्य सामने आए जिन्होंने सारी घटना की दिशा हीबदल दी। डी.आई.जी. सिन्हा ने जिस सूझ-बूझ का प्रमाण दिया इस सारे मामले में उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा थी। साथ ही एक छोटे से बॉक्स में बधाई देते हुए यह सूचना भी थी कि डी.आई.जी.के रिक्त स्थान को डी.आई.जी. सिन्हा ने सँभाल लिया है।" मीडिया समाज को मजबूत बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करता है, लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मीडिया संस्थान वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के हाथों बिके हुए हैं।

चुनाव जीतने के लिए नेता लोग नए-नए तरीके अपनाते हैं। वे किसी भी कीमत पर चुनाव को जीतना चाहते हैं। रैलियाँ निकालना, नारेबाजी करना, भाषणबाजी, सरकारी योजनाएं आदि सभी तरीके चुनाव को जीतने के लिए ही किए जाते हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू चुनाव जीतने के लिए रैली के संबंध में कहते हैं कि "अब एक ऐसी रैली करवा दो जैसी इस प्रांत के इतिहास में कभी न हुई हो। देखते रह जाए दा साहब भी। पैसा पानी की तरह भी बहाना पड़े तो कोई चिंता नहीं।" वोट प्राप्त करने के लिए नेता लोग पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं। वे लोगों को पैसे देकर उन्हें अपनी पार्टी का वोट देने के लिए कहते हैं। जनता को तरह-तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वे अपना स्वार्थ साधने लग जाते हैं। ये नेता लोग चुनाव जीतने के लिए अपने ही लोगों द्वारा नारे लगवाते हैं ताकि वोट प्राप्त करने में कुछ सहायता हो सके। सुकुल बाबू चुनाव होने तक बिसू की मौत के प्रसंग को जिंदा रखने का भरसक प्रयास करते हैं। जब वे सरोहा गाँव में भाषण देने के लिए जाते हैं तो वे लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम अन्याय व

अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। तब सुकुल बाबू के आदमी नारे लगाते हुए कहते हैं कि "सुकुल बाबू जिंदाबाद !... हरिजनों के हमदर्द, जिंदाबाद !""⁹ मुख्यमंत्री दा साहब भी चुनाव जीतने के लिए सरोहा गाँव में भाषण देने आते हैं और उनके भाषण में भी इसी प्रकार की नारेबाजी की जाती है।

निष्कर्ष

अतः यह कहा जा सकता है कि 'महाभोज' उपन्यास मन्नू भंडारी की एक सशक्त रचना है। इस उपन्यास में राजनीतिक गतिविधियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। बिसेसर नामक एक युवक की सरोहा गाँव में हत्या कर दी जाती है। यही घटना उपन्यास की अन्य गतिविधियों को गति प्रदान करती है। इस घटना को इसलिए अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि उस समय सरोहा में उपचुनाव होने वाले थे। आज राजनीति चंद नेताओं की कठपुतली बनकर रह गई है। राजनीतिक चरित्रों की मुख्य विडंबना है कि वे अपनी कुर्सी को बचाने हेतु सब कुछ करते हैं फिर चाहे वे सत्ता पक्ष से जुड़े हो या विपक्ष से। 'महाभोज' के दा साहब मुख्यमंत्री हैं और सुकुल बाबू विरोधी पक्ष के नेता। बिसू बिंदा और सक्सेना को सामग्री बनाकर सभी स्वार्थी लोग अपने-अपने ढंग से महाभोज का आयोजन करने में जुट जाते हैं। आज हमारे देश में राजनीति में ईमानदार व कर्मठ व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो जनता के लिए निःस्वार्थ भाव से कार्य करें।

संदर्भसूची

1. (सं.) रामचन्द्र वर्मा, मानक हिन्दी कोश, चौथा खंड, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, संस्करण 1965, पृ०494
2. अनूपचंद कपूर, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत, प्रीमियर पब्लिशिंग कंपनी, दिल्ली, पृ० 4
3. डॉ रामेश्वर प्रसाद गुप्त, वाल्मीकि रामायण में राजनीतिक तत्त्व, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, 1995, पृ०3
4. मन्नू भंडारी, महाभोज, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, इकतालीसवाँ संस्करण 2017, पृ०93
5. वही, पृ०128
6. वही, पृ०116
7. वही, पृ०117
8. वही, पृ० 63
9. वही, पृ० 26

पिंकी देवी

शोधार्थी,

हिंदी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

Email : sarhaya.a@gmail.com

पता : ग्राम किशनपुरा, पोस्ट ऑफिस—विशनपुरा, पिन

कोड—126114, तहसील व जिला जींद,

हरियाणा, मो० : 7015490942

सारांश

हमें अपने जीवन, कला, संस्कृति, साहित्य आदि के क्षेत्र में अनेक ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं जो सदैव अपनी अद्भुत प्रतिभा से हमें प्रभावित करते रहते हैं। ब्रिटेन के साहित्य एवं समाज से जुड़े कथाकार तेजेन्द्र शर्मा एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं। वे कहानीकार, कवि, गजलकार, मंच संचालक, अभिनेता, टी०वी० सीरियल लेखक, संपादक, मंच अभिनेता होने के साथ कथा यू०के० के महासचिव भी हैं। हिन्दी भाषा और साहित्य को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कामन्स एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ले जाने का श्रेय तेजेन्द्र शर्मा को जाता है।

विश्व की समकालीन ज्वलंत समस्याओं को इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उठाया है जिनमें स्त्री, धर्म, मृत्यु, बाजारवाद, विस्थापन, पलायन व भारतीय एवं पाश्चात्य मूल्यों की टकराहट एवं सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण है। अर्थात् वर्तमान संदर्भों में ऐसा कोई भी मुद्दा बाकी नहीं है जिस पर तेजेन्द्र शर्मा का लेखन न सीमाओं में बंधा है और न ही धर्म के आधार पर बाँटा गया है। एक तरफ इंग्लैण्ड की धरती से जुड़े हुए हैं, वहीं साथ-साथ भारतीय भूमि का दर्द आज भी इनके भीतर समाया हुआ है।

तेजेन्द्र शर्मा की अधिकांश कहानियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी एवं भारतीय संस्कृति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इनके लेखन में पाश्चात्य संस्कृति की स्पष्ट झलक भी दिखती है, वहीं भारतीय संस्कृति को भी सिमेटे हुए है।

राजेन्द्र यादव का कहना है कि “प्रवासी साहित्य संस्कृतियों के संगम की खूबसूरत कथायें हैं। हाँलाकि ये संगम न होकर सही मायने में द्वन्द्व हैं।”

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से जब हम आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं, तो उसका एक निश्चित अर्थ है – अंग्रेज एक नई और लगभग अजनबी सभ्यता और संस्कार के साथ हिन्दुस्तान आये थे, यह स्वाभाविक है कि उनके द्वारा हिन्दुस्तान को जो नई आकृति देने की कोशिश की गई उससे एक तरह का तनाव ही उत्पन्न हुआ।

इसी तरह जब भारतीयों ने प्रवास शुरू किया तो उन्हें बिल्कुल भिन्न सभ्यता और संस्कृति का सामना करना पड़ा। पुराने डायस्पोरा में जहाँ वे बहुसंख्या में थे, वे अपने मूल्यों व संस्कृति को बचा पाए। उन्होंने अगली पीढ़ी को भी अपने संस्कार प्रदान किए। वहीं नए डायस्पोरा में ये मुश्किल रहा। वहाँ भारतीयों की संख्या नगण्य थी। उन्हें विदेश में बसने के लिए स्वयं दूसरे देश के संस्कारों में ढलना पड़ा। किन्तु अपने पुराने मूल्यों व रूढ़ियों को वे एकदम त्याग नहीं

पाए। वे दो संस्कृतियों व मूल्यों के बीच संक्रमण काल रहा है। इसका असर भारतीयों के रिश्तों पर भी पड़ा। स्त्री-पुरुष जो एक परिवार की नींव होते हैं उनके जुड़ने की परिस्थितियाँ, तरीकों, कारणों, सब में परिवर्तन आ गया। प्रेम संबंध, वैवाहिक रिश्ते और इन रिश्तों को निभाने की कोशिशों और वजहों में बदलाव हुए। सामंती संस्कार वाले भारतीय परिवार न तो पूरी तरह परम्परावादी रह पाए न ही पूरी तरह आधुनिक।

तेजेन्द्र शर्मा की कहानियों में भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार की सभ्यता का अद्भुत परिचय मिलता है ‘हाथ से फिसलती जमीन’ कहानी एक निम्न जाति के भारतीय लड़के नरेन के विदेश में बसने, यूरोपियन लड़की से शादी करने और फिर उसके साथ घर बसाने की तथा उसके बाद वर्णभेद के कारण उसके जीवन में आये बदलावों, मोड़ों को बताती कहानी है। जिसमें नरेन को भारतीय सभ्यता व जैकी को पश्चिमी सभ्यता के रूप में दिखाया गया है। नरेन विदेशी संस्कृति को पूर्णतः अपना नहीं पाता। वह कैसे विदेश में सब कुछ से भरपूर होकर पैसा, घर, पत्नी, बच्चे, नाती, पोते के बीच रहकर भी अकेला है। नरेन का भारत में जीवन प्रतिभा के बावजूद जाति दंश के कारण प्रभावित रहा। उसके प्रेम प्रसंग में भी उसकी जाति आड़े आती है। वह भारत छोड़ लंदन जा बसता है। रेलवे में नौकरी करते हुए उसकी जैकी से मुलाकात होती है और पहली मुलाकात में प्यार हो जाता है। बच्चे होने के बाद जैकी बच्चों में मसरुफ हो जाती है और नरेन से उसकी दूरियाँ बढ़ जाती है। जैकी बच्चों में भारतीयता नहीं आने देती। नरेन घर में एक ‘साइड-पर्सन’ बनकर रह जाता है। एक यात्रिकता से घर चलता है। नरेन कमाता है, जैकी घर-परिवार सँभालती है। दोनों एक-दूसरे की भूमिकाएँ में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। नरेन को उसके भारत के घर-परिवार की याद सताती है किन्तु वह वापस जा नहीं पाता। विदेश में परिवार में भारतीय और विदेशी संस्कृति के बीच वर्चस्व का द्वंद्वयहाँ केन्द्रीय समस्या है।

‘टेलीफोन लाइन’ कहानी में पश्चिमी संस्कृति के माध्यम से रिश्तों की मुनाफेवाद नीति को उजागर किया गया है। कहानी पूर्णतः पश्चिमी सभ्यता को प्रतीकात्मक ढंग से अभिव्यक्त करती है, “सर क्या आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं?” सर हमारे पास एकदम नई स्क्रीम है। “अंकल जी प्लीज फोन ले लीजिए। मेरा टारगेट नहीं हो पा रहा प्लीज।” किस भाँति मल्टीनेशनल कंपनियों के अनचाहे फोन से व्यक्ति के जीवन को परेशान करके अपने टारगेट्स को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, उसी भाँति तेजेन्द्र शर्मा की कहानी

‘टेलीफोन लाइन’ के तार इन कंपनियों तथा सोफिया दोनों ही पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अवतार सिंह केवल एक उपभोक्ता मात्र बनकर रह जाता है “हाँ अवतार, सुन रही हूँ। तुम मेरी बात सुनो तुम मेरे दोस्त हो तुम मुझसे प्यार भी करते थे तुम आजकल हो भी अकेले भला तुम तुम खुद ही मेरे बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारा घर भी बस जाएगा और मेरी बेटी की जिंदगी भी सैटल हो जाएगी। तुम सुन रहे हो।” तेजेन्द्र शर्मा ने पाश्चात्य संस्कृति में जहाँ एक तरफ कंपनियों के टारगेट को दिया है, वहीं दूसरी तरफ सोफिया का टारगेट “बेटी को सैटल करना।” यहाँ बड़ी खूबासूरती के माध्यम से रिश्तों को लेकर उजागर किया है क्योंकि कहानी को समझने के लिए विविध दृष्टिकोण पाश्चात्य संस्कृति के रंग-रूप में प्रस्तुत होते हैं।

‘कोख का किराया’ कहानी में तेजेन्द्र शर्मा ने भारतीय संस्कृति का सजीव व मार्मिक वर्णन किया है। जिसमें मैनी पात्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति दया, परोपकार, त्याग की भावना को उजागर किया है। जिसमें जया व डेविड एक निरस्तान जोड़ा है। उन्हें अपनी जिंदगी में संतान की कमी महसूस होती रहती है, फिर मैनी ‘सेरोगेट माँ’ बनकर उनकी जिंदगी में बच्चे की कमी को पूरा करती है, वह उस बच्चे का बहुत ध्यान रखती है व जया और डेविड को जन्म देकर दे आती है। जिस कारण उसे अपने ही परिवार के तानों का सामना करना पड़ता है। वह ‘सेरोगेट माँ’ बनकर स्वयं के समस्त अधिकारों से वंचित हो जाती है ‘कितनी जल्दी सब बदल जाता है। एक अनुभूति के लिए मैनी ने क्या-क्या खो दिया। ‘सेरोगेट माँ’ बनने के चक्कर में न वह माँ रह पाई और न ही पत्नी। बस सेरोगेट ही रह गई।’ भारतीय संस्कृति के त्याग को उजागर किया गया है।

‘कैंसर’ कहानी में भारतीय संस्कृति का बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें पति का अपनी पत्नी के प्रति स्नेह, लगाव को दिखाया गया है। शास्त्रों में पत्नी को देवी के रूप में स्वीकार किया गया है उसे घर की लक्ष्मी माना गया है व पति को हमेशा पानी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ‘कैंसर’ कहानी में उसकी पत्नी पूनम को ब्रेस्ट कैंसर है तो वह अपनी पत्नी की वेदना और उसकी ओर बढ़ती हुई मृत्युचाप की आहटों को महसूस करता है। चूंकि अभी पूनम की उम्र मात्र 33 वर्ष ही है तथा दो छोटे बच्चे हैं। “क्या प्यार मनुष्य को इतना कमजोर बना देता है? नहीं संभवतः प्यार के खो जाने का डर उससे कुछ भी करवा सकता है।” फिर पूनम को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसमें एक पति की पत्नी के प्रति निष्ठा को उजागर किया है जो भारतीय संस्कृति का यथार्थ चित्रण है। जिसे तेजेन्द्र शर्मा ने बड़ी खूबासूरती से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है।

‘ओवरफ्लो पार्किंग’ में तेजेन्द्र शर्मा ने मृत्यु की पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारा ध्यान केन्द्रित किया है। “मौत भी एक

महत्वपूर्ण धंधा है यहाँ। हर चीज का पैकेज है। ताबूत की क्वालिटी, फूलों का वाइस, रोल्स रॉयस का मॉडल, पुरोहित का इंतजाम, क्रियाकर्म की अवधि। रेट फिक्स है। न कोई अधिक माँगेगा और न ही कम करेगा। आपकी मर्जी आपको मरना है या नहीं मरना है।”

मृत्यु के साजो-समान का पूरा कारोबार और बाजार है यहाँ। अर्थात् प्रवासी संस्कृति में जीवन मूल्य पर ही नहीं अपितु मृत्यु पर भी बाजारवाद संस्कृति हावी है। तेजेन्द्र शर्मा ने अपनी इस कहानी के माध्यम से यही दर्शाया है कि इंग्लैण्ड जैसे विकसित राष्ट्र में बाजारवाद एवं उसका विस्तार किस भाँति उच्च स्थान पर पहुँच चुका है।

‘अभिषप्त’ कहानी में भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति का मेल दिखाया गया है। रजनीकांत विदेश जाकर बसता है क्योंकि उसे पश्चिमी सभ्यता व चकाचौंध अपनी तरफ आकर्षित करती है। वह अपनी संस्कृति को छोड़ जाता है परन्तु वहाँ जाकर वह संस्कृति और सभ्यता से छल नहीं पाता। वह अपने से तीन साल बड़ी उम्र की स्वच्छंद सोच वाली लड़की निशा से शादी करता है। पर निशा की सारी बातें मानने को विवश है। निशा के पास उसकी बातों को न मानने के तर्क हैं। बेटा होने के बावजूद भी वह उसे भी अपनी तरह अंग्रेजी कायदे सिखाती है। रजनीकांत को हमेशा अपनी संस्कृति और गाँव आते हैं।

‘विदेशी परिवेश’ में वैवाहिक बंधन व्यक्ति की अभिरुचि, इच्छा व दृष्टिकोण के अलग-अलग होने के कारण अप्रासंगिक हो जाते हैं। अपनों से विलग होकर असहनीय पीड़ा को व्यक्ति अंदर ही अंदर महसूस करता है और प्रत्येक स्थिति को नियति मानकर भोगने के लिए अभिशप्त हो जाता है। दोनों अपनी-अपनी संस्कृति में रहकर जीवन बिताते हैं। तेजेन्द्र शर्मा ने अपनी कहानी ‘अंतिम संस्कार का खेल’ में पश्चिमी संस्कृति का नग्न यथार्थता को हम सभी के सम्मुख बहुत ही सरलता एवं सहजता से प्रस्तुत किया है कि आज किसी भी भारतीय नागरिक के लिए यह इतना सरल एवं सहज नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का अंतिम संस्कार भी राजनीति का खेल बनकर रह जाये। “नरेन इस बात को नहीं मानता था कि ब्रिटेन में रंगभेद की नीति आज भी सक्रिय है। न जाने क्यों इतने वर्षों के बाद भी नरेन गोरे अधिकारियों की सोच को ठीक से समझ नहीं पाया है।”

युवा पीढ़ी को अपनी कहानी के माध्यम से यही संदेश देते हैं कि पश्चिमी संस्कृति एवं सभ्यता में स्वयं को सलंगन करना इतना सरल नहीं है जितना कि आज की युवा पीढ़ी वर्ग सोचता है।

निष्कर्ष :-

रूप में कहा जा सकता है कि तेजेन्द्र शर्मा ने अपनी कहानियों में भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति के समन्वय के

साथ-साथ समस्याओं को भी उजागर किया है। इन्होंने अपनी कहानियों में दोनों ही संस्कृति का सुंदर समन्वय दिखाया गया है। पश्चिमी सभ्यता के दुःप्रभाव से टूटते मानवीय मूल्य, भारतीयों का पश्चिमी परिवेश को आत्मसात् न कर पाना आदि को दर्शाया गया है। फिर भी वह दोनों संस्कृतियों को साथ लेकर चले हैं। अपनी कहानियों में नवीन धरातलों को छूकर अपने लेखन को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. बृजनारायण शर्मा, हरि भटनागर, संपादक, तेजेन्द्र शर्मा : वक्त के आइने में, 2004, भोपाल
2. धीरेन्द्र अस्थाना, बेघर आँखे।
3. तेजेन्द्र शर्मा, नयी जमीन, नया का आकाश (समग्र कहानियाँ-2), टेलीफोन लाइन, पृष्ठ 356
4. पूर्वोक्त, पृष्ठ 368
5. तेजेन्द्र शर्मा, अंतिम संस्कार का खेल, पृष्ठ 3
6. तेजेन्द्र शर्मा, कैँसर, पृष्ठ 46
7. तेजेन्द्र शर्मा, कोख का किराया, पृष्ठ 49
8. शम्भू गुप्त (अक्टूबर 2012), 'कहानी में बार-बार इधर से उधर और उधर से इधर होता समय, www.rechnakar.org से पुनप्राप्त।
9. तेजेन्द्र शर्मा, अभिशप्त, पृष्ठ 325
10. हाथ से फिसलती जमग्नि, पृष्ठ 105
11. तेजेन्द्र शर्मा, देह की कीमत, पृष्ठ 14

अंजली,

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, बाबा मस्तनाथ
विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर,
रोहतक



सारांश

इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर खड़ा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने में इस कदर उलझा हुआ है कि वह अपने मन की आवाज सुनने के बजाय भीड़ के शोर में स्वयं को विस्मृत करता जा रहा है। दूसरों की पीड़ा उसे दिखाई-सुनाई नहीं पड़ती। संवेदनहीन बनकर वह आत्मकेंद्रित हो चुका है। मनुष्य की यह अवस्था न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक है। इस आत्मकेन्द्रित मनुष्य को साहित्य संस्कारित करती रही है। विशेष रूप से कथा साहित्य में इस मनुष्य को लक्ष्य किया गया है। वर्तमान समय के कई कहानीकार अपनी-अपनी कहानियों में इन संवेदना शून्य स्थितियों को उजागर कर रहे हैं। विजय संदेश भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में इस संवेदना शून्य और आत्मकेंद्रित मनुष्य को निशाना बनाया है। वे जनजीवन में समाहित संवेदनाओं को उजागर करने में सिद्धहस्त हैं। उनकी कहानियों में समाज के उन आम पात्रों का चित्रण है जो समाज में व्याप्त संवेदनहीनता के शिकार हैं।

विजय संदेश की कहानियों में ग्रामीण, शहरी, शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री और पुरुष सभी तरह के पात्र हैं जो जीवन के उधेड़बुन में व्यस्त हैं और संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा जगत से जुड़े प्रबुद्धजनों की कथा-व्यथा को वर्णन करने में लेखक ने विशेष रुचि दिखाई है। शैक्षिक परिवेश से जुड़ा स्वार्थी युवा अपने ही वर्ग के लिए त्रासदायक बना हुआ है। परिणामस्वरूप स्वस्थ होते हुए भी वह मानसिक रूप से विकलांगता का शिकार होता जा रहा है। धुप्प अंधेरे में गुम होते युवाओं की दुर्दशा समाज के सामने यक्ष प्रश्न की तरह खड़ी है। इन विसंगतियों और विद्रूपताओं से सचेत करती उनकी कहानियाँ मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने हेतु कृतसंकल्पित हैं। शिल्प की दृष्टि से भी ये कहानियाँ परिपक्व हैं। कहानियों का शिल्प सहज, सरल, अनगढ़ और प्रयासहीन है। कहानियों में एक निश्चित फार्म (रूप) का प्रयोग हुआ है। कहानियों में यात्रा वृत्तांत से प्रभावित वर्णनात्मक शैली का आधिक्य है।

विषय प्रवेश –

मनुष्य एक ओर विकास के कई सोपान गढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अपनी क्षुद्रताओं के वशीभूत होकर अमानवीय बनता जा रहा है। जैसे तो वह पृथ्वी को विजित कर दूसरे ग्रहों की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन अपने मन के गहरे गहवर से पराजित हो चुका है। इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर खड़ा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने में इस कदर उलझा हुआ है कि वह

अपने मन की आवाज सुनने के बजाय भीड़ के शोर में स्वयं को विस्मृत करता जा रहा है। दूसरों की पीड़ा उसे दिखाई-सुनाई नहीं पड़ती। संवेदनहीन बनकर वह आत्मकेंद्रित हो चुका है। मनुष्य की यह अवस्था न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक है। इस आत्मकेन्द्रित मनुष्य को साहित्य संस्कारित करती रही है। विशेष रूप से विजय संदेश के कथा साहित्य में इस मनुष्य को लक्ष्य किया गया है।

विजय संदेश ने अपने कथा साहित्य में इसकी आवश्यकता पर बल दिया है, उन्होंने वर्तमान समय में साहित्य और समाज के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभायी है जिससे आम आदमी के मन में भी साहित्य के लिए भरोसा पैदा हुआ है। विजय संदेश ने अपना साहित्य मानव जीवन के उत्थान को ध्यान में रखते हुए लिखा है।

वर्तमान समय के कई कहानीकार अपनी कहानियों में वर्तमान जीवन के संवेदनशून्य स्थितियों को उजागर कर रहे हैं। झारखंड के विजय संदेश का नाम भी इनमें उल्लेखनीय है। इनका एक कहानी संग्रह बेकसूर और अन्य कहानियाँ शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, जिसमें 12 कहानियाँ हैं और पत्र पत्रिकाओं में भी छिट-पुट कई कहानियाँ प्रकाशित हैं। सभी कहानियाँ वर्तमान जीवन का साक्षात्कार कराती हैं। इनकी कहानियों में ग्रामीण, शहरी, शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री और पुरुष सभी तरह के पात्र हैं जो जीवन के उधेड़बुन में व्यस्त हैं और संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा जगत से जुड़े प्रबुद्धजनों की कथा-व्यथा को वर्णन करने में लेखक ने विशेष रुचि दिखाई है। शैक्षिक परिवेश से जुड़ा स्वार्थी युवा अपने ही वर्ग के लिए त्रासदायक बना हुआ है। परिणामस्वरूप स्वस्थ होते हुए भी वह मानसिक रूप से विकलांगता का शिकार होता जा रहा है। धुप्प अंधेरे में गुम होते युवाओं की दुर्दशा समाज के सामने यक्ष प्रश्न की तरह खड़ी है।

विजय संदेश की कहानियों को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

1. सामाजिक विसंगति और आमजन के दुःख-पीड़ा व संघर्षों को व्यक्त करती कहानियाँ
2. शिक्षा जगत से जुड़े प्रबुद्धजनों के कथा-व्यथा को व्यक्त करती कहानियाँ
3. स्त्री जीवन के संघर्ष-सफलता और शिक्षा से सफलता प्राप्त करने वाले लोगों की कहानियाँ

उक्त तीनों वर्गों के कहानियों में लेखक स्वार्थी तत्त्वों का पर्दाफाश करते हैं। शोषकों के चेहरों से मुखौटों को हटाते हैं और

संघर्षों से विजय की कहानियाँ सुनाते हैं। इसके साथ ही इनकी कई कहानियों में विषय वैविध्य के दर्शन होते हैं जिनमें ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, दलित जन के संघर्ष और प्रकृति वर्णन का सजीव चित्रण हुआ है। अपनी कहानियों के उत्स के बारे में बताते हुए वे कहते हैं— “मैं जिस परिवेश में पला—बढ़ा, देखा—सुना उस परिवेश का यथार्थ मेरी कहानियों में आपको मिलेगा। इस संग्रह की लगभग सभी कहानियाँ उसी परिवेश में गुँथी हुई हैं, जिसमें जीवन के ऊहापोह का संघर्ष तो है ही, व्यंग्य—विनोद और मनोदशाओं की रंग—त्वरा भी है। कहानी के पात्र प्रायः गंवई हैं और मेरे आस—पास के हैं। इस संग्रह की कहानियों में राजनीतिक टिप्पणियाँ कम हैं। पर, सामाजिक विसंगतियों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। मैं अनुभव करता रहा हूँ कि वर्तमान व्यवस्था में सामाजिक चेतना थोड़ी कुंद हो गयी है। इसलिए कहानियों में सामाजिक वैषम्यों पर चोट है। कुछ कहानियों में परंपरागत मूल्यों को जीने वाले बुजुर्ग पिता की दयनीय स्थिति है तो कुछ में पढ़े—लिखे आधुनिक जीवन—शैली को जीने वाले युवाओं के यथार्थ अंकित हैं, तो कुछ में प्रायः पारिवारिक संबंधों की रीढ़ मानी जानेवाली स्त्रियों के संघर्ष की कहानी है। वे आधुनिक जीवन—शैली को पसंद करने के बावजूद भारतीय सामाजिक मूल्य, शिक्षा और संस्कार को बचाने की पूरी कोशिश करती हैं। एक—दो कहानियाँ ऐसी भी हैं, जिनमें राष्ट्र के संदर्भ में गंभीर और बेबाक सवाल को तलखी के साथ उठाया गया है।”¹

कहानीकार की सहानुभूति समाज के उन वर्गों के प्रति है जो न केवल आर्थिक दृष्टि से विपन्न हैं, बल्कि जो सामाजिक दृष्टि से भी अपमानित — तिरस्कृत होने को विवश हैं। इसी का यह प्रभाव है कि इन्होंने अपने कथा साहित्य में अधिकांश पात्रों का चयन समाज के निचले वर्गों से ही लिया है। इसे हम उनकी विशेष सामाजिक दृष्टि भी कह सकते हैं व उनकी सामाजिक जागरूकता का प्रमाण भी मान सकते हैं।

समसामयिक जीवन में सामाजिक व नैतिक आदर्शों में बढ़ती हुई अनास्था के कारण सामाजिक मूल्य तेजी से टूट रहे हैं, मानवीय संबंध भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके हैं और आज इसी अनास्था के कारण भाइ—भाई में वह प्यार नहीं, जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार था। माता—पिता, गुरु—शिष्य, पति—पत्नी प्रेमी—प्रेमिका में अब यह आदर्श कहीं दिखाई नहीं देता। यह संबंध इस हद तक दूषित हो गए हैं कि सुधार की अब कोई गुजाइश ही नहीं रह गई है। इसी सामाजिक विघटन के परिणामस्वरूप पारिवारिक सामुदायिक ढाँचे चरमरा कर टूट गए हैं, बिखर गए हैं और यह टूटना अब भी जारी है। व्यक्ति संबंधों के निरंतर विघटन के कारण आज का आदमी न किसी को अपना सका है और न किसी का हो सका है। संदेश जी ने समाज की रूढ़ियों, विसंगतियों, अंधविश्वासों के प्रति

विद्रोह अपनी कहानियों में व्यक्त किया है। उनकी कहानी “ उदास—सूना घर” पारिवारिक व सामाजिक विघटन को लेकर लिखी गई एक सशक्त कहानी है। उनकी कहानियों में हम सामाजिक विघटन को देखते हैं। यह आज हमारे समाज में ज्यों की त्यों बनी हुई है। अपने शाश्वत रूप में आदमी व आदमी के बीच यह बँटवारा उनको नहीं भाता है। इस कहानी के अंश हमें सोचने पर विवश करती है, जैसे — “कभी जिस घर में दिन—रात काम ही काम था। मजदूरों को साँस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मजदूर अनाज की कोठियों में दिन—रात अन्न भरा करते थे। गाय—बैलों की हॉक से पूरा परिसर गुँजता रहता था। जहाँ एक ही परिवार में बूढ़े, वयस्क, स्त्रियाँ, बच्चे सभी होते थे, वही आज उपेक्षित और उदास है। सबकी अलग—अलग दुनिया हो गयी है। जबतक चारों भाइयों की पत्नियाँ जीवित थी, घर की दीवारें सोने—चांदी की तरह दमकती थीं। किंतु, अब संयुक्त परिवार बिखर गया है, दीवारों से चमक गायब है और उसे पुराना कहकर खारिज किया जा चुका है। परिवार के वे सदस्य जो कभी घर के मुखिया कहलाते थे, आज उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश हैं। गाँववाले इस घर में अब शिवेश बाबू के अतिरिक्त कोई और नहीं रहता। शिवेश बाबू की मजबूरी है कि वे घर में अकेले हैं। कहने को दो बेटे और बहुएँ हैं फिर भी अकेलापन है क्योंकि, बेटे—बहू गाँव से करीब पाँच किलोमीटर दूर अलग किराए के मकान में रहते हैं। वृद्ध पिता के साथ कोई नहीं रहना चाहता।”²

भारतीय समाज में पारिवारिक विघटन का प्रभाव इतना गहरा पड़ा है कि जिसने हमें सोचने पर विवश कर दिया है। शहरों के नाभिक परिवार ने स्थिति को और विकराल बना दिया है। कहानीकार ऐसी स्थितियों से हमें सचेत करते हैं। सहानुभूति और संवेदना का भावनात्मक स्पर्श प्रदान करते हैं। इसमें कहानीकार की मानवतावादी दृष्टि स्पष्ट होती है। उन्होंने अपनी कहानियों के विषय में कहा है— “मेरी इन कहानियों के केंद्र में मनुष्य है, मनुष्य की पीड़ा, वेदना और संघर्ष है। कहानियों को पढ़ते या उससे गुजरते हुए आप उसकी पीड़ा को, उसके दर्द और संघर्ष को महसूस कर सकते हैं। कहानियों में मनुष्य—जीवन की कई संवेदनाएँ आकार लेती हुई आगे बढ़ती हैं और मानव—मन की गहराई में उतर कर वे मानवीय सत्य का उद्घाटन करती हुई अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करती हैं। कुछ कहानियाँ सुखांत हैं तो कुछ दुखांत भी हैं, जिसमें कहानी के चरित्र प्रायः जीवनगत समस्याओं और संघर्षों को जीते हुए स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध की मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं।”³

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का मूल सम्प्रेष्य मानवता को माना है। उन्होंने साहित्य की मूल प्रवृत्ति मानवीयता को घोषित किया है। अशोक के फूल की पंक्तियाँ द्विवेदी जी के

मानवीय संवेदना के चितरे होने का प्रतिफलन ही तो है—

“ समूची मनुष्यता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके प्रेम करे, एक समूह दूसरे को दूर रखने की इच्छा न करके पास लाने का प्रयत्न करे कोई किसी का आश्रित न हो, कोई किसी से वंचित समूह न हो। इस महान उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्रणोदित होना चाहिये। ”⁴

इस प्रकार साहित्य में संवेदना आवश्यक है। निश्चित ही संदेश जी का कहानी साहित्य इससे पूर्ण है, क्योंकि वे निर्धन के पक्षधर हैं, शोषित के पक्षधर हैं, सामाजिक विषमता के विष को पी रहे जन के पक्षधर हैं। उनकी साहित्यिक दृष्टि और दूरदर्शिता में दूसरों की वेदना को समझने का सामर्थ्य है। वे एक संवेदनशील कहानीकार हैं।

कहानियों में शिल्प—

डॉ. नगेन्द्र द्वारा सम्पादित हिन्दी साहित्य का इतिहास में अभी के दौर में लिखी जा रही कहानियों के बारे में कहा गया है— “स्पष्ट है कि विगत पच्चीस वर्षों में हिंदी कहानी बहुत समृद्ध हुई है। उसमें वस्तु और शिल्प दोनों के स्तर पर बड़ी विविधता आयी है।”⁵

अतः शिल्प के स्तर पर नवीनता का प्रयोग देखने को मिल रहा है। संदेश जी की कहानियाँ भी इसका अपवाद नहीं। सामान्यता में विशिष्टता को समेटे हुए संदेश जी की कहानियाँ शिल्प की दृष्टि से विशिष्ट हैं। उनकी कहानियों का शिल्प कथ्य के अनुकूल सहज, सरल, अनगढ़ तथा प्रयासहीन है। शिल्प की दृष्टि से उनकी कहानियाँ परिपक्व हैं। कहानियों में एक निश्चित फार्म(रूप) का प्रयोग हुआ है। कहानियों में यात्रावृत्त से प्रभावित वर्णनात्मक शैली का आधिक्य है। इसके साथ ही कहीं-कहीं अन्य शैलियों का भी प्रयोग मिलता है। अपनी कहानियों के इस फार्म (रूप) के बारे में वे लिखते हैं—

“ प्रायः सभी कहानियों में स्थानीय भूगोल, प्रकृति, संस्कृति से लेकर जनजीवन के यथार्थ की सच्चाई गुँथी हुई हैं। इन कहानियों में यात्रा – साहित्य का आशिक स्वाद भी मिल सकता है। इसका कारण यह है कि उनमें अनायास कई क्षेत्रों, जिसमें देश और विदेश दोनों शामिल हैं, उसकी भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक झलक आ गयी है, जिससे कहानियों की परंपरित शैली भले ही बदल गयी है, पर इससे उसका स्वाद और आकर्षण बढ़ गया है। प्रायः सभी कहानियों में लोक विश्वासों पर आधारित कुछ चुटीली और कुछ लोक प्रचलित लोकोक्तियाँ भी यथाप्रसंग शामिल हो गयी हैं। ”⁶

प्रसिद्ध कहानीकार अमरकान्त की मान्यता है कि— “कथा में तो शिल्प होना ही चाहिए, उनमें शैली तथा टेकनीक होनी चाहिए। एक विशेष अन्दाज से कहना चाहिए। ताजगी व नवीनता होनी चाहिए, रूप होना चाहिए। इन चारों चीजों से मिलकर शिल्प का निर्माण होता है। शिल्प ऐसा होना चाहिए जो कथा की स्वभाविक

गतिशीलता में कोई बाधा न पहुँचा जाए या कथा के सौन्दर्य को नष्ट न करें या कथा को काल्पनिक न लगे या अधूरी न लगे।”⁶

इस दृष्टि से संदेश जी की कहानियाँ खरी उतरती हैं। यात्रा वृत्तांतत्मक शैली के कारण सुख का अनुभव होता है। इस विशेष कहानी शैली से कहानियों में कौतूहल व साहित्यिक तरलता आ गयी है।

संदेश जी की कहानियों की भाषा में ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही परिवेश का चित्रण हुआ है। उनका भाषा कोश अत्यन्त समृद्ध है। उनकी सहज और सादगी भरी भाषा तत्सम, तद्भव, देशज, अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के कारण और अधिक आकर्षक बन गई हैं। उनकी कहानियों की भाषा पात्र विशेष की मनःस्थिति के अनुकूल प्रवाहित होती गयी है। उल्लेख्य है कि उनकी भाषा को सहज—सरल बनाने की भूमिका का निर्वाह मुहावरों एवं लोकाक्तियों ने अधिक किया है। प्रकृति चित्रण में चित्रमयी भाषा का प्रयोग हुआ है।

निष्कर्ष—

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कहानीकार विजय संदेश ने भारतीय समाज के मध्य-निचले तबके की विभिन्न समस्याओं, विसंगतियों दिशाहीनता अन्तर्द्वन्द्व, खोखली मानसिकता व आर्थिक विवशताओं को बड़े प्रामाणिक ढंग से अपनी कथा में ध्यान देकर आज के सामाजिक परिवेश से पाठक की गहरी पहचान करवाने की चेष्टा की है। कहानीकार विजय संदेश का अपना भोगा हुआ जीवन निम्न-मध्यवर्गीय परिवार का जीवन था। अतः उन्होंने युवा वर्ग को अन्तर्द्वन्द्व की मनःस्थिति, असफल प्रेम, मुखौटाधारी प्रवृत्ति, खोखली मानसिकता और आर्थिक समस्याओं को जिस प्रामाणिकता एवं सच्चाई के साथ चित्रित किया है, यह आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। सहज और स्वाभाविकता संदेश जी की कथा कृतियों की विशेषताएँ हैं, जो कि सभी रचनाकारों की रचनाओं में देखने को नहीं मिलतीं। इतना ही नहीं सैद्धांतिक आग्रह से परे अनुभव की सच्चाई और उसको सम्प्रेषित करने वाली शिल्प कला उनके कहानी संग्रह में दृष्टिगोचर होती है। वर्तमान भारतीय निम्न मध्यमवर्गीय एवं स्त्री जीवन जिन संकटों, अन्तर्विरोधों व असंगतियों से गुजरा है, उसका आख्यान यहां बड़ी संजीदगी से उपलब्ध है। अपने स्वार्थ से वशीभूत शिक्षा जगत के विद्वान आपस में एक— दूसरे से हलाकान है, जिसको कहानियों में उकेरा गया है। इतना होते हुए भी उनकी कहानियों में निराशा के भाव नहीं हैं। कहानियाँ सकारात्मकता और ऊर्जा से भरे हुए हैं, उनमें सोदेश्यता सर्वत्र है, जो उनकी कहानियों को अप्रतिम बनाता है।

संदर्भ सूची

1. संदेश, विजय, बेकसूर और अन्य कहानियाँ, साहित्यभूमि प्रकाशन

,नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023,पृ.9

2. वही

3.वही

4.श्रीवास, डॉ. दिनेश ,आधुनिक हिन्दी गद्य साहित्य. रुद्र प्रकाशन,
बिलासपुर , प्रथम संस्करण, 2021,पृ.141

5.संदेश विजय, बेकसूर और अन्य कहानियां, साहित्यभूमि प्रकाशन
,नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023,पृ.9

6.लाल, मनोहर , कहानीकार अमरकांत, लायल पब्लिशर ,लखनऊ
,द्वितीय संस्करण 2015, पृ.41

7.नगेन्द्र, डॉ.(स) हिंदी साहित्य का इतिहास, मयूर पेपरबैक्स, नई
दिल्ली, तृतीय संस्करण 2009, पृ.7

डॉ. दिनेश श्रीवास

सहा. प्राध्यापक हिंदी,

शा. इं. वि. पी. जी. महाविद्यालय

कोरबा छत्तीसगढ़,

मो.नं.- 7770899636,

ईमेल-dineshsriwash77@gmail.com

सारांश

21वीं शती के उभरते हुए कथाकारों में डॉ० दिनेश श्रीवास का नाम सबसे आगे है। वे लोकप्रिय कवि हैं, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। माली उनका पहला उपन्यास है, जिसे पाठकों ने हाथों-हाथ लिया है और अबतक उसकी सैकड़ों प्रतियाँ बिक चुकी है। श्री दिनेश श्रीवास जी उच्च कोटि के संवेदनशील रचनाकार हैं, जिसे उन्होंने अपने पहले ही उपन्यास में परिचय दे दिया है। माली उपन्यास के केन्द्र में वर्तमान दौर की सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियाँ हैं। विसंगतियों पर आलोचकीय दृष्टि के साथ-साथ कटु प्रहार भी है। कथा नायक जयेश और नायिका विमला अपनी बुद्धिमत्ता से उन विसंगतियों का सामना करते हुए अनेक संघर्षों के बाद अंततः सफल होते हैं। इस उपन्यास में आद्योपांत फरेब और निष्ठा के बीच द्वन्द्व है और उस द्वन्द्व में संघर्षरत नायक जयेश की जीत होती है।

विषय प्रवेश

डॉ० दिनेश श्रीवास की कृति माली ढहते-छीजते मानव-मूल्यों को केन्द्र में रखकर लिखी गयी व्यंग्य-प्रधान औपन्यासिक रचना है। एक परिचर्चा में इस कृति के वैशिष्ट्य पर टिप्पणी करते हुए प्रख्यात समीक्षक श्री रवीन्द्र तिवारी कहते हैं कि "माली में प्रशासन और मानवीय मूल्यों का निचोड़ है। प्रशासन के भीतर किस तरह से मानवीय-मूल्यों का पतन हो रहा है। प्रशासनिक गलियारों में किस तरह से लोगों का उपयोग किया जाता है। महत्वकांक्षाएँ पूर्ति की भावनाएँ हों या फिर क्रेडिट लेने की होड़- इन सभी को माली उपन्यास में बेहद खूबसूरती से परिभाषित किया गया है और इसे रोचक तरीके से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है।" उपन्यास की कथा एक स्वप्न से शुरु होती है जो अंत होते-होते क्रमशः घोर यथार्थ में परिवर्तित हो गयी है। कथाकार ने बड़े ही नाटकीय ढंग से कथारंभ किया है; गोया वे नाटक का कोई दृश्य प्रस्तुत कर रहे हों, यथा- "कलेक्टर महोदय की कुर्सी ऊँचे मंचनुमा स्थान पर स्थित है, पीछे की दीवारों में महापुरुषों की तस्वीरें हैं, दाएँ तरफ फूलों का गुच्छ रखा है जिसमें गुलाब और गेंदा के फूल गुँथे हैं, पीछे कपड़े का जो पटल बनाया गया है वह किसी सिल्क साड़ी का है, जिस पर गुलाब की कलियाँ चिपकाई गई हैं। जिलाधीश की कुर्सी के सामने कुछ दूरी पर छोटी-छोटी कुर्सियाँ हैं, उसके पहले एक मेज पर फरियादियों की सूची रखी है।" नाटकीय अंदाज में उपन्यास लेखन की यह अद्भुत और नवीन शैली है, जिसे कथाकार ने अपनी कल्पना की कूँची से आकर्षक और रोचक रूप दिया है। इस प्रस्तुति में उन्होंने जिस तकनीक का प्रयोग किया है, वह उपन्यास लेखन के क्षेत्र में पहला है।

उल्लेख्य है कि माली उपन्यास अपने समय और

युग-चेतना से संपृक्त है। इसमें 20वीं शती के उत्तरार्ध और 21वीं शती के पूर्वार्ध के भारत का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत हुआ है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि इस उपन्यास के बहाने उपन्यासकार ने वर्तमान समय की आधी सदी यानी पचास वर्षों के भारतीय राजनीतिक-सामाजिक परिवेश का जीवंत और प्रामाणिक चित्र खींचा है, जिसमें उनके द्वारा राजनीतिक अवसरवादिता, नेता-नौकरशाह गंठजोड़ और भ्रष्टाचार की गहन पड़ताल या छान-बीन की गयी है। लेखक ने संकेत किया है कि आजादी के दस-बीस वर्षों के भीतर ही इस देश की नौकरशाही में बेईमानी और भ्रष्टाचार का घुन उसके नस-नस में इस तरह घुस गया कि देखकर आश्चर्य होता है। देश-हित पीछे छूट गया था और आम आदमी की जरूरतें व उसकी अपेक्षाएँ उनकी कार्य-सूची में कहीं था ही नहीं। नेता से लेकर नौकरशाह तक अकर्मण्य हो गए थे और जो थोड़े-बहुत कर्तव्यनिष्ठ और देश-हित का ध्यान रखने वाले अधिकारी-कर्मचारी थे भी तो उन्हें कई तरह से दंडित, अपमानित और प्रताड़ित किया जाता था। उपन्यास में कथानायक जयेश उनमें से एक है जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के कारण अकर्मण्य नौकरशाहों की आँखों की किरकिरी बना हुआ था। राजनीतिज्ञ और नौकरशाह दोनों मिलकर अपनी राजनीतिक गोटी सँकने और निजी हितों की पूर्ति के लिए जयेश के विरुद्ध षड्यंत्र के वे सारे दाँव-पेंच खेलते हैं, जिसमें फंसकर जयेश उलझता चला जाता है। यहाँ तक कि उसे घर-परिवार से दूर अनजान जगह पर पलायन करना पड़ता है। उपन्यासकार ने कथानायक जयेश के बहाने देश की राजनीतिक व्यवस्था में एक ईमानदार, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के फंसने-फंसाने के दुष्क्र से लेकर प्रशासन और नौकरशाह के घाल-मेल को बड़ी बारीकी से रेखांकित करने का प्रयास किया है।

माली उपन्यास में राजनीतिक ताने-बाने और विसंगतियों पर तीखे प्रहार के साथ भारतीय राजनीति उन दिनों जिस तरह कई तरह की आशंकाओं, उठा-पटक और अनगिन समस्याओं से जूझ रही थी, उसकी भी पड़ताल की गयी है। यह भी कि राजनीतिज्ञ और नौकरशाह किस तरह अवसरवादिता को अपना अधिकार मान बैठे थे, इसका अनुमान भी उपन्यास को पढ़ते हुए होता है। राजनीतिक गलियारे में पार्षद जयलाल मेहता और मंत्री जी के बीच अवसरवादिता का जो धिनौना खेल चल रहा था, जयेश का पलायन उस धिनौने खेल का एक दृष्टांत मात्र है। धिनौने शतरंजी चाल में वे अपने-अपने वर्चस्व के लिए हर तरह की चाल-खुटचाल चल रहे थे। प्रख्यात आलोचक श्री अवधेश चंसौलिया व्यंग्यात्मक लहजे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि 'इस उपन्यास में प्रशासन और राजनीति का खतरनाक जोड़ किस

तरह से साधारण जनता के लिए कष्टकारी हो जाता है तथा न्याय-व्यवस्था तक को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों मिलकर कैसे-कैसे हथकंडे अपनाते हैं और ईमानदार प्रशासक को किस तरह षड्यंत्रपूर्वक फंसाकर उसे अपने अनुकूल बनाने का वे धिनौना प्रयास करते हैं, उसका जीवंत दस्तावेज है।³

माली उपन्यास का एक पहलू इस राष्ट्र-समाज के आम आदमी की मानवीय संवेदनाओं और उनके सरोकारों से जुड़ा हुआ भी है। चूँकि, लेखक स्वयं आम आदमी की तरह आम आदमी के जन-जीवन और उनके सरोकारों से गहरे तक जुड़े हैं, इसलिए उनके इस उपन्यास में आम आदमी की भावनाओं, समस्याओं और संवेदनाओं को प्रखर और मुखर शब्द मिल सका है। इन शब्दों से उन्होंने मध्यवर्गीय चेतना के रूढ़िवादी संस्कारों को बाहर निकालने का प्रयास किया है। इसी से उनकी दृष्टि प्रायः आम आदमी के जीवन की जटिलताओं और संघर्षों पर केन्द्रित है। ऐसा लगता है जैसे उपन्यास की घटनाएँ-परिघटनाएँ उनकी आँखों के सामने ही घटित हुई हैं और वे उसके प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। माली उपन्यास की भूमिका लिखते हुए उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। वे लिखते हैं- "इसके कई पात्र मेरे आस-पास थे। उनको मैंने कागज पर उकेरने का कार्य किया है।"⁴ लेखक की इस स्वीकारोक्ति से प्रतीति होती है कि उपन्यास के पात्र और घटनाएँ भले ही उनके आस-पास के हों, यह भी संभव है कि उनकी आँखों के सामने कुछ घटनाएँ घटित हुई हों, पर देखा जाये तो ऐसी घटनाएँ और ऐसे पात्र आज राष्ट्र के हर कोने में मिलते हैं। जयेश, सोमेन, जैसे पात्र आम आदमी के ही प्रतीक-प्रतिनिधि हैं। जयेश ईमानदार अधिकारी के साथ-साथ कर्मठ और संघर्षशील चरित्र है और उसमें आम आदमी की खूबसूरती और बदसूरती दोनों निहित है। इस खूबसूरती और बदसूरती वाले पात्रों में जयेश के साथ सोमेन भी है। दोनों आत्मकेंद्रित हैं और कभी-कभी तो लगता है जैसे वे अंशतः छोटी मानसिकता और मनोवृत्तिवाले हैं। वे अहं और पुरुषवादी मानसिकता के शिकार हैं। उनके जीवन-मूल्यों में कभी-कभी क्षरित परिवर्तन दिखता है। यह परिवर्तन उनके व्यवहार में, चरित्र में और सोच में है, जो शायद उनमें उनके अपने मनोविज्ञान के कारण है। जयेश और सोमेन के इस मनोविज्ञान को परखने की कोशिश करने पर प्रतीति होती है कि निजी मनोविज्ञान की जटिलताओं ने उनके मानव-मन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सोमेन और जया पति-पत्नी हैं। एक ही छत के नीचे रहते हैं। पर, दोनों में आत्मीयता की नितांत कमी है और आत्मीयता की जगह औपचारिकता ने ले ली है। तनाव में जीते हुए वे स्वयं तक सिमटकर रह गए हैं। सोमेन जया के तनाव और नाराजगी को दूर करने के लिए साथ में घूमने निकलता है। वे दोनों किसी पर्यटन-स्थल पर जाते हैं। दो प्रेमियों या जीवन-साथी के साथ घूमने के लिए यह मुफ़ीद जगह थी। दोनों ने काफी इंजॉय भी किया, किंतु 'इगो' का मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ भी प्रबल हो गया और किसी बात को लेकर फिर से दोनों के बीच तनाव हो गया। लेखक उस घटना का जिक्र करते हुए लिखते

हैं कि "जया ने कुछ नहीं कहा। सोमेन ने जया की तरफ देखा। उसका चेहरा असहज हो चुका था। सोमेन ने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। दोनों बहुत देर तक चुप रहे। फिर, दोनों वापस आने लगे। रास्ते में सोमेन ने कई बार जया से बात करने की कोशिश की, लेकिन जया ने चुप्पी नहीं तोड़ी।"⁵ दूसरी ओर विमला और जयेश हैं। दोनों आदर्श दम्पति हैं। पर, संस्कारों में दोनों भिन्न हैं। विमला में जहाँ भारतीय संस्कार हैं। स्त्रीजन्य भारतीय संस्कारों के कारण ही वह अनेक झंझावातों के बीच स्त्री की अस्मिता को मजबूती से रखने का प्रयास करती है जबकि, जयेश नैतिकता और अनैतिकता के मध्य दोलायमान होता रहता है। उपन्यास की नायिका विमला सुंदर, सुशील और गुणवती है। जयेश की तरह वह भी सरकारी अधिकारी है और अधिकारियों के निजी वैशिष्ट्य के साथ मृदुभाषी है। अपने ससुराल के सभी सदस्यों से प्रेम, आदर और श्रद्धा-भाव रखती है। उसके अवचेतन में ही मानवीय गुण हैं। आचरण में शुचिता और व्यवहार में त्याग विमला की निजी विशेषता है। ये कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जो माली उपन्यास में पात्रों की टकराहट और उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को रेखांकित करते हैं।

निष्कर्ष

माली उपन्यास से हिन्दी उपन्यास साहित्य में श्री दिनेश श्रीवास ने अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है। उपन्यास का शीर्षक माली प्रतीकात्मक है। इस प्रतीकात्मकता की जद में उन्होंने राजनीतिक दुर्भिसंधियों से लेकर सामाजिक विसंगतियों, पारिवारिक अभिसंधियों तथा मानवीय संबंधों के अवमूल्यन पर तीखे-चुभते तीर की तरह तल्ल होकर लिखा है। इसी तरह मध्यवर्गीय आम आदमी की समस्याओं, उनके दुःखों तथा संघर्षों की भी पड़ताल की है। पूरे उपन्यास में राजनीतिक दाँव-पेंच हो या सामाजिक विसंगतियों की कुरुपता-लेखक ने बड़ी बारीकी से उसे बिंबित किया है। रोमांचक कथा की पृष्ठभूमि में वे यह कहने का साहस करते हैं कि वर्तमान दौर में आज की क्षुद्र राजनीति व्यक्ति-व्यक्ति और रिश्तों-रिश्तों तक में घुस चुकी है। वे मानते हैं कि छल-प्रपंच की राजनीति राष्ट्र में हो, समाज में हो या हो घर में, वह कभी हितकर नहीं हो सकती। उसका प्रभाव और परिणाम हमेशा गलत होता है। इसी क्रम में वे सवाल करते हैं कि हमारा माली यानी शासक-प्रशासक कैसा हो ? उसका जवाब भी उन्होंने ही दिया है। पटेल ट्यूटोरियल, बिलासपुर (छ०ग०) के सम्मान समारोह में श्री रवीन्द्र तिवारी से बात-चीत कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि "जिस चमन का माली जितना ईमानदार होगा, वह चमन उतना ही पल्लवित-पुष्पित होगा।"⁶ स्पष्ट है कि माली उपन्यास में लेखक का दृष्टिकोण क्या है ? वे राष्ट्र-समाज रूपी बगिया के लिए कैसा माली चाहते हैं ? उपन्यासकार के दृष्टिकोण को देखते हुए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान दौर के उपन्यासों की कड़ी में यह एक जरूरी और सशक्त उपन्यास है। माली उपन्यास की भाषा-शैली हो या उसकी पठनीयता-आरंभ से अंत

तक एक जैसी बनी हुई है। भाषा सहज, सरल और संप्रेष्य है, पर जहाँ-जहाँ विचार हावी हैं, वहाँ-वहाँ भाषा गंभीर हो गयी है।

संदर्भ-संकेत :

- 1) दैनिक भास्कर, बिलासपुर (छ०ग०) 02 अक्टूबर, 2023
- 2) श्रीवास, दिनेश, माली (उपन्यास) पुस्तकनामा, गाजियाबाद (उ०प्र०), 2023, पृ० 13.
- 3) चंसौलिया, अवधेश, प्रशासन और राजनीति, श्रीराम एक्सप्रेस (सांध्य दैनिक) 18 सितम्बर, 2023 लेखक की कलम से, पृ० 07.
- 4) उपर्युक्त, पृ० 30.
6. बात-चीत, [Youtube.com](https://www.youtube.com) पटेल ट्यूटोरियल, बिलासपुर (छ०ग०) 15 अक्टूबर, 2023

डॉ० विजय कुमार संदेश

हिन्दी विभाग,

मार्खम कॉलेज, हजारीबाग,

झारखण्ड-825301

मो० : 09430193804

Email ID : sandesh.vijay@gmail.com

सारांश

20वीं शती के भारतीय राजनैतिक इतिहास में आचार्य विनोबा भावे एक कर्मठ स्वतंत्रता-सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी दर्शन के अनुयायी के रूप में ख्यात रहे हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के गागोड़े नामक स्थान में 11 सितम्बर 1895 तथा निधन 15 नवम्बर 1982 को वर्धा, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में हुआ था। गांधीजी के पटु-शिष्य होने के कारण उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है। गांधी जी के सत्य, प्रेम और अहिंसा के विचार को उन्होंने हृदय के अंतरतम से स्वीकार किया था। वे मनुष्य के कल्याण और अधिकार के लिए ताउम्र संघर्षरत रहे। राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान को भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा।

विषय प्रवेश

आचार्य विनोबा भावे राष्ट्रपिता गांधी के सच्चे अनुयायी थे। श्री रामगोपाल शर्मा ने लिखा है कि "विनोबा भावे गांधी की परंपरा में आते हैं और गांधीजी की तरह ही एक सच्चे राष्ट्रवादी के रूप में जाने जाते हैं।" गांधीजी से उनकी पहली भेंट जून 1916 में हुई थी और इस भेंट ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे गांधीमय हो गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपना समस्त जीवन उनकी राह पर चलते हुए स्वयं को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1916 में गांधीजी से मिलने के बाद इन्होंने संकल्प लिया के राष्ट्र-सेवा के लिए वे आमरण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और राष्ट्र-सेवा के साथ-साथ मानव-कल्याण के लिए आध्यात्मिक साधना करेंगे। अपने इस संकल्प पर वे आजीवन दृढ़ रहे।

राष्ट्र-साधना और राष्ट्र-विकास के लिए उन्होंने गांधीजी द्वारा चलाये गए सभी आंदोलनों में खुलकर हिस्सा लिया था। इसी से "गांधीजी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनाया था।" किंतु, वे केवल गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी ही नहीं थे प्रत्युत् स्वतंत्रता-संघर्ष के योद्धा और व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक भी थे। यही कारण है कि स्वतंत्रता आंदोलन को वे स्वतंत्रता-यज्ञ कहा करते थे। अंग्रेजी हुकूमत से राष्ट्र की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने गांधीजी के अनुयायी के रूप में अहिंसात्मक प्रतिरोध का स्वर बुलंद किया था। झंडा सत्याग्रह हो या नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन- उन्होंने अहिंसा का दामन कभी नहीं छोड़ा। वे गांधीजी की तरह ही अहिंसा के पुजारी थे। अपने सात दशकीय भारतीय राजनीतिक पारी में उन्होंने सत्य, अहिंसा और समानता के सिद्धांत का सदैव पालन किया। उन्होंने अपना संपूर्ण निजी जीवन गरीबों और दबे-कुचले वंचित-वर्ग के लोगों के लिए समर्पित कर दिया था।

स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी और अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के निमित्त वे कई बार अंग्रेजी हुकूमत के कोप का भाजन बने और जेल भी गए। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण वे वर्ष 1920 से 1942 के बीच कई बार जेल गए। वर्ष 1922 में झंडा सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था। अतः अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध कदम उठाने के आरोप में सीआरपीसी की धारा 109 के तहत गिरफ्तार करके उन्हें नागपुर जेल में डाल दिया था। उल्लेख्य है कि इस धारा में अवारा-गुंडों को गिरफ्तार किया जाता है जबकि, विनोबा एक साधारण आंदोलनकारी थे। इस जेल में उन्हें पत्थर तोड़ने जैसे कठिन काम दिये गए। फिर यहाँ से उन्हें अकोला जेल कुछ महीनों के बाद भेज दिया गया। यह जेल-यात्रा उनके लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि जेल में रहकर ही उन्होंने कुअवसर के बीच सुअवसर खोजने का रास्ता तलाश लिया था। जेल में अधिकांश समय उन्होंने अध्ययन-चिंतन में बिताया। इसी तरह वे वर्ष 1925 में हरिजन सत्याग्रह और 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण जेल गए। वर्ष 1942 में सत्याग्रही के तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस तरह कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही दो दशकों तक सत्याग्रह-आंदोलन आदि के कारण वे समय-समय पर जेल जाते रहे पर अपने लक्ष्य को कभी डिगने नहीं दिया।

स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में अहिंसक हथियार के रूप में खादी और चरखा उनका प्रमुख हथियार था। खादी को तो उन्होंने बगावत का झंडा तक कहा था। स्वतंत्रता की लड़ाई में खादी का महत्व बताते हुए आचार्य विनोबा ने कहा था कि "हमें स्वराज्य इसलिए चाहिए कि हमारी बुद्धि जगे और जड़ता तथा आलस्य हटे। यह शक्ति खादी में है और इसीलिए हम खादी के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। स्वराज्य चाहते हैं तो खादी के बगैर वह संभव नहीं है।" स्पष्ट है कि वे खादी को स्वराज पाने का सबसे असरकारक साधन मानते थे। इसी तरह समाज की आर्थिक उन्नति के लिए भी खादी उनकी दृष्टि में बेहतर संसाधन था। खादी के द्वारा वे एक ओर जहाँ देश की अधिकांश नंग-धड़ंग जनता के शरीर को ढंकना चाहते थे, दूसरी ओर खादी के सहारे उन्हें स्वावलंबी बनाना उनका उद्देश्य था। वे जनता को स्वावलंबी बनाकर उसे अपनी शक्ति के प्रति जागृत करना चाहते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि जनता की आर्थिक समृद्धि के बिना एक अच्छे समाज की परिकल्पना ही बेमानी है। खादी की तरह चरखा स्वावलंबन का उनका प्रिय आधार था। वे उसे श्रम-निष्ठा से भी जोड़कर देखते थे। यह जानी हुई बात है कि जिस

देश की अधिकांश आबादी खेती या कृषि आधारित हो— वह देश आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समझा जाता है। उन्होंने लिखा है कि “हिन्दुस्तान में 75 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं।”⁴ उन्होंने तुलनात्मक तौर पर कहा कि अमेरिका भारत से तीन गुणा बड़ा राष्ट्र है और आबादी भी भारत से कम है। बावजूद इसके वह समृद्ध है। इसका एकमात्र कारण उसकी औद्योगिकी और प्रौद्योगिकी है। भारत की आर्थिकी के संबंध में उनकी यह अवधारणा थी कि चूंकि यह कृषि-प्रधान देश है। अतः “यहाँ के काश्तकारों को और भी धंधें दिये जायें, तभी वे संभल सकेंगे।”⁵ खादी और चरखा को वे लघु उद्योग के रूप में वे ताउम्र देखते रहे।

राष्ट्र-समाज की आर्थिक-समृद्धि के लिए विनोबा ने गांधीजी के मॉडल को अंगीकृत व स्वीकृत किया था। इसके लिए उन्होंने गांधीजी के कुटीर उद्योग और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को सीधे-सीधे अपनाया। इसी तरह सामाजिक-आर्थिक ध्येय की पूर्ति के लिए उन्होंने सर्वोदय के सिद्धांत की अपने ढंग से व्याख्या की थी। विनोबा ने सर्वोदय के बारे में बताया कि सर्वोदय से एक ऐसे जातिविहीन, वर्गविहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना होगी, जिसमें छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, ऊँच-नीच का भेद नहीं होगा। यानी साम्य-समाज की प्रतिस्थापना होगी। डॉ० पुष्पेन्द्र दुबे ने लिखा है कि “विनोबा आर्थिक साम्य के पक्षधर हैं। जबतक देश में आर्थिक साम्य स्थापित नहीं होगा तबतक शांति नहीं होगी।”⁶ विनोबा ने सर्वोदय और भूदान के द्वारा इसे प्रत्यक्ष सिद्ध किया। विनोबा के सर्वोदय की अवधारणा को साम्य-समाजवाद के रूप में गांधीजी के सर्वोदय के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। देश की आजादी के बाद विनोबा भावे ने गांधीजी के इस दर्शन को एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जिसका एकमात्र उद्देश्य आजाद भारत में समतामूलक समाज और व्यवस्था का निर्माण करना था। इसका सीधा संबंध आम आदमी के कल्याण से सम्बद्ध था। यह गरीबों के भौतिक उत्थान के लिए तो था ही, अमीरों के नैतिक उत्थान के लिए भी था। इस तरह सर्वोदय का अर्थ विनोबा जी की दृष्टि में एक आदर्श समाज की प्रतिस्थापना और मानव-मूल्यों के विकास से जुड़ा हुआ था। सर्वोदय वास्तव में उनके मानवतावादी दृष्टिकोण की परिणति थी जिसके संबंध में वे कहा करते थे कि यह समाज की एक ऐसी संरचना होगी जिसमें वर्ग-वर्ण, जाति-नस्ल और धर्म आदि के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अभिप्राय यह कि इस सामाजिक संरचना के भीतर राष्ट्र-समाज के सभी लोग आपस में प्रेम, भाईचारे और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में रहकर राष्ट्र-समाज के विकास में अपना योगदान देंगे। विनोबा भावे का यह मानवतावादी सर्वोदयवाद सामाजिक न्याय का एक प्रारूप भी था, जिसे एक युग-द्रष्टा की तरह उन्होंने आगे बढ़ाया। विनोबा के सामने समूची मानवता के लिए सामाजिक अन्याय उन दिनों यक्ष-प्रश्न की तरह मुँहबाये खड़ा था। इस यक्ष प्रश्न के प्रत्युत्तर के लिए ही उन्होंने सर्वोदय का नारा बुलंद किया था। उल्लेख्य है कि उन्हीं दिनों कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भी मानवता की

रक्षा और मनुष्य के कल्याण के लिए गांधीवाद के समानान्तर खड़ा था। विनोबा साम्यवाद के विचारों से सहमत तो थे, पर उसकी कार्य-शैली से असहमत थे। वे मार्क्स के साम्यवाद और सर्वोदयवाद के संबंध में अपनी अवधारणा के संबंध में कहते हैं कि “सामाजिक और आर्थिक आजादी लाने के लिए दुनिया में कौन-सा शब्द कारगर होगा? इसके लिए एक शब्द है कम्यूनिज्म और दूसरा है सर्वोदय।”⁷ दोनों की तुलना में तर्कसहित वे सर्वोदय का पक्ष लेते हैं और अपना निष्कर्ष देते हैं कि मनुष्य के कल्याण के लिए हमें सर्वोदय का झंडा लेकर मैदान में आना होगा। विनोबा की इस उक्ति से प्रतीति होती है कि विनोबा भावे सर्वोदय की स्थापना में आर्थिक विषमता की खाई के साथ ही सामाजिक विषमता की खाई को भी पाटना चाहते थे।

सर्वोदय के क्रम में ही हम विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। उन्होंने आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए ही भूदान और ग्रामदान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया था। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने लगभग पूरे देश की पद-यात्रा की थी। जीवन भर भूमिहीनों के लिए सामंतों-जमीन्दारों तथा छोटे-बड़े राजाओं से भूमिदान मांगते रहे और भूमिहीनों में जीवन भर बाँटते रहे। उल्लेख्य है कि विनोबा का यह भूदान कार्यक्रम जो देश की आजादी के बाद सन् 1951 में शुरु हुआ था, यह एक स्वैच्छिक भूमि-सुधार कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के तहत विनोबा चाहते थे कि दान में ली गयी भूमि के वितरण में सरकार के कानूनी नियमों का भी प्रावधान हो और सरकार की भी उसमें भागीदारी रहे ताकि भूमिहीनों को दिये गए भूमि में किसी तरह की कोई परेशानी या झंझट बाद में न हो। समय के अंतराल में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम-परिनियम आदि बने। 1951 में शुरु किया गया यह कार्यक्रम अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया और इसी के पेटे से ग्रामदान जैसी योजना का भी जन्म हुआ। यह भूदान का अगला चरण था, जिसे ‘ग्राम उपहार आंदोलन’ भी कहा गया। इस ग्रामदान के माध्यम से विनोबा का उद्देश्य आत्मनिर्भर गाँव बनाना था। आंदोलन को भारत सरकार सहित राज्य सरकारों का समर्थन तो मिला ही जयप्रकाश नारायण जैसे कई समाजवादी नेताओं का भी साथ मिला। आधुनिक विश्व के इतिहास में यह एक अद्वितीय उदाहरण है।

निष्कर्ष

इस छोटी-सी टिप्पणी से उजागर होता है कि समाज के समतलीकरण के लिए विनोबा भावे का यह एक सकारात्मक कदम था। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में इससे काफी सहायता मिली, विशेषकर दलितों-पिछड़ों और आदिवासियों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भूदान आंदोलन 20वीं शती के उत्तरार्ध का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसने विश्व-समुदाय को काफी प्रभावित किया। यह

एक ऐसी परिकल्पना थी, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाये कम है।

संदर्भ संकेत :

1. शर्मा, रामगोपाल, आचार्य विनोबा भावे, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2020, पृ० 07.
2. देशपांडे, निर्मला, विनोबा, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 2017, पृ० 104.
3. भावे, विनोबा, खादी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2013, पृ० 21-22.
4. उपर्युक्त, पृ० 06.
5. भावे, विनोबा, खादी-विचार, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2014, पृ० 69.
6. मेहता, गीता, 21वीं शताब्दी में आचार्य विनोबा भावे की प्रासंगिकता, प्रलेक प्रकाशन, मुंबई, 2022, पृ० 339.
7. विनोबा, सर्वोदय और साम्यवाद, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2011, पृ० 06.

अनिमा तिग्गा,

सहायक प्राध्यापक,

राजनीति विज्ञान विभाग,

देवघर कॉलेज, देवघर, झारखण्ड-814112

मो० : 9102319850

सारांश

प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारक कृषि समाज में कृषि के विकास को प्रभावित करता है जैसे भूमि काश्तकारी, परिचालन जोत का आकार, विखंडन और भूमि स्वामित्व की समस्याएं। सामाजिक व्यवस्था का असर जोत और क्षेत्र व्यवस्थाओं पर और साथ ही बंदोबस्त पैटर्न और खेतों की पहुंच की संबंधित समस्याओं पर भी पड़ता है। जोत के आकार को नियंत्रित करने में विरासत के कानून का प्रभाव कृषि विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा में से एक का मूल कारण है। भूमि विखंडन एक मुद्दा है क्योंकि यह कृषि उत्पादकता को कम करता है और उपलब्ध आर्थिक अवसरों को कम करता है। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आमतौर पर किसान और उसके परिवार के लिए पर्याप्त उत्पादन करता है। अतिरिक्त को बेचने के लिए, यदि कोई हो, तो किसान को उपयुक्त बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा। इस तरह के निवेश पर प्रतिफल आमतौर पर अपर्याप्त होता है और छोटे भू-स्वामित्व वाले किसान को नुकसान भी हो सकता है। कई बार, किसान परिवहन प्रणाली में अक्षमताओं से पीड़ित होते हैं।

शब्दकुंजी : भूमि, विखंडन, भूमि स्वामित्व, समस्याएं, आर्थिक, परिवहन प्रणाली।

प्रस्तावना :

भूमि जोत" या "कृषि जोत" शब्द भारत में किसानों द्वारा धारित कृषि भूमि के औसत आकार को इंगित करता है। भूमि जोत में अधिक से अधिक महिलाएं कृषि भूमि के संचालन और प्रबंधन में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भूमि सुधार, भूमि पुनर्वितरण ने एक केंद्रीय स्थान लिया है। कृषि जोत का अर्थ दो प्रकार से होता है, भूस्वामी की जोत, कृषक की जोत। भूस्वामी की जोत उस आकार से है जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व है। कृषक की जोत भूमि के उस आकार से है जिसको कृषक के द्वारा वास्तव में जोता गया है। भूस्वामी की जोत और कृषक की जोत दोनों एक ही हो सकती हैं। भूस्वामी अपनी समस्त भूमि पर खेती करता है आर्थिक जोत उस विशेष आकार की जोत को इंगित करता है जो किसान परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

मिट्टी की गुणवत्ता और जलवायु की स्थिति और सिंचाई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक जोत का आकार भिन्न होता है। मूल जोत आर्थिक जोत से छोटी होती है और यह किसानों को केवल जीवन निर्वाह प्रदान करती है। भारत में कृषि जोत का आकार काफी छोटा, खंडित और अलाभकारी है। भारत में जोत का औसत आकार बहुत छोटा है। जोत के लगातार उप-विखंडन

और विखंडन के कारण देश में प्रति जोत संचालित औसत क्षेत्र धीरे-धीरे कम हो रहा है। भूमि का विखंडन भारत में व्याप्त है। यह खंडित प्रकृति है। कृषि उत्पादकता के निम्न स्तर की व्याख्या करने में भूमि जोतों की संख्या प्रमुख भूमिका निभा रही है। कृषि विकास में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अलग-अलग स्थानिक पैमाने पर छोटी और अत्याधिक खंडित परिचालन भूमि जोत है। यह परिचालन भूमि जोत कृषि में निर्णय लेने की मूलभूत इकाई है जिसका उद्देश्य किसानों की आजीविका की स्थिति में सुधार करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है।

समस्या का चयन :-

कृषि जोत के लगातार विखंडन के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कृषि जोत का बढ़ता उप-विभाजन और विखंडन कृषि संचालन में आधुनिक पद्धति को अपनाना काफी कठिन हो गया है। नई तकनीक का प्रयोग, उर्वरक का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं के लिए समाधान करना अलाभकारी जोतों में कठिन हो गया है। जोत के उप-विभाजन के कारण बड़ी संख्या में छोटे भूखंडों के बीच सीमा रेखा बनाने के लिए भूमि का एक अच्छा हिस्सा बर्बाद हो गया है। उप-विभाजन के कारण भूखंड इतने छोटे हो जाते हैं कि ऐसी भूमि पर खेती करना काफी कठिन है। कृषि जोत का विखंडन किसानों के लिए कृषि संचालन को सही ढंग से चलाने में कठिनाई पैदा करता है।

छोटे और खंडित खेत अकसर सीमा विवादों से घिरे रहते हैं। सीमाओं पर इन सभी झगड़ों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमेबाजी की मात्रा बढ़ जाती है। जोत के निरंतर उप-विभाजन के कारण भूमि का आकार इतना छोटा हो गया है कि किसान खेती की नई तकनीकों को भी नहीं अपना सकता है। जोत का छोटा आकार किसान के परिवार के सभी सदस्यों को नौकरी प्रदान नहीं कर पाता है जिससे व्यवसायों के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी उत्पन्न होने लगी है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

- परिचालन भूमि जोत के स्थानिक वितरण पैटर्न को समझना।
- विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच परिचालन भूमि जोत के वितरण, पैटर्न और भूमि विखंडन के स्तर की जांच करना।
- किसानों को उपलब्ध व्यापक सेवाओं के स्तर की जांच करने के लिए।
- खेतों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक कार्य योजना तैयार करना।

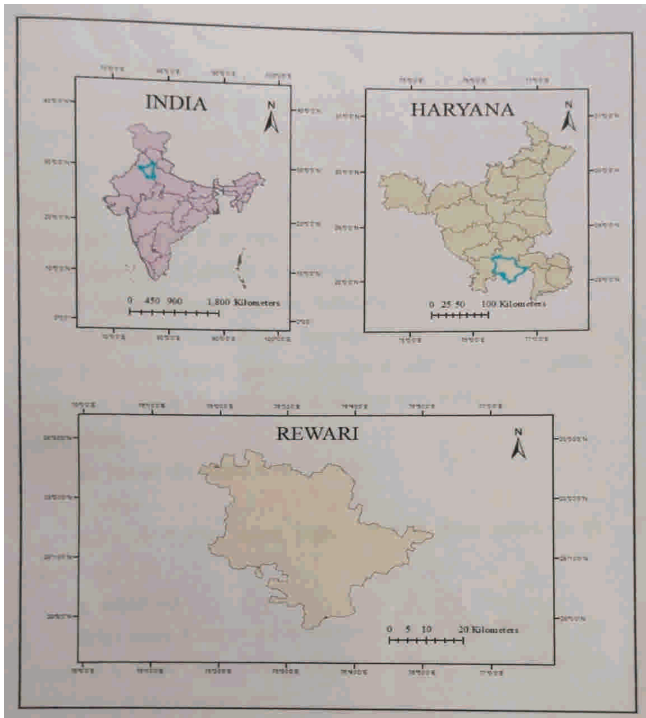
अध्ययन क्षेत्र :-

रेवाड़ी जिला भारत के हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से एक है। इसे

1 नवम्बर 1989 को हरियाणा सरकार द्वारा गुडगांव जिले से अलग किया गया था। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय रेवाड़ी शहर है। जो जिले का सबसे बड़ा शहर भी है। मध्ययुगीन काल में, यह एक महत्वपूर्ण बाजार शहर था। यह दक्षिणी हरियाणा में स्थित है। 2011 तक यह पंचकूला के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है। रेवाड़ी जिला 28°10'48" उत्तर से 76°37'12" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। रेवाड़ी जिले का कुल क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर (615 वर्ग मील) है। इसकी कुल जनसंख्या 900332 है। जनसंख्या घनत्व 560 प्रति वर्ग कि.मी. 1.500 वर्ग मील) है।

रेवाड़ी जिले का इतिहास दिल्ली के इतिहास का समकालीन है। महाभारत काल में रेवत नाम के एक राजा थे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रेवती था। लेकिन राजा प्यार से उसे रीवा बुलाते थे। राजा ने अपनी बेटी के नाम पर "रीवा वाड़ी" नामक शहर की स्थापना की। रीवा का विवाह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ हुआ और राजा ने "रीवा वाड़ी" शहर को अपनी बेटी को दहेज के रूप में दान कर दिया। बाद में रीवा वाड़ी शहर रेवाड़ी बन गया। रेवाड़ी जिले में 7 ब्लाक खंड है, बावल, उहीना, धारुहेड़ा, जाटूसाना, खोल, नाहर और रेवाड़ी है।

मानचित्र : 1 अध्ययन क्षेत्र की स्थिति



स्रोत : आर्क जीआईएस पर आधारित

रेवाड़ी जिले में भूमि जोत की धारणाएं:

रेवाड़ी जिले में भूस्वामी की जोत तथा किसान की जोत समान आकार को हो सकती है या भिन्न भिन्न प्रकार की भी हो सकती है। जब कोई भू-स्वामी अपनी कुल भूमि पर स्वयं ही खेती करता है तो भू स्वामी

जोत और कृषि जोत समान आकार वाली होगी। यदि भू-स्वामी अपनी सम्पूर्ण भूमि पर खेती न करके उसमें से कुछ भाग लगान पर उठा देता है और शेष पर स्वयं खेती करता है तो भूस्वामी की जोत तथा किसान की जोत का आकार, अलग-अलग होगा। कृषि जोत की निम्नलिखित धारणाएं हैं—

(i) **आर्थिक जोत (Economic holding):** कीटिंग्स के अनुसार आर्थिक जोत वह है, जो कि एक व्यक्ति को आवश्यक व्यय निकालने के पश्चात् उस तथा उसके परिवार को उचित सुविधाओं सहित पर्याप्त उत्पादन का अवसर प्रदान करती है। रेवाड़ी जिले में आर्थिक जोत के अन्तर्गत एकपरिवार 40 से 50 एकड़ भूमि को रखते हैं।

(ii) **पारिवारिक जोत (Family holding) :** प्रथम पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में पारिवारिक जोत शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थ में किया गया है—“पारिवारिक जोत वह जोत है, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तथा कृषि की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत एक औसत आकार वाले परिवार के लिए उसे सहायता सहित जा कृषि कार्य में सामान्यतः उपलब्ध होती है। एक हल इकाई तथा एक कार्य इकाई के बराबर हो।” एक हल इकाई अथवा एक कार्य इकाई का आशय उस क्षेत्रफल से है जिसको एक किसान एक हल के प्रयोग में ठीक प्रकार जोत और बो सके, अर्थात् इतना छोटा भी न हो कि एक किसान और एक हल को पूरा कार्य न मिल सक और आकार इतना बड़ा भी न हो कि एक किसान (अपने परिवार के सदस्यों सहित) एक हल सहित उस पर पूरी तरह से खेती न कर सके। शोधार्थीके अनुसार, आर्थिक जोत और पारिवारिक जोत को एकदूसरे का पर्यायवाची माना जा सकता है।

(iii) **आदर्श या अनुकूलतम जोत (Optimum holding) —** अध्ययन क्षेत्र में आदर्श या अनुकूलतम जोत का अर्थ उस अधिकतम आकार से है, जिस पर परिवार का स्वामित्व होना चाहिए। पारिवारिक जोत की तीन गुना जोत अनुकूलतम जोत कही गई है। जोत के आकार की अधिकतम सीमा के निर्धारण के मूल में यह विचार कामकर रहा है कि जोत की ऊपरी सीमा उस स्तर तक नियत कर दी जाय, जहाँ तक उस एक परिवार का स्वामित्व स्वीकार किया जा सकता है। बागों तथा गन्नों के खेतों आदि को उपयुक्त व्यवस्था के अपवाद के रूप अलग रखना होगा। उनके अनुकूलतम आकार का निर्धारण करते समय यह बात ध्यान में रखनी होगी कि उत्पादन की मात्रा में कमी न हो जाय। दूसरे शब्दों में, बागीचों और गन्नों के फार्मों की जमीन के संदर्भ में अनुकूलतम जोत उसे कहा जायगा जिस पर उत्पादन को नई तकनीक को सीमा में रहते भूमि, श्रम और पूँजी का कुशलतम उपयोग किया जा सके।

(iv) **क्रियात्मक जोत (Operational holding)**— कृषि संगणन (1970-71) के अनुसार "क्रियात्मक जांत को उन सभी भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से कृषि/उत्पादन के कार्यमें प्रयुक्त होती है और एक व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर (स्वामित्व, कानूनी स्थिति, आकार एवं को ध्यान में रखें बिना) एक तकनीकी इकाई के रूप में प्रस्तुत होती है।" एक तकनीकी इकाई का आशय ऐसी इकाई से है, जो एक प्रबन्ध के अन्तर्गत हो और जिसके उत्पादन के साधन एक ही हो।

(अ) **अधिकतम जोत (Maximum holding)**— अधिकतम जोत से आशय भूमि के उस अधिकतम क्षेत्रफल से है, जिस का एक किसान कानूनी रूप से अपने स्वामित्व में रखसकता है। जिलेके विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी द्वारा भिन्न-भिन्न अधिकतम क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं।

रेवाड़ी जिले में भूमि जोत के विखंडन के कारण : रेवाड़ी जिले में भूमि जोत के विखंडन के कारणों को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है –

(1) **कृषि पर जनसंख्या दबाव की भारत में वृद्धि (Increased pressure of population on agriculture)**— रेवाड़ी जिलेमें भूमि के उप-विभाजन एवं विखण्डन का प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि है। जिले में प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ जाती है, परन्तु जमीन में वृद्धि नहीं होती है। इसी बढ़ी हुई जनसंख्या की आधी जनसंख्या कृषि कार्य में ही जग जाती है, जिसके कारण जमीन का बँटवारा होने लगता है। वाडिया एवं मर्चेंट का भी कहना है कि "खेतों के विखण्डन का कारण जिले की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, जिसको कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योगों से रोजगार दिलाना संभव नहीं है तथा जिसकी भूमि को प्राप्त करने की प्यास को शांत करना बहुत कठिन है।" रेवाड़ी में सन् 1991 में प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का औसत 1.11 एकड़ था, जो सन् 2001 में घटकर 0.6 एकड़ रह गया।

(2) **उत्तराधिकार का नियम (Laws of Inheritance)**: विखंडन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण उत्तराधिकारी का नियम है। हमारे क्षेत्रमें प्रचलित नियम है कि पिता की सम्पत्ति में पुत्र का हिस्सा होगा। नये हिन्दू अधिनियम के अनुसार लड़कियों को भी पैतृक सम्पत्ति में अधिकार मिल गया है। इस उत्तराधिकार के नियम के फलस्वरूप जमीन का बँटवारा हो जाता है और वह जमीन खंड-खंड में विभाजित हो जाती है।

(3) **संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास (Decline of joint family system)**— शोध क्षेत्र में धीरे-धीरे संयुक्त परिवार प्रणाली का लोप होता जा रहा है। संयुक्त परिवार प्रणाली में तो जमीन का बँटवारा नहीं होता था। परन्तु जब संयुक्त परिवार का ह्रास होने लगा, तो जमीन भी

बँटने लगी और उन जमीनों का विखंडन भी होने लगा।

(4) **किसानों की ऋणग्रस्तता (Indebtedness of farmers)**:— क्षेत्र में भूमि के विखंडता का एक कारण किसानों की ऋणग्रस्तता है। किसानों का काम ऋण पर ही चलता है। ऋण जब किसानों के द्वारा चुकाया नहीं जाता है तो इसके लिए वह अपनी भूमि का ही एक भाग बेचकर ऋण चुकाता है। भूमि की बिक्री से भूमि के विखंडन की प्रवृत्ति बढ़ रहा है।

(5) **भूमि के लगाव (Attachment of land)** : अध्ययन क्षेत्र में लोगों की रुढ़िवादी प्रवृत्ति के कारण उन्हें भूमि से लगाव हो जाता है। इस मोह के चलते लोग जमीन पर खेती करें या न करें, परन्तु अपना हिस्सा लेने में पीछे नहीं रहते हैं। यह प्रवृत्ति जमीन को छोटे-छोटे टुकड़े में बाँट देती है।

(6) **हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग का पतन (Decline of handicrafts and village Industries)** :- रेवाड़ी में भूमि के विखण्डन के लिए हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग का पतन भी जिम्मेवार है। अध्ययन क्षेत्र में जैसे जैसे हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग समाप्त होते गया, वैसे-वैसे इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगर खेती पर निर्भर होते गये और अपनी-अपनी जमीन बाँटते गये थे। इससे जमीन की जोतों का विखंडन होने लगा।

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में भूमि जोत की धारणाएं एवं उनके विखंडन के क्या क्या कारण रहे हैं। इन धारणाओं और कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए तभी क्षेत्र में भूमि विखंडन को रोका जा सकता है।

संदर्भ सूची:-

1. बर्गमैन, (1968). को आपरेशन इन इंडिया. एग्रीकल्चरल डवलपमेंट एलाइड पब्लिशर्स, पृ.सं. 433.
2. जॉनसन, O-E-G- (1970). विखंडन की अर्थव्यवस्था, नाइजीरियाई जर्नल ऑफ डेकोनोमिक्स एंड सोशल स्टडीज, वोल्यूम 12, पृ.सं. 175-184.
3. टीथर, ई. के. (1970). द हेजगेरो: ए एनालिसिस ऑफ द चेचिंग लैंडस्केप. भूगोल, वोल्यूम 5. पृ.सं. 55
4. ऊषा, आर. (1971), साइज ऑफ फार्म एंड प्रोडक्टिविटी आर्थिक और राजनीतिक विकली एनालाइज ऑफ एग्रीकल्चर, पृ.सं. 15-23.
5. हुआंग, वाई. (1973). देशों में खेत के आकार के कुछ निर्धारकों पर। अमेरिकन जर्नल आफ एग्रीकल्चर इकोनोमीज, वोल्यूम 55, पृ. सं. 89-92.
6. स्मिथ. (1975). संयुक्त राज्य अमेरिका में खंडित फार्म. अमेरिकी भूगोलवेता एसोसियेशन, पृ.सं. 58-70.

7. गुप्ता, एमडी. (2002). त्रिपुरा के आदिवासियों की खेती के पारंपरिक तरीके को झुमते हुए, भौगोलिक समीक्ष आस्ट्रेलियन जर्नल आफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 51, पृ.सं. 58–70. II, 64(4), पृ.सं. 346–353.
8. टोडोरोवा, एस. ए. और लुलचेवा, डी. (2005). बल्गेरियाई कृषि पर भूमि का विखंडन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव. जर्नल सेन्ट्रल यूरोपियन एग्रीकल्चर, वॉल्यूम 6, संख्या 4, पृ.सं. 556–558.
9. हंग, वी., औले, जी. और मार्श, एच. (2007). उत्तरी वियतनाम में भूमि विखंडन अर्थशास्त्र,

डॉ० दीपा

असिस्टेंट प्रोफेसर

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

रोहतक

अंजु

शोधार्थी

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

रोहतक



सारांश

भारत तथा विश्व के सभी क्षेत्रों में मानव सभ्यता के विकास के प्रत्येक चरण में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी सहभागिता के बिना मानव समाज का विकास तो क्या अस्तित्व भी सम्भव नहीं है। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को निर्धारित करने में समाज के साथ-साथ राज्य की भूमिका सकारात्मक होती गई है। प्राचीन काल से ही राज्य चाहे उसका स्वरूप कुछ भी रहा हो, अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग अवश्य रहा है। शासकों की कुछ कटिबद्धता इतिहास के हर चरण में देखने को मिली हैं। यदि भारतीय सभ्यता के इतिहास को इस दृष्टि से देखें, तो राज्य और इसके प्रशासन की कटिबद्धताओं को विशेषतः स्त्रियों के सन्दर्भ में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है –

प्राचीन भारत

भारत की प्राचीन सभ्यता 'सिंधु सभ्यता' है। पुरातात्विक साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि सैधव सभ्यता नगरीय थी और उसका संचालन किसी व्यवस्थित प्रशासन के बिना सम्भव नहीं था। इन सभ्यताओं में राजनैतिक एवं सामाजिक संस्थाएं जन कल्याण के प्रति अवश्य ही सजग रही होंगी। महिलाओं के संदर्भ में जो भी साक्ष्य मिलते हैं, उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि तत्कालीन प्रशासन तथा समाज महिलाओं के प्रति सजग व संवेदनशील रहा होगा।

'सिंधु सभ्यता' के बाद ऋग्वेदिक काल में राजतंत्र प्रचलन में था। ऋग्वेद में राजा को प्रजा का रक्षक कहा गया है, परन्तु ऋग्वेदिक काल की न्याय व विधि व्यवस्था के विषय में हमें निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। न्याय प्रक्रिया का कार्य सम्भवतः राजा पुरोहित की सहायता से करता था। इस समय में चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि अपराधों के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन इस समय मृत्युदण्ड का प्रावधान नहीं था। शारीरिक दण्ड के लिए केवल जुर्माना लिया जाता था। इन उल्लेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था अच्छी बनाए रखने का पूर्ण प्रयास किया जाता था। इसके लिए अपराधियों को दण्ड भी दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था से स्त्रियाँ भी स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती थी।

उत्तरवैदिक काल में भी राजतंत्र था, जिसमें राजा प्रजा के हित में धर्मानुकूल आचरण करने की प्रतिज्ञा लेता था। राजा के निर्वाचन में प्रजा का भी हाथ होता था। अन्यायी राजा को प्रजा दण्ड दे सकती थी एवं उसे राज्य से च्युत करने का भी अधिकार था। 'सभा', 'समिति' नामक प्रतिनिधि संस्थाएँ थी, जो राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। स्त्रियों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अतः राजा द्वारा अपने राज्य संचालन में स्त्रियों से सम्बन्धित प्रावधानों को भी महत्व दिया

जाता था।

'महाकाव्य काल' में देखा गया है कि राजा अपने अभिषेक के अवसर पर प्रजा-पालन की शपथ लेता है। महाभारत अन्यायी व दुराचारी शासकों के वध की अनुमति प्रदान करता है।

मध्यकालीन भारत

मध्यकालीन भारत के शासकों द्वारा प्रजा के हित में किए गए कार्यों का स्पष्ट उल्लेख सल्तनत काल से मिलता है। इस काल में शासन के द्वारा स्त्रियों, बच्चों व साधनहीन लोगों को 'जजिया' कर से मुक्त रखा गया। यद्यपि मुस्लिम कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। राज्य की सकारात्मक भूमिका के स्पष्ट दर्शन हमें मुगलकाल में भी होते हैं। यह पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील थी। मुगलकाल में अकबर राष्ट्रीय सम्राट की छवि को धारण करता है। उसके द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग की उन्नति का प्रयास किया गया है। स्त्रियों के सम्बन्ध में भी कुछ प्रयास देखे गए हैं। जैसे- सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास, विधवा-विवाह को मंजूरी देना। बाल-विवाह एवं बहुविवाह को हतोत्साहित किया। यदि पहली पत्नी बंध्या न हो, तो एकाधिक स्त्रियों से विवाह करना राज्य को नामंजूर था। विवाह की उम्र बढ़ाकर लड़कियों की 14 वर्ष तथा लड़कों की 16 वर्ष कर दी गई तथा विधवा-विवाह को कानूनी समर्थन दिया गया। यह सुधार पूर्णतः सफल नहीं हो सके। समाज द्वारा इन सुधारों को स्वीकारा नहीं गया। यही कारण है कि कालांतर में मुगल या फिर प्रारम्भिक ब्रिटिश शासनकाल में स्त्रियों की दशा दयनीय हो चुकी थी।

ब्रिटिश शासनकाल

प्रारम्भ में ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक और धार्मिक विषयों में तटस्थता की नीति अपनाई, परन्तु 18वीं सदी के अन्तिम चरण में ब्रिटिश शासन द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु विविध कानूनों का निर्माण किया गया। इसकी पृष्ठ भूमि में राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, महर्षि दयानन्द सरस्वती, डी०वी० कर्वे, महादेव गोविन्द रानाडे एवं अन्य नेताओं द्वारा किए गए प्रयास थे।

ब्रिटिश शासन द्वारा महिलाओं की स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जो विधायी प्रयास किए, उनमें पहला महत्वपूर्ण प्रयास सती प्रथा का उन्मूलन करना था। राजा राममोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने इस क्रूर प्रथा पर प्रहार किया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1829 के 70वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया। महिलाओं से

सम्बन्धित एक अन्य क्रूर प्रथा जो विशेषतः राजपूत और बंगालियों में प्रचलित थी, वह बालिका वध की थी। महिलाओं की दुरावस्था में बाल-विवाह की प्रथा भी अभिशाप थी। अतः 1872 में 'सिविल मेरिज एक्ट' द्वारा चौदह वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया और बहुपत्नी प्रथा का भी अन्त किया।

निष्कर्ष:

इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से सामने आए और इसने स्त्रियों की दशा को अनुकूल रूप से प्रभावित किया। वस्तुतः ये विधान स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की दशा में मील का पत्थर साबित हुए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. शर्मा डी0डी0, गुप्ता ओ0पी0 (2004) 'समाजशास्त्र' प्रतियोगिता साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. देसाई नीरा व ठक्कर उषा (2009) 'भारतीय समाज में महिलाएँ' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
3. अहुजा राम : (2003) 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. सिंह नरेन्द्र 'मानवाधिकार एवं महिला सहभागिता' प्रकाशक राहुल पब्लिकेशन हाउस, 34816, शास्त्रीनगर, मेरठ।

डॉ० हिमांशु कुमार

ए-10, ओरचिड ग्रीन ओम विहार,
दिल्ली रोड, रुड़की (हरिद्वार)

सारांश

मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती ।
भगवान् भारत वर्ष में गूँजे हमारी आरती ।
हो भद्र भावोद्भाविनी, वह भारती हे भगवते ।
सीतापते सीतापते, गीतापते गीतापते ।
मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारत
.....

तीन सजावत देश को, गुरु, सती और शूर ।
तीन लजावत देश को, कपटी, कायर क्रूर ।।

भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर अनेक गुरुओं और संतों का पदार्पण होते रहा है, इनमें यागवल्क्य, भारद्वाज, अष्टावक्र, वेदव्यास, शंकराचार्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, संदीपनी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यमदग्नि, परशुराम, रामकृष्ण परम हंस, विवेकानंद आदि मुख्य हैं, जिनके ज्ञान और विवेक से भारतवर्ष गौरवान्वित हुआ है। भारतवर्ष को सजाने संवारने वाले और विश्व गुरु बनाने वाले शिक्षक, सती, संत और शूर हैं, जिनपर हमें नाज और ताज है ।

भारतीय गुरुओं की इसी सुदीर्घ परंपरा में तमिलनाडु के तरुत्तनी ग्राम में 5 सितंबर 1888 को जिस नवजात शिशु ने जन्म लिया और अपने वैदुष्य और शिक्षकत्व धर्म से न केवल भारतवर्ष को अपितु संपूर्ण विश्व को प्रकाशित और गौरवान्वित किया, इतिहास उसे डा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जानता है ।

पिता चाहते थे पुत्र पुजारी बने, लेकिन पुत्र की ख्वाहिश अंग्रेजी सीखने और शिक्षक बनने की थी। हरि ईच्छा बलीयसी, जहाँ चाह वहाँ राह की लोकोक्ति चरितार्थ हुई। मेधावी राधाकृष्णन ने कृश्चियन कालेज मद्रास से दर्शन शास्त्र में एम.ए. की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और उसी कालेज में प्राध्यापक नियुक्त हो गए। वे अपनी प्रतिभा के बल पर निरंतर आगे बढ़ते गए ।

कुछ दिनों के बाद वे रेजिडेंसी कालेज मद्रास में प्राध्यापक बन गए। पुनः मैसूर और कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनाए गए। लंबी अवधि तक आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। पुनरु आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। पं मदन मोहन मालवीय उन्हें आफर देकर अपने यहां ले आए। वे 1946 तक वहां के कुलपति रहे। वे अपने कुलपतित्व काल में प्रत्येक रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विश्वनाथ मंदिर में प्रातः 8 से 10 बजे तक श्रीमद्भगवद्गीता पर प्रवचन करते थे और उनके उद्बोधन को सुनने के लिए न केवल छात्र छात्राओं का अपितु शिक्षकों तथा अन्य श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। यह बात मैंने रांची के सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डा के.के.सिंहा से

सुनी थी, जो 1945-46 में बी.एच.यू वाराणसी के छात्र हुआ करते थे ।

उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा शिष्टमंडलों का सफल नेतृत्व किया। उन्होंने 1948-49 में यूनेस्को के एक्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष पद को गौरवान्वित किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद माना जाता है ।

डॉ० राधाकृष्णन 1949-1952 में स्वतंत्र भारत के रूस में राजदूत रहे। अपने राजदूतत्व काल में वे नियमित रूप से लेनिन पुस्तकालय अपने अध्ययन हेतु जाया करते थे। ज्ञान के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा ने उन्हें एक आदर्श शिक्षक बना दिया। आदर्श शिक्षक का यह एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है ।

1952 से 1962 तक वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और 1962 से 1967 तक वे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध उन्हीं के राष्ट्रपतित्वकाल में लड़ा गया था। अपने ओजस्वी भाषणों से भारतीय सैनिकों के मनोबल को ऊंचा उठाने में उनका योगदान सराहनीय था ।

डॉ० राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन और संस्कृति पर अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं:-

- 1 एथिक्स आफ वेदांत (वेदांत की नैतिक भूमिका)
- 2 दी फिलासफी आफ रवीन्द्र नाथ टैगोर (रवीन्द्र नाथ टैगोर का दर्शन)
- 3 दी रेन आफ रिलीजन इन कंटेंपरेरी फिलासफी (सामयिक दर्शन के क्षेत्र में धर्म का प्रभाव)
- 4 इंडियन फिलासफी (भारतीय दर्शन)
- 5 दी फिलासफी आफ दी उपनिषद्स (उपनिषदों का दर्शन)
- 6 भगवद्गीता इस्ट एण्ड वेस्ट सम रिप्लेक्शनस
- 7 इस्टर्न रिलीजन एण्ड वेस्टर्न थौट्स ।
- 8 एन आडियलिस्टिक व्यू आफ लाइफ
- 9 हिंदू व्यू आफ लाइफ
- 10 भारतीय संस्कृति

सत्य की खोज, संस्कृति तथा समाज डॉ० राधाकृष्णन के दर्शन पर शिष्टी द्वारा संपादित एक पुस्तक प्रसिद्ध है। यह एक अभिनंदन ग्रंथ है, जिसमें भारतीय दर्शन और डा राधाकृष्णन के अन्वेषणों पर अनेक विद्वानों के खोजपूर्ण लेख हैं ।

अपनी रचनात्मक एवम् दार्शनिक उपलब्धियों के कारण वे देश और विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों के द्वारा डाक्टरेट्स की मानद उपाधियों से नवाजे गए। डा राधाकृष्णन को 1954 में स्वतंत्रता सेनानी सी.राजगोपालाचारी और भौतिक शास्त्री डा सी.वी.रमण के साथ सबसे पहले भारत-रत्न के साथ सम्मानित किया गया था ।

डॉ० राधाकृष्णन भाषण कला के आचार्य थे। विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन पर भाषण देने के लिए उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाया जाता था। श्रोता उनके भाषणों से मंत्र मुग्ध हो जाते थे। डा राधाकृष्णन में विचारों, कल्पना यथा भाषा द्वारा विचित्र ताना बाना बुनने की अदभुत क्षमता थी। वस्तुतः उनके प्रवचनों की वास्तविक महता उनके अंतर में निवास करती थी, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। उनकी यही आध्यात्मिक शक्ति सबको प्रभावित करती थी, अपनी ओर आकर्षित करती थी और संकुचित क्षेत्र से उठाकर उन्मुक्त वातावरण में ले जाती थी।

हाजिर—जबाबी में वे गजब के थे। एक बार वे इंग्लैंड गए। विश्व में उन्हें हिंदूत्व के परम विद्वान के रूप में जाना जाता था, तब देश परतंत्र था। बड़ी संख्या में लोग उनके भाषण को सुनने के लिए आए थे। भोजन के समय एक अंग्रेज ने राधाकृष्णन से पूछा—क्या हिंदू नाम का कोई समाज है? कोई संस्कृति है? तुम कितने बिखरे हुए हो? तुम्हारा एक सा रंग नहीं, कोई गोरा, कोई काला, कोई बौना, कोई धोती पहनता है, कोई लूंगी कोई कुर्ता तो कोई कमीज। देखो! हम अंग्रेज सभी एक जैसे हैं, सब गोरे गोरे लाल लाल। इस पर डा राधाकृष्णन ने तपाक से उत्तर दिया—घोड़े अलग अलग रंग रूप के होते हैं, पर गधे एक जैसे होते हैं। अलग अलग रंग और विविधता विकास के लक्षण हैं। अंग्रेज को काठ मार गया।

मैं अपने पाठकों को बताना चाहता हूँ कि जब उनके शिष्यों और शुभैषियों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। वे चाहते तो अपना जन्मदिन राष्ट्रपति दिवस के रूप में मना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में शिक्षक ही सर्वोपरि होता है। शिक्षक ही राष्ट्रपति बनाता है, अतः वह सर्वोत्तम भावेन संपूज्य है। सचमुच वे आदर्श शिक्षक के साक्षात् पर्याय थे। उन्हें जन्मदिन पर कोटिशः नमन, वंदन और अभिनंदन है।

ऐसे गुरुजनों के ज्ञान से भविष्य का भारत अपनी खोई समृद्धि और श्रेष्ठता को हस्तगत करेगा क्योंकि अब हम एक और नेक बन गए।

शिक्षक दिवस के पावन पुनीत अवसर पर भविष्य के भारत के सर्वांगीण कल्याण और विकास के लिए परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है:—

सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो।

गुण, शील, साहस, बल तथा सबमें भरा उत्साह हो।

सबके हृदय में सर्वदा, संवेदना की दाह हो।

हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो।

डॉ० जंग बहादुर पाण्डेय 'तारेश'

पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग

रांची विश्वविद्यालय, रांची

चलभाषरू9431595318

सारांश

हिमाचल प्रदेश को देव भूमि भी कहा जाता है। इसे देवताओं के घर के रूप में भी जाना जाता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज्यादा मंदिर हैं और इनमें से ज्यादातर प्रमुख आकर्षक का केन्द्र बने हुए हैं। इन मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर चामुण्डा देवी का मंदिर है जो कि जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है।

चामुण्डा देवी मंदिर शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहां पर आकर श्रद्धालु अपने भावना के पुष्प मां चामुण्डा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश के कोने-कोने से भक्त यहां पर आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चामुण्डा देवी का मंदिर समुद्र तल से 1000 मी. की ऊंचाई पर स्थित है। यह धर्मशाला से 15 कि०मी० की दूरी पर है। यहां प्रकृति ने अपनी सुंदरता भरपूर मात्रा में प्रदान की है। चामुण्डा देवी मंदिर बंकर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पर्यटकों के लिए यह एक पिकनिक स्पॉट भी है। यहां कि प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

चामुण्डा देवी मंदिर मुख्यतः माता काली को समर्पित है। माता काली शक्ति और संहार की देवी है। जब-जब धरती पर कोई संकट आया है तब-तब माता ने दानवों का संहार किया है। असुर चण्ड-मुण्ड के संहार के कारण माता का नाम चामुण्डा पड़ गया।

दूर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में सौ वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में असुरों की विजय हुई। असुरों का राजा महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और देवता सामान्य मनुष्यों की भांति धरती पर विचलन करने लगे।

देवताओं के ऊपर असुरों ने काफी अत्याचार किया। देवताओं ने विचार किया और वह भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा।

देवताओं ने पूछा वो देवी कौन हैं ? जो कि हमारे कष्टों का निवारण करेगी! इसी योजना के फलस्वरूप त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो देखते ही देखते एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया।

इस देवी को सभी देवी-देवताओं ने कुछ न कुछ भेट स्वरूप प्रदान किया। भगवान शंकर ने सिंह, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा तथा समुद्र ने कभी न मैली होने वाली माला प्रदान की।

तभी देवताओं ने देवी की आराधना की ताकि देवी प्रसन्न हों जाएं और उनके कष्टों का निवारण हो सके। और हुआ भी ऐसा ही। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दे दिया और कहा मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। इसी के फलस्वरूप देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध

प्रारंभ कर दिया। जिसमें देवी कि विजय हुई और तभी से देवी का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ गया।

चामुण्डा देवी मंदिर 51 शक्ति पीठ मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ हैं। जिन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। ये सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे।

शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया य क्योंकि वे शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात सती को काफी बुरी लगी और वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गयीं।

यज्ञ स्थल पर शिव का काफी अपमान किया गया, जिसे सती सहन न कर सकी और वह हवन कुण्ड में कुद पड़ीं। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वे आये और सती के अर्द्ध जले तो शरीर को हवन कुण्ड से निकाल कर तांडव करने लगे।

जिस कारण सारे ब्रह्माण्ड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्माण्ड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया जो अंग जहां पर गिरा वह शक्ति पीठ बन गया। मान्यता है कि चामुण्डा देवी मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे।

माता का नाम चामुण्डा पड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है। दूर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति कथा वर्णित है। हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुम्भ और निशुम्भ नामक दो दैत्यों का राज था। उनके द्वारा धरती व स्वर्ग पर काफी अत्याचार किया गया।

जिसके फलस्वरूप देवताओं एवं मनुष्यों ने देवी दूर्गा कि आराधना की और देवी दूर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वे अवश्य ही इन दोनों दैत्यों से उनकी रक्षा करेंगी। इसके पश्चात् देवी दूर्गा ने कोशिकी नाम से अवतार ग्रहण किया।

माता कोशिकी को शुम्भ और निशुम्भ के दूतों ने देख लिया और उन दोनों से कहा महाराज आप तीनों लोको के राजा हैं। आपके यहां पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं। इन्द्र का ऐरावत हाथी भी आप ही के पास है। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्वसुन्दर है।

यह वचन सुन कर शुम्भ और निशुम्भ ने अपना एक दूत देवी कोशिकी के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुन्दरी से जाकर कहना कि शुम्भ और निशुम्भ तीनों लोके के राजा हैं और वो दोनों तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं।

यह सुन दूत माता कोशिकी के पास गया और दोनों दैत्यों द्वारा कहे गये वचन माता को सुना दिये। माता ने कहा मैं मानती हूं कि

शुम्भ और निशुम्भ दोनों ही महान बलशाली हैं। परन्तु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूँ? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा— वहीं मेरा स्वामी होगा और मैं उसी से विवाह करूँगी। इसलिए शुंभ और निशुंभ स्वयं ही यहां पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है?

सत्यमुक्ते त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितम्।

त्रैलोक्याधिपतिरुशुंभो निशुंभश्चापि तादृशरू।

किं वन्न यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या यत् क्रियते कथम्।

श्रुयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा कृता पुरा।

यों मां जयति संग्रामे, यों में दर्प व्यपोहति।

यों में प्रतिबलो लोके, सरुमें भर्ता भविष्यति।

तदागच्छतु शुंभो अत्र निशुंभो वा महासुररू।

मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणि गृहणातु में लघुरू।

दुर्गासप्तशती 5/116-121

ये सारी बातें दूत ने शुम्भ और निशुम्भ को बताईं। तो वे दोनों कोशिकी के वचन सुन कर उस पर क्रोधित हो गये और कहा उस नारी का यह दूरसाहस कि वह हमें युद्ध के लिए ललकारे। तभी उन्होंने चण्ड और मुण्ड नामक दो असुरों को भेजा और कहा कि उसके केश पकड़कर हमारे पास ले आओ।

चण्ड और मुण्ड देवी कोशिकी के पास गये और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी ने अपना काली रूप धारण कर लिया और असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। उन दोनों असुरों को मारने के कारण माता का नाम चामुण्डा पड गया। ऐसी चामुंडा देवी को मेरा सादर प्रणाम है:—

या देवी सर्वभूतेषु चामुंडा रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

डॉ० तारामणि पाण्डेय

कृतकार्य शिक्षिका, महारानी प्रेम मंजरी

प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय रातू रोड़ रांची

चलभाष:—9431595318

8797687656,9386336807

सारांश

मृदा एक आधार भूत संसाधन है। मनुष्य की अधिकांश मूल भूत आवश्यकतायें यथा—भोजन, वस्त्र, गृह आदि मृदा से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सम्पूरित होती हैं। जनपद की अक्षांशीय विस्तार 28° 10' से 29° 54' एवं देशान्तरीय विस्तार 78° 58' पूर्वी देशान्तर से 79° 47' तक है। सम्पूर्ण क्षेत्रफल 4120 वर्ग किलोमीटर है। मिट्टी निर्माण में विशेष योगदान जलवायु का होता है। परिच्छेदिका का आशय मिट्टी के उन संस्तरों में है जो एक-दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं। कृषि भूमि 330.36 हजार हेक्टेयर, एक से अधिक बार बोई गई भूमि 213.69 हजार हेक्टेयर एवं सकल बोई गई भूमि 544.06 हजार हेक्टेयर है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में मृदा संसाधन की समस्यायें प्रमुख हैं जिनका निराकरण आवश्यक है।

भूमिका

भौगोलिक दृष्टिकोण से मिट्टियों को खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण माना गया है। इस प्रकार धरातलीय संरचना में विभिन्न प्रकार के खनिजों का योगदान मिट्टियों के निर्माण एवं रचना में महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी पर देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। जनमानस की रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों अनिवार्य आवश्यकतायें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूमि (मिट्टी) पर ही आधारित हैं। मृदा एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। खेती का मूल ही मिट्टी एवं पानी है। इन दोनों का योग अच्छी फसल उत्पादन की गारण्टी है। आधुनिक खेती में खाद्यान्न, फसलों की बोनी, अर्थ बोनी व संकर किस्मों, सघन कृषि प्रणाली, जैविक खादों के उपयोग में कमी, रासायनिक उर्वरकों का असन्तुलित प्रयोग तथा कृषि रसायनों के अत्यधिक प्रयोग का मृदा गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मृदा गुणवत्ता से आशय है, कि मृदा की भौतिक रासायनिक एवं जैविक दशाएं फसलोत्पादन के अनुकूल बनी रहे। टिकाऊ एवं सतत् उत्पादन के लिए आवश्यक है कि भूमि को स्वस्थ बनाएं रखा जाए जिससे हम वर्तमान जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति के साथ-साथ भविष्य की संस्तुतियों की आवश्यकता का भी ध्यान रख सकें। आने वाले समय में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत को घटाना तथा उपलब्ध संसाधनों जैसे उर्वरक, सिंचाई जल, कीटनाशी इत्यादि के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करते हुए उत्पादकता एवं मृदा गुणवत्ता को बनाएं रखना नितान्त आवश्यक है।

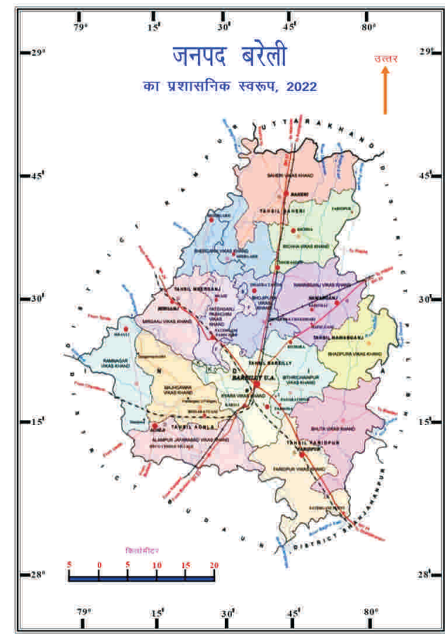
अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध-पत्र का अध्ययन क्षेत्र जनपद बरेली है जो

रुहेलखण्ड भौगोलिक क्षेत्र का अभिन्न अंग है। इसका अक्षांशीय विस्तार 28° 10' उत्तरी अक्षांश से 29° 54' तथा देशान्तरीय विस्तार 78° 58' पूर्वी देशान्तर से 79° 47' तक विस्तृत है। सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 4120 वर्ग किलोमीटर है। इसकी उत्तरी सीमा पर जनपद ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) एवं दक्षिणी सीमा पर जनपद बदायूँ, पूर्वी सीमा पर पीलीभीत एवं शाहजहाँपुर जनपद तथा पश्चिमी सीमा पर जनपद रामपुर स्थित है।

प्रशासनिक दृष्टि से 01 जनपद मुख्यालय बरेली, 06 तहसील मुख्यालय (बहेड़ी, मीरगंज, आवलां, नबाबगंज बरेली एवं फरीदपुर), 15 विकासखण्ड मुख्यालय, 144 न्याय पंचायत, 1008 ग्राम पंचायत एवं 2072 राजस्व ग्राम सम्मिलित है। स्थानीय प्रशासन एवं निकायों की दृष्टि से 01 नगर निगम, 04 नगर पालिका परिशद एवं 15 टाउन एरिया स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 44.48 लाख व्यक्ति है जिलेम 23.57 लाख पुरुष एवं 20.90 लाख स्त्रियां सम्मिलित है।

ऐतिहासिक दृष्टि से बरेली की स्थापना जगत सिंह कठेरिया ने 1500 ई० में जगतपुर स्थापित करके की। वर्तमान में यह जगतपुर बरेली के पुराने शहर का एक मोहल्ला है। रुहेलों के काल में यहाँ नबावी रही तथा अंग्रेजा के समय में बरेली रुहेलखण्ड कमिश्नरी का मुख्यालय रहा। वर्तमान में यह मण्डल मुख्यालय है।



मोक्ष परिकल्पना

मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन जो प्रकृति द्वारा सर्वसुलभ है।

मृदा कृषि कार्यो लिए महत्वपूर्ण आधार है। अध्ययन क्षेत्र में निम्न परिकल्पनाय उभरकर सामने आई है जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. जनपद बरेली मैदानी भू-भाग में स्थिति होने के परिणामस्वरूप कृषि कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
2. अध्ययन क्षेत्र की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है जो कृषि कार्य हेतु मिट्टी की उपयोगिता को निरन्तर बढ़ा रही है।
3. अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास दर मृदा का प्रभाव निरन्तर पड़ रहा है।
4. अध्ययन क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिवास एवं सामाजिक संस्थाओं के लिए प्रयुक्त भूमि में बढ़ोतरी परिलक्षित है।
5. अध्ययन क्षेत्र में अन्धाधुन्ध रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के फलस्वरूप मृदा गुणवत्ता में कमी दिखलाई पड़ रही है।

प्राकृतिक स्वरूप

जनपद बरेली प्राकृतिक दृष्टिकोण से मैदानी उच्चावचन को वरदान प्राप्त है। धरातलीय हष्टि से औसत ऊँचाई 172 मीटर है। भू वैज्ञानिक संरचना दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र गांगेय मैदान की कांप मृदा से निर्मित है यहाँ घर रामगंगा, बहंगुल, भाकरा, देवरनिया, सिंह किच्छा मुख्य नदियां बहती है। शुष्क मानसूनी जलवायु से युक्त इस क्षेत्र का औसत तापमान 25.15 डिग्री सेन्टीग्रेड, वार्षिक वर्षा 100 सेन्टीमीटर सापेक्षिक आर्द्रता 69 प्रतिशत एवं औसत वायु की गति 5.45 प्रति घन्टा किलो मीटर है। जनपद बरेली से कृषि भूमि की प्राप्ति हेतु प्राकृतिक वनस्पति को साफ कर दिया गया है तथापि रामगंगा नदी के खादर आज भी प्राकृतिक वनस्पति का कुछ हिस्सा पाया जाता है। वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 305 हेक्टेयर है। नदियों के समीपवर्ती क्षेत्र मे वन्य जीवों के झुण्ड दिखलाई पड़ते है।

आर्थिक स्वरूप

जनपद बरेली एक कृषि प्रधान क्षेत्र। है। 'कृषि' यहाँ की मुख्य आर्थिक क्रिया है। कुल कार्यशील जनसंख्या का 55 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 330.36 हजार हेक्टेयर, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल 213.69 हजार हेक्टेयर एवं सकल बोया गया क्षेत्रफल 544.06 हजार हेक्टेयर है। कृषि गहनता 165 प्रतिशत है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 320.98 हजार हेक्टेयर, एक से अधिक बार सिंचित भूमि 189.29 हजार हेक्टेयर एवं सकल सिंचित भूमि 510.27 हजार हेक्टेयर है। सिंचाई गहनता 159 प्रतिशत है। जनपद बरेली में परिवहन साधनों में सड़क एवं रेलमार्ग मुख्य है। रेलमार्ग की कुल लम्बाई 284 किलोमीटर है तथा रेलवे स्टेशनों की संख्या 30 है। बरेली मुख्य रेलवे जंक्शन है। सड़क मार्ग की लम्बाई 6280 किलोमीटर है। बस स्टेशनों की संख्या 127 है।

डाकघरों की संख्या 293 है। यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों का विकास तेजी से हुआ है। बरेली, बहेड़ी, मीरगंज, नबाबगंज, आंवला, फरीदपुर प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है।

मृदा निर्माण के कारक

किसी पदार्थ का संसाधन या तटस्थ बना रहना मानव प्राविधिकी के स्तर पर निर्भर करता है सामान्यतः मिट्टी का निर्माण मूल चट्टान के विघटन से होता परन्तु इसके अतिरिक्त जलवायु, वनस्पति, कालावधि तथा जल आदि कारकों का भी योगदान महत्वपूर्ण है। मिट्टी निर्माण मे विशेष योगदान जलवायु का होता है। भूमि की सतह पर किसी प्रमुख स्थान पर ये पाँच कारक एक साथ अपना प्रभाव डालकर मृदा उत्पत्ति करते हैं। (1) जलवायु (2) पैतृक पदार्थ (3) भूतल रूप या घरातल (4) जीवमण्डल (5) समय या भूमि की आय।



मृदा की संरचना एवं परिच्छेदिकायें

जनक सामग्री पर मृदा निर्माण प्रक्रमों द्वारा हजारों वर्ष कार्य करने से उसमें विभिन्न समानान्तर परतें बन जाती है और एक नए प्राकृतिक मृदा पिण्ड का निर्माण होता है जो अभि लक्षणों में पूर्ववर्ती जनक सामग्री से अत्यन्त भिन्न होता है। परिच्छेदिका का आशय मिट्टी उन संस्तरो में है जो एक-दूसरे के ऊपर आधारित होते है तथा मिट्टी में खोदे गये गर्त में अनावृत होने पर दिखाई देते हैं। मृदा संरचना का स्थाई होना आवश्यक एवं अनिवार्य है क्योंकि ऐसी संरचना ही मृदा उर्वरता की कुंजी है। मृदा में पाई जाने वाली समान्तर सतहें जब एक निश्चित गहराई (पैतृक पदार्थ) तक खोदी जाती है तो ये सतहें मिलकर जो इकाई बनाती है वह मृदा परिच्छेदिका कहलाती है।

मृदा वर्गीकरण के आधार

मृदा का वर्गीकरण एक बहुत ही जटिल कार्य है, क्योंकि

धरातल पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ अपने आप में अनेक भिन्नता लिए हुए पाई जाती है। मृदा उपयोग की सीमा इनके उचित ज्ञान व अध्ययन से ही आँकी जा सकती है जो इनके वर्गीकरण का एक आधार हो सकता है। मृदा का वर्गीकरण इनके जटिल चारित्रिक गुण व विशेषताओं के आधार पर हो सकता है जो किसी एक गुण विशेषता के आधार पर ही न होकर बनावट जल संगठन व रासायनिक विशेषताओं के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है।

मृदा का स्थानिक वितरण

किसी भी भू-भाग की भूमि तथा उसकी मिट्टियों का स्वरूप संगठन उसके जल संसाधनों की उपलब्धता संग्रहण तथा उपयोग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जनपद बरेली में मिट्टियों का निर्माण नवीन कल्प में नदियों द्वारा बहाकर लाये गये अवसादों के निक्षेप से हुआ है जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। (1) नवीन अवसादी निक्षेप जो प्रतिवर्ष नदियों द्वारा अपने बाढ़ क्षेत्र में या समीपवर्ती तटीय भागों में जमा कर दिए जाते हैं, इन्हें खादर कहा जाता है। (2) पुरातन अवसादी निक्षेप जहाँ अब नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, इन्हें बाँगर कहा जात है। अध्ययन क्षेत्र में चिकनी या कॉप मिट्टी, सिल्ट युक्त बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, उसर मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाते हैं।



कृषि भूमि

जनपद बरेली में कृषि भूमि 330.36 हेक्टेयर है। एक से अधिक बार कृषि भूमि 213.69 हजार हेक्टेयर है। जबकि सकल कृषि भूमि 544.06 हजार हेक्टेयर है। कृषि गहनता 165 प्रतिशत है। जैसा कि तालिका—में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 01 जनपद बरेली में कृषि भूमि का क्षेत्रीय वितरण, 2021–2022

क्र० सं०	विकासखण्ड	मृदा बोया गया क्षेत्रफल		एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल		सकल बोया गया क्षेत्रफल	कृषि गहनता प्रतिशत में
		हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत		
1-	बहेड़ी	34574	86.87	22321	64.56	56895	164
2-	शेरगढ़	21790	80.51	15003	68.82	36793	169
3-	रिच्छा	20986	79.00	14980	71.38	35966	171
4-	मीरगंज	18107	79.40	11712	64.68	29819	165
5-	फतेहगंज	13763	78.65	9876	70.30	23439	170
6-	भोजीपुरा	15313	80.08	11196	73.11	26509	173
7-	क्यारा	10842	66.73	7990	73.69	18832	174
8-	रामनगर	19237	85.68	12507	65.01	31744	165
9-	मझगवां	27734	91.60	14196	51.18	41930	151
10-	आलमपुर जाफराबाद	23594	86.34	17851	75.66	41445	176
11-	बिथरी चैनपुर	19543	84.75	7228	36.98	26777	137
12-	नबाबगंज	27398	83.57	20219	73.80	47617	174
13-	मदपुरा	20141	85.71	12227	60.70	32368	161
14-	भूता	27392	78.34	17518	63.95	44910	164
15-	फरीदपुर	23828	73.43	17230	72.30	41058	172
योग ग्रामीण		324242	81.90	211854	65.33	536096	165
नगरीय योग		6127	55.78	1838	30.00	7965	130
योग जनपद		330369	81.19	213692	64.68	544061	165

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, जनपद बरेली, 2022।

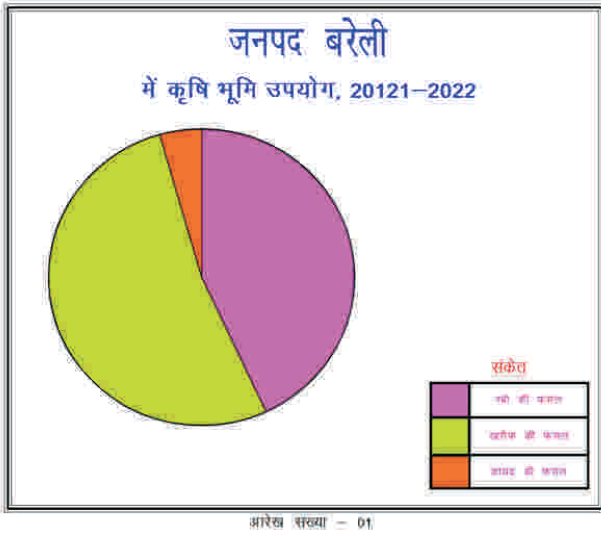
कृषि भूमि उपयोग:

जनपद बरेली में सकल बोया गया क्षेत्रफल 544.06 हजार हेक्टेयर है जिसमें रबी की फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल 234.54 हजार हेक्टेयर, खरीफ की फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल 284.85 हजार हेक्टेयर एवं जायद की फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल 24.6 हजार हेक्टेयर है। जैसा कि तालिका—में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 02 जनपद बरेली में कृषि भूमि उपयोग का क्षेत्रीय वितरण, 2021–2022

क्र० सं०	विकासखण्ड	सकल बोया गया क्षेत्रफल			सकल बोया गया क्षेत्रफल
		रबी की फसल	खरीफ की फसल	जायद की फसल	
1-	बहेड़ी	28.99	58.76	12.25	56895
2-	शेरगढ़	37.61	58.83	3.56	36793
3-	रिच्छा	41.88	56.59	1.53	35966
4-	मीरगंज	42.18	53.16	4.66	29819
5-	फतेहगंज	46.12	48.57	5.31	23439
6-	भोजीपुरा	44.91	51.96	3.13	26509
7-	क्यारा	48.95	46.55	4.50	18832
8-	रामनगर	49.50	44.89	5.61	31744
9-	मझगवां	47.41	49.37	3.22	41930
10-	आलमपुर जाफराबाद	49.52	45.20	5.28	41445
11-	बिथरी चैनपुर	49.18	47.75	3.07	26777
12-	नबाबगंज	42.48	55.48	2.04	47617
13-	मदपुरा	39.22	59.36	1.42	32368
14-	भूता	45.72	52.40	1.88	44910
15-	फरीदपुर	49.01	44.65	6.34	41058
योग ग्रामीण		43.42	52.07	4.51	536096
नगरीय योग		22.16	71.69	6.15	7965
योग जनपद		43.11	52.36	4.53	544061

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद बरेली 2022।



निष्कर्ष

जनपद बरेली रुहेलखण्ड सम्भाग में स्थित है एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। वर्तमान में यहाँ पर कृषि कार्य मृदा क्षरण के कारण बाधित हो रहा है। अधिकांश क्षेत्र अनवरत रूप से गहन कृषि का होना अर्थात् बार-बार जुताई, गुड़ाई एवं निराई से अध्ययन क्षेत्र की मिट्टियाँ पोली हो रही है। जिनको वर्षा की तेज बौछारों का जल बहाकर ले जाता है। बाढ़ के कारण कृषि योग्य भूमि प्रभावित होती है। कृषि भूमि की उर्वरता को बनाये रखने के लिए मृदा का संरक्षण आवश्यक है। भूमि में उचित फसल-चक्र अपनाया जाए।

फसलों के साथ दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। फसल बुवाई से मृदा परीक्षण आवश्यक है। कृषि विभाग द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर कृषकों को संगोष्ठी के माध्यम मृदा परीक्षण के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। अध्ययन क्षेत्र की मृदा के संरक्षण के लिए उपयुक्त कृषि अपशिष्टों तथा अवशेषों के समुचित प्रबन्ध की अति आवश्यकता है। फसल उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि और मृदा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गोबर की खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, मुर्गी खाद, हरी खाद, फसल अवशेषों इत्यादि का समय-समय पर प्रयोग करना चाहिए। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटैश के प्रयोग का आदर्श अनुपात 4: 2: 1 रखना आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र में बजर एवं कल्लर भूमि पर ग्राम समाज एवं संस्थागत भूमि पर सड़कों के मेंढों पर सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत सघन किनारे वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू करके बड़े क्षेत्र पर मृदा अपरदन को नियन्त्रित किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों को समय-समय पर कृषकों को प्रचार-प्रसार एवं संगोष्ठियों के माध्यम से मृदा की उपयोगिता उसके कटाव से होने वाली हानियों और मृदा संरक्षण से होने वाले लाभों से अवगत होने की आवश्यक है।

सन्दर्भ

- 1 सिंह विनय 2010 : मृदा विज्ञान भारती भण्डार मेरठ पृष्ठ-1

- 2 गौतम अलका 2010 : संसाधन एवं पर्यावरण शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद पृष्ठ-22
- 3 राव वी०पी० 2009 : भारत की भौगोलिक समीक्षा वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर पृष्ठ-92
- 4 शर्मा बी०एल० एवं भारद्वाज पलक 2013 : कृषि भूगोल रस्तोगी पब्लिकेशन्स मेरठ पृष्ठ-95
- 5 सिंह सविन्द्र 2010 : पर्यावरण भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद पृष्ठ-96
- 6 मलिक सिंह जगपाल 2011: मृदा उर्वरता प्रबन्ध कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका नवम्बर पृष्ठ-15
- 7 कुमार संजीव 2011 : मृदा उपजाऊपन चुनौतियाँ एवं समाधान कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका नवम्बर पृष्ठ-19
- 8 तिवारी के० एन० 2011 : मृदा जीर्णोद्धार में इको की पहल कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका नवम्बर पृष्ठ-27
- 9 मृदा गुणवत्ता विशेषांक कुरुक्षेत्र पत्रिका नवम्बर 2011।
- 10 रानी मधु 2011: मृदा उर्वरता बढ़ाने में जैविक उर्वरकों की भूमिका कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका नवम्बर पृष्ठ-29
- 11 डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ बरेली 1981 पृष्ठ-4
- 12 जिला विकास पुस्तिका जनपद बरेली 2015 पृष्ठ-3
- 13 जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद बरेली 2018।
- 14 नन्दन गिरिराज 2008 : बरेली दर्शन प्रकाश बुक डिपो बरेली पृष्ठ-3,4
- 15 जिला सूचना निदर्शनी पुस्तिका बरेली 2015 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बरेली पृष्ठ-92

निर्देशक

डॉ० एन० यू० खान
पूर्व प्राचार्य
जी० एफ० पी० जी० कॉलेज
शाहजहाँपुर

शोधार्थी

पंचम सिंह

सारांश :

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में निर्धनता को कम करने एवं रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। आर्थिक संकट के समय में ये रोजगार कार्यक्रम सकारात्मक परिणाम के सूचक होते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) इसका एक ज्वलंत उदाहरण है जो भारतीय ग्रामीण विकास में अपना अहम भूमिका निभा रही है। ग्रामीण आजिविका को वृद्धि करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है।

मुख्य शब्द : मनरेगा, रोजगार कार्यक्रम, मानव दिवस, जॉब कार्ड

प्रस्तावना :

भारत एक विकासशील राष्ट्र है यहाँ लगभग 6 लाख 38 हजार गाँव हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि है। गाँवों में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण लोग अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या 35.40 करोड़ थी जो सन् 2011 में बढ़कर 121 करोड़ से अधिक हो गई। आंकड़ों के अनुसार 1981 में 83 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या थी जो 2011 में घटकर 68.48 प्रतिशत रह गई। ये आंकड़े बताते हैं कि एक समय अंतराल के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है परन्तु ग्रामीण जनसंख्या में कमी आ रही है। जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण रोजगार सृजन नहीं होने के कारण लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुचि कम ले रहे हैं।

रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गाँवों से पलायन को रोकने, आवास के समीप रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण परिवार की आर्थिक सशक्तिकरण एवं महिला श्रमिकों में सामाजिक शक्तिकरण लाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा 5 सितम्बर 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संसद में पारित किया गया। **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का परिचय :-**

ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नरेगा योजना का प्रारम्भ 2 फरवरी 2006 को सर्वप्रथम आन्ध्रप्रदेश के अन्नतपुर जिले से किया गया। इस योजना में पूर्व में संचालित सम्पूर्ण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना का विलय कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गाँधी की 140वीं जयन्ती पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के द्वारा इसका नवीन नामकरण **मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)** किया गया। प्रारम्भ में इस योजना की शुरुआत 200 जिलों में किया गया। वर्ष 2007-2008 में पुनः 138 जिलों में इनका

विस्तार किया गया। 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया वर्तमान में सुखाग्रस्त एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के दिन (मानव दिवस) को बढ़ाकर 100 से 150 कर दिया गया है। यह विश्व का सबसे बृहत् रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा नरेगा हेतु कुल बजट (60,000 करोड़ रुपये, 2023-24) आवंटित किया गया है। वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी इस योजना में 55 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

इस योजना में कुल बजट का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात 60:40 का प्रावधान मनरेगा में किया गया है। कार्य की परिसीमा अपने निवास स्थान से 05 किलोमीटर के अन्दर किया गया है। कार्य परिसीमा के बाहर काम उपलब्ध कराने पर मजदूरी दर का 10% अतिरिक्त वहन करने का प्रावधान है। जिस दिन से काम की मांग की जाती है। उस दिन से 15 दिन के अन्दर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है जो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में मनरेगा का मजदूरी दर भिन्न-भिन्न है।

शोध का उद्देश्य :

ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप सकारात्मक आर्थिक परिवर्तन को प्रकाश में लाना।

साहित्य का पुनरावलोकन :

डॉ. अतुल कुमार तिवारी ने "नरेगा ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का अभियान" नामक लेख में बताया है कि नरेगा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। प्रारंभ से अब तक लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग मनरेगा से लाभान्वित हो चुके हैं। नरेगा से महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हद तक बेरोजगारी को दूर किया जा सका है। लोगों की आय में वृद्धि हुई है। रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं।

निकिता ओसवाल ने अपने शोध में बताया है कि हरियाणा अकुशल श्रमिकों को मजदूरी आवंटन में सबसे आगे है। अनुसूचित जातियों को राष्ट्र तथा राज्य के औसत दर से अधिक मानव सृजित दिवस दिया गया।

सनी कुमार सुमन ने अपने अपने शोध पत्र में बताया कि मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है परिणामस्वरूप ग्रामीण मजदूरों में पलायन की कमी देखी जा रही है।

विक्रम सिंह ने अपने आलेख "भारत के ग्रामीण विकास

में मनरेगा का योगदान एवं चुनौतियाँ” नामक शीर्षक में बताया है कि मनरेगा में रोजगार पानेवाले का अधिकतम हिस्सा महिलाओं का है मनरेगा कार्यक्रम से महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है।

शिव कुमार के शोध कार्य के निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि मनरेगा लागू होने से गैर कृषि मजदूरी में वृद्धि हुई है तथा लाभार्थियों के आय में वृद्धि हुई है।

शोध परिकल्पनाएँ

1. मनरेगा में संलग्न मजदूर वर्ग की आय वृद्धि का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण मजदूरों के पलायन रोकने में मनरेगा कार्यक्रम के योगदान का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :

किसी भी शोध के लिए संमकों का होना अतिआवश्यक है बिना संमकों के शोध करना असंभव है इस शोध में तथ्यों की सत्यता एवं संमकों के उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का समावेश किया गया है।

नावाडीह प्रखण्ड में मनरेगा की स्थिति :

प्रस्तुत शोध अध्ययन झारखण्ड के बोकारो जिले के अन्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के परसबनी पंचायत पर आधारित है। शोध अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक है। अध्ययन की समस्त ईकाइयाँ नावाडीह प्रखण्ड के परसबनी पंचायत के पंजीकृत लाभार्थी (जॉब-कार्डधारी) हैं परसबनी पंचायत के 200 लाभार्थियों का चयन आंकड़ों को एकत्रित करने (सूचनादाता के रूप में) के लिए किया गया है प्रस्तुत शोध अध्ययन दिसम्बर 2022 में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों संमकों के आधार पर किया गया है। आंकड़ों को एकत्रित करने के पश्चात उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण का निष्कर्ष निकालते हुए, निष्कर्ष के आधार पर शोध समस्या के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या – 1

लाभार्थियों की वैयक्तिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि

सामाजिक पृष्ठभूमि	विवरण				योग
	महिला 80 (40)	पुरुष 120 (60)			
लैंगिक स्थिति	एकल 130 (65)	संयुक्त 70 (35)			200 (100)
परिवारिक स्थिति	विवाहित 170 (85)	अविवाहित 22 (11)	विधवा 08 (04)	200 (100)	
वैवाहिक स्थिति	छोटा परिवार 140(70)	मध्य परिवार 50 (25)	बड़ा परिवार 10 (05)	200 (100)	
परिवार का आकार	हिन्दु 150 (75)	मुस्लिम 50 (25)	सिक्ख 00 (00)	इसाई 00 (0)	200 (100)
धार्मिक संरचना	अनु.जाति 30 (15)	अ.ज.जाति 30 (15)	पिछड़ा वर्ग 110 (55)	सामान्य 30 (15)	200 (100)
जातिगत स्थिति	18-30 30 (15)	30-40 40 (20)	40-50 66 (33)	50-60 34 (17)	60 तथा अधिक 30 (15)
आयु वर्षों में	कृषक 32 (16)	कृषि मजदूर 38 (19)	विहाड़ी मजदूर 68 (34)	निजी व्यवसाय 30 (15)	सेवा क्षेत्र 32 (16)
व्यवसाय	निरक्षर 22 (11)	प्राथमिक 68 (34)	उच्च प्राथमिक 48 (24)	उच्च विद्यालय 42 (21)	इण्टर 20 (10)
शैक्षिक स्थिति	0-10 2(1)	10-20 4(2)	20-30 28 (14)	30-40 46(23)	40-50 50(25)
वार्षिक परिवारिक आय (इंजार रु. में)	0-10 2(1)	10-20 4(2)	20-30 28 (14)	30-40 46(23)	40-50 50(25)
					50 तथा अधिक 70 (35)
					योग 200 (100)

बोकारो जिले के कुल प्रखण्डों में पंचायतों की संख्या एवं संबंधित पंचायतों में जॉब कार्डों की कुल संख्या –

सारणी संख्या – 2

क्र.सं.	प्रखण्ड का नाम	कुल पंचायत	जॉब कार्ड की संख्या
1.	बैरमो	19	6328
2.	चन्दन-कियारी	38	79154
3.	चन्दपुरा	23	31160
4.	चास	54	109500
5.	गोमिया	36	83738
6.	जरीडीह	17	34118
7.	कसमार	15	40116
8.	नावाडीह	24	67040
9.	पेटरवार	23	56491

नावाडीह प्रखण्ड में पंचायतों एवं जॉब कार्डों की कुल संख्या (2022-23) के अनुसार-

सारणी संख्या –3

क्र.सं.	प्रखण्ड का नाम	कुल पंचायत
1.	अहारडीह	2604
2.	बाराडीह	1842
3.	बरई	3387
4.	भलमारा	2651
5.	भेण्डरा	1277
6.	बिरनी	2425
7.	चपरी	2506
8.	चिरुडीह	2861
9.	दहियारी	2025
10.	गोनियाटो	2609
11.	गुंजरडीह	2551
12.	काछो	2464
13.	कंजकिरो	4037
14.	खरपीटो	3350
15.	मुंगो रंगामाटी	2415
16.	नारायणपुर	3287
17.	नावाडीह	2827
18.	पलामू	3646
19.	पैक	3977
20.	परसबनी	2602
21.	पोखरिया	3754
22.	पोटसो	2771
23.	सुरही	2702
24.	सहरिया	2470
कुल		67040

सारणी संख्या – 1 में लाभार्थियों की वैयक्तिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है। लैंगिक स्थिति के अन्तर्गत चयनित कुल 200 उत्तरदाताओं में से 80 महिला (40 प्रतिशत) तथा 120 पुरुष (60 प्रतिशत) हैं इनमें महिलाओं की अपेक्षाकृत पुरुषों की संख्या अधिक है। पारिवारिक स्थिति के अनुसार 130 एकल परिवार (65 प्रतिशत) तथा 70 संयुक्त परिवार (35 प्रतिशत) हैं वैवाहिक स्थिति के अन्तर्गत तथा 08 विधवा विधुर (4 प्रतिशत) हैं। परिवार के आकार के अन्तर्गत 140 छोटे परिवार (70 प्रतिशत) 50 मध्य परिवार (25 प्रतिशत) तथा 10 बड़े परिवार (5 प्रतिशत) हैं। धार्मिक संरचना

के अन्तर्गत हिन्दू 150 (75 प्रतिशत) तथा मुस्लिम 50 (25 प्रतिशत) है। जातिगत स्थिति के अन्तर्गत 30 अनुसूचित जाति (15 प्रतिशत) 30 अनुसूचित जनजाति (15 प्रतिशत) 110 पिछड़ा वर्ग (55 प्रतिशत) तथा सामान्य 30 (15 प्रतिशत) है। आयु वर्ग के अन्तर्गत 18-30 आयु वर्ग के 30 (15 प्रतिशत) 30-40 आयु वर्ग के 40 (20 प्रतिशत), 45-50 आयु वर्ग के 66 (33 प्रतिशत), 50-66 आयु वर्ग के 34 (17 प्रतिशत) तथा 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के 30 (15 प्रतिशत) है।

व्यवसाय के अन्तर्गत 32 कृषक (16 प्रतिशत), 38 कृषि मजदूर (19 प्रतिशत), 68 दिहाड़ी मजदूर (34 प्रतिशत), 30 निजि व्यवसाय (15 प्रतिशत) तथा 32 सेवा क्षेत्र (16 प्रतिशत) से है। शैक्षिक स्थिति के अन्तर्गत 22 (11 प्रतिशत) निरक्षर, 68 (34 प्रतिशत) प्राथमिक, 48 (24 प्रतिशत) उच्च प्राथमिक, 42 (21 प्रतिशत) उच्च विद्यालय, 20 (10 प्रतिशत) इण्टर तथा 00 (00 प्रतिशत) स्नातक तक शिक्षा प्राप्त किए है। वार्षिक पारिवारिक आय के अन्तर्गत 0-10 हजार रुपये वार्षिक आय वाले आय वाले 2 (1 प्रतिशत), 10-20 हजार रुपये वार्षिक आय वाले 4 (2 प्रतिशत), 20-30 हजार रुपये वार्षिक आय वाले 28 (14 प्रतिशत), 30-40 हजार रुपये वार्षिक आय वाले 46 (23 प्रतिशत), 40-50 हजार रुपये वार्षिक आय वाले 50 (25 प्रतिशत) तथा 50 हजार अधिक वार्षिक आय वाले की संख्या (70 प्रतिशत) है।

सारणी संख्या 2 में बोकारो जिले के कुल 9 प्रखण्डों के कुल पंचायतों एवं संबंधित प्रखण्ड के कुल जॉब कार्डों को दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए जैसे बेरमों प्रखण्ड में कुल 19 पंचायत है तथा कुल जॉब कार्डों की संख्या 6328, चन्दनकियारी प्रखण्ड में 38 पंचायत तथा कुल जॉब कार्डों की संख्या 79154, चन्द्रपुरा प्रखण्ड में कुल 23 पंचायत तथा कुल 31160 जॉब कार्ड, चास प्रखण्ड में कुल 54 पंचायत तथा जॉब की संख्या जॉब कार्ड 109500, गोमिया प्रखण्ड में पंचायतों की कुल संख्या 36 तथा कुल जॉब कार्डों की संख्या 83738 जरीडीह प्रखण्ड में कुल पंचायतों की संख्या 17 तथा जॉब कार्डों की कुल संख्या 34118, कसमार प्रखण्ड में पंचायतों में कुल संख्या 15 तथा जॉब कार्डों की कुल संख्या 40116, पेटरवार प्रखण्ड में पंचायतों की कुल संख्या 23 तथा जॉब कार्डों की कुल संख्या 56491 एवं नावाडीह प्रखण्ड में पंचायतों की कुल संख्या 24 तथा जॉब कार्डों की कुल संख्या 67040 है।

सारणी संख्या - 3 में नावाडीह प्रखण्ड के कुल 24 पंचायतों एवं संबंधित पंचायत के कुल जॉब कार्डों की संख्या की इस प्रकार दर्शाया गया है— अहारहीह 2604, बाराडीह 1842, बरई 3387, भलमारा 2651, भेण्डरा 1277, बिरनी 2425, चपरी 2506, चिरुडीह 2861, दहियारी 2025, गोनियाटो 2609, गुंजरडीह 2551, काछो 2464, कंजकिरो 4037, खरपीटो 3350, मुंगों रंगामाटी 2415, नारायणपुर 3287, नावाडीह 2827, पलामू 3646, पेंक 3977, परसबनी 2602, पोखरिया 3754, पोटसो 277, सहरिया 2470 तथा सुरही 2702 तथा इनकी कुल संख्या 67040 है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में ग्रामीण बेरोजगारी नियंत्रण करने में मनरेगा सहायक सिद्ध हो रही है। मनरेगा से लोगों के आय में वृद्धि हुई है तथा महिलाएँ आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त हुई है ग्रामीण परिसंपत्तियों के संरक्षण में वृद्धि हो रही है। मनरेगा कार्यक्रम में कुछ समस्याएँ भी देखने को मिल रही है— उदाहरण के लिए मजदूरों को जॉब डिमांड की पार्वती न देना, बेरोजगारी भत्ता न देना, कार्यस्थल सुविधाओं का अभाव, फर्जी हाजरी लगाना, काम के लिए पैसे की मांग इत्यादि परन्तु जिन राज्यों में मजदूर और लाभार्थी जागरूक है वहां मनरेगा कार्यक्रम सुचारूप से संचालित हो रही है आन्ध्रप्रदेश इसका ज्वलंत उदाहरण है।

बोकारो जिले के अन्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के परसबनी पंचायत में विगत 5 वर्षों में ग्रामीण परिसंपत्तियों एवं लोगों की आय में वृद्धि से मनरेगा के प्रति लाभार्थियों एवं मजदूरों रुझान बढ़ा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनरेगा ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभा रही है।

संदर्भ सूची

1. www.nrega.nic.in
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005
3. कटारिया, डॉ. सुरेन्द्र "आर्थिक मंदी से जुझने में नरेगा का योगदान" कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, अंक दिसम्बर 2009, पृ. 09
4. तिवारी, डॉ. अतुल कुमार "नरेगा ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का अभियान" कुरुक्षेत्र प्रकाशन विभाग भारत सरकार, अंक-दिसम्बर 2009, पृ. 13
5. योजना
6. महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, 2005 परद शोध अध्ययनों का संकल्प, 2006-12
7. तिवारी इत्यादि, मनरेगा फॉर एनवायरमेंट सर्विस एनहेंसमेंट एण्ड वल्नरेबिलिटी रिडक्श : रेपिड अप्रेजल इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक
8. आनंद प्रकाश मिश्र, ग्रामीण निर्धनता, साहित्य भवन, आगरा, 1998
9. लुईस क्लोरेंस, असामनता और गरीब, साहित्य भवन, आगरा, 2003
10. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी, रिसर्च मैथडोलॉजी, कॉलेज, बुक डीपो, जयपुर, 1998
11. ब्रह्मदेव शर्मा, गरीबी का मकड़जाल, साहित्य भवन, आगरा,

1999

12. डॉ. बी.एल. माथुर, भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन, आगरा, 1997
13. डॉ. डी.सी. पंत, भारत में ग्रामीण विकास, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 1998
14. डॉ. वी.सी. सिन्हा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं साहित्यकी, एस. बी.डी.पी. पब्लिशिंग हाउस, मथुरा, 2005
15. हनुमान सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर)

नाम : रूपलाल महतो
पिता – फागु महतो
ग्राम – डाही
पोस्ट – बिरनी
थाना – नावाडीह
जिला – बोकारो
राज्य – झारखण्ड
पिन कोड – 829144
मो0 न0 – 9006427733

सारांश :

किसी भी मनुष्य के मानसिक संवेगों, आन्तरिक अनुभूतियों, अतृप्त वासनाओं, दिवास्वप्नों और असामान्य व्यवहार के विश्लेषणपरक अध्ययन को 'मनोविज्ञान' की संज्ञा दी जाती है। कतिपय चरित्रा अन्तर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं और कतिपय चरित्रा बहिर्मुखी प्रवृत्ति के। यह दीर्घ बात है कि मनोविज्ञान सामान्यजन के चिन्तन, व्यवहार और पेचीदगी भरे संवेगों का अध्ययन करता है अथवा विचित्र और अव्यवहारिक मनोवृत्ति के पात्रों का। मनुष्य के विशुद्ध होने अथवा उदात्त बने रहने के पीछे कुछ अनुवांशिक प्रभाव होते हैं और कुछ स्वभावजन्य विशेषता होती है।

हिन्दी साहित्य में मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण को आधार बनाकर बहुत कम शोधपरक कार्य हुए हैं। प्रथम महायुद्ध की विभीषिका ने विश्वस्तर पर अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति पर सोचने के लिए बाध्य किया है। किसी व्यक्ति-विशेष के नेपोलियन अथवा हिटलर बनने के पीछे कतिपय विशिष्ट कार्य-कारण होते हैं। हर एक व्यक्ति न मार्क्स बन सकता है, नायड या एडलर। युंग ने आर्किटाइपल इमेजस के साथ मिथक और दिवास्वप्नों की बात की है। प्रत्येक रचनाकार अपने मानसिक अभावों की पूर्ति कला-जगत के संसार में करता है। वह अपने व्यक्तित्व की अपूर्णता या लघुता को किसी पात्रा-विशेष में पूर्णता या असीमित भाव में देखना चाहता है। हिन्दी कथा साहित्य में लिबिडो, इडिपस ग्रन्थि, हीन मनोग्रन्थि, उच्च मनोग्रन्थि, अन्तःप्रज्ञा, अंतश्चेतना को आधार बनाकर मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन कम हुए हैं।

शब्द कुंजी: मनोश्लेषणात्मक, व्यक्तिक, सामाजिक मनोविज्ञान, धार्मिक मनोविज्ञान, गुबार, राफेल, एकनिष्ठ, पुरुषार्थी, मक्कारी

मनोविज्ञान

मनोविज्ञान वह शैक्षिक और अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी (मनुष्य, पशु आदि) के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे- चिन्तन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। 'व्यवहार' में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं।

जीवन में प्रत्येक छोटी बड़ी घटना अपना प्रभाव मानस पटल पर छोड़ती है। यह मनोविज्ञान का ही प्रभाव है कि लेखक मनोविज्ञान की सहायता

से पात्रों के क्रियाकलापों का अभ्यांतर से संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि मनोभाव का उत्थान-पतन तथा मानसिक प्रक्रिया से कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। इसका अभिव्यक्तिकरण पात्रों के व्यवहारों के माध्यम से होता है और आलोचक मनोविज्ञान की सर्च लाइट के सहारे मन के अगम और अंधकारमय स्थलों में प्रवेश करके वहां का रहस्य उद्घाटित कर देता है तथा व्यवहार को संचालित करने वाले सूत्रों को खोज कर प्रकट करता है।

मनोविज्ञान की कोई निश्चित परिभाषा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन की सूक्ष्म एवं त्वरित क्रियाशीलता को विज्ञान के नियम-उपनियमों में बांधना सरल कार्य नहीं है। जितनी ही इसकी खोज होती है उतनी ही नयी परतें खुलती हैं।

सी.वुडवर्थ के अनुसार- "मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है"¹

रघुनाथ सफाया के अनुसार- " भारतीय मनोविज्ञान दर्शन का अभिन्न अंग है। यह उन मूल मान्यताओं पर आधारित है जिनका विकास भारतीय मनुष्यों और दार्शनिकों के सत्य दर्शन से हुआ है।"²

पुरुष मनोविज्ञान

पुरुष मनोविज्ञान को जानने के लिए हमें सभी कड़ियों का अध्ययन करना आवश्यक है जो पुरुष मनोविज्ञान की सभी पहलुओं को समझने में सहायक हों। मानव प्रयोगात्मक विज्ञान का ऐसा क्षेत्र है जहां मानव के उन सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जिस पर प्रयोग करना संभव है। सैद्धांतिक रूप से तो मानव व्यवहार के किसी भी पहलू पर प्रयोग किया जा सकता है लेकिन मनोवैज्ञानिक उससे पहले का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं जो पृथक किया जा सके। अतः पुरुष मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें पुरुष के व्यक्तित्व उनके राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष को समझना होगा जो पुरुष मनोविज्ञान के अभिन्न अंग हैं। रचनाकार शील कौशिक ने अपने साहित्य के माध्यम से पुरुष मनोविज्ञान के सभी पहलुओं को दर्शाया है। आज का पुरुष समाज में अपने आप को साबित करने या समाज में बराबरी करने के लिए अपने शोकों को बढ़ता जा रहा है। आज समाज में फँसे व्यसनी जाल में फँसता जा रहा है। वह रूप ,शराब को ही अपने जीवन की सामाजिक बढ़ोतरी का आधार मान बैठा है। वह झूठी शानो शौकत में फँसता जा रहा है-

“ईर्ष्या व द्वेष

रुपया और शबाब के

ऐब पाल लिए

उसने

नेताओं का साथ लिया

**झूठ, फरेब और मक्कारी
और दंभ जैसे
मर्ज पाल लिए
उसने”³**

एक पुरुष की स्त्री को लेकर, उसके सामाजिक दायित्व को लेकर उसकी सोच को शील कौशिक ने अपनी कहानी 'छूटा हुआ आसमान' में दर्शाया है कि आज का पुरुष भी इस बात को हजम नहीं कर पाया है कि औरतें पुरुषों से आगे बढ़ सकती हैं। उनसे अच्छा कार्य कर सकती हैं। उनके मन में आज भी स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना का अभाव दिखाई देता है। लघु कथा 'सच तो यही है' में दर्शाया है कि पुरुष स्त्री को समाज में किस रूप में देखता है। उसकी स्त्री को लेकर क्या सोच है?

'अरे ऐसा क्या कर दिया औरतों ने?'

“पढ़ा सुना नहीं तुमने फ्रांस से राफेल विमान को महिला पायलट ने अंबाला की हवाई पट्टी पर उतारा है। पिछले दिनों अमेरिका में भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह पर नए जीवन की खोज में उपग्रह उतारा य तो मैं गर्व से फूल गई, उसे निर्देशित करने वाली महिला ही थी।”

खामोशी में लिपटा गुब्बार का बड़ा- सा गोला सुकेश के आँतो में फंस गया।

सुनंदा का बोलना जारी था- “आज की औरत साधारण वीरता, एकनिष्ठ समर्पण और बल-बुद्धि में पुरुष से किसी भी दृष्टि से काम नहीं है। बार-बार अपनी योग्यता से समय की दीवार पर लिखे सत्य को स्त्री ने प्रमाणित किया है। सुकेश ने पत्नी को बाहुपाश में लिया और कहा- “हॉ यार! कह तो तुम ठीक रही हो।”

वह उसे बेडरूम की ओर ले चला।

“मेरा मन बिल्कुल नहीं है।

आलिंगन.. बस एक बार प्लीज

नहीं-मेरा मन...

और जबरदस्ती कर उसने मन मस्तिष्क में अटका गुब्बार दाग दिया। वह सफल हो गया था। कुटिल मुस्कान फेंकते हुए सुकेश ने कहा- “हॉ तो क्या कह रही थी तुम? महिलाओं के बराबरी की बराबरी का बखाना ...वह तो बहुत दूर की कौड़ी है, पहले तुम 'योर बॉडी इज योर ओन' का एहसास तो कर लो।”⁴

पुरुष के सामाजिक पक्ष का उद्घाटन करते हुए शील कौशिक ने अपनी कहानी 'पुरुषार्थी सूरदास' में मुख्य पात्र सूरदास को दर्शाया है कि किस प्रकार एक 65-70 वर्ष के अंधे व्यक्ति से लोग दुर्व्यवहार करते हैं। छोटा बच्चा उसे भिखारी समझ लेता है। एक युवती उसे थप्पड़ मार देती है। लेखिका लिखती हैं-

“सूरदास अंधेपन की मार सहते-सहते कितना सहिष्णु हो गया है।”⁵

शील कौशिक ने अपने साहित्य में पुरुष के धार्मिक पक्ष को दिखाने की भी कोशिश की है। वे अपनी लघु कथा 'जिद अच्छी है' में आज के पुरुष के धर्म के नियमों, परंपराओं के प्रति उसके दृष्टिकोण को

दिखाने की कोशिश करती हैं। आज का व्यक्ति इन परंपराओं को तोड़ता है। पुरानी रीति-रिवाजों में बदलाव करता है। इन बंधनों में खुद को बांधता नहीं है। बाबूजी जब श्राद्ध पक्ष में नए भवन की नींव रखने के लिए मना करते हैं तो उनका बेटा कहता है कि-

क्यों ठेकेदार भाई! श्राद्ध पक्ष तो बीती पीढ़ी को गौरव देने व पुनः स्मरण करने के दिन हैं, ये अशुभ कैसे हो सकते हैं? हमारे बड़े हमारा अहित कैसे होने दे सकते हैं? वे तो आशीर्वाद ही देंगे। हमारी खुशी में खुश होंगे.....

श्राद्धों में अपने साथ-साथ कई मजदूरों की रोजी-रोटी सुनिश्चित देख ठेकेदार ने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए।”⁶

निष्कर्षतः

हम कह सकते हैं शील कौशिक ने अपने साहित्य के माध्यम से पुरुष मनोविज्ञान का बहुत ही मार्मिक प्रयोग दर्शाया है तथा पुरुष के सामाजिक मनोविज्ञान, धार्मिक मनोविज्ञान को अपनी कविता और कहानियों के माध्यम से स्पष्ट करने में सफल रही हैं। शील कौशिक ने अपने साहित्य के माध्यम से पुरुष मनोविज्ञान के व्यक्तिक पक्ष को उद्घाटित किया है। किस प्रकार उसके मनोभावों से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है तथा उसका व्यक्तित्व समाज के सामने आता है। अतः हम कह सकते हैं कि शील कौशिक ने अपने साहित्य के माध्यम से पुरुष मनोविज्ञान के सभी पहलुओं का बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है।

संदर्भ सूची:

1. Woodworth, Psychology, The fundamental human adjustment P.16 (1942)
2. रघुनाथ सफाया- इंडिया साइकोलॉजी, पृष्ठ- 8
3. डॉ. शील कौशिक, एक सच यह भी, पृष्ठ- 69
4. डॉ. शील कौशिक, छूटा हुआ सामान, पृष्ठ- 41
5. डॉ. शील कौशिक, महक रिश्तों की, पृष्ठ- 87
6. डॉ. शील कौशिक, छूटा हुआ सामान, पृष्ठ- 33

हितेष कुमारी

शोधार्थी

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,

रोहतक

डॉ० प्रवेश कुमारी

सहायक प्राध्यापक

शोध निर्देशक

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,

रोहतक

सारांश :

पुनर्जागरण कालीन चेतना, स्वातंत्र्य संघर्ष, छायावादी रोमानियत और गांधीवादी मूल्यों के बीच बदलते मानवीय संबंधों की अभिव्यक्ति प्रेमचन्दकालीन साहित्य में हुई है। पुनर्जागरण के फलस्वरूप व्यक्ति और समाज में सुधारवादी भावना का प्रसार हुआ जिससे लोगों में जागृति आई और वे स्वतंत्रता के महत्व को समझने लगे जिसमें गांधी जी की भूमिका अविस्मरणीय है। उनके साथ देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक सभी प्रश्न एक ही संदर्भ से जुड़ गये और नेहरू जी के शब्दों में एक पंचरंगी जीवन दृष्टि विकसित होने लगी।

गांधी जी के साथ पहली बार स्त्री, बच्चे, बूढ़े और जवान सब एक साथ, एक स्वर में एक छत के नीचे व्यक्तिगत राग-द्वेष से परे आजादी के तराने गा रहे थे, एक-दूसरे का सहयोग कर रहे थे और आजादी को झपट लेने हेतु आतुर थे। लोग साधारण मनुष्य की छोटी-छोटी मांगों के साथ बिना लाग-लपेट और शब-सुबहा के एक-दूसरे का हाथ थामे मैदान में डटे थे और तब तक डटे रहे जब तक उन्होंने अपनी मांगे मनवा न ली, भले इसके लिए कड़ियों को अपने प्राणों तक गंवाने पड़े। कर्मभूमि की मुन्नी कहती है — “जम जमा करने को नहीं मांगते, न हमें भोग-विलास की इच्छा है, लेकिन पेट की रोटी और तन ढांकने को कपड़ा तो चाहिए। साल-भर खाने-पहनने को छोड़ दो, गृहस्थी का जो कुछ खरच पड़े वह दे दो, बाकी जितना बचे, उठा ले जाओ। मुदा गरीबों की कौन सुनता है? सरकार को देखो हाकिमों को तो अपने लिए बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, हर नियामत खाने को चाहिए, सैर तमाशा चाहिए, पर गरीबों का इतना सुख भी नहीं देखा जाता। जिसे देखो, गरीबों ही का रक्त चूसने को तैयार है।”

किसान-मजदूर की यह शाश्वत लालसा बदले हुए तेवर में तत्कालीन साहित्य-समाज में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। पर इससे मानवता के प्रति आस्था, सहयोग, समर्पण, प्रेम और विश्वास का भाव उनमें कम नहीं होता, वे विरोधियों को क्षमा करने का वही भाव रखते हैं, दूसरे की हार का जश्न नहीं मनाते और न ही अपनी विजय पर बातलें फोड़ते हैं और यह सब होता है तो इसलिए कि उनमें भारतीयता का संपूर्ण तत्व विद्यमान है और साथ ही गांधी जी का नेतृत्व प्राप्त है। गांधी जी महान प्रयोगवादी थे और उनके प्रयोगों का सबसे बड़ा लक्ष्य संपूर्ण मानव इतिहास की असफलताओं को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के स्वभावमें ही आमूल परिवर्तन लाना था। गांधी जी के पूर्व देश के सभी उन्नायकों की शक्ति में विलक्षणता थी लेकिन गांधी जी ने पहली बाबर साधारणता को आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया। साधारणता का यह दर्शन तत्कालीन भारत के लिए सबसे उपयोगी दर्शन था। भारतीय जनता ने

पहली बार यह अनुभव किया कि आदर्श अनुकरण करने की नहीं, उपलब्ध करने की वस्तु है। देश की सांस्कृतिक चेतना में यह बहुत बड़ी क्रांति थी।

गांधी जी ने इस दर्शन को सांस्कृतिक अर्थ दिया और राजनीति को सांस्कृतिक चेतना का अनिवार्य अंग बनाया। एक तरह से गांधी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन प्रेम का दर्शन है और इस क्रम में उन्होंने प्रेम का जो अर्थ दिया वह अलग, अलौकिक या अतिरिक्त न होकर जीवन जीने की एक स्वाभाविक तथा आंतरिक कला है। अहिंसा के अन्तर्गत गांधी जी ने जीवन की जो व्याख्या की उसी में उनकी प्रेम संबंधी अवधारणा भी पूरी तरह व्यक्त हो जाती है। गांधी जी के लिए स्त्री, अहिंसा, प्रेम और पीड़ा ये एक सीधी लकीर में विकसित होने वाली शक्तियाँ हैं। स्त्री अहिंसा का अवतार है। अहिंसा का अर्थ है असीम प्रेम और प्रेम का अर्थ है असीम कष्ट सहने की शक्ति।

इस परिभाषा के केन्द्र में प्रेम है जो कष्ट सहने की शक्ति तथा अहिंसा दोनों को परिभाषित करता है। प्रेम के बिना न तो अहिंसा संभव है न प्रेम के बिना कष्ट सहने की शक्ति ही आ सकती है। प्रेमी के लिए कष्ट सहने में जिस त्याग अथवा उत्सर्ग का संकेत है वही पीड़ा तथा अहिंसा इस प्रेम को सार्वजनिक बनाती है अर्थात् सबसे प्रेम और सबके लिए कष्ट सहने की शक्ति। प्रेम त्याग से ही पनपता है शुद्ध प्रेम देह का नहीं आत्मा का ही संभव है। देह का प्रेम विषय का ही है प्रेम की शक्ति वही है जो आत्मा पर सत्य की शक्ति है। प्रेम संबंधी इन विचारों का विश्लेषण करने पर गांधी जी की दृष्टि से प्रेम का कुछ ऐसा

स्वरूप सामने आता है — प्रेम का तात्पर्य है सत्य से प्रेम और सत्य उस आत्मा का ही प्रतिरूप है जो सबमें है। अर्थात् सच्चा प्रेम वह है जो सबसे हो, सबकी आत्मा से। इस प्रेम का तात्पर्य है सबके लिए कष्ट सहन करने तथा त्याग करने की असीम शक्ति। इन्हीं गुणों का मिला जुला रूप अहिंसा है।

गांधी जी प्रेम को एक घनात्मक वृत्ति मानते हैं, जिसका उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में आत्मिक एकता स्थापित करना और इसके लिए कष्ट सहन करके सामूहिक सुख की सृष्टि करना। पारस्परिक त्याग प्रेम को किसी प्रकार ऋणात्मक नहीं बनाता क्योंकि यह पारस्परिक आदान-प्रदान के द्वारा प्रेम को निरंतर गतिशील तथा संतुलित रखता है। इसके अलावा गांधी जी इस बात में विश्वास करते थे कि प्रेम मुख्यतः स्त्री गुण है क्योंकि प्रेम की क्षमता स्त्री में पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। अतः पुरुष के प्रेम में पूर्णता तभी आ सकती है जब वह स्त्री प्रेम को अपनाये। गांधी जी का आदर्श राम राज्य और अर्द्धनारीश्वर की कल्पना है। लेकिन स्त्री-पुरुष को गांधी जी सर्वथा

समान न मानकर पृथक मानते हैं। जहाँ मूल में स्त्री-पुरुष एक हैं वहाँ यह भी उतना ही सच है कि शरीर रचना की दृष्टि से दोनों में गहरा अंतर है। इसलिए दोनों का काम भी जुदा-जुदा होगा। प्रेम और नारी-पुरुष संबंधी दृष्टियों की यह साम्यता इस युग के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े कथाकार को एक धरातल पर खड़ा कर देती है "स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है, जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, वह सफल नहीं हो सका।" पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है जिसे वह इरादा करने भी हटा नहीं सकता। वही पशुता उसे पुरुष बनाती है।

विकास के क्रम से वह स्त्री से पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा वह भी स्त्री हो जाएगा। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया इन्हीं आधारों पर यह सृष्टि थमी हुई है और यह स्त्रियों के गुण हैं।²

गांधी युग और साथ-साथ प्रेमचन्द युग की सबसे बड़ी विशेषता नारियों का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश था जिससे वे पुरुषों के साथ जीवनप के व्यापक कमक्षेत्र में प्रवृत्त हुईं। सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का इतनी बड़ी संख्या में उतरना एक बहुत बड़ी घटना थी और इसने जहाँ आजादी के आंदोलन को तीव्रता प्रदान की वहीं सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन में अनेक जटिलतायें भी उत्पन्न कीं। यहाँ तक कि गांधी जी के आश्रम भी इन जटिलताओं से बच नहीं सके। खुले प्रकाश में एक ही लक्ष्य की ओर उन्मुखा होकर साथ-साथ काम करते हुए स्त्री-पुरुष के संबंधों के नये-नये आयाम उद्घाटित होने लगे।

हिन्दी उपन्यास साहित्य के लिए यह अपूर्व अवसर था। अभी तक उपन्यासों में केवल अधूरा पुरुष या अधूरी स्त्री देखने को मिली थी। स्त्रियों के तेजी से घर से बाहर निकलने तथा पुरुषों के साथ आजादी के आंदोलन में कूद पड़ने की इस गति ने संबंधों में एक गहरी हलचल पैदा कर दी। सारे संबंधों में एक नई ऐंठन, तनाव और द्वन्द्व उत्पन्न हो गया था। जहाँ हर पढ़ी-लिखी औरत यह महसूस कर रही थी कि उसका क्षेत्र और लक्ष्य गहने गढ़ाने, सास-श्वसुर की सेवा करने और बच्चे पैदा करने के अलावा भी कुछ है। हर पति यह अनुभव कर रहा था कि उसे अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, बीबी-बच्चे और सुख-सम्पत्ति के अलावा कुछ और चाहिए। प्रत्येक संबंध अपनी पारंपरिक सीमाओं का अतिक्रमण कर आधुनिक भाव-बोध से संपृक्त हो रहे थे।

हिन्दी उपन्यासों के सामने अपार रचनात्मकता से परिपूर्ण यह अभूतपूर्व अवसर था जिसका प्रेमचन्द और उनके समकालीनों ने पर्याप्त उपयोग किया। प्रेम के व्यापक क्षेत्र को प्रेमचन्द के समकालीन उपन्यासकारों ने न सिर्फ अपने उपन्यासों का विषय बनाया अपितु गहराई में जाकर संबंधों की युगसापेक्ष अनुभूतियों को चित्रित कर नई

परिभाषायें गढ़ीं। इनकी प्रेमधारणा एक तरफ परंपरा की कड़ियों को जोड़ते हुए त्याग, करुणा, ममत्व, विश्वास, समर्पण के महत्व को निरूपित करती हैं तो दूसरी तरफ भोग, विलास, स्वच्छन्दता, विश्वासघात से टूटते मानवीय संबंध और समाज में फैलते व्यभिचार को प्रतिबिम्बित करती है।

इस युग के प्रसिद्ध उपन्यासकारों की मनोवृत्तियाँ प्रेम के जिस रूप को ग्रहण करती थीं, उसी की युगानुरूप अभिव्यक्ति उनके उपन्यासों में दिखाई पड़ती है। प्रेमचन्द, प्रसाद और उग्र काशी में एक ही समय सक्रिय थे। ये तीनों विभिन्न मनोवृत्तियों के लेखक थे। उपन्यासकार के तौर पर प्रेमचन्द यदि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के पोषक थे तो प्रसाद कंकाल में नग्न यथार्थवाद के चितरे के रूप में सामने आते हैं। उनका 'तितली' नामक उपन्यास अवश्य ही प्रेमचन्द की परंपरा में लिखा गया था

किन्तु अधूरी इरावती पुनः धर्म में निहित पाप के उद्घाटन की दिशा में कंकाल की तरह ही सचेष्ट है। प्रेमचन्द प्रेम के सात्विक एवं मर्यादित रूप को व्यक्त करते हैं किन्तु कंकाल की 'गाला' या 'घंटी' स्वच्छंदतावादी प्रेम की पुतलियां हैं। तितली की 'शैला' की तुलना रंगभूमि की 'सोफिया' से की जा सकती है। इसी तरह प्रसाद की 'मैना' प्रेमचन्द की वार वनिताओं की परंपरा में आती है पर जोहरा का प्रेम और त्याग मैना में कहाँ? प्रेमचन्द के पात्र जहाँ प्रेम में सर्वस्व समर्पित कर प्रेमी के कल्याण में प्रवृत्त हैं वहीं प्रसाद के पात्र जीवन के द्वन्द्व में जूझते दिखाई पड़ते हैं। "क्या मैं सचमुच इन्द्रदेव को प्यार करती हूँ? मैं उतना ही कर सकती हूँ जितना मधुबन के लिए तितली कर रही है।

उसके भीतर से जैसे किसी ने कहा 'ना'! वह अपनी नग्न मूर्ति देखकर भयभीत हो गई। उसने चारों ओर अवलम्ब खोजने के लिए आंख उठाकर देखा। ओह! वह कितनी दुर्बल है।"³

शैला अपने द्वन्द्व को तितली से खोलकर कहती है क्योंकि तितली उसकी तथा प्रसाद जी की दृष्टि में आदर्श नारी तथा आदर्श प्रेम का उदाहरण है। "न जाने क्यों मेरे मन में ऐसी भावना उठती है कि मुझे, मैं जैसी हूँ उसी रूप में स्नेह करने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं। कुछ न कुछ दूसरा आवरण लोग चाहते हैं।" इन्द्रदेव के सम्बन्ध में वह तितली से कहती है — "उनका समर्पण इतना निरीह है कि मैं जैसे बर्फ की सी शीतलता में चारों ओर से घिर जाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह का दान कर देना नहीं सीख सकी। मैं जैसे और कुछ उपकरणों से बनी हूँ।" शैला के लिए प्रेम एक समस्या है — वह दया, सहानुभूति तथा सुरक्षा को प्रेम के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। फिर प्रेम क्या है? शैला उसी की तलाश में पीड़ित रहती है। प्रेम के जिस अंतराल विहीन एकत्व तथा आत्मविस्मृति की कल्पना वह करती है वह न तो इन्द्रदेव से मिलता है न वाटसन से और न मानव कल्याण की उस भावना से जिससे प्रेरित होकर वह भारत आई है।

प्रेमचन्द और प्रसाद दोनों जातिमुक्त प्रेम के पक्षधर

हैं किन्तु, प्रेमचन्द जहाँ सामाजिक सरोकारों की अधिक परवाह करते हैं वहाँ प्रसाद लक्ष्मण-रेखा के उल्लंघन से हिचकते नहीं हैं। वे प्रेमचन्द से अधिक स्वच्छंदतावादी प्रतीत होते हैं। प्रेम में शारीरिकता प्रसाद के लिए प्रेमचन्द की तरह वर्जना का विषय नहीं। लेकिन साम्प्रदायिक तर्कों का सहारा लेकर वे प्रेम को एक ओर मानव कल्याण के नाम पर अमूर्त बना देते हैं और दूसरी ओर प्रेम का सहारा लेकर वे एक स्थापित व्यवस्था और संस्कृति से समझौते कराते हैं। उन्हें साम्प्रदायिक समन्वय भारतीय धर्म तथा पुरुष की श्रेष्ठता के साथ ही स्वीकार है। नारी का गौरव गान अमूर्त स्तर पर ही है जबकि व्यावहारिक स्तर पर पुरुष के प्रति स्त्री का पूर्ण समर्पण तथा त्याग ही उनका चरम लक्ष्य बना रहता है। प्रेमचन्द और प्रसाद की तुलना में उपन्यासकार उग्र, अधिक बेबाक, स्वच्छन्द और नग्न यथार्थवाद के समर्थक के रूप में सामने आते हैं। जिस तरह हिन्दी कथा साहित्य में प्रेमचन्द एवं प्रसाद के नामों पर पृथक-पृथक निकायों की चर्चा होती है उसी तरह उग्र के नाम पर भी एक स्कूल का उल्लेख होता है। बुधुवा की बेटी, चन्द हसीनों के खतूत, घंटा आदि अनेक उपन्यासों में उग्र के प्रकृतवाद की सपाट अभिव्यक्ति हुई है। वे हिन्दी में एमिल जोला, मोपांसा, फ्रावेल आदि की परंपरा को यत्किंचित अवतरित करते दिखाई पड़ते हैं। वे प्रेम का आध्यात्मिकरण नहीं करते बल्कि उनके यहाँ वासना और प्रेम की सीमारेखायें बनती बिगड़ती रहती हैं। वे विनय और सोफिया के मनोमय प्रेम से आगे जाकर दैहिक वासना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उग्र ने वेश्या को केन्द्र बनाकर उसे जटिल रूप में दिखाने का प्रयास 'शराबी' में किया है। लेकिन प्रेम की जटिल मानसिकता का साक्षात् करने की दृष्टि से उपन्यास संभावनाहीन है। इसमें यथार्थवादी उग्र आदर्शोन्मुख प्रेमचन्द से सुधारवादी नैतिकता में कहीं अधिक बढ़े-चढ़े दिखाई पड़ते हैं। अंतर सिर्फ यह है कि प्रेमचन्द की सुमन वेश्यावृत्ति त्यागकर सेवा का व्रत ले लेती है और उग्र की जवाहर मानिक की जवांमर्दी के सहारे उसकी घरवाली बन जाती है। उग्र जी जवाहर को वैरागिनी बनाना नहीं चाहते और अपनी बाल प्रेमिका हीरा से बिछुड़ा हुआ मानिक वेश्या जवाहर से विवाह कर सामाजिक विद्रोह की दिशा में पहल करता है। उग्र का सुधारवादी पक्ष इतना प्रबल है कि जवाहर से विवाह करते ही शराबी मानिक सच्चरित्र तथा सद्गृहस्थ बन जाता है। "मानिक लाल अब कई महीने से सारे शहर में बदनाम होता हुआ भी शरीफ हो गया है। वह अब न तो आवारा दोस्तों के साथ शहर की सफेद-काली गलियों में चक्कर लगाता है और न पियक्कड़ों की तरह पीकर इधर-उधर लुच्चई करता है।"⁵

उग्र का दृष्टिकोण नायकत्वपूर्ण है और मानिक - जवाहर के प्रेम में शौर्यपूर्ण प्रेम की परम्परा काम करती है। मानिक गोली खाकर भी जवाहर का उस बदनाम कूचे से हरण कर लेता है। इस साहसिक प्रेम को उग्र जी ने सुधारवादी चासनी में पाग दिया है। इसी कारण मानिक अपनी बाल-प्रेमिका हीरा को उसके पति की मृत्यु के बाद प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता बल्कि वेश्या से विवाह कर एक

पतिता का उद्धार करता है।

वेश्या को केन्द्र में रखकर प्रेमचन्द युग में जिस उपन्यास की सर्वाधिक ख्याति हुई वह 'चित्रलेखा' है। पाप और पुण्य के शाश्वत प्रश्नों से जूझते प्रेम के जिस रूप की अभिव्यंजना इस उपन्यास में हुई है वह पाठकों का ध्यान बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। सभ्यता के आरम्भ से लेकर अब तक मनुष्य ने प्रेम की प्राप्ति हेतु प्रयास किये हैं। वह विधनों से खेला है और आद्यन्त प्रेम ही उसका लक्ष्य रहा है। एक-दूसरे से प्रगाढ़ सहानुभूति और एक-दूसरे के अस्तित्व को एक कर देना ही प्रेम है, जीवन का सर्व-सुन्दर लक्ष्य है। बीजगुप्त अपनी प्रेमिका चित्र लेखा से कहता है —

"प्रेम एक-दूसरे के भेद-भाव को नहीं देखता, प्रेम दो हृदयों की अभिन्नता का द्योतक है।"⁶ हृदय की इसी अभिन्नता का प्रयास प्रेमचन्द के समकालीन उपन्यासकारों का लक्ष्य रहा है और संभवतः मानव जाति का भी। प्रताप नारायण श्रीवास्तव की 'विदा' में पुरुष-स्त्री संबंध की समस्या विश्वविद्यालय में दर्शन के रीडर निर्मल सिन्हा तथा कुमुदिनी के वैवाहिक जीवन को लेकर उठायी गयी है। निर्मल का ख्याल है कि वे कुमुदिनी को प्राणों से बढ़कर प्यार करते हैं — "क्या मैं कुमुद को प्यार करता हूँ? हाँ अपने प्राणों से भी बढ़कर।" लेकिन उनका यह भी ख्याल है कि "स्त्री का प्रेम वासनापूर्ण होता है और केवल मातृप्रेम शुद्ध सात्विक और निःस्वार्थ होता है। प्रेम तथा पत्नी को महत्व देते हुए भी उसके प्रेम को वासनापूर्ण मानना अविकसित मस्तिष्क की ही धारणा हो सकती है जिसे उपन्यास में गौरवान्वित किया गया है। दूसरी ओर कुमुदिनी सोचती है — "मैं उन्हें प्यार करती हूँ, अपने से भी अधिक प्यार करती हूँ। दिन रात उनका ही प्रतिबिम्ब मेरे सम्मुख रहता है, उनके लिए मैं जान देने को तैयार हूँ। लेकिनलेकिन मैं अपने को नत नहीं कर सकती।"⁸

प्रताप नारायण ने चाहे स्पष्ट न लिखा हो लेकिन स्त्री के इस नत न होने वाले व्यक्तित्व के लिए वे आधुनिक शिक्षा को उत्तरदायी मानते हैं। उनके लिए इसका उत्तरदायी क्राइस्ट चर्च कॉलेज है जहाँ कुमुदिनी ने पश्चिमी संस्कारों की शिक्षा प्राप्त की है। अर्थात् स्त्री शिक्षित हो, स्वतंत्र हो लेकिन पश्चिम का अनुकरण करके नहीं - पूर्वी संस्कारों और भारतीय परंपरा की शिक्षा प्राप्त करके। पुरुष और स्त्री की समानता का प्रश्न उपन्यास की दूसरी नायिका चपला भी उठाती है — "सच्ची स्त्री की स्वाधीनता वहाँ है जहाँ स्त्री पर अत्याचार न हो। स्त्री-पुरुष दोनों एक होकर रहें। दोनों में मतभेद न होने पावेस्त्री घर की मालकिन हो और पुरुष बाहर का। लेकिन दोनों में मतैक्य हो। दोनों उस पवित्र प्रेम-सूत्र में बंधें हों जहाँ न राग है, न अभिमान है, न द्वेष है और न कलह। असीम शांति है, अनन्त प्रेम है। स्त्रियाँ इतनी स्वतंत्र हों कि वे हर एक से मिल सकें, अपनी रक्षा कर सकें, खूब शिक्षा प्राप्त कर सकें। समय पड़े तो अपनी जीविका का प्रबन्ध भी कर सकें। वे इतनी

स्वतंत्र हों कि अगर पुरुष उन पर अत्याचार करे तो वे उसका प्रतिकार भी कर सकें। इतनी स्वाधीन हों कि अपने वर के संबंध में अपना मत दे सकें। लेकिन इतना नहीं कि वे गली-गली मारी फिर कर अपना स्वामी आप चुनें। मेरा तो विचार है कि एक स्त्री के स्वामी चुनने का भार उसके पिता पर ही होना चाहिए लेकिन उसकी भी राय हो। अगर वह नापसंद करती है तो उसके लिए दूसरा वर चुना जाए।⁹

नारी जागरण का यह स्वर और समानता की उसकी आदिम आकांक्षा पुनर्जागरण के इस दौर में कई उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र — राजनीति, शिक्षा, अर्थ में वे पुरुष का साथ दे रही थीं और उनके समान अधिकार चाहती थीं तो इसमें गलत क्या था। प्रेम में अभिमान नहीं होता, अपनी इच्छा, मान, अहं को विसर्जित कर ही प्रेम पाया जा सकता है और यही इस उपन्यास का लक्ष्य है। चपला अपनी सखी कुमुदिनी के प्यार को छीनना नहीं चाहती, वह निर्मल से प्यार करती है और निर्मल कुमुदिनी का पति है। इसलिए वह निर्णय लेती है कि विवाह नहीं करेगी। “मैं देशसेवा करना चाहती हूँ हमारी बहनों की दशा बड़ी खराब है। उन्हें देखकर मुझे नींद नहीं आती, खाना नहीं हजम होता मैं विवाह नहीं करूंगी।”¹⁰

निर्मल के लिए प्रेम भक्ति है — प्रेम का अंतिम रूप भक्ति है। पहले मनुष्य किसी की ओर आकर्षित होता है, यह शुद्ध आकर्षण है, आकर्षण मोह में बदलता है, मोह अनुराग में, अनुराग प्रेम में और प्रेम भक्ति में। भक्ति में पाप नहीं होता, सन्देह नहीं होता, वासना नहीं होती। केवल असीम, अखंड, निःस्वार्थ प्रेम होता है।¹¹ यही विदा के प्रेम का चरम आदर्श है। सियाराम शरण गुप्त की ‘नारी’ की प्रेम धारणा गांधीवादी प्रेम धारणा के आत्मपीड़क पक्ष पर आधारित है। उपन्यास में जिन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है वे भावना निर्मित कर्तव्यों के आदर्श हैं। कथानक भारतीय नारी से जुड़ा है। भारत की अकेली नारी क्या करे? चाहे वह विधवा हो, परित्यक्ता हो या अविवाहिता हो — समाज उसे पुरुष से अलग अकेले रहने की कितनी स्वतंत्रता या सुरक्षा देता है? उसे स्वतंत्र वरण की या प्राकृतिक आवश्यकताओं की परितृप्ति की कितनी छूट है? गांधी जी यौन भावना को प्राकृतिक नहीं मानते — उनकी दृष्टि में यह मानव के लिए एक पाप है चाहे आवश्यक पाप ही क्यों न हो। अतः उस पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो उसका उदात्तीकरण आवश्यक है। लेकिन उदात्तीकरण के लिए भी संबंध आवश्यक है और रूढ़िवादी नैतिकता संबंधों के द्वार भी बन्द कर देती है। जमना अपने पुत्र (हल्ली) के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य को ध्यान में रखकर अपनी भावनाओं का उदात्तीकरण करती है — लेकिन अपने हृदय को वह सामान्य तथा सहज मानवीय संबंध के लिए खुला रखती है। इस संबंध का आधार अजित है। रूढ़िवादी सामाजिक मान्यतायें, हल्ली और अजित — इन सबके बीच जमना का नारीत्व परीक्षा की चरम स्थितियों से गुजरता है लेकिन वह अविजित रहती है।

निराला की ‘अप्सरा’ प्रणय एवं राष्ट्र प्रेम को आदर्श रूप में

मानवीय धरातल पर प्रस्तुत करती है जबकि अलका यथार्थ की मनोभूमि पर उतरकर प्रेम को अभिव्यजित करती है। उनके प्रारंभिक इन दोनों उपन्यासों में प्रेम की सुधारवादी प्रवृत्तियाँ हैं जिनमें औपन्यासिक नाटकीयता के साथ वेश्यापुत्री का प्रेम (अप्सरा) तथा पति-पत्नी का प्रेम चित्रित किया गया है। निराला के अपेक्षाकृत प्रौढ़ उपन्यास ‘निरूपमा’ में प्रेम का प्रखर रूप दिखाई पड़ता है। इस पर शरतचन्द्र के उपन्यासों का भीहल्का सा प्रभाव है। सुख-सुविधाओं के बीच पली हुई धनी युवती निरूपमा आर्थिक दृष्टि से विपन्न लेकिन बौद्धिक दृष्टि से तेजस्वी युवक कृष्णकुमार की ओर आकर्षित होती है। यह प्रेम वर्गीय विषमता की दरारें भरने की कोशिश में सचेष्ट है। निराला के उपन्यासों में प्रेम का स्वच्छन्दतावादी रूप प्रखरता से अभिव्यक्त हुआ है। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने ‘माँ’ और भिखारिणी उपन्यासों में प्रेमचन्द की परंपरा का निर्वहन किया जबकि चतुरसेन शास्त्री ‘हृदय की परख’, ‘हृदय की प्यास’, ‘अमर-अभिलाषा’ और ‘आत्मदाह’

षीर्षक उपन्यासों में प्रेमचन्द से प्रभावित होते हुए भी अपनी एक अलग राह निकालते हैं जिससे प्रेम को नई दिशा प्राप्त होती है। ऋषभचरण जैन ने उग्र की भांति तत्कालीन समाज के वर्जित विषयों पर ‘दिल्ली का कलंक’, ‘दिल्ली का व्यभिचार’, ‘वेश्यापुत्र’, ‘रहस्यमयी’ आदि उपन्यासों की रचना की जिसमें शहरों में व्याप्त प्रेम का खोखला और धिनौना रूप उजागर होता है। भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यासों — प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, लालिमा आदि में मध्यवर्गीय पारिवारिक — सामाजिक जीवन का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण मिलता है। अपने पात्रों के संदर्भ में जीवन की उपलब्धियों — अनुपलब्धियों का तटस्थ, व्यावहारिक और कहीं-कहीं भावुकतापूर्ण प्रस्तुतिकरण उनकी उल्लेखनीय विशेषतायें हैं। जैनेन्द्र और इलाचन्द्र जोशी भी प्रेमचन्द युग में लिखना शुरू कर चुके थे। जैनेन्द्र की ‘परख’ और इलाचन्द्र जोशी की ‘घृणामयी’ या लज्जा ने उस युग में प्रेम की कुछ बन्द खिड़कियों को खोलने का काम किया। इनमें प्रेमचन्द, प्रसाद और उग्र आदि के द्वारा वर्णित प्रेम की विशेषताओं के समाहार का प्रयत्न दिखलाई पड़ता है। परख की ‘कट्टो’ प्रेम की मासूमियत को व्यक्त करती है किन्तु उसमें मनोवैज्ञानिक उतार-चढ़ाव भी दृष्टिगत होता है। ‘कट्टो’ के माध्यम से जैनेन्द्र प्रेम की उस धारणा की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं जो यह मानती है कि प्रेम विश्वास और उत्सर्ग की वस्तु है — छल, प्रपंच और चतुराई से अलग। ‘सत्यधन’ इसमें पीछे रह जाता है। गांव की भोली किशोरी कट्टो ही पारंगत सिद्ध होती है। वह बिहारी को उसी तरह का प्रेम-पाठ पढ़ाती है जैसा पाठ शताब्दियों पूर्व सूर की गोपियाँ उद्धव को पढ़ा चुकी थी।

प्रेम, विवाह, शारीरिकता और समर्पण के बीच द्वन्द्व की संरचना जैनेन्द्र की विशेषतायें हैं। प्रेम किसी से, विवाह किसी से, और जिससे विवाह उससे प्रायः अशरीरी संबंध यह जैनेन्द्र के बुद्धि विरोधी अभियान हैं। प्रेम विवशता नहीं, चयन है। और जब चयन

कर लिया तो तन और मन की दूरी क्यों। अतः शारीरिक समर्पण प्रेम की कुंजी है इसका प्रथम दर्शन जैनेन्द्र में मिलता है।

इलाचन्द्र जोशी अपने उपन्यासों में प्रेम की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने वाले सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने स्पष्टतः मनोवैज्ञानिक समस्याओं को आधार बनाकर अपने चरित्रों तथा कथानकों की सृष्टि की है। उनके उपन्यासों में जिस प्रेम की सृष्टि हुई है उसमें अहम् भाव प्रधान है और वह पुरुष पात्र में स्थित होता है। स्त्री उसका शिकार होकर प्रेम की पीड़ा भोगती है और पुरुष स्वयं अपने अहं की आग में जलकर भस्म हो जाता है। अतः मूलतः यह अहम् ही होता है जो पुरुष से प्रेम और यौन आकर्षण का अभिनय कराता है। इस प्रकार जोशी जी पुरुष-स्त्री संबंध की समस्या को चिरंतन अहं भाव की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करते हैं। इसके मूल में पुरुष की हीनता ग्रंथि होती है। वे प्रेम के माध्यम से पुरुष के शोषक तथा स्त्री के शोषित रूप को ही उपस्थित करते हैं। उनकी 'घृणामयी' अहं, समाज, प्रेम और वासना के टकरावों को मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के द्वारा पेश करती है।

प्रेमचन्द्र का प्रेम दर्शन बहुआयामी है। उसमें राष्ट्रप्रेम, मनोमय प्रेम (प्लेटोनिक लव), पारिवारिक प्रेम और संपूर्ण चराचर के प्रति प्रसरणशील प्रेम की वैविध्यपूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। प्रसाद के प्रेम दर्शन में उदात्त और अनुदात्त दोनों के रंग मिलते हैं। उग्र में वीभत्सता और नग्नता की स्थिति मिलती है। जैनेन्द्र और इलाचन्द्र जोशी में मनोवैज्ञानिकता अधिक है। प्रेमचन्द्र में प्रेम विषयक दृष्टि कोण का उत्तरोत्तर विकास और परिमार्जन हुआ है। 'सोजे वतन' म राष्ट्रप्रेम और वैयक्तिक प्रेम तथा वासना एवं साधना का जो संघर्ष प्रारंभ होता है वह निरंतर नई-नई दिशाओं का अन्वेषण करता है। 'प्रेम की वेदी' शीर्षक नाटक तक आते-आते प्रेमचन्द्र आधुनिक प्रेम का भी विश्लेषण करने लगते हैं। उनके गाँदान में प्रेम की विविध छवियाँ दिखलाई पड़ती हैं। दुलारी सहुआइन एवं होरी के अद्वैतिक निगूढ प्रेम, झुनिया और गोबर के साहसिक प्रेम, सीलिया और मातादीन के घात-प्रतिघातमूलक किन्तु अंततः समर्पणमूलक प्रेम तथा मालती मेहता के आकर्षण-विकर्षणमूलक प्रेम की अनेक छवियाँ गोदान के एलबम में देखी जा सकती हैं।

निष्कर्ष:

उपन्यासकार प्रेमचन्द्र प्रेम की जैसी विराट व्याख्या करते हैं वैसी उपन्यासकार प्रसाद एवं उग्र नहीं कर पाते। प्रसाद की कविताओं, कहानियों एवं नाटकों में प्रेम का विस्तृत निरूपण हुआ है किन्तु उनके उपन्यासों में ऐसा संभव नहीं हो पाया है। उग्र का प्रेम-चित्रण नग्नता से जुड़कर भी प्रेमचन्द्रयुगीन आदर्शवाद को ध्वस्त नहीं कर पाता है। प्रेमचन्द्र जिस वफा और सेवा और त्याग को प्रेम की भित्ति मानते हैं उससे प्रसाद, उग्र या अन्य समकालीन उपन्यासकार भी असहमत नहीं हैं। उनके साहित्य में चित्रित कई प्रेमिकायें आदर्श का परिपोषण करती हैं। वहाँ वेश्यायें भी सतीत्व दर्शित करती हैं। निष्कर्षतः प्रेमचन्द्र युग द्विवेदीयुगीन मर्यादावाद, गांधीयुगीन सत्य एवं

अहिंसावाद तथा छायावादयुगीन स्वच्छन्दतावाद के बीच विकसित हुआ है। द्विवेदीयुगीन सदाचार और छायावादकालीन भावात्मक जीवन मूल्यों एवं यथास्थिति से टकराने की मनोवृत्ति को प्रेमचन्द्र एवं उनके समकालीन उपन्यासकार एक साथ प्रतिबिम्बित करते हैं जिसमें प्रेम की भूमिका सर्वकल्याणकारी है।

अतः प्रेमचन्द्र के समकालीन उपन्यासकारों की प्रेम धारणा समाज के अंतरंग संबंधों से रस ग्रहण करते तत्कालीन आंदोलनों से प्रेरित युग के कदमों की चाप है।

संदर्भ-संकेत :

1. कर्मभूमि, प्रेमचन्द्र, पृ0 203
2. गोदान, प्रेमचन्द्र, पृ0 142, कर्मभूमि, पृ0 135
3. तितली, प्रसाद, पृ0 241
4. वही, पृ0 249
5. शराबी, उग्र, पृ0 198
6. चित्रलेखा, भगवतीचरण वर्मा, पृ0 104
7. विदा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पृ0 48-49
8. वही, पृ0 187
9. वही, पृ0 183-184
10. वही, पृ0 214-220
11. वही, पृ0 274

चन्द्रमणि किशोर

(एम0ए0 हिन्दी, लब्ध स्वर्णपदक प्राप्त)

शोध छात्र, हिन्दी विभाग,

राँची विश्वविद्यालय, राँची

सचल भाष : 917979852019

Chandramanikishore@gmail.com

सारांश:-

प्रस्तुत शोध पत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में महिला सशक्तिकरण की क्या भूमिका है बताया गया है कि हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में लड़कियों की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि उनके साथ लड़कों के बराबर व्यवहार नहीं किया जाता, पोषण में कमी होती है और प्राथमिक स्तर तक भी उन्हें अपनी शिक्षा पूरी नहीं करने दी जाती। कन्या भ्रूण हत्या बड़े पैमाने पर होती है और जन्म लेने वाली लड़कियों की जीवित रहने की दर भी लड़कों की तुलना में बहुत कम होती है। इसे दूर करने के लिए बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता थी जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बीबीबीपी अभियान शुरू किया गया था। इससे निकट भविष्य में भारत को महाशक्ति बनने का दर्जा हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। बीबीबीपी अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से की थी क्योंकि यह देश में सबसे कम सीएस आर वाले जिलों में से एक था। इस कार्यक्रम को पीएम ने 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया था।

मुख्य शब्द: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण

भूमिका:

बीबीबीपी अभियान के साथ-साथ बालिकाओं की समग्र प्रगति के वित्तीय पहलुओं की देखभाल के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के खर्चों को कवर करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू की गई थी। सीएसआर 1991 में 945 से गिरकर 2011 में 918 हो गया था जो एक बहुत ही चिंताजनक बात थी। मामलों के राज्य शुरुआत में बीबीबीपी अभियान 100 जिलों में शुरू किया गया था जिसे अब देश के सभी 640 जिलों तक बढ़ा दिया गया है। बीबीबीपी अभियान बालिकाओं के लिए बेहतर सुरक्षा, पोषण और शिक्षा सुनिश्चित करके बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विस्तृत दिशा निर्देश सुनियोजित उद्देश्यों, लक्ष्य समूहों और विभिन्न मंत्रालयों और प्रशासनिक मशीनरी के बीच बेहतर समन्वय को सूचीबद्ध करते हैं जो इसे प्रभावी बना रहे हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य लड़कियों के लिए जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक सेवाओं की प्रभावशीलता में सुधार करना है। 22 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम (बेटियाँ बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना) शुरू की। 2011 की जनगणना के अनुसार, हरियाणा राज्य कम लिंगानुपात का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि 2011 में 0-6 वर्ष की आयु के बीच प्रति 1000

लड़कों पर लड़कियों की संख्या के रूप में परिभाषित बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट चोंकाने वाली है। सीएसआर में गिरावट महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख संकेतक है। सीएसआर दोनों को दर्शाता है, पक्षपात पूर्ण लिंगवाद द्वारा विशेषता जन्मपूर्व भेदभाव, और जन्म के बाद लड़कियों के खिलाफ भेदभाव। सामाजिक संरचना एक ओर लड़कियों के प्रतिभेद भावकर रही है, दूसरी ओर निदान उपकरणों की आसान पहुंच, पहुंच और उसके बाद दुरुपयोग, 1961 से निरंतर जारी है। 1991 में 945 से घटकर 2001 में 927 और आगे भी गिरावट आई है। 918 लड़कियों के लिंग चयनात्मक उन्मूलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है जिससे बाल लिंग अनुपात कम हो गया है। मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, बेटों को प्राथमिकता और बेटियों के प्रति भेदभाव ने समस्या को बढ़ा दिया है। बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एटोस और लचीले प्रयासों की आवश्यकता के साथ, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की घोषणा की है। यह एक राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से किया गया था और देश भर के 100 चयनित जिलों में बहुक्षेत्रीय गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जहां सीएसआर कम था। यह नोडल मंत्रालय के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एकत्रि-मंत्रालयी प्रयास है। इसलिए हमारे देश की भलाई के लिए उन्हें समान अधिकार देकर सशक्त बनाना आवश्यक है ताकि वे बिना किसी भेदभाव के स्वस्थ जीवन जी सकें। इसी दृष्टिकोण के साथ समाज में जन जागरूकता बढ़ाने या बालिकाओं को बचाने और शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और क्षेत्रीय स्तर पर बीबीबीपी अभियान शुरू किया गया है। इससे लड़कियाँ स्वतंत्र और आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगी।

तालिका 1.1

भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात 2001 से 2011 तक प्रति हजार पुरुषों पर स्त्री व 0-6 वर्ष के बच्चियों का लिंगानुपात

क्र.सं.	राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश	2011 जनगणना		2001 जनगणना	
		लिंगानुपात	0-6 वर्ष की बच्चियों का लिंगानुपात	लिंगानुपात	0-6 वर्ष की बच्चियों का लिंगानुपात
1	भारत	943	918	933	927
2	केरल	1084	964	1058	960
3	पुडुचेरी	1037	967	1001	967
4	तमिलनाडु	996	943	987	942
5	आंध्रप्रदेश	993	939	987	942
6	छत्तीसगढ़	991	969	989	975
7	महाराष्ट्र	989	970	972	973
8	मणिपुर	985	930	974	957
9	उड़ीसा	979	941	972	953
10	मिजोरम	976	970	935	964
11	गोवा	973	942	961	938
12	कर्नाटक	973	948	985	948
13	हिमाचल प्रदेश	972	959	968	956
14	उत्तराखण्ड	963	890	962	908
15	त्रिपुरा	960	957	948	968
16	असम	958	962	935	965
17	पश्चिम बंगाल	950	956	934	960
18	झारखण्ड	948	948	941	965

19	उत्तरांचल	946	911	948	959
20	अरुणाचल प्रदेश	938	972	893	964
21	नागालैण्ड	931	943	900	964
22	मध्यप्रदेश	931	918	919	932
23	महाराष्ट्र	929	894	922	913
24	राजस्थान	928	888	921	909
25	गुजरात	919	890	920	883
26	बिहार	918	935	919	883
27	उत्तर प्रदेश	912	902	898	916
28	पंजाब	895	846	878	798
29	सिक्किम	890	957	875	963
30	जम्मू व कश्मीर	889	862	892	941
31	हरियाणा	879	834	861	819
32	अण्डमान एंव निकोबार द्वीप समूह	876	968	846	957
33	दिल्ली	868	871	821	868
34	चण्डीगढ़	818	880	777	845
35	वाकर और नगर हवेली	774	926	812	979
36	ममन और दीव	918	904	710	926

स्रोत : जनसांख्यिकी 2011 के अनुसार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश में पुरुष-स्त्री अनुपात चिंताजनक है। यह देश के सामने एक गंभीर चुनौती है। वर्ष 2001 से लेकर 2011 तक की सभी स्त्री-पुरुष अनुपात के बीचमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई, लेकिन अभी भी देश में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जनगणना 2011 से पता चलता है कि कुल 36 में से 6 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात 2001 की जनगणना की तुलना में कम है जबकि 0-6 वर्ष की बच्चियों के लिंगानुपात में अत्यधिक गिरावट आई है। वर्ष 2001 में कुल जनसंख्याको 16 प्रतिशत बच्चों 0-6 आयुवर्ग के थे लेकिन जनगणना 2011 में इनकी संख्या घटकर 13 प्रतिशत हो गई जो प्रत्येक 1000 बालको की तुलना में 918 बालिकाओं के साथ ही न्यूनतम स्तर पर है।

30 में से 20 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में यह स्तर 2001 की जनगणना की तुलना में कम हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार (प्रत्येक 1000 बालकों की तुलना में बालिका) अरुणाचल प्रदेश में यह स्तर अधिकतम 972, तथा हरियाणा में यह स्तर सबसे न्यूनतम 834 पर है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मंडीगढ़, राजस्थान, उत्तराखण्ड, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रत्येक 1000 बालकों की तुलना में 900 से कम बालिकाओं की संख्या दर्ज की गई है। इसी प्रकार जनगणना 2011 के अनुसार 0-6 वर्ष की आयु समूह में बच्चों की संख्या 158.8 मिलियन है। 2001 में दर्ज की गई संख्या के लगभग मिलियन कम है वर्ष 2011 में इस 166.8 मिलियन में ग्रामीण बच्चों की आबादी 117.6 मिलियन और शहरी की आबादी 41.2 मिलियन दर्ज की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 8.9 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई है। जबकि शहरी क्षेत्र में 39 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे तो गिरते हुए लिंगानुपात की समस्या देशव्यापी है परंतु हरियाणा राज्य लिंगानुपात के मामले में बेहद संवेदनशील स्तर पर है। हरियाणा राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं तथा 0-4 आयु वर्ग समूह के अनुसार महज 830 लड़कियां हैं सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य में हरियाणा पांचवें स्थान पर है। हरियाणा से कम लिंगानुपात वाले नगर और दीवदादन और नगर हवेली, चंडीगढ़ और दिल्ली में है यह सभी केन्द्र शासित प्रदेश राजधानी है अगर देश के राज्यों की स्थिति देखे तो हरियाणा राज्य सबसे पीछे है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में लिंगानुपात की स्थिति को निम्न द्वारा देखा जा सकता अध्ययन के उद्देश्य

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बारे में जानना।

2. योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का अध्ययन करना।
शोध प्रविधि :- यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जिसके लिए पुस्तकों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नल में प्रकाशित शोधपत्रों का अध्ययन किया गया है तथा विभिन्न समाचार पत्रों व पुस्तकों से आंकड़ों को इकट्ठा किया गया है। इस प्रकार शोध पत्र हेतु विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

साहित्यिक सर्वेक्षण:

1. उमेशचन्द्र, अग्रवाल (2004) बालिकाभ्रूण हत्या और रोकथाम के प्रयास, इन्होंने प्रस्तुत लेख में बालिकाभ्रूण हत्या की समस्या का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नितनए प्रयोगों और अनुसंधानों के माध्यम से जहाँ एक ओर लाइलाज समझी जाने वाली अनेक बीमारियों से लाखों-करोड़ों लोगों की मुक्ति के द्वार खोले गए हैं, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक सोच और कुंठित प्रवृत्ति के लोगों ने इनमें से कुछ को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रकृति के विरुद्ध धिनौनी छेड़छाड़ और नैसर्गिक सिद्धांतों को झुठलाने के लिए प्रयोग करने की होड़ लगी हुई है।

2. टी. सुन्दारामन (2016) भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र दृष्टिकोण लेखक ने बताया है कि भारत में महिला स्वास्थ्य व बाल स्वास्थ्य की दिशा में प्रगति व प्रारम्भिक दशकों में मृत्युदर का बड़ा अनुपात छोटे बच्चों की मृत्युदर से संबंधित था। इनमें से ज्यादा मृत्यु दर 5 साल से छोटे बच्चों से संबंधित व गर्भावस्था के दौरान भी मृत्युदर की संख्या ज्यादा थी। इन दोनों तरह की मृत्युदर में तेजी से कमी आई है जैसे नब्बे के दशक की शुरुआत में बाल उत्तर जीविकाव सुरक्षित मातृत्व प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2005 में इन सब कार्यक्रमों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जोड़ा गया ताकि मातृ-मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी आस के।

3. संतोष जैन एवं सुरिद्रा जैन (2016) बालिका सशक्ति करण में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण का महत्व प्रस्तुत लेख में लेखिकाने बालिकाओं के सशक्तिकरण, उनके स्वास्थ्य व पोषण के महत्वको बताया है। बचपन से बालिकाओं के साथ अनेक तरह का भेदभाव किया जाता है। कन्या होने के कारण लड़कों की उपेक्षा उन्हें सही मात्रा में भोजन भी नहीं दिया जाता जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

4. अंजना रानी, योगेन्द्र सिंह, पंकज कौशिक एवं प्रदीप (2017) हरियाणाराज्य में जिलारोहतक, झज्जर व भिवानी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर एक वैचारिक सर्वेक्षण, प्रस्तुत शोधकार्य महिा दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के हरियाणा अध्ययन केन्द्र के अर्न्तगत पूर्णकिया गया। शोध परियोजना हरियाणा राज्य में जिला रोहतक, झज्जर व भिवानी में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना पर एक वैचारिक सर्वेक्षण पर आधारित। जिसके मुख्य उद्देश्य योजना के प्रति ग्रामीणों के जागरूकता स्तर, पंचायत सदस्यों की भूमिका और योजना के लागू होने के पश्चात् लोगों में आने वाले सामाजिक, मानसिक व आर्थिक

बदलाव को जानने का प्रयास है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्तुत शोध में ग्रामीण सरपंचों व पंचों, आशा वर्करो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व ए.एन.एम. कार्यकर्ताओं से सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अर्न्तगत प्रदान की गई सहभागिता को जानने का प्रयास किया गया है कि वे किस तरह से अपना योगदान इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रदान कर रहे हैं। उनकी स्वयं की इस योजना को लेकर क्या विचारधारा है। जिसके लिए तीनों जिलों से शोध के लिए कुल 375 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्य पूर्ण विधि द्वारा किया गया है। जिन में 300 ग्रामीण (पुरुष – महिला) 30 पंचायत प्रतिनिधि और 45 आशा वर्करो, आंगन वाड़ी कार्यकर्ताओं व ए.एन.एम कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है।

5. आनन्दभास्कर, (2017) डिस्अपियरेन्स ऑफगर्लचिल्ड्रन अमरजिंगट्रेडस इन सेक्शरेशोंइन इण्डिया, यह लेख दर्शाता है कि भारत में लिंग भेद, महिलाओं का गिरतास्तर, दूसरीसामाजिकसांस्कृतिकप्रथाएँ, जन्म पूर्वनिदानतकनी कोका दुरुपयोग और सरकारी नीतियों और योजनाओं की विफलता आदि घटते हुए लिंगानुपात का मुख्य कारण है। लेखक ने अपने लेखका समापन करते हुए सरकार की नीतियों का प्रभावशाली क्रियान्वयन करने, कन्याभ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए क्रियान्वित प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को सख्तीसे लागू करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में गैर सरकारी संगठन तथा स्वयं सेवी संगठनों को मिल-जुलकर लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

6. पुलरावड़ी, (2017) एन एनालिसिस ऑफ डिकलाइग सेक्शरेशों इन इण्डिया, लेखक के अनुसार कम लिंगानुपात महिलाओं की निम्न जीवन स्तरका पर्यायवाची है। भारत में लिंग अनुपात महिलाओं के निम्न जीवनके शुरुआती चरण में ही शुरु हो जाता है। घटते लिंगानुपात की समस्या के समाधान बिना विकास प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। इसके अनुसार घटते लिंगानुपात का मुख्य कारण लड़कियों की मृत्युदर का अधिक होना है। जिसके कारण समाज में लड़कियोंकी संख्या में तेजी से कमी आई है।

वैश्विक स्तर पर कई जगहों पर महिलाओं की लगभग आधी संख्या अभी भी पुरुषों से पीछे है। भारतीय संस्कृति ने सदैव अपनी वैचारिक अवधारणा के तहत महिलाओं को देवी के रूप में माना है लेकिन सच्चाई मिथक की अवधारणासेकोसों दूर है। दरअसल, भारतीय समाज लैंगिक असमानता और विष मलिंग से पीड़ित है। लैंगिक समानता तभी हासिल होगी जब महिलाओं और पुरुषों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, अधिकार और जिम्मेदारियाँ मिलेंगी। जब महिलाएं सशक्त हुईं, तो पूरे परिवार को लाभ हुआ, इस प्रकार समग्र रूप से समाज को लाभ हुआ और इन लाभोंका अक्सर भावी पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ता था। विषम बाल लिंगानुपात महिला बांझपन, उससे जुड़े मूल्य की कमी और अनादर का एक प्रमुख संकेतक है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के एक बड़े हिस्सेकोभेदभावऔरशोषणकाशिकार होना पड़ा है। विषम

लिंगानुपातपक्षपातीयौनप्राथमिकताओं के साथ-साथ जन्मकेबादलड़कियोंके प्रतिभेदभावदोनों के कारणहै। ऐसेमें सरकार को लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होगा और बालिकाओंके स्वस्थ विकास के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ अपनानी होंगी। इसलिए देश में लैंगिक असमानता को रोकने के लिए बीबीबीपी कार्यक्रम के रूप में पंचात्मक उपाय एक घंटेकी आवश्यकता थी। भारत सरकार ने जन्म के समयलिंग अनुपात (एसआरबी) लैंगिक असमानता को कम करने और लड़कियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अग्रणी कार्यक्रम के रूपमें 2015 मेंबेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया।

हमारा राष्ट्र नारी शक्ति की ओर अग्रसर है और भारतीय नारीत्व को पुन परिभाषित कर रहा है, क्योंकि हम विकास विमर्श में केंद्र का सीन प्राप्त कर रहे हैं। विकास की रूप रेखा में महिला-केंद्रित विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास में परिवर्तन देखा गया है। सशक्तिकरणके मानदंडकोन केवल आर्थिक विकास को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है, बल्कि सामाजिक विकास पर भी अधिक जोर दिया गया है, जिसमें शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोज मर्ग की गरिमा, आत्मविश्वास और शिक्षा जैसी सेवाओं तक पहुंचकी मांग करने का साहस शामिल है, जो बदल गया है शक्ति संबंध. समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने की यह दृढ़ प्रतिबद्धताह में नारी शक्ति की एक नई अवधारणा देती है, जो महिला सशक्तिकरण का एक भारतीय संस्करण है जिसने महिला मतदाताओं को सरकार की ओर आकर्षित किया है।

सभी जिलों की वर्तमान महिलाओं का यह व्यापक समर्थन 2022 के भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों में देखा जा सकता है, जिसमें बताया गया है कि सरकार पुरुषों की तुलना में महिलाओं के बीच चुनाव आयोग के रूप में अधिक लोक प्रिय है। यह रहस्योद्घाटन उन अनेक राक्षसों का प्रतिकार करता है जो अन्यथा सलाह देते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के लिए हैं जो अन्यथा सलाह देते हैं। जब महिला एक जुटता की समग्र समझ की बात आती है तो आर्थिक नियतिवाद के अन्य पहलुओं को पार किया जाता है और इसे सुरक्षा, सुरक्षा, गरिमा और नेतृत्व के बड़े पैमाने पर सवाल उठाया जाता है, भाजपा के नेतृत्ववाली सरकारने एक आदर्श बदलावशुरू किया है। यह रहस्योद्घाटन उन अनेक राक्षसों का प्रतिकार करता है जो अन्यथा सलाह देते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकारके लिए हैं जो अन्यथा सलाह देते हैं। जब महिला एक जुटता की समग्र समझ की बात आती है, तो आर्थिक नियतिवाद के अन्य पहलुओं को पार किया जाता है और इसे सुरक्षा, सुरक्षा, गरिमा और नेतृत्व के बड़े पैमाने पर सवाल उठाया जाता है, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने एक आदर्श बदलाव शुरू किया है। यह रहस्योद्घाटन उन अनेक राक्षसों का प्रतिकार करता है जो अन्यथा सलाह देते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकारके लिए हैं जो अन्यथा सलाह देते हैं। जब महिला एक जुटता की समग्र समझ की बात आती है, तो आर्थिक

नियतिवाद के अन्य पहलुओं को पार किया जाता है और इसे सुरक्षा, सुरक्षा, गरिमा और नेतृत्व के बड़े पैमाने पर सवाल उठाया जाता है, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने एक आदर्श बदलाव शुरू किया है। महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में देखा गया, लेकिन उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में भी बढ़ावा दिया गया, एक विरासत जो स्वतंत्र भारत में तेजी से खो रही थी। यह विचार कि हमें महिलाओं को राष्ट्र-निर्माता के रूप में देखना चाहिए, ने महिलाओं में राष्ट्र के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा की। इसके अलावा, इस तरह के दृष्टिकोण ने महिलाओं को पीड़ित होने से नहीं रोका बल्कि महिलाओं को कोन केवल अपने जीवन के एजेंट के रूप में बल्कि अपनी छवि के अनुसार राष्ट्र को नया आकार देने के लिए भी एजेंट के रूप में प्रस्तुत किया। नारी शक्ति के विमर्श और नीतियों ने राष्ट्रनिर्माण में महिलाओं की मुक्ति के सवाल पर एक नया मोड़ दिया।

मोदी सरकार की नीतियों ने वास्तव में जाति, वर्ग, क्षेत्र और धार्मिक से ऊपर उठकर महिलाओं के अधिकारों के सवाल को संबोधित किया है। मुख्यधारा के विद्वानों, कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के बीच, अक्सर महिलाओं का प्रश्न अभिजात वर्ग और शहरी भारत के इर्द-गिर्द घूमता रहा। अधिकतर एक प्रमुख स्थिति से व्यक्त किया गया जिसने विभिन्न सामाजिक वर्गों की महिलाओं को हाशिए पर छोड़ दिया, उनके जीवन और आजीविका का केंद्रीय प्रश्न अक्सर अछूता रह गया। मोदी सरकार के तहत, इन बारी कियों पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया। उन कमियों को दूर करने के लिए सुविचारित नीतियां और अभियान तैयार किए गए और तथा कथित साधारण से निपटने में अंतर्संबंध का एक सूक्ष्म दृष्टिकोण लागू किया गया: वे महिलाएं जिन्हें पिछली सरकारों की मुख्यधारा के प्रवचन और नीतियों से बाहर रखा गया था।

सरकार द्वारा तीन व्यापक और जन नीतियां लागू की गई हैं जो यह समझने के लिए केंद्रीय हैं कि भाजपा सरकार अपने महिला निर्वाचन क्षेत्र से कितनी प्रभावी ढंग से जुड़ी है। तीन महत्वपूर्ण नीतियां जिन्होंने महिलाओं को प्रभावित किया और उनकी चिंताओं को एक साथ लाया, वे हैं उज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन। ईंधन, पानी और शौचालय तक पहुंच की कमी से महिलाएं ही सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं और जब हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं और हाशिए की महिलाओं को देखते हैं तो ये असमानताएं और भी बढ़ जाती हैं। जब हम इन महिलाओं को पानी या लकड़ी लाने, या खुले में शौच के लिए जाने पर आने वाले कई खतरों पर विचार करते हैं, तो ये दैनिक काम लगभग एक घातक चरित्र प्राप्त कर लेते हैं। पानी, गैस और शौचालय के सवाल पर काम करते हुए, सरकार अधिकांश महिलाओं और उनकी तात्कालिक, रोज मर्चा की चिंताओं तक पहुंच गई है। इस सेन केवल सुरक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता आई बल्कि सामान्य महिलाओं के जीवन में सम्मान भी आया।

योजना के उद्देश्य

पक्षपातलिंग चुनावकी प्रक्रिया का उन्मूलन बालिकाओं का अस्तित्व और

सुरक्षा सुनिश्चित करना।

बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना।

बालिकाओं को शोषण से बचाना वह उन्हें सही ढंग से गलत के बार में अवगत कराना।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है।

लोगों को इसके प्रति जागरूक करना एवं महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाएं वितरित करने में सुधार करना है।

इस योजना के तहत मुख्य रूप से लड़के एवं लड़कियों के लिंग अनुपात में ध्यान केंद्रित किया गया है। ताकि महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और सेक्स डेटर मिनेशन टेस्ट कोरो का जास के।

इस योजना का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को बचाना एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है।

शिक्षा के साथ • साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने एवं उनकी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है।

रणनीतियाँ

बालिका और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन और समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का कार्यान्वयन करना।

इस मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाना और उसे संशोधित करने रहना सुशासन का पैमाना बनेगा।

निम्न लिंगानुपात वाले जिलों की पहचान कर ध्यान देते हुए गहन और एकीकृत कार्रवाई करना।

सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थानीय महिला संगठनों युवाओं की सहभागिता लेते हुए पंचायती राज्य संस्थाओं सीनीय निकायों और जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करते हुए सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक की भूमिका में ढालना जिला ब्लॉक जमीनी स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत समायोजन को सक्षम करना। महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों और अपराधों की रोकथाम।

महिलाओं एवं बालिकाओं बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ : अब तक की उपलब्धियां शुरुआत से लेकर बीते 6 वर्षों के दौरान बीबीबीपी योजना बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में काम करती रही है। इस योजना के परिणाम स्वरूप लैंगिक भेदभाव की व्यापकता और इस खत्म करने में समुदाय की भूमिका को लेकर आम लोगों में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ी है। इसने भारत में सीएसआर में गिरावट के मुद्दे पर चिंता जताई है। अभियान का समर्थन करने वाले लोगों की सामूहिक चेतना के रिणाम स्वरूप, जनता में बीबी बीपी की चर्चा शुरु हुई है।

निगरानी योग्य लक्ष्यों के संदर्भ में प्रगति :

1. जन्म के समय लिंगानुपात

जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में राष्ट्रीय स्तर पर सुधार देखा

गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एच एम आई एस आकड़ों के अनुसार एसआरबी में 918 (2014-15) के मुकाबले 16 अंकों का सुधार होकर 934 (2019-20) हो गया है।

बीबीबीपी के तहत कवर किए गए 640 जिलों में से 422 जिलों में 2014-15 से लेकर 2018-19 तक सुधार दिखा है।

2014-15 में कुछ जिलों में एस आरबी बहुत कम था, योजनाक कार्यान्वयन के बाद वहां काफी सुधार दिखा है जैसे – मऊ (उत्तरप्रदेश) में 694 (2014-15) से 951 (2019-20), करनाल (हरियाणा) 758 (2014-15) से 898 (2019-20), महेंद्रगढ़ (हरियाणा) 791 (2014-15) से 919 (2019-20), रेवाड़ी (हरियाणा) 803 (2014-15) से 924 (2019-20) और पटियाला (पंजाब) 847 (2014-15) 933 (2019-20)। की शिक्षा व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देना।

2. स्वास्थ्य:

पहली तिमाही के ए एनसी पंजीकरण प्रतिशत में 2014-15 के 61 प्रतिशत से 2019-20 में 71 प्रतिशत का सुधार दिखा है। (एचएमआईएस, एम ओ एच एंड एफ डब्ल्यू के अनुसार) संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में भी 2014-15 के 87 प्रतिशत से 2019-20 में 94 प्रतिशत तक का सुधार दिखा है। (एच एम आईएस, एम ओए चए डए फडब्ल्यू)

3. शिक्षा :

यूडी आई एसई डाटा के अनुसार स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में 77.45 (2014-15) से 81.32 (2018-19) अंतिम आंकड़े का सुधार हुआ है। लड़कियों के लिए अलग बनाए गए शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत 2014-15 के 92.1 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 95.1 प्रतिशत हो गया है। (यूडी आई एसई डाटा के अनुसार 2018-19 अंतिम आंकड़ा)

व्यवहार में परिवर्तन:

बीबीबीपी योजना कन्याभ्रूण हत्या, लड़कियों में शिक्षा की कमी और जीवन चक्र के अधिकारों से वंचित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रही है। यह योजना बालिकाओं से संबंधित पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए समुदाय के साथ जुड़ने और बच्ची के जन्मको उत्सव की तरह मनाने के लिए नई प्रथाओं की शुरुआत करने में सफल रही है।

बीबीबीपी के लोगो को काफी सराहा और लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। लोग अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए बीबीबीपी के लोगोका उपयोग स्कूली बसों, भवनों, स्टेशनरी, परिवहन वाहनों आदि पर अपनी इच्छा से कर रहे हैं। लोकप्रिय भारतीय त्योहारों जैसे लोहड़ी, कलश यात्रा, राखी, गणेश चतुर्दशी पंडाल, फूलों के त्योहार आदि में लोगोका इस्तेमाल हुआ है। लड़कों के जन्म के समय होने वाले रीति-रिवाज की तरह लड़की के जन्म को भी मनाने जैसे—कुआं पूजन, थाली बजाना आदि के लिए अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मचारी समुदाय के स्तर पर काम कर रहे हैं। बालिकाओं की महत्ता

को समझाने के लिए अब समुदाय के स्तर पर और अस्पतालों में प्रशासन द्वारा माताओं और बच्चियों को सम्मानित किया जा रहा है। बेटे जन्मोत्सव जिले में मनाया जाने वाला प्रमुख कार्यक्रम है।

निष्कर्ष :

सरकार का बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ अभियान महिला सशक्तिकरण की दिशामें एक सराहनीयक दम है। उन्होंने बालिकाओं के संरक्षण और पोषण की अहमियत पर जोर दिया। मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर एक नई सुबह नाम से एक विशाल समारोह में इस अभियान के बारे में बात करते हुए समय आगया है कि हम यह महसूस करें कि देश की आधी आबादी को नजर अंदाज कर और असहाय बनाकर उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। देश के विकास में वे समान रूप से भागीदार होने चाहिए।

एक पुराने संस्कृत मंत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को यहाँ तक कि हमारी धार्मिक मान्यताओं में प्रथम सीन दिया गया है। जहाँ सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है, लक्ष्मी धनकी, जबकि दुर्गा और काली शक्तिका प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहा मौजूदा परिदृश्य में यह कल्पना तभी हकीकत बनेगी, जब समाज में पुरुष और महिला की स्थिति समान होगी। समान संख्या में बेटियाँ बेटों की तरह जन्म लेनी चाहिए और उनका उपयुक्त पालन तथा शिक्षा-दीक्षा होनी चाहिए ताकि वे जीवन में अपनी यथोचित भूमिका निभा सकें।

बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ का असली मकसद यह है कि बेटे और बेटे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा समान अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें इस विचार को बढ़ावा देना चाहिए कि हमारे परिवार को बालिकाके संरक्षण और पोषण के लिए वह सब कुछ करना चाहिए, जो उस के लिए जरूरी हो। मैं इस नारे को पूरे समाज को आगे ले जाने और हमारी महिलाओं के प्रति सही नजरिए को स्वीकारने का एक जरिया मानता हूँ। महात्मा गाँधीने हमेशा हीम हिला को उच्च शक्तिमाना क्योंकि जब अंदरूनी मजबूती की बात आती है, तो पुरुष कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते।

संदर्भ सूची

1. भारत में बालिका-बेटे पढ़ाओ पर बेटे बचाओ जना का निहिताथरू महत्वपूर्ण विश्लेषण सूचना बारो 2018
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ के अंतर्गत वाचार दिल्ली 2019
3. चंद्रांजे मताओं के लिए शिक्षा सीधा संबंध बच्चों को बेहतर पोषण से है सर्वेक्षण 2019
4. निकोरे, एम. ए बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ : कार्यान्वयन की एक आलोचनात्मक समीक्षा 2019
5. गृहमंत्रालय, जे. ओ. भारत के रजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय 2019
6. अग्रवाल, उमेश चन्द्र, बालिकाभ्रूण हत्या और रोकथाम के प्रयास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2004, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या

7. सुन्दारामनटी० भारत में स्वास्थ्यक्षेत्र – दृष्टिकोण और भावी रूप रेखा, योजना संसद मार्ग, नई दिल्ली, फरवरी 2016
8. जैनसंतोष एवं जैन सुरिद्रा, बालिका सशक्ति करण में बालिकाओं स्वास्थ्य के एवं पोषण का महत्व, कुरुक्षेत्र, 2016
9. रानी अंजना, सिंह योगेन्द्र कौशिक पंकज एवं प्रदीप, हरियाणा राज्य में जिला रोहतक, झज्जर व भिवानी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर एक वैचारिक सर्वेक्षण, शोध परियोजना, हरियाणा अध्ययन केन्द्र, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक, 2017
10. आनन्द भास्कर, डिस्अपियरेन्स ऑफगर्ल चिल्ड्रन ट्रेड सइन् सेक्श रेशों 2017
11. राव, पुलडी., एन एनालिसिस ऑफ डिकलाइग सेक्शरेशों इन इण्डिया, इण्डियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसिस, वोल्यूम 2, अंक 12, 2017,
12. मिश्रा रोली, डिस्- प्रेफरन्स फॉर दी गर्ल चाइल्ड – दी ट्रेड कोन्टीन्यूस, एशियन मिररइन्टर नैशनल जर्नल, वोल्यूम 3 जून 2017,

शोध निर्देशिका

डॉ. बबीता,

असिन्टेन्ट प्रोफेसर

राजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग,

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

शोधार्थी

पुनम

राजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग,

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

सारांश:—

एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परंपरा, संस्कृति, ज्ञान और कौशल को हस्तांतरित करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। प्राचीन भारत में अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में परंपरा बरकरार रहती थी। अंग्रेजों के आगमन के बाद जो शिक्षा प्रणाली भारत में लागू हुई, वह शिक्षा देश के जीवन्त व्यवहार से कटी हुई है और उसने अपना उद्देश्य बहुत सीमित कर दिया है केवल सूचनाएँ देना और नौकरियाँ दिलाना। गाँधी जी के अनुसार इस शिक्षा ने अपना वह धर्म भुला दिया है कि वह समता मूलक समाज के निर्माण में सहायक होगी। शिक्षा शून्यता में नहीं होती, वह सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक संदर्भों से घिरी रहती है। अतः शिक्षा की प्रासंगिकता पर बल देते हुए और उसके वास्तविक अर्थ को समझते हुए पाठ्यवस्तु, शिक्षण प्रणाली व मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए।

गाँधी जी ने कहा था कि, "शिक्षा के आधार भूत सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह है कि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसकी रचना की जानी चाहिए। अपनी पाठशालाओं में समाज की आवश्यकताओं का विचार ही नहीं किया जाता।

गाँधी जी ने आगे कहा कि, 'शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इस संबंध में सरकार पर भरोसा रखकर बैठे रहें, तो यह व्यर्थ समय गँवाने के समान होगा। यह भी हो सकता है कि सरकार के सलाहकारों को गलत जानकारी हो अथवा वे स्वार्थी हों। सम्भव है ऐसे अनेक कारणों से सरकार के मार्फत वर्तमान पद्धति में महत्वपूर्ण फेर फार होते-होते बहुत समय निकल जाए।'

शिक्षा के जानकारों का कहना है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी, उस पीढ़ी के लिए करती है, जो सामाजिक जीवन के लिए अभी प्रस्तुत नहीं है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परम्परा, संस्कृति, ज्ञान और कौशल को हस्तांतरित करने में शिक्षा की अहं भूमिका होती है। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रणालियाँ प्रचलित थीं। अंग्रेजों के भारत में आगमन से पूर्व तक अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से परिवार और परिवार-समूहों में हस्तशिल्प, कौशल व व्यवसाय को सिखाया जाता था और इस प्रकार एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में परम्परा बरकरार रहती थी। भाषा, व्याकरण, साहित्य, गणित, धर्म, दर्शन व ज्योतिष की शिक्षा औपचारिक क्षेत्र के अन्तर्गत आती थी। परन्तु आचरण, व्यवहार और जीवन-पद्धति की शिक्षा, घर-समाज में अनौपचारिक रूप से दी जाती थी।

अंग्रेजों के आगमन के बाद जो शिक्षा- प्रणाली भारत में लागू

हुई और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण से जिस शिक्षा का फैलाव हुआ, वह शिक्षा देश के जीवन्त व्यवहार से अपना कोई नाता नहीं रखती। देशज विचार और नैतिक पक्ष से भी उसका कोई संबंध नहीं दीखता। शिक्षा ने अपना उद्देश्य बहुत सीमित कर दिया है केवल नौकरियाँ 1 दिलाना। हालाँकि इस उद्देश्य में भी वह सफल नहीं हो पायी है।

आज प्रचलित शिक्षा में पढ़ने-लिखने के बाद युवा अपने परिवेश से पूरी तरह कट जाता है और हीन भावना से ग्रस्त हो अपने को पिछड़ा और कुठित महसूस करने लगता है। अपने समाज की सामर्थ्य और विशिष्टता को वह पिछड़ापन मान लेता है व उस शहरी परन्तु परायी जीवन-पद्धति को अपनाता है, जिस से वह एकाकार नहीं हो पाता। हाँ, एक झूठा अभिमान ऐसे युवाओं में अवश्य हो जाता है। न तो उसमें कोई ज्ञान होता है, न हुनर, न ही कोई दक्षता। और परम्परागत कौशलों को वह छोड़ बैठता है। 1835 में मैकाले ने तो ऐसी शिक्षा प्रणाली देश में लागू की थी जिसका उद्देश्य ऐसे बाबू तैयार करना था जो सोच में विदेशी हों और मात्र रक्त और वर्ण में देशी हों। यद्यपि ऐसे तैयार विदेशी व त्लोगों को भी अंग्रेज अपने समकक्ष मानने को तैयार नहीं थे। स्वयं एक अंग्रेज एडम द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि 1830 के आस-पास संयुक्त प्रांत (बिहारमिलाकर) में लगभग एक लाख प्राथमिक पाठशालाएँ काम करती थीं और गाँव के जमींदारों और साहूकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त करती थीं।

आधुनिक शिक्षा अधिकांशतः मात्र सूचनात्मक है। यह सूचना भी परायी आयातित और संदर्भित देश-समाज से कटी रहती है। जहाँ ऐसी सूचना उस निर्दिष्ट देश-समाज से जुड़ी हुई भी हो, वहाँ भी प्रासंगिक नहीं है। इससे छात्र-छात्राओं को जो जानकारी परोसी जाती है, उसमें निजता के भाव की रिक्तता रहती है। यह स्थिति उस बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ देती है। उसे लगता है कि उसका जो भी निजी है, उसके परिवेश से संबंधित है, वह अप्रासंगिक है और वह ललचायी नजरों से उस देश-समाज के बहु प्रगट लक्षणों को देखने लगता है, जिसमें उसे अपने लिए कुछ भी नहीं मिलता। इससे वह पिछड़ा और कुठित महसूस करने लगता है। उसकी परम्परागत धरोहर दृ भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर उसे निरर्थक लगने लगती है। इससे वह अपने को पिछड़ा महसूस करता है और अपनी श्रेष्ठता और सामर्थ्य के प्रति नकारात्मक भाव रखने लगता है। वह दूसरी सभ्यता और दूसरे समाज के लक्षणों को-वस्तुपरक, विचारपरक और विद्यापरक - विशिष्ट समझकर उनकी नकल करने लगता है। यदि वह ग्रामीण परिवेश से है तो उसे शहरी रीति-रिवाज, रहन-सहन, सोच-विचार के प्रतीक, विशेष लगने लगते हैं। परिणामतः आज युवा

की स्थिति ऐसी है कि उसने जो पाया उसे अपनाया नहीं और जो चाहा उसे पाया नहीं। ऐसे युवा समाज के लिए कोई उपयोगी भूमिका नहीं निभा पाते क्योंकि वे सदा हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं वमात्र झूठा अभिमान पाले रखते हैं। ऐसी मात्र जानकारी भरी शिक्षा उस युवा को कोई नया हुनर या नयी कार्यों को हीन मानकर बेरोजगार ही रहता है।

वास्तविक शिक्षा के द्वारा तो युवा में उन क्षमताओं का विकास होना चाहिए जो उसे एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने में मदद करे ताकि एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण हो जिसमें आत्मविश्वास हो, जो सही गलत काफैसला ले सके, जिसे अपने देश-समाज की समझ हो, जिसमें इस प्रकार की विश्लेषणात्मक क्षमता हो कि वह समस्याओं को सुलझाने के लिए दक्षता और साहस से निर्णय ले सके। वास्तविक शिक्षा में तो युवा को ऐसी दृष्टि मिलनी चाहिए जो उसे सोचने के लिए प्रेरित करे और जीवन जीने का रास्ता दिखला सके। आज की शिक्षा ने साक्षरता और शिक्षा के अंतर को भी भुला दिया है। प्रायः ये दोनों शब्द आज पर्याय के रूप में प्रयोग होने लगे हैं। साक्षरता तो मात्र अक्षर ज्ञान है, शिक्षा उससे कहीं ज्यादा और गहरी चीज है। बिना अक्षर ज्ञान के भी व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। हमारे देश में आज भी ऐसे हजारों लोग होंगे, जिनके पास जलवायु, खेती, जल-संरक्षण, वास्तुकला, स्वास्थ्य और चिकित्सा, बच्चों का लालन-पालन, आदि से संबंधित पारम्परिक ज्ञान होगा। हमारे पारम्परिक जानकार लोग मौसम के बारे में ऐसा सही अनुमान लगाते हैं जिनके सामने बड़े-बड़े मौसम वैज्ञानिक भी हार मान लेते हैं। ऐसे हुनरमंद और जानकारों को लोग आजकल निरक्षर मानकर उनका उपहास उड़ाते हैं या फिर उनकी अवहेलना करते हैं।

आधुनिक शिक्षा, नौकरी या आजीविका का साधन है, यह दावा भी आज झूठा साबित हो रहा है। शिक्षा मात्र यदि व्यावसायिकता है तो भी आज वह अपनी उपयोगिता खो चुकी है क्योंकि बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है। इस आधुनिक शिक्षा ने नौकरियों तो उपलब्ध नहीं करायी अपितु पारम्परिक उद्योगों की ओर युवाओं के लौटने का रास्ता भी बंद कर दिया है।

इस आधुनिक शिक्षा ने हाथ से काम करने के महत्व को भी कम कर दिया है और नौकरी का अर्थ सिमटकर मात्र कुर्सी पर बैठकर काम करने तक ही सीमित हो गया है। इस आधुनिक शिक्षा ने साक्षरों की एक ऐसी ऊँची जमात को खड़ा किया है जो क्लर्की को या मशीन से काम करने को विशेष मानने लगी है। इससे शारीरिक श्रम की महत्ता घट गई है। इससे यह तथ्य भी विलुप्त हो गया है कि शिक्षा मात्र साधन है, साध्य नहीं है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रमुख हो गए हैं। हम यह बात भूल गये हैं कि इस आधुनिक प्रौद्योगिकी ने पूरे समाज का कल्याण न करके, बाजारी शक्तियों का एक हथियार बनकर, सुविधासम्पन्न और सुविधावंचित लोगों के बीच की खाई को बढ़ाया ही है। इस प्रकार इस आधुनिक शिक्षा ने मन और बुद्धि के स्तर पर हमें हीन और दीन बनाया है। वहीं भौतिक स्तर पर अधिक दरिद्र

और अशक्त बनाया है।

महात्मा गाँधी ने एक जगह कहा है कि, "शिक्षा अर्थात् जानने योग्य ज्ञान। जानने योग्य तो केवल आत्मा ही है इसलिए विद्या अर्थात् आत्म ज्ञान। लेकिन आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित आदि जानना चाहिए। ये सब साधनरूप हैं। इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अक्षर ज्ञान होना आवश्यक है। अक्षर-ज्ञान के बिना भी इन विषयों को जानने वाले व्यक्ति हमने देखे हैं जो व्यक्ति इतना जानता है, वह अक्षर-ज्ञान अथवा साहित्य इत्यादि के ज्ञान के पीछे दीवाना नहीं होगा। वह तो आत्म-ज्ञान के ही पीछे पागल होगा। आत्म-ज्ञान की प्राप्ति में जो विषय विघ्न रूप हैं, उनका त्याग करेगा और जो सहायक हैं, उनका पालन करेगा। इस बात को समझने वाले व्यक्ति का विद्यार्थी-जीवन कभी समाप्त नहीं होता और वह खाते-पीते, सोते, खोदते, बुनते, कातते, कोई भी काम करते समय ज्ञान प्राप्त करता ही रहता है। इसके लिए पर्यवेक्षक शक्ति को विकसित करना चाहिए। उस व्यक्ति को सर्वदा शिक्षकों के समूह की आवश्यकता नहीं होती बल्कि वह समस्त विश्व को शिक्षक के रूप में मानकर गुण ग्रहण करता रहता है।" (महात्मा गाँधी, 1919)।

शिक्षा, विद्या और ज्ञान

'ज्ञान', 'ज्ञा' धातु से बना है जिसका अर्थ है- जानना। यह ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। 1. कर्मेन्द्रियों द्वारा और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा। आँख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूँघती है, जिह्वा चखती है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर भेद हो सकता है। देखने में मात्र आकार को देखना या फिर आकार के रूप,रंग को भी देखना। सूँघने का एक अर्थ तो यह है कि सभी फूलों की सुगन्ध एक जैसी है। एक सूँघने का अर्थ यह है कि हम बता सकें कि यह किस फूल की गंध है। जिह्वा का कार्य है चखना, पर इस चखने में भी प्रकार हैं

खट्टा है, मीठा है, चटपटा है तीखा और उसके अन्तर्गत भी आवन्तर भेद। इन्हें इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, जिसकी एक सीमा होती है।

परंतु इस ज्ञान में मूल्यों का समाहित होना मन से होता है। कोई अनुभव सुखद है या दुःखद यह हमारा मन निर्धारित करता है। परन्तु हमारे मन में भी पहले से बुद्धि ने कुछ संस्कार डाल दिये हैं। इंद्रियाँ घोड़े के समान हैं, चलाने से चलती हैं। परंतु इंद्रियों से परे एक ज्ञान है, जिसे अतीन्द्रिय भी कह सकते हैं। कभी-कभी लगता है कि हमें कोई याद कर रहा है। यह इसी प्रकार का ज्ञान है। आमतौर पर ऐसा ज्ञान श्रेष्ठ व्यक्तियों को होता है, परन्तु सामान्य जनों को भी हो सकता है। 'ज्ञान' का पर्यायवाची अंग्रेजी में 'नॉलिज' हो सकता है यद्यपि यह भी उपयुक्त पर्याय नहीं है। क्योंकि 'ज्ञान' में knowledge से कुछ ज्यादा है। परन्तु 'ज्ञान' की सीमा है कि आपका कहाँ तक पहुँचना है। इसका कुछ पूर्वानुमान लगाया जाता है। ज्ञान का एक दूसरा पर्याय है, 'अवगमन' यानी गहराई से जाना।

यह भी पहुँचने का द्योतक है। यानी एक सीमा तक पहुँचना । ज्ञान ही अस्तित्व का प्रमाण है। ज्ञान में स्मृति का बड़ा योगदान है। यह स्मृति, पूर्व ज्ञान को पहचानने में भी मदद करती है।

विद्या शब्द 'विद्' धातु से बना है। संस्कृत में 'विद्' धातु से चार अर्थ निकलते हैं।

1. जानना
2. पाना
3. चलना
4. होना

संस्कृत का एक बहुप्रचलित वाक्यांश है।

'सा विद्या या विमुक्तये', विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। विमुक्ति का एक आध्यात्मिक अर्थ है कि इस संसार के प्रपंचों से मुक्ति। परन्तु सांसारिक स्तर पर भी मुक्ति का एक अर्थ है राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, मिथ्या कथन से मुक्ति। यानी ऐसे मानव का निर्माण जो सचरित्र हो, सहृदय हो व दूसरे के प्रति समभाव रखें। मुक्ति का अर्थ यहाँ अपने को गहराई से पहचानने से है। अपनी सजगता और चेतना की जागृति से है। मुक्ति इस अहंकार से कि 'मैं सब कुछ जान गया।' ज्ञान की सीमा को निरंतर बढ़ाता चलाँ, क्योंकि वही सार्थक विद्या होगी, जो दूसरे के लिए देश-समाज के काम की होगी।

पतंजलि के महाभाष्य में विद्या को चार प्रकार से फलवती माना गया है दृ 1. अध्ययन सेय 2. मनन सेय 3. प्रवचन सेय और 4. प्रयोग से। परंतु इस प्रकार के भारतीय मनीषियों की विवेचना में विद्या का भौतिक उपयोगितावाद से ज्यादा सम्बन्ध नहीं है। यहाँ तो विद्या का लक्ष्य समर्थ मानव बनाना है। विचारों की शुद्धि से ही निष्कर्ष की शुद्धि आती है। यह प्राचीनविचार ही गाँधी जी के उन विचारों से परिलक्षित होता है, जब वे कहते हैं कि आधुनिक औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। गाँधी जी के अनुसार इस शिक्षा ने अपना वह धर्म भुला दिया कि वह आत्मविभोर व समतामूलक समाज के निर्माण में सहायक होगी। उल्टे इस आधुनिक शिक्षा ने आदमी को आलसी, आत्मकेंद्रित, अरचनात्मक और अपने परिवेश से काटकर रख दिया है। अर्थात् आधुनिक शिक्षा विद्या के स्थान पर अविद्या है। पुरानी विद्या में बच्चे की जातीय पहचान बनाए रखने के लिए जातीय स्मृति का बहुत महत्व था। यह विद्या प्रायः वाचिक थी परन्तु "हिन्दुस्तान की निरक्षरता वाचिक शिक्षा के कारण शिक्षा विहीन नहीं थी, इस निरक्षरता में भी शिक्षा थी।" (विद्यानिवास मिश्र, 'अध्यापन रू भारतीय दृष्टि', नई दिल्ली 1998)।

शिक्षा शून्यता में नहीं होती वह सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों से घिरी रहती है। यद्यपि आधुनिक सोच ने शिक्षा के व्यापीकरण में शिक्षा के सर्वसुलभीकरणपर तो ध्यान दिया है, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता पर ध्यान नहीं दिया यद्यपि आज भी अभिभावक शिक्षा की सुलभता के स्थान पर उसकी प्रासंगिकता पर बल देते देखते हैं।

अतः आवश्यक है कि आज शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझते हुए

निम्न पर विचार किया जाए।

1. पाठ्य वस्तु
2. शिक्षण प्रणाली
3. मूल्यांकन

इसके अंतर्गत शिक्षा 'क्या', शिक्षा 'क्यों' मुख्य है। आज प्रायः ध्यान मात्र शिक्षा 'कैसे' पर ही है।

इन बिंदुओं पर ही विद्या के सही स्वरूप, उसकी गुणवत्ता, प्रासंगिकता और स्थानीयता के साथ ज्ञान और जानकारी के अंतर, आदि पर भी विचार किया जा सकता है। विद्या को उसके समग्र रूप में देखते हुए उसको खण्ड-खण्ड में विषयवार न बाँटकर, समग्र रूप में ज्ञान-प्राप्ति के लक्ष्य की दृष्टि से समझना होगा।

सन्दर्भ—

1. <https://hi-quora-com>
2. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी
3. ड ज्ञ ळंदकीप
4. प्रोफेसर लोकेश जैन और डॉ महेश नारायण दीक्षित
5. महात्मा गांधी और शिक्षा दर्शन (प्रोफेसर सोहम तोमर)

डॉ० (श्रीमती) राजेश गिल

सहायक प्रोफेसर

शिक्षा विभाग

महाराजा सूरजमल संस्थान, नई दिल्ली

Review of Social Sector Expenditures of States at Aggregate Level in India

Dr. Manju Dalal

Abstract

In the present study, an attempt is made to examine the impact of state finances on some major social indicators of the society like health, education, water supply and sanitation etc. Economic development not only considers the increase in real per capita income but it necessarily, includes the changes in social welfare indicators with the change in economic indicators. Improvements in social indicators also exhibit the role, planning and effective and efficient implementation of policies by the government mechanism. Therefore, it becomes must to examine the impacts of economic indicators on the social indicators of the economy. Due to some limitations, this paper explained pattern of expenditure on some important components of social sector for states at aggregate level. Secondary data and simple statistical tools like ratios percentage have been used to explain impact of state finances on some important indicators of the society. From the study, it is found that capital expenditure on social services has been less than the revenue expenditure, which demands the focus of government for prioritization of development policies and effective implementation system.

Keywords: Social Sector, Indicators, Expenditure, State Finances, Fiscal Key Indicators

1. Introduction

The financial condition of any economy (state economy) has special impacts on its social and economic lives of the citizens of that country. Certainly, the increase in per capita real income, is an indicator of the economic growth, but not necessary the case for economic development. Economic development includes welfare in addition of economic growth. Welfare depends on the development of social services, which too much extent depends on expenditure strategies adopted by the government. There have been many studies in the past which explains the impact of income on social sector in many ways, some of them are discussed here to see the gaps with this study. Badola and Mukherjee (2021), also highlighted the role of public financing of human development (HD) is inevitable, especially for developing countries like India where access to resources and economic opportunities are not equitably distributed among people. Author found that due to deteriorated financial condition of governments due to Covid-19, there is possibility that larger share of public expenditure will be devoted to provide livelihood supports to people in terms of free foods, income support whereas expenditures on

health (except emergency healthcare) and education infrastructure may be postponed or reduced. Joshi (2006), found that, India indeed has made noticeable improvements in key social indicators on education and health since the 1980s, mainly as a result of large-scale government programmes. But even then, the conditions with respect to social sector development in India are appalling when compared with conditions prevailing in countries like Sri Lanka, China and some countries of south-east Asia. The educational and health status of a vast majority of the population continues to remain poor even after a decade of reforms which demand an immediate and sustained response from the government. Mittal (2016), found inequality in social sector expenditure resulted inequal human development in the states. At the policy level the study recommends for more public expenditure to have a balanced and improved human development in India. The study also looks at the composition of social expenditure where it shows that States' share of capital expenditure in total social sector expenditure is improving over the years although its share was very small as compared to the share of revenue expenditure. Budgets are recommended to be adequately allocated to provide support to policies and programmes necessary to achieve growth and development of the country by author. Lamartina, Serena and Zaghini, Andrea (2019), examined the development of government expenditure and economic growth in 23 Organization Economic Cooperation and Development countries. The empirical evidence provides indication of a structural positive correlation between public spending and per-capita gross domestic product (GDP), which is consistent with the so-called Wagner's law. A long-run elasticity larger than 1 suggests a more than proportional increase of government expenditure with respect to economic activity. Author found that, the correlation was higher in countries with lower per-capita GDP and suggested for more development by government activities with respect to economies in a more advanced state of development.

In the light of above facts, in the present study, it is tried to find the impact of financial condition of all states and union territories of India, at aggregate level, on the expenditures on social services in many ways, which constitute the following *objectives* of the study: -

1. To examine various kinds of budget deficits of the state governments at aggregate level,
2. To evaluate the expenditure incurred by states on social services, and
3. To calculate the elasticities of expenditure for the various categories i.e., revenue and capital expenditure and for various sub heads of these categories on social services, at aggregate state level and find the areas, where states should reprioritise its expenditure for the human development and welfare of the society.

2. Data Sources and Methodology

The present study is based on secondary data which covers period from 2011-12 to 2021-22 for all states at aggregate level in India. Simple linear regression and simple statistical tools like ratios and percentages have been used to examine data on various variables. Data has been collected from the following sources:

- Reserve Bank of India (RBI), Handbook of Statistics on State Government Finances, 2021-22.
- Reserve Bank of India (RBI), State Finances: A Study of Budgets, 2021-22.

3. Major Fiscal Key Indicators at Aggregate State Level

Table 1 exhibit the trend of major fiscal indicators as a percentage of GSDP of states at aggregate level. It can be seen that, in the initiated years of the study period, there was revenue surplus in the accounts of state government which increased to 2 percent deficits as a percentage of GSDP, till the year 2020-21. No doubt, this may be due to Covid-19 to much

deficits, which increased to 4.7 percent of GSDP and has been around 3.7 percent, by the end of the study period, seems unfollow the path of FRBM Act, 2003. Primary deficits also increased to 2.7 percent, in year 2020-21, followed a decline by 1 percent, by the end of the study period. Primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payments which explain the scope for the governments for which government can make policy for the reduction of wasteful or unnecessary expenditure to its fiscal deficit. Increasing ratios of primary deficits, also seems matter of concern, which explain limited scope for the state to reduce unnecessary expenditure. Interest payments have been around 1.5 to 2 percent of GSDP all over the study period, doesn't seem significant reduction in interest payment during the study period. The FRBM Act, says that states have to try to bring their fiscal deficit down to 3% of GDP but this seems impossible as the interest payments of most states are around or even more than 2% of GSDP. The high level of interest payments in the fiscal deficit challenges the sustainability of debt at state level.

High level of interest payments, converted surpluses into deficits in revenue account of states. It can be seen that, if there have had not been interest payments, there would have been revenue surplus in the accounts of the state government, at aggregate level and same situation could had been for individual state, which is not a matter of study here.

1. Pattern of Expenditure on Some important components of Social Sector

Social services are the various types of services provided by the government to the common people of the society which are used by people on daily basis. Due to externalities engaged with these services, these are called public goods/services. Social services include education, sports, art, culture, medical facilities, family welfare, water supply and sanitation, housing, urban development, welfare of SC/ST, labour welfare, social security, nutrition, natural calamities and others services. Revenue and capital, both kinds of expenditure, on social services are included combinedly, in the present study, to examine the various ratios of expenditure on social services.

Year	As a Percentage of GDP				
	Gross Fiscal Deficit	Revenue Deficit	Primary Deficit	Primary Revenue Deficit	Net RBI Credit to States
1	2	3	4	5	6
2011-12	(1.9)	(-0.3)	(0.4)	(-1.8)	(-0.0)
2012-13	(2.0)	(-0.2)	(0.5)	(-1.7)	(-0.0)
2013-14	(2.2)	(0.1)	(0.7)	(-1.4)	(0.0)
2014-15	(2.6)	(0.4)	(1.1)	(-1.2)	(0.0)
2015-16	(3.1)	(0.0)	(1.5)	(-1.5)	(-0.0)
2016-17	(3.5)	(0.3)	(1.8)	(-1.4)	(0.0)
2017-18	(2.4)	(0.1)	(0.7)	(-1.6)	(0.0)
2018-19	(2.4)	(0.1)	(0.8)	(-1.6)	(-0.0)
2019-20	(2.6)	(0.6)	(0.9)	(-1.1)	(0.0)
2020-21 (RE)	(4.7)	(2.0)	(2.7)	(0.0)	(0.0)
2021-22 (BE)	(3.7)	(0.5)	(1.7)	(-1.4)	(0.0)

RE: Revised Estimates. BE: Budget Estimates \$: Based on latest GDP.
 Notes: 1. Negative (-) sign indicates surplus in deficit indicators.
 2. Revenue deficit is the difference between revenue expenditure and revenue receipts.
 3. Gross fiscal deficit is aggregate expenditure (aggregate disbursement net of debt repayments) minus revenue receipts and non-debt capital receipts.
 4. Primary deficit is gross fiscal deficit less of interest payments.
 5. Primary revenue deficit is revenue deficit less of interest payments.
 6. The net RBI credit to State Governments refers to annual variations in loans and advances given to them by the RBI net of their incremental deposits with the RBI.
 8. Data from 2017-18 onwards include Delhi and Puducherry also.

extent. Situation can be seen more worse for the fiscal

Various ratios of total expenditure on social services are presented in Table 2. Expenditure on education as a ratio of aggregate expenditure declined by 2.9 percent basis during the study period, as percent of GSDP also, ratio has been stable around 2.6 percent. Statistics do not appear to reveal any satisfactory situation for development in terms of expenditure on education. Situation has been extremely disappointing.

The situation has been slightly better in terms of medical services compared to education. Expenditure on medical, public health and family welfare as a proportion of aggregate expenditure, increased by 1.8 points, during the study period and as a percentage of GSDP, it increased to above 1 per cent, by the end of the study period. There is no doubt, that the increase in expenditure ratio for medical purposes in 2020, has been definitely due to Covid-19. In the absence of this natural disaster, the situation would have been different.

Social sector expenditure as a percent of total disbursement increased from 38.7 percent in 2011-12 to 42.5 percent in 2021-22. Social sector expenditure as a percent of total disbursement increased from 38.7 percent in 2011-12 to 42.5 percent in 2021-22. In spite of unsatisfactory status of expenditure on education, this 3.8 percent increment in expenditure on social services in total disbursement gives satisfaction to some extent.

Expenditure of states on medical and public health, family welfare and water supply and sanitation as percentage of GSDP is shown separately in Table 3. This data was available

Particulars	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(RE)	2021-22 (BE)
(1) All States and UTs Expenditure on Education as a ratio of Aggregate Expenditure	16.3	16.4	16.5	16	15.3	14.7	15	14.4	15.1	14.3	13.6
(2) All States and UTs Exp on Education (% to GDP)	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.7	2.6
(3) All States and UTs Expenditure on Medical, Public Health and Family Welfare as a ratio of Aggregate Expenditure	4.2	4.3	4.4	4.8	4.7	4.6	5	5	5.1	5.6	6
(4) All States and UTs Exp on Medical, Public Health and Family Welfare (% to GDP)	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1	1.2
(5) Social Sector Expenditure as per cent of Total Disbursement	38.7	39.3	39.8	41.0	41.1	41.7	41.1	40.2	40.4	40.9	42.5

Notes: (i) Aggregate Expenditure includes revenue and capital, both kinds of expenditure, on social services. (ii) Total Disbursement includes revenue and capital expenditure on social and economic services (including payments of loans for these heads)

Source: RBI, State Finances: A Study of Budgets.

Year	Per cent of GDP				
	Total Expenditure*	Medical and Public Health*	Family Welfare*	Water Supply and Sanitation*	Medical and Public Health, Family Welfare and Water Supply and Sanitation*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2+3+4)
2020-21	17.2	0.9	0.2	0.4	1.4
2021-22 (BE)	18.0	1.0	0.1	0.5	1.7

Source: RBI, State Finances: A Study of Budgets

only from 2020-21, hence only previous years of the study could be included, which may be taken as a limitation of the study. Expenditure for all social services, mentioned in this table, has been around only 1.5 per cent of GSDP. Nominal growth noted for these services.

1. Income Elasticities of State Government Expenditure on Social Services

Income elasticity of Expenditure can be defined as a percentage change in expenditure with respect to percentage change in income of the state/government i.e., Gross State Domestic Product (GSDP).

Percentage change in Expenditure

$$\text{Expenditure Elasticity} = \frac{\text{Percentage change in Expenditure}}{\text{Percentage change in GSDP}}$$

Percentage change in GSDP

In the present study, expenditure elasticities are calculated separately for Revenue Expenditure (REXP) and Capital Expenditure (CEXP) on social services. Revenue expenditures are the ongoing operating expenses, which are short-term expenses used to run the daily activities whereas, Capital expenditures are typically one-time large purchases of fixed assets that will be used for revenue generation over a longer period. Assuming a Log linear relationship between whereas, Capital expenditures are typically one-time large purchases of fixed assets that will be used for revenue generation over a longer period.

Assuming a Log linear relationship between expenditure and state income, following regression equations have been used to estimate expenditure elasticities for revenue and capital expenditure on social services respectively: -

$$\ln(\text{REXP}) = \alpha + \beta \ln(\text{GSDP}) \text{-----(1)}$$

$$\ln(\text{CEXP}) = \alpha + \beta \ln(\text{GSDP}) \text{-----(2)}$$

The estimate of α would signify the logarithm of the level of expenditure when state domestic product normalises to unity. β represents the elasticity of expenditure. The elasticity would be higher, expected or lower depending upon whether the estimated value of β is

greater than, equal or less than unity i.e., $\beta >, =, < 1$. This implies that expenditure will grow faster, equal or less than the growth rate of state domestic product depending on whether $\beta >, =, < 1$.

2. Analysis of Results

Results obtained from OLS expenditure equation 1 have been presented in Table 4. Values of R^2 of has been low or moderate whereas corresponding values of F statistics found satisfactory except, Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Labour Welfare, Nutrition, Natural Calamities and Others. Table 4 shows that, elasticities of revenue expenditure on various social services have been more than 1 but for nutrition it has been very low which points towards hunger. although revenue expenditure elasticities for Education, Welfare of Sc/St Labour Welfare and Natural Calamities have been greater than one but these services could catch these figures of elasticities barely.

There has not been any data for capital expenditure on labour welfare, nutrition and natural calamities, due to which, study for only remaining compositions of capital expenditure on social services, has become possible. Results obtained from OLS expenditure equation 2 have been presented in Table 5. Like revenue expenditure, values of R^2 for capital expenditure on most of the social services also found low and moderate whereas, corresponding values of F statistics found satisfactory except, Housing. Capital expenditure elasticities for Medical & Public Health and Housing has been below than 1 indicates low increase in capital expenditure for these services. Capital expenditure on social services, seems to follow the deteriorated financial condition of states at aggregate level by the end of the study period.

With the exception of Education, Sports, Art & Culture and Family Welfare, elasticities for capital expenditures for all services have been below than the elasticities for revenue expenditures indicates no attentions and priorities have been given to the development of physical infrastructure at states level. Housing and Medical Facilities are basic necessities for everyone, which should be on top priorities in the development policies of state governments.

Ln (REXP) = $\alpha + \beta$ Ln (GSDP)			
Expenditures	Intercept (t-Value)	LN (GSDP) (t-Value)	R2 (F-Value)
Revenue Expenditure on Social Services (1 to 12)	-10.312 (-2.113) **	1.452 (4.901)	.750 (24.017)
1. Education, Sports, Art and Culture	-3.734 (-.689)	1.004 (3.052)	.538 (9.314)
2. Medical and Public Health	-13.171 (-2.735) *	1.498 (5.125)	.767 (26.263)
3. Family Welfare	-11.430 (-2.177) *	1.283 (4.025)	.669 (16.197)
4. Water Supply and Sanitation	-23.869 (-2.716)	2.069 (3.877)	.653 (15.028)
5. Housing	-24.438 (-2.807)	2.080 (3.933)	.659 (15.467)
6. Urban Development	-20.603 (-3.245)	1.901 (4.932)	.752 (24.322)
7. Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	-5.909 (-.894)	1.027 (2.559) *	.450 (6.548)
1. Labour Welfare	-10.744 (-1.323)	1.025 (2.444) *	.428 (5.974)
2. Social Security	-13.171 (-2.735) *	1.498 (5.125)	.767 (26.263)
3. Nutrition	9.972 (169.365)	.002 (.499) ***	.030 (0.249)
11. Natural Calamities	-6.987 (-.788)	1.038 (1.927)	.317 (3.713)
12. Others	-16.170 (-3.359)	1.498 (5.125)	.030 (0.299)

Note: '*' indicates Significant at level of 5 percent, '**' indicates Significant at level of 10 percent, '***' indicates Insignificant value.

Source: Calculated by Author.

Ln (CEXP) = $\alpha + \beta$ Ln (GSDP)			
Expenditures	Intercept (t-Value)	LN (GSDP) (t-Value)	R2 (F-Value)
Capital Expenditure on Social Services (1 to 9)	-14.275 (-1.816) **	1.547 (3.241)	.568 (10.502)
1. Education, Sports, Art and Culture	-16.275 (-2.070) **	1.547 (3.241)	.568 (10.502)
2. Medical and Public Health	-5.799 (-.712)	.923 (1.865) **	.303 (3.479)
3. Family Welfare	-38.196 (-3.018)	2.666 (3.469)	.601 (12.034)
4. Water Supply and Sanitation	-16.860 (-2.035) **	1.631 (3.243)	.568 (10.514)
5. Housing	-3.534 (-.317)	.749 (1.108) ***	.133 (1.228)
6. Urban Development	-18.005 (-2.020)	1.677 (3.098)	.545 (9.595)
7. Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	-12.430 (-2.367)	1.283 (4.028)	.669 (16.197)
8. Social Security and Welfare	-11.569 (-1.405)	1.183 (2.365)	.412 (5.595)
9. Others *	-8.734 (-1.612)	1.004 (3.052)	.538 (9.314)

Note: '*' indicates Significant at level of 5 percent, '**' indicates Significant at level of 10 percent. '***' indicates Insignificant value.

Source: Calculated by Author.

7. Conclusion and Policy Implications

In nutshell, in this study, it is found that, fiscal key indicators of the states at aggregate level deteriorated by the end of the study period, obstacles in the execution of various economic activities due to Covid-19 may be the broad reason for this. With the exception of some social services like Nutrition, Medical and Public Health and Housing, expenditure for most of the social services increased more

than the increase in income of the states at aggregate level. But there are some shortcomings like: **firstly**: - for some social services like Labour Welfare, Housing and Natural Calamities there has not been any capital expenditure for these services (can be said by non-availability of data). If there has been capital expenditure that might have been negligible in amount, **Secondly**: - elasticities for capital expenditure on social services have been much lower than the elasticities for revenue expenditure for these services, which raise the matter of serious concern for the development of physical infrastructure simultaneously for the human development in the states, and **Thirdly**, weak correlation found between the states income and expenditure on the social sector, leads to low level of welfare in the society.

State governments should redesign and prioritise their human and infrastructural development policies to incur more, revenue and capital expenditure, on Housing, Food Security for Nutrition, Labour welfare and on Other Social Service, as per requirements, to enhance the level of physical and human capital in the nation. No doubt, only expenditure is not the guarantee of welfare, effective implementation of the policy is also a crucial aspect of the welfare policy which should be considered. Targeted people should be covered by welfare policies for which government needs to work on its policy implementation mechanism also.

Bibliography

- Lamartina, Serena and Zaghini, Andrea (2019), "Increasing Public Expenditure: Wagner's Law in OECD Countries", German Economic Review, Published by De Gruyter, <https://doi.org/10.1111/j.1468-0475.2010.00517.x>
- Pranjali, Mittal (2016), "Social Sector Expenditure and Human Development of Indian States", Online at <https://mpra.ub.uni-erlangen.de/75804/> MPRA Paper No. 75804, posted 25 Dec 2016 01:31 UTC.
- Joshi, Seema (2006), Impact of Economic Reforms on Social Sector Expenditure in India", EPW, Vol. 41, Issue - 04, 28 Jan, 2006.
- Mukherjee, Sacchidananda and Badola, Shivani (2021) "Public Financing of Human Development in India", Indian Journal of Human Development, Vol.15, Issue -1, April.

- Khoja, Ishfaq Ahmad and Khan, N.A. (2019), "Fiscal Adjustments and Social Spending: An Analysis of the Indian Economy", Arthshastra Indian Journal of Economics and Research, Vol. 8, Issue - 3, May-June.

Dr. Manju Dalal

Associate Professor (Economics),
B.P.S. Institute of Higher Learning,
Khanpur Kalan, Sonapat, Haryana- 131305,
email: manjudalal2007@gmail.com.



Abstract:

This research paper explores the intricate relationship between post-humanism, education, and technology, tracing this evolution from historical critiques of human existence to the present day. Focusing on seminal works like "Anatomy of Melancholy" and "Utopia," it reveals early hints of post-humanist thought. Post-humanism is analysed not just as a futuristic concept but as a continuous historical thread, marking a profound shift in our interaction with technology.

The study delves into the phenomenon of post-human suffering, arising from society's increasing reliance on technology for survival and identity. It scrutinises the educational landscape, revealing a society deeply intertwined with technology, reshaping conventional methods of knowledge dissemination and evaluation. The rise of the internet and artificial intelligence democratises information, yet the politics of speed, as theorised by Paul Virilio, ushers in an era defined by perpetual motion.

Additionally, the paper critiques examinations, often acting as exclusionary tools, perpetuating social disparities. Amid these challenges, ethical considerations in technology integration are paramount. The research advocates for a balanced approach, preserving human essence while embracing the transformative potential of technology.

In navigating the complexities of the post-human world, the study emphasises the need for a nuanced understanding. This comprehension is crucial for harmonising the symbiotic relationship between humans and technology, ensuring human identity remains intact while harnessing technology's transformative power in education and society.

Keywords: Post-humanism, Education Technology, Post-Human Suffering, Ethical Technology Integration, Paul Virilio's Dromology.

Discussion:

Post-Humanism is like all post-discourses about something that went before Humanism. Humanism is the most wonderful thing that happened to us at that time because Humanism resolved a lot of problems at that moment of history. Humanism was a solution to the traumas and the trials and injustices that human beings suffered from at the beginning of the Renaissance and in the late medieval period. But like all discourses humanism also went hand in hand with its own critique, even from the beginnings of humanism it can be seen that there has been a post-humanism in existence in the sense of

critique of humanism and what lies beyond the human. We see in renaissance literature for example a lot of non-human entities the ghost in Macbeth or any ghost in Shakespeare the man infestations of the human mind and the terrors of human existence in the forms of some supernatural entities, that is also one early example of post humanism. Even though today we connect post humanism mostly with technology. There was a lot of satire and critique of the human existence in books like Anatomy of Melancholy or Utopia or any of the classics one can think about. The classics are Classics because of the critique that they did of our existence which has a perennial enduring effect and after this we moved on to the postmodern period and then the trans humanist period and now the post humanist period. All these are large terms that actually try to attempt to understand back in the 18th century we placed the human being along with Gods, along with the universe and its various manifestations such as in the great chain of being, we see that human being is part of a whole massive network starting from God and the angels going down to the minerals. So everything that all the discourses that we have initiated and we have thrived on are ultimately about in many ways ourselves.

What is this recent trans humanism and post-humanism?

We have, in the past 50 years or so, a lot of proliferation of science fiction and technological interference in our novels and movies and this trans humanism or this phase that is called is a way of enhancing the human, going beyond the average human, looking at what human beings cannot do and trying to find solutions for it. So the trans human is way of negotiating with our limitations, negotiating with our mistakes and problems, trying to understand what lies beyond the limitations of the human. Even in trans humanist discourses like science fiction there are lots of ways in which the human is questioned. So it is also in a way a critique of humanism. The technological enhancement of human capabilities came with the coming of the internet and also all the changes that happened in our discourses because of these technological advancements that have been exponentially growing.

Then we have the post-human phase. In the post-human phase, the human being is no longer the centre of the world, but not in the sense of going beyond our capabilities and enhancing them

but more in the sense of cohabiting the world with the non-human (the non-human can be machine, the animals etc.). Perhaps it is why in the post-humanist discourses there is animal studies, all kinds of machine studies, data feminism, perhaps every aspect of the human life has now become in some way connected to what is the non-human and we are trying to peacefully coexist with the non-human in many ways and this also touches upon discourses like environmentalism because on the one hand when we talk about machine on the other hand is nature, so new ways of understanding the environment, new ways of understanding the society, new ways of understanding even education or Politics or Media or any of the discourses which we inhabit. As needless to say as, it is an age of cloning, of genetic engineering, of organ transplants and all the ways in which we are technologically trying to solve our problems. How we can live a longer life, how we can remember more or learn more or experience more deeply, how we can enhance our human life in many ways perhaps trans humanism has merged into post humanism and this enhanced human being is now living in in the context of all the other non-human entities of the universe.

The post human is a blend in experience that the post human is a blend of the actual and the virtual because technology gives us experiences that are beyond our understanding, that are beyond our normal level of human intelligence or human capability. This is a world where one can access a sublime level of existence through the use of Technology, maybe in a roller coaster or while watching a Hollywood movie or while using some of the other technological enhancement devices in the media industry etc.. Thus, this is a time when we are in a process of extending beyond ourselves, coming through the trans human, we are in the process of becoming something else maybe because starting from Darwin we know that human being is in an evolutionary stage, human human being is a link in a chain of evolution so this is a process in which we are trying to come to terms with what lies around us and this post human is in a way quoting Arnold:

“Wandering between two worlds-one dead, and the other powerless to be born”

Because the human is our reality, the human is what we are because if we cut our finger, it still bleeds or if you hit your toe, it still hurts. Perhaps, the human is the real the post human. Like the global is virtual in in many ways, the human is the real, the local is the real, the indigenous is the real, and the global, the transnational, the post human is the virtual. Therefore we are caught between two worlds, one real and the other virtual. We are not happy with our reality and we are

continuously negotiating with that virtual reality that we want to belong to.

Concept of Post human Suffering:

This is a world when we are all trying to cope with our existence, our realities, which for all of us has to do with education. Human beings are incapable of knowing themselves or mastering their environment except through technology.

Can you know what is inside your body, can you know what is there in the region that you're living except unless you use the satellite camera, unless you use Google you cannot really know, you cannot view of what is happening in this world around us we cannot know what is inside our body except through technology. These are two small basic examples and there are multifarious ways in which technology is helping us to be human. We are living because of all the medical technology and all the technology that is there around us otherwise we would have died, we would have perished.

So to be human, we are depending so much on technology and without technology not only can we not know ourselves instead we cannot even exist, this is the condition these days. It is very interesting to know how the discourse of death has changed of late. Death has become so much institutionalised, so much commodified, there is even something called Death studies. What is happening is when you fall ill or when you become old especially in the multinational cities in the Metropolis etc the hospitals does just take over, you cannot suffer pain or the normal suffering that we have in our lives of pain of Sorrows etc. even we don't experience these days because technology numbs us. When we feel sad, we don't cry, we don't process our sadness, we just take refuge in technology or when we are in pain, we take take refuge in technology. So what we are kind of seizing to experience, what is what is human because we prioritise the virtual or the post human or beyond what is human. This is one side of it, the other side is that technology completes us. Without technology I will not be able to speak, write to you or you will not be able to do research, human beings will not be able to achieve whatever they are achieving in this world without technology.

Thus, post human suffering is the knowledge that we are incomplete and inadequate without technology. If suddenly the technology that we use such as, a laptop or a mobile phone or a refrigerator or a washing machine or any of these things that are so much part of us that once we start using them, you cannot stop using them perhaps you become dependent on them.

Human beings are not turning naturally into post human, these needs of technology are thrust upon us also. It is not our natural need rather it is that we are made to believe that we should use these technologies, i.e., our life is incomplete without these technologies.

In education technology, among a lot of positive effects one is the access to exponentially growing knowledge. So much knowledge across the world is at our fingertips and that is also why research is burgeoning these days, everybody's doing research because it is easy to do research-one can just go online, take whatever one wants, either read it or copy it or understand it and rewrite it. The concept of research was an intellectual, personal, philosophical, reflective activity in the past but because of age of globalisation, globalised media and technologies have completely transformed research and education. Technology gives us the means of storing, processing, analysing knowledge.

Post human Society understands that it is impossible to have education without technology because technology is all about expression and communication. Before a year or two, we were all using PowerPoint Presentations and other apps etc. to convey our ideas but now we are also using AI. The experience of the human is multifold chain changing because of the use of artificial intelligence. It is good because even though we may critique it at some point but we all use it because it is a wonderfully attractive way of expressing, knowing, processing, and communicating knowledge in education as well as facets of our life.

Lastly what does technology give us? Speed.

Today we have reached a stage when we have become so productive that every day one can learn new things, at breakneck speed Professors can write papers or books etc.. Everything has become so fast that people who are not keeping up with the pace in which the world is growing are left behind. Sadly, because nobody is going to stop for us, there is so much of everything happening everywhere at break neck speed, at supersonic speed, and whether we realise it or not, the post human educational scenario around us is growing at an unbelievable speed. And now is that good or bad, we always think that speed is good, we will all be happier if we could do things faster because speed is something we all desire to have. Even when we say I am a slow person, you are thinking that it would have been better if you were a little faster. But as we all know speed has its disadvantages also, and not only disadvantages but also politics.

What is Politics of Speed?

Paul Virillio is a very important theorist these days, who has talked about the city as being made on the model of warfare.

Paul Virillio has written about the war model city wherein he theorised the interconnection between speed, technology and war. Paul Virillio is a French writer, died recently in 2018 and he lived in the thick of all the developments that happened in the European world, the Western World. He developed a new concept of the modern city relating it to the speed, technology and war.

There is one of his works *Speed and Politics: Essay on Dromology* (1977), where Paul Virillio analyses this war model city. Dromology is a term that he developed in the context of this war- based city. He analyses the importance of accelerated speed, how accelerated speed turns us into post human. At the same time, it also creates an artificial world where it is very difficult for us to inhabit and it also has its own politics because this concept of speed and technologies of motion, the concept of mobility, is all ultimately according to Virillio based on the reality of warfare. It is shocking to realise that many of our Technologies including internet are developed in the context of warfare and war is the biggest industry in the world, the arms and ammunition industry is in a way what rules the worlds. It is what requires maximum financial support, the maximum money flow is there and the power centres are also there. America and its involvement in war in the second half of the 20th century is a case in point. Here, Virillio is talking about how the postmodern world or the post human world, is deeply related to ideas related to war and he calls it the Dromology or Dromocratic Revolution, how Innovations in speed influence social and political life. Here in the war model society where we are all living in a breakneck speed, culture is changing, education is changing, politics is changing. There is more disorder, there is more anarchism, people are always on the move and this is what many theorists have foretold of the future, in the studies of the future, futurism or futuristic studies or Futures theories, i.e., many discourses have developed in the past relating to Futures. Everybody has had a in Culture Studies deeply leftist view, everybody has had traditionally a rather negative and paranoid view of the Futures where we have Deleuze and Guattari or Marshall McLuhan or Jean Baudrillard or Slavoj Zizek etc. who talked about the the fear and paranoia that future entails us. Virillio, especially relates it to the representations of this city and the representations of the human being in cinema also (war is related to cinema)

War Model City

He shows that the city and all its institutions, including education or religion or politics or economics all have

ultimately military origins. Even Friedrich Nietzsche, has talked about Christianity, in his *Genealogical Study of Christianity*, how Christianity emerged from the conflict of the weaker people with their rulers and the values of the weaker people like submission, suffering etc. These have been understood as greater values compared to the values of the rulers like power or authority, so it is a military conflict that has led to development of humanity in many ways, he even uses the example of churches as fortified defence.

As We Know from history, and in a very interesting way Virillio shows that the city and its institutions have military origins and this is also related to the city life in the streets, where people are moving about and they are buying things, everyday life in the streets is lived out thus, there also city life lies. The spectacle of the street is a very important concept in this regard. The spectacle of the street where one can also relate it to Baudrillard's concept of the spectacle- the traffic of the people, the progressions and movements and events, the conflicts and debates and liaisons.

For example- City of Bath in the United Nations, where lots of people used to come and do their transactions, they used to do a lot of undercover things etc. In Ibsen's *Enemy of the People*, the city where people's life is so much tied to the Bath, that is the theme of *Enemy of the People* and when these baths are declared to be polluted the people cannot take it because it is in that public bath that their life is.

This Overexposed City is penetrated by media and advertising, information technology. It is according to Virillio, Overexposed. Guy Debord talked about *Society of the Spectacle*, where for us everything is a spectacle in this overwhelming urban space and life. There is so much of the spectacle in education, we have to show that we know, we are good writers, we are knowledgeable people, we are all desperately trying to groom ourselves so that we can belong to this crowd that is out there.

The War Model City can be compared to the war model education. Power/Knowledge as Foucault termed it is growing exponentially, it's multiplying, it's ubiquitous, it's everywhere like the second world war- everywhere there was bombing, everywhere people were suffering and struggling and dying. Here, Power/Knowledge is growing exponentially. Everyday so many new disciplines are coming into being, like- critical planned studies, security studies, peace studies, critical disaster studies, death studies, conflict studies, suicide studies etc. So, why do we have to lay out our society, our life like a patient etherised upon the table or why do we have to dissect this body so closely, why do we have to look at every single aspect of the society? It is because knowledge is no longer a simple, straightforward thing in this

posthuman education. Knowledge is a complex assemblage to use a term by Deleuze and Guattari- Knowledge is a complex assemblage like weapons. Weapons are not simple things, in order to defeat enemies, one has to use very complicated weapons. Similarly, the knowledges have become our weapons with which we are waging this war called Education.

One good side of it is that knowledge today is no longer the prerogative of the centre or the universities, the universities are no longer holding knowledge within themselves. Knowledge is everywhere because of the internet, everyone of us has access to knowledge. But the other side of it is that we are all constantly under pressure. Look at exams, it has become so undemocratic. There is so much conflict, everything is based only on performance like war. In war also it doesn't matter who you are, what your moral position is, whether you are good or bad it doesn't matter, only matters is how you perform, how you can wield your weapons and these weapons are in the form of exams, the jobs that we aspire for and also our race, class and gender these are all becoming weapons against us. People of some class cannot ever pass an exam because exam requires a lot of money to prepare, for people of some gender cannot study because they do not get access to education, they have too many non-academic things to do in their daily lives. So it is not a very simple and democratic world. In a war, like- Septimus Warren Smith in *Mrs Dalloway* written by Virginia Woolf, was suffering from shell shock. When you are fighting in the war you are traumatised, there is a PTSD syndrome that develops in you, similarly in the educational scenario there is so much rootlessness and restlessness and depression, is like a mechanism of subjugating the society.

In War Model Society, War model City, War Model Education one becomes posthuman, one stops being human and this speed that one acquires will only augment the wealth and power of those groups that control us. The groups that control university education and the economic sector etc become more powerful because we cater to their needs and we live according to their requirements, control and power is manifested as devices that accelerate speed as well as reduce speed. There are two ways in which power works upon us there are two ways in which technology works upon us- One is to accelerate our speed and the other is to reduce our speed. The apps, learning technology, the educational technology that we use accelerate our speed. But on the other hand, exams that people write are ways of reducing speed also because we have to wait for a long time as everybody realises education is not only about your merit

rather it is also in many ways about your luck . Because it is exam oriented, if you have a headache on the exam day or if you could not reach the exam centre on time, your merit is gone and you are out of the race. So how democratic is it? Perhaps, exams are a weapon wielded upon us and we should understand that when we prepare for these exams, they diminish our speed and productivity in many ways. For years people spend their youth trying to pass exams while they should be contributing to the society. This is all because the university works like a corporate. The university is a corporation where there are only two focuses - focus one is elimination. People are eliminated for the wrong reasons also and not only the right reasons and second focus is on productivity. They want only the rich people, metropolitan people or only the capable people to come and take exam and pass exam. This corporation that the university is a very dangerous thing because universities have had a centuries of tradition, they were there even before Renaissance occurred and universities should not become corporations because it is a means of dehumanising people, it is a means of turning people into the posthuman.

References:

- Baudrillard, Jean. *Simulacra and Simulation*. University of Michigan Press, 1994. (Original work published in 1981).
- Debord, Guy. *The Society of the Spectacle*. Zone Books, 1995.
- Haraway, D. J. (1985). "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century." *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*. New York: Rutledge.
- Hayles, N. K. (1999). "How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics." *The University of Chicago Press*.
- Arnold, Matthew. "Grande Chartreuse." Lines 109-112.
- McLuhan, Marshall. *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*. University of Toronto Press, 1962.
- Virilio, Paul. *Speed and Politics: An Essay on Dromology*. Semiotext(e), 2006.
- Wolfe, C. (2009). "What is Posthumanism?" *University of Minnesota Press*.

Abstract

Educating the girl child refers to every aspect of education that aims at developing the skill and knowledge of girls and women. This includes the general education at colleges, schools, professional education, technical and vocational educations, health education, etc. The education of the women encompasses both non-literary and literary education. The education of the girl child has the ability of bringing socio-economic changes. Democratic countries including India have a constitution that guarantees equal rights to both women and men. Primary education is a key right. When a girl is protected through her rights, the society is assured of its sustainability. Realizing how important education is, both government and non-government have taken various projects to strengthen girl's child education. Realizing the importance of women education, the government, and many non-government organizations took many projects to spread women education. Literacy programs are being taken in favour of women. Girl child education is a pivot for families, communities and societies today. Investing in girls' education transforms communities, countries and the entire world. Girls who are able to get educated will be able to join the workforce, earn livelihoods, take care of their families and marry at a mature and responsible age. This way they can build better futures for themselves and their families.

In today's society, gender equality continues to be a prevalent problem because of the persistent gap in terms of access to chances for women and men. Gender equality is a basic human right that every human being is entitled to regardless of race, sexuality, ethnicity, or religion. The role men and women play in society is completely determined and as a result, there is a gender gap. When girls in our community are more educated, more influence is placed on gender equality. As women get equality, human rights become a powerful value of societies as women in governance tend to fight for underprivileged groups. Women's leadership in government also becomes more prevalent, and when women lead, women push for more impartial rules of governance.

Educated girls gave higher courage and independence to make

decisions that change their lives. They are better promoted to examine the social imperative that women reside in the home, growing children and doing the regular housework. Education from the best schools in India enables young women to think beyond cultural standards and continue their desires for a better life. One of the clearest and obvious benefits of educating girl child from the best schools in India is the prospect for the economic development of a country. When women of a country are learned and educated, the whole economy develops and flourishes. The educated girl becomes an educated woman. Offering girls with education is a primary step in developing future generations of healthy, educated, and empowering girls. Educated women of the community can become future leaders, direct towards transformation, and build more powerful and significant societies. And therefore, a nation is regarded only as wealthy because of its citizens. It is one of the vital importance of girl child education. The educated girls can demonstrate to be strong in their several professions. When the girl child has the chance to be educated it offers her the better opportunity to become a successful engineer, doctor, or the choice of the profession she wishes.

Educating girl child assist in the improvement of a good life. The girl can read and learn about her rights. They won't be trodden down about her rights. There will be a general improvement in their life. Educated girls bring an awareness of the importance and health and hygiene. Girl child education is one of the most vital concepts. Every girl in our society must have to be educated because education is the most influential and vital weapon that can be used to solve the difficulties of human lives. Educating the girl child refers to every aspect of education that aims at developing the skill and knowledge of girls and women. This includes the general education at colleges, schools, professional education, technical and vocational educations, health education, etc. The education of the women encompasses both non-literary and literary education. The education of the girl child has the ability of

bringing socio-economic changes. Democratic countries including India have a constitution that guarantees equal rights to both women and men. Primary education is a key right. When a girl is protected through her rights, the society is assured of its sustainability. Realizing how important education is, both government and non-government have taken various projects to strengthen girl's child education. Realizing the importance of women education, the government, and many non-government organizations took many projects to spread women education. Literacy programs are being taken in favour of women. Apart from ensuring enough schools and their easy access to girls, many key elements need to be in order before girls' education can increase and run a smooth course. So, while dedicated educated classrooms and schools for girls will boost attendance, there are several other issues that need to be addressed and resolved. Such as;

1. Girls' safety within these surroundings is paramount— often parents are scared of distances that their girls need to travel to receive an education. Especially in rural areas where neither roads nor transportation are available or reliable. This can be a deterrent leading to massive dropouts from girls attending school.

2. Access to free education— this is the only way that parents in marginalized and rural economies will agree to send their girls to school. By eliminating any expense and cost burden to families will make them more receptive to the idea of education.

3. The academic curriculum ideally should be a blend of subjects and vocational courses that support girls in the careers they choose to pursue. The curriculum offered should be created keeping in mind that most of these girls are likely to be either married off or allowed to work in selective professions. In both cases, apart from traditional education methods, schools should also offer robust and easy to understand vocational courses that can be of help should girls wish to pursue occupations in their later age

4. Access to free and hygienic sanitation— this is also one of the reasons why we see girls dropping out of schools without completing even their primary education. Schools set up in rural areas as well as tier 2 and 3 towns should have

provisions for clean toilets and hygienic waste disposal system for girls to avail of during their menstruation cycles

5. Language based education— Native language centric education will see higher consumption amongst families who prefer their children being educated in their mother tongues. This also helps in parents being involved in their child's education making them willing and open to send their daughters to school as well.

6. Freedom to study with no burden of household chores— once parents understand that the role of education for their girls is equally important as it is for their sons, they can be persuaded to let the girl child study without expecting her to help with household chores. Parents need to see the benefits of education for the girl child and how it will impact and enhance their quality of life. Once we are able to achieve that, girls can devote their time to learning well and studying hard.

“Beti Bachao, Beti Padhao” (“save the girl child, educate the girl child”) is the country's slogan to prevent female infanticide and move the spotlight to the importance of girl education. If India wants to be perceived as a highly developed nation and one amongst the leading voices in world affairs, then it must focus on girl education and work hard to ensure that there are no gaps and education is openly and freely offered to both genders. Around the world, 129 million girls are out of school, including 32 million of primary school age, 30 million of lower-secondary school age, and 67 million of upper-secondary school age. In countries affected by conflict, girls are more than twice as likely to be out of school than girls living in non-affected countries.

The overall quality education can even assist prevent disputes in the first place by giving knowledge on social skills, problem-solving, and critical thinking at the schools. Investing in girls' education transforms communities, countries and the entire world. Girls who receive an education are less likely to marry young and more likely to lead healthy, productive lives. They earn higher incomes, participate in the decisions that most affect them, and build better futures for themselves and their

families. Girls' education strengthens economies and reduces inequality. It contributes to more stable, resilient societies that give all individuals – including boys and men – the opportunity to fulfil their potential. But education for girls is about more than access to school. It's also about girls feeling safe in classrooms and supported in the subjects and careers they choose to pursue – including those in which they are often under-represented.

I would suggest that every mother in the family should take step to send the girls child to school and every father should take initiative to reach the girl child to school as well as every brother should hold the hand of the sister to make her feel I am there for you.

Dr. Shibhu V Raja

Principal

Holy Mary International School

Pandasarai, Laheri Asab, Dahbhanga (Bihar)

Pin - 8466001

Mob. No. 7544001228

Abstract

Women have played a significant role in society since ancient times, contributing to various aspects of human civilization. At the same time, women have faced systemic discrimination under patriarchal systems from times immemorial. As a response to these inequalities, women often come together to form female spaces in order to create a sense of belonging and empathy amongst themselves. The true significance of female spaces, however, lies in their function as an avenue for women to subvert the patriarchal influences of society. This paper investigates female spaces in Indian society through an analytical study of the multiple generations of women from the pre-partition period to the contemporary period as portrayed in Mahesh Dattani's play *Final Solutions*. The paper also delves into the influences of patriarchy upon these female spaces and the power relations that exist between them. *Final Solutions* was published in 1992 against the backdrop of the Ayodhya communal riots is a work of great significance not simply because of its commendable social contribution. While the play is primarily built around the context of religious tensions and communal violence, it also provides a realistic depiction of the marginalized condition of women in Indian society throughout the latter half of 20th Century. This paper addresses the vulnerabilities and injustices faced by women in times of conflict, through a feminist psychoanalysis of the characters of Daksha (Hardika), Aruna and Smita.

Keywords – Marginalization, Patriarchy, Female Space, Identity, Powerlessness, Individuality.

Introduction

Post-independence Drama is not a sudden phenomenon. Drama in India has a 200 years long history, starting from ancient times to the contemporary times. We have had our own different theaters and British legacy has also been there for a long time. Theatre in the British Raj became well established in the west in Bombay, in South in Madras, in East in Calcutta, in North in Varanasi - the four major epicenters of theatre in India paved the way for the modern Indian Drama. Krishna Kriplani points out –

'The Modern English Drama owned its first flowering to foreign grafting.'

The post modern era proved to be fruitful for the Indian English Drama because of young writer like Mahesh Dattani and Manjula Padmanabhan. R.K. Dhawan observing

the same put forwards:

“Very recently Indian English drama has shot into prominence. Young writers like Mahesh Dattani and Manjula Padmanabhan have infused new life into this branch of writing. Both Dattani and Padmanabhan project stark realism through their plays. Dattani showcases the mean ugly and unhappy aspects of human life. Manjula Padmanabhan on the other hand delineates a dehumanized terrifying world in which mothers sell their sons for the price of rice.” (Dhawan, 201)

Mahesh Dattani, young Bangalore based playwright is considered as one of best playwrights of the post-independence era. He won Sahitya Akademi Award for his sensational work *Final Solutions* in the year 1998. His earlier plays - *Where There's a Will* (1988), *Dance Like a Man* (1989), *Tara* (1990), and *Bravely Fought the Queen* (1991). He is considered to be one of India's most daring, innovative and important playwrights in English language as he represents the actual image of the Indian society of contemporary times. His plays represent revolutionary themes and threshold issues of contemporary society, such as gender discrimination, child sexual harassment, gay-lesbian (LGBT) relationship, class conflict, matriarchy, generation gap etc. Dattani's plays touches to the reality, his characters are living and of heartening nature. His plays discuss the urge of people to create their own space in the society. Madhu Jain comments:

Dattani is an authentic contemporary voice whose plays are rooted in contemporary urban experience and yet have a significance which can travel beyond India's borders. Recognizing Dattani's plays as a mirror to the contemporary society, Prof. John McRae opines:

“Mahesh Dattani has given us images which could only be created in the theatre, images which deserve to be seen by audiences worldwide and he also says that these images have given Indian drama a vital place in modern theatre. The role of playwrights, according to Dattani, is to probe the tangled attitudes in contemporary India towards communal differences, consumerism and gender.” (McRae, 92) Dattani's play *Final Solutions*, first performed on 11 December 1993 at Tara Theatre, Mumbai, directed by Alyque Padamsee represents the communal issues through various characters that arouse fear and hatred among the individuals. Although the play particularly deals with the issue of

communal harmony, it also deals with miserable conditions of women in a society where male members behave like 'autocratic' rulers, and also depicts different ideologies of three generations of females through the characters of Daksha(Hardika), Aruna, Smita. Dattani portrays the outburst of female characters from religious bigotry to religious liberalism. The play, *Final solutions* was also translated into Hindi by Shahid Anwar and was performed in 1998 under the direction of Arvind Gaur for Asmita Theatre. *The play stretches from the Partition(1947) to the 20th century and studies the attitudes of three generations of women of a Gujarati family includes- Daksha-Hardika(mother of Ramnik Gandhi-representing the first generation),Aruna(wife of Ramnik Gandhi- representing the second generation),Smita(daughter of Ramnik Gandhi-representing the third generation). All the three characters depict their individual identity, do not consider themselves as shadow of males and thus, are making their own space in the patriarchal and religion prejudiced society. Dattani delineates through his dramatic techniques that women of the contemporary society can think beyond their physical conscience on political matters and have a better realization than man in every aspect of life. The play lingers between traditionalism and modernism throughout.*

DISCUSSION

Patriarchy is a social system, according to which men are believed to have more power, dominance, and privilege than women in both the public and private sphere. Daksha-Hardika is believed to be the sufferer of the patriarchal ideology from early childhood. She is subject to economic dependence, violence, domestication and the peripherals of decision-making due to her dependency on patriarchal figures in her life.

She was forced to marry at a young age of 16, by changing her name from Daksha to Hardika in order to match her name with her husband's name, Hari. She loved listening songs sung by Noor Jehan, Shamshad Begum and Suraiya, and wanted to become like them herself but was admonished from singing. Her miserable conditions are represented in her diary, wherefore she writes:

All my dreams have been shattered...I can never be a singer, like Noor Jehan. Hari's family is against my singing film songs. His parents heard me humming a love song to Hari last night. And this morning they told him to tell me...I am just a young girl who doesn't matter to anyone outside her home. (F.S. Act I p.4)

Daksha-Hardika was even abandoned to visit her friend, Zarine's house as she belonged to a Muslim family. She was also falsely accused of eating together with Zarine at her

house, as a consequence, her husband, Hari hits her for meeting Zarine without seeking his permission. Patriarchal ideology is depicted in Daksha-Hardika's dialogue which is as follows:

Ah! Do not hit me! (Angrily). Do not do that! I swear I did not eat anything! Ah stop that! All right. I won't go there again. Please leave me alone. (Crying) Please! Stop! (lies on the floor sobbing) (F.S. Act III p.71)

Furthermore, the paper delves into the psyche of all the three female characters, each possessing individualistic ideologies.

Daksha-Hardika, the eldest woman in the play is pictured as a distrustful woman of other religions due to her own distressing past events that took place forty years back.

"That night I couldn't sleep. I listened. I was angry that Ramnik was blinded by his ideals. Why did he offer that boy a job in our shop? What was he doing? How did he know they were innocent? Couldn't he see there was more violence in that boy's eyes than those stone-throwers' threats?" (F.S. Act I p.33)'

The significant shift from 31st March 1948 to the contemporary times reflect her prejudices of communalism through her diary, in which respect she mentions:

'After forty years... I opened my diary again. And I wrote a dozen pages before. A dozen pages now. A young girl childish scribble.' (F.S. Act I p.6)

Although very partial towards her own religion, Daksha-Hardika later on, at the end of the play realizes that her hatred for Muslims was self conceived and gets ready to bring change in her ideology that could be figured out through her last dialogue:

'Do you think...do you think those boys will ever come back?'(F.S. Act III p.75)

Aruna, a pious housewife 'Our Krishna will protect us'(F.S. Act I p.13), outlined as a prejudiced Hindu woman who gets infuriated on the arrival of Javed and Bobby, two Muslim boys, as all her religious prejudices that she has been practicing from her childhood are dealt a major blow.

'Why did he allow these persons access to my home? They murdered his granddad. They'll despise us for defending them. They feel inferior to us when they ask for assistance. I know!... they oppose equality. They aspire to be better. (F.S. Act p.)

Aruna is not liberal in her religious ideologies, perhaps laments her husband, Ramnik Gandhi to provide shelter to Javed and Bobby. She begs her husband to unlock the door and give the boys to the enraged crowd. 'Open the door and let them come and take them!' (F.S. Act I p.23)

She, in fact trembles in resentment when her husband asks her to feed the Muslim boys.

Ramnik- So bring them a glass of water.

(Aruna stares at him as if he has asked her to go and kill someone) (F.S. Act I p.26)

Her religious perspective can also be seen in the fact when she does not allow Javed and Bobby to touch the water vessels that she uses to bathe the gods.

She even enforces all the religious activities upon Smita thinking it is only correct way to teach her about God. Her husband, Ramnik is a non prejudiced practitioner of religion and thus resists Aruna's religious imposition upon their daughter, Smita.

Ramnik- I don't like the way you impose things on Smita

Aruna- How will she learn otherwise? She will end up like you. (F.S. Act I p.12)

Aruna belongs to a community of people with hollow religious beliefs that can be seen in several dialogues where Smita charges Aruna directly:

'I can see so clearly how wrong you are. You accuse me of running away from my religion. Maybe I shouldn't be. What if I did what you do? Praying and fasting and purifying myself all day...' (F.S. Act III p.57)

Aruna is stunned on discovering about her daughter's and Bobby's friendship and blames education as it's root cause. Educating people like Aruna is the only possible way to wipe out all prejudices from their minds concerning religion specifically and thus help them persuade liberal ideas. Aruna's shallow mindedness can be seen in the following dialogue of hers:

Aruna (to Smita)- You...you know them?

Smita- I know who they are.

Aruna- Stop her studies! From now on, she can stay at home! (F.S. Act II p.31)

Smita, unlike her mother and grandmother does not believe in religious prejudices, she represents the dynamism of new generation. Through her character, Dattani illustrates the liberal ideology that later on in the play helps to change the views of Aruna and Daksha-Hardika. Smita considers the whole situation as an individual and constructs an ideology beyond the ideology of religious and racial prejudices. She expresses her utter dismay in rebellious manner to her mother:

'This time for strength I am so glad these two dropped in. We would have never have spoken about what makes us so different from each other. We would have gone on living our lives with our petty similarities'(F.S. Act p.)

Smita represents the liberal voice and is rationalist and objective in her attitude. She confronts her prejudiced

mother by opening up her heart and putting forth opinion's regarding her mother's wrong beliefs under the name of 'sanskar'.

'It's all very well to have progressive ideas. But are you progressing or are you drifting? God knows, I don't want all this violence. How can I, when I won't even harm a goat or a chicken? But to throw everything away just like that? Doesn't it mean anything to you? For so many generations we have preserved our sanskar because we believe it is the truth! It is the way shown to us by our saints. We must know no other path.'(F.S. Act III p.57)

Her liberal ideology is constructed beyond the traditional religious prejudices. She, indeed feels suffocated due to her mother's religious biasness and desperately yearns for her freedom when she says:

"Maybe we should all run away from home like Javed. For five minutes every day. So we can quickly gulp in some fresh air and go back in" (F.S. Act III p.67)

Aruna feels dejected after learning that her college learned daughter feels burdened of what she is proud of. Smita holds the power to change the conventional thinking and to make better realization of her hidden potentials. She wants to take decision for herself and if it is right she can protest against those agencies who are responsible for her sublimation.

'It stifles me! Yes! Maybe I am prejudiced because I do not belong. But not belonging makes things so clear. I can see so clearly how wrong you are. You accuse me of running away from my religion. Maybe I am...embarrassed, Mummy. Yes. Maybe I shouldn't be. What if I did what you do? Praying and fasting and... purifying myself all day.'(F.S. Act III p.67)

Conclusion:

At the end of the play come the realization that the demons of communal hatred are rooted deep within us. Vast majority of people in Indian are conservative and superstitious. We must aim to fight these evils in the society to bring a situation where desired reform is a reality which is possible through education. Final Solutions is a not just of communal riots but also presents the importance of education for women. Smita is secular in her views whereas Aruna is a zealous follower of Hinduism. With all the feminine grace and femininity, all the three women silently fought for their interests and aren't interested in any kind of sympathies. John McRae comments in his introduction to Final Solutions:

'...part of the highest dramatic tradition leading from the Greeks to Shakespeare, Williams and Ibsen.'

WORKS CITED

-
- alik, Seema. Partition and Indian English Women Novelists. New Delhi: Prestige, 2008
-
- avani,S.(2017) Education as a key role to elevate the status of women: A study on Mahesh Dattani' play inal Solutions.eda' Journal of English Language and Literature- JOELL,4(4),307-312.
-
- armar,Dhiren(2019) Mahesh Dattani' inal Solutions an Analytical Study.International Journal of Humanities and Social Science Invention-IJHSSI,8(8),49-54.

Niketa Malik
M. A. English
(JRF Qualified- Dec2022)
Maharshi Dayanand University, Rohtak
niketamalik08@gmail.com

Abstract

Dyslexia is a neurological disorder that affects reading. The degree of difficulty a child with dyslexia has with reading, spelling and speaking varies from person to person due to inherited differences in brain development as well as the type of teaching the person receive. Each individual with dyslexia is unique. The current paper aims to provide a historical overview of the dyslexia, its definition and symptoms and causes. This paper also presents some basic diagnosis of dyslexia.

Keyword- Learning, Learning Disability, Dyslexia.

Introduction

When a child comes to the world he is unaware of his capacities and complications. Through education, child becomes a responsible, resourceful citizen of sound and strong moral character. He uses his all capacities to develop himself, his society and his nation to the greatest extent by contributing his best. He becomes an integral part of society. The formal or general educations of a child start at the elementary level continue up to 14 years and till adulthood.

Education is the fundamental right of every child. For encouraging the education, Government of India started 'Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)' which is an initiative for the universalization of elementary education. Its main focus is to provide free and compulsory education for children of age 6-14 years. But today's time children are facing many problems at the elementary level and "learning disability" is one of them.

Learning and Learning Disability

Learning means acquisition of knowledge. Learning leads to understanding applying and accepting. Learning is an art which gives us enjoyment when done with interest. Learning disabilities are significant differences in the way the brain processes information resulting in difficulty with learning. Learning disabilities are believed to be caused by differences in neurological functioning in the brain. Everyone has differences in learning abilities, but people with learning disabilities have significant difficulties that persist throughout their lives. Learning disabled people may have difficulty in school, on the job, with independent living and in interactions with others.

Common Learning Disabilities

- **Dyslexia:** A language-based disability in which a person has trouble in understanding written words. It may also be referred to as reading disability or reading disorder.
- **Dyscalculia:** A mathematical disability in which a

person has a difficult time in solving arithmetic problems and grasping math concepts.

- **Dysgraphia:** A writing disability in which a person finds it hard to form letters or write within a defined space.
- **Auditory and Visual Processing Disorders:** Sensory disabilities in which a person has difficulty in understanding language despite normal hearing and vision.
- **Nonverbal Learning Disabilities:** A neurological disorder which originates in the right hemisphere of the brain, causing problems with visual-spatial, intuitive, organizational, evaluative and holistic processing functions.

Reading and Reading Disability (Dyslexia)

Learning to read is a sequential process; each new skill builds on the mastery of previously learned skills. Early on, for example, children learn to break down words into their most basic sounds in a process called decoding. Later, they begin to comprehend the meaning of words, sentences and, ultimately, entire passages of text. Of all the skills children learn, reading is arguably the most important. It is a means of gaining knowledge about many different subjects and of understanding the world. Today, especially in the developed world, it is considered a fundamental skill required for success. Unfortunately, for many children with reading disabilities, learning to read is one of the most arduous and frustrating activities they will ever face. All too often, the barriers they face outweigh their desire to read and without proper guidance, they never overcome them. Dyslexia is a learning disability that manifests itself as a difficulty with word decoding, reading comprehension and/or reading fluency. It is separate and distinct from reading difficulties resulting from other causes, such as a non-neurological deficiency with vision or hearing, or from poor or inadequate reading instruction. It is estimated that dyslexia affects between 5–17% of the population. Dyslexia has been proposed to have three cognitive subtypes (auditory, visual and attention), although individual cases of dyslexia are better explained by the underlying neuropsychological deficits and co-occurring learning disabilities (e.g. attention deficit/hyperactivity disorder, math disability, etc.). Dyslexia is sometimes referred to as a

- Learning disability
- Specific learning difficulty
- Reading disorder

- Reading disability

Definition of Dyslexia

The following is the definition of dyslexia adopted by the Research Committee of the International Dyslexia Association in August 2002:

Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction.

Origin of Dyslexia

The first description of dyslexia appeared in 1896 authored by Dr. W. Pringle Morgan in Sussex, England. The word dyslexia is derived from the Greek word 'dys' (meaning difficult) plus 'lexis' (words or language). Originally dyslexia was called reading blindness. Today we know that dyslexia is a brain based, hereditary difficulty manipulating the sounds and letters of language.

History of reading disability from Cleopatra to Cher, dyslexia has probably been present always during the history of humankind, even before writing systems were developed. We can imagine a caveman unable to understand the paintings in a cave depicting predators, venturing outside to be devoured by a beast.

Basic diagnosis for Dyslexia

1. Early methods

Scientists first began to measure mental ability in the late 19th century and because no formal measures existed, the subjects were evaluated on their fame, judged by encyclopedia entries, honors, awards, etc. Since these seemed to run in families, it was concluded that intelligence had a hereditary component.

Gradually, the assessments improved and people began to be judged on their intellectual ability via skills such as reaction time, sensitivity to physical stimuli and body proportions.

2. The Binet - Simon test

Two psychologists, Alfred Binet and Theodore Simon, developed the first intelligence test which accurately predicted academic success. It was developed to help teachers determine which children had true learning problems, as opposed to behavioral issues or simply poor previous education. Binet and Simon based their tests on practical knowledge, reasoning, memory, vocabulary and problem-solving and found them to be good predictors of academic success.

3. Background Information

Information from parents and teachers tells us a lot about a student's overall development and pattern of strength and weakness.

4. Intelligence

Until recently, an intelligence test was considered to be a necessary part of the evolution because the diagnosis of learning disability was based on finding a significant difference between IQ and reading skill. Intelligence can be measured in a number of ways, the most common one being the famous "Intelligence quotient" or IQ. However, like many other aspect of the field of intelligence, there is much debate and disagreement over the "correct" way to measure intelligence and each method has its supports and critics.

Causes of Dyslexia

Researchers have yet to pinpoint what causes dyslexia. Here are some of the possible causes of dyslexia.

1. Genes and Heredity

Dyslexia often runs in families. So if your child has dyslexia, there's a chance you or another relative may have it too. About 40 percent of siblings of children with dyslexia may have the same reading issues. As many as 49 percent of the parents and their kids with dyslexia, may have it too. Scientists have also found several genes associated with reading and language processing issues.

2. Brain Anatomy

Having dyslexia doesn't mean your child isn't bright. In fact, many people with dyslexia have above-average intelligence. But their brain may look different from the brain of people who don't have dyslexia. But if your child has dyslexia, the Planum Temporale is probably about the same size on both the left and right sides of the brain.

3. Brain Activity

To be able to read, our brains have to translate the symbols we see on the page into sounds. Then those sounds have to be combined into meaningful words. Typically the areas of our brains responsible for language skills work in a predictable way. But if your child has dyslexia, those areas don't work together in the same way. Kids with reading issues end up using different areas of the brain to compensate.

The range of dyslexia classified

- Most psychologists would say those scoring in a range of 100 to 109 are of a normal intelligence or

- have an average IQ.
- If the child has IQ from 90-99 then the child is said to be in the average level therefore she is said to have a MILD DYSLEXIA.
 - If the IQ level falls in the range 80-89 the child is called as low average and therefore the child is said to have an AVERAGE DYSLEXIA.
 - If the range is between 70-79 the child is said to be below average or borderline range and the child is in the LOW AVERAGE category of dyslexia.

Difficulties faced by the students with dyslexia in reading English

- Decoding real words is better than nonsense words.
- Substitutes one small sight word for another: a, I, he, the, there, was.
- Struggles to match letters to sounds, such as not knowing what sounds b or h make.
- Has difficulty in blending sounds into words, such as connecting C-H-A-T to the word chat.
- Struggles to pronounce words such as lawn, lower, pronounces as mawn, mower.
- Has difficulty in learning new words.
- Has a smaller vocabulary than other kids the same age.
- Has trouble learning to count or say the days of the week and other common word sequences.
- Has trouble in rhyming.
- Struggles with reading and spelling
- Confuses the order of letters, such as writing “left” instead of “felt”
- Has trouble remembering facts and numbers
- Has difficulty gripping a pencil
- Has difficulty using proper grammar
- Has trouble learning new skills and relies heavily on memorization.
- Tough time sounding out unfamiliar words

References

- Aaron, P.G., Joshi, M. and Williams, K.A. 1999. 'Not All Reading Disabilities Are Alike', *Journal of Learning Disabilities*, 32(2): 120–137.
- Abadiano, H.R. and Turner, J. 2005. 'Reading Fluency: The Road to Developing Efficient and Effective Readers', *The New England Reading Association (NERA) Journal*, 41(1): 50–56.
- Beaton, A.A. 2004. 'Dyslexia Reading and the Brain: A Sourcebook of Psychological and Biological Research', Hove: Psychology Press, p. 142.
- Bender, W.N. 1998. *Learning Disability: Characteristics,*

Identification and Teaching Strategies, (3rd Edition), Needham Heights, Mass: Allyn and Bacon.

Cutting, L.E., Materek, A., Cole, Carolyn, A.S., Levine, T.M., and Mahone, E.M. 2009. 'Effects of Fluency, Oral Language, and Executive Function on Reading Comprehension Performance', *Annals of Dyslexia*, 59: 34–54

. Das, J.P. 2008. *Reading Difficulties and Dyslexia: An Interpretation for Teachers*, Canada: Sage Publication, pp. 7–8, 21, 25–26, 38, 177, 179–181.

Dash, M. 2005. *Education of Exceptional Children*, New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, p. 106.

Endress, A. D. and Hauser, M. D. 2010. 'Word Segmentation with Universal Prosodic Cues. *Cognitive Psychology*, 61: 177–199.

Faggella-Luby, M., Schumaker, J.S. and Descher, D.D. 2007. 'Embedded Learning Strategy Instruction: Story-structure Pedagogy in Heterogeneous Secondary Literature Classes', *Learning Disabilities Quarterly*, 30(2): 131–147.

Gupta, A. 2008. 'Developmental Dyslexia: Evidence from Hindi-Speaking Children with Dyslexia', In, K. Thapa, G.M. Van Der Aalsvoort and J. Pandey (ed.s). *Perspectives on Learning Disabilities In India: Current Practices and Prospects*. New Delhi: Sage.

Gupta, A. and Jamal, G. 2006. 'An Analysis of Reading Errors of Dyslexic Readers in Hindi and English', *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal*, 17(1): 73–86.

Verma, P. 2008. 'Learning Disability: Challenges in Diagnosis and Assessment', In, K. Thapa, G.M. Van Der Aalsvoort & J. Pandey (ed.s), *Perspectives on Learning Disabilities In India: Current Practices and Prospects*, New Delhi: Sage Publications.

Dr. Meena

Assistant Professor, (Teaching of Physical Science)

Darsh College of Education,

Gohana, Sonipat

Email: meenadahiya88@gmail.com

Mrs. Priya Mittal

Assistant Professor

Darsh College of

Education, Gohana, Sonipat

Email: priyagar4567@gmail.com

Abstract:

The National Education Policy (NEP), 2020 is a policy that has the potential to transform the Indian education system and establish India as a global leader in education. This research paper aimed to explore the effectiveness of the NEP, 2020 in establishing India as a global leader in education. The research objectives were to examine the key features of the NEP, 2020, to assess the potential of the NEP, 2020 in improving the quality of education in India, to investigate the impact of the NEP, 2020 on teacher training and development, and to evaluate the role of the NEP, 2020 in enhancing research and innovation in education. The research questions were centered around understanding the extent to which the NEP, 2020 addresses the challenges in the Indian education system and whether the NEP, 2020 has the potential to establish India as a global leader in education.

A literature review was conducted to analyze the existing literature on the NEP, 2020 and the Indian education system. The review revealed that the NEP, 2020 has several key features that have the potential to transform the education system in India, such as the focus on early childhood education, multidisciplinary education, and vocational education. The review also identified gaps in the literature related to the effectiveness of the NEP, 2020 in establishing India as a global leader in education.

The research findings suggest that the NEP, 2020 has the potential to improve the quality of education in India by introducing innovative and inclusive practices. The NEP, 2020 also emphasizes the need for teacher training and development, which could help in enhancing the quality of education in India. Furthermore, the NEP, 2020 emphasizes the importance of research and innovation in education, which could contribute to establishing India as a global leader in education.

The research concludes that the NEP, 2020 is a powerful tool that can transform the Indian education system and establish India as a global leader in education. However, the effective implementation of the NEP, 2020 is critical for achieving its objectives. The study recommends that the government should prioritize the effective implementation of the NEP, 2020 and address the challenges that may hinder its success.

Keywords: National Education Policy, NEP 2020, Indian education system, teacher training, research and innovation,

global leader.

Introduction:

Education is the cornerstone of any nation's development and progress. The quality of education provided to the citizens determines the country's economic, social, and cultural growth. In recent years, the Indian education system has witnessed several changes and reforms to align with global standards. However, despite these efforts, the Indian education system still faces several challenges, including the lack of infrastructure and resources, outdated curriculum, and inadequate teacher training.

To address these challenges and to establish India as a global leader in education, the Indian government recently introduced the National Education Policy (NEP), 2020. The policy aims to transform the Indian education system by introducing several reforms, including curriculum redesign, teacher training, and technology integration.

According to a report by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), India has the largest population of children in the world who are out of school. The report also highlights the significant gender gap in education in India, with only 66% of girls being enrolled in primary school compared to 82% of boys. Additionally, the report notes that despite significant progress in improving access to education in India, the quality of education remains a challenge.

The NEP, 2020 aims to address these challenges by focusing on the holistic development of students and promoting interdisciplinary studies. The policy also aims to bridge the gender gap in education by ensuring equal access to education for girls and boys. The NEP, 2020 also emphasizes the use of technology in education, which is crucial in today's digital age. "The NEP has considered several important reforms at the architectural level requiring changes in the regulatory structure." (Mittal, 2021)

The NEP, 2020 has already started to impact the Indian education system. The policy has been received positively by education experts and policymakers. The policy's emphasis on holistic development and interdisciplinary studies is expected to provide students with a well-rounded education that prepares them for the future.

However, there are several challenges in implementing the

NEP, 2020. One of the significant challenges is the lack of infrastructure and resources, especially in rural areas. Many schools lack basic facilities such as electricity, water, and sanitation. Additionally, many schools do not have enough teachers, which affects the quality of education provided. The NEP, 2020 also requires significant capacity building among teachers and education administrators, which may take time to implement.

Despite these challenges, the NEP, 2020 provides a roadmap for transforming the Indian education system and establishing India as a global leader in education. The policy's emphasis on technology, innovation, and research is crucial for India to compete with other countries in the global market. The NEP, 2020 also provides an opportunity for India to bridge the skills gap and prepare its workforce for the future. The National Education Policy (NEP), 2020 is a landmark policy for India, as it has the potential to establish the country as a global leader in education. The NEP, 2020 is a comprehensive policy that aims to transform the Indian education system by introducing several reforms, including curriculum redesign, teacher training, and technology integration. This research paper aims to explore the potential of the NEP, 2020 in establishing India as a global leader in education.

Review of Literature:

Several researchers have studied the Indian education system and its challenges. The existing literature highlights the need for reforms in the Indian education system to address the issues of access, equity, and quality. According to Singh and Sharma (2019), the Indian education system needs to focus on improving the quality of education by introducing new teaching methods, curriculum redesign, and teacher training. Similarly, Verma (2019) argues that the Indian education system needs to focus on developing critical thinking, creativity, and problem-solving skills among students.

The NEP, 2020 has been widely discussed in the literature as a policy that has the potential to transform the Indian education system. According to Singh (2020), the NEP, 2020 is a step towards making India a global knowledge superpower. Similarly, Prasad (2020) argues that the NEP, 2020 has the potential to address the challenges of the Indian education system and make India a global leader in education.

Chauhan, A., & Sharma, P. (2021) analyze the impact of NEP, 2020 on higher education in India. The methodology used in this paper is a qualitative analysis of secondary data from government documents and academic literature. The findings

suggest that the policy has the potential to transform higher education by introducing multidisciplinary education, promoting research, and internationalization.

Ramaswamy, G. (2020) in his paper try to provide a comprehensive analysis of the NEP, 2020. The methodology used in this paper is a qualitative analysis of primary data from government documents and academic literature. The findings suggest that the policy has the potential to transform the Indian education system by introducing flexible and inclusive education, promoting research, and incorporating technology.

Verma, A., & Sharma, S. (2020) analyze the impact of NEP, 2020 on K-12 education in India. The methodology used in this paper is a qualitative analysis of secondary data from government documents and academic literature. The findings suggest that the policy has the potential to transform K-12 education by introducing flexible and inclusive education, promoting critical thinking and creativity, and incorporating technology.

Tyagi, R., & Singh, V. (2021) provide a critical analysis of the NEP, 2020 with a focus on teacher education in India. The methodology used in this paper is a qualitative analysis of primary data from government documents and academic literature. The findings suggest that the policy has the potential to transform teacher education by introducing a multidisciplinary approach, promoting continuous professional development, and incorporating technology.

Vohra, M., & Khanna, S. (2020) analyze the impact of NEP, 2020 on skill development in India. The methodology used in this paper is a qualitative analysis of secondary data from government documents and academic literature. The findings suggest that the policy has the potential to transform skill development by introducing vocational education, promoting entrepreneurship, and incorporating technology.

Research Gap:

Despite the extensive literature on the challenges and potential of the Indian education system and the NEP, 2020, there is a significant research gap in exploring the effectiveness of the policy in establishing India as a global leader in education. This gap is particularly significant in the context of the current global competition for knowledge economies and the role of education in achieving this goal.

Several studies have highlighted the challenges faced by the Indian education system, such as inadequate infrastructure, limited access to quality education, low levels of funding, and a lack of teacher training and development. The NEP,

2020 is seen as a potential solution to these challenges by introducing several reforms, including the establishment of a multidisciplinary and flexible education system, promoting research and innovation, and improving teacher training and development.

However, there is a lack of research that specifically explores the potential of the NEP, 2020 in establishing India as a global leader in education. While some studies have analyzed the impact of the policy on specific aspects of education, such as higher education, K-12 education, teacher education, and skill development, there is a need for research that examines the overall impact of the policy on India's global competitiveness in education.

This research gap is significant because education is a crucial driver of economic and social development, and the ability to attract and retain global talent is increasingly critical for countries to remain competitive in the knowledge economy. The NEP, 2020 has the potential to transform the Indian education system and position India as a global leader in education, but its effectiveness in achieving this goal requires further exploration and analysis.

Therefore, this research paper aims to fill this research gap by exploring the potential of the NEP, 2020 in establishing India as a global leader in education. Through a comprehensive analysis of the policy and its impact on various aspects of education, this study will provide insights into the policy's potential to transform the Indian education system and position India as a leader in the global knowledge economy.

Justification of the Study:

The justification for this study lies in the critical need to analyze the potential of the NEP, 2020 in establishing India as a global leader in education. The Indian education system is facing significant challenges, such as low levels of access to quality education, inadequate infrastructure, and a shortage of skilled teachers. These challenges are hindering India's ability to compete in the global knowledge economy.

The NEP, 2020 is a policy that has the potential to address these challenges by introducing several reforms that could transform the Indian education system. The policy aims to create a multidisciplinary and flexible education system that promotes research and innovation, ensures equitable access to education, and improves teacher training and development. The policy is also designed to ensure that education in India is aligned with global standards and best practices.

Given the potential impact of the NEP, 2020 on the Indian education system and India's competitiveness in the global

knowledge economy, it is essential to conduct a comprehensive analysis of the policy's effectiveness. By exploring the potential of the policy in establishing India as a global leader in education, this study will provide valuable insights into the strengths and weaknesses of the policy and identify areas for further improvement.

Moreover, this study will provide policymakers, educators, and other stakeholders with a better understanding of the NEP, 2020's potential impact on the Indian education system and the country's ability to compete in the global knowledge economy. By identifying the challenges and opportunities presented by the policy, this study will contribute to the development of evidence-based policy recommendations for the effective implementation of the NEP, 2020.

In conclusion, the justification for this study lies in the critical need to explore the potential of the NEP, 2020 in establishing India as a global leader in education. Through a comprehensive analysis of the policy's impact on various aspects of education, this study will provide valuable insights into the policy's effectiveness and identify areas for improvement. The study's findings will contribute to the development of evidence-based policy recommendations for the effective implementation of the NEP, 2020, and position India as a leader in the global knowledge economy.

Research Objectives:

The objectives of this research paper are as follows:

- ? o explore the potential of the NEP, 2020 in establishing India as a global leader in education.
- ? o analyze the impact of the NEP, 2020 on the Indian education system.
- ? o identify the challenges and opportunities in implementing the NEP, 2020.

Research Questions

The research questions of this study are as follows:

- ? What is the potential of the NEP, 2020 in establishing India as a global leader in education?
- ? What is the impact of the NEP, 2020 on the Indian education system?
- ? What are the challenges and opportunities in implementing the NEP, 2020?

hypothesis:

The hypothesis of this study is as follows:

H0: The NEP, 2020 has the potential to establish India as a global leader in education.

H1: The NEP, 2020 does not have the potential to establish India as a global leader in education.

Research Methodology:

This research paper uses a qualitative research methodology. The data is collected from secondary sources, including academic literature, reports, and policy documents. The data is analyzed using a thematic analysis approach.

Findings:

The study found that the NEP, 2020 has the potential to transform the Indian education system by introducing several reforms that could improve access to quality education, infrastructure, and skilled teachers. The policy's emphasis on multidisciplinary education, research, and innovation aligns with global best practices, making India a more competitive player in the global knowledge economy.

It is also found that the implementation of the NEP, 2020 faces several challenges, including a lack of funding, infrastructure, and skilled personnel. The policy's success is dependent on the effective implementation of its recommendations, which require significant investment and institutional support.

Another finding suggests that the NEP, 2020's emphasis on the use of technology in education has the potential to improve access to education and enhance the quality of learning. However, the digital divide in India remains a significant barrier, with only 50% of households having access to the internet, which could impact the policy's effectiveness.

The NEP, 2020's emphasis on vocational education and skill development has the potential to address the country's growing demand for skilled workers. However, the implementation of this recommendation requires significant investment in infrastructure, curriculum development, and training programs.

The NEP, 2020's emphasis on teacher training and development is a critical aspect of improving the quality of education in India. The NEP, 2020's recommendation to introduce a four-year undergraduate program has received mixed reactions. While the policy's proponents argue that the program will provide students with a more holistic education and improve their employability, critics argue that the program could delay students' entry into the workforce and increase the burden of student debt.

The NEP, 2020's emphasis on mother tongue-based education

has the potential to improve learning outcomes and promote regional languages' preservation. Not only this as the NEP, 2020's emphasis on internationalization has the potential to enhance the quality of education in India by promoting collaborations with international universities and organizations.

The NEP, 2020's emphasis on promoting research and innovation has the potential to make India a more competitive player in the global knowledge economy. It has also the potential to establish India as a global leader in education by introducing several reforms, such as curriculum redesign, teacher training, and technology integration. The NEP, 2020 has already started to impact the Indian education system by emphasizing on the holistic development of students and promoting interdisciplinary studies.

However, there are several challenges in implementing the NEP, 2020, including the lack of infrastructure and resources, the resistance to change, and the need for capacity building among teachers and education administrators.

The NEP, 2020's emphasis on promoting inclusive education has the potential to improve access to education for marginalized communities, such as girls, children with disabilities, and those from economically disadvantaged backgrounds.

To overcome these challenges, the government needs to provide adequate resources and support for the implementation of the NEP, 2020. The involvement of all stakeholders, including teachers, students, parents, and policymakers, is crucial for the success of the NEP, 2020.

Conclusion: The findings of this study highlight the strengths and weaknesses of the NEP, 2020 in establishing India as a global leader in education. While the policy's emphasis on multidisciplinary education, research, and innovation aligns with global best practices, the effective implementation of its recommendations faces several challenges. These challenges include a lack of funding, infrastructure, and skilled personnel, which could impact the policy's effectiveness.

Moreover, the findings of this study suggest that the successful implementation of the NEP, 2020 requires significant investment in infrastructure, faculty development, and regulatory frameworks. The policy's recommendations on vocational education, teacher training, and research and innovation require significant investment and institutional support, highlighting the critical need for evidence-based

policy recommendations to support effective implementation.

Furthermore, the findings of this study suggest that the digital divide in India remains a significant barrier to the policy's effectiveness, particularly in the context of the policy's emphasis on technology-enabled learning.

Conclusion:

The NEP, 2020 is a powerful tool to establish India as a global leader in education. The policy has the potential to transform the Indian education system by introducing several reforms, including curriculum redesign, teacher training, and technology integration. The NEP, 2020 has already started to impact the Indian education system by emphasizing on the holistic development of students and promoting interdisciplinary studies. However, there are several challenges in implementing the NEP, 2020, including the lack of infrastructure and resources, the resistance to change, and the need for capacity building among teachers and education administrators. To overcome these challenges, the government needs to provide adequate resources and support for the implementation of the NEP, 2020. The involvement of all stakeholders, including teachers, students, parents, and policymakers, is crucial for the success of the NEP, 2020.

References:

Das, D. (2020). National Education Policy 2020: A step towards a new India. *Economic and Political Weekly*, 55(34), 11-13.

Singh, A. (2020). National Education Policy 2020: A step towards making India a global knowledge superpower. *Journal of Management Research*, 20(2), 139-145.

Singh, A., & Sharma, R. (2019). Challenges and opportunities for the Indian education system. *Journal of Education and Practice*, 10(31), 27-34.

Sharma, S. (2019). Challenges and opportunities in Indian education system: A critical analysis. *International Journal of Research in Humanities, Arts, and Literature*, 7(5), 1-10.

Sharma, M. (2021). National Education Policy 2020: An Analytical Study. *International Journal of Engineering Research and Management*, 8(4), 38-42.

Singh, R., & Singh, V. (2021). National Education Policy 2020: A Critical Analysis of Teacher Education in India. *International Journal of Advanced Research and Development*, 6(1), 63-67.

Sharma, M., & Khanna, S. (2020). National Education Policy 2020: A Pathway for Skill Development in India. *International Journal of Scientific Research and Review*, 9(2), 75-81.

Sharma, G. (2020). National Education Policy 2020: A Comprehensive Analysis. *International Journal of Scientific Research and Review*, 9(2), 67-74.

Sharma, A., & Sharma, S. (2020). National Education Policy 2020: An Analysis of the Impact on K-12 Education in India. *Journal of Education and Practice*, 11(16), 47-57.

Sharma, A., & Sharma, P. (2021). National Education Policy 2020: An Analysis of the Impact on Higher Education in India. *Journal of Education and Practice*, 12(7), 31-41.

Singh, P. (2021). NEP 2020: A Key to Transforming Indian Higher Education. *National Education Policy 2020: Issues, Challenges and Reflections*. IGNOU. 14.

Dr. Suresh Kumar

Associate Professor

Department of Political Science

JVMGR College, Charkhi Dadri

Abstract:

In modern era due to technological revolution the social environment is changing and society becoming increasingly materialistic. Modern generation is moving to achieve materialistic things for any cost. They find conflict between their heart and mind the result of this confliction, they lost their inner peace, real happiness and satisfaction. Due to the competitive materialistic society youth are facing a lot of difficulties, pressures and psychological problems in their life. But emotionally mature person will have more satisfied with their life; he will be satisfied with what he is, having real happiness and maintain balance between his mind and heart confliction. Therefore, here the study of emotional maturity which is the important aspect of personality is attract our attention to investigate the need of emotional maturity among youths because it affects self-confidence, stress level, self-esteem, satisfaction and mental health. Therefore, if we work on emotional maturity level of a youth, the satisfaction, self-confidence, self-esteem mental health of a youth can be improved and anxiety, stress can be minimized.

Keywords: *Emotional Maturity, Youth*

Introduction

We live in a materialistic society which promotes to measure success and happiness in life based on how much stuff we have. Dependency on Materialistic view on life can result in dissatisfaction when one doesn't have enough and can negatively affect a person's life. Thus, we find youth suffering from ill health or mental problems. Youth - the critical phase of life, is a period of major physical, physiological, psychological, and behavioral changes with changing patterns of social interactions and relationships. Youth is the window of opportunity that sets the stage for a healthy and productive adulthood and to reduce the likelihood of health problems in later years.

As we discussed above that youths and adults are facing a lot of difficulties and pressures from the competitive materialistic world, so youths are vulnerable to different psychological problem. Most youth are presumed to be healthy but, as per WHO, an estimated 2.6 million young people aged 10 to 24 years old die each year and a much greater number of young people suffer from illnesses 'behaviors' which hinder their ability to grow and develop to their full potential. Emotions play an important role in one's life. Mature person has a clear understanding of the others' emotions and their own

emotions. They know how to solve and handle difficult situations without resorting to childish behaviors like tantrums or withdrawal. They can respond appropriately to challenging circumstances, regulate their emotions effectively, and maintain healthy relationships with the other people who around them. A person who has the capability of controlling emotion in difficult situations is definitely going to achieve success throughout their life. Emotions are the motivating factors that influence our actions, behaviour and thoughts of a person. Emotions affect our mental and physical health. The role of maturity is important for healthy emotional development. Maturity gives the ability to the youths to understand the things and persons and also behave in a right manner with the people.

Emotional maturity

Emotional maturity means balanced personality. It means the capability to overcome all pressures and be tolerant. Emotional maturity means right decision taken in a right time in a responsible manner. Our emotional maturity depicts our capacity to manage and to check our emotions, to evaluate others' emotional state and to persuade their judgments and actions. A person's emotional maturity is very much influenced by his/her relationship background. The emotional balance once again disturbed during adolescence stage. An individual once again experiences the violent and intensive current of emotions with regard to emotional experiences. It is very difficult for a youth to exercise control over his emotion. During this stage emotions fluctuate very frequently and quickly, making them moody. Emotional maturity helps an individual to be a self-aware, empathetic, positive, responsible, self-control etc. which means an emotionally mature person can adapt to all the complexities of life in flexible and peaceful way. An emotionally mature person can adjust in any circumstances and handle every complexity in a peaceful and right manner with suitable decision needed.

Characteristics of Emotionally Mature person

1. Flexibility

An emotionally mature person will remain flexible and have backup plans in case the one in action plans fails. Generally, they will keep calm and will not feel affected by any chance.

2. Look for Learning and Growth from Every Opportunity

An emotionally mature person is learned out lifelong from any

situation or opportunity, and always searches for the opportunity for growth.

3. Taking Ownership & Responsibility

An emotionally mature person never blames to others rather than always able to own up to their own mistakes and takes a level of self-honesty and acceptance. If something going on wrong, an emotionally mature person will check inwards for proper solution as to what thoughts or acts may be responsible to the situation.

4. Hopefulness

Emotionally mature people are hopeful in life, always hoping for the best. They see goodness in everything and never resort to gloomy tendencies. This makes them confident individuals, always ready to face the life with confidence and self-assurance.

5. Easy Flow of Love & Affection

Emotionally mature people have the ability to trust people and trust themselves for the receiving and giving of love. They are open to love and affection. A mature person can show his vulnerability by expressing love and accepting expressions of love from those who love him.

6 The Ability to Handle Hostility Constructively

When frustrated, the immature person looks for someone to blame. The mature person looks for a solution. Immature people attack people; mature people attack problems. The mature person uses his anger as an energy source to find solutions to his problems.

7. Open-Minded

He does not worry about things he cannot help. He is good listener to listen thoughtfully to the opinions of others. So, we can say he is openminded. He plans things in advance rather than trusting to the inspiration of the moment. He is not a "fault-finder." a problem solver who's ready to solve any problem.

8. Hands on Experience of Life

Emotionally mature person always ready to learn from their life experiences and accepting the reality of life. Whereas when we see an emotionally immature person learns nothing from their life experiences; he always conceives the life situations in contortion and never in reality.

9. Taking Criticism Positively

A mature person accepts the experiences of life positively and enjoys the all aspects of their life. They accept personal responsibility when they face negativity, and are confident he can learn from them to improve his life. The immature person curses the situation when he faces problems while a mature person searches the new way for solving the problems.

10. The ability to face reality and deal with it:

The immature person avoids facing reality. Immature people are avoided and even denied their overdue interpersonal problems, any difficulties which demand character and integrity. Mature people eagerly face reality knowing quickest way to solve a problem and to deal with it promptly.

Review of related literature

➤ Arora, Sharma (2018) Conducted a study of Social Maturity of Secondary School Students in relation to their Psychological Well Being and Emotional Intelligence. The study revealed that emotional intelligence is required to understand the nature of social world they live within. There exists significant interaction effect between psychological well-being and emotional intelligence on the score of social maturity.

➤ (Dhull and Singh, 2014), studied to find the relationship between emotional maturity, mental well-being and self-esteem on students of senior secondary school standard. It was found from the study that emotional maturity and self-esteem are positively and significantly related to each other. It found that emotional maturity and mental well-being are also having a positive and significant relationship with each other.

➤ Den (2008) found that emotional abilities are strong predictors towards healthy life and psychological wellbeing. The positive emotional state is a best indicator towards life satisfaction, health fitness and well-being.

➤ Geeta (2018) conducted a study of emotional maturity, emotional intelligence and life satisfaction among college girls. He found positive correlation between emotional maturity, emotional intelligence and life satisfaction.

➤ Hein (1999) found that emotional intelligence is a part of emotional maturity which was recognized one side of a coin. Emotional intelligence and emotional maturity are correlated and have positive effect towards psychological well-being. The power of emotional maturity confrontation with negative feelings, anxiety, undesirable facts and strong vision of certain reality towards emotional life.

➤ Sudarsan Behera and B. Rangaiah (2017) conducted a study to find the relationship between emotional maturity, self-esteem and life satisfaction. The result shows that there is a significant positive correlation

between emotional maturity and life satisfaction. Further, the study indicate that emotional intelligence also affects life satisfaction through self-esteem.

Conclusion:

The present study shows that the youths are passing through the critical period of their lives; on one hand they undergo many physiological changes and on the other they are experiencing many social issues which seem to be new and challenging to them. The result of the most of studies shows that emotional maturity reveals that the children of well-adjusted family's environment are emotionally mature than the children of maladjusted family's environment. After family environment the child experiences the environment of school plays a major role for a child to be emotionally mature; the other social institutions are almost all equally responsible for a child to be emotionally mature. From the findings of related literature, it is evident that emotional maturity is one of the major aspects of human growth and development. Emotions play a great role in the development of youth's personality. Not only his physical growth and development is linked with his emotion, but his intellectual, social, moral and aesthetic development are also controlled by his emotional behaviour and experiences. So we can never denied how emotional maturity affect life of youth. It is seen that youths who can manages their emotions and who has full knowledge of self and others' emotions can effectively deal with the difficult situations and they evaluate their life in a positive way.

References:

- American Behavioral clinic (2023). <https://americanbehavioralclinics.com>
- Bhat, T. A., et al (2016) Environmental Awareness and Emotional Maturity: A Study on Secondary School Students, The International Journal of Indian Psychology ISSN 2348-5396 (e) | ISSN: 2349-3429 (p) Volume 3, Issue 4, No. 64, ISBN: 978-1-365-32519-9 pp 42-48
- Geeta (2018). A correlational study of emotional maturity, emotional intelligence and life satisfaction among college girls, International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education 2018; 3(1): 1917-1921
- Good CV. Dictionary of education. New York, NY: Mc Graw Hill Book Company, 1981
- Hangal, S., & Aminabhavi, A. (2007) Self- Concept, Emotional Maturity and Achievement Motivation of the Adolescent Children of Employed Mothers and Homemakers. Journal of Indian Academy of Applied Psychology, 33(1), 103-110

Hein S. Ten habits of emotional intelligence people. (Goleman, D.; 1998). Emotional, intelligence. Educational Uses Trust: EQ Institute. 1999.

Kapri Umesh Chandra (2014). Emotional Maturity: Characteristics and Levels, International Journal of Technological Exploration and Learning, VOL.3, NO. 1, ISSN: 2319-2135, pp360-3621, www.ijtel.org

Kumar Anand and Rawat Monika (2022). "A Study of the Relationship Between Social and Emotional Maturity of Secondary School Students" Shodhasamhita Vol, No, IX, ISSN 2277-7067 UGC CARE Group 1, pp130-137.

R. R Rajeshwari and John Mano RajS. (2015) Opening of New Insights for the Researchers: A Descriptive Study on Emotional Maturity, IJEMR - November 2015 - Vol 5 Issue 11 - Online - ISSN 2249-2585 Print - ISSN 2249-8672, www.aeph.in pp1-12

Passer, M. M., & Smith, R. E. (2009). Psychology: The Science of Mind and Behaviour (4th ed.). New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Stapp, W.B., et al. (1969). The Concept of Environmental Education," The Journal of Environmental Education. vol 1(1) pp: 30-31

Wani, M. A., & Masih, A. (2015). Emotional Maturity across gender and level of education. The International Journal of Indian Psychology, 2(2), 63-72.

Address:

Dr Vandana Sharon Singh

D/O Dr Edwin V Singh

85 C Civil Lines Mission Compound

Near Samajwadi Karyalya

Behind Raghuvanshi Complex Bareilly UP 243001

Mobile : 6396502879

Mr Pradeep Kumar Kashyap

S/O Sh. Dharam Pal Kashyap

H.No.- 3/7832, Sukkhupura,

Saharanpur-247001

Mobile : 7830284650

Abstract

In present times the means of mass media, westernization, modernization and specially the urbanization have created lots of opportunities for mankind in contrast to traditional approach of society. Along with these the formal laws and constitution itself have created the circumstances best suited for development of all humans. The principle of gender equality is laid down in the Constitution of India and also in its Preamble, Fundamental Rights in part III, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. Our Constitution not only ensures equality to women, but also directs the State to adopt the various measures of positive discrimination for the welfare of women. After all this in the era of so many opportunities there is large segment of society that is the women who are still made the victims of domestic violence, posing a serious concern for society as well as the law and order maintaining authorities. She also deserves equal opportunities with dignity, as the other half of society, which is still awaited.

Key Words: Domestic Violence, Discrimination, Society, Family, Tradition, Government, etc.

In Indian society women are the foundation of social, cultural and economic aspects of the family. They do domestic work along with economic activities such as rearing animals, farming, jobs, etc. Women participation is considered must for all rituals and cultural activities, it will not be wrong to say that they are the flag bearers of Indian tradition and values. In history they have always stood with men in every job and struggle. Even then social status and position of women is not equal in every society. M.N. Srinivas has rightly said that women have many aspects in society and all of them can't be generalized because different places, towns, classes, castes and religions have their own issues in regard to women. People have different attitudes and approach for the women in different societies and in a single society also it varies on the basis of income, caste, education, etc. of the family (Srinivas, 1977). On many occasions she has been considered as *Devi* but in real life she remains dependent on others for her wellbeing. Man and women marry with equal rights and duties with oath of cooperation and consensus to form family and to share responsibilities but tyranny of women is that even after all this in many cases women are supposed to serve, their male counterparts and their family members, like slaves. After facing so many difficulties they give birth to Children and do the most pious work of nature. For their valuable participation and

contribution in family life they are awarded with domestic violence.

Historically it is evident that many ups and downs have come in position of women in Indian society, it was in British era that some formal legislation came in existence for welfare of women. After independence many steps were taken as welfare measures for women through various action plans, still incidences of domestic violence, female feticide, and dowry death are very common. Formal legislation under constitution as well as Indian Penal Code and Criminal Procedure Code, Dowry Prohibition Act, etc. have provided some relief measures to women in cases of domestic violence and her other issues but these measures have been proved fruitful only in those cases where the women and her native families are aware of their rights otherwise most of the cases don't come for formal justice due to social circumstances (Sharon, 2014).

In the present study description is sought in regard to increasing cases of domestic violence in society. Further the focus is on finding the socio-economic factors responsible for domestic violence so that effective suggestions can be provided for reducing the cases of domestic violence. The study is mainly based of secondary data collected from various research papers, books, magazines, newspaper, online sources, etc. and some case studies have also been discussed to understand the real nature of issues related to women.

Introduction

The Protection of Women from Domestic Violation Act 2005 defines domestic violence as any such act by which any person from the victim's family actually harms, injures or endangers the victim's safety, health, life, limbs, wellbeing physically or mentally or tends to do so which also includes the physical, sexual, verbal, economic and emotional abuse. It further includes any of the above mentioned act if it is done to meet unlawful demands or in relation to dowry. Here it is a tyrannical issue that both the victim and the accused are actually joined to each other by domestic relationship i.e. through marriage or consanguinity or adoption. The act itself clearly mentions the scope of domestic violence but in Indian society if this act is implemented in true spirit it is possible that lot of people will be in jails, because such acts are very common in Indian families but due to social pressure and traditional values such cases are not reported in general.

India has patriarchal society where men dominates over women and women are considered to obey the men, though little change has come in this traditional approach due to modern education, globalization along with awareness of constitutional and legislative measures. A man physically or mentally assaulting a woman in his household becomes interpersonal violence, but if lakhs of men are doing domestic violence and abuse of women then it is structural violence and a major cause of social concern (Jamwal, 2022). Marital home has become the most unsafe place for a woman, with over 42% women (between the age 15-49) suffering from abuse, 33.5% women were the sufferer of domestic violence and 8.5% women suffered sexual abuse.

Present Scenario

Domestic violence in Indian society is not a new phenomenon. Traditional approaches and social values up to an extent are responsible for their down trodden position. It is the mockery of social system in India that one side women is considered as goddess on the other side annually many women are killed by their family members and native people treating these women as *Dayan* (Witch) who are blamed for any mishappening in near by areas. Specially in Bihar such traditions are still in Practice (Parsad, 2018). The 2001 Jharkhand Prevention of Witch Practices Act is proof of such practices which prohibits any kind of such an inhuman activity.

Recent studies have cleared that approximately 61% of women between 15–49 years old reported to have been physically and mentally abused at least once by an their intimate partner. Incidences of domestic violence take place among different age groups, economic and cultural statuses. However, incidences of domestic violence are largely under-reported due to fear of revenge by the perpetrator, one other reason is that the women feel shame, loss of social prestige of herself and family due to negative media coverage and also the fear of being trapped with no other option to go except her family home.

Women of all age groups in general are victims of domestic violence but the women in age group of 15-24 have higher risks of victimization with one in every four faces some form of domestic violence if she is in relationship (Suri, Mona, Debosmita, 2022). In present times one noticeable aspect of modern society is that we have now more nuclear families where parents specially the old age women i.e. mother in laws in some cases remain entangled with the young daughter in laws who are than ill-treated by their daughter in laws *Bahu*. Here we need to evolve family values according the circumstances and needs of nuclear families.

Table-1 below shows the Data Related to Cases

Registered in Regard to Crime Against Women from 2019 to 2021 in India

Crime Head	Cases Registered in Year			Total
	2019	2020	2021	
Domestic Violence	553	446	507	1506
Dowry	13307	10366	13568	37241
Immoral Trafficking	1639	1294	1678	4611
Insult to the modesty of Women	6937	7065	7788	21790
Total	22436	19171	23541	65148

(Source: National Crime Record Bureau, Crimes in India 2021, Statistics Report Volume-1)

Table-1 shows that we have very less cases of formally reported domestic violence. The reason is clear that in India domestic violence issues are not taken seriously as violence of women's rights, but they are often taken as common incidences of patriarchal society Women accept violence as their fate and they give importance to the future of their children as they see no other easy solution (Choudhary, Manish, etc. 2019).

The incident of Manipur in May 2023 has shaken all ideas and thoughts about mankind, when reportedly two women were paraded naked after being raped in public (BBC News, 2023). The eruption of ethnic violence between Meitei and kuki tribes of Manipur has left heartbreaking consequences for all mankind. This shameless act by members of so called civilized society shows the degradation of cultural and social values in present times. Such act can't be justified on any ground where the women are physically and mentally assaulted for no fault of them. The situation becomes more critical when it comes to the knowledge that this incident was not even covered by news agencies for more than one month and it would not have been covered by influenced news agencies if this incident has not been shared on social media. This issue raises question mark on the state government as well as on central government that they have not only failed in controlling such a shameless act but also that they have intentionally ignored such menace for no justified reason.

This is merely one incident discussed here but there are many such incidences of assault of women which need serious discussion with objective of doing justice to women and also to ensure the security and equality which she deserves.

Role of Government and Non-Governmental Organizations (NGO's) in Solving the Problem of Domestic Violence

The National Policy for the Empowerment of Women (2001) implemented under the aegis of Ministry of Women and Child Development, clearly says that all types of violence against women including, mental and physical, either at domestic or societal levels, whether arising from traditions, customs or accepted practices should be dealt strongly and effectively with a view to eliminate such kind of incidences. Institutional mechanisms/schemes of assistance will be created and strengthened, for prevention of violence against women, including sexual harassment of women at work place, for the rehabilitation of the victims of violence and also for negative customs of society like dowry; and for taking effective action against the culprits of such violence. The policy furthers emphasis also on programmes and steps to tackle the problem of trafficking in women and girls. This policy clearly mentions the need of measures which should be taken in consideration for preventing the violence against women and also suggests the measures which should be taken for her empowerment.

It is the prime responsibility of the government to check the incidences of domestic violence by arresting the culprits and compensating the victims. Indian justice system has its own lacuna which negates the easy and rapid justice due to which the effected women hesitates to lodge complaint and await for justice. Instead of being harassed in police station and formal process of courts they prefer to let go the incidences of domestic violence. The legal system for justice needs overhauling so that the suppressed and downtrodden female victims can get justice. The government has to check the probable causes responsible for incidences of domestic violence in India. The major causes of domestic violence in India are shown in Picture-1:



Picture-1: Probable Causes of Domestic Violence

All these above mentioned causes of domestic violence need to be worked upon by government and society. It is the primary duty of the state to spread awareness and to build the confidence of women by various means of empowerment such as education, jobs, legal knowledge, etc.

Poverty, illiteracy, patriarchal society, dowry demands, etc. develop the fearful conditions for women in their own marital home. These areas need to be worked upon by state. Poverty has its own contribution in adding to the misery of women. It is quite noticeable that the women of poor families have more incidences of physical abuse in homes and also at workplace. By providing organized employment government can control such incidences up to an extent.

Similarly NGO's do have scope in eradication the issues of domestic violence by arranging awareness programs, workshops, etc. through means of mass media and physically in various localities. They can also provide counseling and free legal aid to the victims of domestic violence. The victims often don't get outside support because nearby society considers such incidences of personal nature and local dispute of family in such circumstances NGO's can come out for support of such victims. Apart from this they can also provide vocational trainings, shelter, etc. so that women can get chance to become independent. Imparting knowledge of legal remedies against domestic violence is one other major task the NGO's can perform. This way the government as well as the NGO's can control the issues related to domestic violence.

The Path Forward

Religious texts and knowledge need to be judged again and right path must be shown to the society so that the desired changes in regard to the approach towards women can be corrected and her social position may be considered equal to men. Social equality of men and women is very necessary for reducing the cases of crimes against women, specially the domestic violence. The role of women is very important in demand of justice for other women in her family. It is the women itself who can provide first mental and physical support to the other women in need when she is abused with domestic violence.

In Present times mass media plays effective role in giving direction to thoughts of people, similarly it can play important role in spreading awareness about women rights

as well as right behavior sense for in laws of married women. It is very shameful for Indian society, government and content developers that most of the advertisement of new films and web series show bold, nude and abusive character of women in their advertisements, instead of this family movies and good content can help in developing right approach for women.

More recruitment of women in police forces as well as in other sectors may also help in reducing the cases of domestic violence. Similarly they must be provided more job opportunities which will make them self-dependent and confident who can raise voice against injustice. Education along with legal knowledge is the first tool which makes any human being confident and strong enough to demand his or her rights. So the subjects related to prima facie knowledge of statutory rights and procedure must also be introduced in the school education.

Corruption in formal investigating agencies have also to be looked after because in many cases either the victim is pressurized by police and other social groups for compromise or the wrong facts are placed by police in investigation due to corrupt practices, which defies the purpose of complaint and the complainant rights. Women officers in such cases can change such system if given chance.

Status of women also depends upon the caste in which she is born, the women in lower caste faces more discrimination at their homes as well as in outside life. So it is necessary that door to door awareness programs must be organized specially in those residential areas which are abode to lower castes. With this the weekly or monthly visits of higher authorities like lady police officers and other civil authorities may boost their confidence and will also set a deterrent on culprits.

Conclusion

For Indian scenario it seems very correct to say that discrimination against women starts even before they are born and it is continued till they die. This discrimination has many faces such as female feticide, infanticide, domestic violence, mental abuse, dowry death, physical exploitation, etc. The domestic violence has many ill effects on physical, psychological, social and economic aspects of girls and

women. After discussing this sensitive topic of women it seems necessary that all the stake holders of society need to analyze the factors responsible for domestic violence so that many families can be prevented from menace of domestic violence. Such incidences have very deep effect on the life of victims and their children, so the factors responsible for such a menace should be controlled. The dignity and freedom should be ensured by their family members and society, both, likes her counterpart men.

References

- Ahuja, R (1987). *Crimes against Women*, Rawat Publication, Jaipur.
- BBC News (2023). <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-66283526>
- Chaudhary, R. Manish, Gaurav (2019), Domestic Violence against Women in India: A Study. *Panacea International Research Journal*, Vol.1 (2).
- Crimes in India 2021, Statistics Report Volume-1. *National Crime Record Bureau*, Ministry of Home Affairs, India.
- Jamwal, Malwika Singh (2022). Domestic Violence: A Harsh Reality. *International Journal of Innovative Research in Technology*, Vol.9 (5), Pp. 18-22.
- Government of India, *The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005*.
- M. N. Srinivas (1977). The Changing Position of Indian Women. *Man*, 12(2), 221-238.
- Parsad, Richa (2018). Dayan EkAndhavishvas. *International Research Journal of Management Sociology & Humanities*, Vol.9 (7) Pp. 123-126.
- Poonacha, Veena and Divya Pandey (1999). Responses to Domestic Violence in the States of Maharashtra and Madhya Pradesh. *Domestic Violence in India: A Summary Report*, International Center For Research On Women Washington, DC.
- Sharon, S. Prescila (2014). Domestic Violence Against Women in India: A Family Menace. *Indian Journal of Applied Research*, Vol. 4 (12), Pp. 147-149.

Suri, Mona, Debosmita, (2022). Domestic Violence and Women Health in India: Insights from NFHS-4. *Observer Research Foundation*.
<https://wcd.nic.in/womendevelopment/national-policy-women-empowerment>

Dr. Madhusudan
Assistant Professor
Department of Sociology
Government College BaundKalan
(CharkhiDadri)
Haryana, India
Mobile No. 9729747413
E-mail: madhusudan8787@gmail.com



Abstract

Change is the law of nature. This signifies with the rapid increase of technological advancement around the world. The other side of this advancement leads to diminishing of natural resources. Depletion of Natural resources making us to search for other renewable sources for our survival. Survival makes way to new energy sources and the topmost of it comes Green Energy is the most important of all ecological strategies due to its positive effects on three major areas – Environmental, economic and social. Green energy is any energy type that is generated from natural resources such as sunlight, wind or water. While most green energy sources are also renewable, not all renewable energy sources are considered entirely green. Renewable energy comes from the sources that are constantly and naturally renewed by earth such as wind and solar.

Paper

Change is the law of nature. This signifies with the rapid increase of technological advancement around the world. The other side of this advancement leads to diminishing of natural resources. Depletion of Natural resources making us to search for other renewable sources for our survival. Survival makes way to new energy sources and the topmost of it comes **Green Energy** is the most important of all ecological strategies due to its positive effects on three major areas – Environmental, economic and social. Green energy is any energy type that is generated from natural resources such as sunlight, wind or water. While most green energy sources are also renewable, not all renewable energy sources are considered entirely green. Renewable energy comes from the sources that are constantly and naturally renewed by earth such as wind and solar. The colour green is usually associated with health, nature and sustainability. Renewable energy is often called as sustainable energy. It makes sense that renewable energy is related to the colour that embodies nature. Conventional energy sources such as oil, coal and natural gas are highly effectively drivers of economic growth but at the same time hazard to environment and human health. The potential of renewable energy sources is enormous as they can meet the world's energy demand. Renewable energy sources such as biomass, wind, solar, hydropower, and geothermal can provide sustainable energy services, based on the use of routinely available, indigenous resources. This is supported by number of studies which indicates contribution of renewables to global energy supplies increased from 20 percent to 50 percent.

We are mostly dependent on fossil fuels to meet our daily demand of energy which however releases greenhouse

gases into the atmosphere – trapping the sun's heat and leads to global warming. Climate scientists agree that the Earth's average temperature has risen in the past century and if this trend continues the sea levels will rise. They also predict that floods, heat waves, droughts, and other extreme weather conditions could occur frequently. Acid rain, Smog and respiratory diseases are the dramatic toll on atmosphere and humans.

Renewable energy helps us to develop energy independence and security. Replacing some of our petroleum with fuels made from plant matter could save money and strengthen our energy. Some of the green energies are as follows-

Solar Energy–It is the ultimate energy source driving the earth and all other sources of energy are actually stored form of solar energy. Only one billionth of the sun's energy reaches the earth surface but it is more than enough to meet the global energy requirement.

The process of directly converting solar energy to heat or electricity is considered a renewable energy source with the help of photovoltaic cells. There are two basic forms of Radiant solar energy use - passive and active. Passive solar energy systems are static, and do not require the input of energy in the form of moving parts or pumping fluids to utilize the sun's energy. Buildings can be designed to capture and collect the sun's energy directly. Materials are selected for their special characteristics -glass allows the sun to enter the building to provide light and heat, water and stone materials have high heat capacities. They can absorb large amounts of solar energy during the day, which can then be used during the night. Green house is another example of passive radiant solar energy. Active solar energy systems require the input of some energy to drivemechanical devices (e.g., solar panels), which collect the energy and pump fluids used to store and distribute the energy. The building costs for a house heated by passive solar energy may initially be more expensive but as the year passes it reveals noticeable savings. The solar panels used in active solar energy are expensive to purchase, install and maintain. The only biggest drawback of any solar energy system is that it requires a consistent supply of sunlight to work. Most parts of the world because of their latitude and climate have less than ideal conditions for a solar-only home. Therefore, it is usually necessary for solar houses to have conventional backup systems (e.g. a gas furnace or hot-water heater) this double-system requirements further adds to its cost.

Hydroelectric Energy – It is generated by using the flowing water energy to power generating turbines for producing electricity. Most hydroelectric power is generated

by dams across large –flow rivers. A dam built across river creates a reservoir behind it. The height of the water behind the dam is greater than that below the dam which represents stored potential energy. When water flows down through the penstock of the dam, driving the turbines, some of this potential energy is converted into electricity. Hydroelectric power, like other alternative sources, is clean and relatively cheap over the long term even with initial construction costs and upkeep. Sediments deposited in reservoir due to less water flow clog the penstock renders the dam useless for power generation. Large-scale dams can sometimes damage the regional environment also like flooding, wildlife, and aquatic human population. Modernization and upgrading of old power stations are often less costly than developing a new power plant, have relatively smaller environment and social impacts, and require less time for implementation. Hydropower can provide important services to electric power systems. Storage hydropower plants can often be operated flexibly with its rapid response load-following and balancing capabilities, peaking capacity and power quality attributes, hydropower can play an important role in ensuring reliable electricity service and reducing carbon emissions. In addition, storage and pumped storage hydropower can help reduce the challenges of integrating variable renewable resources such as wind, solar photovoltaic, and wave power.

Wind Power- It is the result of the sun's uneven heating of the atmosphere. Warm air expands and rises, and cool air contracts and sinks. This movement of the air is called wind. Wind has been used as an energy source for millennia. It has been used to pump water, to power ships, and to mill grains. Areas with constant and strong winds can be used by wind turbines to generate electricity. Wind energy does not produce air pollution and it is limitless and inexpensive to produce. There is initial cost of manufacturing the wind turbine and associated upkeep and repairs. The major drawback is that it requires lots of open land, constant supply of wind. Migrating birds and insects can become entangled and killed by the turning blades. This can be counteract by using the same land for other purposes like ranching, farming and recreation.

Biomass Energy- Biomass is the term used for all organic material originated from plants. Biomass energy, or bioenergy is the conversion of biomass into useful forms of energy such as heat, electricity and liquid fuels. Biomass for bioenergy comes either directly from the energy crops, or from residues generated in the processing of crops for food or other products such as pulp and paper from the wood industry, construction and demolition wood, pellets used in transportation, and the clean fraction of municipal solid waste (MSW). The biomass to bioenergy system can be considered as the management of flow of solar generated materials, food, and fibre in our environment. The use of biomass as a fuel source has serious environmental effects. Deforestation, burning of biomass leads to increase in carbon dioxide and hence contribute to global warming. Major biomass uses fall into two broad categories- Low-efficiency traditional

biomass such as wood, straws, dung and other manures are used for cooking, lighting and space heating by poorer populations creating serious negative impacts on health and living conditions.

High-efficiency modern bioenergy uses more convenient solids, liquids and gases as secondary energy carriers to generate heat, electricity, combined heat and power (CHP), and transport fuels for various sectors. Liquid biofuels and biodiesel are used for global road transport and some industrial uses. Biomass derived gases, primarily methane, from anaerobic digestion of agricultural residues and municipal solid waste (MSW) treatment are used to generate electricity, heat or both.

Geothermal energy –It uses heat from earth's internal geological processes in order to produce electricity or produce heating. One source of geothermal energy is steam. Groundwater percolates down through cracks in the subsurface rocks until it reaches rocks heated by underlying magma, and the heat converts the water to steam. This steam comes back in the form of geyser or hot spring or sometimes wells can be dug on this steam reservoir and bring it to the surface to drive generating turbines and produce electricity. Hot water can be circulated to heat buildings. Regions near tectonic plate boundaries have the best potential for geothermal activity. The Rift Valley region of East Africa also has geothermal power plants. Geothermal energy may not always be renewable in a particular region if the steam is withdrawn at a rate faster than it can be replenished, or if the heating source cools off. It is relatively environmentally friendly, it is not practical for all situations

Wave power -Very large energy fluxes can occur in deep water sea waves. The power in the wave is proportional to the square of the amplitude and to the period of the motion. Therefore the long period ~10 s, large amplitude ~2 m waves have considerable interest for power generation, with energy fluxes commonly averaging between 50 and 70 k W m⁻¹ width of oncoming wave. The possibility of generating electrical power from these deep water waves has been recognized for many years, and there are countless ideas for machines to extract the power. Very small scale autonomous systems are used for marine warning lights. There are many difficulties facing wave power developments such as Wave patterns are irregular in amplitude, phase and direction. It is difficult to design devices to extract power efficiently over the wide range of variables, probability of extreme gales or hurricanes, peak power generally available in the deep water

Role of Teachers

In today's societies energy needs increase endless in time. The importance of renewable energy sources comes to the fore every day due to the inability of the non-renewable and non-eco-friendly energy sources, such as coal, oil and natural gas, which are frequently used to meet this need, as well as the environmental problems they cause. The need for teachers who are aware of the importance of renewable, eco-

friendly energy sources and new generations to be trained by these teachers is increasing day by day. There are serious investments being made in green/renewable energy/alternate sources that will not harm the environment, natural life and human health, but which can also respond to ever-increasing energy demand. Among these renewable energy sources, Hydro Energy, Solar Energy, Geothermal Energy, Wind Energy, Wave Energy, Hydrogen Energy and Biomass Energy are gaining importance as sources that can meet energy needs in the coming centuries. Renewable energy sources are both healthy and reliable sources and are also known as “Eco-Friendly Energy Sources”. Therefore, education should become the important tool to introduce the necessity and importance of using renewable energy sources into the minds of individuals. Today's dire need is of raising generations that do not pollute the environment and have knowledge about renewable energy sources is emphasized during the education process. The shortcomings in energy awareness originate from the lack of education and from indifference. In general, it is thought that education is an important factor in acquiring cognition and behaviour related to the use of renewable energy sources. The more knowledgeable and sensitive the teachers are about these eco-friendly resources, the more effective and easier it will be for students to gain knowledge, value and behaviour concerning this issue. Thus, teachers who are knowledgeable about renewable energy sources can guide students by providing knowledge and competence on how to use these resources in daily life. For this reason, the teachers' own attitudes towards renewable energy sources will also affect the attitudes of their students.

Therefore, courses related to renewable energy sources should be included in the course catalogues of the faculties of education at pre-service teacher training programme in universities. In addition, research centres focusing on renewable energy should be established and pre-service teachers should be actively involved in activities and projects like awareness about biodiversity, waste management, cleanliness etc. More Green Schools should be established to promote awareness about usage of Green energy. This can't be done without the help of parents and community. We as a teacher educator do our best to restore the depleted resources.

References-

-Antonia V. Herzog, Timothy E. Lipmann and Daniel M. Kaman, Renewable Energy Sources: <http://www.eolss.com>.
 -Sources, (2010). Paper published at: PROCESOS DE MERCADO. Volume VII, Número 1, Primavera ISSN: 1697-6797-13.
 -Gabriel Calzada Álvarez, Study of the effects on employment of public aid to Renewable energy sources. Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Cambridge University Press, 1st published 2012.

-Shamsudin, M.A., Harun, A.H., N., Nordin. Haniza, H., Abdul Talib, C., 2014.

The effect of online project-based learning on students' attitudes towards

Renewable energy. Malaysian J. Dist. Educ. 16 (2), 39–57.

-Siddique, M.N.I., Wahid, Z.A., 2018. Achievements and perspectives of anaerobic

Co-digestion: A review. J. Clean. Prod. 194, 359–371.

Amita Dhaaka

73, Duplex 2, Rajat Vihar, Sector-62,

Noida

201307, Ph. No. 9810116728

Abstract

Automobile sector plays a vital role in world economy. The study aims to analyze the dividend payout of Indian automobile companies under NSE to check the retained earnings and infrastructure development of selected automobile companies. All 17 companies are taken under NSE under different categories like 2&3 wheelers, Auto & Trucks, Dealers & Distributors, Light Weighted and Heavy Weighted Vehicles (LHVS & HVCS), Passenger Cars, Tractors and Trucks & LCVs. Total 17 companies are found by adding all under these categories but when Dividend Payouts of these companies were recorded from source of moneycontrol, there are 5 Companies from which 3 companies named CTT, HND and HMT did not pay any dividend in previous ten years and rest of 2 companies named TTA and TML paid dividend only in year 2014 on which ANOVA test can not be applied, it clarifies the reason behind excluding these companies from the sample that we took. By analysis, it is found that the average dividend payouts of selected automobile companies are not same at 5% level of significance but it is same at 1% level of significance. Besides this, dividend payouts are not differ with regard to previous ten years at level of 1% and 5% level of significance.

Keywords: Dividend Payouts, Net Profit, EPS and DPS

Introduction

In automobile industry of India, there are 7 sectors 2 & 3 wheelers, Auto & Trucks, Dealers & Distributors, Light Weighted and Heavy Weighted Vehicles (LHVS & HVCS), Passenger Cars, Tractors and Trucks & LCVs from which all top companies are taken listed under NSE.

Indian automobile sector is a growing sector according to recorded data. In 2022, India became 4th largest country in world after USA, China and Japan. Now, in 2023 India got 3rd position by beating Japan at global level because Japan is now at 4th position. In this study, dividend payouts of NSE listed automobile companies are analysed to check the significant relationship of dividend payouts of companies by comparing on the basis of their previous years and by comparing between automobile companies taken in this study as sample.

2 & 3 Wheelers	Auto & Trucks	Dealers & Distributors	LCVS / HVCS	Passenger Cars	Tractors	Trucks/LCVs
Bajaj Auto	M&M	Car Trade Tech	TATA Motors	Maruti Suzuki	Escorts Kubota	Ashok Leyland
TVS Motors			Eicher Motors	Hind Motors	HMT	Force Motors
Hero Motocorp			TML-D		VST Tillers	SML Isuzu
Atul Auto						

Dividend Payout: Dividend is part of a company's total net profit which distributed among shareholders of these concerned company. Payment of dividend depends upon company's financial condition and its owner that company has sufficient profits to pay its debts at time or not and owner wants to use whole net profit to develop company's infrastructure or in retained earnings.

Dividend Payout Ratio = Dividend Per Share / Earning Per Share,

Dividend Per Share = Total Dividend Paid / Number of Shareholders and

Earning Per Share = (Net Income - Preference Dividend) / Weighted Average Number of Shares Outstanding.

Earning Per Share is also known as the Bottom Line of a firm's worth.

What the Dividend Payout Ratio Tells You?

1. The dividend payout ratio is the proportion of earnings paid out as dividends to shareholders, typically expressed as a percentage.
2. Some companies pay out all their earnings to shareholders, while some only pay out a portion of their earnings.
3. If a company pays out some of its earnings as dividends, the remaining portion is retained by the business-to measure the level of earnings retained, the retention ratio is calculated.
4. Several considerations go into interpreting the dividend payout ratio, most importantly the company's level of maturity. Alternatively, the dividend payout ratio can also be calculated as:

Dividend Payout Ratio = 1 - Retention Ratio?

The dividend payout ratio provides an indication of how much money a company is returning to shareholders versus how much it is keeping on hand to reinvest in growth, pay off debt, or add to cash reserves (retained earnings). Several considerations go into interpreting the dividend payout ratio, most importantly the company's level of maturity. A new, growth-oriented company that aims to expand, develop new

products, and move into new markets would be expected to reinvest most or all of its earnings and could be forgiven for having a low or even zero payout ratio. The payout ratio is 0% for companies that do not pay dividends and is 100% for companies that pay out their entire net income as dividends. (ADAM HAYES, Updated February 06, 2023) On the other hand, an older, established company that returns a pittance to shareholders would test investors' patience and could tempt activists to intervene. In 2012 and after nearly twenty years since its last paid dividend, Apple (AAPL) began to pay a dividend when the new CEO felt the company's enormous cash flow made a 0% payout ratio difficult to justify.¹² Since it implies that a company has moved past its initial growth stage, a high payout ratio means share prices are unlikely to appreciate rapidly.

Dividends are Industry Specific

Dividend payouts vary widely by industry, and like most ratios, they are most useful to compare within a given industry. Real estate investment partnerships (REITs), for example, are legally obligated to distribute at least 90% of earnings to shareholders as they enjoy special tax exemptions. Master limited partnerships (MLPs) tend to have high payout ratios, as well.

Is a High Dividend Payout Ratio Good?

A high dividend payout ratio is not always valued by active investors. An unusually high dividend payout ratio can indicate that a company is trying to mask a bad business situation from investors by offering extravagant dividends, or that it simply does not plan to aggressively use working capital to expand.

Three Major Risks to which you can not ignore during calculating Dividend Payout Ratios: (Joseph Hogue, 2020)

1. Paying out too much of earning as a dividend and not reinvesting in the business.
2. Is the dividend payment or high payout ratio supported by cash flows?
3. Don't use the Payout Ratio for REIT or MLP.



Theories Of Dividend

Three types of theories of dividend are there:

1. Walter's model
2. Gordon's model
3. Modigliani and Miller's hypothesis

1. Walter's model:

Professor James E. Walter argues that the choice of dividend policies almost always affects the value of the enterprise. His model shows clearly the importance of the relationship between the firm's internal rate of return (r) and its cost of capital (k) in determining the dividend policy that will maximise the wealth of shareholders. According to Walter, Dividend Payout affects the market value of a firm, company or enterprises, so it clarifies the relationship between dividend policy and market value of firm.

2. Gordon's Model:

One very popular model explicitly relating the market value of the firm to dividend policy is developed by Myron Gordon.

3. Modigliani and Miller's hypothesis:

According to Modigliani and Miller (M-M), dividend policy of a firm is irrelevant as it does not affect the wealth of the shareholders. They argue that the value of the firm depends on the firm's earnings which result from its investment policy. Thus, when investment decision of the firm is given, dividend decision the split of earnings between dividends and retained earnings which have no significance in determining the value of the firm. M – M's hypothesis of irrelevance is based on the following assumptions.

LITERATURE REVIEW

1.) David Javakhadze, Stephen P. Ferris and Nilanjan Sen (2014): The study title was "An international analysis of dividend smoothing." This study was based on agency-based-models and asymmetric information theories which examined dividend smoothing at global level. Tests were applied on a cross section of more than 2,000 firms from 24 countries which showed that managers of firm with low market to book ratios and less cash engaged in higher dividend smoothin and firms with highly-concentrated ownership structure and strong corporate governance smooth dividends less. Managers of firms in an industry facing high level of competition smooths more dividends. The study determined that the legal protections provided to

shareholders and the culture of the country in which the firm is incorporated, as well as [tax](#) regime, have additional explanatory power for dividend smoothing. Our results are most consistent with the simultaneous presence of agency and [information asymmetry](#) effects in smooth dividends. This study used an international sample of firms from twenty-four countries to test the predictions of the agency and information asymmetry explanations for dividend smoothing. Our findings established that dividend smoothing occurs distinct cross-sectional patterns internationally. It determined that equity ownership concentration negative impact on dividend smoothing and the presence of multiple large block-holders increases dividend smoothing.

2.) Rembulan Rahmadia, Muhamad Nadratuzzaman and Syafaat Muhari (2016): The study title was “Analysis of Factors that Impact Dividend Payout Ratio on Listed Companies at Jakarta Islamic Index.” This research examined the effect of Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Assets Growth and Dividend Payout Ratio in a Year Before (DPRt-1) towards Dividend Payout Ratio (DPR) on Listed Companies at Jakarta Islamic Index during 2009-2014 period. The study used annual report that collected from Indonesia Stock Exchange. It applied panel data regression to analyse and used common effect model. It showed a positive and significant effect of ROA and DPR in a year before to Dividend Payout Ratio and a negative and significant effect of Asset Growth to Dividend Payout Ratio. The study also showed no significant effect of Debt to Equity Ratio to Dividend Payout Ratio. It was found the variables that most influence on the dividend payout ratio is DPRt-1 with a regression coefficient of 0.437055, which indicates that each additional of 1 factor of DPRt-1, then the amount of Dividend Payout Ratio would increase by 0.437055 assuming that the other independent variable is fixed. The coefficient determination of adjusted R² results in the regression model is 0.728767. This suggests that the ability of independent variables are ROA, DER, Asset Growth and Dividend Payout Ratio in a previous year in explaining the dependent variable is the Dividend Payout Ratio amounted to 72.88%.

3.) Byson Majanga (2015): The study title was “**The Dividend Effect on Stock Price-An Empirical Analysis of Malawi Listed Companies.**” This paper aimed to establish if there exists such a direct relationship between a firm's dividends and its stock price with particular emphasis on the Malawi stock exchange. The study analysed secondary data sets of 13 local companies listed on the Malawi Stock Exchange for the period 2008 to 2014 inclusive. This study applied correlation analysis stock price as an independent variable and dividends, retention ratio, profit after tax,

earnings per share and return on equity, as dependent variables, over the seven years. The study showed a strong positive association between stock prices. The study established that there is a strong positive relationship between a firm's dividends and its stock price on the stock market Malawi Stock Exchange (MSE). The study further found that stock price is an outcome of a number of factors, dividends being one of them and having a very significant contribution. The findings in this study will help investors, both potential and existing; as well as managers of listed companies to understand and appreciate the impact of dividend declaration or absence of it, on the psychology of stockholders which later affects the respective company's stock price on the stock exchange.

4.) David S. Koo, Santhosh Ramalingegowda & Yong Yu (2017): The study title was “The effect of financial reporting quality on corporate dividend policy.” This study examined how financial reporting quality affects corporate dividend policy. The study found that higher quality reporting is associated with higher dividends. This positive association is more pronounced among firms with more severe free cash flow problems and among firms with higher ownership by monitoring-type institutional investors. It also analysed the relation between reporting quality and under or overpayment of dividends suggests that reporting quality largely mitigates underpayment of dividends. Both granger causality test and a difference-in-difference analysis of dividend changed around a quasi-exogenous reporting event yield evidence consistent with the direction of causality going from financial reporting to dividends. Overall, these findings are consistent with financial reporting quality acting as a governance mechanism that induces managers to pay dividends by disciplining free cash flow problems. Its findings supported the view that dividends are the result of enhanced monitoring.

5.) Pradana Jati Kusuma, Sri Hartoyo, Hendro Sasongko (2018): The study title was “Analysis of Factors that Influence Dividend Payout Ratio of Coal Companies in Indonesia Stock Exchange.” This study analyzed the company internal and macroeconomic conditions on the ratio of dividend distribution, as well as knowing the conditions of coal companies on the IDX during the decline in coal prices. The weakness of the global economy has resulted in a decline in various commodity prices including coal prices. Multiple regression models were used to analyze 55 samples from 11 coal subsector companies carrying research period from 2013 to 2017. The results showed that return on assets, exchange rates, world oil

prices had a positive and significant partial effect on the dividend payout ratio of the coal subsector where dividend payout ratio in the coal sub-sector is influenced by the variables return on asset, exchange rate, and oil price. This result has a positive and significant effect on dividend policy in the coal subsector and all independent variables in the two subsectors simultaneously affect the dividend payout ratio. Dividends distributed by growth companies were a signal to investors that companies are still able to generate profits with uncertain global economic conditions. The results found that of the eight variables only three had significant.

6.) Dezhū Ye, Jie Deng, Yi Liu, Samuel H. Szewczyk and Xiao Chen (2019): The study title was “**Does board gender diversity increase dividend payouts? Analysis of global evidence.**” This paper was motivated by three considerations. First, the issue of board gender diversity is of considerable importance worldwide. Second, many countries are implementing corporate governance reforms, especially to improve board gender diversity. Third, most early studies of the governance effect of board gender diversity focus only on a single country. In nowadays number of female directors are increasing (Adams and Kirchmaier, 2016). As a sample 63,464 firm were collected from 22 countries carrying period of 2000 to 2013 in which researcher conducted a series of [multiple regression](#) analysis by which a significantly positive relationship between board gender diversity and dividend payouts were revealed. The results confirmed that board gender diversity facilitated [corporate governance](#) and consequently promoted dividend payouts. The study also showed that a good institutional environment may weaken the impact of board gender diversity on dividend payouts. Institutional ownership was positively associated with board gender diversity corporating dividend payouts increase when female senior executives have shareholdings. The findings of its analysis robusted after controlling for potential endogeneity concerns.

7.) Saleh Sitompul and Siti Khadijah Nasution (2020): The study title was “Analysis Net Profit, Dividend, Debt, Cash Flow, and Capital Net Working That Influence Investment Decisions on Manufacturing Companies.” This research was conducted to analyze the influence of factors of net profit, dividends, debt, cash flow and net working capitals simultaneously and partially on investment decisions of manufacturing companies. The population of this study were 35 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017-2019. Samples were selected using a purposive sampling method totaling 24 companies. Data were processed using multiple linear regression tests using SPSS. The results of this study indicated that the variable net

income, dividends, debt, cash flow and net working capital simultaneously influence the investment decisions of manufacturing companies. Partially, the positive and significant influence is dividends and debt, while the variable net income, cash flow and net working capital have a positive but not significant effect on investment decisions. Keywords: Net profit, Dividends, Debt, Cash Flow, and Net Working Capital and Investment Decisions. d to the data user community. Secondary data consists of cross section data and time series data (pooling data).

8.) Dapeng Pan, J. Leon Zhao, Shaokun Fan & Ziqiong Zhang (2021): The study title was “**Dividend or No Dividend in Delegated Blockchain Governance: A Game Theoretic Analysis.**” Delegated blockchain governance is the frontier of blockchain design issues that is to improve the scalability of blockchain networks. Delegated proof of stake (DPoS) blockchains such as EOS must select a few super nodes for transaction verification. In particular, the blockchain community has debated recently on whether dividend should be allowed when electing super nodes, which might be considered as unethical or unfair, leading to an open research topic and a new research gap that has theoretical value for both academia and industry. In this paper, researcher built a theoretical framework to study how dividend affects user's decisions and welfare in a DPoS blockchain and this study was based on game theory, researcher proposed a three-player Hotelling model with two policies to study the behaviors of voters and candidates and first, a static game analysis was used to show that the benefits of dividend for voters and for candidates vary with the size of reward and there exists an interval, in which the zero dividend policy would be good for the welfare of both candidates and voters. Then, evolutionary game analysis was used to examine the process dynamics of super node selection, the study found that the campaign strategy of candidates has to do with the size of platform reward given to the candidates by the blockchain platform. Especially in the asymmetric case, we find that higher level of platform reward turns to benefit candidates with large number of votes even more. Its findings were instrumental for designing dividend policies in DPoS blockchains and can stimulate more potential research in blockchain governance.

9.) Metyria Imelda Hutabarat, Harlen Silalahi, Hendrik Elisa Sutejo Samosir, Muhammad Raja Siregar and Hanna Meilani Damanik (2022): The study title was “Analysis current ratio return on asset and debt to equity ratio on dividend payout ratio.” The distribution of dividend payments showed the state of the company's performance.

The study aimed to find out the results of financial ratios to the Dividend Payout Ratio for food and beverage companies on the Indonesia Stock Exchange carrying research period from 2016 to 2021. Data collection in this research used secondary data in the form of data collection from the company's annual financial reports published on the Indonesia Stock Exchange. The analytical method used multiple linear regression which results showed that the Current Ratio had positive but not significant effect on the Dividend Payout Ratio. Return on Assets partial results had positive and significant effect on the Dividend Payout Ratio. Debt to Equity Ratio was partially proven to had no significant negative effect on the Dividend Payout Ratio. Simultaneous test showed that the Current Ratio, Return on Assets and Debt to Equity Ratio had positive and significant effect on the Dividend Payout Ratio. The urgency of research in knowing the results of financial ratios on the Dividend Payout Ratio in order to attract the attention of investors to invest more so that the issuer's capital will also increase which makes the company grow. The research contribution will give a signal to the public and those who wish to know the Dividend Payout Ratio of food and beverage companies.

10.) Seda Bilyay-Erdogan, Gamze Ozturk Danisman and Ender Demir (2023):

The study title was “ESG performance and dividend payout: A channel analysis.” This paper investigated the impact of ESG (Environmental, Social, and Governance) performance on corporate [dividend policy](#). The researchers employed a panel data set comprised of 1094 non-financial listed firms in 21 European countries from 2002 to 2019. They showed that companies with higher ESG performance are likely to pay higher dividends. The results of this study were robust to alternative variable definitions and specifications and address endogeneity concerns. Then, they investigated the possible transmission channels through which [corporate ESG](#) performance enhances dividend payouts. The study presented novel evidence that "earnings" and "risk" were two possible channels through which ESG performance augments corporated dividends.

OBJECTIVES OF STUDY

To analyze the Dividend Payouts of selected automobile companies trading under NSE.

HYPOTHESIS

H0₁: The mean DP Ratio of selected automobile companies are same in previous ten years.

H0₂: The Dividend Payouts do not differ with regard to previous ten years

RESEARCH METHODOLOGY

In research methodology, sample is taken on the basis of dividend payouts only. The companies who paid dividend

annually and excluded the companies from the sample which did not pay any dividend or paid 0% dividend. To analyse the dividend payouts of the selected companies, Arithmetic Mean, Standard Deviation, C.V%(to check consistency of dividend payouts in previous 10 years) and ANOVA(Two Way Classification).

Sectors	2&3W			A&T	D&D	L&S	MSZ			FTR			T&S				
Companies	BJJ	TVS	HRC	ATL	MM	CRF	TTA	EMT	T&L	MSZ	HND	EKT	HMT	VST	ALD	FRM	SML
Year																	
2014	44.6	25.42	61.59	27.61	22.94		193.87	24.24	193.9	13.02	0	9	0	15.62	0	5.08	24.94
2015	51.42	25.95	50.22	27.04	22.44	0	0	0	20.34	0	19.88	0	18.64	38.25	6.49	23.5	
2016	73.63	35.44	45.89	24.3	25.42	0	35.76	0	14.07	0	16.45	0	17.48	39.56	7.34	22.62	
2017	3.77	21.28	51.44	31.09	23.08	0	0	0	18.38	0	8.94	0	9	25.4	0	18.37	
2018	39.12	23.66	45.91	20.19	21.24	0	18.51	0	29.34	0	5.2	0	11.57	31.98	8.96	136.25	
2019	37.13	24.81	56.05	21.68	19.43	0	14.59	0	32.21	0	4.92	0	93.77	43.35	8.95	13.36	
2020	102.1	28.07	53.32	11.5	89.23	0	35.84	0	42.76	0	4.41	0	143.9	530.3	22.64	0	
2021	0	27.16	64.02	0	108.7	0	0	0	42.85	0	2.8	0	0	0	-11.8	0	
2022	80.71	19.93	76.75	0	22.04	0	29.29	0	36.09	0	9.63	0	17.39	32.5	-8.83	0	
2023	71.98	15.93	68.65	0	21.92	0	21.89	0	22.51	0	12.56	0	18.7	21.27	8.66	0	
Mean	50.45	24.77	57.384	16.341	37.75		18.012	18.01	36.76	9.359	33.71	76.38	4.751	23.904			
S.D	32.75	5.241	10.178	12.428	32.65		14.139	11.55	9.395	46.94	160.2	9.78	40.895				
CV%	64.91	21.16	17.74	76.06	86.49		78.5	43.17	8.366	139.2	209.8	205.8	171.08				

Companies	BJJ	TVS	HRC	ATL	MM	EMT	MSZ	EKT	VST	ALD	FRM	SML
Year												
2014						24.24				0	5.08	24.94
2015	44.6	25.42	61.59	27.61	22.94		13.02	9	15.62			
2016	51.42	25.95	50.22	27.04	22.44	0	20.34	19.88	18.64	38.25	6.49	23.5
2017	73.63	35.44	45.89	24.3	25.42	35.76	14.07	16.45	17.48	39.56	7.34	22.62
2018	3.77	21.28	51.44	31.09	23.08	0	14.38	8.94	0	26.6	0	18.37
2019	39.12	23.66	45.91	20.19	21.24	18.51	29.34	5.2	11.57	31.98	8.96	136.25
2020	37.13	24.81	56.05	21.68	19.43	14.59	32.21	4.92	93.77	43.35	8.95	13.36
2021	102.1	28.07	53.32	11.5	89.23	35.84	42.76	4.41	143.9	530.3	22.64	0
2022	0	27.16	64.02	0	108.7	0	42.85	2.8	0	0	-11.8	0
2023	80.71	19.93	76.75	0	22.04	29.29	36.09	9.63	17.39	32.5	-8.83	0
Mean	50.45	24.77	57.384	16.341	37.75	18.012	26.757	9.359	33.71	76.38	4.751	23.904
S.D	32.75	5.241	10.178	12.428	32.65	14.139	11.55	9.395	46.94	160.2	9.78	40.895
CV%	64.91	21.16	17.737	76.056	86.49	78.496	43.167	8.366	139.2	209.8	205.8	171.08

We applied Two Way Classification ANOVA (F Test) on DP ratio of 12 automobile companies : (1) On the basis of time period and (2) On the basis of 12 companies under different sectors. By using ANOVA, we comes to know about significant relationship between DP ratios of companies in specified time period.

We may also known about the retained earnings and infrastructure position in these companies because if a company pay minimum dividend or 0% dividend, it means that the company have more retained earnings and it has source to develop its infrastructure.

CONCLUSION

In findings, we can see that company Ashok Leyland (ALD) under sector Trucks/LCVs has highest Arithmetic mean(76.38) or average while company Force Motots(FRM) under same sector Trucks/LCVs has lowest mean (4.75) of dividend payouts, Ashok Leyland(ALD) has highest rate of Standard Deviation(160.2) while company TVS Motors(TVS) under sector 2&3 Wheelers has lowest Standard Deviation (5.24) and company Ashok Leyland (ALD) has highest consistency(209.8 in percentage) of dividend payouts while company Escorts Kubota(EKT) under sector tractors has lowest consistency(8.366 in percentage) of dividend payouts in previous 10 years. In

calculated results **on basis of years**, we can see that F is greater than the critical value of F at 5% level of significance, so the null hypothesis is rejected. Hence the mean DP Ratio are not same for selected NSE Listed automobile companies in previous ten years. On the other hand, F is less than the critical value of F at 1% level of significance, so the null hypothesis is accepted . It means DP Ratio of selected automobile companies are same in previous ten years. In calculated results **on basis of companies**, we can see that F is less than the critical value of F at 5% level of significance, so the null hypothesis is accepted. Hence the mean DP Ratio do not differ with regard to previous ten years. On the other hand, F is less than the critical value of F at 1% level of significance also, so the null hypothesis is accepted . It means DP Ratio do not differ with regard to previous ten years. Here we can conclude that there is no any chance for DP Ratio being same in previous ten years at any level of significance.

ABBREVIATIONS	
2&3 Wheelers	2&3W
Auto & Trucks	A&T
Dealers & Distributors	D&D
LCVS/HVCS	LHS
Passenger Cars	PCR
Tractors	TTR
Trucks/LCVs	TLS
Bajaj Auto	BJJ
TVS Motors	TVS
Hero Motocorp	HRC
Atul Auto	ATL
M&M	MM
Car Trade Tech	CRT
TATA Motors	TTA
Eicher Motors	EMT
TML-D	TML
Maruti Suzuki	MSZ
Hind Motors	HND
Escorts Kubota	EKT

References:

- 1.) [Journal of Corporate Finance, Volume 29](#), December 2014, Pages 200-220
- 2.) International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol. 6, No.2, April 2016, pp. 87–97 E-ISSN: 2225-8329, P-ISSN: 2308-0337 © 2016 HRMARS www.hrmars.com
- 3.) Majanga, Byson, The Dividend Effect on Stock Price-An Empirical Analysis of Malawi Listed Companies (August 10, 2015). Accounting and Finance Research Vol. 4, No. 3; 2015 ,

- Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2741534>
- 4.) [Review of Accounting Studies](#) volume 22, pages753–790 (2017)
 - 5.) Journal Dinamika Manajemen, [Vol 9, No 2 \(2018\)](#) , 189-197 <http://jdm.unnes.ac.id> Nationally Accredited based on the Decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education, Number 36a/E/KPT/2016 Analysis of Factors that Influence Dividend Payout Ratio.
 - 6.) [Journal of Corporate Finance, Volume 58](#), October 2019, Pages 1-26
 - 7.) International Journal of Research and Review Vol.7; Issue: 3; March 2020 Website: www.ijrrjournal.com Research Paper E-ISSN: 2349-9788; P-ISSN: 2454-2237
 - 8.) [Journal of Systems Science and Systems Engineering](#) volume 30, pages288–306 (2021)
 - 9.) Hutabarat, M. I., Silalahi, H., Samosir, H. E. S., Siregar, M. R., & Damanik, H. M. (2023). Analysis current ratio return on asset and debt to equity ratio on dividend payout ratio. *Enrichment : Journal of Management*, 13(2), 1552-1559. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i2.1477>
 - 10.) [Finance Research Letters, Volume 55, Part A](#), July 2023, 103827
 - 11.) Books used in study: R.P. Rustugi (Financial Management) and T.R. Gain & S.C. Aggarwal (Quantitative Techniques for Managerial Decisions)

From

Address: H.No. 1612/20, Ambedkar Colony Street 1,
City: Rohtak, Pin Code: 124001, State: Haryana

Mobile No: 7206994062

ISSN-2231-5837

RNI-UPBIL/2021/38102

JOURNAL IMPACT FACTOR NO: 7.01

UDC. UNDER APPROVAL NO. 62715

To

Dr. Harisharan Varma, D.Litt

Chief Editor

Abstract

This paper is intended to articulate upon foreign direct investment.

There has, in recent times, been an increasing interest in understanding foreign direct investment (FDI) and, in particular, FDI reporting in developing countries.

This paper elucidates the examination of foreign direct investment and the benefits that it can bring over other forms of investment in other countries. The issue of why foreign direct investment would be chosen over **exporting, licensing, and franchising** will be presented. For each of the alternatives, the downsides that are present as compared to foreign direct investment will be discussed to illustrate why foreign firms might choose to forego these types of investments and entry into other countries.

At the end of this examination, it should be clear that foreign direct investment is often considered a superior means of entry into a foreign country over the alternative methods that are present because it provides a company with a greater level of control over the foreign operations, as well as a way to more easily overcome local laws that may be present. As investing into another country's economy, buying into a foreign company or otherwise expanding business abroad can be extremely financially rewarding and might provide with the boost needed to jump to a new level of success. However, foreign direct investment also carries risks, and it is highly important to evaluate the economic climate thoroughly before doing it.

Keywords: Foreign Direct Investment (FDI); foreign company/enterprise; innovations; international; country; owner.

Introduction:

It is necessary to explain what is meant by the term Foreign Direct Investment (FDI) and its concept, before actually discussing the downsides of exporting, licensing or franchising as compared with foreign direct investment.

Foreign direct investment occurs when individuals or companies in one country purchase ownership of assets in other country. The purchase of the assets occur in a way that allow the foreign individuals or companies to control the means of production, the distribution, or other activities associated with a good or service in the foreign country.

This could be understood through citing an example: A company in the United States might purchase the production

facility that is used to manufacturer automobiles in China. By owning the production facility, the company from the United States is able to control the production process to ensure the quality of the vehicles, as well as the process that is used to turn raw materials into the final product.

Foreign investment was introduced in 1991 under Foreign Exchange Management Act (FEMA).

What is FDI?

A foreign direct investment (FDI) is an investment in the form of a controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. It is thus distinguished from a foreign portfolio investment by a notion of direct control.

The origin of the investment does not impact the definition, as an FDI: the investment may be made either "inorganically" by buying a company in the target country or "organically" by expanding the operations of an existing business in that country.

Broadly, foreign direct investment includes "mergers and acquisitions, building new facilities, reinvesting profits earned from overseas operations, and intra company loans". In a narrow sense, foreign direct investment refers just to building new facility, and a lasting management interest (10 percent or more of voting stock) in an enterprise operating in an economy other than that of the investor. FDI is the sum of equity capital, long-term capital, and short-term capital as shown in the balance of payments. FDI usually involves participation in management, joint-venture, transfer of technology and expertise. Stock of FDI is the net (i.e., outward FDI minus inward FDI) cumulative FDI for any given period. Direct investment excludes investment through purchase of shares.

Types of FDI:

1. **Horizontal FDI** arises when a firm duplicates its home country-based activities at the same value chain stage in a host country through FDI.
2. **Platform FDI** Foreign direct investment from a source country into a destination country for the purpose of exporting to a third country.
3. **Vertical FDI** takes place when a firm through FDI moves upstream or downstream in different value chains i.e., when firms perform value-adding activities stage by stage in a vertical fashion in a host country.

Methods of FDI:

The foreign direct investor may acquire voting power of an enterprise in an economy through any of the following methods:

- by incorporating a wholly owned subsidiary or company anywhere
- by acquiring shares in an associated enterprise
- through a merger or an acquisition of an unrelated enterprise
- participating in an equity joint venture with another investor or enterprise

Advantages of FDI:

1. Economic Development Stimulation

Foreign direct investment can stimulate the target country's economic development, creating a more conducive environment for you as the investor and benefits for the local industry.

2. Easy International Trade

Commonly, a country has its own import tariff, and this is one of the reasons why trading with it is quite difficult. Also, there are industries that usually require their presence in the international markets to ensure their sales and goals will be completely met. With FDI, all these will be made easier.

3. Employment and Economic Boost

Foreign direct investment creates new jobs, as investors build new companies in the target country, create new opportunities. This leads to an increase in income and more buying power to the people, which in turn leads to an economic boost.

4. Development of Human Capital Resources

One big advantage brought about by FDI is the development of human capital resources, which is also often understated as it is not immediately apparent. Human capital is the competence and knowledge of those able to perform labor, more known to us as the workforce. The attributes gained by training and sharing experience would increase the education and overall human capital of a country. Its resource is not a tangible asset that is owned by companies, but instead something that is on loan. With this in mind, a country with FDI can benefit greatly by developing its human resources while maintaining ownership.

5. Tax Incentives

Parent enterprises would also provide foreign direct

investment to get additional expertise, technology and products. As the foreign investor, you can receive tax incentives that will be highly useful in your selected field of business.

6. Resource Transfer

Foreign direct investment will allow resource transfer and other exchanges of knowledge, where various countries are given access to new technologies and skills.

7. Reduced Disparity between Revenues and Costs

Foreign direct investment can reduce the disparity between revenues and costs. With such, countries will be able to make sure that production costs will be the same and can be sold easily.

8. Increased Productivity

The facilities and equipment provided by foreign investors can increase a workforce's productivity in the target country.

9. Increment in Income

Another big advantage of foreign direct investment is the increase of the target country's income. With more jobs and higher wages, the national income normally increases. As a result, economic growth is spurred. Take note that larger corporations would usually offer higher salary levels than what you would normally find in the target country, which can lead to increment in income.

Disadvantages of FDI:

1. Hindrance to Domestic Investment

As it focuses its resources elsewhere other than the investor's home country, foreign direct investment can sometimes hinder domestic investment.

2. Risk from Political Changes

Because political issues in other countries can instantly change, foreign direct investment is very risky. Plus, most of the risk factors that you are going to experience are extremely high.

3. Negative Influence on Exchange Rates

Foreign direct investments can occasionally affect exchange rates to the advantage of one country and the detriment of another.

4. Higher Costs

If you invest in some foreign countries, you might notice that it is more expensive than when you export goods. So, it is very imperative to prepare sufficient money to set up your operations.

5. Economic Non-Viability

Considering that foreign direct investments may be capital-intensive from the point of view of the investor, it can sometimes be very risky or economically non-viable.

6. Expropriation

Remember that political changes can also lead to expropriation, which is a scenario where the government will have control over your property and assets.

7. Negative Impact on the Country's Investment

The rules that govern foreign exchange rates and direct investments might negatively have an impact on the investing country. Investment may be banned in some foreign markets, which means that it is impossible to pursue an inviting opportunity.

8. Modern-Day Economic Colonialism

Many third-world countries, or at least those with history of colonialism, worry that foreign direct investment would result in some kind of modern day economic colonialism, which exposes host countries and leave them vulnerable to foreign companies' exploitations.

Foreign Direct Investment Incentives:

- Low corporate tax and individual income tax rates
- Tax holidays
- Other types of tax concessions
- Preferential tariffs
- Special economic zones
- EPZ – Export Processing Zones
- Bonded warehouses
- Maquiladoras
- Investment financial subsidies
- Free land or land subsidies
- Relocation & expatriation
- Infrastructure subsidies
- R&D support
- Energy
- Derogation from regulations (usually for very large projects)

Foreign Direct Investment (FDI) stocks measure the total level of direct investment at a given point in time, usually the end of a quarter or of a year. The outward FDI stock is the value of the resident investors' equity in and net loans to enterprises in foreign economies. The inward FDI stock is the value of foreign investors' equity in and net loans to enterprises resident in the reporting economy. FDI stocks are measured in USD and as a share of GDP. FDI creates stable and long-lasting links between economies.

FDI Flows:

Foreign Direct Investment (FDI) flows record the value of cross-border transactions related to direct investment during a given period of time, usually a quarter or a year. Financial flows consist of equity transactions, reinvestment of earnings, and intercompany debt transactions. Outward flows represent transactions that increase the investment that investors in the reporting economy have in enterprises in a foreign economy, such as through purchases of equity or reinvestment of earnings, less any transactions that decrease the investment that investors in the reporting economy have in enterprises in a foreign economy, such as sales of equity or borrowing by the resident investor from the foreign enterprise. Inward flows represent transactions that increase the investment that foreign investors have in enterprises resident in the reporting economy less transactions that decrease the investment of foreign investors in resident enterprises. FDI flows are measured in USD and as a share of GDP. FDI creates stable and long-lasting links between economies.

FDI Restrictiveness:

FDI restrictiveness is an OECD index gauging the restrictiveness of a country's foreign direct investment (FDI) rules by looking at four main types of restrictions: foreign equity restrictions; discriminatory screening or approval mechanisms; restrictions on key foreign personnel and operational restrictions. Implementation issues are not addressed and factors such as the degree of transparency or discretion in granting approvals are not taken into account. The index here shows the total and nine component sectors taking values between 0 for open and 1 for closed.

COMPARING WITH EXPORTING, LICENSING, FRANCHISING

Exporting:

Exporting is the process of sending products that are produced in one country to another country for sell by local businesses. While this may seem like a relatively easy process, it can become very problematic when products are

FDI Stocks:

being exported to countries that may not be friendly with the country of origin for the products. For example, many countries are known to place large import tariffs on products from foreign nations. This makes it very difficult for foreign producers to be able to compete in foreign countries because their products have higher retail prices as compared to the same products that are produced in the country in question. Even worse, it is not uncommon for countries to completely prevent the import of certain types of products, even if the import of such products was allowed in the past. If this occurs, a company that once derived a great deal of revenue from exporting a product to a specific country can quickly find its primary market has been closed.

However, if a company owns the assets related to the production of a product in the foreign country, then it has the ability to overcome any limitations on imported products. Because the company is producing the product in the country of question, the product is not being imported at all. This means that any restrictions that occur in the form of import tariffs or even the limitation of the number of products that can enter the country become irrelevant.

Foreign direct investment is essentially a way to overcome any restrictions that are placed on products that are not produced in the country in question. The products are produced in that country, and the country in which the products are being sold are benefiting because local workers are making the products. Any negative issues that may arise because of the idea of foreign products flooding a particular country's market are able to be overcome. The end result for the company making the investment is that they are not only able to control the manufacturing or distribution process, but they are also able to have a hedge against any political or social changes that might occur in a country resulting in the inability for its products to be exported to the country in question.

Licensing:

Licensing is the process by which a company signs a contract with another company to allow it to have access to its intellectual property. An example of this might be a company in the United States that has a patent on a specific type of computer technology. The license agreement might allow the foreign country to use the patented technology to produce a similar product, or even act duplicate product. Another example of the use of a license agreement might be a company allowing its tooling process in a manufacturing operation to be used to produce similar types of products in a foreign country. The key to understanding licensing is that an agreement is created that allows one party's patents or other intellectual property to be used for a specific amount of

money in return.

In both of the situations that have been described, the real issue that is present is that the company licensing its product or service is giving control over its product or service to another company. While the licensing agreement may expressly state specific types of controls that will be present, and even specific processes that must be used in the manufacturing or distribution process, the licensor in the agreement is still giving control to the licensee. There is no guarantee that the licensee will fully comply with the license agreement. Even more, there is no agreement that the licensee will have the skills and knowledge to handle problems that may arise in order to preserve the highest reputation of the product, as well as for the licensor's reputation within the business community.

On the surface, licensing does have many financial benefits for a company. Licensing does not require any direct investment on the part of a company. The burden of finances for the foreign operations and the burden of overseeing the foreign operations are transferred to the licensee. However, with the transfer of burdens is also the transfer of control. The use of foreign direct investment allows the company to regain control because it owns the means of production or distribution. The foreign operations can be changed when problems arise to prevent any problems with the reputation of the product or the company. In addition, the company can impose strict oversight in regards to the foreign operations because it owns those operations. In a license agreement, this is not the case and the level of control is not the same.

Franchising:

Franchising is very similar to the process of licensing. However, the difference lies in the fact that franchising is the process of gaining the right to use a company's trademark or brand name. Rather than an agreement being established for intellectual property, such as computer technology, an agreement is established for the use of a name, such as being able to use the McDonald's brand name to open a fast-food restaurant in a foreign country. For the ability to use the trademark or the brand name, a fee is paid by the franchisee to the franchiser.

As with licensing, the franchising option might appear to have many benefits for the company allowing for the franchising of its name or other trademarks. The franchising pays a fee for the use of the rights. In addition, most or all of the costs of opening the business using the trademark falls to the franchisee. The franchiser shifts all of

the financial burden to the franchisee while collecting franchise fees. In most cases, the franchisee fees are established at the outset of the agreement. What this means is that the franchiser collects the fees regardless of whether the franchisee makes any money at all in the agreement.

The downside in this type of agreement, however, is that the franchiser loses a great deal of control over the franchise operations. While most franchise agreements include specific details about the way in which the trademark or brand name can be used, there is no guarantee that the franchisee will conduct its operations to the same standards that the franchiser has established for its own operations. Again, an example of this can be a fast-food restaurant. A McDonald's restaurant in one location may have the highest standards for customer service and food quality. However, a McDonald's restaurant in another location that is operated by a different franchisee may place very little emphasis on customer service or food quality. The end result is that the company runs the risk of losing customers and having its reputation ruined because of the way in which franchisees use, and even abuse, their trademarks.

These potential problems are why many companies favor foreign direct investment instead of franchising. If the company controls the assets related to production and operation, then it can control the standards for customer service and product quality. It does not have to worry about trying to monitor the operations of individual franchisees only to find that they are meeting the requirements of the franchise agreement, even if those standards are at the minimum level of the agreement.

Instead, direct investment, along with direct ownership, provides the level of control that is possible in any situation where assets are owned and controlled in the business world. While this may involve greater costs at the outset, it can also prevent greater problems related to disgruntled customers or a tarnished brand name or trademark in the future.

Conclusion:

The information that has been presented in this paper has demonstrated why many companies would choose to use foreign direct investment to enter a foreign market as opposed to exporting, franchising, or licensing. These methods of gaining a presence in a foreign market typically involve lower costs for a company as compared with buying direct control of operations in a foreign country. However, reduced costs also require that a company give up a great level of control over the foreign operations. The company must trust that the foreign licensee, franchisee, or distributor will operate with the highest standards and with the greatest respect for the

product.

In the end, foreign direct investment allows a company to enter a foreign market with the ability to overcome the problems associated with licensing and franchising. Even more, the problems that are associated with import tariffs and with the perceptions that a foreign company is attempting to take over a market to the detriment of local companies can be overcome. The assets associated with the local operations may be owned by a foreign company, but the operations are still local. Residents of the country are employed and the products that are manufactured are local products. Finally, the company making the foreign direct investment can control the local operations and ensure that those operations meet the standards it has set for how it interacts with customers, as well as the quality of the products that customers receive, regardless of where they may be in the world when they buy one of those products.

References:

- <https://itchybrainscentral.com/example-essays/foreign-direct-investment-paper>
- <http://www.makeinindia.com/policy/foreign-direct-investment/>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_direct_investment
- <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD>
- <https://www.investopedia.com/terms/f/fdi.asp>

Dr. Anita Gupta

205/33, Ram Nagar Kath Mandi
Rohtak 124001 (Haryana)
Contact no. 9467763875



Abstract

This paper primarily discusses about Discourse or we can say that how different discourses are created in a society to maintain various power structure. It further tries to distinguish between text analysis and discourse analysis and also talks about that these two are not totally different from each other but substantiates each other. Various Post-modernist thinkers and various illustrations are also discussed for a better understanding of how discourse is created and maintained in a particular society.

Introduction

"Discourses are artefacts of language through which the very reality they purport to reflect is constructed" (Riggins,1997). Discourse refers to both spoken and written words or language in which close examination of both oral/ talk and text and their relationship to the context, be it social, historical, cultural etc., in which they are constructed are analyzed. It analyzes both verbal as well as non- verbal form of communication. Like it can be used to analyze - vocabulary (particular words or particular phrases, their associations with particular kind of ideologies),grammar (in which way sentences are constructed for exposing hidden meanings behind the text),structure of sentences(structure of a text can be analyzed for how particular structure of a sentence creates emphasis or builds a narrative or creates moral obligation), genre (political speeches) and nonverbal aspects of speech; like tone of voice and pauses can be analyzed to understand the real intention/motive of speaker etc.

Discourse analysis is generally used in humanities and social sciences, like one can use it in linguistics, sociology, anthropology, political science and cultural studies etc. which is different from text analysis which focuses on rules of grammar or on logical linkages between two or more sentences. Discourses are never neutral; always reflects some ideologies, value system, belief system and social practices. Foucault (eminent French philosopher) used Discourse to represent the coexistence of power and knowledge.

There are different methods of Discourse Analysis like feminist, structuralist etc., but this article is more focused on Postmodernist approach of discourse analysis.

How discourse analysis is different from text Analysis

Text analysis and Discourse analysis are different but they are someway associated with each other. In text analysis one analyzes something only on the basis of text without

connecting or locating it in its social context, cultural context or without locating it in a particular society and only focuses on rule of grammar or logical formation of sentences whereas in Discourse analysis, one analyzes text by connecting it with society and one also tries to get the information about author's background or in which context (historical, social or cultural) text/document is created.

"Language is not only an instrument of communication or even of knowledge, but also an instrument of power. One seeks not only to be understood but also to be believed, obeyed, respected and distinguished"(Bourdieu).

A famous Hindi poem illustrates this:

??????????????????,
 ??????????????????,
 ??????????????????,
 ???????????????????

Above poem illustrates that how language is used to assign particular characteristic to some sections of the society and through language how power structure is maintained in the society.

Phrases like, "Aur kyachuriyaan (Bangles) phenkerghar me bethjau"are very often used in Indian society (usuallyby male members of the society); so, what this illustration is about?

Generally, women used to wear bangles and in our society; bangles are associated with weakness. Hence, if we deconstruct this phrase then we find that this phrase depicts the patriarchal structure of our society where weakness is usually assigned to female members of the society and reasserts women as a weaker sex.

Language can be used as an instrument of power. Idea of power being exercised through consent (Ideological Hegemony); Hegemony refers to the ability of dominant class to create a web of believes and institutional as well as social relations which are highlighted or projected as acceptable to all parts of society. By using various means; multiple discourses are created in the society and tries to get legitimacy which is a very important component of discourse. Dominant group of society exercises control in the society by creating particular discourse. For Example:

Women Discourse

Traits like softness, care, love are generally associated with women and traits like aggression, power generally associated with male members of the society but it is not necessarily right,

it totally depends upon particular individual like in which socio-cultural context one is grown up. Additionally, traits like aggression and power are even glorified and accredited more importance whereas empathy, care and lovingness are lesser valued.

"One is not born a woman, but becomes one" (Simon de Beauvoir).

Simon de Beauvoir, a French novelist and author of "The Second Sex" argued that women is not born but made. By using this sentence, she emphasized that dependent, derivative status of woman as 'the other of man' was the product of her upbringing in the society or how she was brought up. She strongly encouraged women to strive to transform their status and life style across all cultural and social reference points.

It is often believed that girls are weak in Mathematics (based on such social beliefs a certain discourse is created). But now we have a list of various eminent women mathematician: Shakuntla Devi (known as human computer because of her capability of performing lengthy calculations in her mind faster than a computer), Raman Parimala, Dr. Mangla Narlikar, Sujata Ramdorai and many more.

Various studies shows that the difference in mathematical abilities among men and women is not genetic but due to the way both are brought up.

Components of discourse:

? Discourses are never neutral always reflect some ideologies, value system, believe system and social practices.

? Discourse produces truth and knowledge through which power is exercised. As described by eminent French philosopher Foucault discourse constructs certain thought through the ordering and combinations of words which reveals certain idea and displaces certain other.

? Legitimacy is the third and very important element of discourse.

For example: Some discourses try to get legitimacy by following process of democracy like consent is achieved through the majority voting in the parliament (represents people of concerned nation). And by doing this certain power exercising groups becomes successful in getting legitimacy and people used to believe that policies of the state are the result of public consent.

Theories of Discourse Analysis:

There are various theories of Discourse analysis like Structuralism, Feminism, Modernism etc. but in this article Post Modernism theory is particularly focused. There are some basic principles of this theory:

? Criticism comprehensive explanatory theories.

? truth is relative and not absolute.

? A new vision to concepts of history, time and place. Post-Modernism was a reaction against Modernism and modernist values that 'there can be an objective reality', the explanatory statements of scientists and historians can be objectively true and false.

Post-Modernists believe that societies are fragmented/divided and pluralistic in nature not monistic. Post-Modernists reject Modernist idea of objective natural reality and described it as a kind of immature (not mature) realism. They reject the viewpoint of objectivity, and highlight that there is no such thing as absolute truth (all kind of Knowledge is socially constructed).

Major Post-Modernist Thinkers

Jean-Francois Lyotard (French Philosopher)

According to him Postmodernism is "Incredulity (disbelief) towards meta-narratives". By this he highlights disbelief about all types of theories and ideologies that claimed to be universal.

For Example: There is a popular social myth that girls are weak in mathematics that's why they don't opt for STEM subjects.

Michel Foucault (French Philosopher)

Foucault was primarily concerned with the forms of Knowledge. Foucault always believed that knowledge is socially constructed and Truth always being a social construct.

Michel Foucault is also one of the pioneers of Postmodernism, and worked on the concept of discourse and power and strength, as he believed that the speeches are strongly associated with institutions and scientific knowledge. In the sense that knowledge in an era of what constitutes a speech includes specific rules agreed upon by the community, that's why it is knowledge which constitutes the real power. In other words, all the power and authority of the society, that are expressed in the speech that power and knowledge, and this is illustrated by Foucault in his book 'The Discourse of Language'. Foucault believes that there is a very close association between knowledge and power.

Foucault affected by various thinkers when observed over the thread of knowledge power and authority of the society, and the fact that power and authority is interrelated. Foucault examines in his book "Discipline and Punish"; power system, as structured institutions and organisations, and a device for control and discipline and punishment, as well as the expression of a liberal society. Foucault was also influenced by the Bentham's work (Eribon, 1991; Thompson, 2003).

Jean Jacques Derrida (French Philosopher)

Deconstruction theory was derived from the works of Derrida. According to him "Deconstruction appears to centre around the idea that Language and meaning are often inadequate in trying to convey the message or unable to communicate the idea, which a communicator wants to express. Since the confusion arises from the language and not the object then one should try to breakdown or deconstruct the language to see if we can better understand where the confusion arises".

Various Discourse within a Discourse:

Various Discourses are created within a Discourse to maintain power structures in the society. For Example:

Feminism: Liberal Feminism, Social Feminism, Radical Feminism etc.

Ecology: Reformist Ecology, Radical Ecology etc.

Advantages:

- ? Discourse produces truth and knowledge.
- ? Meaningful interpretation of world and people.
- ? Role of Deconstruction (existing value system, believes)
- ? Useful in exposing hidden meaning
- ? Helps in understand how language is used to fulfill different motives.

Some Concerns:

- ? Lack of proper format or guideline
- ? Interpretation of data questionable (because of subjectivity)
- ? Liability and validity of research findings because it can be deconstructed number of times.

Applicability:

Statement: Girls usually opt for humanities subjects not for STEMS subjects.

Assumption in society: Usually Girls are weak in STEMS subjects that is the reason why they choose/opt for Humanities Subjects.

Discourse Analysis of this Assumption will not be simply understanding the meaning of this assumption but it will question this assumption by deconstructing it and locating this statement in socio-cultural context of that particular society in which this statement is created.

CDA (Critical Discourse Analysis):

Critical Discourse analysis (tries to explore relation between text; written or spoken; and locate it in its context, may be in cultural context, social context, political context or in economic context etc. to expose hidden power structures in the society and can be helpful in making a society which will be based on the principles of equality, freedom, inclusion and social justice.

Conclusion:

Though there are some limitations in this approach but still it is a very critical approach to understand a society or we can say that how power structures are maintained in a society and they can be in any form may be in the form of gender discrimination or Caste discrimination.

Discourse Analysts should analyze a policy (like Education related policies) or any structure (Like Caste Structure or Patriarchal structure or any tradition etc.) which exists in society from both perspective (text analysis and Discourse perspective) and he/she should expose existing power equations in the society.

In terms of analysis, CDA takes the view that texts need to be considered in terms of what they include but also what they exclude or per se omit-alternative paths of constructing or defining the world. The critical discourse analyst's work is not to simply read political and social ideologies in a textual form or study the various structures which exist in the society as it is but to consider the multiple ways in which a text could have been written or questions those structures which tries to maintain the power and also what can be other alternatives of representing the world, understanding the world and the social actions that are determined by these ways of thinking and being.

References:

- Elaati, T. (2016). POSTMODERNISM THEORY, ResearchGate.
- Khan & MacEachen. (2021). Foucauldian Discourse Analysis: Moving Beyond a Social Constructionist Analytic, SAGE journals.
- Heywood, A. (2017). Political Ideologies: An Introduction. (7th edition). Palgrave Macmillan.
- Fairclough, N. (2001). Critical discourse analysis as a method in social scientific research. *Methods of critical discourse analysis*, 5 (11), 121-138. <https://www.britannica.com/topic/postmodernism-philosophy>
- Potter, J. (2004). Discourse analysis. *Handbook of data analysis*, 607-624.
- Berg, B.L. (2001). *Qualitative research methods for the social sciences*. Allyn & Bacon.
- Howarth, D. (2010). Power, discourse, and policy: articulating a hegemony approach to critical policy studies. *Critical policy studies*, 3(3-4), 309-335.
- Chouliaraki, L. (2008). Discourse analysis. <https://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/>

<https://rhymeslyrics.com/mummy-ki-roti-gol-gol/>

Ball, S. (1993) 'What is Policy? Texts, Trajectories and Tool Boxes', Discourse: Studies in the cultural Politics of Education, 13,2, pp. 10-7.

Name: Aarti Tomar

Research Scholar

NIEPA (National Institute of Educational Planning and Administration), New Delhi, India.

Email: aartitomar002@gmail.com

Postal Address: - Aarti Tomar

G-Block, Flat no.- 254, Gaur Cascades, Rajnagar
Extension, Ghaziabad, UttarPradesh

Pin - 201017.

Mobile no. - 9354045687



ABSTRACT

This article illuminates the normative basis for international law's regulation of public emergencies by arguing that human rights are best conceived as norms arising from a fiduciary relationship between states (or state-like actors) and persons subject to their power. States bear a fiduciary duty to guarantee subjects' secure and equal freedom, a duty that flows from their institutional assumption of sovereign powers. The fiduciary theory disarms Carl Schmitt's critique of constitutionalism by explaining how emergency powers can be reconciled with the rule of law.

I. Introduction

At the heart of international human rights law (IHRL) lies a practical challenge intertwined with a theoretical problem. The practical challenge is that many of the most grave and systematic human rights abuses occur during public emergencies, when states employ extraordinary powers to address threats to public order.¹ In responding to this challenge, each of the leading international and regional covenants on civil and political rights regulates states' entry into and conduct within states of emergency.

Promoting accountability : one of the biggest challenges in India is the lack of accountability for human rights violations. This could be achieved by strengthening oversight mechanism improving the reporting and investigation of human rights abuses and ensuring that perpetrators are prosecuted and punished.

Education and awareness

Education and awareness : Education and awareness raising campaigns to promote a culture of respect for human rights and the rule of law in India . This could include initiatives such as civic education programs.

Public awareness campaigns and human rights training for officials and law enforcement agencies.

Strengthening civil society Civil society organizations play a crucial role in promoting human rights and the rule of law in India.

This can be achieved by funding resources encouraging dialogue and collaboration between civil society.

Conclusion Independent means voluntary restraints and discipline voluntary acceptance of the rule of law.

Human rights must be safeguarded to have the rule of law serve as the vehicle for putting human rights into practice and making them a reality.

Even though our nation has made great strides toward ensuring access to justice defending human rights and upholding the rule of law there are still several issues that need to be resolved fundamentals rights are protected by the Indian constitution and the judiciary has been essential in defending these rights. Corruption a lack of adequate infrastructure and a slow pace of the justice delivery system has been some of the obstacles that have hindered the successful implementation of these issues the government has implemented several initiatives including the creation of special courts the implementation of fast track courts and judicial reforms.

To mitigate the challenges encountered by marginalized communities and ensure the unfaltering preservation of the rule of law across all realms of governance it is imperative for the administration/authorities to assume a proactive stance. It is emphatically asserted that the rule of law regimes supreme necessitates the implementation of various reformative measures aimed at securing its assurance .

Abstract

This article illuminates the normative basis for international law's regulation of public emergencies by arguing that human rights are best conceived as norms arising from a fiduciary relationship between states (or state-like actors) and persons subject to their power. States bear a fiduciary duty to guarantee subjects' secure and equal freedom, a duty that flows from their institutional assumption of sovereign powers. The fiduciary theory disarms Carl Schmitt's critique of constitutionalism by explaining how emergency powers can be reconciled with the rule of law.

I. Introduction

At the heart of international human rights law (IHRL) lies a practical challenge intertwined with a theoretical problem. The practical challenge is that many of the most grave and systematic human rights abuses occur during public emergencies, when states employ extraordinary powers to address threats to public order.¹ In responding to this challenge, each of the leading international and regional covenants on civil and political rights regulates states' entry into and conduct within states of emergency.

Promoting accountability : one of the biggest challenges in India is the lack of accountability for human rights violations. This could be achieved by strengthening oversight mechanism improving the reporting and investigation of

human rights abuses and ensuring that perpetration are prosecuted and punished.

Education and awareness

Education and awareness : Education and awareness raising campaigns to promote a culture of respect for human rights and the rule of law in India . This could include initiatives such as civic education programs.Public awareness campaigns and human rights training for officials and law enforcement. Agencies.

Strengthening civil society

Civil society organization play a crucial role in promoting human rights and the rule of law in India.This can be achieved by funding resources encouraging dialogue and collaboration between civil society.

Conclusion

Independent mean voluntary restraints and discipline voluntary acceptance of the rule of law.

Human rights must be safeguarded to have the rule of law serve is the vehicle for putting human rights in to practice and making them a reality.

Even though our nation has made great strides toward ensuring access to justice defending human rights and upholding the rule of law there are still several issues that need to be resolved fundamentals rights are protected by the Indian constitution and the judiciary has been essential in defending these rights. Corruption a lack of adequate infrastructure and a slow pace of the justice delivery system has been some of the obstacles that have hindered the successful implementation of these issues the government has implemented several initiatives including the creation of special courts the implementation of fast track courts and judicial reforms.

To mitigate the challenges encountered by marginalized communities and ensure the unfaltering preservation of the rule of law across all realms of governance it is imperative for the administration/authorities to assume a proactive stance. It is emphatically asserted that the rule of law regimes supreme necessitates the implementation of various reformative measures aimed at securing its assurance .

Dr. Santosh Kumar Sharma

M.COM, PGDIM MAT.MGMT.MBA, LLB, LLM With
PhD.

H.NO. 5113 Sector-3 Fbd-pin Code 121004

Mo.-9899882948- santosh.sharma2013@gmail.com

Abstract

Wordsworth's "Descriptive Sketches" have always been seen as essentially check work, despite the author's earnestness and genuine connection to nature. Wordsworth's poetry hinges on his observations of nature, especially in "An Evening Walk" and "Descriptive Sketches." Nature is a sentient being, and Wordsworth considers it to be the greatest and best teacher available. Everyone who reads or writes about Wordsworth knows how he deals with nature.

This review paper will take a fresh look at a previously under-researched facet of his nature poetry. Wordsworth has been erroneously pigeonholed for over a century as a poet who is opposed to science and scientific methodology. There is widespread agreement amongst experts that William Wordsworth is unquestionably the best poet to ever write about the countryside, nature in all its forms, and natural beauty. He is spot on in his analysis of the material and spiritual dimensions of Earthly existence.

Keywords: *Imagination, Picturesque, Personification, Romanticism, Topographic.*

1. Introduction

Romanticism became the new vogue in English literature during the transition of the 18th and 19th centuries. All of them demonstrated Wordsworth's sincere affection for nature and ardent zeal for seeking out the reality of life. The representative poet of Romanticism, William Wordsworth, introduced a completely fresh and new stream of air to the European literary scene with his poems, which gained more significance. In English literature, Wordsworth is the shining star who never dims. William Wordsworth's poetry becomes more important in English literature.

William Wordsworth's entire life was closely entwined with nature, the perennially revered theme of human song. He was also identified as “A Worshiper of Nature.” William Wordsworth had a strong belief that only by living in tune with nature could a person experience true happiness. He also believed that nature could illuminate human kindness and universal brotherhood. He used stunning illustrations of the tremendous God's creation, including mountains, rocks, rivers, and trees, in his poems on the natural world. Wordsworth's dissatisfaction with the two poetry collections is evident in the numerous changes he made to them, especially during the duration of “*An Evening Walk*” roughly doubled just after alteration. The more

extensive adjustment and addition was made to “*An Evening Walk*,” rather than “*Descriptive Sketches*,” which may seem counterintuitive given that “*An Evening Walk*” is widely regarded as having an even more structural strength as well as stronger constant diction of description as geographical poetry. His rewriting was motivated by something other than the poem's lack of literary worth as topographical poetry.

Wordsworth was born in an area close to the flora. Cockermouth, a town located on the northern edge of the English Lake District, is his birthplace and place of upbringing. He dawdled when he was playing in the fields and woods. He was taken care of by a relative who provided him with basic food and shelter while allowing him the opportunity to enjoy the outdoors at the age of eight. His mind was winged by the natural sights and sounds, and he began to come to know the cottagers, shepherds, and lone wanderers who subsequently appeared in his dreams and even some of his later writings.

Wordsworth, at fourteen years old, was sent to Hawkshead School in northwest England's picturesque lake country. There, he was more interested in learning from the flowers, hills, and stars than he was in his books, and he spent less time in the classroom and more time outside. Unlike “*An Evening Walk*,” in which the poet simply strolls around town, “*Descriptive Sketches*” takes the reader on a trip throughout Europe. Paraphrase Wordsworth, “on the banks of the Loire” refers to France in 1791 and 1792, when the poem was written in its entirety. This directly developed from his encounter with thoroughgoing France as well as its millennia-old hopes for mankind, and as several the century written records of worldwide journey, it's a look at how people all over the world (176-679), Italy (8-175), France (45-79), France once more (7-09), and Savoy—make do with different environmental, cultural, and governmental constraints (68-739).

• An Evening Walk

One of William Wordsworth's earliest poems is titled “*An Evening Walk*.” While away at Cambridge University for education, William wrote the poem as a letter to his sister Dorothy. His early memories and outdoor experiences are highlighted in the poem. William was able to examine his loss of innocence and the shift that all go through as people

age by thinking back to nature. William's relationship with the natural world in the Lake District (and with his sister) enabled him to cope with bereavement and find value and significance in ordinary situations. Wordsworth's poetry is known for its spiritual reverence for nature, distaste for modernity, interest in the individual and imagination, fascination with children, and use of everyday language.

Wordsworth's development as a genius was greatly impacted by the hues, scents, and sounds of nature, as well as the sky's blueness, the sun's glint on the river, and the song and plumage of birds. The little boy's deep passion for nature later found expression in his writings.

Wordsworth did respectfully adhere to a particular descriptive concept when he wrote "*An Evening Walk*," but his dismissive allusion to the scenic does seem to indicate his desire to disassociate himself from that ideal. All of this points to Wordsworth's dismissal of the picturesque being more than just a matter of disobeying its technical precepts, but rather an indirect representation of his change of attitude towards the poetry tradition he still was functioning in.

Even though Blake, who was extremely tactful regarding any type of suggestion of "Natural Religion," holds Wordsworth's lyrics responsible for a gastrointestinal sickness that nearly killed him, these readers have Blake's full agreement. "*The majority of scholarly readers have focused on the poet's transition from Nature Worship or even Pantheism to a highly qualified form of natural religion, with increasing awareness of the "ennobling interchange" between mind and Nature and a late yielding of primacy to the activity of the mind or the idealising power of Imagination.*" Fortunately, scholarship tempers the affections (Blake).

A huge portion of "*An Evening Walk*" results from the simple act of reflecting on the theme, a more profound artistic urge. "*How dear to my heart is the scenes of my childhood. He likes to dwell lovingly on every detail of the landscape because by so doing he can momentarily pull himself together. There is the possibility of poetry in this; in the mature Wordsworth, it will emerge as natural piety binding his days each to each. But the mature Wordsworth does not make catalogues. It might even be said without too violent a paradox that the mature Wordsworth does not write descriptive poetry*" (Frederick 130).

A poetic epistle called "*An Evening Walk*" is "*Addressed to a young Lady.*" As is traditional, it opens with a setting description of the poet and his buddy, then moves on to a discussion of formative experiences while

simultaneously preaching (e.g., "*Alas! the idle tale of man is found Depicted in the dial's moral round,*" etc.), pride in one's community, scenery, modesty, a reflection of one's potential and humanity in the form of a body of water "pensive, sadly pleasing visions," as well as retreat. Wordsworth was the best geographical poet since Dyer even at the start of his career.

Gill (2007) concluded that the new poem is completely different from "*An Evening Walk*" although sharing the same genre. For starters, the Swiss Alps are used as the backdrop rather than the English Lake District (Gill22). The poem's structure is roughly (but not precisely) based on his extended journey. The poetic narrator has far more leeway to express his or her emotions.

Bloom (1971) stated that William Wordsworth, an English Romantic poet, is responsible for the 1793 publication of "*An Evening Walk*": "*A Romantic Poem for Nature Lovers.*" Dorothy Wordsworth, a future poet, and diarist was the recipient of his dedication when he was a teenager. Wordsworth muses that his young daughter's seeming indifference to the grandeur of the landscape may be because, as a child, she is already in tune with nature (Bloom).

Morris (1993) in his book "*Exploring Stereotyped Images in Victorian and Twentieth-Century Literature and Society*" a sonnet is a composition with fourteen lines. There is no break between the two sections of this poem, thus the distinction between the octave (the first eight lines of the poem) and the sestet (the last six lines) might not be visually apparent. However, the two are identified by a distinctive rhyme pattern. The sestet's rhyme scheme is "CDEDEC," whereas the octave's rhyme pattern is abba abba. Wordsworth emphasises the mood of the night. The first phrase, "*It is a beautiful evening, tranquil and free,*" captures the soft, serene beauty of evening on the French Riviera (Morris).

Bernstein (1992) said that "*An Evening Walk*" conveys a sense of separation from the sister he is writing to rather than from Romantic ideals. Since the distance is an emotional one, the poem is comparatively devoid of emotion. Perhaps as a result of a tense relationship with his sister Dorothy, Wordsworth appears emotionally detached in this poem. He differs in this way from the Romantic ideology of feeling. Instead, he indulges in detailed descriptions, vibrant visuals, and astute observations of the surrounding natural environment. It is obvious that Wordsworth deeply valued words, and it is

only by a sad coincidence that his name serves as a reminder of this. The poet must first cause the reader to "hear" the words for them to "see" what the poet sees. Although it is rarely explicitly stated, the distance gives the poem a sense of man's alienation from himself. Instead, the reader connects with the narrator right away and puts themselves in his shoes, their memories blending (Bernstein).

experiences detailed in "*Descriptive Sketches*" which were later incorporated by Wordsworth into his lengthy autobiographical poem "*The Prelude*" (1850) (Wordsworth "DS").

Wordsworth committed his poetry to his "beloved native places" from the very beginning. Even though he tended to abandon the environment as a primary source of subject matter in his later years, they continued to find a new origin of motivation for him throughout his life.

Wordsworth's ambitious walking excursions, which he started in the institute as well as continued long after, served as the inspiration for the style of poems that had come to be recognised as being distinctly his. He got motivation for a few of his lofty lyrics while on trips both domestically and overseas. "*Descriptive Sketches of a Pedestrian Tour in the Alps*," his first collection, commemorates the summer walking tour through France and Switzerland in 1790.

The French book "*Descriptive Sketches*" chronicles a 1790 walking journey of the Alps. Bussiere and Legouis (1891) stated "*Of the young man's passion for nature, his early poems, both published in 1793, furnish direct proof. They are the most minute and copious inventories of the aspects he saw, of the noises he heard, in his native lakes (An Evening Walk) or his wanderings through Switzerland (Descriptive Sketches). Such acuteness and copiousness of observation were only possible in the case of a devotee. However contorted and knotty the verse may be however artificial the diction, the poet's fervour is as manifest here as in the most eloquent of his subsequent effusions. Though he follows in the train of a succession of descriptive poets, he outdoes them all in the abundance of precise touches*" (Bussiere & Legouis).

It is challenging to reconstruct Wordsworth's instant reaction to these events; thirteen years later, the political unrest that occurred between August 10 and September 22 remains acknowledged. There is no denying this is radical. It was written at least five months after the events they described, yet it fits well with Wordsworth's millenarian vision described in the final chapter of "*Descriptive Sketches* Wordsworth's sole work from this

time was written in the present tense. Mazarr (2004) said that in this work, Wordsworth's raging outrage at unfair governments as well as their enthusiastic desire for a new world is strongly expressed without a trace of hesitation (Mazarr39).

All this information supports the idea that Wordsworth's radical viewpoint remained unwavering during this time. Wordsworth's previous perspective, from which he saw the British ground assault against the French revolutionary authorities as "most unnatural strife,"

Aubin (1936) is aware of its historical significance: "*An Evening Walk is an epistle in verse, Addressed to a young Lady. Conventionally enough it opens with a statement of the poet's situation far from his friend and proceeds to the early memories theme, moralizing (Alas! the idle tale of man is found Depicted in the dial's moral round, etc.), genre scenes, modesty and local pride (Did Sabine grace adorn my living line, Bandusia's praise, wild stream, should yield to thine), humanitarianism, prospect, water-mirror, pensive, sadly pleasing visions, and retirement. Even at the outset of his career, Wordsworth was the greatest topographical poet since Dyer*" (Aubin).

"*An Evening Walk*," like "*Descriptive sketches*," does more than simply compile the common elements of topographical poetry listed by Aubin; it also captures the conflicts between various poetic traditions and changes within the poetic genre itself as they occur in the new sociopolitical climate of late eighteenth century England.

Aubin said that Denham's "*Cooper's Hill*" serves as an excellent example of topographical poetry with two atypical features: instruction and description. Instructional as well as descriptive poems had frequently become interwoven by the time James Thomson, the foremost descriptive poet of the twentieth century, wrote this: "*On the whole, each preserved its integrity*" (Aubin).

Reid stated that "*Wordsworth was not exactly truthful when he recalled the circumstances surrounding his 'reluctant' return to England in December 1792, claiming that he was an active partisan whom only the 'absolute want/ Of funds' prevented from making a common cause/ With some who perished.*" He portrays himself romantically, as a revolutionary martyr who gives up his artistic dreams and dies a poet known only to "me" (himself). However, Wordsworth was quick and effective in real life, writing two topographical poems on January

29, 1793, just over a month after his return: "An Evening Walk" as well as "Descriptive sketches" (Reid 140).

2. CONCLUSION

Wordsworth emphasises nature's value for a person's mental and spiritual development. A positive relationship with nature fosters a person's connection to the social and spiritual realms. He sees the environment as a living thing that gives him joy and teaches him things. He has left readers with plenty of beautiful and heartfelt poems that will stand the test of time, but only a handful of well-known poems that show the evolution of his love for nature, his conception of Mother nature spiritualism, happiness within Mother nature, love and compassion within 'Mother nature,' mystical unification of 'Mother Nature,' the deep connection among both nature as well as humanity, comforting impact as well as the healing power of nature, and nature's teaching capability have been picked from the collection of his huge projects under pondering. A careful examination of how he treats nature can help the readers to understand and interpret most of his poems.

Reference

- Abrams, Meyer H. "Structure and style in the greater romantic lyric." *From sensibility to romanticism: Essays presented to Frederick A. Pottle*. New York: Oxford UP, 1965.
- Aubin, Robert Arnold. "Topographical poetry in XVIII-century England." vol.6. Modern Language Association of America, 1936, pp. 56-176.
- Bazerman, Charles. "What written knowledge does: Three examples of academic discourse." *Landmark Essays*, 2020, p. 159.
- Bernstein, Charles. "A poetics." *Harvard University Press*, 1992.
- Blake, William. "The Complete Poetry and Prose of William Blake: Newly Revised Edition: Edited by David V. Erdman: Commentary by Harold Bloom." Anchor books, 1988.
- Bloom, Harold. "The visionary company: A reading of English romantic poetry." Vol. 117. Cornell University Press, 1971.
- Bromwich, David. "Disowned by Memory: Wordsworth's Poetry of the 1790s." University of Chicago Press, 2000.
- Bussiere, M. M., and Emile Legouis. "Le General Michel Beaupuy." 1891.
- Frederick A. Pottle, "The Idiom of Poetry," Cornell University Press, 1946, p. 130.
- Gill, Stephen. "Wordsworth and The River Duddon." *Essays in Criticism* vol.57, no.1 2007, pp.22-41.
- Greenbie, Marjorie LattaBarstbw. "Wordsworth's Theory of Poetic Diction." vol. 57, Yale University Press, 1907.
- Harper, George McLean. "Wordsworth: His Life, Works, and Literature." John Murray, 1916, p. 132.
- Jackson, Geoffrey. "Nominal and Actual Audiences: Some Strategies of Communication in Wordsworth's Poetry." *The Wordsworth Circle* vol.12, no.4, 1981, pp. 226.
- Legouis, Emile. "The Early Life of William Wordsworth, 1770-1798: A Study of The Prelude". JM Dent, 1921. pp. 135-137.
- Milton, John. "L'Allegro, in John Milton: Complete Poems and Major Prose." Merritt Y. Hughes (ed.), The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1957, p. 69
- Mazarr, Michael J. "The psychological sources of Islamic terrorism." *Policy review*, vol. 125, 2004, p.39.
- McKusick, James C. "Wordsworth's Home at Grasmere." *Green Writing*, 2000, p. 53.
- Morris, John, ed. "Exploring Stereotyped Images in Victorian and Twentieth-Century Literature and Society." Edwin Mellen Press, 1993.
- Newlyn, Lucy. "Wordsworth Among the Glow-Worms." *Essays in Criticism*, vol. 61, no. 3, 2011, p. 249.
- Owen, H. J. B. "Wordsworth as Critic." Toronto." University of Toronto Press, 1969.
- Quayle, Thomas. "Poetic diction: A study of eighteenth-century verse." Good Press, 2022, p. 175.
- Rudy, John G. "Wordsworth, and the Zen Mind: The Poetry of Self-Emptying." SUNY Press, 1996.
- Reid, Ian. "Wordsworth institutionalized: the shaping of an educational ideology." *History of Education*, vol.31, no.1, 2002, p. 140.
- Sheats, Paul D. "The Making of Wordsworth's Poetry, 1785-1798." *The Making of Wordsworth's Poetry*, Harvard University Press, 2013, pp. 56-60.
- Scott-Curtis, Conrad T. "Landscape to a blind man's eye: Wordsworth's poetics of kinaesthesia." Stanford University, 1998.
- Price, Uvedale. "Essays on the Picturesque, as compared with the Sublime and the Beautiful; and, on the Use of Studying Pictures, for the purpose of Improving Real Landscape." vol. 2. J. Mawman, 1810.

Vincent, Patrick. "Sons of Nature: The Bourgeois Pursuit of Happiness in the Swiss Alps and Wordsworth's Lake District." *Fashioning England and the English*, 2018, pp. 147.
Wordsworth, William. "An evening walk (EW)." vol. 9, Cornell University Press, 1984.
Wordsworth William. "Descriptive Sketches (DS)." Cornell University Press. 1973.

Dr. Ram Manohar

Lohia Avadh University Ayodhya(up)
Research Supervisor
Dr. Vinod Kumar Mishra
Principal(indira Gandhi P.g. College
Gauriganj Amethi).

Ghanshyam Kumar

Research Scholar(english)
Indira Gandhi P.g. College Gauriganj Amethi.
Mobile-9792466499
Email-ghanshyamapm01@gmail.com
Address-
Vill-sonaisa(hainsa),post-rasulabad
Dist-ayodhya (up),pin Code-224172



सारांश

सम्पूर्ण विश्व ही नादमय है। सामान्य रूप से नाद का अर्थ मधुर ध्वनि है। नाद ग्राह्य भी होता है और अग्राह्य भी। ग्राह्य नाद आनंद देता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अग्राह्य नाद वह है जो कानों को पीड़ा देता है। इससे हम बचना चाहते हैं। मतंग, शारंगदेव जैसे संगीतकारों ने संगीतोपयोगी ध्वनि के लिए 'नाद' शब्द का प्रयोग करते हुए उसे आध्यात्मिक रूप से महिमामंडित किया। 'संगीत दर्पण' में नाद के दो भेद बताए गए हैं—आहतनाद और अनाहतनाद। आहतनाद संगीतज्ञों का उपास्य है। अनाहतनाद योगी जन साध्य है। आहतनाद गीत, वाद्य और नृत्य तीनों संगीत रूपों में निहित है। अनाहतनाद बिना किसी आघात के स्वयं उत्पन्न होता है। यह स्वयम्भू होता है। यह नाद तो विरल व निस्संदेह मुक्तिदायक है किन्तु आहतनाद भी सांसारिकता से परे अलौकिकता की ओर ले जाने वाला होता है।

भूमिका

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही नादमय है। वैज्ञानिक दृष्टि से दो वस्तुओं की टक्कर अथवा रगड़ पास की वायु को आन्दोलित करती है तथा जलतरंग की भाँति वह वायु, वातावरण में कम्पन उत्पन्न करती हुई हमारे कर्ण-रन्ध्रों में प्रवेश कर प्रकृति-प्रदत्त कर्ण-यन्त्र को स्पन्दित करती है, जिससे हमारी चेतना को ध्वनि का अनुभव होता है। "जब तक हमारे कर्ण-यन्त्र वातावरण में उत्पन्न आन्दोलनों को ग्रहण नहीं करते, तब तक हमारे लिए ध्वनि का कोई अस्तित्व नहीं होता। यद्यपि यह विश्व नाद से भरपूर है, किन्तु हम अपने कर्णयन्त्रों की सीमित शक्ति के कारण उन सबका श्रवण नहीं कर पाते। 1 सृष्टि नाद के अधीन है जैसा कि संगीत दर्पणकार का भी कथन है—"नादाधीनमतो जगत्" 2

नाद की शाब्दिक व्युत्पत्ति

साधारण रूप से नाद का अर्थ मधुर ध्वनि है। "नाद" का सामान्य अर्थ ध्वनि अथवा "आवाज" है। सृष्टि, संगीत और साहित्य का आधार "नाद" शब्द नमद शब्दों की सन्धि से बना है। 'न' से भाव नकार और 'द' से भाव दकार है। नकार का अर्थ है वायु (Breath) और दकार का अर्थ है अग्नि (Energy)। जब नकार और दकार का योग होता है तो नाद की उत्पत्ति होती है — संगीत रत्नाकरकार की भी यही मान्यता है—

"नकारं प्राणानामानं दकारमनलं विदुः

जातः प्राणाग्नि संयोगातेन नादोऽभिधीयते ।" 3

शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से "नाद" शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की "नद्" धातु से हुई है, जिसका अर्थ है— 'नदति इति नादः' अर्थात् जो ध्वनि आनन्द प्रदान करे वही नाद है— संगीतोपयोगी, कानों को सुरीली तथा मधुर लगने वाली, चित्त को आनन्द देने वाली तथा मन का रंजन करने वाली सुखदायिनी ध्वनि को संगीत की भाषा में नाद

कहते हैं। मधुर और कर्णप्रिय ध्वनि के लिए नाद संज्ञा है, गायन, तन्तुवाद्यों का वादन, मृदंग या पखावज की थाप, वंशी की फूंक इत्यादि नियमित कम्पन या तरंग पैदा करते हैं और इसीलिए उनकी ध्वनि मधुर होती है। इसके विरुद्ध बिजली की गड़गड़ाहट, गोली की धमाधम—ये सभी अनियमित कम्पन पैदा करते हैं और इसीलिए कर्णकटु है। उनको 'नाद' न कहते हुए कोलाहल या शोर कहते हैं।

नाद और वाक्

भरतमुनि ने नाद के सन्दर्भ में "वाक्" शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार "तस्माद्वाचः परम् नास्ति वाग्हि सर्वस्य कारणम् ।" 4 अर्थात् वाक् से परे और कुछ नहीं है, वाक् ही सम्पूर्ण वाङ्मय एवं चराचर जगत् की जननी है। संसार का कोई भी जीव-जन्तु व प्राणी वाक्-नाद से बाहर नहीं है। नाद से वर्ण, वर्ण से शब्द रूप से वाक्य से भाषा उद्भूत होती है और भाषा से सृष्टि का सब व्यवहार चलता है, अतएव सम्पूर्ण सृष्टि ही नाद के अधीन है—

नादेन व्यज्यते वर्णः पदं वर्णात् पदावचः

नादेन व्यज्यते वर्णः पदं वर्णात् पदावचः

वचसो व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगत् 5

नाद ब्रह्मः ऐतिहासिक सन्दर्भ

संगीत के शास्त्रकार व चिन्तक समय-समय पर नादतत्त्व पर चिन्तन एवं मनन करते रहे हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि भारतीय संगीत का उद्गम ही नाद ब्रह्म में देखा गया है। व्याकरण और साहित्य में जिसे शब्द ब्रह्म कहा गया है, संगीत में उसे 'नाद ब्रह्म' से विभूषित किया गया। निरन्तर नाद का अनुसन्धान करने से वासनाएँ सम्यक् रूप से क्षीण हो जाती हैं और मन और प्राण निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है। 6 संगीत के विशिष्ट स्वर न केवल हमारी शारीरिक तंत्रिकाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारी पाशविक वृत्तियों का दमन भी करते हैं।

मतंग ने संगीतोपयोगी ध्वनि के लिए 'नाद' शब्द का प्रयोग करते हुए "नाद" को आध्यात्मिक रूप से महिमा-मंडित किया है। 13वीं शताब्दी में शारंगदेव ने संगीत-रत्नाकर में नाद की चर्चा विस्तृतरूप से की और उसे 'ब्रह्म' की संज्ञा से विभूषित किया। 'मंगलाचरण' में नाद-ब्रह्म की उपासना करते हुए उन्होंने कहा है—

"चैतन्य सर्वभूतानां 'विवृतं' जगदात्पना

नाद ब्रह्मा तदानन्दमद्वितीयमुपास्महे ।" 7

नाद के प्रकार

संगीत-दर्पण में नाद के दो भेद इस प्रकार बताए गए हैं—

आहतोऽनाहतश्चेति द्विधा नादो निगद्यते

सोऽयं प्रकाशते पिण्डे तस्मात् पिण्डोऽभिधीयते । 8

अतः नाद के दो भेद है

1. आहत नाद—यह नाद संगीतज्ञों का उपास्य है

2. अनाहत नाद—योगजन साध्य है।

जो नाद दो वस्तुओं के संघर्षण अथवा वाद्यों पर आघात करने से उत्पन्न हो उसे आहत नाद कहते हैं। जो नाद “बिना आघात के उत्पन्न हो तथा साधारणतः सुनाई न दे वह अनाहत नाद कहलाता है।

आहत नाद

आहत नाद का अर्थ है आघात द्वारा उत्पन्न नाद। अतः जो नाद आघात करने से उत्पन्न होता है, वह आहत नाद है। संगीत में यही नाद उपयोगी है। तालु आदि स्थानों से जिह्वा और प्राणवायु के आघात से एवं वाद्यों में आघात से जो नाद उत्पन्न होता है, उसे “आहत नाद” कहते हैं। आहत नाद के बार में “नारद संहिता” का मत है कि—

आहतस्तु द्वितीयोऽसौ वाद्येश्वाघात् कर्मणा

तेन गीत स्वरोत्पत्तिः स नादो जायते भुवि । 9

अर्थात् द्वितीय नाद जिसे “आहत नाद कहते हैं, वह विविध वाद्यों में वायु के आघात से प्रकट होता है और उससे सातों स्वरों की उत्पत्ति स्पष्ट प्रतीत होती है। यह नाद देहधारियों की देहों में इस प्रकार होता है कि गायक गाता है और वाद्य उसके स्वरानुकूल समध्वनि का सहयोग देकर उसके सौन्दर्य रूपी रूपक, माधुर्य और आनन्द में सुचारुता एवं मनोहरता में अभिवृद्धि प्रदान करते हैं।

आहत नाद की प्रकिया

आहत नाद गीत—वाद्य एवं नृत्य सभी में निहित है। संगीत रत्नाकर में आहत नाद की प्रकिया इस प्रकार बताई गई है—“बोलने की इच्छा प्रकट होने पर अन्तरात्मा मन को प्रेरित करती है और मन की प्रेरणा देहस्थित अग्नि पर धक्का लगाती है और अग्नि के द्वारा प्रेरित वायु, जो ब्रह्म ग्रन्थि में स्थित रहती है, वह ऊपर की ओर दौड़ती है। आशय यह है कि वह आहत नाद मूलाधार से आरम्भ होकर नाभि पर केन्द्रित होता हुआ हृदय, कंठ और मस्तिष्क पर्यन्त दौड़कर फिर मुख में ध्वनि को प्रकट कर देता है।” 10

किन्तु अहोबल पंडित “नादोत्पत्ति प्रकिया का स्थल “हृदय” को मानते हैं। अतः यहाँ वैश्वव सम्प्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि उसी सम्प्रदाय में हृदय ही चेतना का प्रमुख स्थान है। आहत नाद सगुण व साकार है। जनजीवन में भी इसकी निरन्तर प्रकिया होती रहती है। जब हम किसी अभ्यंतर ध्वनि को वाणी द्वारा प्रकट करते हैं, तब वह भी आहत नाद ही है। वायु और अग्नि के संयोग द्वारा देह में आहत नाद का प्रकट हो जाना, जो हजारों वर्ष के हमारे आचार्यों ने सिद्ध किया था, वही तथ्य आज रेडियो द्वारा

अग्नि—रूपिणी विद्युत शक्ति और वायु लहरी के आघात संयोग की नाद—शक्ति को आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। इस सम्बन्ध में शरच्चन्द श्रीधर परांजये का कथन है—

“ध्वनि विज्ञान का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि नाद नियमित कम्पनों का समूह है। सुनने में नाद भले ही अटूट प्रतीत होता है, परन्तु यथार्थ में वह ध्वनि—तरंगों का समूह है। जैसे नदी का प्रवाह दिखने में अखण्ड दिखाई देता है परन्तु वास्तव में असंख्य जल बिन्दुओं का समूह है, ठीक उसी प्रकार गायन या वादन का नाद भले ही अखण्ड सुनाई पड़े, परन्तु यथार्थ में वह विशिष्ट तरंगों का समूह मात्र है। वातावरण का माध्यम है, जिससे ये तरंगे हमारे कान तक पहुंच जाती हैं। वातावरण न होता तो हम नाद सुन ही नहीं सकते। आघात से पैदा होने वाली ध्वनि—तरंगे वातावरण में वर्तुलाकार रूप में प्रवास करती हैं।.... भौतिक विज्ञान की दृष्टि से नाद नियमित कम्पन तथा नियमित कालावाली ध्वनि है।” 11

आहत नाद के प्रकार

संगीतोपयोगी ध्वनि ही संगीत में ग्राह्य है। आचार्य मतंग ने आहदनाद संगीत के पांच भेद बताये हैं जो मनुश्य शरीर के भिन्न—भिन्न स्थानों से उत्पन्न होते हैं—सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त तथा कृत्रिम जो क्रमशः गुह्य, हृदय, कण्ठ, तालु तथा मुख से उत्पन्न होते हैं। नारदीय शिक्षा में पंचविधनाद बताये गये हैं। घर्षण—प्रकिया में प्रयुक्त उपकरण के आधार पर यह वर्गीकरण है—

1. नखज— तन्तु वाद्यों के नाद वीणा आदि वाद्य नखज हैं।
2. वायुज— सुशिर वाद्यों के नाद वंशी आदि वाद्य वायुज हैं।
3. चर्मज—मृदंग, तबलादि के नाद
4. लोहज— ताल, मंजरि, मंजीरा, झांझ इत्यादि के नाद
5. शरीरज—मानव कंठ द्वारा अभिव्यक्त नाद

आहत नाद और संगीत

सृष्टि का मुख्य आधार ध्वनि है। इसी से सम्पूर्ण सृष्टि का व्यवहार क्रम चलता है। यही जड़ जगत तथा चेतन रूप का प्रथम स्पन्दन है। संगीत की सृष्टि का आधार स्वर होते हैं जो नाद की परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी—इन चारों अवस्थाओं के मध्य से होकर क्रमशः मूर्छना, ग्राम, वर्ण, अलंकार, राग आदि क्रम विशेषों में विकसित होकर वाक्य और स्वरों के मिले सम्बन्ध से मधुमय संगीत की भव्य भूमिका प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा को अनादि कहा गया है, उसी प्रकार संगीत को भी अनादि कहा गया है। ‘ओइम्’ प्रथम ध्वनि है। ध्वनि से नाद, नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर और स्वर से सप्तक उत्पन्न होता है। ध्वनि का जो उतार—चढ़ाव सम्भाषण में भावों का बोधक होता है, वही नियत अवधान देने पर संगीत के स्वरों का स्थान ले लेता है। इसी अवधान से संगीत प्रयोज्य सात स्वर शडज, ऋशभ गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत एवं निशाद का जन्म हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि मोर से शडज, चातक से रिशभ, बकरा से गांधार, कौआ से मध्यम, कोकिला से पंचम, मेढ़क से धैवत तथा हाथी से निशाद स्वर की उत्पत्ति हुई।

नाद संगीत कला का प्राण, लय उसकी गति है। नाद के तत्वों के अभिव्यक्ति की अवस्था तक लाने की क्रमगत रूपरेखा को यदि लय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वरों को नाद और नाद को स्वरों की आवश्यकता होती है। एक दूसरे के अभाव में इनकी स्थिति अंध और पंगु के तुल्य होती है। संगीत की सृष्टि सारभूत तत्त्व के रूप में स्वरात्मक एवं लयात्मक नाद से होती है। आहत नाद गीत, वाद्य एवं नृत्य-तीनों संगीत-रूपों में निहित है। नाद के अभाव में संगीत एकदम निश्प्राण है। अपने नाद-सौन्दर्य के कारण ही संगीत हृदय से ग्राह्य व रसात्मक बनता है। नाद ही संगीत में रस-निश्पत्ति का मूलभूत साधन है।

संगीतकारों का मानना है कि संगीत में शब्द के अर्थ का बोध हुए बिना ही भाव या रस की प्रतीति हो जाती है। यहाँ तक कि शब्द हो या न हो, नाद के बल से संगीत में रस-निश्पत्ति हो जाती है।

अनाहत नाद

जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि बिना किसी आघात या घर्षण से जो नाद उत्पन्न होता है उसे "अनाहत नाद" कहते हैं। साथ ही इसे अनहद या दिव्य नाद भी कहा जाता है। संगीत परिजात में अहोबल पंडित ने अनाहत नाद का वर्णन इस प्रकार किया है—“जो जन्य नहीं हैं, वह नाद नित्य सुनाई पड़ता है वही अनाहत नाद है।” 12 अनाहत या अनहद नाद उस अद्भुत ध्वनि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो मानव शरीर के भीतर आप से आप उठती रहती है। समाधिस्थ योगियों को यह प्रतीति रहती है कि वे अपने भीतर एक प्रकार की मधुर ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं। सन्त लोग भी इस ध्वनि में पूरी आस्था रखते हैं। संत ज्ञानेश्वर का कहना है—“अनाहत नाद से दिशाएँ ओत-प्रोत हो जाती हैं। 13

अनाहत नाद ही ओंकार है जो समस्त जगत पिण्ड में बिना आघात के झंकृत होता रहता है। संत महात्माओं ने उसे 'सोऽहं' ध्वनि से भी विभूषित किया है। किन्तु इस दिव्य अनाहत नाद को सुनना इतना सरल-सुगम नहीं है। केवल एक साधक व्यक्ति ही अपनी साधना से इसे सुन सकता है। यह नाद लोक के लिए अनुरक्तिदायक नहीं, अपितु मुक्तिदायक है।

निष्कर्ष

नाद तत्त्व समस्त सचराचर जगत् की आत्मा है। इसे नाद ब्रह्म के नाम से पुकारा जाता है। नाद का सामान्य रूप ध्वनि है। ध्वनि प्रकृति का गुण है, जो आकाश की भाँति व्यापक और अखण्ड है। जिस प्रकार एक अंकुर से वट वृक्ष की तथा पंचभूत आदि तत्वों से जगत् की सृष्टि होती है, उसी प्रकार एक नाद से उत्पन्न कुछ स्वरों के माध्यम से संगीत के विस्तृत रूप की रचना होती है। साहित्य का आधार नाद का स्वर व्यंजनात्मक स्वरूप है, संगीत का आधार नाद का स्वरात्मक आरोह और अवरोह है। नाद के रूपों साहित्य और संगीत को हम मनुष्यता का लक्षण मानते आए हैं। इनसे अपरिचित व्यक्ति को हमारी संस्कृति में पशु की संज्ञा दी गई है। नाद सौन्दर्य जनित आनन्द

अनन्त व असीम है। नाद-सौन्दर्य की अभिव्यक्ति से साधन भी अनन्त हैं।

नाद अद्वितीय और आनन्दस्वरूप है। मणि और प्रभा की खोज करने पर जिस प्रकार मणि की प्राप्ति होती है, ब्रह्म और नाद का भी वैसा ही सम्बन्ध है। डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने यथार्थ ही कहा है—“जीवन रूपी संगीत ही नादब्रह्म या वाग्देवी की वीणा है, जिसके सप्तक में विश्व के आनन्द की सप्त धाराएँ मूर्त रूप ग्रहण करती हैं। संगीत की सच्ची साधना वही है जिसके फलस्वरूप मानव का मन उस उच्चतर सूक्ष्म नाद का अनुभव करने के योग्य बन सके। जिस नाद ने भगवान कृष्ण की मुरली से प्रस्फुटित होकर जगत् वश में कर लिया और जो नाद प्रत्येक प्राणी के हृदय में चेतन रूप में विद्यमान है तथा तो नाद कबीर, सूर, तुलसी जैसे कवियों की भक्ति-साधना का माध्यम बना, वह नाद वन्दनीय है।

1 भारतीय संगीत वाद्य-डॉ० लालमणि मिश्र पृ०-1

2 संगीत-दर्पण 1/14

3 संगीत-रत्नाकर, पं० शाङ्गदेव, प्रथम अध्याय, श्लोक-7

4 नाट्यशास्त्र, 14/3

5 संगीत-दर्पण 1/14

6 नाद बिन्दूनिशद 2/1-5

7 संगीत-रत्नाकर श्लोक 1, पृ० 108

8 संगीत दर्पण, श्लोक 15 पृ० 16

9 भ०सं० की० पृ० 15

10 संगीत रतनाकर पृ० 112, श्लोक 5

11 संगीत बोध पृ० 41

12 संगीत पारिजात पृ० 91

13 ज्ञानेश्वरी, अध्याय 6

डॉ० रुचि गर्ग

प्रवक्ता, संगीत विभाग
राजकीय सर्वोदय कन्या
विद्यालय, पड़पड़गंज,
दिल्ली

सम्पर्क — 9871182345

जर्नल भेजने के लिए आवासीय पता:

डा० रुचि गर्ग, C/O शुद्धोधन अग्रवाल

प्लॉट नं० 16, शक्ति खण्ड-2

इंदिरापुरम, गाजियाबाद, 201014

सारांश :

भाषा का व्यवहार पूरा जगत में मौखिक और लिखित रूप में होता है। भाषा समाज के अर्जित सम्पत्ति है, भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है। संताली भाषा के विशिष्ट ध्वनियों को उच्चारित करने के लिए कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण रोमन, नागरी, बंगला और अन्य लिपि में नहीं किया जा सकता। पंडितों ने इस ध्वनियों को “चेक एण्ड ग्लोटल चेक साउण्ड” कहा है। वर्तमान समय में प्रिंटिंग प्रेस ओलचिकी एवं अन्य लिपि के लिए ही कार्यरत है। “भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।”

संताली आग्नेय परिवार के भाषा हैं। “संताली, मुंडारी, हो आदि भाषाओं को सबसे पहले मैक्समूलर ने द्रविड़ भाषाओं से अलग समझा। डॉ० ग्रियर्सन ने इन्हें कोल भाषा-परिवार के अंतर्गत रखने का प्रयत्न किया।¹ प्राचीन संताल भाषा तत्कालिन बोलचाल की भाषा से कुछ भिन्न है। इसके विकास का काल 17वीं शताब्दी के बाद का है। यह मुंडारी शाखा की भाषा है। कुछ संताल लेखकों का मानना है कि लगभग 18वीं शताब्दी में भाषा लिखने के लिए बाबा तिलका मांडी ने कैथी लिपि का व्यवहार किया था। उस दौरान संताली बोलचाल की भाषा ही थी। संताली भाषा के जानकारों से इसका लिखित रूप 17 वीं शताब्दी में इसके स्पष्ट रूप “संताली” सामने आए। कुछ समय तक होड़-रोड़ की प्रवृत्तियाँ आधुनिक भाषा में मिल रही, पर धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है।

भाषा पर स्थान, जलवायु, पहाड़, समुद्र और सभ्यता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जलवायु अलग अलग होने के कारण लोगों के उच्चारण में अंतर पड़ता है, इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के कारण भी नये नये विचारों के लिए नये नये शब्द उत्पन्न होते हैं जिससे भाषा का शब्द भंडार बढ़ता जाता है।

आजादी के बाद परिभाषित शब्दों की आवश्यकता हुई, अनेक अंतराष्ट्रीय शब्द अपनाये जा रहे हैं, नये शब्द बनाये जा रहे हैं तथा भारत के अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण किये जा रहे हैं। अब तक यह भाषा पत्र-व्यवहार, समाचार पत्र, एवं साहित्यिक भाषा हो गई है। यह भाषा विकास होती नजर आ रही है। 20 वीं शताब्दी के 3 और 4 दशक को संताली साहित्यिक का स्वर्ण युग कहा गया है।

19वीं सदी के अन्त तक संताली मुख्यतः गद्य की भाषा थी। इसके बाद इसका प्रयोग पद्य में होने लगा। जैसे-जैसे संताली का गद्य और पद्य में प्रयोग बढ़ता गया, इसमें शुद्धता एवं एकरूपता आती गई। अब रूप की दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी होती जा रही है।

किसी भी भाषा में नित्य नये शब्दों, वाक्यों का आगमन होता रहता है और पुराने शब्द टुटते मिटते रहते हैं।

हम जानते हैं कि हर भाषा का अपना प्रभाव हुआ करता है। हर आदमी की अपने-अपने हिसाब से भाषा पर पकड़ होती है और उसी के अनुसार वह एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। जब पारस्परिक सम्पर्क के कारण एक जाति की भाषा का दूसरी जाति की भाषा पर असर पड़ता है, तब निश्चित रूप से शब्दों का आदान-प्रदान भी होता है।

आज की संताली भाषा का क्षेत्र व्यापक हुआ करता है। इसे सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, और व्यापारिक आदि मान्यता प्राप्त होती है। भाषा का अपना गठित व्याकरण हुआ करता है। जब कोई बोली विकास करते – करते उक्त सभी मान्यताएँ प्राप्त कर लेती है, तब वह मान्य भाषा का रूप धारण कर लेती है।

अतः कुछ साहित्यिक संस्थाओं द्वारा साहित्यिक पत्रिकाएँ प्रकाशित की गईं। इसके अलावे राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर के कुछ साहित्यकार संस्थाओं का भी गठन किया गया। भाषा और साहित्य के विकास पर संताली लेखकों ने तीन दर्जन से ज्यादा अखिल भारतीय सम्मेलन कर चुके हैं। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। हरेक सम्मेलन में भाषा और साहित्य के विकास पर विस्तृत चर्चा के अलावे राज्य स्तर पर संताली को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रस्ताव पारित किये गये हैं। संताली भाषा के साहित्यिक महत्व भी दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस भाषा में अनेक प्रकार से महत्व तत्वों विद्यमान है, अन्य भाषाओं से भी अनुवाद करके अपनी गिनती संख्या बढ़ा रही है।

सबसे पहले मिशनरियों द्वारा संताली के प्रति उत्साह देखकर स्थानीय रचनाकारों ने लिखित साहित्यों का सृजन आरंभ किया। इसमें 1936 ई० में प्रकाशित कविता संग्रह ‘ओनोंडहें बाहा डालवाक’ नामक पुस्तक का पाउल जूझार सोरेन की मौलिक कविताएँ हैं। 1942 ई० से 1945 ई० तक डब्ल्यू० जी० आचार्य लोकगीतों का दो संग्रह प्रकाशित किया – “होड़ सेरेज” और “दोड़ सेरेज”। श्री पंचानन मराण्डी लिखित ‘सेरेज इता’ (गीत के बीज) और श्री ठाकुर प्रसाद मुर्मू द्वारा लिखित ‘एमेन आड़ाड.’ (जागरण ज्ञान) दोनो संग्रह फुटकर कविताओं के हैं। 1953 ई० में देवनागरी लिपि में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा रचित 14 कविताओं का संग्रह ‘भुरका इंपिल’ (शुकृतारा) का प्रकाशन हुआ। 1953 ई० में डोमन साहू समीर द्वारा रचित पुस्तक ‘दिसोम बाबा’ (राष्ट्रपिता) जो संताली लोकगीत-छन्द में है। बाहा सेरेज, नामक पुस्तक भी बंगला लिपि में 1927 साल में प्रकाशित संताली का सबसे पहला उपन्यास बाहा

डलवाक् नाम से प्रकाशित हुआ। “1936 से 1938 ई० साल तक इस उपन्यास पुस्तक “पेड़ा होड़” पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक मूल रूप से “फुलेर साजी”, नामक बंगला उपन्यास का संताली अनुवाद है।”³ सबसे पहले रेव० पी० ओ० बोडिंग द्वारा 1924 ई० में संताली लोककथाओं का संग्रह “होड़ काहनीको” नामक पुस्तक प्रकाशित किया। 1930 ई० में चैतन्य हेम्रम नामक एक संताल पादरी ने ‘संताल परगना’ संताल आर पहाड़िया को वाक् इतिहास लिखा। 1945 ई० में बोडिंग की ‘गाम कहानी’ दूसरी लोक कथा संग्रह प्रकाशित हुआ। लेकिन संताल का पहला उपन्यास 1936 ई० में रोमन लिपि में प्रकाशित हुआ ‘हाड़माज विलेज’ (हाड़मा का गाँव) जिसके लेखक आर० कार्टैयर्स थे। इन्होंने मूलरूप से इसे अंग्रेजी में लिखकर प्रकाशित किया। ‘हाड़माज विलेज’ इसका संताल अनुवाद आर० आर० किस्कु रापाज ने किया है। देश स्वाधीन होने के बाद से संताली भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और उड़िसा राज्यों में संतालों की आबादी बहुतायत है। संतालों द्वारा अनेक सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ संचालित हैं। अनेक सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा नाटकों का मंचन होना आरम्भ हुआ। ऑडियो और विडियो कैसेटों का निर्माण होने लगा। “संताली नाटक पाँच दशकों से लिखे एवं खेले जा रहे हैं। संताली साहित्य की प्रगति का प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक नाटक ही कर रहे हैं।”⁴ चालिस दशक से ही कई व्यवसायिक नाट्य संस्थाओं द्वारा बिहार, बंगाल, उड़िसा और झारखण्ड के संताली सांस्कृतिक क्षेत्र में नाटकों का मंचन होता रहा है।

“संताली नाटकों के मंचन साथ-साथ जो भी विडियो फिल्में तैयार की गईं उन फिल्मों की पटकथा स्वयं निर्माताओं द्वारा लिखित और निर्देशित हैं। इन फिल्मों का चित्र बी. एच. एस. कैमरा से लिया गया है अपने संस्कार और संस्कृति के धरातल पर आधारित फिल्म के युग में भी इन लेखकों और निर्देशकों द्वारा तैयार की गई संताली विडियो फिल्मों से एक और बात सामने आती है, सांस्कृतिक चिंतन से ओत-प्रोत समाज को कुछ देने की भावने।”⁵

संताल जाति के लोग प्रकृति से गहरे रूप से जुड़े हैं। संतालों के गीतों से प्रकृति की सौन्दर्य अनुभूति होती है। पहाड़ों और जंगलों से जुड़े जीवन प्रकृति की सहज अनुभूति के लिए उन्मुक्त है। संतालों के लोक गीत उनके जीवन शैली और सांस्कृतिक धारा की निरंतरता का दर्पण है।

संताली भाषा की विशिष्ट ध्वनियाँ –

जब इसाई मिशनरियों ने संताली भाषा लिखना प्रारंभ किया था तो उन्होंने बंगला और रोमन लिपियों का सहारा लिया था। बोडिंग साहब संसार की अनेक लिपियों को जाँचने-परखने के बाद रोमन लिपि को उपयुक्त समझा। रोमन अक्षरों को संताली ध्वनियों में उच्चारित करने के लिए “डार्क्रीटिकल मार्क्स” का सहारा लिया। जब रोमन लिपि में संताली भाषा लिखी जाने लगी तो उनको खुद डार्क्रीटिकल मार्क्स एक समस्या लगी। वर्तमान में प्रयुक्त नागरी, बंगला लिपियों में जब

संताली लिखी जाती है, वह भी डार्क्रीटिकल मार्क्स के सहारे से ही लिखी जाती है।

1.संताली भाषा में चार चेकड है। पी० ओ० बोडिंग के अनुसार ये चेक साउण्ड क्रमशः के० सी० पी० और टी० है। के० सी० पी० और टी० के ऊपर एफोस्ट्रोफी लगाकर ये चेकड साउण्ड को उच्चारित कर उन्होंने रोमन अक्षरों को संताली भाषा के लिए व्यवहार में लाया। यद्यपि इसाई मिशनरियों में उपरोक्त चार चेकड साउण्ड के बारे में भी विद्वानों में एकमत नहीं था फिर भी उस काल में रोमन लिपि के सहारे अमूल्य संताली पुस्तकों की रचना हुई। परन्तु संताली भाषा को विशिष्ट ध्वनियों के उच्चारित करने में सफलता हासिल नहीं कर पाये थे। इसलिए उन्होंने रोमन लिपि में “डार्क्रीटिकल मार्क्स” लगाकर लिखना ही ज्यादा उचित समझा। जैसे— आ के उच्चारण में जितना मुँह खोलना पड़ता है। आ के उच्चारण में मुँह कम खोलना पड़ता है तथा जीब के आगे के हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है। इस स्वर-वर्ण के नीचे एक बिन्दु लगाकर व्यवहार किया जाता है। जैसे—मालिक, बाबु, थारी, आतिज आदि।

2. **ks**, – इसका उच्चारण हल्का सी ओ की तरह होता है। अतः यह एक अर्द्धविकसित पश्व स्वर कहलाता है। इसकी मात्रा के रूप में ‘i’ के उच्चारण में नीचे एक बिन्दु लगाकर पढ़ा जाता है। जैसे हिन्दी में रोम, लोम आदि शब्द आये हुए ‘i’ के बंगला एवं मैथली के शब्द धन मन तन के उच्चारण में ‘i’ ध्वनी अथवा अंग्रेजी में खुला “**ks**” के जैसे उच्चारण होता है। यह दूसरा विशेष स्वर है। जैसे—होड़ (आदमी), ओकोय (कौन), ओड़ाक, बोलोन आदि।

3.“यं” – जब यह किसी स्वर के साथ आता है तब उसका उच्चारण बहुत कुछ ज “युं” के तरह होता है। जैसे—याम—याम, युंतुम।

4.क, च, त, प, ये चारो अर्द्धव्यंजन हलंत के साथ संताली भाषा के शब्द के अंत में ही प्रयोग होता है। इसके उच्चारण के पहले ध्वनि (श्वास) कंठ तक आते-आते एकाएक रुक जाती है। इसके बाद स्पष्ट होता है। इसका उच्चारण बड़ा हल्की सी होती है। इसे अर्द्ध व्यंजन कहते हैं। जैसे—माक्, साक्, मेत्, उप् आदि।

5.ड—यह भी स्वतंत्र वर्ण है। इसमें मात्रा भी लगती है। जैसे— बाड, बाराड, गेराड, देलाड आदि।

6.संताली भाषा में स्वर वर्णों के उच्चारण में ठिड़ापन दिखाई पड़ता है। उच्चारण की यह सरलता ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की शैच्छिकता में प्रदर्शित होती है। स अन्य ध्वनियों में भी दिखाई पड़ती है। जैसे— दारे (पेड़), इसमें “रे” मे उच्चारण के इकार एवं एकार के बीच का ध्वनि होता है।

7.जब ह्रस्व स्वर शब्द जोड़कर उच्चारण किया जाता है तो दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। पढ़ने में एक प्रकार के लगते हैं। जैसे—गोच्—एन—आय से गोच्एनाय।

8.विसर्ग— इसका उच्चारण आधा ह जैसा होता है। जैसे—दाः, लाः, चाः, माः, राः आदि।

9. जैसे हिन्दी और बंगला में “श” और “श” का व्यवहार होता है लेकिन संताली में नहीं होता है। केवल “स” से ही काम चल जाता है। जैसे—दिसा, निसा, उडिसा आदि।

निष्कर्ष :

अब संताली भाषा और ध्वनियों में भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, दिनों—दिन इस भाषा की अन्य विकसित भाषाओं जैसे मानक रूप प्राप्त कर चुके हैं। संताली भाषा मानक होने के साथ—साथ देश के अन्य कई राज्यों में भी द्वितीय राज्य भाषा के रूप में सम्मान प्राप्त कर सकता है। इस भाषा में वर्तमान में बहुत सी कार्य करने की आवश्यकता है। इस भाषा को लोगों के बीच में बहुत ही सहजता से प्रचार—प्रसार की आवश्यकता है। संताली भाषा के माध्यम से लोगों में मध्यकाल के अनुरूप लिखित साहित्य का सृजन हो रहा है।

संदर्भ सूची

1. तिवारी, भोलानाथ — भाषा विज्ञान, प्रकाशक — किताव महल —22, सरोजनी नायडु मार्ग, इलाहाबाद साल — 2013 (संतावनवां संस्करण)
2. केशरी, विशेष्वर प्रसाद —झारखंडी भाषाओं की समस्याएँ और संभावनाएँ, ज्योति संगम पथ, अपर बाजार, राँची — 834001, पृष्ठ सं — 17
3. बास्के धिरेन्द्रनाथ — साँवताली भाषा ओ साहित्य इतिहास, श्रीमती ओनिता बास्के, 18/1, शांतिनगर रेजेन पार्क, कोलकाता — 700041, द्वितीय प्रकाशन — 2005, पृष्ठ सं — 125
4. बोस, डॉ. कमल कुमार —झारखंड की भाषाओं का नाट्य साहित्य, प्रकाशक — अरविन्द प्रकाशन, लोहारघाट, आलमगंज चौकी, पोस्ट — गुलजारबाग, पटना, बिहार — 800007, प्रथम संस्करण — 2015, पृष्ठ सं — 83—84
5. सोरेन, भोगला — संताली भाषा लिपि और साहित्य का विकास — पृष्ठ सं — 28, 29

शम्भुनाथ सोरेन,

सहायक प्रोफेसर,

संताली विभाग, मानभुम महाविद्यालय, मानबजार,

पो/थाना — मानबजार, जिला — पुरुलिया, पश्चिम बंगला,

पिन— 723131, मो — 9800432482